

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

अर्थशास्त्र

मुरलीधर जोशी

अध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय

और

सेवाराम शर्मा

अध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ

दि अपर इंडिया पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड

१९५१

प्रथम संस्करण १९५१

सर्वाधिकार सुरक्षित

कम्पोजिंग दि अणर इडिया पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड
मुद्रण जनता प्रेस, लखनऊ

प्रस्तावना

गत पञ्चीम-ताम वर्षोंमें पाश्चात्य देशोंमें अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंके विवेचन और विदलेषणमें बड़े वेगसे प्रगति हुई है। कोईभी आधुनिक अर्थशास्त्री इन प्रवृत्तियोंसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। प्रस्तुत पुस्तकमें अर्थशास्त्रके सम्पूर्ण क्षेत्रके सिद्धान्तोंकी विवेचना की गई है। प्रत्येक विषयपर आधुनिक मतका प्रतिपादन करते हुए तत्सम्बन्धी अन्य मतोंकी विवेचना भी कर दी गई है। आशा है कि पाठको—विशेषकर विश्वविद्यालयोंके विद्यार्थियों—के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

साधारणतः अर्थशास्त्रके दो विभाग किये जाते हैं। एक विभाग सिद्धान्तोंका निरूपण करता है और दूसरा आर्थिक समस्याओंका अध्ययन करता है। दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तकमें अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंपर ही प्रकाश डालनेका प्रयास किया गया है। अतएव इसमें पाठकोको आर्थिक समस्याओं और उनके समाधानों का विशेष वर्णन नहीं मिलेगा।

अर्थशास्त्रकी आधुनिक पुस्तकोंमें एक विशेष दृष्टिकोणके आधारपर सम्पूर्ण विषयोंकी विवेचना करनेकी प्रथा चल पड़ी है। किसीमें आर्थिक क्षेत्रको, किसीमें राष्ट्रीय आयको, किसीमें मूल्यको और किसीमें सीमान्त विश्लेषणको प्रधानता दी गई है। इस रीतिसे विषयका प्रतिपादन करनेमें कुछ विनोयताएँ अवश्य हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकोंने अपनेको किसी एक दृष्टिकोणसे बद्ध नहीं किया है। उन्होंने केवल एकही दृष्टिकोण अपने सामने रखा है और वह यह कि पाठक इस विषयके विविध प्रकरणोंको सुगमताके साथ समझ सकें। यही कारण है कि आधुनिक प्रवृत्तियोंका समावेश करते हुए भी अध्यायोंके क्रममें कुछ अशतक पुरानाही ढंग रखा गया है।

इस पुस्तकको लिखनेमें सबसे बड़ी कठिनाई लेखकोंको विषय सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दोंको प्राप्त करनेमें हुई। प्रचलित पुस्तकों, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्रादि, अर्थ-कोषोंमें जो शब्द प्राप्त हुए उनमें अनेक अनुपयुक्त जान पड़े। अतएव लेखकोंने बहुतसे शब्दोंकी मृष्टि स्वयंकी है। कही कहीपर एकही अर्थमें दो शब्दोंका भी

प्रयोग होगया है जैसे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा, मजूरी और पारिश्रमिक इत्यादि । अभी अर्थशास्त्र शब्दावली बननेको है । अतएव लेखकोंने अपनेको किसी शब्द-विशेष से बद्ध नहीं कर लिया है । पाठकोंकी सुविधाके लिए पुस्तकमें प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दोंकी एक शब्दावली पुस्तकके अन्तमें दे दी गई है ।

अर्थशास्त्रके सम्पूर्ण क्षेत्रकी दिवचना करनेमें एक समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि भिन्न भिन्न विषयाका किस अनुपातमें समन्वय किया जाये । अर्थशास्त्रके अन्तर्गत अनेक विषय और प्रकरण हैं और प्रत्येकमें सम्बन्धित अनेक मत हैं । अतएव किस विषयको कितना स्थान देना चाहिए इसका निर्णय करना कठिन है । हाँ सक्ता है कि ग्रन्थ पुस्तकमें किसी प्रकारके विषयको उम मात्रामें विवेचना न हो पाई हो जिस मात्रामें अन्य पुस्तकामें प्राप्त हो सके या पाठक आशा करते हैं । कालान्तरमें भिन्न भिन्न विषयोंके महत्वमें परिवर्तन होता रहता है और भिन्न भिन्न प्रकरणोंके सन्तुलनमें लेखकोंकी मनोवृत्तिका भी प्रभाव पड़ता है । पाठकोंसे हमारा सविनय अनुरोध है कि वे हमको पुस्तककी त्रुटियों और असुविधाओंकी सूचना देना कष्ट करें जिससे हम दूसरे संस्करणमें पुस्तकको अधिक उपयोगी बना सकें ।

हमारे ज्ञानका आधार प्रधानतया पाश्चात्य देशोंके अर्थशास्त्रियोंकी पुस्तकें और लेख हैं । हम इनके बहुत आभारी हैं । हमका मार्शल टॉसिंग वीगू, दिक्सीड, दिक्सेल, बीजर, नाइट, रीबिन्स, माइज़ेज हायक ओहलिन, वगैरे और हेंबरलरकी पुस्तकें से विशेष सहायता मिली है । विश्वविद्यालयमें अध्यापनका कार्य करनेके कारण हमको स्वयंभी सोचन-मनन और तर्क करनेका अवसर प्राप्त हुआ है । इसके लिए हम अपने सहयोगी अध्यापकों और अर्थशास्त्रके छात्रोंके भी आभारी हैं ।

सत्यनरु विश्वविद्यालय

मुरलीधर जोशी
सेवाराम धर्मा

विषय-सूची

१ अर्थशास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र	...	पृष्ठ	१
अर्थशास्त्र का विषय	२
अर्थशास्त्र का क्षेत्र ✓	३
आर्थिक विस्लेषण की रीतियाँ ✓	१०
आर्थिक क्षेत्र	१३
अर्थशास्त्र और विज्ञान	१४
अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध	१५
अर्थशास्त्र के नियम	१६
२ आवश्यकताएँ	१८
उपभोग का महत्व ✓	१८
आवश्यकताएँ और उनकी विरोधनाएँ ✓	१८
उपयोगिता ✓	२२
नमागत-उपयोगिता-ह्रास नियम	२३
कुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता ✓	२५
सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम ✓	२८
३ माग	३३
माग का तात्पर्य	३३
माग का नियम ✓	३५
माग में परिवर्तन	३७
माग की लोच	३८
माग की लोच में भिन्नता	४२
माग की लोच का महत्व	४५
उपभोक्ता की बचत ✓	४५
४ तटस्थ रेखाएँ	४६
उपयोगिता का दोष	४६
तटस्थ रेखा का आकार	५१
स्थानापन्नता की दर	५२

सीमांत उपयोगिताया का अनुपात	५३
सटस्य रखा की स्पर्सरर्या और उसका ढलान	५३
आय रखा	५५
आय उपभोग रखा	५६
मूल्य उपभोग रखा	५६
स्थानापन्नता की लोच	५७

५ बाजार

बाजार के प्रकार	५८
गुद्ध बाजार के लक्षण	६०
बाजार का विस्तार	६१
धर्म बाजार	६३
बाजारों की व्यवस्था	६३
सद्दा	६४

६ प्रतिस्पर्धा

प्रतिस्पर्धा का अर्थ	६७
पूर्ण प्रतिस्पर्धा के फल	६८
पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार	७०
उत्पत्ति विभेदीकरण	७१
मूल्य भेद	७२
एकाधिकार के आधार	७४
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार की सीमा	७५
उत्पादक साधना की गतिशीलता	७६
भूमि की गतिशीलता	७७
धर्म की गतिशीलता	७७
पूजी की गतिशीलता	७८
पूर्ण उत्पन्न और गतिशीलता	७८

७ मूल्य निर्धारण की विधि

मूल्य के प्रकार	८०
मूल्य का महत्व	८०
माग पूर्ति और मूल्य	८१
काल भेद और मूल्य	८२

क्षणिक काल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, और मूल्य	८३
अल्पकाल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य	८३
अल्पकाल, एकाधिकार और मूल्य	८७
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य	८८
बाजार-मूल्य और सामान्य-मूल्य	८९
औसत उत्पादन-व्यय और औसत आय	९१
सम्मिलित उत्पत्ति और मूल्य	९६
सम्मिलित माग	९६
एक वस्तु के भिन्न भिन्न मूल्य	९७
८ प्रतिस्थापना	९८
प्रतिस्थापना का महत्व	९८
प्रतिस्थापना और तटस्थ-स्थिति	९८
दो प्रकार की स्थानापन्न वस्तुएं	९९
प्रतिस्थापना और मूल्य	९९
सीमान्त स्थानापन्नता	१००
प्रतिस्थापना और उपभोग	१०१
प्रतिस्थापना और उत्पादन	१०१
प्रतिस्थापना और वितरण	१०२
प्रतिस्थापना की विरोधी शक्तियां	१०३
९ आर्थिक सन्तुलन	१०४
मूल्यों का पारस्परिक सम्बन्ध	१०४
मूल्यों का सन्तुलन	१०५
संस्था का सन्तुलन	१०७
उद्योग और उसका सन्तुलन	१११
उत्पादन और उसका सन्तुलन	१११
१० मूल्य और उसके सिद्धान्त	११४
मूल्य का अर्थ	११४
मूल्य का श्रम सिद्धान्त	११५
उत्पादन-व्यय सिद्धान्त	११७
श्रम और उत्पादन-व्यय सिद्धान्तों की त्रुटियां	११८
सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त	११९

११/ उत्पादन के साधन—भूमि	१२२
/ उत्पादन का अर्थ	१२२
/ उत्पादन के साधन	१२३
/ भूमि	१२५
उत्पत्ति का त्रिभागन ह्रास सिद्धान्त	१२६
परिवर्तनाय अनुपात का सिद्धान्त	१२८
सर्वोत्तम विनियोग का सिद्धान्त	१३१
साधन की अविभाज्यता	१३२
१२/ आर्थिक साधन—श्रम	१३४
/ श्रम की परिभाषा	१३४
जन सख्या	१३५
जन सख्या में परिवर्तन का महत्व	१३८
वर्द्धशील जन सख्या	१३८
ह्रासशील जन सख्या	१३९
/ कुशलता	१४०
/ श्रमविभाजन के लाभ	१४२
१३/ उत्पादन के साधन—पूँजी	१४४
उत्पादन काल और उसकी दीर्घता	१४५
उत्पादन अवधि और उत्पादनशीलता	१४७
/ पूँजी की वैकल्पिक परिभाषा	१४८
विभिन्न प्रकार की पूँजी	१४८
/ पूँजी और वचन	१५०
पूँजी का संरक्षण	१५०
१४/ व्यवस्था	१५२
व्यवस्था की आवश्यकता	१५२
बड़े परिमाण में उत्पत्ति	१५३
व्यवस्था के रूप	१५५
उत्पादन व्यय	१५८
१५/ उद्योग-वन्धों का अभिनवीकरण	१६२
अभिनवीकरण का अभिप्राय	१६२

अभिनवीकरण के मुख्य अंग १६२
अभिनवीकरण के लाभ तथा हानिया १६४
वैज्ञानिक प्रबन्ध का अर्थ तथा उद्देश्य १६६
वैज्ञानिक प्रबन्ध के दोष १६८
१६ आर्थिक पद्धतिया १७०
पूजीवाद का अर्थ १७०
पूजीवाद के लक्षण १७१
पूजीवाद का विकास १७३
माक्सवाद १७४
माक्सवाद की शाखाए १७५
समाजवाद १७५
साम्यवाद १७६
आर्थिक उत्पत्ति और पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम १७७
न्याययुक्त वितरण १७८
१७ राष्ट्रीय आय १८०
राष्ट्रीय आय का अर्थ १८०
राष्ट्रीय आय की माप विधि १८१
वैकल्पिक माप-विधिया १८२
राष्ट्रीय आय और भौतिक उत्पाद १८३
राष्ट्रीय आय मापने के लाभ १८५
१८ भूमि-कर १८८
रिकाडों का भूमि-कर सिद्धान्त १८८
रिकाडों के सिद्धान्त की आलोचना १८९
भूमि-कर का आधुनिक सिद्धान्त १९३
कृषि-सम्बन्धी समुन्नति और भूमि-कर १९५
१९ मजूरी (पारिश्रमिक) और उसके सिद्धान्त १९६
मजूरी की परिभाषा १९६
मजूरी का लोह सिद्धान्त १९७
मजूरी कोश सिद्धान्त १९८
सौमान्त उत्पत्ति सिद्धान्त १९८

मजूरी का आधुनिक सिद्धांत	२०१
जीवन स्तर और मजूरी	२०२
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मजूरी	२०३
नय आविष्कार और मजूरी	२०६
मजूरी भुगतान	२०६
२० व्याज और उसके सिद्धान्त	२०८
गूढ़ तथा मिश्रित व्याज	२०८
व्याज की दर	२०८
पूँजी की उत्पादनशीलता और व्याज	२११
उपभोग व्यापक वृद्धि और व्याज	२१२
व्याज और द्रव्य बरीयता	२१४
व्याज और पूँजी की उत्पादनशीलता	२१४
२१ लाभ	२१७
गूढ़ और मिश्रित लाभ	२१७
लाभ का भूमि पर सिद्धांत	२१७
जोनिम और लाभ	२२०
व्याज का प्रगतिशील सिद्धांत	२२१
२२ द्रव्य	२२३
द्रव्य की आवश्यकता	२२३
वस्तु विनिमय की प्रथा	२२४
विनिमय का माध्यम	२२५
म द का माप दंड	२२६
कानयापन माप दंड	२२८
द्रव्य और दान	२२६
द्रव्य के प्रकार	२२६
धातु द्रव्य	२३०
मुद्रा	२३१
नोट	२३४
विनिमयसाध्य नोट	२३६
अविनिमयसाध्य नोट	२३७
साम द्रव्य	२३६

साख द्रव्य का सृजन	२४०
२३ द्रव्य पद्धतिया	२४४
द्रव्य पद्धतिया के प्रकार	२४४
द्विधातु पद्धति	२४५
प्रशम नियम	२४६
स्वण द्रव्य पद्धति	२४६
स्वण मुद्रा पद्धति	२४७
अमुद्रित स्वण द्रव्य पद्धति	२४७
स्वण विनिमय द्रव्य पद्धति	२४८
स्वण द्रव्य पद्धति के मुण और दोष	२४८
स्वण द्रव्य पद्धति के व्यावहारिक नियम	२४९
स्वण द्रव्य पद्धति का अत	२४९
अविनिमयसाध्य प्रविधत द्रव्य पद्धति	२५५
२४ द्रव्य का विनिमय मूल्य	२६१
मूल्य और विनिमय मूल्य	२६१
द्रव्य का विनिमय मूल्य	२६२
मूचक अक	२६३
द्रव्य के विनिमय मूल्य का पारिमाणिक सिद्धांत	२६६
द्रव्य का मचयन सिद्धांत	२७०
द्रव्य के विनिमय म य म परिवर्तन का प्रभाव	२७२
२५ वैक	२७५
साख और साख पत्र	२७५
वका का विकास और उनके काम	२७७
वका की लनी देनी	२७८
वेन्द्रीय वक	२८२
२६ विदेशी विनिमय	२८०
विदेशी विनिमय की आवश्यकता	२८०
अ तराष्ट्रीय देनी का सामजस्य	२८१
व्यापारिक विमता सिद्धांत	२८४
स्वण द्रव्य पद्धति और विदेशी विनिमय	२८५

नियन्त्रित विदेशी विनिमय	२६७-४
यविनिमयमाध्य द्रव्य पद्धति और विदेशी विनिमय	३००
विदेशी विनिमय नियन्त्रण कोष	३०२
२७ अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष और विश्व बैंक	३०५
द्रव्य कोष	३०५
कोष और विदेशी विनिमय की दर	३०७
विनिवबक	३१०
२८ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	३१३
पथक सिद्धांत की आवश्यकता	३१३
उद्योग धंधों के स्थानीकरण से सम्बन्ध	३१३
तुलनात्मक उत्पादन व्यय सिद्धान्त	३१५
भान की लोच और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	३१८
२९ उन्मुक्त और संरक्षित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	३२०
उन्मुक्त के लाभ	३२०
संरक्षण	३२१
संरक्षण के लाभ और हानियाँ	३२१
संरक्षण और र्छम्पय	३२५
निर्यात और आर्थिक सहायता	३२६
व्यापारिक समनुबन्ध	३२७
३० आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्ष	३२८
आर्थिक प्रगति	३२८
आर्थिक चक्र	३२९
बकारी	३३२
आर्थिक चक्र के सिद्धांत	३३४
कृषि सिद्धान्त	३३४
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त	३३५
द्रव्य सम्बन्धी सिद्धान्त	३३७
हायक का सिद्धांत	३३९
उपभोग हानि सिद्धान्त	३४१
यचन और पूँजी लगाव सिद्धान्त	३४३

अर्थशास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र

इन समारमों मनुष्य जिस वातावरणमें जन्म लेता है वह वास्तवमें अनेक प्रकारकी परिस्थितियोंका सम्मिश्रण मात्र है। इनमेंसे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके उत्पन्न करनेमें उसका कुछ हाथ नहीं है और कुछ ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे उसीके आचरण और व्यवहारके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। इन सभी प्रकारकी परिस्थितियोंका उसपर तथा उसके कार्योंपर प्रभाव अवश्य पड़ता है। अतएव वह इन परिस्थितियों और सम्बन्धी तथ्योंको समझनेकी चेष्टा करता है। सम्भव है कि प्राग्भूममें वह केवल स्वाभाविक उत्पन्नतावाही ऐसा करता रहा हो परन्तु निश्चयही आगे चलकर इस प्रकार प्राप्त ज्ञानका प्रयोग उसने या तो परिस्थितियोंको अपने अनुकूल अथवा अपने को परिस्थितियोंके अनुकूल बनानेमें किया। यही नहीं जहाँ परिवर्तन सम्भव नहीं हुआ वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियोंसे सन्ध करानेमें भी इस ज्ञानसे उसको बड़ी सहायता मिली।

उत्पन्नता जाग्रत करने वाली वस्तुधर्मों में प्रकृतिका स्थान सर्वप्रथम है। मनुष्य अपने आस पास जीव-जन्तुओं और पेड़-पौदोंको देखता है और उनकी उत्पत्ति एवं विकास, गुण तथा प्रवृत्ति जाननेकी चेष्टा करता है। इसी प्रकार वह आकाशमें सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रोंको देखता है। पृथ्वी पर प्रकाश, धूप, वृष्टि, नदी, समुद्र, पहाड़ इत्यादि को देखता है। खानेसे लनिज पदार्थ, लोहा, कोयला, सोना, चादी इत्यादि निकलते हुए देखता है। निश्चय ही उसके मनमें इनके विषयमें जाननेकी उत्कंठा होती है। केवल देख-सुनकर प्राप्त साधारण बोधसे ही उसको सन्तोष नहीं होता। वह गहराईमें जाना चाहता है और कार्य-कारणके सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वह इन विषयोंकी छान-बीन करके उनके अन्तर्गत नियमों और सिद्धान्तोंकी स्थापना करता है तथा उनके आधार पर भावी परिस्थितियोंके विषयमें कुछ, कुछ, कुछ भविष्यवाणी, कहने लगता है, और, कहता, कहता, है। इस प्रकारके ज्ञानको विज्ञान कहते हैं। भिन्न भिन्न विषयोंके सम्बन्धमें एकत्रित

ज्ञान-विज्ञान विभिन्न शास्त्रोंके अन्तर्गत आते हैं। उदाहरणके लिए प्राणियोंके विषयमें जो विज्ञान है, उसका समावेश प्राणि शास्त्रमें, पेड़-पौदोंका वनस्पति शास्त्र में और ग्रह-नक्षत्रों आदिका खगोल शास्त्र में है। इसी प्रकार रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र इत्यादि भी अपने अपने विषयोंके विज्ञानको प्रतिपादित करते हैं। इनमें भी कुछ विषयों पर अधिक ज्ञान प्राप्त हो चुका है क्योंकि उनके प्राप्त करनेके अधिक साधन उपलब्ध हैं; अन्य बहुतसे विषयों पर अभी ज्ञान बहुत ही परिमित है।

अर्थशास्त्र का विषय

मनुष्य न केवल बाह्य परिस्थितिको ही समझनेका प्रयत्न करता है, वरन् वह अपने और अपने कार्योंके विषयमें भी जानना चाहता है। उदाहरणके लिए, वह अपने शरीरके तथा अपनी मनोवृत्तिके विषयमें भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इन विषयोंकी विवेचना तथा व्याख्याके फलस्वरूप शरीरविज्ञान शास्त्र और मनोविज्ञान शास्त्रकी उत्पत्ति हुई है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाजमें रहना पसन्द करता है। अतएव उसके अन्य मनुष्योंसे अनेक प्रकारके सम्बन्ध हो जाते हैं। इन सम्बन्धोंके अध्ययनके फलस्वरूप अनेक शास्त्रोंकी सृष्टि हुई है। जैसे समाजके संगठन रूपमें रहनेके लिए व्यवस्था एवं नियमकी आवश्यकता होती है, जिसके लिए किसी प्रकारके शासन अथवा शासकसमूह का होना आवश्यक है। इनके फलस्वरूप राजा और प्रजा, शासक और शासित, राज्य और नागरिकोंके बीच अनेक प्रकारके कर्तव्य और उत्तरदायित्वके पट्टन उपस्थित हो जाते हैं, जिनका विवेचन राजनीति शास्त्रमें किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य और मनुष्यके बीच धर्म सम्बन्धी, भावा सम्बन्धी, नीतिसम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनका अध्ययन तत्सम्बन्धी शास्त्रोंमें किया जाता है।

मनुष्यकी अनेक प्रकारकी आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्तिके लिए वह सतत प्रयत्न करता रहता है। इन्हीं आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए किसान खेतोंमें और श्रमजीवी कारखानोंमें काम करते हैं। कुछ मनुष्य अध्यापनका कार्य करते हैं, कुछ चिकित्साका, कुछ व्यापारका और कुछ सरकारी नौकरीका। इन्हीं आवश्यकताओं

की पूर्तिके लिए विविध प्रकारके बल कारखानो, बैंक, रेल, जहाज, डाक और तार इत्यादिका निर्माण हुआ है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए साधारणतः मनुष्य चिन्तित रहता है और कठिन परिश्रम तथा दौड़धूप करता है। अतएव यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि मनुष्य इस विषयकी ओर विशेषरूप से आकृष्ट हुआ है तथा उसने इसके अध्ययनकी चेष्टा की है जिसके परिणामस्वरूप एक शास्त्रकी उत्पत्ति हुई, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं।

अर्थशास्त्रके नामही से उस विद्याका बोध होता है, जिसका सम्बन्ध 'अर्थ' अर्थात् धन, द्रव्य और सम्पत्तिसे हो। हम देखते भी हैं कि मनुष्यके समयका एक बड़ा भाग अर्थके उपाजन और उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिमें व्यय होता है। जिन आवश्यकताओंकी पूर्ति अर्थ द्वारा होसकती है उनको आर्थिक आवश्यकताएँ कह सकते हैं। आजकलके आर्थिक समाजमें प्रायः सभी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमें अर्थकी आवश्यकता पड़ती है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि मनुष्यकी कुछ आवश्यकताएँ आर्थिक होती हैं और कुछ अनार्थिक और तत्सम्बन्धी आर्थिक तथा अनार्थिक कार्य भी होते हैं। वास्तव में प्रत्येक आवश्यकता तथा कार्यका कम या अधिक मात्रा में आर्थिक पक्ष अवश्य रहता है। अतएव इन कार्यों और आवश्यकताओंसे अर्थशास्त्रका सम्बन्ध हो जाता है तभी अर्थशास्त्री को उनका अध्ययन करना पड़ता है।

मनुष्यकी आवश्यकताएँ जहाँ अपरिमित होती हैं, वही उनकी पूर्तिके साधन परिमितभी होते हैं। अतएव मनुष्य अपनेको इस प्रकारकी परिस्थिति में पाता है जिसमें उसे यह निर्णय करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओंकी पूर्ति की जावे और किम अश्व में। हम देखते हैं कि प्रत्येक कुटुम्ब की आय सीमित होती है परन्तु उसके सामने अनेक प्रकारकी आवश्यकताएँ रहती हैं, जिन सभी की तृप्ति इस सीमित आय से नहीं हो सकती क्योंकि आय का जो भाग एक आवश्यकता की पूर्ति पर व्यय किया जाता है, वह दूसरी आवश्यकताकी पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहता। अर्थात् एक आवश्यकताकी पूर्ति का अर्थ हुआ किसी दूसरी इच्छा का अतृप्त रहना। मनुष्यकी आवश्यकताओंकी पूर्ति उपभोगकी वस्तुओंसे होती है। समाजके सभी लोगों की सभी आवश्यकताओंके लिए उपभोगकी वस्तुएँ पर्याप्त नहीं होती हैं। इसका प्रधान कारण यही है कि इन वस्तुओंको उपभोग

करनेके साधन, प्राकृतिक सामग्री, पूजी और मनुष्यों की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति सीमित है। अतएव यह एक महत्वपूर्ण समस्या है कि इन सीमित साधनोंका असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ किस प्रकार सामंजस्य किया जाय। इस समस्याको हम आर्थिक समस्या भी कह सकते हैं। यह समस्या प्रत्येक व्यक्ति, कुटुम्ब और समाज के सामन है। यही समस्या अतीतकाल में भी रही है और भविष्य में भी रहेगी। यह ठीक है कि अतीतकाल की अपेक्षा वर्तमान समय में उत्पत्तिके साधनों और वस्तुओंके उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गयी है परन्तु साथ ही साथ आवश्यकताओंकी समस्या में भी वृद्धि हुई है। अतएव समस्या ज्यों की त्यों बनी है। यह समस्या प्रत्येक प्रकारकी आर्थिक पद्धति में पायी जाती है। देश में पूँजीवादी व्यवस्था हो अथवा समाजवादी, प्रत्येक व्यवस्थाको इस परिस्थितिका सामना करना पड़ना है और प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न रीतियोंसे इस समस्याको सुलभमाना चाहता है। पृथ्वीके अधिकांश भागमें आजकल पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था है अतएव इस पुस्तकमें प्रधानतया इसी बातकी विवेचना की जायेगी कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाता है। इस व्यवस्थाके प्रतिष्ठित ३० अर्थ प्रकार की व्यवस्थाएँ प्रचलित हैं उनमें किस प्रकारमें इसका समाधान किया गया है, इसका भी संक्षेपमें विवेचन किया जायेगा।

मनव्य अर्थशास्त्र इस परिस्थिति में पाता है कि उसकी आवश्यकताएँ तो अपरिमित हैं किन्तु उसके पास उनकी पूर्तिके साधन परिमित हैं। इन साधनोंमें एक विशेष गुण यह है कि इनमेंसे बहुतस इस प्रकारके हैं जिनसे अनेक प्रकारकी आवश्यकताओंकी पूर्तिका कार्य लिया जा सकता है। उदाहरणके लिए भूमि एक उत्पत्तिके साधन है। भूमि पर कई प्रकारका अनाज पैदा किया जा सकता है, मकान बनाया जा सकता है; तालाब अथवा कुआँ खुदवाया जा सकता है; और भी अनेक प्रकारके भूमिका उपयोग हो सकता है। परन्तु यदि भूमि का एक टुकड़ा किसी समय एक कार्यमें लगा दिया गया तो उसी समय उससे दूसरा कार्य नहीं लिया जा सकता। यही अवस्था श्रम और पूँजीकी भी है। ऐसी दशा में परिमित एवं विविध कार्योंके योग्य साधनों का अपरिमित आवश्यकताओंने सामंजस्य करने में जिस प्रकारका आचरण होना है, वह मनुष्यके लिए बड़े महत्वका है, क्योंकि उसीके आधार पर हम वान का निर्णय होता है कि उसकी किन आवश्यकताओंकी पूर्ति

होसकेंगी और किस अंश तक। कई आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतमें अर्थशास्त्र के विषयका मूल तत्व यही है। हम समार में जितने आर्थिक कार्य, आर्थिक सम्प्राप्ति और आर्थिक सम्बन्ध पाते हैं वह सब इसी मूल तत्व पर केन्द्रित है। एक प्रकारसे अर्थशास्त्रके विषयको इस दृष्टिकोणसे देखना ठीक भी है। किसी समस्याको समझने, सुलझाने और समाधान करनेका कार्य ही किसी भी शास्त्रका मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य और समाजके सामने एक बड़ी विकट समस्या यह है कि वह अनेक प्रकारकी आवश्यकताओंसे घिरा हुआ है और इनमें बराबर वृद्धि हो रही है। इनकी पूर्तिके लिए वह अपने पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में वह क्या करना है और वंसा क्या करता है, इसका विश्लेषण करना और इनको कार्य-कारणसे सम्बन्धित कर उनके साधारण व्यापार पर प्रकाश डालना एक महत्वपूर्ण विज्ञानसम्बन्धी कार्य है। अर्थशास्त्रके मूल में यही तत्व है।

इसी परिस्थितिसे हम दूसरे प्रकारसे भी देख सकते हैं। मनुष्यकी जीवन रहनके लिए वायुकी आवश्यकता है। परन्तु सीमायसे प्रकृतिने वायुको इतनी प्रचुर मात्रामें प्रदान किया है कि उसके सम्बन्धमें कभी भी इस प्रकार की समस्या पैदा नहीं हुई कि 'कब' 'कहाँ' और 'कितनी मात्रामें' इसका प्रयोग करें। सभी वायु सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्ति करने पर भी यह बहुत परिमाणमें बची रहती है। इसलिए वायुके सम्बन्धमें कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। यही कारण है कि वायुके लिए हमको किसी प्रकारका मूल्य नहीं देना पड़ता। जिस वस्तुको बिना प्रयास और बिना मूल्यके किसी भी मात्रामें प्राप्त किया जासके, उसको हम बिना मूल्यकी वस्तु कहेंगे। इस प्रकारकी वस्तुएँ हमारे वृत्ते कामकी हो सकती हैं परन्तु आर्थिक दृष्टिसे इनका कोई महत्व नहीं है। अतएव इन वस्तुओंको हम आर्थिक वस्तुओंमें नहीं रखते। मनुष्यके दुर्भाग्यसे ऐसी वस्तुओंकी संख्या बहुतही कम है। अधिकांश वस्तुओंकी मात्रा सीमित होती है और उनको प्राप्त करनेके लिए हमको स्वयं परिश्रम करना पड़ता है अथवा मूल्य देकर दूसरेसे लेना पड़ता है। प्रकृतिने सभी वस्तुओंको प्रचुरताके साथ नहीं दिया। भूमि का क्षेत्र सीमित है और कृषिके योग्य भूमि का जो बहुतही सीमित। इसी प्रकार खनिज पदार्थोंका परिमाण भी सीमित है। आवश्यकताओं का कम मात्रामें होनेके कारण

इनको प्राप्त करनेके लिए श्रम अथवा द्रव्यके रूपमें मूल्य चुकाना पड़ता है। मनुष्य की बनाई हुई वस्तुएँ भी सीमितही होती हैं क्योंकि उनको बनानेके साधन भी सीमित हैं। अतएव उनको प्राप्त करनेके लिए भी मूल्य देना होता है। एक प्रकारसे हम कह सकते हैं कि मूल्यवाली वस्तुएँ ही आर्थिक वस्तुएँ हैं और इन वस्तुओंके उपभोगसे जिन आवश्यकताओंकी पूर्ति होनी है वही आर्थिक आवश्यकताएँ समझी जाती हैं।

अर्थशास्त्र का क्षेत्र

आर्थिक साधनोंके परिमित होनेके कारण अनेक प्रकारके आर्थिक व्यापार उत्पन्न होजाते हैं। पहिला महत्वपूर्ण व्यापार उत्पत्तिके साधनोंसे भिन्न भिन्न प्रकारकी वस्तुएँ भिन्न भिन्न मात्राओंमें उत्पन्न करना है। उत्पत्तिकी इस क्रियापर राष्ट्रीय आयका परिमाण और उसका स्वरूप निर्भर करता है। आर्थिक साधनोंके समुचित प्रयोग पर आर्थिक क्रियाका स्तर निर्भर करता है। अतएव राष्ट्रीय आय कितनी है और किस प्रकार की है और इसमें किस प्रकारका परिवर्तन हो रहा है यह अर्थशास्त्रका एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। दो प्रकार की वस्तुओंका उत्पादन होता है। एक तो उपभोग्य वस्तुएँ और दूसरी उत्पादक वस्तुएँ। इन वस्तुओंकी उत्पत्तिकी क्रियामें जो साधन भाग लेते हैं, उनकी द्रव्यरूपी आय भी इसी क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इस द्रव्यरूपी आयके व्यय पर ही उत्पन्नकी हुई वस्तुओंकी माग अवलम्बित रहती है और मागके आधार पर उत्पत्तिका स्तर निर्भर करता है। यदि मागमें किसी कारण कमी आ जाय तो आर्थिक साधनोंमें बेकारी, उत्पत्तिकी मात्रामें कमी और आर्थिक क्षेमका ह्रास होने लगता है। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्थामें इस प्रकारकी अवस्था बहुधा हो जाया करती है। इस प्रकारकी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो जाती हैं और किस प्रकार इनका प्रतिकार किया जासकता है, यह आधुनिक आर्थिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण अंग हो गया है क्योंकि इसी पर राष्ट्रीय आयका और साधनोंके उपयोग का परिमाण निर्भर करता है।

दूसरा आर्थिक व्यापार जो कि प्रत्येक आर्थिक व्यवस्थामें पाया जाता है,

विनिमयका है। प्राचीनसे प्राचीन मनुष्यजाति में भी किसी न किसी मात्रामें भ्रमविभाजन और विशिष्टीकरण पाया गया है। आधुनिक ससारमें तो यह विशिष्टीकरण इतना विस्तृत एवं व्यापक हो गया है कि कोई भी मनुष्य अपने उपभोग की वस्तुओंका एक छोटा भाग भी स्वयं नहीं उत्पन्न करता। लाखों करोड़ों वस्तुओंके बीच वह एक भी समूची वस्तु नहीं बनाता; केवल उसका एक नगण्य भाग बनाता है। ऐसी अवस्थामें अपनी अपनी आवश्यकताओं की तृप्तिके लिए विनिमयका कार्य आवश्यक हो जाता है। प्राचीन कालमें यह कार्य वस्तु-विनिमय की प्रथा द्वारा सम्पन्न होता था। आजकल वही द्रव्यके माध्यमसे होता है। विनिमयकी सुगमताके लिए दो बातोंका होना अनिवार्य है। एक तो विनिमयका आधार और दूसरा उसका माध्यम। विनिमयका आधार मूल्य है और माध्यम द्रव्य। आजकल द्रव्यके रूपमें ही मूल्य प्रकट किया जाता है और द्रव्यकी सहायतासे क्रय-विक्रय होता है।

द्रव्यका परिमाण सरकार, केन्द्रीय बैंक और अन्य व्यापारी बैंको द्वारा निर्धारित होता है। प्रगतिशील देशोंमें बैंको द्वारा प्रचलित किये गये साखद्रव्य की ही प्रधानता है। आर्थिक पद्धतिके सगठन तथा संचालन में द्रव्यका इतना महत्व है कि इसके परिमाण, व्यय और सचयके परिवर्तनसे आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अतएव द्रव्य और द्रव्य सम्बन्धी सस्थाओंके नियन्त्रण की आवश्यकता होती है।

द्रव्यके रूपमें वस्तुओंके जो मूल्य निर्धारित होते हैं, उन्हींके आधार पर पूँजी-वादी पद्धतिमें उत्पातिका स्तर और स्वरूप बनता और बदलता जाता है। आर्थिक स्वतन्त्रता की व्यवस्थामें उत्पादक उन्हीं वस्तुओंका, उन्हीं मात्राओंमें उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें अधिक लाभ हो। वस्तुओंके बनानेमें जो लागत लगती है वह इन वस्तुओंके उत्पादनमें लगे साधनोंके मूल्यका ही समुच्चय है। वस्तुओंके मूल्य और लागतके अन्तर पर ही लाभकी मात्रा निर्भर करती है। अतएव उत्पादकको अपना व्यवसाय और उत्पादनकी मात्राको स्थिर करनेके लिए वस्तुओं और साधनोंके मूल्यकी जानकारी होनी चाहिए। यह मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है और इसपर किन किन बातोंका प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण अर्थशास्त्र का एक प्रधान भग है। यदि हम ध्यानसे देखें तो ज्ञात होगा कि मूल्यस्तरों पर न केवल

लाभकी मात्रा निर्भर करती है अपितु उत्पात्तिके साधनोंकी नियुक्ति, राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय भी इन्हीपर निर्भर करती है।

उत्पादित आय भिन्न भिन्न भनूप्यो अथवा वर्गोंमें विम प्रकार विभक्त होती है, यहभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आयका जो भाग उनको मिलता है, उसीपर उनका आर्थिक क्षेम निर्भर करता है। आजकल मुख्यतः आय द्रव्यके रूपमें होती है, जिसका उपार्जन उत्पात्तिके कार्यमें सहायता देनेमें होता है। यह द्रव्यमयी आय श्रमजीवियों को पारिश्रमिक और वेतनके रूपमें और पूजोपतियोंको व्याज, लगान और लाभके रूपमें प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि इस आयकी मात्रा उत्पात्तिके साधनों के प्रयोग और उनके मूल्यपर अवलम्बित होती है। श्रमजीवियोंकी आयका परिमाण इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी नियुक्ति कितने समयके लिए और कितने पारिश्रमिक पर होगी। उत्पात्तिके अन्य साधनोंके मूल्यका निर्धारण भी उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार माधारण वस्तुओंके मूल्यका।

राष्ट्रीय आय किम प्रकार समाजमें भिन्न भिन्न आर्थिक वर्गोंमें और किस अनुपात में विभाजित होती है, इसका प्रभाव कबल इन वर्गोंके क्षेमपर ही नहीं परन्तु सारो आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। अनुभवस यह ज्ञात हुआ है कि कम आयवाने अपनी आयका अधिकांश भाग उपभोगकी वस्तुएँ खरीदनेमें व्यय कर देने हैं और धनी वर्ग अपनी आयका एक बड़ा भाग बचा लेते हैं। इसी बचत ने उद्योग-धन्धों के लिए पूँजी बनती है। यदि यह बचत पूँजीके रूपमें प्रकट होती रहे और आर्थिक कार्यमें लगती रहे तो इससे आर्थिक साधनोंकी काम मिलता रहेगा और उत्पात्तिकी मात्रा और आयस्तरमें भी वृद्धि होती रहेगी। परन्तु बहुधा ऐसा होजाता है कि यह बचत पूँजीके रूपमें न सकर सचित रूपमें बेकार पड़ी रहजाती है क्योंकि इनको लगानेसे पूँजीपतियोंको लाभकी आशा नहीं होती। बचत और इसके उपयोगके व्यवधानमें आर्थिक कार्यमें शिथिलता और मन्दी आजाती है। कुछ लोगका विश्वास है कि सामाजिक आयमेंसे यदि कम आय वाले वर्गोंको अधिक भाग प्राप्त हो तो उनकी व्ययशीलतासे उपभोगके पदार्थोंकी माग बढ़गी, जिससे पूँजीकी उत्पादकतामें वृद्धिकी आशा बनी रहेगी, क्योंकि पूँजीवादी समाजमें आयका वितरण बहुत असमान होता है और अधिकांश बचतकी मात्रा एक छोटे वर्गके पास केन्द्रित रहती है अतएव वर्ग सम्बन्धी वितरणका इस प्रकरणमें बहुत महत्व

हो जाता है।

..

उत्पत्तिका चरम उद्देश्य उपभोग है। उत्पादक वस्तुओंका प्रयोजन भी उपभोग की वस्तुओंके निर्माणमें सहायता देना है। अतएव इनका मूल्य भी इनकी महायता से निर्मित उपभोगकी वस्तुओंके मूल्य पर निर्भर करता है। उत्पादकोंको उपभोक्ताओंके लिए वस्तुएं बनानी हैं। साधारणतः पूजीवादी व्यवस्थामें उपभोक्ताको कोई भी वस्तु किसी भी मात्रामें प्राप्त करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किस परिमाणमें जिन जिन वस्तुओंको प्राप्त करनेकी चेष्टा करेगा इसका निश्चय अवश्यही उसकी आयके परिमाण, उसकी आवश्यकताओंकी गतिमा और आवश्यकताओंको तृप्त करने वाली वस्तुओंके मूल्य पर निर्भर करेगा। यह जानी हुई बात है कि उत्पादक वर्ग विज्ञापन और अपने क्रय-पातुर्यसे अपनी वस्तुओंकी माग उत्पन्न करते हैं और उनके बेचनेमें समर्थ होते हैं। परन्तु अन्तर्गतवा वही उत्पादक अपने व्यवसायमें सफल होंगे जो अपने उद्योग-धंधोंका शीघ्रतासे उपभोक्ताओंकी मागमें होने वाले परिवर्तनोंके साथ सामंजस्य बनाये रख सकेंगे। इस प्रकरणमें एक गूढ़ विषयकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि किस प्रकार उत्पत्ति और उपभोगकी क्रियाएं एक साथ गुयी हुई हैं। उत्पत्ति की क्रियासे आयका सृजन होता है। इस आयका माधनोंके स्वामियामें विनिरण होता है। इसके फलस्वरूप भिन्न भिन्न वस्तुओंकी भिन्न भिन्न मात्रामें माग होती है और इसके आधार पर पुनः उत्पत्तिकी क्रिया निर्भर करती है।

आधुनिक कालमें कोईभी देश स्वावलम्बी नहीं रह सकता। भारतवर्ष बहुतसी वस्तुएं दूसरे देशोंसे मोल लगा है और अपनी वस्तुओंको दूसरे देशोंमें बेचता है। इनके प्रतिनिष्ठ एक देशकी पूजीभी दूसरे देशमें लगी होती है। इस प्रकारके अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धोंके कारण आयात-निर्यात, विदेशीविनिमय, लेनदेन का अत्यन्तुलन इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनका विवेचन और विश्लेषणभी अर्थशास्त्रके अन्तर्गत होता है।

प्रत्येक देशकी सरकारमें उसकी आर्थिक पद्धति का महत्वपूर्ण अंग होती है। अपनी कर-जोय-खुशनीति एवं आर्थिक विज्ञानों द्वारा वह उद्यत्तिकी मात्रा और उसमें स्वरूप, राष्ट्रीय आय और उसके विनिरणमें बहुत प्रभाव डाल सकती है। अतएव राजस्वनीति सम्बन्धी सभी कार्य अर्थशास्त्री के अध्ययनके विषय होजाते हैं।

आर्थिक विश्लेषण की रीतियाँ

हमने देखा कि अर्थशास्त्रके अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं। अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार इन समस्याओंका विश्लेषण करके उनके कार्यकारण सम्बन्ध की खोज की जाय और किस प्रकार उनके अन्तर्गत नियमोंका ज्ञान प्राप्त किया जाय। कुछ विज्ञान ऐसे हैं जिनके विषयोंका अध्ययन और विश्लेषण प्रयोग-शालाके अन्दर वातावरणको अनुकूल बनाकर अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों को नियन्त्रित करके किया जा सकता है। उदाहरणके लिये रसायनशास्त्र में विविध रसायनोंका अलग अलग सम्मिश्रण करके नियन्त्रित वातावरणमें उनका प्रभाव देखा जा सकता है। अर्थशास्त्रीकी समस्याएँ इस प्रकारकी हैं जिनका अध्ययन नियन्त्रित वातावरणमें किसी प्रयोगशालाके अन्दर नहीं हो सकता। यह भी सम्भव नहीं होता है कि अन्य व्यवधानोंको हटाकर किसी एक कारणके प्रभावका अध्ययन किया जा सके। उदाहरणके लिए यदि हम यह जानना चाहें कि चीनीके मूल्यमें वृद्धि होनेसे इसकी माँग और उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है तो यह सम्भव नहीं है कि हम उन सब अन्य कारणोंको हटा सकें जिनका चीनीकी माँग एवं उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है जिसमें केवल चीनीके मूल्यकी वृद्धिका प्रभाव अलगसे ज्ञात हो सके। यदि माँग घट गई, तो हम यह नहीं कह सकते कि यह कमी केवल मूल्यकी वृद्धिके कारण हुई है। माँगकी कमीके और भी कारण हो सकते हैं जिनका प्रभाव भी सम्भव है उसी समय पड़ रहा हो जबकि चीनीके मूल्यमें वृद्धि हुई है। उदाहरणके लिए, डाक्टरों ने चायमें कोई ऐसी बात दूध निकाली जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, जिसके कारण लोग धीरे धीरे चायका प्रयोग कम कर रहे हों। अतः चीनीकी माँग गिरने लगी हो। अब चूँकि दोनों कारण साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि माँगकी कमी पर किम कारणका कितना प्रभाव पड़ रहा है। यदि माँगकी कमीके दो ही कारण होने लगे भी हम चाय पीनेवालोंको अलग कर मूल्यकी वृद्धिका प्रभाव चाय न पीनेवाले मनुष्योंको माँगके परिवर्तनके आधार पर निश्चित करनेमें बहुत कठिनाईका अनुभव करते। परन्तु माँगको प्रभावित करनेवाले अन्य बहुतसे कारण हो सकते हैं जिनका प्रभाव हम नहीं रोक सकते। वास्तव में अर्थशास्त्र का विषयही ऐसा है जिसमें हम स्वाधीन मनुष्योंके

व्यवहार और कार्योंका अध्ययन करते हैं अतएव यह असम्भव है कि हम उनको प्रयोगशालामें नियन्त्रित कर उनपर कार्यकारण सम्बन्धी प्रयोग करें। यही कारण है कि अर्थशास्त्रीकी प्रयोगशाला कोई कमरा नहीं बल्कि सारा जगत् है।

आर्थिक विश्लेषण की एक रीति, जो ऐतिहासिक रीति कही जाती है, यह है कि हम पूर्वघटित आर्थिक घटनाओंके आधार पर उन आर्थिक नियमोंको खोज निकालें जिनसे ये घटनाएँ समझाई जा सकें। आर्थिक घटनाएँ नित्य हो घटती रहती हैं। यदि हम किसी विशेष प्रकार के घटनासम्बन्धी नियम जानना चाहें तो भिन्न भिन्न समयोंमें घटित उस प्रकारकी घटनाके क्रम का अध्ययन तथा विश्लेषण करके उसमें कार्यकारण सम्बन्धके खोजनेका प्रयत्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि अनेक बार हमको दिखायी दे कि जब जब भी चीनीके मूल्यमें वृद्धि हुई है तभी चीनीकी मागमें कमी पायी गयी है, तो इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि मूल्य की वृद्धि कारण मागमें कमी हुई है और उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि भविष्यमें भी मूल्यमें वृद्धि होगी तो मागमें कमी आ जायेगी। पूर्वघटित घटनाओं का विवरण आकड़ोंके रूपमें इकट्ठा किया जाता है। अनेक आर्थिक घटनाएँ आकड़ोंमें मापी जा सकती हैं जैसे मूल्य, उत्पाति, भाग, कर, व्याज की दर, बेकारी इत्यादि। यदि घटनाओंसे सलग्न आकड़े ऐतिहासिक क्रम से इकट्ठा किये जायें और इनमें असम्बद्ध घटनाओंको छोड़कर सम्बद्ध घटनाओंके आधार पर पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात किया जाय तो इनका सभान धर्म निर्धारित किया जा सकता है। इस रीति का प्रयोग अस्त नहीं है और इसके आधारपर प्राप्त नियमोंकी अवश्यम्भाविता भी सन्देहजनक है। कोई भी ऐतिहासिक घटना तत्कालीन परिस्थितियोंमें सलग्न रहती है। कोई भी घटना भिन्न भिन्न कालोंमें एक ही परिस्थितिमें नहीं बल्कि भिन्न भिन्न परिस्थितियोंमें घटित होती है। अतएव उसके सम्बन्धमें जो सामान्य धर्म हम स्थापित करते हैं वह पूर्णरूप से लागू नहीं होगा क्योंकि सलग्न परिस्थितियाँ एक ही प्रकारकी नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त दो घटनाएँ एकके पीछे एक घट रही हैं इससे हम यह तात्पर्य नहीं निकाल सकते कि वे कार्यकारणसे अवश्यही सम्बन्धित हों। वे पूर्णतः स्वतन्त्र हो सकती हैं अथवा ऐसा भी हो सकता है कि वे दोनों घटनाएँ किसी तीसरी घटनासे प्रभावित हो रही हों।

एक और रीति का भी प्रयोग किया जाता है जिसको आनुमानिक रीति कहने हैं। यह सर्वविदित है कि वास्तविक आर्थिक घटनाएँ बहुत गहन, पेचीली और उलझी होती हैं जिससे उनका पूर्ण रूपसे विदलपण करना बहुत ही कठिन कार्य है। अतएव विदलपणके लिए अर्थशास्त्री आर्थिक परिस्थितिको काल्पनिक रूपसे सरल बनानेकी चेष्टा करता है। इस कल्पित आर्थिक व्यवस्थामें वह कुछ बातोंको स्वयमिद मान लेता है। उदाहरणके लिए मनुष्य आर्थिक कार्योंको अपने लाभके उद्देश्यसे करना है, आर्थिक व्यवहारोंमें पूर्ण स्पर्धा पायी जाती है इत्यादि। इन अनुमानोंके आधार पर वह तर्क द्वारा नये नये परिणाम निकालता है। अब ये नये परिणाम वास्तविक जगत्में कहा तक लागू होंगे, यह इस बात पर निर्भर है कि उसकी कल्पनाएँ वास्तविक स्थितिसे कितनी भिन्न हैं। यदि वास्तविक स्थितियोंमें कल्पित स्थितियोंसे अधिक विभिन्नता न हो तो हम कह सकते हैं कि जो परिणाम काल्पनिक स्थितियोंके आधार पर प्राप्त किये गये हैं, वे वास्तविक जगत् में भी ठीक उतरेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो वास्तविक जगत् में ये परिणाम पूर्णरूप से लागू नहीं होंगे। उदाहरणके लिए, यदि पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाके आधार पर हम इस परिणाम पर पहुँचें कि अमृक-वस्तु का अमृक मूल्य होगा और यदि वास्तविक समारमें अपूर्ण प्रतिस्पर्द्धा हो तो हमारा परिणाम ठीक नहीं उतरगा। यह नहीं समझना चाहिए कि वास्तविक जीवन इन कल्पित अवस्थाग्रामें भिन्न है अतएव इस आनुमानिक रीति का कोई महत्व नहीं है। एक मिश्रित और पेचीली स्थिति का विदलपण करनेके लिए इस रीति का प्रयोग बहुधा सुविधाजनक होता है। एक सरल आर्थिक प्रतिरूप कल्पितकर उसके आधारपर कुछ परिणाम निकाले जाते हैं और श्रमणः इस कल्पित प्रतिरूपमें वास्तविकता का समावेश करके उनमें संशोधन किया जा सकता है। यह भी नहीं समझना चाहिए कि जिन अर्थशास्त्रियों ने इस विधिका प्रयोग किया है वे वास्तविकतामें अनभिज्ञ थे। हा, इस बातको पूर्णरूप से ध्यानमें रखना चाहिए कि आनुमानिक आधार पर जो कारण-कारण शृंखला का प्रतिपादन किया जाता है उसकी वास्तविकता और यथार्थता तभी प्रमाणित हो सकती है, जब कि वे कल्पनाएँ वास्तविकतामें अधिक दूर न हों।

व्यवहारमें अर्थशास्त्रीको अपने विषयको समझनेमें और उसके विदलपणमें इन सभी रीतियोंकी आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रीति का महत्व इसलिए है कि

इसके प्रयोगमें हम वास्तविकताके साथ चलते हैं और उसके आधार पर ही सामान्य धर्म जाननेकी चप्टा करते हैं। परन्तु आर्थिक विषयोकी सम्भीरता और जटिलता के कारण प्रत्येक अवस्थामें इस रीतिका प्रयोग सम्भव नहीं होता। अतएव हमको आनुमानिक रीतिका आश्रय लेना पड़ता है। इस रीतिके आधार पर जो परिणाम प्राप्त किये जातेहैं उनकी यथार्थताकी परीक्षाके लिए हमको उन्हें वास्तविकता की कसौटी पर कसना पड़ता है।

आर्थिक क्षेत्र

जब मनुष्य किसी विषयका अध्ययन एवं विस्लेषण करता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। एक उद्देश्य तो उस विषयका ज्ञान प्राप्त करना, उसके विविध अंगों-प्रत्यंगोंका अध्ययन करके उनके कार्य-कारण पर प्रकाश डालना और तत्सम्बन्धी सामान्य धर्म खोज निकालना है। इस ज्ञानकी प्राप्तिके लिए उसे अनेक प्रकारकी वैज्ञानिक रीतियों और प्रयोगोंको काममें लाना पड़ता है। परन्तु हमारा उद्देश्य केवल ज्ञानप्राप्ति ही नहीं होसकता। इस जगत्में केवल ज्ञानही से हमारा काम नहीं चलता। हमको कर्म करने पड़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करनेकी मनोमूर्ति, अवकाश तथा साधन केवल कुछही लोगोंको उपलब्ध होने हैं परन्तु कर्म सभीको करने पड़ते हैं क्योंकि बिना कर्म किये हम अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं कर सकने। योंतो थोडा बहुत प्रत्येक मनुष्य अपने कार्योंके विषयमें जानना ही है, परन्तु प्रत्येक मनुष्यको उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अतएव ऐसे लोगोंके कार्य उतनी उत्तमतासे नहीं होसकते जितनी कि तत्सम्बन्धी ज्ञान प्राप्तिसे होसकने हैं। यदि हमें किसी विषयका ज्ञान होजाये तो उस विषय सम्बन्धी कार्योंको हम अधिक सुगमता से और अच्छे ढंगसे करसकने हैं। अतएव प्राप्त ज्ञानका व्यवहारमें प्रयोग होना चाहिए। उदाहरणके लिए, यदि मनुष्यको शरीरके अवयवों, उनके कार्यों और सम्बन्धोंका ज्ञान प्राप्त हो तो व्यवहारमें उस ज्ञानसे शारीरिक व्याधियोंको दूर अथवा कम करनेमें उसको सुविधा होगी।

आर्थिक क्षेत्रमें जो कार्य किये जाते हैं उनका उद्देश्य अन्ततोगत्वा आवश्यकताओं की पूर्ति कर आर्थिक क्षेत्रको बढाना है अतएव इस क्षेत्रके अध्ययन और विस्लेषण

से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उससे आर्थिक क्षेमकी वृद्धिमें सहायता मिलने की भावना होना स्वाभाविक है। जिन विज्ञानोंका सीधा सम्बन्ध मानव समाज से है और विशेषकर जो मनुष्यकी आर्थिक आवश्यकताओंसे सम्बन्धित हैं उनको तो अर्थ-शास्त्रके कार्यक्षेत्रमें बहुत महत्व प्राप्त है। अतएव अर्थशास्त्रीको अपने ज्ञानके प्रकाशमें आर्थिक क्षेमकी वृद्धिके लिए सरकारको, अन्य संस्थाओंको और व्यक्तियों को उचित आर्थिक नीतिका अवलम्बन करनेमें सहायता देनी चाहिए।

अर्थशास्त्र और विज्ञान

कभी कभी यह प्रश्न किया जाता है कि अर्थशास्त्रको विज्ञान कहना चाहिए अथवा नहीं। वास्तवमें यह प्रश्न ठीक नहीं है। जब हम आर्थिक परिस्थितियों, कार्यों और सम्बन्धोंका वैज्ञानिक रीतियोंसे अध्ययन और विश्लेषण करते हैं और उनके आधारपर कार्य-कारणके सम्बन्धोंका ज्ञान करते हैं और तत्सम्बन्धी नियमोंका प्रतिपादन करते हैं तो निश्चय ही हम इस विद्याको विज्ञान द्वारा सम्बोधित करेंगे। हो सकता है कि हमारा विज्ञान अनेक कठिनाइयोंके कारण अभीतक उच्च स्तर तक न पहुँच सका हो। परन्तु हमारा लक्ष्य और ध्येय यही है। अर्थशास्त्रको इससे भी कोई भयोजन नहीं कि हमारी आवश्यकताएँ अच्छी हैं अथवा बुरी और हमारा लक्ष्य वाछनीय है अथवा अवाछनीय। अर्थशास्त्री तो वास्तवमें जो आर्थिक कार्य हो रहे हैं और जो आर्थिक सम्बन्ध पाये जाते हैं उनका ही अध्ययन और विश्लेषण करता है और उनके विषयमें ही सामान्य धर्म का प्रतिपादन करता है। मनुष्यको मदिरापान करना चाहिए अथवा नहीं, उसको अधिक द्रव्य भोजनमें व्यय करना चाहिए अथवा सिनेमामें, इनका उत्तर अर्थशास्त्रकी परिधिसे बाहर है। इसका उत्तर सम्भवतः नीति शास्त्र देसके। अर्थशास्त्री देखता है कि लोग मदिरा पीते हैं, उनके लिए मूल्य देनेको तत्पर हैं अतएव उत्पादकोंको मदिरा उत्पादन करनेमें लाभ की आशा होती है और उत्पत्तिके कुछ साधन मदिरा बनानेके काममें आते हैं जिसके फलस्वरूप यह साधन अन्य आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके लिए प्राप्त नहीं होते। इस प्रकारकी परिस्थितियोंका अर्थशास्त्री अध्ययन करता है।

अर्थशास्त्र विज्ञान तो अवश्य है, परन्तु अन्य विज्ञानोंकी अपेक्षा इसका सम्बन्ध

कार्यक्षेत्रसे अधिक है। ऐसा होना अवश्यम्भावी है, क्योंकि इसका विषय ही इस प्रकार का है। अर्थशास्त्रके विषयको अच्छी तरह समझकर और उसका मनन कर जो क्रियाएँ की जायेंगी उनसे आर्थिक क्षेत्रमें वृद्धि होनेकी सम्भावना है। यही कारण है कि इंग्लैंडके विद्वान अर्थशास्त्री प्रोफेसर पीगू ने कहा है कि अर्थशास्त्री इस प्रकारके विज्ञानकी वृद्धिची चेष्टा करेगा जो कि क्रियाका आधार बन सके।

अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध

इस अध्यायके प्रारम्भमें ही लिखा जा चुका है कि भिन्न भिन्न विषयोंके अध्ययनके फलस्वरूप भिन्न भिन्न शास्त्रोंकी सृष्टि हुई है। परन्तु वास्तवमें इन सभी विषयों और तत्सम्बन्धी शास्त्रोंमें पृथक्ता नहीं है। सभी विषय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमें, कम या अधिक मात्रामें एक दूसरेसे सम्बन्धित हैं। अर्थशास्त्रका सम्बन्ध मनुष्यों के एक विशेष प्रकारके व्यवहार एवं आचरणसे है परन्तु इस व्यवहार एवं आचरणके लिए मनुष्य अपनेको अन्य परिस्थितियोंसे अलग नहीं कर सकता। इन प्रकरणमें अर्थशास्त्रसे केवल उन्हीं शास्त्रोंके सम्बन्धकी विवेचना, मक्षेपमें की जायेगी जो उसके अधिक निकट हैं।

अर्थशास्त्रका समाजशास्त्रसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्रका एक भाग है क्योंकि दोनोंके विषय और क्षेत्र अलग अलग हैं। परन्तु चूंकि आर्थिक कार्य एवं सम्बन्ध सामाजिक पद्धति, वर्गीकरण, संस्थाओं, विचारों और व्यवहारोंमें प्रभाविन होते हैं अतएव अर्थशास्त्रीको समाज सम्बन्धी विषयोंकी जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार मानव शास्त्र में भी अर्थशास्त्र सम्बन्धित है। भिन्न भिन्न युगोंमें भिन्न भिन्न प्रकारकी संस्कृतियोंमें मनुष्यका अध्ययन मानवशास्त्र का विषय है। इस विषयके अध्ययनसे अर्थशास्त्रीको प्राचीन, आर्थिक संस्थाओं और सम्बन्धोंको समझनेमें सहायता मिल सकती है। राजस्वशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्रको जोड़ता है। राज्यका विधान किस प्रकार का है, आर्थिक क्षेत्रमें राज्यकी क्या नीति है और राज्य किस प्रकार आर्थिक कार्योंका नियन्त्रण करता है, राज्यकी कर-व्यय-ऋणनीति क्या है, इनका आर्थिक स्थिति और क्रियाओंपर गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक क्षेत्रसे नीति शास्त्रकी विशेष

सम्बन्ध है। माना कि अर्थशास्त्रीको, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस विषयसे विशेष प्रयोजन नहीं होता है फिर भी अनेक आर्थिक नीतियाँ और विधान नीतिशास्त्रकी उक्तियों पर ही आधारित रहती हैं। उदाहरणके लिये प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक न्यूनतम जीवनस्तरको सुरक्षित करना, मन्तोंपजनक पारिश्रमिक देना, सामाजिक शांति करना, सम्पत्तिके बिनरणमें असमानता कम करना, इस प्रकारके सभी कार्य अधिकतर नीतिशास्त्रसे सम्बन्धित हैं। मनो-विज्ञानसे भी अर्थशास्त्रका सम्बन्ध है। उपयोगिताकी प्राप्ति, लाभकी आशा, निराशा, उपयोग और बचत करनेकी प्रवृत्ति इस प्रकारकी मनोवृत्तियोंका आर्थिक कार्यों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

अर्थशास्त्र के नियम

प्रायः कहा जाता है कि अर्थशास्त्रके नियम प्राकृतिक विज्ञानोंमें प्रमाणित नियमोंके समान अनिवार्य नहीं होते हैं अर्थात् अर्थशास्त्रके नियमोंमें हमको इस प्रकारकी आशा नहीं करनी चाहिए कि वे सभी काममें और सभी परिस्थितियोंमें चरितार्थ होंगे। परन्तु यदि हम इस विषयके मूलमें जायें तो पता चलता है कि इन प्रकारका आक्षेप ठीक नहीं है। अर्थशास्त्रके नियम अन्य विज्ञानोंके नियमोंके समान ही हैं। किसी भी नियममें यही बोध होता है कि किसी दीर्घदी परिस्थितियोंमें किम परिणामकी आशा करनी चाहिए। यदि यह आशा पूरी नहीं होसकी है तो अवश्यमेव परिस्थितिमें बदलाव होगा। उदाहरणके लिए बाजारका एक नियम है कि यदि किसी वस्तुके परिमाणमें वृद्धि होजाये तो उसका मूल्य गिरने लगेगा। अब यदि वस्तुके परिमाणमें वृद्धि होगई और फिर भी मूल्य नहीं गिरा तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि नियम अनुद्ध है। यह नियम चरितार्थ इसलिए नहीं हो रहा होगा कि सम्भव है परिस्थितियोंमें अन्तर पड़ गया हो। होसकता है मागभी उन्हीं अनुपातमें बढ़ गयी हो जिस अनुपातमें बाजारमें पूर्ति बढ़ी है। अथवा बड़े हुए परिमाणको बाजारमें न रखकर उत्पादक अथवा व्यापारी संग्रह कर रहे हो।

अर्थशास्त्रके और प्राकृतिक नियमोंके भेद करनेका प्रधान कारण होसकता है यह रहा हो कि प्राकृतिक विज्ञान सम्बन्धी नियमोंकी प्रयोगशालाओं में परीक्षा की

जाम सकती है, जहाँ परिस्थितियाँ नियन्त्रित की जा सकती हैं। जैसा कि पहिले बताया जा चुका है कि अर्थशास्त्री की प्रयोगशाला किसी कमरे के भीतर सीमित नहीं की जा सकती और न आर्थिक परिस्थितियाँ ही इच्छानुकूल बनायी जा सकती हैं। अतएव आर्थिक नियमोंकी परीक्षा करनेके लिए हमको सदैव इस प्रकारकी शुद्ध परिस्थितियाँ प्राप्त नहीं होती हैं जिनमें वह नियम पूर्णरूप से चरितार्थ हो सके। यही कारण है कि आर्थिक नियमोंके प्रतिपादनमें प्रायः जब अन्य बातें मयावत् रहें, यह वाक्य जोड़ दिया जाता है।

आवश्यकताएं

उपभोग का महत्व

हम चारों ओर मनुष्यको अनेक प्रकारके वार्योंमें व्यस्त पाते हैं। कोई खेतमें, कोई कारखानेमें, कोई व्यापारमें, कोई दफ्तरमें और कोई किसी अन्य व्यवसायमें लगा दिलायी देता है। इसका प्रधान कारण यह है कि साधारणतः मनुष्य इसी प्रकारके वार्योंसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करसकता है। आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए विविध प्रकारकी वस्तुओं और सेवाओंका उपभोग करना पड़ता है। उपभोग शब्दका सम्बन्ध उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्तिसे है। कुछ वस्तुएं ऐसीहैं जिनका अस्तित्व एकही बारके उपभोगसे, कमसे कम बाह्य रूपमें तो समाप्त होजाता है—रोटी, फल, कोयला इस प्रकारके उदाहरण हैं; और कुछ वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। इनका अस्तित्व एव उपयोगिता दीर्घकाल तक बनी रहती है। कपड़ा, फर्निचर, रेडियो इसके उदाहरण हैं। वस्तुओंके उपभोगमें हम वस्तुओंकी उपयोगिता प्राप्त करते हैं। यदि किसी वस्तुकी उपयोगिता उपभोक्ताकी आवश्यकताकी पूर्तिके बिना नष्ट होजाये तो उसको उपभोग नहीं कहा जायेगा। ऐसी स्थितिमें हम कहेंगे कि वह वस्तु नष्ट होगयी। उदाहरणके लिए बाढ़, भूचाल, आधी, अग्नि आदि प्रकोपोंमें जो विनाश होताहै उसको उपभोग नहीं कहा जाता। उपभोगमें किसी आवश्यकताकी पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। आवश्यकता अच्छी है अथवा बुरी, इसका प्रश्न नहीं है। कंसीभी आवश्यकताहो, यदि किसी वस्तु अथवा सेवा द्वारा उसकी पूर्ति होजाये तो ऐसी स्थितिमें उपभोग शब्द प्रयोग किया जाता है।

आवश्यकताएं और उनकी विशेषताएं

हम देखते हैं कि मनुष्यको अनेक प्रकारकी वस्तुओं एव सेवाओंकी आवश्यकता

ही है। जन्ममे मरण पर्यन्त इन आवश्यकताओंमे छुटकारा नहीं मिलता। चाहे मनुष्य वनमानुषकी अवस्थामें हो अथवा आधुनिक सभ्यताके नये युगमें, आवश्यकताएं उसको घेरे रहती हैं। हायह अवश्यहै कि सभी मनुष्योंकी सभी अवस्थाओंमें एकही प्रकारकी आवश्यकताएं नहीं होती। जब मनुष्य पशुवत् जीवन व्यतीत करता था तो उसकी आवश्यकताएं केवल उदर-पूर्ति तकही सीमित थी। ज्यों ज्यों वह सभ्यताकी ओर अग्रसर होता गया, उसकी आवश्यकताओं की संख्यामें वृद्धि होती गयी। कहा जाताहै कि सभ्यताका विकास और आवश्यकताओं की वृद्धि साथ साथ चली आयी है। आधुनिक कालमें तो आवश्यकताओं का कोई अन्त ही नहीं दिखायी पड़ता। भाधारणतः मनुष्य अपनेको इनक बोझमे दबा हुआ पाता है। प्रारम्भिक आवश्यकताओं के अनिश्चित, जिनकी पूर्ति जीवन-रक्षाके लिए अनिवार्य है, जैसे भ्रष्ट, वस्त्र, मकान, आधुनिक कालमें सांस्कृतिक और भोगविलास सम्बन्धी आवश्यकताओं की बहुत वृद्धि हुई है। इन्हीं बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए आर्थिक साधनों, कार्यों और सम्बन्धोंकी भी वृद्धि हुई है।

आवश्यकताओंमें अनेक प्रकारकी विभेदताएं दिखायी देती हैं।

(१) आवश्यकताओं की मात्रा अपरिमित है। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसकी सभी आवश्यकताओंकी पूर्ति होगयी हो। धनी मे धनी मनुष्यको भी यही प्रतीत होताहै कि यदि उसक पास और अधिक धन होता, तो वह और अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता अथवा इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति विविध प्रकारसे कर पाता। आवश्यकताएं सदैव प्रत्यक्ष नहीं रहती हैं। जैसेही किसी प्रबल आवश्यकताकी पूर्ति हुई, दूसरी आवश्यकता उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार मनुष्यके आर्थिक और आय स्तरमें वृद्धि होनेके कारणभी अनेक प्रकारकी आवश्यकताएं उत्पन्न होजाती हैं। एक साधारण आवश्यकताकी पूर्तिके लियेही अनेक वस्तुओंकी आवश्यकता होतीहै। उदाहरणके लिए उदर-पूर्ति का काम रखे सूप भोजनसेभी चल सकता है, परन्तु मनुष्यकी तृप्ति इस प्रकारके भोजनमे नहीं होती। वह बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन चाहताहै साथही समय समयपर उसमें परिवर्तनभी चाहता है। इसी प्रकार सर्दी-गर्मीसे शरीरकी रक्षाके लिए उसे धस्त्राकी आवश्यकता होती है। काम तो साधारण वस्त्रोंमे भी चल

जाता है, परन्तु मनुष्यका इससे मन्तोष बढ़ा होता है। उसको तो बढ़िया और विविध प्रकारके वस्त्र चाहिए, घूमनके लिए अन्न, सोनेके लिए अन्न, खानके और सज्जनके लिए अन्न। इसी विविधता और चिन्तासिन्तासे समावेशसे एक सरल सी आवश्यकताभी दुर्लभ बन जाती है।

पाश्चात्य देशोंकी विचार-धाराके अनुसार इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप ही सभ्यताकी वृद्धि हुई है। यदि मनुष्य सन्तोषी होकर हाथपर हाथ रखकर बैठ जाता तो सुख, आराम और विलासकी अनेक सामग्रियाँ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, कहाँसे उपलब्ध होतीं। यह बात हमको भी मान्य है कि मनुष्यके शारीरिक एवं मानसिक सुख-सन्तोषके लिए विविध प्रकारकी वस्तुओंकी आवश्यकता होती है। अपनी वर्तमान अवस्थासे असन्तोषके कारण ही वह उद्यम एवं उद्योग करनेको प्रेरित होता है जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकारके आविष्कार होत हैं, जिससे मनुष्यकी आर्थिक अवस्थामें विकास होता है। यदि सन्तोषावस्था मनुष्यको आलसी और निष्क्रिय बनाने लगे तो इस प्रकारका सन्तोष उसके और समाजके लिए हितकर न होगा। वह असन्तोष जो मनुष्यको प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्यकारी समझा जाना चाहिए।

(२) हमने बताया कि कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी एक आवश्यकता की पूर्णरूप से पूर्ति नहीं कर सकता। आवश्यकताओं की एक विविधता यह है कि किसी विशेष समय में किसी विशेष वस्तुकी आवश्यकता की पूर्णरूप से पूर्ति की जा सकती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आवश्यकताओं की पूर्तिके साधन हमारे पास बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उस आवश्यकताकी तीव्रता घटती जाती है और अन्तमें ऐसा समय आजाता है कि वह आवश्यकता उस समय बिल्कुल शान्त हो जाती है। इसका उदाहरण हम भोजनकी आवश्यकतासे देखते हैं। भूखकी सीमा होती है जैसे जैसे भोजनकी सामग्री हमें अधिक मात्रामें प्राप्त होती जाती है, वैसे वैसे भूख मिटती जाती है। जब पेट भर जाता है तो भोजनकी आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार परिमाणके साथ प्रत्येक आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और पर्याप्त मात्रामें उस वस्तुकी प्राप्ति होत पर उसकी आवश्यकताकी पूर्णरूप से पूर्ति हो जाती है। अर्थशास्त्र का एक मुख्य सिद्धान्त जिसे 'वृत्तान्त-उपयोगिता-ह्रासनिष्ठ' कहते हैं, आवश्यकताओं

की इसी विशेषता पर आधारित है। इन नियमका विवेचन आगे चल कर किया जायेगा।

(३) आवश्यकताओंकी आपसमें प्रतिस्पर्धा रहती है। इसका प्रधान कारण यह है कि मनुष्यके पास एकमात्र सभी आवश्यकताओं की पूर्तिके साधन नहीं होते। इसलिए उसको निर्णय करना पड़ना है कि किस आवश्यकता की पूर्ति किस अंश तक की जाये। इसका उदाहरण हमको अपने निम्नके व्यवहारमें मिलता है। यदि किसी विद्यार्थीको एक पुस्तक और एक कोट की आवश्यकता है और उसके पास एकही वस्तुको खरीदनेके लिए धन है तो इन दो आवश्यकताओं में होड़ होगी और विद्यार्थीको इनमेंसे एकको चुनना पड़ेगा यदि वह कोट खरीदता है, तो उसे किताब से वंचित रहना पड़ेगा।

(४) आवश्यकताएँ विकल्पित भी होती हैं अर्थात् किसी आवश्यकताकी पूर्ति अनेक वस्तुआसे होसकती है। ये वस्तुएँ एक दूसरेकी स्थानापन्न होसकती हैं। उदाहरणार्थ भूख-निवारणके लिये गेहूँ, जौ चना अथवा बाजरेकी रोटी खायी जासकती है। कुछ अंशमें एक अन्न-दूसरे अन्नका स्थानापन्न होसकता है। यदि गेहूँका मूल्य बढ़जाय तो लौंग जौ, चना इत्यादि अन्नोको काममें लाने लग जायेंगे। यदि एक आवश्यकता दो वस्तुओंमें से किसी एकसे सन्तुष्ट की जासकती है तो लोग उस वस्तुको खरीदेंगे, जिसका मूल्य कम होगा। इस प्रकारकी वस्तुओंमें बहुत अधिक मात्रामें प्रतिस्पर्धा होती है। उत्पादनके कार्यमें भी कई साधन ऐसे होते हैं जो एक दूसरेके स्थानापन्न होसकते हैं। उत्पादन का प्रायः यह विचार करना पड़ता है कि वह मजदूरों की सरायोंमें वृद्धि करे अथवा मशीनों की। इस प्रवृत्तिके आधार पर प्रतिस्थापन सिद्धान्त बना है। हम आगे चलकर देखेंगे कि इस सिद्धान्त का प्रयोग अर्थशास्त्रके सभी भागोंमें होता है।

(५) आवश्यकताएँ एक दूसरेकी पूरक भी होती हैं। किसी एक आवश्यकताकी पूर्तिके लिये अनेक वस्तुओंकी एकसाथ आवश्यकता होती है, जैसे टैनिस् खेलनेके लिये बस्ता, गेंद, जाल और परदों की एकसाथ आवश्यकता होती है। इन सबके सहयोगमें ही टैनिस् खेलनेकी आवश्यकता की पूर्ति होसकती है। इस प्रकार विशेष रूपसे सम्बंधित वस्तुओंमें से किसी एकके मूल्यमें परिवर्तन होनेसे तत्सम्बन्धी वस्तुओंकी मांग में एवं उनके मूल्यमें भी परिवर्तनकी सम्भावना रहती है।

(६) किसी मनुष्य अथवा परिवारकी विविध आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए जा वस्तुएँ निम्न व्यवहारमें लाई जाती हैं, उन सबसे मिलकर उस मनुष्य अथवा कुटुम्बका जीवन-स्तर निर्धारित होता है। इन वस्तुओंके उपभोगका स्वभाव पड़ जाता है, जिसमें बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इसी प्रकार अनेक वस्तुओंका प्रयोग लोकाचारमें होता है। इनमेंभी परिवर्तन धीरे धीरे होता है। हम प्रवृत्तिसे वस्तुओंके उपभोग और उनकी मागमें कुछ अश्वत्थ की स्थिरता आजाती है, जिससे उत्पादन कार्यमें भी उमी सीमा तक स्थिरता आजाती है।

उपयोगिता

जब हम यह कहते हैं कि हमारी अमुक आवश्यकता है तो उससे किसी वस्तुका अभाव सूचित होता है। यदि वह वस्तु पर्याप्त मात्रामें प्राप्त होजाती है तो अभाव दूर होजाता है और हम कहते हैं कि इस आवश्यकता की पूर्ति होगयी। वस्तुओं और सेवाओंके उपभोगसे हमको जो तृप्ति होती है उसको मापनेके लिये उपयोगिता शब्दका प्रयोग किया जाता है। तृप्ति एक मानासिक अवस्था है जिसका विश्लेषण बहुतही कठिन कार्य है। किसी एकही मनुष्यको भिन्न भिन्न परिस्थितियोंमें एकही वस्तुसे भिन्न भिन्न मात्रामें तृप्ति मिलती है, जिनकी माप करना एवं उनकी तुलना करना सुगम नहीं होता। अन्य मनुष्योंको किसी वस्तु अथवा सेवासे किस मात्रामें तृप्ति मिलनी है, इसका ज्ञान होना तो अत्यन्त दुष्कर है। फिरभी इस कार्यके लिये किसी प्रकारका बाह्य मापदण्ड काममें लाना अनिवार्य होजाता है।

किसी मनुष्यको एक वस्तुके उपभोगसे कितनी मात्रामें तृप्ति प्राप्त होती है इसका निरपेक्ष स्पष्ट नहीं अनुमान नहीं होसकता किन्तु विविध वस्तुओंके उपभोगसे उसको जो अपेक्ष तृप्ति मिलनेकी सम्भावना रहती है उसका अनुमान किया जासकता है। यदि दो वस्तुओंका मूल्य समान हो और कोई व्यक्ति उन दोनोंमें से एकको खरीदता है तो इसमें प्रष्ट होता है कि वह दूसरी वस्तुकी अपेक्षा उस वस्तुके उपभोग से अधिक मात्रामें तृप्तिकी आशा करता है। किसी वस्तुको प्राप्त करनेके लिए मूल्य देना पड़ता है। उस मूल्यसे अन्य वस्तुएँ भी प्राप्त होसकती हैं। जब कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है तो वह उससे प्राप्त होनेवाली तृप्तिकी तुलना उन

वस्तुओंमें प्राप्त होनेवाली तृप्तिये करता है जो उसने नहीं खरीदी। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तुको प्राप्त करनेके लिये मनुष्य जो द्रव्य देता है, उसमें वस्तुसे प्राप्त होनेवाली उपयोगिताका बोध होना है। यदि वह यह निश्चय नहीं कर पा रहा कि वह उस वस्तुको ले अथवा द्रव्यको अपने पास रखे तो इसमें बोध होता है कि किसी दूसरी वस्तुसे अपेक्षित तृप्ति पहली वस्तुकी अपेक्षित तृप्तिके समकक्ष है।

किसी दी हुई परिस्थितिमें किसी वस्तुके उपभोग से जो तृप्ति मिलती है उसको उपयोगिता कहते हैं। इस उपयोगिताकी माप तो नहीं हो सकती परन्तु किसी व्यक्ति विशेषकी उस परिस्थितिमें उस वस्तुमें अपेक्षित उपयोगिताकी अन्य वस्तु अथवा द्रव्यमें अपेक्षित उपयोगितासे हम तुलना कर सकते हैं। यदि किन्हीं दो वस्तुओंके लिए मनुष्य समान द्रव्य देनेको तैयार हो तो हम यह कह सकते हैं कि वह उन दोनोंमें समान उपयोगिताकी आशा करता है। अतएव साधारणतया कहा जा सकता है कि दो वस्तुओंकी अपेक्षित उपयोगिताएँ उभी अनुपातमें हैं जिस अनुपातमें उनको प्राप्त करनेके लिए द्रव्य दिया जाता है। इस प्रकरणमें हम यह बताना चाहते हैं कि द्रव्यमें उपयोगिताकी माप और तुलना करनेमें सुविधा होती है। द्रव्य-विहीन आर्थिक गणितोंमें भी इस प्रकारका तुलनात्मक कार्य किया जा सकता है जबकि एक वस्तुसे अपेक्षित उपयोगिताकी तुलना सीधे दूसरी वस्तुमें अपेक्षित उपयोगितासे की जाती है।

क्रमगत-उपयोगिता-ह्रास नियम

आवश्यकताओं और उनकी विशेषताओंकी चर्चा करते हुए हमने बताया था कि प्रत्येक आवश्यकता सीमित होती है अर्थात् उसका निवारण हो सकता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उस आवश्यकताकी पूर्ति करनेके साधनोंका सग्रह अथवा उपभोग होता जाता है, वैसे वैसे उस आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और एक समय आ जाता है जब उसका लोप हो जाता है। इसी बातको हम दूसरे प्रकारमें भी कह सकते हैं। किसी समय अथवा परिस्थितिमें यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेषका लगातार उपभोग अथवा संचय करता है तो उस वस्तु की क्रमागत इकाइयोंमें प्राप्त उपयोगिता घटने लगती है क्योंकि उस वस्तु की आव-

क्षय्यताकी तीव्रता घटने लगती है। अतएव तृप्तिही मात्राभी कम होने लगती है। जब वह वस्तु इतनी मात्रामें संचित होजाती है अथवा उपभोग की जाती है कि आवश्यकता बिल्कुल शान्त होजाती है तो ऐसी अवस्थामें तृप्तिके कुल परिमाणमें वृद्धि नहीं होती और हम कह सकतेहैं कि उपयोगिता शून्य होगई है। अब यदि इस सीमाके आगेभी उपभोग किया जाय तो कुल उपयोगितामें हानि होनेकी सम्भावना रहतीहै अर्थात् उपयोगिता प्रतिलूल होने लगती है। उपयोगिताको इस प्रकारकी प्रवृत्तिके आधार पर एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बनाहै, जिसको 'क्रमगत-उपयोगिता-ह्रास नियम' कहते हैं। इस नियमको व्याख्या इस प्रकारसे कीजाती है, जैसे जैसे किसी वानावधि में किसी वस्तुका मग्नह कमशः बडता जाताहै, वैसे वैसे क्रमागत प्राप्त उपयोगिताका ह्रास होने लगता है। अर्थात् वस्तुकी किसी इकाई से प्राप्त उपयोगिता उससे पहिलेकी इकाईकी उपयोगितासे कम रहती है। इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि वस्तुकी इकाइयोंमें असमान उपयोगिता निहित है। सभी इकाइयोंका स्वरूप उत्यादि विवेचनाए समानहं परन्तु जैसे जैसे एक मनुष्य उम वस्तुकी इकाइयोंका क्रमशः उपभोग अथवा संचय करता जाताहै, वैसे वैसे उसको प्राप्त क्रमागत उपयोगिताका ह्रास होने लगता है। उदाहरणके लिए कोई मनुष्य केले खरीदता है जोकि सब बातोंमें समान है। तुलनाके निमित्त मान लीजिये कि पहिल केलेसे उमका १०० इकाई उपयोगिता प्राप्त होनी है। जब वह दो केले खेताहै तो (केलेकी इच्छाकी आञ्जिक तृप्ति हो चुकनेके कारण) मान लीजिए ८० इकाई उपयोगिताकी वृद्धि हुई अर्थात् दो केलोंमें कुल १८० इकाई उपयोगिता प्राप्त हुई। यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि दूसरे केलेकी उपयोगिता ८० इकाई है और पहिलेकी १००। दोनों केले संबंधा समान है परन्तु क्योंकि वह व्यक्ति एक केला लचुका है अतएव उमके मनमें दूसरे केलेके लिए पहिले जैसी तीव्र अभिलाषा नहीं है। कहनेका तात्पर्य यहहै कि किसी वस्तुकी उपयोगिता जाननेके लिए यह आवश्यकहै कि उपभोक्ता के पास उम वस्तुकी कितनी इकाइया है। उपरोक्त उदाहरण में जब वह व्यक्ति नेमरा केला खरीदता है तो मान लीजिये कुल उपयोगितामें ५० इकाइयोंकी वृद्धि होजाती है। अर्थात् कुल उपयोगिता २३० इकाइया होजाती है। इसी प्रकार मान लीजिये कि चौथे केलेसे केवल २० इकाई उपयोगिता की वृद्धि होजाती है। इस प्रकार ४ केलोंकी कुल उपयोगिता २५० इकाइया हुई। यह नहीं कहना

चाहिए कि तीसरे केलोकी उपयोगिता ५० और चौथे केलोकी २० इकाइयाँ हैं बल्कि इस प्रवृत्ति को इस प्रकार बनाना चाहिए कि जब प्राप्त बेलोकी सरया दो में तीन होगयी हो तो कुल उपयोगितामें ५० इकाइयोंकी वृद्धि हुई और जब मग्या तीनसे चार हुई तो कुल उपयोगितामें २० इकाई की वृद्धि हुई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज्यों ज्यों केलोंकी संख्या बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों कुल उपयोगिता कम अनुपातमें बढ़ रही है।

कुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता

ऊपर दिए गए केनोंके उदाहरणमें हम कुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता के भेद और उनके सम्बन्धका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। इस उदाहरणको बड़ा कर हम आगे दी हुई तालिकामें दिखा रहे हैं *

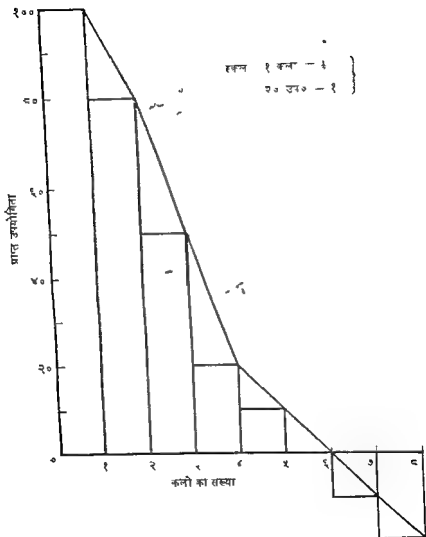
बेलोंकी संख्या	कुल उपयोगिता	सीमान्त उपयोगिता
१	१००	१००
२	१८०	८०
३	२३०	५०
४	२५०	२०
५	२६०	१०
६	२६०	०
७	२५०	—१०
८	२३०	—२०

* ध्यान रहे कि तालिका में जो संख्याएँ दी गयी हैं वह सब कार्त्तव्यनिक हैं। वास्तव में कुल उपयोगिता और न सीमान्त उपयोगिता इस प्रकार संख्या के रूपमें प्रकट की जा सकती हैं। यहाँ पर संख्याओं द्वारा केवल इस बातको दिखानेकी चेष्टा की गयी है कि कुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता किस प्रकारसे सम्बन्धित हैं।

किसी वस्तुकी जिनगीभी इकाइया लीगयी हो उन मर्माकी उपयोगिताके समुदायको कुल उपयोगिता कहते हैं। तालिकाके कॉलम २ में केलोंकी भिन्न भिन्न मर्यादाकी कुल उपयोगिता दिखायी गयी है। उदाहरणके लिए ५ केलोंकी कुल उपयोगिता २६० इकाई है। वस्तुकी इकाइयोंकी नमागर्त वृद्धिसे प्रत्येक बार कुल उपयोगितामें जो वृद्धि होतीहै, उसे सीमान्त उपयोगिता कहते हैं। इसको तालिकाके कॉलम ३ में दिखाया गया है। जब केलोंकी संख्या बढ़कर ३ से ४ हुई तो कुल उपयोगिता २३० से २५० इकाइया होगयी अर्थात् कुल उपयोगितामें २० इकाइया की वृद्धि हुई। अतः ४ केले लेने पर सीमान्त उपयोगिता २० है। इसी प्रकार ५ केले लेने पर सीमान्त उपयोगिता १० है जबकि कुल उपयोगिता २५० से बढ़कर २६० इकाइया होजाती है। सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करनेकी सरल विधि यहहै कि जब वस्तुकी संख्यामें एन इकाई बढ़ा या घटा दीगयी हो तो दो क्रमागत कुल उपयोगिताओं का अन्तर निकाल लिया जाये।

इस तालिकासे यहभी पता चलताहै कि ५ केलोंके प्राप्त करने तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, यद्यपि क्रमागत वृद्धिका अनुपात घटता जाता है। छठे केलेके लेनेपर उपयोगिता पूर्ववत् रहनीहै और सातवें और आठवें केलोंके लेने पर घटने लगती है। अब यदि हम सीमान्त उपयोगिताके कॉलमको ध्यानपूर्वक देखें तो मालूम होगा कि केलोंकी संख्यामें वृद्धि होनेपर क्रमागत सीमान्त उपयोगिता घटती जातीहै; परन्तु पांच केलो तक (जहाँ तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहनी है) यह धनात्मक रहनी है। ६ केले लेने पर सीमान्त उपयोगिता शून्य होजाती है और कुल उपयोगिताकी वृद्धिभी समाप्त होजाती है अर्थात् कुल उपयोगिताके अधिकतम स्तर पर सीमान्त उपयोगिता शून्य रहनी है। जब केलोंकी सातवाँ और आठवीं इकाई लीजाती है तो सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक होजाती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। सामने दिये रेखा-चित्रमें सीमान्त उपयोगिता दिखायी गयी है।

इस चित्रमें समकोण चतुर्भुज द्वारा सीमान्त उपयोगिता दिखायी गयी है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे केलोंकी संख्या बढ़ती जाती है, चतुर्भुजका क्षेत्रफल घटता जाता है। यदि इन चतुर्भुजोंके सिरोंकी अविविच्छिन्न रेखा द्वारा जोड़ें तो दाहिनी ओर की गिरती हुई इस रेखासे भी घटती हुई सीमान्त उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है।



न मागत उपयोगिता ह्यम नियमके कुछ अपवाद भी बनाये जाते हैं। देखा जाता है कि यदि कोई वस्तु बहुत ही सूक्ष्म मात्रामें ली जाये तो कुछ सीमा तक सीमान्त उपयोगिता घटनेके बदले बढ़ती जान पड़ती है। परन्तु यदि हम किसी वस्तुकी इकाई पर्याप्त मात्रामें लें तो यह नियम प्रारम्भसे ही लागू होजायेगा। उदाहरणके लिए अमरुदकी छोटी छोटी फाकोंको भी उसकी इकाई माना जा सकता है और एक अमरुदको अथवा एक सेर अमरुदकी भी। किसी वस्तुकी इकाई का पर्याप्त परिमाण क्या हो, इसका परिमाण भिन्न भिन्न वस्तुओंके लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होगा।

इसी प्रकार यदि ४ कुर्सियोंका एक सेट होता है और किसी व्यक्ति के पास ३ कुर्सियाँ हैं तो चौथी कुर्सीसे उसको अधिक सीमान्त उपयोगिता जान पड़ेगी। ऐसी परिस्थितिमें चारों कुर्सियाँ एक पूरे सेटको एक पर्याप्त मात्राकी इकाई समझना चाहिये। यही बात डाकके टिकट इकट्ठा करनेवालों अथवा विलक्षण वस्तुओंका संग्रह करनेवालों के विषयमें भी कही जा सकती है। पूर्वोक्त उदाहरण न मागत-उपयोगिता-ह्यम नियमके वास्तविक रूपमें अपवाद नहीं है।

सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम

प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसको अधिकतम मनोरंजन और तृप्ति मिले। वह अपने परिमित साधनोंका प्रयोग इस प्रकारसे करना चाहता है जिससे उसे प्रत्येक साधनके सीमान्त उपयोगमें सम उपयोगिता प्राप्त हो। यदि किसी साधनके एक दिशाके उपयोगमें दूसरी दिशाके उपयोग द्वारा अधिक उपयोगिता प्राप्त होनेकी सम्भावना हो तो वह उसके हितमें होगा कि वह उस साधनको कम उपयोगिता वाले उपयोगमें हटाकर अधिक उपयोगिता वाले उपयोगमें लगाये। जब उसके साधनोंकी सीमान्तिक उपयोगिताएँ सभी उपयोगोंमें समान होजानी हैं तो फिर साधनको एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें बदलनेमें कोई लाभ नहीं होता। साधनोंका विविध उपयोगोंमें वितरण करनेकी इस प्रवृत्तिको सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम प्रतिस्थापना सिद्धान्त भी है क्योंकि इसके अन्तर्गत साधनोंके विभिन्न उपयोगोंकी इस प्रकारसे प्रतिस्थापना होनी है कि किसी भी

उपयोगोंसे समान सीमान्तिक उपयोगिता प्राप्त हो। जब इस प्रकारका वितरण हो जाता है तो फिर तटस्थतावा आधिभवि होजाता है, मतएव इस दशाको तटस्थता सिद्धान्तभी कहा गया है। प्रति स्थापना दीर्घक अध्याय में सिद्धान्त का पूर्ण रूपेण विवेचन किया गया है। वह हम देखेंगे कि यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र के सभी भागों अर्थात् उन्मोग, उत्पादन, विनिमय और वितरणमें चरितार्थ होता है।

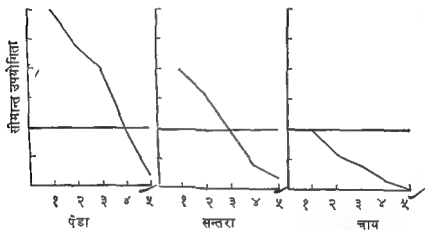
उपभोगके सम्बन्धमें इस प्रवृत्तिको 'सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम' कहते हैं। इस नियम की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी आय को भिन्न भिन्न वस्तुओंमें इस प्रकार व्यय करेगा, जिससे उसको विभिन्न वस्तुओंमें व्यय किये गये रुपये अथवा आनोसे समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो। आय एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग विविध वस्तुओंको प्राप्त करनेमें होता है। यदि आयकी एक इकाईसे एक उपयोगकी अपेक्षा दूसरे उपयोगमें अधिक उपयोगिता मिलनेकी सम्भावना हो तो उसको दूसरे उपयोगमें व्यय करनेमें अधिक तृप्ति मिलेगी। परन्तु जब किसी उपयोगमें द्रव्यकी एक इकाईके बाद दूसरी इकाई प्रमशः व्यय की जायेगी तो उस उपयोगकी सीमान्तिक उपयोगिता घटनी जायेगी और ऐसी स्थिति आजायेगी जबकि दूसरे उपयोगसे अधिक तृप्ति होगी। इस दूसरे और इसी प्रकार तीसरे, चौथे उपयोगोंमें भी क्रमागत-उपयोगिता-ह्रास नियम लागू होगा। अतएव वह व्यक्ति द्रव्यकी विभिन्न इकाइयोंको व्यय करनेके पहिले यह जाननेकी चेष्टा करेगा कि किस वस्तुमें व्यय करनेसे उसे अधिक सीमान्त उपयोगिता प्राप्त होगी। उसको अपने कुल व्ययसे अधिकतम उपयोगिता सभी मिल सकेगी जब द्रव्यकी प्रत्येक इकाईसे सभी उपयोगोंमें समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो। इस नियमको हम साधारण एव सुगम उदाहरणसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक लडकेके पास एक रुपया है, जिससे वह चाय, पेडा और सन्तरे लेना चाहता है। सुगमताके लिए हम यही मान लेतेहैं कि इन सभी वस्तुओंकी इकाईका मूल्य दो आना है। अब प्रश्न यह है कि वह कितनी इकाइया भिन्न भिन्न वस्तुओंकी मोलले, जिससे उसे अधिकतम उपयोगिताकी प्राप्ति हो। वह निश्चयही अपने मनमें प्रत्येक वस्तुकी विभिन्न इकाइयोंसे प्राप्त होनेवाली उपयोगिताओं की तुलना करेगा। अबले पृष्ठ पर दीगयी तालिकामें काल्पनिक मरयादोंमें इन तीनों वस्तुओंकी विभिन्न इकाइयोंसे प्राप्त उपयोगिता दीगयी है।

प्रति दुस्रीमें प्राप्त वस्तुकी इकाइया	आपेक्षित उपयोगिता		
	चाय	पेडा	सन्तरे
१	५	१५	१०
२	३	१२	८
३	२	१०	५
४	१	५	२
५	०	१	१

इस तालिकाको ध्यानमें रखते हुए उस लडकेको एक रुपया निम्न प्रकारसे व्यय करनेमें अधिकतम उपयोगिता मिलेगी,

वस्तुओंकी इकाई	उपयोगिता	कुल
१ प्याली चाय	५	५
४ पेडे	$१५ + १२ + १० + ५$	४२
३ सन्तरे	$१० + ८ + ५$	२३
	कुल उपयोगिता	७०

यदि वह चौथे पेड़के स्थानमें एक प्याली चाय और पिये तो कुल उपयोगितामें ५ इकाईकी कमी और ३ इकाईकी वृद्धि होगी अर्थात् कुल उपयोगितामें २ इकाई की कमी होजायेगी, कुल उपयोगिता ६८ (७० - ५ + ३) रह जायेगी। पाठक स्वयं जाच करके जात कर सकतेहैं कि अन्य किसी प्रकारमें वस्तुओंकी मोल लनमें कुल उपयोगिता ७० से कम ही मिलेगी। इस उदाहरणमें प्रत्येक वस्तुमें व्यय की गयी दुम्रन्नीकी सीमान्त उपयोगिता ५ है। इसी स्थितिको रेखाचित्र द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं।



इस रेखाचित्र में गड़ी रेखा द्वारा प्रति दुम्रन्नीसे प्राप्त वस्तुका परिमाण और खड़ी रेखा द्वारा सीमान्तिक उपयोगिता दिखायी गयी है। स्पष्ट है कि आठ दुम्रन्तियों से चार पेड़े, तीन सन्तरे और एक प्याली चाय लनेसे उसको समान (५) सीमान्तिक उपयोगिता मिलती है।

वास्तवमें सभी वस्तुओंकी उद्देश्योंका मूल्य समान नहीं होता है। इस बात को ध्यानमें रखते हुए हम इस सिद्धान्तको इस प्रकारसे भी कह सकतेहैं कि प्रत्येक विचारवान् मनुष्य इस प्रकार व्यय करेगा जिसमें सभी मोल लीगयी वस्तुओंकी सीमान्त उपयोगिता उनके मूल्यके अनुपातमें हो। उदाहरणके लिए यदि छातेका मूल्य १० रुपया, टोपीका २ रुपया और हमालका १ रुपया हो तो कोई मनुष्य

छाने का खरीदना नहीं चाहेगा, यदि छात्रोंमें अनेकान उद्योगिता कमसे कम टोपियों और १० रुमालोंके बराबर न हो। इस सम्बन्धको समीकरणके रूपमें प्रकार लिखा जा सकता है :

<u>छानेका मूल्य</u>	=	<u>टोपीका मूल्य</u>	=	<u>रूमालका मूल्य</u>
छानेकी		टोपीकी		रूमालकी
सीमान्त उपयोगिता		सीमान्त उपयोगिता		सीमान्त उपयोगिता

यदि किसी वस्तुके मूल्यमें परिवर्तन होजाये तो भिन्न भिन्न वस्तुओंकी इकाइयों का खरीदनेमें भी इसी प्रकार परिवर्तन होनेकी प्रवृत्ति होगी, जिससे अनुपात पूर्ववत् होजाये।

भिन्न भिन्न वस्तुओं पर द्रव्यको व्यय करनेमें कोईभी व्यक्ति कुल उपयोगिताको तभी अधिकतम बना सकता है जब कि मोल मीगयी वस्तुओंकी सीमान्त उपयोगिताएँ उनके मूल्यके अनुपातमें हो।

वास्तविक संसारमें भिन्न भिन्न वस्तुओंकी मागकी स्थिरता और अनेक मूल्यों में बहुत भिन्नता होनेके कारण इस अनुपातके अनुसार चलना कठिन होजाता है। परन्तु प्रवृत्ति इस प्रकारकी अवश्य रहती है। एक बात और भी ध्यानमें रखनेकी है कि बाजारमें फँसल और रुचिमें परिवर्तन होतके कारण भिन्न भिन्न वस्तुओंकी सापेक्ष सीमांतिक उपयोगिताओं में भी अन्तर आजाता है। यदि कुछ काल तक वस्तुओंके मूल्य और रुचिमें परिवर्तन न हो तो मनुष्यको अपने व्ययके वितरणसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनेमें सुगमता होगी।

मांग

मांग का तात्पर्य

अर्थशास्त्र में 'मांग' शब्दका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थमें होता है। किसी मनुष्यकी किसीभी वस्तु सम्बन्धी मांग उसके मूल्यके साथ निहित रहती है। 'मोहनकी २० ग्रामोंकी मांग है' यह वाक्य असम्बद्ध समझा जायेगा, जबतक इसके साथ ग्रामका भाव न जोड़ दिया जाये। वस्तुतः हमको कहना चाहिए, 'यदि ग्रामका मूल्य चार ग्राने प्रति ग्राम हो तो इस मूल्यपर मोहनकी मांग २० ग्रामकी है।' यदि ग्रामका भाव चार ग्राने न होकर पाच ग्राने अर्थात् तीन ग्राने हो तो सम्भव है कि मोहनकी मांगमें भी अन्तर पड़ जाये। भिन्न भिन्न मूल्यों पर मोहनके लिए ग्रामोंकी मांग भिन्न भिन्न होगी। अतएव मांगका तात्पर्य यह है कि किसी समय विशेषमें खरीदार भिन्न भिन्न मूल्योंपर किसी वस्तुकी कितनी इकाइया खरीदेगा।

मांगका आवश्यकताओं और उनकी विशेषताओंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरे अध्यायमें हमने बताया है कि किसीभी वस्तुकी आवश्यकता की तीव्रता उस वस्तु के संग्रहसे कम होजाती है। आवश्यकता की तीव्रतामें न्यूनता ग्रानेके कारण उस वस्तुकी उपयोगिता भी कम होतीचली जाती है अतएव उसका मूल्यभी उपभोक्ताकी दृष्टिमें गिरता जाता है। आवश्यकताकी तीव्रताका मांगपर भी प्रभाव पड़ता है। यदि किसी मनुष्यको किसी वस्तुकी आवश्यकता बहुत तीव्रहो तो उसके लिए उस वस्तुकी उपयोगिता बहुत अधिक होगी और वह उसको अधिक मूल्यपर भी खरीद लेगा। परन्तु यदि आवश्यकता थिथिल पड़ गयीहो तो वह उस वस्तुको कम मूल्य पर खरीदना चाहेगा। इस प्रकार हम देखतेहैं कि मोहन अधिक परिमाणमें ग्राम खरीदना तभी पसन्द करेगा जबकि विक्रेता उनका मूल्य घटाये। अधिक मूल्य होने पर वह कम ग्राम खरीदेगा। मांगकी इस प्रवृत्तिका *इस मूल्यपर ही खरीदना* द्वारा निदर्शन कर सकते हैं :

मूल्य (आने में)	मोहनकी माग
८ प्रति आम	० आम
७ " "	१
६ " "	५
५ " "	१०
४ " "	२०
३ " "	३०
२ " "	३५

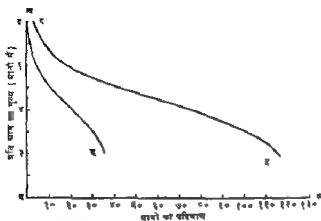
स्मरण रहे कि उपरिलिखित तालिका किसी विशेष व्यक्ति की किसी विशेष समय पर आमोंकी मागकी द्योतक है; भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए एक ही समय पर अथवा एकही ध्यवितके लिए भिन्न भिन्न समयों पर यह तालिका भी भिन्न हो सकती है क्योंकि प्रत्येक मनुष्यकी किसीभी वस्तु सम्बन्धी माग उसकी आय, अभिरुचि और अन्य वस्तुओंके मूल्यपर अवलम्बित रहती है। इनमें परिवर्तन होने से उसकी मागमें भी परिवर्तन होनेकी सम्भावना रहती है। परन्तु किसी समय विशेषमें इन सब बातोंके मयावत् रहनेपर वह भिन्न भिन्न मूल्योंपर उस वस्तुको भिन्न भिन्न परिमाणों में खरीदनेको तत्पर रहेगा। भिन्न भिन्न मनुष्यों की आय, अभिरुचि, आवश्यकताकी तीव्रता किसी वस्तुके लिये भिन्न भिन्न होती है। अतएव प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न मूल्योंपर किसी वस्तुको समान परिमाणमें नहीं खरीदेगा। ऊपर दीगयी तालिकाके अनुसार मोहन ६ आनेके हिसाबसे ५ आम खरीदता है, दूसरे उपभोक्ताकी माग, जिसको आममें अधिक अभिरुचि नहीं है अथवा जो इस भावपर आम खरीदने में असमर्थ है, ६ आने प्रति आम मूल्य होनेपर शून्य हो सकती है। अतएव प्रत्येक उपभोक्ताकी आमकी मागकी तालिका भिन्न भिन्न होने की सम्भावना है। यदि हम किसी समय विशेषके लिए सभी उपभोक्ताओं की मागकी तालिकाओं का समुच्चय करें तो हमको सभी उपभोक्ताओं की कुल आमों की मागकी तालिका प्राप्त होसकती है। कल्पना कीजिए, आमोंके बाजारमें पाच उपभोक्ताहैं, जिनकी किसी एक दिनकी मागकी तालिका निम्न प्रकारकी है:

प्रति ग्राम का मूल्य	दैनिक माग					
	क	ख	ग	घ	ङ	कुल
८ आना	०	०	१	०	२	३
७	१	०	२	०	५	८
६	५	०	५	२	८	२०
५	१०	१	१०	५	१५	४१
४	२०	३	१५	१०	२५	७३
३	३०	५	२०	१५	३०	१००
२	३५	१०	२०	२०	३०	११५

अन्तिम कोष्टकमें उपभोक्ताओं की भिन्न भिन्न मूल्योंसे सम्बन्धित कुल माग पाषो उपभोक्ताओं की भागोंके योगसे प्राप्त कीगयी है। उदाहरणके लिए यदि ग्रामोंका मूल्य ४ आने प्रति ग्रामहो तो कुल माग ७३ होगी और यदि २ आने हो तो कुल माग ११५ होगी। इस कुल मागकी तालिकाको (तथा प्रत्येक उपभोक्ताकी माग की तालिकाको) रेखाचित्र द्वाराभी व्यक्त किया जासकता है।

मांग का नियम

माग की तालिका और रेखाचित्र से मागके विषयमें हमको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मालूम होती है। वह यहकि जैसे जैसे ग्रामका मूल्य घटता जाता है, वैसे वैसे उसकी माग बढ़ती जाती है और जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है, वैसे वैसे माग घटती जाती है। यही बात स्वाभाविकभी मालूम पड़ती है। यदि किसी वस्तुको अधिक मात्रामें बेचनाहो तो उसके मूल्यको घटाना ही पड़ेगा; क्योंकि अधिक मात्रामें लेनेमें किसीभी उपभोक्ताको कम सीमान्तिक उपयोगिता प्राप्त होती है। अतएव अन्य बातोंके यथावत् रहनेपर उपभोक्ताओं को अधिक मात्रामें खरीदने के लिए मूल्य घटाकर ही आकृष्ट किया जासकता है। इसी बातको हम दूसरे प्रकारसे भी कह सकते हैं। कोई उपभोक्ता किसी मूल्यपर वस्तु खरीदता है तो



इस रेखाचित्रमें d व रेखा मोहनके मागकी तालिका और d' रेखा कुल मागकी दर्शाती है।

वह अपनेको उसी मूल्यसे प्राप्त होनेवाली दूसरी वस्तुसे वंचित करता है अर्थात् जिस दूसरी वस्तुकी वह लेसकना था, उसका उसे त्याग करना पड़ता है। अब यदि उसको पहिली वस्तु कम मूल्यपर प्राप्त होसके तो दूसरी वस्तुकी अपेक्षा वह वस्तु अधिक क्रय सिद्ध हो जायेगी। अर्थात् यदि दो वस्तुओंमें प्रतियोगिता हो और उनमेंसे एकके मूल्यमें कमी करदी जाये तो जिस वस्तुका मूल्य कम कर दिया गया है उसकी माग बढ़ जायेगी और अपेक्षतः अधिक मूल्यवाली वस्तुके स्थानमें भी इसी वस्तुकी अधिक मात्रामें लेनेकी प्रवृत्ति होगी क्योंकि मूल्यमें कमी होनेसे अन्य स्थानापन्न वस्तुओंका स्थानभी कुछ अंश तक वही वस्तु ग्रहण करने लगेगी। अतएव इसकी मागमें वृद्धि अवश्य हो जायेगी।

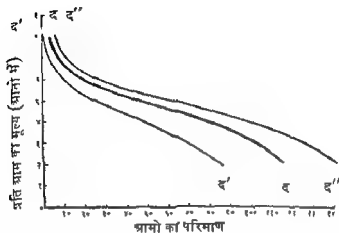
चाहे हम इस विषयको घटती हुई सीमान्तिक उपयोगिताके दृष्टिकोणसे देखें अथवा स्थानापन्न वस्तुओंके परिभाषणमें अन्तरके दृष्टिकोणसे देखें, किसी वस्तुकी माग अधिक मूल्यपर कम और कम मूल्यपर अधिक रहेगी। इसीको माग का नियम भी कहते हैं। यह स्थिति रेखाचित्रमें दाहिनी ओर गिरती हुई मागकी रेखासे व्यक्त होती है।

भाग में परिवर्तन

भागके नियमके अनुसार अन्य बातें यथावत् रहनेपर भी मूल्यमें कमी होनेसे किसी वस्तुकी भागमें वृद्धि और मूल्यमें वृद्धि होनेपर भागमें कमी होजाती है। यह प्रवृत्ति किसीभी भागकी तालिका अथवा भागकी रेखामें देखीजा सकती है। परन्तु मूल्यमें कमी अथवा वृद्धि न हो। परभी किसी वस्तुकी भागमें कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। भागमें इसप्रकार होनेवाली कमी अथवा वृद्धिको 'भागमें परिवर्तन' के नामसे पुकारते हैं। परिवर्तनकी परिभाषा इसप्रकार है। यदि किन्हीं दियेगये मूल्योपर उपभोक्ता पहिलेसे कम अथवा अधिक परिमाणमें उस वस्तुको खरीदें तो हम कहनेहैं कि उस वस्तुकी भागमें परिवर्तन होगया है। यदि दियेगये मूल्यो पर उपभोक्ता पहिलेसे अधिक परिमाणमें उस वस्तुको खरीदें तो हम कहेंगे कि भाग का प्रसार हुआ और यदि कम मात्रामें खरीदें तो हम कहेंगे कि भागमें सकुचन हुआ। नीचे दीहुई तालिकामें भागके परिवर्तनको दिखाया गया है।

आमाका मूल्य (आना)	पहिलेकी भाग	इकाई की भाग	
		क	ख
८ प्रति आना	३	५	०
७ " "	८	१२	२
६ " "	२०	३०	१०
५ " "	४१	६०	२५
४ " "	७३	९०	४५
३ " "	१००	१२०	६०
२ " "	११५	१४०	८५

नयी भागका कोष्टक (क) भागमें प्रसार और कोष्टक (ख) भागमें सकुचन सूचित करता है। इस तालिकाको रेखाचित्रमें पृष्ठ पर दिखाया गया है :



पिछली भागको द द रेखासे दिखलाया गया है। द' द' रेखासे मागमें सकुचन और द'' द'' रेखासे मागमें प्रसार दिखलाया गया है।

इस प्रकार हम देखतेहैं कि मागमें परिवर्तन होनेपर मागकी तालिका और रेखाभिन्न बदत जाते हैं। मागमें परिवर्तन होनेका कारण यहहै कि अन्य सब बातें पूर्ववत् नही रहती हैं। घट बढ होनेसे भिन्न भिन्न वस्तुओं सम्बन्धी अभिरुचि में परिवर्तन होनेसे अथवा अन्य वस्तुओंके कम या अधिक मात्रा और मूल्यमें प्राप्त होनेके कारणभी किसी वस्तुकी मागमें परिवर्तन होसकता है। साधारणतः आय की वृद्धिसे किमी वस्तुकी कुल मागमें प्रसार और आयकी कमीसे मागमें सकुचन होजाता है। यदि किमी कारणसे लोग ग्रामोंको पहिलेमें अधिक पसन्द करने लगे तो भी मागका प्रसार होगा और यदि कम पसन्द करें तो माग सकुचित हो जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी वस्तुकी प्रतिरूप वस्तुओंकी सन्ख्यामें वृद्धि होजाये अथवा किमी प्रतियोगिता वाली वस्तुका मूल्य कम करदियां जाये तो पहिली वस्तुकी मागमें सकुचन हो जायेगा। इसके प्रतिकूल यदि प्रतिरूप वस्तुओंकी मर्याद कम होजाय अथवा किसी प्रतियोगिता करनेवाली वस्तुका मूल्य बढजाये तो पहिली वस्तुकी मागमें प्रसार होगा। उदाहरणके लिए यदि कोई नया फल बाजारमें बिकने लगे तो कुछ लोग ग्रामोंकी कमी करके इस नये फलको लेने लगेंगे। अतएव ग्रामकी मागकी रेखा बायी ओर नीचेको होजायेगी। और यदि सेब, सन्तरा इत्यादि फलोंके मूल्यमें

वृद्धि होजाये तो कुछ लोग इनके बदले आम लेने लगेंगे और आमकी मागमें प्रसार होजायेगा।

भाग की लोच

अभी हम देख चुके हैं कि मूल्यमें परिवर्तन होनेसे किसी वस्तु की मागके परिमाणमें भी परिवर्तन होजाता है। 'परन्तु सभी वस्तुओंके मूल्यमें कुछ घट-बढ़ हो जानेका प्रभाव सभी मनुष्यों पर एकसा नहीं पड़ता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके मूल्यमें थोड़ासा अन्तर होजाने पर उनकी मागमें विशेष परिवर्तन नहीं होता है जैसे नमक। परन्तु यह बात चीनीके लिए नहीं कह सकते हैं। यदि चीनीका मूल्य १ रुपया प्रति सेर से घटकर १४ आने प्रति सेर होजाये तो उसकी मागमें अवश्य ही वृद्धि होगी और १ रुपया २ आने प्रति सेर होनेपर माग घट जायेगी। हा यह बात अवश्य है कि कुछ धनीलोग जिनकी १ रुपयेके भावपर चीनीकी आवश्यकता पूर्णरूप से तृप्त होजाती है, वह १४ आने सेरके हिसाबसे भी उतनी ही मात्रामें चीनी खरीदेंगे और १ रुपया २ आने प्रति सेरपर भी उतनीही मात्रामें खरीदेंगे। यदि चीनी २ आने प्रति सेरके हिसाबसे बिकने लगे तो प्रायः सभीलोग इस भावपर चीनीको पर्याप्त परिमाणमें खरीद लेंगे और डेढ़ आने प्रति सेरपर मागमें विशेष वृद्धि न होगी। किसी वस्तुके मूल्यमें परिवर्तन होनेसे जो मागके परिमाणमें परिवर्तन होजाता है उसको मागकी लोच कहते हैं। अर्थात् मागकी लोच मूल्य-परिवर्तनसे प्रभावित होकर मागमें पड़नेवाले अन्तरकी माप है। यदि मूल्यके परिवर्तनसे मागमें कुछभी अन्तर न हो तो उसको बेलोच माप कहेंगे। शायदही ऐसी कोई वस्तु हो जिसकी समुदायिक माग बेलोच हो। वास्तवमें भिन्न भिन्न वस्तुओंकी माग कम या अधिक लोचदार होती है। इसको जाननेकी एक सुगम रीति यह है कि किसी वस्तुके मूल्यमें परिवर्तन होनेके कारण उस वस्तुमें कियेगये व्यय में परिवर्तनको मान्य किया जाय। मान लीजिये आमके मूल्यमें कुछ वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप उसकी मागकी मात्रामें इतनीही कमी हुई कि उसपर कियागया कुल व्यय पूर्ववत्ही रहा अथवा आमके मूल्यमें कुछ कमी होनेपर उसकी मागमें इतनीही वृद्धि हुई कि उसपर कियागया कुल व्यय उतनाही रहा

तो ऐसी अवस्थामें हम कहतेहैं कि इन दो मूल्य-स्तरों के अन्तर्गत मागकी लोच एक इकाई है। परन्तु यदि मूल्य घटनेसे कुल व्यय बढ़जाये और मूल्य बढ़नेसे कुल व्यय घटजाये तो हम कह सकतेहैं कि मागकी लोच एक इकाईसे अधिक है। इसके प्रतिकूल यदि मूल्यके घटनेसे कुल व्यय घटजाये और मूल्यके बढ़नेसे कुल व्यय बढ़जाये तो हम कह सकतेहैं कि मागकी लोच एक इकाईसे कम है। इस बातको नीचे दोट्टई तालिकामें दिखाया गया है :

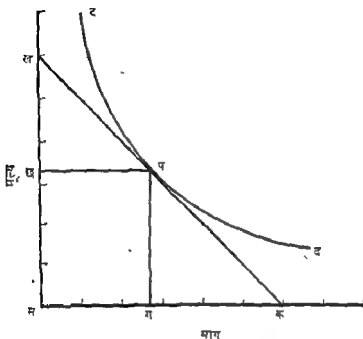
रेखाचित्र (क) में द २ और द २ मूल्योंके अन्तर्गत भागकी लोच इकाईसे अधिक है क्योंकि 'म' प २' 'द २, ब २' का क्षेत्रफल (कुल मूल्य) 'म, प १' 'द १, ब १' से अधिक है। चित्र (ख) में 'द ३' और 'द ४' के अन्तर्गत भागकी लोच इकाई है क्योंकि 'म, प ३' 'द ३, ब ३' और 'म, प ४' 'प ४, ब ४' का क्षेत्रफल बराबर है और रेखा चित्र (ग) में 'द ५' और 'द ६' मूल्योंके अन्तर्गत भागकी लोच इकाईसे कम है क्योंकि 'म, प ६' 'द ६, ब ६' का क्षेत्रफल 'म, प ५' 'द ५, ब ५' से कम है। इन तीनों रेखाचित्रों में भागकी रेखाएँ एकसी हैं परन्तु भागकी रेखाओंके एक सी होनेका तात्पर्य यह न समझना चाहिये कि भागकी लोच भी एकसी ही है; भिन्न भिन्न मूल्योंपर लोच भिन्न भिन्न है। अतएव हमको बिना विश्लेषणके नहीं कहना चाहिए कि किसी वस्तुकी भाग कम या अधिक लोचवाली है, जबतक कि सारी रेखाकी एक सी लोच न हो। चूँकि लोच भिन्न भिन्न मूल्योंपर भिन्न भिन्न होसकती है इस कारण भागकी लोचका विवेचन करते समय हमको किसी मूल्य-विशेषपर लोचके सम्बन्धमें बताना चाहिए।

एक और प्रकारसे भागकी लोच अको द्वारा प्रकटकी जासकती है। यदि किसी वस्तुके मूल्यमें कमी होनेके कारण भाग उसी अनुपातमें बड़े तो हम कहेंगे कि लोच एक इकाई है। यदि भाग अधिक अनुपातमें बड़े तो लोच एकसे अधिक है और यदि भाग कम अनुपातमें बड़े तो लोच एकसे कम समझी जायेगी। यदि भाग बिल्कुल ही न बड़े तो लोच शून्य समझी जायेगी। इस सम्बन्धको निम्नलिखित समीकरण के रूपमें लिख सकते हैं।

$$\text{लोच} = \frac{\text{भागमें प्रतिशत वृद्धि}}{\text{मूल्यमें प्रतिशत कमी}}$$

उदाहरणके लिये यदि आमके मूल्यमें १० प्रतिशत कमी होनेपर उसकी भागके परिमाणमें १० प्रतिशत वृद्धि हो तो लोच एक इकाई, १५ प्रतिशत वृद्धि होनेपर इकाईसे अधिक और ५ प्रतिशत वृद्धि होनेपर इकाईसे कम और पूर्ववत् रहनेपर शून्य होगी।

गणितकी ओर जिनकी प्रवृत्ति हो, ऐसे पाठकोंके लिए भागकी लोचको रेखाचित्र द्वारा दिखलाया और मापा जा सकता है।



इस चित्रमें 'म, क' रेखा द्वारा मूल्य और 'म, ख' रेखा द्वारा मागका परिमाण दिखाया गया है। 'द, द' किसी वस्तुकी मागकी रेखा है। 'प' इस रेखापर एक बिन्दु है जो यह दिखाता है कि 'म, ख' मूल्यपर 'म ग' माग है। 'क ख' रेखा 'प' बिन्दु पर स्पर्श-रेखा है। मागकी लोच 'प' बिन्दुपर 'प क' : 'प म' अनुपात द्वारा प्रकट की जाती है। यदि 'प ख' = $(२ \times प क)$ तो मागकी लोच २ हुई, अर्थात् यदि मूल्यमें एक प्रतिशत कमी हो तो मागके परिमाणमें २ प्रतिशत वृद्धि होगी। इसी सम्बन्धको 'ग क' : 'ग म' अथवा 'म ख' : 'ख क' अनुपात द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। -

माग की लोच में भिन्नता

किसी भी वस्तुकी माग-लोच सभी मनुष्यों अथवा सभी मूल्योंपर समान नहीं

होसकती है। फिरभी साधारणतः हम कह सकतेहैं कि आवश्यकताकी वस्तुओंकी माग कम लोचदार होतीहै और विलासिताकी वस्तुओंकी माग अधिक लोचदार होती है। इसीप्रकार हम कह सकतेहैं कि साधारणतः किसी वस्तुके ऊचे मूल्य-स्तरों पर माग अधिक लोचदार होती है और जैसे जैसे मूल्य गिरता जाता है, लोच भी कम होती जाती है। यहाँ तक कि बहुत कम मूल्य-स्तर पर लोच शून्य होसकती है। उदाहरणके लिए घड़ीकी मागसे गेहूँकी माग कम लोचदार होगी और घड़ीकी मागमें भी ऊचे मूल्यपर अधिक लोच और बहुत कम मूल्यपर कम लोचकी सम्भावना होगी। इस प्रकारके साधारण सम्बन्धोंमें कठिनाई यह होनीहै कि कोई वस्तु एक मनुष्यके लिये आवश्यकताकी और दूसरेके लिए विलासिताकी वस्तु समझी जा सकती है। उदाहरणके लिए विश्वविद्यालयका छात्र फाउन्टेनपेन को आवश्यक वस्तु समझे परन्तु एक मजदूरके लिए तो वह विलासिताकी वस्तु ही समझी जायेगी। इसी प्रकार धनी व्यक्तिके लिए दो रुपये सेरके हिसाबसे चीनीका मूल्य भले ही ऊँचा न हो परन्तु एक मध्यम श्रेणीके व्यक्तिके लिए तो यह मूल्य ऊँचाही होगा।

मागकी लोचमें भिन्नता होनेके कुछ प्रमुख कारण नीचे दिये जाते हैं :

(१) यदि किसी वस्तुकी स्थानापन्न वस्तुएँ प्रचुरतासे प्राप्त हो और वह उस वस्तुका स्थान भुगमताके साथ ग्रहण कर सकें तो उस वस्तुकी माग अधिक लोचदार होगी। इसका कारण यहहै कि यदि उस वस्तुके मूल्यमें कमी होजाये तो लोग अन्य स्थानापन्न वस्तुओंके बदले इस वस्तुकी अधिक मात्रामें खर्च लगेंगे और यदि उसके मूल्यमें वृद्धि होजाये तो इसको छोड़कर अन्य स्थानापन्न वस्तुओंको लेंगे जिससे इसकी मागमें अधिक कमी होजायेगी।

यदि किसी वस्तुकी कोई योग्य स्थानापन्न वस्तु न हो अथवा स्थानापन्न वस्तुओं की संख्यामें कमी होजाये तो उस वस्तुकी माग कम लोचदार हो जायेगी; क्योंकि वस्तुओंके चुनावका क्षेत्र इस प्रकार सकुचित होजाता है। उदाहरणके लिए बाजारमें अनेक प्रकारकी चाय विकती है। यदि एक प्रकारकी चायके मूल्यमें वृद्धि होजाये तो अनेक लोग दूसरे प्रकारकी चाय खरीदने लगेंगे। अतएव पहिली चाय की मागमें बहुत कमीकी सम्भावना रहेगी। परन्तु यदि एकही प्रकारकी चाय होती तो चायके उपभोक्ताओंको यह सुविधा प्राप्त न होती और मूल्य बढ़नेपर भी उनको यही चाय खरीदनी पड़ती अर्थात् चायकी माग कम लोचदार होती।

(२) यदि किसी वस्तुका उपयोग अनेक कार्योंमें होसकता हो तो उसकी माग अधिक लोचदार होगी क्योंकि मूल्यके गिर जानेसे उस वस्तुका उपयोग उन कार्यों में भी होने लगेगा जिनमें ऊँचे मूल्यपर नहीं किया जाता था और मूल्यके बढ़ जाने पर उस वस्तुका उपयोग अधिक आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रहेगा।

(३) यदि किसी वस्तुके मूल्य बहुत ऊँचे स्तरसे गिरकर नीचे स्तरपर आजायें तो न केवल ऊँचे मूल्यपर खरीदनेवाले उपभोक्ता उस वस्तुको अधिक मात्रामें खरीदने लगेंगे वरन् निम्न आयवाले उपभोक्ताभी उसकी और अधिक सख्यामें आकर्षित होने लगेंगे। निम्न आयवाले उपभोक्ता अधिक सख्यामें पाये जाते हैं अतएव ऐसा होनेपर मागमें अधिक वृद्धि होजाती है। ऐसी अवस्थामें माग अधिक लोचदार होजाती है। परन्तु यदि किसी वस्तुका मूल्य आरम्भमें ही घटने नीचे स्तर पर हो कि न्यूनतम आयवाले उपभोक्ताभी उस मूल्यपर पर्याप्त मात्रामें उस वस्तुको खरीद सके तो ऐसी अवस्थामें मुख्य घटनेपर मागमें बहुत कम वृद्धि होगी। अर्थात् मागमें बहुत कम लोच रहेगी।

(४) यदि कुल व्ययकी तुलनामें कि नौ एक वस्तु पर नगण्य व्यय होता है तो उस वस्तु की मागमें कम लोच रहती है। उदाहरणके लिए किसी परिवारमें महीनेमें भोजनके पदार्थोंमें जितना व्यय होता है उसकी तुलनामें नमक पर नगण्य ही व्यय होता है। अतएव यदि नमकके मूल्यमें वृद्धि होजाये तो भी उसकी मागमें अधिक कमी नहीं होगी। परन्तु यदि कुल व्ययका एक बड़ा भाग किसी एक ही वस्तुके उपर होता हो तो ऐसी वस्तुके मूल्यमें वृद्धि होनेसे उसकी मागके परिमाणको अधिक घटानेका प्रवृत्ति होगी।

यदि दो वस्तुओंकी माग सम्मिलित हो तो जिस वस्तुपर कम व्यय होता है, उस की मागमें कम लोच होती है। उदाहरणके लिए भूभ्रपानके लिए सिगरेट और दियासलाईकी सम्मिलित माग रहती है और धूम्रपानके कुल व्ययमें दियासलाई पर किया गया व्यय बहुत कम रहता है। अतएव दियासलाईके मूल्यमें वृद्धि होने के कारण धूम्रपानमें अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और दियासलाईकी मागमें भी अधिक कमी नहीं होगी।

(५) जो वस्तुएँ टिकाऊ होती हैं और जो अरम्भमें होनेपर कामके योग्य बन सकती हैं उनकी मागमें अधिक लोच होती है। उदाहरणके लिए यदि जूतोंके,

मूल्यमें वृद्धि होजाये तो हम कुछ समय तक मरम्मत करवा कर पुराने जूतोसे काम चला सकते है। नये जूतोके मूल्यकी तुलनामें मरम्मतमें बहुत कम पैसा लगता है।

इसप्रकार हम देखते है कि किसी वस्तुकी मागकी लोचका विषय पेचीला है। इसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए कई बातोको साय साय ध्यानमें रखना पडता है।

माग की लोच का महत्व

मागकी लोचका ज्ञान अनेक व्यावहारिक कौश्योंमें आवश्यक होता है। किसी भी उत्पादक अथवा विप्रेताको केवल इतनाही ज्ञान सेना पर्याप्त नहीं होता कि वह चालू मूल्यपर किसी वस्तुकी किस परिमाणमें बेच सकता है। वह यहभी जानना चाहेगा कि यदि वह किसी वस्तुका मूल्य कम करे तो उसकी बिक्रीमें कितनी वृद्धि होगी। यदि मूल्यमें कमी करनेसे माग बहुत बढ़ जातीहै तो सम्भवतः मूल्य घटानेसे प्रति अवध जो क्षति उसको होतीहै, उसमें अधिक लाभ उसको बिक्रीमें वृद्धिसे होसकता है। परन्तु यदि माग बहुत कम बढ़े तो उसको हानि होनेकी सम्भावना है। साधारणतः जिन वस्तुओंमें बहुत कम लोच रहतीहै उनका मूल्य अधिक रहनेपर विप्रेताको अधिक लाभ होनेकी सम्भावना रहती है। प्रत्येक विप्रेता को, चाहे वह वस्तुओंको बेचे अथवा अपना श्रम बेचे, यह बात ध्यानमें रखनी पडतीहै कि प्रत्येक अवस्थामें मूल्य अधिक रखनेसे ही अधिक आय नहीं होती है। एकाधिकारीको अपना मूल्य और उत्पत्तिकी मात्राका निर्धारण करनेमें विशेष रूप से मागकी लोचको ध्यानमें रखना पडता है; जैसाकि एकाधिकारी मूल्यके प्रकरण में बताया जायेगा।

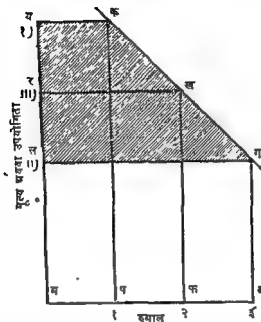
राज्यको भी अपनी कर-नीतिके सम्बन्धमें मागकी लोचको ध्यानमें रखना पडता है। यदि किसी वस्तुपर राज्यको अपनी आय बढ़ानेके लिये कर लगाना आवश्यकहो तो वह ऐसी वस्तुओं पर कर लगाताहै जिनकी मागमें कम लोच हो। यदि अधिक लोचवाली वस्तुओं पर कर लगाया जाये तो करके कारण मूल्यमें वृद्धि होने पर उनकी माग बहुत घट जायेगी और राज्यको अधिक आय नहीं होगी।

उपभोक्ता की वचत

कुछ समय पूर्व अर्थशास्त्र की पुस्तकोंमें 'उपभोक्ताकी वचत' के विषयको बहुत

बड़ा महत्व दिया जाना था। अमागत उपयोगिता-हानि नियम और मागकी तालिका पर इसको आधारित किया गया है। किसी भी उपभोक्ताको किसी भी वस्तुकी प्रारम्भिक इकाइयोंमें अधिक तृप्ति तथा अमागत बढ़ती हुई इकाइयोंसे कम तृप्ति मिलती है। अतः वह प्रारम्भिक इकाइयोंके लिये अधिक मूल्य देनेकी तत्पर होगा और बढ़तीहुई इकाइयों पर कम मूल्य लगायेगा क्योंकि उसकी आवश्यकताकी उग्रता कम होती जाती है। उदाहरणके लिए मान लीजिए एक रुमालके लिए कोई मनुष्य एक रुपया तक देनेकी तैयार है, दूसरे रुमालके लिए बारह आना और तीसरेके लिए आठ आना क्योंकि एक रुमालसे वह एक रुपयेके बराबर तृप्ति की, दो रुमाल खरीदनेपर बारह आनेके बराबर तृप्तिमें वृद्धिकी अर्थात् १ रुपया १२ आनेके बराबर कुल तृप्तिकी और तीन रुमाल खरीदने पर आठ आनेके बराबर तृप्ति में वृद्धिकी अर्थात् २ रुपये ४ आनेके बराबर कुल तृप्तिकी प्राप्ति करता है। यदि बाजारमें प्रति रुमालका मूल्य आठ आना हो तो वह तीन रुमाल खरीदेगा, जिनका मूल्य डेढ़ रुपया हुआ। परन्तु उसको कुल तृप्ति सवा दो रुपयेके बराबर हुई क्योंकि वह तीन रुमालोंके लिए सवा दो रुपये तक देनेकी तत्पर था। अतएव उसको (सवा दो-डेढ़) अर्थात् १२ आनेकी बचत हुई। इस उदाहरणको रेखाचित्र द्वाराभी दिखाया जा सकता है।

इस रेखाचित्रमें उपभोक्ता एक रुमालके लिये १ रुपया तक मूल्य देनेकी तत्पर है। उपयोगिताके रूपमें हम कह सकतेहैं कि वह एक रुमालसे 'म प' 'क य' उपयोगिता प्राप्त करनेकी आशा करता है। दूसरे रुमालसे १२ आने अथवा 'प फ' 'ख क' उपयोगिता और तीसरेसे ८ आने अथवा 'फ ब' 'ग ख' उपयोगिताकी आशा करता है। तीन रुमालों पर ८ आना प्रति रुमालकी दर अर्थात् 'म ल' मूल्य पर कुल व्यय डेढ़ रुपया अर्थात् 'म व' 'ग ल' हुआ। उपयोगिताके शब्दोंमें उसको डेढ़ रुपया देनेसे अपनेको 'म व ग ल' के बराबर उपयोगितासे वंचित करना पड़ा। परन्तु उसको तीन रुमालोंमें १ रुपया + १२ आने + ८ आने = सवा दो रुपया अथवा 'म व ग क य' क्षेत्रफलके बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। अतएव सवा दो रुपया - डेढ़ रुपया = १२ आने अथवा 'म व ग क य' - 'म व ग ल' = 'य क ग ल' क्षेत्रफलके बराबर उपभोक्ता की बचत हुई।



उपभोक्ताकी वचनको सख्याके रूपमें अथवा क्षेत्रफलके रूपमें प्रकट करनेमें कोई वास्तविकता नहीं है। हम जानतेहैं कि उपयोगिताकी सख्यामें माप नहीं हो सकती है। यह कहना कि उपयोगिता कम या अधिक है; एक बातहै और यह कहना कि उपयोगिता १०० है अथवा ५० है दूसरी बात है। इसी प्रकार उपयोगिताके आधारपर यह कहना कि वस्तुकी पहिली प्रतिके लिए कोई मनुष्य १० रुपये देनेको तत्पर है, दूसरीके लिए ६ रुपये इत्यादि औरभी भ्रम-मूलक है। समाजमें भिन्न भिन्न परिस्थिति, रुचि और आयके लोग रहते हैं, जिनके सम्बन्धमें किसीभी वस्तुकी भिन्न भिन्न प्रतिको उपयोगिताकी सख्यामें अथवा मूल्यके रूप में प्रकट करना असम्भव कार्य है। इसके अतिरिक्त किसी वस्तुके लिए कोई मनुष्य कितना द्रव्य देनेको तत्पर है, यह उस वस्तुकी स्थानापन्न वस्तुओकी उपस्थिति और उनके मूल्य परभी निर्भर रहता है। यदि भूखके निवारणके लिए केवल रोटीही एक वस्तुहो तो एक भूखा मनुष्य एक रोटीके लिए सब कुछ देनेके लिए तत्पर होसकता है। परन्तु पेट भरनेके लिए अन्य वस्तुओकी उपस्थिति में

उसकी यह भावना नहीं होगी। एक भूखा घनी मनुष्य एक रोटी के लिए १००० रुपये तक देनेको तत्पर होसकताहै परन्तु यदि रोटी १ आने को मिलती हो तो इस कथनको कि रोटीसे उसको ६६६ रुपये १५ आनेके बराबर उपभोक्ता की बचत हुई, व्यवहारिक ज्ञान माननेको हम तैयार नहीं होसकते हैं। इस प्रसंगमें हम यहभी बतला देना चाहतेहैं कि हम मागकी रेखाको उन मूल्योके सम्बन्धमें नहीं बना सकेहैं जो व्यवहारमें कभी रहती नहीं। अर्थात् यदि रोटीका मूल्य १००० रुपये प्रति रोटीहो तो कितनी माग होगी, यह आपको बतलाना असम्भव बात है। जो चलने मूल्यहै उन्ही के सम्बन्धमें मागका परिमाण बतलाया जासकता है। इसीप्रकार एक भूखे आदमीको पहिली रोटीसे बेहिसाब उपयोगिता मिलती है। अतएव किसी वस्तुको मोल लेनेसे प्राप्त उपभोक्ताकी बचतको निर्धारित करना असम्भव होजाता है।

तटस्थ रेखाएं

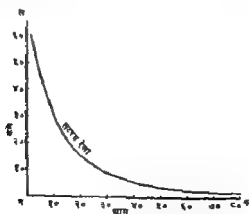
उपयोगिता का दोष

उपयोगिताका उपयुक्त माप न होनेके कारण तटस्थ रेखाओं द्वारा माग और माग के नियमोंका अध्ययन किया जाने लगा है। इन रेखाओंके जन्मदाता तो एजवर्थ थे परन्तु अर्थशास्त्रमें इनका प्रयोग पैरेटो और हिक्सने किया है।

एजवर्थ ने इन रेखाओंकी परिभाषा इस प्रकारकी है; तटस्थ रेखा वह पथ है जिसपर चलनेसे एक वस्तुके स्थानपर दूसरी वस्तुको किसीभी प्रकार और किसी भी मात्रामें प्रयोगमें लानेमें व्यक्ति विशेषको प्रत्येक स्थितिमें समान ही तृप्ति प्राप्त होती है। तटस्थ रेखा बनानेके लिए हमें तटस्थ तालिकाकी आवश्यकता पड़ती है। वह इसप्रकार बनायी जासकती है। मान लीजिए मेरे पास १०० ग्राम और आपके पास कुछ केले हैं। आप मुझे अपने भण्डारमें से केले उठानेकी आज्ञा देते हैं, किन्तु एक प्रतिबन्ध लगाकर। आपके भण्डारसे मैं केले तभी ले सकूंगा जब उन्हें अपनेलिए उपयोगी समझूंगा। आपका प्रतिबन्ध केवल इतना है; 'केले चाहे जितने उठाओ परन्तु उनके समान उपयोगिता जितने आपसे तुम्हें मिलती है, उतने ग्राम मेरे भण्डार में रख दो।' मानलिया कि पहिला केला उठाकर मैंने २० ग्राम रख दिये। दूसरा उठाकर १६, तीसरा उठाकर १०, फिर दो उठाकर १२ इत्यादि। स्पष्ट है कि इस प्रकारके जितनेभी विनिमय होंगे उनके बाद प्रत्येकबार मेरेपास जितनेभी ग्राम और केलोंके समूह होंगे, उनसे कुल मिलाकर मुझे समान ही तृप्ति प्राप्त होती रहगी क्योंकि ग्रामोंके रूपमें हम प्रत्येकबार जितनी उपयोगिता देते हैं, केलोंके रूपमें ठीक उतनीही हमें मिलजाती है। पृष्ठपर एक तटस्थ तालिका दीगयी है:

ग्राम	+	० केले
१००	+	०
८०	+	१
६४	+	२
५४	+	३
४२	+	४
३३	+	५
२९	+	६
२६	+	७
२२	+	८
१९	+	९
१६	+	१०
१२	+	११
९	+	१२
७	+	१३
५	+	१४
३	+	१५
१	+	१६

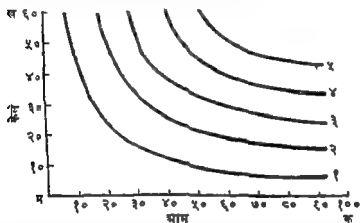
हर पन्तिमें दिये गये ग्रामों और केलोंके समूहसे हमें एकही जैसी तृप्ति प्राप्त होती है। इन समूहोंको हम अपने ज्यामितिज्ञान द्वारा रेखांकित कागजपर इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं।



इस रेखाचित्रमें 'म, क' और 'म, ख' प्रधान रेखायें हैं जोकि एक दूसरे पर 'म' बिन्दुपर समबल बनाती हैं। 'म' बिन्दुको आरम्भ स्थान कहते हैं। और 'म, क' रेखापर ग्राम दिखाये गये हैं और 'म, ख' रेखापर केल।

तटस्थ रेखा का आकार

इस प्रकार ऊपर दिखाये गये प्रत्येक समूहके लिए हमें एक बिन्दु प्राप्त होगा। इन सब बिन्दुओं से होकर जानेवाली बक्ररेखा का नाम तटस्थरेखा है। आरम्भमें १०० ग्रामोंके हमारे पास होनेसे हमें एक तटस्थरेखा प्राप्त होती है। यदि आरम्भमें हमारे पास १०० ग्राम न होकर ८० ग्रामही होते तो दूसरी तटस्थरेखा बनती जो पहिली रेखाके बायीं ओर नीचे होती तथा १२० ग्राम होनेसे तीसरी और पहिली से ऊची। इस प्रकार बहुतसी रेखाओंके समूहसे हमें एक तटस्थ रेखाचित्र प्राप्त होता है। उसका आकार प्रकार निम्नांकित होगा :



ये रेखाएँ आरम्भ स्थान 'म' की ओर उभरी हुई रहती हैं। ऊची और दायी ओरकी रेखाएँ उन समूहोंकी छोटक हैं जिनकी उपयोगिता नीची और बायी ओर की रेखाओं द्वारा छोटक समूहोंसे अधिक है।

नीची रेखासे चाहे हम दायी ओर बढ़ें, चाहे ऊपरकी ओर, हम एक ऊची रेखापर पहुँच जायेंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि एकवस्तु तो हमारे पास वैसीकी वैसी रहे, परन्तु दूसरी हमें और मिलजाये तो हमें अधिक तृप्ति प्राप्त होगी। उदाहरणके लिए ऊपर दी गयी तालिकाके अनुसार ३३ ग्राम और ८ केलोके समूह के स्थानपर यदि ३३ ग्राम और १० केलो तो इस समूहसे हमें पहिले समूहकी

अपेक्षा अधिक तृप्ति प्राप्त होगी। इन रेखाओंका समानान्तर होना आवश्यक नहीं है।

पैरटो का विचार था कि उपयोगिताको काममें लायेबिना तटस्थ रेखाओंकी सहायतासे मापका पूरा सिद्धान्त खड़ा किया जासकता है परन्तु आर्थिक सिद्धान्तकी व्याख्या करते समय वह स्वयं उपयोगिताको मापी जासकने वाली वस्तु ही मानता रहा। हिक्सने पैरेयेके इस विचारको कार्यरूपमें परिणत करनेका प्रयत्न किया है।

स्थानापन्नता की दर

इतनातो कहनेमें आपत्ति नहीं कि उपभोक्ता वस्तुओंके एक समूहकी दूसरे समूहसे वाछनीय समझता है। कितना वाछनीय समझता है, इससे हमारा प्रयोजन नहीं। इस सिद्धान्तके लिए इतनाही कहना पर्याप्त है कि वह अधिक वाछनीय समझता है। वस्तुओंके समूहकी सीमान्त इकाई वह होती है जिसकी प्राप्ति या हानिपर विचार किया जा रहा हो। जब किसी समूहसे एक वस्तुकी इकाईया निकालकर दूसरी वस्तुकी इकाईयांको रखा जा रहा होता है तब हम पहिली वस्तुके स्थानपर दूसरी वस्तुको स्थानापन्न करना चाहते हैं। स्थानापन्नताकी दरसे हमारा तात्पर्य पहिली वस्तुकी उसती इकाईयांसे है जिनके स्थानपर दूसरी वस्तुकी एक इकाईको स्थानापन्न किया जाता है। हमारी तटस्थ तालिकामें हमारे पास ८० ग्राम और १ केला था। उसके उपरान्त हमें १६ ग्राम देकर १ केला मिला। सीमान्त स्थानापन्नताकी दर १६-१ हुई तदनन्तर हमें १० ग्राम देकर १ केला मिला तब सीमान्त ग्रामोंके स्थानापन्नताकी दर १०-१ हुई। फिर दो स्थानमें १२ केले मिले अतएव सीमान्त स्थानापन्नताकी दर ६-१ हुई। इसके बाद ३-१ इत्यादि।

इस दरका एकगुण यह है कि यह ठीक उसीप्रकार घटती जाती है जैसे कि सीमान्त उपयोगिताका क्रमचः ह्रास होता चला जाता है। यदि हम उपयोगिताको भली-प्रकार मापनेमें असमर्थ हैं तो सीमान्त उपयोगिताको मापनाभी हमारे सामर्थ्य में नहीं है। परन्तु दो वस्तुओंकी सीमान्त उपयोगिताओंको पृथक् पृथक् मापनेमें असमर्थ होने पर भी उनके पारस्परिक अनुपातको ठीक प्रकारसे मापनेका तटस्थ रेखाओंद्वारा एक ढंग है।

सीमान्त उपयोगिताओं का अनुपात

मान लीजिए हमारे पास 'क' और 'ख' दो वस्तुओं का एक समूह है और इस समूह से हमें कुछ उपयोगिता मिल रही है। हम 'क' की कुछ इकाइयों के स्थान पर 'ख' की कुछ इकाइयाँ लेना भी चाहते हैं परन्तु इस प्रकार कि 'क' की इकाइयाँ देकर हमें उपयोगिता की जितनी हानि हुई वह सब 'ख' की इकाइयों से पूरी हो जायेगी अर्थात् हमें मिलने वाली उपयोगिता में इस बदल-बदल के कारण हानि न हो या यो कह लीजिए कि इस बदल-बदल के होने हुए भी हम एक ही तटस्थ रेखा पर ऊपर नीचे होने रहें। इस लेन देन में हमें उपयोगिता का कुल लाभ 'ख' की कुल प्राप्त इकाइयाँ \times 'ख' की सीमान्त उपयोगिता होंगी और उपयोगिता की कुल हानि 'क' की कुल दी गयी इकाइयाँ \times 'क' की सीमान्त उपयोगिता होगी। यह हानि-लाभ परस्पर बराबर होना चाहिए। इस सम्बन्ध को नीचे दिये समीकरण द्वारा दिखाया गया है:

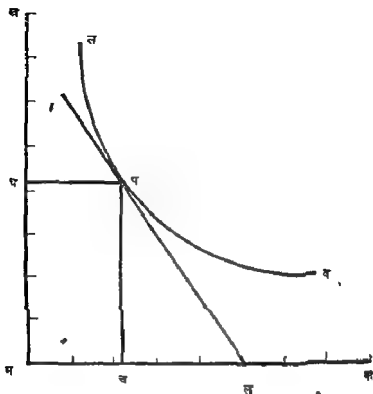
'ख' की प्राप्त इकाइयाँ \times 'ख' की सीमान्त उपयोगिता =

'क' की दी हुई इकाइयाँ \times 'क' की सीमान्त उपयोगिता

$$\text{अथवा } \frac{\text{'क' की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{'ख' की सीमान्त उपयोगिता}} = \frac{\text{'ख' की प्राप्त इकाइयाँ}}{\text{'क' की दी गयी इकाइयाँ}}$$

तटस्थ रेखा की स्पर्शरेखा और उसका ढलान

इस प्रकार सीमान्त उपयोगिताओं के पारस्परिक अनुपात को ठीक प्रकार से मापने का एक ढंग हमें प्राप्त हो जाता है। इस अनुपात को तटस्थ रेखा द्वारा दिखाने का भी एक ढंग है। मान लीजिए 'ल' 'व' एक तटस्थ रेखा है। इस रेखा पर 'प' कोई बिन्दु ले लीजिए। इस बिन्दु से मुख्य रेखाओं पर 'प', 'च' और 'प', 'घ' दो लम्ब खींचिये। 'प', 'ल' रेखा इस प्रकार खींचिए कि वह तटस्थ रेखा को 'प' बिन्दु पर केवल स्पर्श ही करे, जैसा कि पृष्ठ पर के चित्र में दिखाया गया है:



तब जिससमय किसी व्यक्ति के पास 'क' की 'प, घ' मरदा 'म, च' मात्रा और 'ख' की 'प, च' मात्रा हो तो.

$$\frac{\text{'क' की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{'ख' की सीमान्त उपयोगिता}} = \frac{\text{'प, च'}}{\text{'म, च'}}$$

इस अनुपातको 'प ल' रेखाकी ढलान कहा जाता है और यह ढलान ज्यामिति के नियमों के अनुसार भलीप्रकार मापा जा सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि पृथक सीमान्त उपयोगिता के स्थान पर उन दोनों के अनुपातको केवल अनुमानसे ही नहीं प्रत्युत गणित शास्त्र के नियमों के अनुसार भलीप्रकार मापा जा सकता है।

इस प्रकार तटस्थ रेखा, किसी बिन्दु पर उसकी ढलान और सीमान्त स्थानापन्नता की दर की महायता में उपयोगिता, सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता के ह्रास नियम के बिना ही माग के सिद्धान्त को खड़ा किया जा सकता है।

आय रेखा

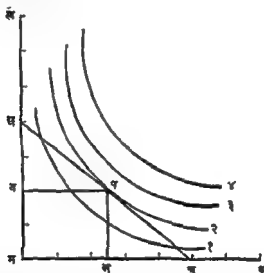
मान लीजिए कोई उपभोक्ता अपनी कुल आय केवल दो वस्तुओं 'क' और 'ख' पर व्यय करता है और निम्नलिखित बातोंसे परिचित है :

(१) तटस्थ रेखाचित्र, जो नीचे दिखाया गया है।

(२) कुल आय।

(३) 'क' और 'ख' का बाजार-मूल्य।

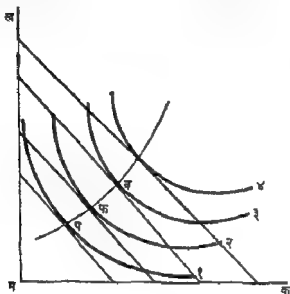
इस आयसे वह उपभोक्ता 'क' और 'ख' को किस मात्रामें खरीदेगा हम 'क' और 'ख' की उपयोगिताको जाने बिनाही मालूम कर सकते हैं।



मान लीजिए उपभोक्ता अपनी कुल आयसे केवल 'क' की 'म, व' मात्रा खरीद सकता है और केवल 'ख' की 'म, व' मात्रा। 'व, व' को मिलानेसे जो रेखा प्राप्त होगी वह चित्रकी किसी एक तटस्थ रेखाको केवल स्पृशं ही करसकेगी। मान लीजिए 'व, व' रेखा तटस्थ रेखा २ को 'प' पर स्पृशं करती है। 'प' से मुख्य रेखाओपर 'प, ल' और 'प, व' लम्ब खींचिये। तब अधिकसे अधिक उपयोगिता प्राप्त करनेके लिए वह व्यक्ति 'क' को 'प, व' अथवा 'म, ल' मात्रा और 'ख' की 'प, ल' अथवा 'म, व' मात्रा खरीदेगा। 'व, व' रेखाको आयरेखा कहा जाता है।

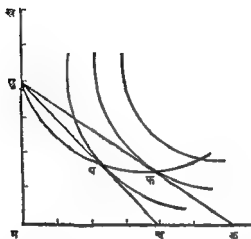
आय-उपभोग रेखा

अब मान लीजिए, उस व्यक्तिकी आयमें क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। यदि बाजार भाव वैसेही रहें तो 'प' बिन्दु क्रमशः ऊँची तटस्थ रेखाओंपर चला जायेगा। निम्न चित्रमें तटस्थ रेखा २ और ३ पर 'क' और 'ब' इस प्रकारके बिन्दु हैं, जिनको मिलाने से 'प, क, ब' जो रेखा प्राप्त होगी, उसे आय-उपभोग रेखा कहते हैं:



मूल्य-उपभोग रेखा

अब मान लीजिए कि उपभोक्ताकी आय और 'ख' वस्तुके बाजार भावमें कोई अन्तर नहीं हुआ है परन्तु 'क' वस्तुका बाजार भाव गिर गया है अब वह अपनी कुल आयमें 'ख' वस्तुकी तो पूर्ववत् मात्रा खरीद सकता है पर 'क' वस्तुकी पहिले से अधिक। आय रेखाभी पहिलेसे अधिक ऊँची तटस्थ रेखाको स्पर्श करेगी और जैसे जैसे 'क' का भाव गिरता जायेगा वैसे वैसे आयरेखा ऊँची ऊँची तटस्थ रेखाओंको स्पर्श करती चली जायेगी। यही बात सामनेके चित्रमें दिखायी गयी है :



‘घ, प, फ’ इत्यादिको मिलानसे प्राप्त होनेवाली रेखाको मूल्य-उपभोग रेखाके नामसे पुकारा जाता है। हमने अबतक केवल दो वस्तुओं ‘क’ और ‘ख’ पर विचार किया है। यदि ‘क’ के प्रतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओंके बाजारभाव निश्चित रहें तो ‘ख’ वस्तु अन्य वस्तुओंका प्रतिनिधित्व कर सकती है और ‘ख’ का स्थान सामान्य क्रय-शक्ति लेसकती है। तटस्थरेखा तब अन्य सब वस्तुओंके स्थानपर ‘क’ की स्थानापन्नता दरकी द्योतक होजाती है और मूल्य-उपभोग रेखा ‘क’ की माग रेखाका रूप धारण करलेती है।

स्थानापन्नता की लोच

तटस्थ रेखाके प्रत्येक बिन्दुपर ‘क’ और ‘ख’ वस्तुओंमें एक विशेष अनुपात होता है। जब हम ‘क’ की थोड़ी मात्राके स्थानपर ‘ख’ की थोड़ी मात्राको स्थानापन्न करते हैं तो इस अनुपातमें परिवर्तन आजाता है और स्थानापन्नताकी दरमें भी। वस्तुओंके पारस्परिक अनुपातमें होनेवाले परिवर्तनकी मात्राको यदि हम सीमान्त स्थानापन्नताकी दरमें होनेवाले परिवर्तनकी मात्रासे भाग दें तो हमें उस विशेष बिन्दुपर ‘क’ के स्थानपर ‘ख’ का प्रतिस्थापन करनेकी स्थानापन्नताकी लोच प्राप्त होती है। उदाहरणके लिए नीचे दीगयी तालिकाका पाचवा समूह देखिए। इसमें

४२ ग्राम और पांच केले हैं। केले और आमोका अनुपात ५:४२ हुआ और सीमान्त स्थानापन्नताकी दर १:३ हुई। अब एक केलेके स्थानपर एक आम लीजिए। इस हिसाबसे नया अनुपात ४:४३ होजाता है और नयी सीमान्त स्थानापन्नताकी दर १:११ हुई।

इसप्रकार वस्तुओंके पारस्परिक अनुपातमें परिवर्तन

$$= \frac{५}{४२} - \frac{४}{४३} = \frac{४७}{१८०६}$$

सीमान्त स्थानापन्नताकी दरमें परिवर्तन

$$= \frac{१}{३} - \frac{१}{११} = \frac{८}{३३}$$

स्थानापन्नताकी लोच

$$= \frac{४७}{१८०६} - \frac{८}{३३}$$

$$= \frac{४७}{१८०६} \times \frac{३३}{३३}$$

$$= \frac{५१७}{४८१६}$$

$$= १(\text{लगभग})$$

बाज़ार

बाजारों के प्रकार

साधारण बोलचालमें बाजारसे हमारा अभिप्राय उस स्थानसे होता है जिस स्थान पर किसी वस्तु अथवा वस्तुओंके खरीदने तथा बेचनेवाले एकत्रित होते हैं जैसे फलबाजार' सब्जीमंडी इत्यादि। अर्थशास्त्रमें बाजार किसी विशेष स्थानको नहीं कहते बल्कि कूर्मा के अनुसार पृथ्वीका कोईभी छोटा या बड़ा भाग जिसपर खरीदने और बेचनेवाले इस प्रकार परस्पर व्यवहार कर सकते हैं कि एकही प्रकारकी वस्तुओंके मूल्य एकसे ही होते चले जायें, बाजार कहा जासकता है। बाजारोंका उनके विस्तारके अनुसार वर्गीकरण किया जासकता है, जैसे प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार। बाजारोंमें जिन वस्तुओंका क्रय-विक्रय होता है, उनके अनुसारभी वर्गीकरण किया जासकता है। जैसे गहूका बाजार, श्रमका बाजार, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार, पूँजीका बाजार, जायदाद का बाजार इत्यादि।

बाजार शुद्ध अथवा अशुद्धभी होसकते हैं। शुद्ध बाजारसे हमारा अभिप्राय उस बाजारसे है जिसमें:

- (१) प्रत्येक ग्राहक और विक्रेता बाजार भावसे भलीभांति परिचिन होता है।
- (२) कोई भी ग्राहक किसीभी विक्रेतासे वस्तु खरीद सकता है।
- (३) कोईभी विक्रेता किसीभी ग्राहकको वस्तु बेच सकता है। ऐसी स्थिति में बाजारके पूरे विस्तारपर उस वस्तुका एकही मूल्य होनेकी प्रवृत्ति होगी। कारण यह है कि यदि कोईभी विक्रेता इससे कम मूल्यपर बेचनेके लिए तैयार हो तो सबके सब ग्राहक उसीसे खरीदेंगे, जबतक कि उसका वस्तुसंग्रह समाप्त नहीं होजाता अथवा वह फिर वस्तुका मूल्य नहीं बढ़ा देता अथवा दूसरे विक्रेताभी मूल्य घटाकर उसके तुल्य नहीं कर देते। इसी प्रकार यदि कोई विक्रेता अधिक

मूल्य लेनेकी चेष्टा करताहै तो उसके पास कोई ग्राहक न आयेगा, जबतक कि दूसरे विक्रेताओमे वस्तु नम मूल्यपर मिल सकती हो।

बाजारको अशुद्ध उससमय कहा जाताहै जबकि वतिपय ग्राहक या वतिपय विक्रेता या वतिपय ग्राहक तथा वतिपय विक्रेता बाजार नावमे अनभिज्ञ हो।

शुद्ध बाजार के लक्षण

शुद्ध बाजारके लिए आवश्यकहै कि उसमें नय-विक्रय-क्रिये जानेवाली वस्तुका भलीभांति वर्गीकरण किया जासके ताकि ग्राहको और विक्रेताओको सुगमतासे पता चलसके कि वे क्या खरीद अथवा बेचरहे हैं। यदि एकही वस्तुके दो भिन्न भिन्न वर्ग पृथक् पृथक् मूल्योपर विक्रे तो बाजार अशुद्ध नहीं होजाता वे दो नमूने वास्तवमें दो भिन्न वस्तुएं हैं। उदाहरणके लिए यदि कैप्स्टन और गोल्डफ्लैक सिगरेटके मूल्य बाजारमें अलग अलग हो तो इससे परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि सिगरेटका बाजार अशुद्धहै क्योंकि ये दो प्रकारकी सिगरेटें वास्तवमें दो भिन्न वस्तुएं हैं। वर्गीकरण ग्राहक और विक्रेता दोनोंके लिए लाभदायक होता है और बाजारको विस्तृत करनेमें सहायता देता है। वर्गीकरण द्वारा भविष्य के दिन लानेकी सौदे बरजेमें भी सुगमता प्राप्त होती है। बाजारकी शुद्धताके लिए यातायात और पत्र-व्यवहार इत्यादिके समुचित साधन होनाभी अत्यन्त आवश्यक है। इनसे बाजारकी स्थितिका ग्राहका और विक्रेताओको पता चलता रहता है। टेलीफोन, तार, रेडियो आदि भाविष्कारोके कारण इन साधनोमें बहुत उन्नति हुई है। और इसी प्रकार मोटर, रेल, जहाज इत्यादि यातायातके साधनोमें उन्नतिके कारण बाजार विस्तृत होगये है। विशेषकर कच्चे माल, प्रवाज इत्यादिके बाजारो का अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार होचुका है।

शुद्ध बाजारके लिए यहभी आवश्यक है कि मूल्य प्रतिस्पर्धा द्वारा निश्चित हो। अर्थात् वस्तुओको एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जानेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु यदि कर लगानेपर भी किसी वस्तुका कर लगानेवाले देश अथवा प्रान्तमें आयात होता रहे, तो वह देश अथवा प्रान्त उन वस्तुके बाजारका भाग बना रहता है। करके कारण ऐसे देश अथवा प्रान्तमें वस्तुका मूल्य अवश्य

अधिक होमा परन्तु यदि किसी कारणसे वस्तु भंजनेवाले देशमें उसका मूल्य गिर जाताहै तो कर लगानेवाले देशमें वह वस्तु अधिक मात्रामें आने लगेगी और इस कारण वहाभी उस वस्तुका मूल्य गिरने लगेगा। परन्तु यदि उस वस्तुकी सख्या अथवा परिमाणपर नियन्त्रण लगादिये जायें तो नियन्त्रण लगानेवाला देश अथवा प्रान्त बाजारका भाग नहीं रहता। वह एक स्वतन्त्र बाजार बन जाताहै क्योंकि उस देश अथवा प्रान्तमें वस्तुके मूल्यका शेष ससारमें उसी वस्तुके मूल्यसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

शुद्ध बाजारके लिए यहभी आवश्यक समझा जाताहै कि वस्तुकी माग अथवा पूर्तिपर किसीभी प्रकारके नियन्त्रण नहीं होने चाहिए। परन्तु इसका यह अर्थ नहींहै कि मूल्यके कम या अधिक होनेके कारण विनेता अथवा ग्राहक वस्तुको बेचने अथवा खरीदनेके लिए विवश किये जायें। वस्तुका मूल्य घटानेकी इच्छा से मागको दबाये रखना अथवा उसका मूल्य बढ़ानेकी इच्छासे वस्तु को बेचने से इन्कार करना कृत्रिम साधन मानेजाते हैं।

शुद्ध बाजारके प्रत्येक भागमें वस्तुका एकमूल्य होनेसे अभिप्राय केवल वस्तु के वास्तविक मूल्यके एक होनेसे है। बाजारके विस्तृत होनेसे उत्पादनके स्थानसे उपभोगके स्थान तक ले जानेके लिये भाड़ा देना पड़ता है। उपभोगके स्थानोंके समीप अथवा दूर होनेके कारण भाड़ेके न्यूनाधिक होनेसे मूल्यमें अन्तर होसकता है। वस्तुतः स्थान-भेद एवं समय-भेदसे वस्तुही दूसरी होजाती है। स्थान-भेद होनेसे हमें उस वस्तुके मूल्यमें भाड़ा, बीमा, एक स्थानसे दूसरे स्थानतक ले जानेवाले आडतियाका लाभ इत्यादि जोड़ना पड़ता है और समय-भेद होनेसे संग्रहकर्ताका लाभ, संग्रह करने का व्यय इत्यादि जोड़ना पड़ता है।

बाजार का विस्तार

बाजारके विस्तृत एवं अन्तर्राष्ट्रीय होनेके लिए यह आवश्यकहै कि उसमें वे सब गुण उर्पास्यत हो जो एक शुद्ध बाजारमें होने चाहिए। परन्तु इसके अतिरिक्त ऐसे बाजारके लिए कुछ औरभी बातोंकी आवश्यकता है। सबसे पहिले तो यह आवश्यकहै कि उस वस्तुका व्यापार बड़े पैमानेपर होता हो। वस्तुकी वनावट और

शुणोमें भेद नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि ऐसा होनेपर वह वस्तु यद्यपि एकही आवश्यकताको सन्तुष्ट करती हो, परन्तु अपने विभिन्न स्वहोके कारण प्रत्येक देश एवं प्रान्तमें उसका भिन्न भिन्न बाजार होगा। इसीलिए यदि एकही प्रकारकी वस्तुओंमें उत्पादक किन्तीभी व्यापार-चिन्ह इत्यादि द्वारा उपभोक्ताओं के मतमें अन्तर उत्पन्न करनेमें सफल होजायें, तो आधुनिक अर्थशास्त्री उन्हें भिन्न वस्तुएँ मानेंगे। उनके अनुसार साबुन एक वस्तु नहीं है, जितनेभी प्रकारके साबुन बाजारमें मिलते हैं, वे भिन्न वस्तुएँ हैं। यही कारण है कि कच्चे मालका विस्तार तो अन्तर्राष्ट्रीय होता है परन्तु अर्थनिर्मित वस्तुओंके बाजारका विस्तार उनसे कम और पूर्ण निर्मित वस्तुओंका उनसे भी कम होता है। इसका कारण यह है कि विज्ञेता कच्चे मालकी अपेक्षा पूर्णनिर्मित अथवा अर्थनिर्मित वस्तुओंके सम्बन्धमें ग्राहकोंके मनमें विज्ञापन, व्यापार-चानुर्ध्वं, व्यापार-चिन्ह इत्यादि प्रकारोंमें पृथक्त्वका भाव उत्पन्न करनेमें अधिक सफल होते हैं।

यदि वस्तुको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर भुगमतासे लेजाया जासकता है तो भी उसका बाजार विस्तृत होता है। भारी बोझवाली भीर कम मूल्यवाली वस्तुओंके बाजार प्रायः सकुचित होते हैं। उदाहरणके लिए कोयले और कच्चे लोहेका मूल्य डमकी तोलके हिमावसे बहुत कम होता है। अतएव उनको दूर ले जानेके भाड़ेसे बचनेके लिए इनसे सम्बद्ध उद्योग घघोंको ही ऐसे स्थानोंपर खोलते हैं, जहाँ इनकी खानें पायी जाती हैं। एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जानेकी सुगमता वस्तु विशेष, कितना स्थान घेरती है, इस बात पर निर्भर है। मैज-कुसियो आदिके बाजार प्रायः विस्तृत नहीं होते क्योंकि ये वस्तुएँ रेलगाड़ी, जहाज आदि में बहुत जगह घेरती हैं। और इसकारण भाड़ा बहुत देना पड़ता है।

विस्तृत बाजारके लिए वस्तुका चिरस्थायी होनाभी आवश्यक है। फल, फूल, तरकारी इत्यादि वस्तुएँ बहुत शीघ्र सड़-गल जाती हैं। अतएव माधारणतः उत्पादनके स्थानके आस-पासही इनका बाजार सीमित रहता है। परन्तु वैज्ञानिक साधनों द्वारा इस प्रकारकी नाशवान वस्तुओंकी सुरक्षित रखनेके दग निकाले जा रहे हैं। फल, मास, मछली, दूध तथा दूधमे प्राप्त होनेवाली अन्य चीजोंको इन साधनों द्वारा सुरक्षित करके दूरदूर तक भेजाजाता है। परन्तु यहाँ इतना कह देना उचित होगा कि ये साधन इस प्रकारकी अनेक वस्तुओंको उपभोक्ताओंकी दृष्टिमें

कोई दूसरीही वस्तु बना देते हैं। उदाहरणके लिए, जमा हुआ दूध या मास, ताजे दूध या माससे सर्वथा भिन्न वस्तु है। बैंक तथा साखपत्रोंके विकासमें और तोल-मापके साधनोंके प्रमाणीकरणसे भी बाजारके विस्तृत होनेमें सहायता प्राप्त हुई है।

श्रम-बाजार

श्रमके बाजारभी नाशवान् वस्तुओंके बाजारके समान अत्यन्त सकुचित होते हैं। वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रकारके श्रमके लिए भिन्न भिन्न बाजार होते हैं। विशेषकर कुशल श्रमके बाजार तो भिन्न होते ही हैं। अकुशल श्रमके लिए भलेही एक बाजार होता हो, परन्तु श्रमजीवी प्रायः एक स्थानसे दूसरे स्थानको जानेमें हिचकिचाते हैं। यद्यपि यातायातके साधनोंमें उन्नति होनेके कारण श्रमजीवियोंके स्थान परिवर्तनके सम्बन्धमें गति शीलता बहुत बढ़ चुकी है, फिरभी श्रमके बाजार बहुत विस्तृत नहीं हो पाये हैं। श्रमके बाजारोंके अशुद्ध होनेका कारण यह है कि श्रम एक अत्यन्तही नाशवान् वस्तु है। यदि एक दिनभी श्रम नहीं किया जाता तो वह सदैवके लिए नष्ट हो जाता है। श्रमजीवीकी इस स्थितिके कारण एकही प्रकारके श्रमका एकही बाजारमें एकमूल्य नहीं होता और पहिले बताया जा चुका है कि शुद्ध बाजारके लिए एक वस्तुका एकही मूल्य होना अत्यन्त आवश्यक है।

बाजारों की व्यवस्था

बाजारोंकी व्यवस्थाके विषयमें ध्यान देनेकी बात है कि इस व्यवस्थामें दलालों और सट्टेवालोंको बहुत महत्व प्राप्त है। वस्तुओंकी निर्माण-विधिकी कई भागोंमें बाटा जा सकता है। कृषि द्वारा अथवा खानोंसे निकालकर कच्चा माल प्राप्त होता है। फिर उद्योग-धंधों द्वारा इस कच्चे मालसे उपयोगके योग्य वस्तुएँ निर्माणकी जाती हैं। फिर इन निर्मित वस्तुओंको उपभोक्ताओं तक पहुँचानेका प्रबन्ध किया जाता है। प्राचीन कालमें जब वस्तुएँ कम मात्रामें तैयार होती थी, तो एकही मनुष्य स्वयं ही कृषक, उद्योगपति और उपभोक्ता हो सकता था। ऐसी परिस्थिति में उत्पादनके एक विभागसे दूसरे विभागमें जातेके लिए विशेष अङ्गजनों की आवश्यकता नहीं थी। श्रम-विभाजन तथा वस्तु-निर्माण-विधिमें उन्नति होनेके कारण ऐसे लोगोंकी

आवश्यकता हुई जो वस्तुको उत्पादकसे उपभोक्ता तक पहुँचानेका प्रबन्ध करे। ये लोग व्यापारी, दलाल इत्यादि हैं। साधारणतः यह समझा जाता है कि इस प्रकारके लोग अथवा सस्थाएँ आर्थिक दृष्टिसे आवश्यक नहीं हैं। इनका काम केवल इतना है कि उत्पादकको मिलनेवाले मूल्य और उपभोक्ता द्वारा दियेगये मूल्यमें अधिकसे अधिक अन्तर डाल दें परन्तु इस प्रकारके विचारमें कोई सार नहीं है। ये व्यापारी और दलाल उत्पादन-वृद्धि के आवश्यक अंग हैं। उत्पादनके एक विभागसे दूसरे विभागमें वस्तुओंका पहुँचाना इनका विशेष कार्य है। इस कार्यके विशेषज्ञ होनेसे ये लोग इसको अधिक कुशलतासे कर पाते हैं। इनके न होनेपर बड़े परिमाणमें उत्पत्तिका होना असम्भव होजाता है। सम्भव है बहुतसे व्यापारी और दलाल निरर्थक हों, उनके न होनेसे उत्पत्तिमें तनिकभी बाधा न पड़तीहो और उनके होनेसे उपभोक्ताओंको अकारणही उपभोगकी वस्तुओंका अधिक मूल्य देना पड़ता हो, पर इस दोषका आरोपण उनके अस्तित्व पर नहीं, बाहुल्य पर किया जासकता है। आजकल बड़ी बड़ी सस्थाएँ कच्चे मालकी खरीद और निर्मित वस्तुओंकी बेचका कार्य इन लोगों द्वारा करानेके स्थानपर स्वयंही करलेती हैं। परन्तु ऐसी सस्थाओंकी सत्यां समार भरमें बहुत थोड़ी हैं।

सट्टा

इसीप्रकार सट्टा करनेवालेभी इतने धृणाके पात्र नहीं जितना कि हम उन्हें समझते हैं। मच बातनी यह है कि माधुनिक उत्पादन-विधिकी नींवही सट्टा है। वस्तुओंकी मांगके अनुमानके आधारपर उत्पादन-क्रिया प्रारम्भ होती है। उद्योगपति जनताकी आवश्यकताओं का अनुमान करके ही ऐसी वस्तुएँ निर्माण करता है, जो उसके विचारमें जनता द्वारा उपभोगकी जायेंगी। ऐसी वस्तुओंकी सख्या अथवा मात्राका भी पहिलेसे ही वह अनुमान करलेता है। कभी कभी तो वह नितान्त नयी वस्तुएँ इस आशासे निर्माण कर बैठताहै कि उनके बाजारमें आनेपर उनके लिए माग पैदा होजायेगी। यह सब सट्टा नहीं तो और क्या है। परन्तु इस सट्टेकी जोखिम आज-कल केवल उत्पादककी ही नहीं उठानी पड़ती बल्कि व्यापारी और सट्टेवाज लोग उसकी सहायता करते हैं।

सट्टेके कार्यका सर्वोत्तम लाभ यहहै कि इस क्रिया द्वारा वस्तुओंके मूल्यमें

स्थिरता बनी रहती है; अधिक अस्थिरता नहीं होने पाती। ये लोग जब किसी वस्तुकी पूर्तिमें ग्यूनता और उसके कारण उसके मूल्य बढ़नेका अनुमान लगाते हैं तो उम वस्तुके पहिलेही भविष्यमें खरीदनेके सौदे करना आरम्भ कर देते हैं। इसप्रकार मागमें वृद्धि होनेके फलस्वरूप उस वस्तुका मूल्य वर्तमानमें ही बढ़ना आरम्भ होजाता है और उसमें आकस्मिक वृद्धि नहीं होपाती। इसी प्रकार जब ये लोग किसी वस्तुके मूल्यके गिरनेका अनुमान लगातेहैं तो उस वस्तुके भविष्यमें बेचनेके सौदे करलेते हैं। उनके इस कार्य द्वारा, पूर्तिमें वृद्धि होनेके कारण उस वस्तुका मूल्य वर्तमानमें ही गिरना आरम्भ होजाता है। उदाहरणके लिए मान लीजिये कि गेहूँका वर्तमान भाव १५ रुपये प्रतिमन है और सट्टा करनेवालो ने अपने अनुभव और निपुणताके आधारपर यह अनुमान किया कि सप्ताहके प्रसिद्ध गेहूँ उत्पन्न करनेवाले प्रदेशोंमें किसी प्राकृतिक सकटके कारण गेहूँकी उत्पत्तिके परिमाणमें कमी आनेकी और फलस्वरूप उसका मूल्य १७ रुपये प्रतिमन होनेकी सम्भावना है। ऐसी परिस्थितिमें वे सट्टेवाले लोग जो चढ़ते बाजारसे लाभ कमानेकी चेष्टा करतेहैं, गेहूँके वर्तमान मूल्यपर भविष्यमें गेहूँ खरीदनेके लिए अपनेको समनुबद्ध करलेते हैं। इनकी इस प्रकारकी मागमें वृद्धिके कारण गेहूँके मूल्यमें वर्तमान कालसे ही वृद्धि होने लगती है। यदि इन लोगोंका अनुमान ठीक निकला और गेहूँका मूल्य समनुबद्ध अवधिकी समाप्ति पर १७ रुपये प्रतिमन हो गया तो सट्टेवाले पूर्व निर्धारित मूल्य १५ रुपयेके भावसे गेहूँ मोल लेकर १७ रुपये प्रतिमनके हिसाबसे बेचकर २ रुपये प्रतिमन लाभ कमा लेते हैं। इस प्रकरणमें हम यहभी बता देना चाहतेहैं कि यह आवश्यक नहीं कि वस्तुतः गेहूँका हस्तान्तरण हो। ऐसा होसकता है और प्रायः होता भी है कि गेहूँके बिना बाजारमें भावेही २ रुपये प्रतिमनके हिसाबसे इन सट्टेवालोको रुपये मिल जायें।

इसीप्रकार यदि गेहूँका भाव भविष्यमें १५ रुपयेसे गिरकर १३ रुपये प्रतिमन होनेकी सम्भावना हो तो इस प्रकारके सट्टेवाले जो गिरते भावसे लाभ कमानेकी चेष्टा करते हैं, वर्तमान मूल्यपर भविष्यमें गेहूँ बेचनेके लिए अपनेको समनुबद्ध करलेते हैं। अवधि समाप्तिपर यदि भाव १३ रुपये प्रतिमन होगया तो वे इस भावपर गेहूँ मोल लेकर पूर्व-निर्धारित १५ रुपयेके हिसाबसे बेचलेते हैं और २ रुपये प्रतिमन लाभ कमा लेते हैं।

इस भावी त्रय-वित्रयसे उनका अभिप्राय तो होता है मूल्योंकी घट-बढ़से लाभ उठाना। परन्तु उनके इस स्वार्थ-सिद्धि के कार्यमें मूल्योंमें स्थिरता आजानी है और मारे समाजका बल्याण होजाता है। उत्पादकों तो विज्ञेय रूपसे इन लोगों द्वारा मेवा होती है। मूल्योंकी स्थिरता तो उत्पत्तिके लिए परमावश्यक है ही, पर ये लोग उसकी बहुत कुछ जोखिम अपने ऊपर ले लेते हैं। थोड़ा विक्रेता फुटकर विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओंकी मागका अनुमान लगाना है और उस अनुमानके आधारपर उत्पादकोंसे मास खरीदनेका सौदा करता है। इसीप्रकार उत्पादक इन लोगोंमें भविष्यमें कच्चा मान खरीदनेका सौदा करलेते हैं, जिसके कारण उन्हें वस्तु-निर्माणकी सामग्रीके मूल्यमें आकस्मिक अस्थिरताका भय नहीं रहता।

सट्टेका कार्य सदा अच्छा नहीं होता, विशेषकर अनभिज्ञ सट्टे वालोंका। सट्टे वालोंमें मूल्योंके घटने-बढ़नेका ठीक अनुमान करनेकी योग्यता होनी चाहिये। अन्यथा यदि उनके अनुमान संबंधी उन्हें निकलेंगे तो मूल्योंमें स्थिरताके स्थान पर और अधिक अस्थिरता आनेकी आशका होजायगी। सट्टे वालोंके पाम पर्याप्त पूँजीका होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि ऋणसोधनकी क्षमता नष्ट होनेसे अन्य लोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सट्टेका कार्य जब केवल लाभ उठानके उद्देश्यमें ही किया जाये, तो होसकता है वह समाजके लिए हानिकारक हो। कभी कभी ये लोग किसी वस्तुकी पूर्ति पर एकाधिकार जमानेके लिए उस वस्तुका खरीदने ही चले जाते हैं। इनकी इस कृत्रिम भागके कारण उस वस्तुके मूल्यमें कृत्रिम वृद्धि होती जाती है। यदि वह वस्तु जीवनके लिए आवश्यक वस्तुओंमें से हो, तो इस कृत्रिम मूल्य वृद्धि के कारण समाजकी कष्ट सहन करना पड़ता है।

प्रतिस्पर्धा

प्रतिस्पर्धा का अर्थ

प्रतिस्पर्धा का वर्तमान आर्थिक जीवनमें अत्यधिक महत्व है। प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थ-व्यवस्थामें सम्बन्ध रखती है। ऐसी अर्थ-व्यवस्थामें जिसमें उत्पादन केवल आवश्यकता-पूर्तिके लिए होता हो, प्रतिस्पर्धा का विकास असम्भव है। प्रतिस्पर्धा का अर्थ यह है कि वस्तुओं के क्रय-विक्रयमें प्रत्येक व्यक्ति को पूरा अधिकार और सुविधा हो कि वह चाहे जिससे सौदा निश्चित करे। पर प्रतिस्पर्धा की यह व्याख्या केवल आर्थिक दृष्टिकोणमें की गयी है। यह उस अवस्था की ओर संकेत करती है जिसमें प्रत्येक आर्थिक क्रियामें बहुतेमें व्यक्ति हों और प्रत्येक को अपने उद्देश्यों की इच्छित रीतिसे पूर्ण करने का उतनाही अधिकार हो जितना दूसरे को। इस प्रकार एक उत्पादक न होकर कई उत्पादक हों और प्रत्येक को अपनी इच्छानुसार मितव्ययी रीतिसे अपनी उत्पादन-योजना को पूरी करने का अधिकार और सुभीता हो। इसी प्रकार बाजारमें बहुतेमें विक्रेता और बहुतेमें ग्राहक हों और वे जहाभी अपना सार्वजनिक लाभ देखें, वही क्रय-विक्रय कर सकें। यही वास्तविक प्रतिस्पर्धा पद्धतिमें आय तथा उत्पादन सम्बन्धी सेवाओं के उपयोग के विषयमें भी ठीक है। श्रमिक इच्छानुसार जहाभी चाहे, नौकरी कर सकता है और उत्पादक अनेक श्रमिकोंमें से जिसको चाहे उत्पादनमें लगा सकता है। व्यक्तियों की आय भी इसी पद्धति पर निर्धारित होगी। कई प्रकार के उद्यमोंमें से जो जहापर जितना उपाजन करने, वही उसकी आय होगी अर्थात् आय व्यक्तियों की श्रम-शक्ति तथा अन्य गुणों पर निर्भर होगी। लेकिन इस श्रम-शक्ति और गुणों का मूल्य बाजारमें सापेक्षिक माग और पूर्ति द्वारा निश्चित होगा।

अर्थशास्त्रमें पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार की प्रतिस्पर्धा मानी जाती है। दो बातों के होनेसे प्रतिस्पर्धा पूर्ण मानी जाती है। पहिली यह है कि प्रतिस्पर्धा का मिद्धान्त

बाजारपर आश्रित है, इसलिए पूर्ण और स्वतन्त्र बाजार तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अनिवार्य आधार है। उत्पादन के साधनों तथा अन्य आर्थिक उपकरणों की गति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध न हो। दूसरी यह कि उद्योग संस्थाओं में अथवा उपभोक्ता वर्ग में कोई इतना बड़ा या प्रभावशाली न हो कि क्रय-विक्रय सम्बन्धी केवल उसके निश्चय का कोई प्रभाव प्रचलित मूल्यों पर पड़े।

पहली शर्त का अभिप्राय यह है कि गति स्वतन्त्र होने के कारण प्रत्येक अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार अधिक से अधिक आयवाला साधन प्राप्त कर सकता है। इसका यह भी अर्थ है कि प्रत्येक साधन निरन्तर विभाज्य हो नहीं तो उसका उपयोग अनेक प्रकार से नहीं हो सकेगा। इसीलिए एक उपयोग से दूसरे उपयोग में उसका स्थानान्तरण भी अत्यन्त कठिन होगा। गतिशीलता प्रतिबन्ध-रहित हो। यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा में आवश्यक इसलिए है कि बिना इसके सबको समान रूप से साधन प्राप्तिके लिए प्रयत्न करने का अवसर नहीं मिलेगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए यह भी आवश्यक है कि आर्थिक लाभ के अवसरों के सम्बन्ध में सभी प्रतिस्पर्धियों की जानकारी बराबर हो और उस जानकारी को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक है आर्थिक शक्त का समान रूप से वितरित होना।

दूसरी शर्त का अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रतिस्पर्धी के पास इतने अधिक साधन और अधिकार न हो कि या तो औरों को अपनी प्रतिस्पर्धा में आने ही न दे या उनके लिए प्रतिस्पर्धा की दशाएँ बदल दे। इसका यह अर्थ नहीं है कि माग और पूर्तिके सिद्धान्त काम न करे। मूल्य माग और पूर्ति पर ही आश्रित होगा और उपभोक्ताओं की माग में परिवर्तन तथा उद्योगपतियों की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप उसमें परिवर्तन भी होंगे पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी एक व्यक्ति की माग या पूर्तिके योग्यता के द्वारा उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको समान रूप से प्रयत्न करने का अवसर मिल सकता है अन्यथा अन्य लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा की दशाएँ और उनकी योग्यताएँ बदल जायेंगी। इसका फल यह होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में छोटे आकार की संस्थाएँ ही उचित होंगी।

पूर्ण प्रतिस्पर्धा का यह भी अर्थ हुआ कि प्रत्येक आयवाला व्यक्ति और उद्योगपति अपनी आय तथा उत्पादन के साधनों का चाहे जिस प्रकार उपयोग करे अथवा न करे किन्तु इन निश्चयों पर यदि किसी प्रकार के प्रतिबन्ध है तो प्रतिस्पर्धा अपूर्ण है।

यदि उत्पादन पूर्ण प्रतिस्पर्धाके आधारपर हो रहा है, तो उसका लक्षण यह होगा कि औसत व्यय और सीमान्त व्यय दोनों बराबर होंगे। इसका कारण यह है कि यदि किसी सस्याका सीमान्त व्यय औसत व्ययसे अधिक है तो कुछ अन्य व्यापारी कम मूल्यपर बेचना आरम्भ करेंगे और फिर सबको वही मूल्य मानना पड़ेगा। अन्ततोगत्वा ऐसी उद्योग-सस्या या तो सीमान्त व्यय कम करेगी या नष्ट हो जायेगी। परन्तु यदि सीमान्त व्यय औसत व्ययसे कम है तो उद्योग सस्याका प्रसार होगा और प्रतिस्पर्धाका नियम है कि कोई सस्या बड़ी नहीं हो सकती। यह नियम पूरा इसप्रकार होता है कि उत्पादन कार्य कम होनेके कारण उम उद्योगमें साधनों की माग बहुत अधिक हो जाती है और इसप्रकार व्यय बढ़ने लगता है। अन्तमें औसत व्यय सीमान्त व्ययके समान होनेपर ही पूर्ण आर्थिक व्यवस्था साम्यावस्था में होगी।

यह भी कहा जाता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मूलक अर्थ-व्यवस्थामें उपभोक्ताका प्रभुत्व होता है। ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रतिस्पर्धा मूलक व्यवस्थामें उत्पादन बाजारके लिए होता है। इसलिए उद्योगपतियोंके सारे निश्चय उपभोक्ताओंकी मागपर निर्भर रहते हैं। इसप्रकार अन्ततोगत्वा किम वस्तुका और किम परिमाणमें उत्पादन होगा, यह उपभोक्ताही निश्चित करता है और इस विषयमें उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है।

पूर्ण प्रतिस्पर्धा के फल

यदि औसत और सीमान्त आय बराबर हो तो पूर्ण प्रतिस्पर्धाका फल यह होगा कि सभी उद्योग-सस्याएँ सर्वोत्तम आकारकी होंगी। उत्पादक साधनाकी विभिन्न उपयोगोंमें वितरणकी प्रवृत्ति भी सर्वोत्तमताकी ओर होगी। इसप्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उत्पादन अधिक से अधिक हो सकता है। इसीप्रकार व्यय और मूल्यकी कमसे कम होनेकी प्रवृत्ति होगी।

सर्वाधिक उत्पादन होनेका कारण यह है कि उपभोक्ता पूर्ण प्रतिस्पर्धामें अपनी आयका वितरण समसीमान्त उपयोगिताके नियमानुसार करता है, इसलिए उपभोग के आधारपर साधन वितरण होनेके कारण प्रत्येक साधनका उभी उद्योगमें उप-

योग किया जाना है, जहाँ वह सबसे अधिक उत्पादक हो।

आधुनिक अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतिस्पर्धा को कल्पनामात्र ही मानते हैं। व्यवहार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अभाव है, क्योंकि हमकी बातें ऐसी हैं जो एक तो पूरी भी नहीं हो सकती और दूसरे वे परस्पर विरोधी हैं। सबकी जानकारी एक ही हो, गतिशीलता पर कोई प्रतिबन्ध न हो, साधन निरन्तर विभाज्य हों तो उत्पादन विस्तृत क्षेत्र पर करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। साधन भी निरन्तर विभाज्य हो ही नहीं सकते।

पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार

जब एक ही व्यक्ति अथवा उद्योग-संस्था उत्पादन और पूर्ण सम्बन्धी अपने निश्चयों द्वारा मूल्य में परिवर्तन कर सकती है अथवा मूल्य निर्धारित कर सकती है तो उसे एकाधिकार की अवस्था कहते हैं। यदि इस प्रकार की कई उद्योग संस्थाएँ हो और प्रतिस्पर्धा उनके बीच में हो तो उसे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा कहेंगे। जब बाजार अशुद्ध हो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बातें पूरी न हो रही हो तब हम उसे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा कहेंगे। एकाधिकारात्मक और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बहुत कुछ पर्याप्तता की बातें हैं और विद्वानों कुछ दिनांक इन दो शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। यद्यपि मतभेदों के प्रवर्तक अब इनमें भेद करने लगे हैं।

एकाधिकार हम अर्थ में कि केवल एक ही विनिर्माता अथवा उत्पादक हो और वह मनमाना मूल्य निश्चित कर, बहुत कम पाया जाता है। पूर्ण एकाधिकार उस अवस्थामें हो सकता है जब किसी वस्तु विशेष के स्थानापन्नों का पूर्णतया अभाव हो तथा वह लोगों के लिये अत्यन्त आवश्यक हो, ऐसा संयोग अलभ्य-सा है। सभी वस्तुओं की प्राप्ति सामान्ये अनन्त भागों में है और यातायात के साधन-सुलभ होने के कारण एक भाग की वस्तु का मूल्य दूसरे भाग के मूल्य से स्वतन्त्र नहीं रह जा सकता। फिर प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई स्थानापन्न मिल ही जाता है। इस कारण प्राकृतिक एकाधिकार कठिन है। कुछ वस्तुएँ अवश्य ऐसी हैं जो एक ही स्थान पर या कुछ थोड़े से स्थानों पर मिलती हैं पर उनकी स्थानापन्न वस्तुएँ हैं।

एकाधिकार के मार्ग में यही दो कठिनाइयाँ हैं। एक तो वस्तु की पूर्ण पूर्ति पर

अधिकार और दूसरी उमकी मागपर पूर्ण अधिकार। यहापर हम फिर स्मरण करावेंगेकि अर्थशास्त्रमें एकाधिकार अथवा एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धाका महत्व मुख्यतया पूर्तिपर अधिक अधिकारकी दृष्टिसे नहीं है वरन् व्यापारीकी मूल्य पर शक्तिकी दृष्टिसे है। चूँकि मूल्य निश्चित होनेमें पूर्तिका भी भाग होताहै, इस लिए पूर्तिके एक बड़े भागपर अधिकारभी आवश्यक होजाता है। पर मूल्य केवल पूर्तिही नहीं निश्चित करती इसलिए माग परभी कुछ अधिकार होना आवश्यक है।

उत्पत्ति विभेदीकरण

पूर्ति पर एकाधिकार पानेके लिए जिस उपायका अधिकतर आश्रय लियाजाता है, उसे उत्पत्ति विभेदीकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त विषय सेबाए भी एक अच्छा उपाय है। कभीतो यह उपाय उत्पत्ति विभेदीकरणका एक अग्रमान होताहै पर उमम स्वतन्त्र भी इस उपायका प्रयोग होता है।

उत्पत्ति विभेदीकरणका तात्पर्य यह है कि किसी वस्तुका नाम बदलकर उसे एक भिन्न वस्तु बनाकर बेचा जाय। उदाहरणके लिए सिगरेट अथवा चाय लीजिए। सिगरेट कई प्रकारकी मिलती है—कैप्सटन, केंची, मोन्टपलेक इत्यादि। इसी प्रकार लिप्टन, ब्रुकबीन्ड, भीलगिरी आदि अनेको प्रकारकी चाय विक्रती है और इनमेंभी बहुतमे उपभेद होने है। अब खाद्य या पेय वस्तुकी दृष्टिसे इन अनेक प्रकारकी चायों अथवा सिगरेटोंमें कोई विशेष अन्तर नहींहै पर नाम भिन्नहोनेके कारण ये भिन्न भिन्न वस्तुएँ मानी जाती है और इनके मूल्य पृथक् पृथक् होते हैं। अब यदि इनको अलग वस्तु मान लिया जाये तो पेटेंट और व्यापार चिह्न सम्बन्धी नियमोंके अनुसार इन्हें बनानेवाली कम्पनिया एकाधिकारी हुई और इसप्रकार इन कम्पनियामें परस्पर प्रतिस्पर्धा एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगी। यहा स्मरण रखना चाहिए कि उत्पत्ति वहीहै अथवा भिन्न। इसकी कसौटी स्थानापन्नताकी लोच है। यदि दो विभेदीकृत वस्तुओंके मूल्योंमें परिवर्तनके फलस्वरूप एक वस्तु दूसरे के स्थानपर ग्रहण करली जाय तो अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे वे एक दूसरीसे भिन्न नहीं हैं। इनके गुण, नाम इत्यादिमें अन्तर हो अथवा न हो। पर यदि डम प्रति-स्थापनमें कठिनाईहै तो जिनकी अधिक कठिनाई होगी, उन्हीके अनुसार वे वस्तुएँ

एक दूसरे से उतनी भिन्न मानी जायेंगी। उत्पत्ति विभेदीकरण अधिकतर विज्ञापन द्वारा किया जाता है। उपभोक्ताओंकी मनोवृत्ति, इच्छाओं और रुचियोंका अध्ययन अथवा अनुमान करके उनके मनमें यह बैठा दिया जाता है कि विभिन्न नामोंमें बिकनवाली वस्तुएं वास्तवमें एक दूसरेमें भिन्न हैं और उनके मूल्यमें अन्तर उनके गुणों अथवा उपयोगिताके अन्तरका परिचायक हैं। विज्ञापनके अतिरिक्त कुछ घोंडकहत बहिरंग अन्तरभी पैदा किये जाते हैं। पर उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक यह विश्वास कर लें कि लिफ्टन और ब्रुकबोर्ड चाय परस्पर इतनी भिन्न हैं कि एक के स्थानपर दूसरीका उपयोग हो ही नहीं सकता। यह काम अधिकतर कुशल और निरंतर विज्ञापन द्वारा होता है और जहां तक व्यापारीका इसमें सफलता मिलती है अर्थात् जहां तक वह स्थानापनताकी सोच पटा सचता है, वही एक उत्पत्ति विभेदीकरण भी हो जाता है।

वस्तुके साथ कुछ सेवाएं जोड़करके भी उन्हें दूसरी वस्तुओंमें भिन्न बनाया जाता है। विना मृत्युके वस्तुको परतक पहूँचा देना अथवा मरम्मत कर देना इत्यादि इन सेवाओंके उदाहरण हैं। ग्राहकोंकी इच्छानुसार विक्रय-समय निश्चय करना तथा बूकानमें अनेक प्रकारकी सुविधाओंका उपलब्ध करना भी इस उद्देश्यको पूरा कर सकते हैं। इस सम्बन्धमें सबसे सामान्य सिद्धान्त न्यूनतम विभेदीकरणका है। उद्योगी और व्यापारी अपनी वस्तुओंको इतनी अधिक भिन्न नहीं बनाते कि उन्हें उनके लिए नई मांग उत्पन्न करनी पड़े अथवा पूर्तिके लिए नए साधन संग्रह करने पड़ें। उनका उद्देश्य मांगको अपनी ओर मोड़ लेना होता है। एकाधिकारका आधार सदैव उत्पादन मनुष्य द्वारा मूल्यपर प्रभाव डालना होता है और यह मांग की दीर्घ दशाओंमें ही सार्थक हो सकता है। इस कारण प्रत्येक उत्पादकका यह उद्देश्य होगा कि उसकी वस्तु और उसके प्रतिस्पर्धियोंकी वस्तुमें कमसे कम अन्तर हो पर वह अन्तर ऐसा हो कि उपभोक्ता उसकी वस्तुको अधिक अच्छी समझे और उसी प्रकारकी अन्य वस्तुओंकी अपेक्षा उसे खरीदनेके लिए अधिक उत्सुक हो।

मूल्य-भेद

प्रतिस्पर्धामें एकाधिकार प्राप्त करनेका दूसरा उपाय मूल्य भेद है। विभिन्न वर्गों,

प्रायः और स्थानोंके व्यक्तियोंमें माग की लोच विभिन्न होती है। कुछ लोग सस्ती वस्तु खरीदते हैं तो कुछ महंगी। सबसे अधिक परिमाणमें बेचनेका उपाय यह है कि वस्तुका मूल्य सदैव बाजारमें प्रचलित मागके अनुसार हो। एकही वस्तुको कई मूल्योंपर बेचनेका उद्देश्य विभिन्न मागोंकी लोचका लाभ उठाना होता है। धनिक वर्गके लिए प्रायः दूसरे दाम बताये जाते हैं। चूंकि धनी लोग सस्ते बाजारोंमें अधिकतर नहीं जाते इसलिए ऐसा कर सकना सम्भव होता है। रत्नके कम्पनिया प्रायः भिन्न भिन्न वस्तुओंके लिए अलग अलग भाड़की दर नियत करती हैं। कभी कभी भिन्न भिन्न वर्गोंके लिए असम असम मूल्य नियत कर दिये जाते हैं, क्योंकि इनमें वर्गगत अभिमानके कारण परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसका लाभ उठाकर उत्पादक प्रत्येककी आर्थिक शक्तिके अनुसार मूल्य नियत करने हैं न कि मीमांस्य ग्राहककी मागके आधार पर। उपयोग-भेदसे भी मूल्य-भेद स्थापित करके लाभ उठाया जा सकता है। गृहकार्योंके लिए कम विद्युत् शक्तिकी आवश्यकता होती है। इसीलिए गृहस्थोंमें उस शक्तिके लिए अधिक दर नियतकी जा सकती है। औद्योगिक कार्योंमें अधिक मात्रामें विद्युत् शक्ति व्यय होती है, इस कारण उद्योगी लोग अधिक दर भानेके लिए तैयार न होंगे। इसलिए उनके लिए नीची दर नियतकी जाती है। इस प्रकार ऊँचे नीचे दोनों दामोंपर अधिकसे अधिक विक्रय हो सकता है। स्थान भेदसे भी मूल्यमें भेद होता है। ग्रामा और नगरोंमें पृथक् पृथक् मूल्य उसी वस्तुके लिए बड़ी बड़ी उद्योग-संस्थाएँ रख सकती हैं। डम्पिंगकी प्रथा स्थान-गत मूल्य-भेदका बहुतही प्रसिद्ध और चरम उदाहरण है। अपने देशमें तो किसी उद्योगपतिका उस उद्योगमें सर्वाधिक अधिकार हो पर अन्य देशोंमें उसे कोई अधिकार न प्राप्त हो। इस स्थितिमें वह अपनी बिजली अन्य देशोंमें कमसे कम, उत्पादन-व्ययसे भी कम मूल्यपर बेचकर बड़ा सकता है। इस प्रकार उसे जो हानि होगी उसे अपने देशमें अत्यधिक मूल्य नियत करके पूरा कर सकता है। इस मूल्यपर उसकी वस्तु कुछ कम बिकेगी पर बिजलीकी यह कमी वह अन्य देशोंमें बहुत अधिक बेचकर पूरी कर लेता है।

✓ बाल-शक्ति मूल्य-भेदका सबसे उत्तम और प्रसिद्ध उदाहरण पुस्तकोंके भिन्न संस्करणोंके लिए पृथक् पृथक् मूल्य नियत करना है। जिस समय पुराना प्रकाशित होती है, उस समय नवीनताके कारण पहिले लेनेकी इच्छाके कारण बहुतसे व्यक्ति

अधिक मूल्यपर भी खरीद लेंगे। कुछ समय पश्चात् उसी पुस्तकका सस्ता संस्करण निकालकर बिक्री पर्याप्त मात्रामें की जासकती है क्योंकि बहुतसे लोग जो अधिक मूल्य होनेके कारण पहिले न लेसके थे, अब लेसकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय पुस्तककी सम्भावित भाग और उसके प्रति जनता की रुचिका भली प्रकार अनुमान लगाया जासकता है। और इस आधारपर अधिक बिक्रीकी आशापर मूल्य कम किया जासकता है। यह आवश्यक नहीं कि पहिले संस्करणका ही मूल्य अधिक हो। दूसरे संस्करण अधिक मूल्यपर निकाले जासकते हैं। मूल्य-भेद पर आश्रित एकाधिकारके लिए आवश्यक है कि विभिन्न बाजारोंकी मागकी लोचमें पर्याप्त अन्तर हो और वस्तु एक बाजारसे दूसरे बाजारमें फिर बेची न जासकती हो।

एकाधिकार तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धाका फल उत्पादन व्ययका बढ़ाना होता है। यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धामें कमसे कम उत्पादन व्यय वाली कुशल उद्योग संस्थाएं मिलती हैं तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धामें उत्पादन कम कुशल और अधिक व्ययशील होजाता है। विज्ञापन और विक्रय व्यय अधिकतर व्यर्थही होते हैं। उपभोक्ताकी तो हर रूपमें हानिही होती है। उपभोक्ताकी बचतका नितान्त लोप करनेकी चेष्टा कीजाती है। मूल्य ऊंचा रखनेके लिए वस्तुओंको प्रायः नष्टभी कर दिया जाता है।

— एकाधिकार के आधार

एकाधिकारका एक आधार कुछ प्राकृतिक सुविधाएँ हैं जैसे समुक्तराष्ट्रीय स्टील कॉर्पोरेशनके पास निवेसकी लगभग सभी खानें हैं। इसी प्रकार हीरो की ससारमें बहुत कम खानें हैं और वे सब दो-तीन कम्पनियोंके पास हैं।

कभी कभी एकाधिकार कुछ विशेष गुणों तथा परिस्थितियोंपर आश्रित होता है। फिल्म अभिनय और अभिनेत्रियाँ, स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक चीन्दयोंके स्थानोंपर होटल आदिका स्वामित्व इस प्रकारके एकाधिकारके उदाहरण हैं।

अधिकतर एकाधिकार कानूनी अधिकारोंपर आश्रित होसकता है। कोई विशेष उत्पादन विधि अथवा आविष्कार किसी विशेष कम्पनीके पास सुरक्षित होसकता है। उत्पत्ति विभेदीकरण भी इसी नियमपर आश्रित है। राजाशासे कभी

कभी इस कम्पनीको किसी क्षेत्र विशेषमें व्यापार करनेका एकाधिकार दिया जाता है। सुप्रसिद्ध ईस्ट-इंडिया कम्पनीका एकाधिकार इसी प्रकारका था। औद्योगिक क्रान्तिसे पूर्व इस प्रकारकी राजाज्ञासे सुरक्षित एकाधिकारके आश्रित बहुतसी संस्थाएँ थीं। कभी कभी यह राजाज्ञा इस कारणभी दी जाती है कि कोई कोई उद्योग प्रतिस्पर्धा द्वारा बुजलतापूर्वक नहीं चलसकते अथवा प्रतिस्पर्धा होनेसे उप-भोक्ताओंको कष्ट और हानि पहुँचनेकी सम्भावना रहती है। स्वास्थ्य सम्बन्धी, यातायातकी तथा समाजके लिए अन्य अत्यन्त आवश्यक सेवाएँ प्रायः राजाज्ञा द्वारा प्रतिस्पर्धासे सुरक्षित रखी जाती हैं। किसी वस्तुकी अत्यन्त कमी होनेपर अथवा अत्यन्त आवश्यकता होनेपर भी राजाज्ञा द्वारा एकाधिकार दिया जाता है। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं, जिनमें पूँजीकी बहुत आवश्यकता होती है परन्तु लाभकी सम्भावना अनिश्चित होती है। ऐसे उद्योग जनताके लिए आवश्यक होनेपर राजाज्ञा द्वारा सुरक्षित कर दिये जाते हैं। रेलमें प्रतिस्पर्धासे सामाजिक हानि हो सकती है अतएव रेलवे कम्पनियोंको भी राजाज्ञा द्वारा एकाधिकार प्राप्त होता है।

एकाधिकार बनानेका चौथा ढंग यह है कि कई उद्योग-संस्थाएँ मिलकर एक संघ बना लेती हैं। अमेरिका और जर्मनी में इस प्रकारकी बहुतसी एकाधिकारी संस्थाओंकी नींव पड़ी थी। यह संघ एकही उद्योगकी कई संस्थाओंका होसकता है अथवा एक उद्योगके कई विभागोंका भी होसकता है। पहिलेको समतल संघ और दूसरेको लम्बरूप संघ कहते हैं। उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेश तथा बिहार चीनी संघ कुछ चीनी बनानेवाली मिलोंका एक संघ होनेके कारण समतल संघ है। परन्तु यदि ईख उगाने, चीनी बनाने और चीनी बेचनेसे सम्बन्धित सभी उद्योगोंका एक संघ बनाया जावे तो वह लम्बरूप संघ होगा। इंग्लैंडमें छोटे छोटे फुटकर बेचने वाले व्यापारियों संघ बनाकर बाजारमें एकाधिकारकी स्थिति पैदा करली है।

इस प्रकारके संघ बनानेके विरुद्ध सरकार प्रायः नियम बना देती है। पर उनसे बेचनेवाले कोई न कोई ढंग व्यापारी लोग निकाल ही लेते हैं।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार की सीमा

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकारकी एक सीमा है। सम्भावित प्रतिस्पर्धा का

भय एकाधिकारीके लिए बहुत बड़ा अकुश है। नयी वस्तुओं और स्थानापन्नोका आविष्कार सदैव सम्भव है। अधिक मूल्य रखनेसे अथवा जन हितका मनमाना निरा-
 दार करनेसे मदिच्छा खो देनेका भय रहता है। एकाधिकारीको राज्य-हस्तक्षेपका भी-
 डर रहता है। एकाधिकारीके अत्यधिक लाभ प्राप्ति करनेकी नीतिका अनुसरण
 करनेपर सामाजिक शान्ति बनाये रखनेके लिए सरकारको हस्तक्षेप करना पड़ता है
 और एकाधिकारी पर कठिन प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। वर्तमान समयमें अधिक
 व्यवस्था इतनी अस्थिर और सबटमयी है कि अनव प्रकारके सरकारी नियन्त्रण
 आवश्यक होगये हैं। इसके अतिरिक्त एकाधिकारीको भागपर बहुत कम अधि-
 कार प्राप्त रहता है। इस कारण उसकी मूल्यको निर्धारित करनेकी शक्ति सदैव
 सीमित होती है और भागके क्षेत्रमें उपभोक्ता सहकारी समितिया तथा राज्य-क्रम
 द्वारा प्राप्त एकाधिकार इस शक्तिको और भी सीमित करते हैं।

उत्पादक साधनों की गतिशीलता

पूर्ण प्रतिस्पर्धाका विवेचन करते समय कहा गया था कि इसके लिए उत्पादक साधनों
 का गतिशील होना अत्यन्त आवश्यक है। साधारणतया गतिशीलताका अर्थ स्थान
 परिवर्तनसे लिया जाता है परन्तु अर्थशास्त्रमें गतिशीलताका मुख्य तात्पर्य उपयोग
 परिवर्तनसे है। इस उपयोग परिवर्तनकी आवश्यकता साधनोंके सीमित होनेके
 कारण पड़ती है। यदि प्रत्येक साधन इच्छित परिमाणमें मिलसकता तो इस परि-
 वर्तनकी आवश्यकताही न पड़ती। ऐसा नहोने के कारण उत्पादक साधन सदैव
 एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें स्थान, कार्य और समयके अन्तर द्वारा परिवर्तित
 होते रहते हैं। कुछ साधनोंकी गतिशीलता इसलिए कम होती है अथवा बिल्कुल
 नहीं होती क्योंकि वे किसी और उपयोगमें आ ही नहीं सकते अथवा केवल कुछही
 उपयोगोंमें आ सकते हैं जैसे भूमि। बीजरने ऐसे साधनोंको विशिष्ट साधन कहा
 है। उन साधनोंकी गतिशीलता अधिक होती है जिनका कई उपयोगोंमें वितरण
 किया जासकता है। बीजरने ऐसे साधनोंको अविशिष्ट साधन कहा है, जैसे श्रम।

गतिशीलता तीन प्रकारकी होती है। देशगत, कार्यगत और कालगत। देशगत
 गतिशीलतासे हमारा अभिप्राय उम गतिशीलतासे है, जिसने होनेमें साधनको एक

स्थानसे दूसरे स्थानपर लेजाया जासकता है। कार्यगत गतिशीलता दो प्रकारकी होसकती है। एकतो वह, जिसके होनेसे साधनको उसी उद्योगमें एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें लगाया जासकता है और दूसरी वह जिसके होनेसे साधन एक उद्योगसे हटाकर किसी अन्य उद्योगमें लगाया जासकता है। कालगत गतिशीलता का तात्पर्य यह है कि साधनका प्रयोग वर्तमान समयमें न करके भविष्यके लिए स्थगित करदिया जाय।

भूमि की गतिशीलता

भूमिका एक स्थानसे दूसरे स्थानपर लेजाना तो सम्भव नहीं है परन्तु किसी विशेष भूमि-भागका एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें परिवर्तन करना सम्भव है। यद्यपि इस परिवर्तनके लिए पूँजीकी न्यूनाधिक मात्रामें आवश्यकता पडती है। इस के अतिरिक्त गतिशीलता का सम्बन्ध भूमिके क्षेत्रफलसे नहीं परन्तु उसकी उत्पादन शीलतासे है। यह तो स्पष्टही है कि पूँजीकी सहायतासे कम उपजाऊ भूमियो को अधिक उपजाऊ बनाया जासकता है। फिरभी किसीभी भूमि-भागके उसके प्राकृतिक गुणो तथा उस स्थानकी जलवायुके अनुसार थोडेही उपयोग हो सकते हैं, बहुत नहीं। इसीलिए भूमिका विविष्ट साधन माना गया है। बहुतसे भूमि-भाग तो पूर्णतया विविष्ट होते हैं। उदाहरणार्थ भारतवर्षकी उत्तरवर्ती पर्वतीय भूमियो पर वनोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं होसकता है।

श्रम की गतिशीलता

श्रमजीवीको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानके लिए दो बातोंकी आवश्यकता होती है। एक तो यातायातके साधनोकी और दूसरे परिवार अथवा ग्रामके लिए मोह न होने की। यातायातके साधनोकी कमी तथा घर परिवारसे सम्बन्ध बनाये रखनेमें बड़ा व्यय होता है और इसकारण श्रमजीवियोकी देशगत गतिशीलता कम होती है। श्रमकी कार्यगत गतिशीलता विभिन्न व्यवसायो अथवा उद्योगो द्वारा प्राप्त होनेवाली आय तथा अन्य लाभोंपर निर्भर करती है। अन्य लाभ

अधिक पारिधमिक द्वाराही नहीं मापे जाते हैं। उस उद्योगमें प्राप्त होनेवाली सभी मुविधाओंकी गणना कर ली जाती है। काम कितना है, छुट्टी कितनी मिलती है, उद्यम निश्चित है अथवा नहीं, नौकरी सुरक्षाका कहातक प्रबन्ध है, मान-मर्यादा बँसी है, इन सब बातोंपर विचार किया जाता है। कुछ कार्योंमें सीखनेकी मुविधाएँ, आवश्यक अभ्यास, शिक्षा और व्यय अधिक होता है और कुछमें कम। कायंमत गतिशीलता पर इसकाभी बहुत प्रभाव पड़ता है। उद्योग विशेषकी शिक्षामें जो व्यय होता है वह एक प्रकार से पूजा लगाना है। कभी कभी इसका प्रबन्ध उस उद्योग अथवा सरकारकी ओरसे होना है। पर अधिकतर यह व्यय धर्मिककी ही करना पड़ना है। कायगत गतिशीलता, यमजीवियोंके इस व्ययको करनेके सामर्थ्य तथा उससे प्राप्त होनेवाले लाभपर निर्भर रहती है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, जिनके लिए विशिष्ट गुणों तथा दीर्घकालीन अभ्यासकी आवश्यकता होती है। इनमें गतिशीलता बहुत कम होती है। इसप्रकार समाजमें धर्म समुदाय होते हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती।

समाजके व्यक्तियोंकी जातीय और व्यक्तिगत विशेषताएँ तथा सामाजिक विशेषताएँ और परम्पराएँ भी गतिशीलतापर बहुत प्रभाव डालती हैं। उदाहरणार्थ भारतवर्षमें वंश और जाति तथा समुक्त परिवार प्रथाएँ गतिशीलताका बहुत निरोध करती हैं। जातिके अनुसार आर्थिक और सामाजिक उन्नतिका न तो किसी व्यक्ति को अवसर मिलता है और न इस प्रकारकी वृत्तिके अच्छा समझा जाता है। घर और जन्मस्थानका मोह स्थानगत गतिशीलताके मार्गमें और पारिवारिक सम्बन्ध कायगत गतिशीलताके मार्गमें बाधक होते हैं।

पूजा की गतिशीलता

स्थायी पूजा अल्पकालमें तो अगतिशीलही होगी। कुछ स्थायी पूजा तो केवल एकही व्यवहारमें आसक्ती है और इसकारण वह सदैवही अगतिशील होगी। जिन यन्त्रोंके तैयार करनेमें अधिक व्यय होता है अथवा जो कठिनतासे और दीर्घ कालमें तैयार होते हैं उनकी गतिशीलता तो कम होगी। स्थायी पूजाकी दीर्घ कालीन गतिशीलतापर सबसे अधिक प्रभाव नवीनताओंका पड़ता है। यदि

नवीनताओंको उद्यममें अपनाने पर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न हो तो उनके द्वारा पूजा बहुत गतिशील हो सकती है। स्थायी पूजाका निरन्तर उपयोगसे नाश होता रहता है और यह आवश्यक नहीं कि उद्योगी उसका पुरानेही रूपमें पुनर्निर्माण करें। इसके प्रतिरिक्त बहुतसी पूजा कच्चेमाल और अर्ध-निर्मित वस्तुओंके रूपमें होती है और उनका उपयोग विभिन्न उद्देश्योंके लिए हो सकती है। इसकारण एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें इनका परिवर्तन सुलभ है। इसप्रकार की पूजाकी गतिशीलता अधिक होती है।

पूर्ण उद्यम और गतिशीलता

पूर्ण उद्यमका अर्थ यह होता है कि उत्पादनके सभी साधन सर्वोत्तम रूपमें उपयोग में लाये जा रहे हों और उनकी आय उनकी उत्पादन शीलता के बराबर हो। ऐसी स्थितिमें गतिशीलता व्यर्थ होगी परन्तु जबतक साधन गतिशील न होंगे पूर्ण उद्यमकी नीतिका सफल होना सम्भव नहीं। गतिशीलता प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था का सिद्धान्त है और पूर्ण उद्यम स्थिर अर्थ-व्यवस्था का। दोनोंमें बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है।

मूल्य निर्धारण की विधि

मूल्य के प्रकार

किसी वस्तुका मूल्य तीन प्रकारका होता है। एक उस वस्तुका वास्तविक मूल्य; दूसरे उसका विनिमय साध्य मूल्य और तीसरे उसका मौद्रिक मूल्य।

वास्तविक मूल्य वस्तुके आन्तरिक गुणों पर निर्भर होता है और स्वयं सिद्ध है। किसी वस्तुके उपयोगी होनेका मूल आधार यही वास्तविक मूल्य है।

विनिमय साध्य मूल्यकी परिभाषा मार्शल ने इस प्रकारकी है 'किसी समय और स्थान पर किसी वस्तुका विनिमय साध्य मूल्य किसी दूसरी वस्तुकी उतनी मात्रा है जो पहिली वस्तुके विनिमयसे प्राप्तकी जा सकती है'।

समाजमें अनेक वस्तुओंके होनेके कारण किसी एक वस्तुके अनेक विनिमय साध्य मूल्य होजाते हैं। जिसके कारण आर्थिक गणित स्तिष्ट होजाती है। इस बाधाको मिटानेका एक साधन यह है कि किसीभी वस्तु विशेषको अन्य वस्तुओंके विनिमय साध्य मूल्यका मापदण्ड मानलिया जाय। आधुनिक समाजके अधिकतर समाजोंमें द्रव्य द्वारा वस्तुओंके मूल्य निर्धारित करनेकी प्रणाली प्रचलित है। जब किसी वस्तुका मूल्य मुद्राओंके रूपमें आका जाता है तो उसे उस वस्तुका मौद्रिक मूल्य अथवा केवल मूल्य कहा जासकता है। 'द्रव्य' के अध्यायमें इस विषयका विशेष रूपसे विवेचन किया गया है।

मूल्य का महत्व

आधुनिक विनिमय प्रधान समाजमें उत्पत्ति और वितरणके सभी कार्य विनिमय द्वारा होते हैं। यह विनिमय वस्तुओं अथवा मानुषी सेवाओंके मूल्यके आधारपर होता है। कृषकके पास अन्न है और उसे कपड़ेकी आवश्यकता है। जुलाहेके पास

कपडा है और उसे अन्नकी आवश्यकता है। कृपक अपने अन्नके मूल्यका अनुमान, उसे उत्पन्न करनेमें श्रम करना पडा था, उसके मूल्यके आधारपर करता है और कपडेके मूल्यका अनुमान उससे मिलनेवाली उपयोगिता के मूल्यके आधार पर। उसीप्रकार जुलाहा अपने कपडे और किसानके अन्नके मूल्यका अनुमान लगाता है। बहुतसे कृपको और जुलाहोके अनुमानोका बाजारमें एक दूसरेसे सम्पर्क होने पर अन्नका कपडेके रूपमें और कपडेका अन्नके रूपमें सर्वप्रिय मूल्य निर्धारित हो जाता है। वस्तुओंका परस्पर वस्तुओंसे ही विनिमय कष्टसाध्य है क्योंकि विनिमय कार्यके पूरा होनेके लिए यह आवश्यक है कि देनेवाले और लेनेवाले दोनोंके पास ऐसी वस्तुएं हो, जो एक दूसरेको चाहिए। केवल यही नहीं वे वस्तुएं दोनोंके पास इच्छित माना में होनी चाहिए। इसकारण प्रत्येक वस्तुका मूल्य द्रव्यके रूप में प्रकट करलिया जाता है और उसके आधारपर उनका पारस्परिक विनिमय होता रहता है।

भाग, पूर्ति और मूल्य

मूल्य स्वयं माग और पूर्तिका एक अंग है। वास्तवमें माग और पूर्तिकी मात्राएँ किसी मूल्य विशेषसे सम्बन्धित करके प्रकट कीजाती हैं अर्थात् माग और पूर्ति दोनों मूल्यपर निर्भर हैं। मूल्यमें वृद्धि होनेपर माग कम होगी और पूर्ति अधिक। इसीप्रकार मूल्य कम होनेपर माग अधिक होगी और पूर्ति कम। दूसरी ओर मूल्य 'स्वयं' माग और पूर्तिपर निर्भर है। पूर्ति कम होनेपर मूल्य अधिक होगा और अधिक होनेपर कम। इसके विपरीत माग कम होनेपर मूल्य कम होगा और अधिक होनेपर अधिक। माग, पूर्ति और मूल्य परस्पर एक दूसरेपर निर्भर हैं। इनमेंसे प्रत्येक शेष दो को निर्धारित करनेमें सहायता देता है और बाजारमें उनके पारस्परिक सम्पर्क से एक प्रकारका सन्तुलन सा स्थापित होनेकी सम्भावना बनी रहती है। पूर्ण सन्तुलनतो कभी स्थापित नहीं होपाता क्योंकि यहतो उस समय स्थापित होगा जबकि किसी मूल्य विशेषपर सम्पूर्ण पूर्ति, सम्पूर्ण मागको पूरा करनेके लिए केवल पर्याप्त मात्राही हो। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता। केवल इस सन्तुलनकी स्थितिसे इन तीनोंमें से एकभी बहुत आगे पीछे नहीं रहने पाता। यदि

पूर्ति मागसे अधिक होनेो विक्रेताओंकी प्रतिस्पर्धा द्वारा मूल्य कम होने लगेगा। इसके फलस्वरूप पूर्ति कम और माग अधिक होने लगेगी। इसीप्रकार जब माग पूर्तिमें अधिक होगी तो ग्राहकोंकी प्रतिस्पर्धाके फलस्वरूप मूल्यका बढ़ना आरम्भ होना लगगा। इसके फलस्वरूप मागमें वमी और पूर्तिमें वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार हरसमय सन्तुलनके भंग होनेपर स्वयंही ऐसी शक्तियोंका प्रादुर्भाव होता रहताहै जो फिर सन्तुलन स्थापित करनेकी चेष्टा करती रहती हैं। ये शक्तियाँ बाजारकी भिन्न भिन्न स्थितियोंमें एकमात्र बल नहीं रखती। यदि विक्रेताओंमें और ग्राहकोंमें परस्पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तो ये शक्तियाँभी पूरे बलसे कार्य करती हैं। यदि विक्रेताओंका एकाधिकार हो तो वे पूर्ति अथवा मूल्यमें से एकपर इन शक्तियों का पूरा प्रभाव नहीं पड़ने देते अर्थात् पूर्तिकी मात्रा अथवा मूल्यमें से एकको अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ा सकते हैं। यदि ग्राहकोंका एकाधिकार हो तो वे माग और मूल्यमें से एकका नियन्त्रण करसकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियोंका विचारहै कि व्यवहारमें न तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा और न एकाधिकार ही होता है। जोन राबिन्सन के कथनानुसार अपूर्ण प्रतिस्पर्धाका ही प्रभुत्व है। चेम्बरलेनने तो एकाधिकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा इत्यादिका भी वर्गीकरण किया है।

काल-भेद और मूल्य

इसके अतिरिक्त कालकी गतिसे भी इस सन्तुलनपर प्रभाव पड़ताहै क्योंकि पूर्ति, माग तथा मूल्यकी स्थितियोंमें अन्तर पड़जाता है। समय व्यतीत होनेसे उत्पत्तिकी मात्रा तथा जनताके स्वभाव, रुचि इत्यादिमें परिवर्तन होनेकी सम्भावना रहती है। फलस्वरूप पूर्ति और मागकी स्थिति वैसे नहीं रहती जैसीकि पहिले थी। इन शक्तियोंके बदलनेसे सन्तुलनभी अपना पुराना स्थान बदललेता है।

अर्थशास्त्री कालके तीन भेद करते हैं। पहिला वहहै जिसमेंकेवल उन्ही वस्तुओं का लेनदेन होताहै जो उत्पन्नकी जाचुकी है और पहिलेसे ही बाजारमें उपस्थित है। दूसरा वह जिसमें पहिलेसे ही प्रस्तुत उत्पादक सामग्री द्वारा पैदाकी जा सकनेवाली वस्तुएँ बाजारमें लायी जा सकती हैं। तीसरा काल वहहै जिसमें नयी उत्पादक सामग्री द्वारा अथवा पुरानी सामग्रीकी उत्पादन शक्तिमें वृद्धि करके उत्पन्नकी जाने

वाली वस्तुएँ भी विनिमयके लिए उपलब्ध होजाती हैं। पहिलेको हम क्षणिक काल, दूसरेको अल्पकाल और तीसरेको दीर्घकाल कहेंगे। स्पष्ट है कि क्षणिक कालमें मूल्य निर्धारण करनेमें प्रभुत्व मागका होगा, दीर्घकालमें पूर्तिका और अल्पकालमें कभी माग और कभी पूर्तिका अथवा दोनों का।

क्षणिक काल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य

क्षणिककाल में पूर्तिका मानातो बाजारमें धटायी और बढ़ायी नहीं जासकती। अतः मूल्य-निर्धारण करनेमें भीमान्त ग्राहकका विशेष महत्व रहता है, उसकी मूल्य-निर्धारण करनेकी शक्तिपर विक्रेताका केवल इतना नियन्त्रण है कि वह ग्राहकके लगायेहुए मूल्यपर वस्तुको न बेचे परन्तु उनका संग्रह करले। इस सम्बन्धमें यह कहदेना है कि प्रत्येक विक्रेता अपने मनमें किसी वस्तुका एक न्यूनतम मूल्य निश्चित करलेता है, जिसके नीचे वह उस वस्तुको नहीं बेचता। वस्तु यदि नश्वरहो तो यह न्यूनतम मूल्य बहुत ही कम होता है परन्तु यदि वस्तु संप्रहृशील हो तो अधिक। यदि विक्रेताके विचारानुसार उसे भविष्यमें मिलनेवाला मूल्य वर्तमानमें मिलनेवाले मूल्य और संग्रहके व्ययसे अधिक है तो वह वस्तु बेचने के स्थानपर वस्तुका संग्रह करना ही उचित समझेगा। भविष्यमें मिलनेवाले मूल्यका अनुमान भविष्यके लिए सीदा करनेवाले बाजारसे किया जासकता है। कृपि द्वारा उत्पन्न बहुसंख्य वस्तुओंका मूल्य इसीप्रकार निर्धारित होता है।

अल्पकाल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य

अल्पकालमें माग बढ़नेसे मूल्य बढ़ना आरम्भ होजाय तो पूर्तिभी बढ़ायी जासकती है। सन्तुलन उस स्थानपर स्थापित होता है जिस स्थानपर कि किसी विशेष मूल्य पर माग और पूर्ति दोनों सम होजायें। मान लीजिए कि खाडकी माग और पूर्ति की तालिकाएँ हमें मालूम है अर्थात् हम जानते हैं कि दिये गये मूल्यपर खाडकी अमुक मात्रामें माग होगी और अमुक मात्रामें पूर्ति। इन तालिकाओं द्वारा सिद्ध किया जासकता है कि सन्तुलन उसीसमय स्थापित होसकता है जबकि किसी विशेष

मूल्य पर माग और पूर्तिकी मात्रा सम होगी। माग और पूर्तिके नियमोंकी सहायतासे तालिकाएँ इसप्रकार बनायी जासकती हैं कि मूल्यके कम होनेपर माग बढ़नी चाहिए और पूर्ति घटनी चाहिए। मूल्यके अधिक होनेपर माग घटनी चाहिए और पूर्ति बढ़नी चाहिए।

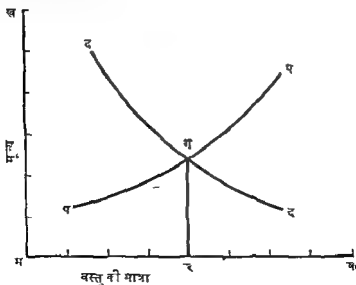
खाटकी माग और पूर्तिकी एवम्नित तालिका

मागकी मात्राएँ (मन)	मूल्य (रुपये)	पूर्तिकी मात्राएँ (मन)
२००	५०	४,०००
३००	४६	३,५००
५००	४८	३,५००
१,०००	४७	३,०००
१,६००	४६	२,५००
२,०००	४५	२,०००
२,५००	४४	१,६००
३,०००	४३	१,०००

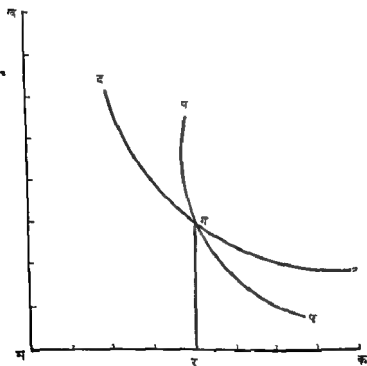
मान लीजिए कि मूल्य ४७ रुपये मन है। इस मूल्यपर माग १,००० मनकी होगी और पूर्ति ३,००० मनकी। इस मूल्यपर मागके परिमाणसे पूर्तिका परिमाण अधिक होनेके कारण विक्रेताओंमें परस्पर प्रतिस्पर्धा होगी। अतएव वे मूल्य कम करके ग्राहकोंको अपनी ओर आकर्षित करनेकी चेष्टा करेंगे। इस परिस्थितिमें ग्राहकलोग मूल्यके और भी गिरनेकी आशामें वस्तु खरीदना स्थगित करदेंगे परन्तु मूल्यकी हर कमीके साथ कुछ लोग खरीदनेके लिए उद्यतहो जायेंगे। दूसरीओर मूल्य के घटनेसे पूर्तिकी मात्रामें कमी होती जायेगी क्योंकि मूल्य घटते घटते कुछ विक्रेताओंके पूर्वनिर्धारित न्यूनतम मूल्यसे कम हो जायेगा। यह क्रिया तब तक होती रहेगी जबतक मूल्य ४५ रुपये प्रतिमन नहीं होजाता। विक्रेता इसमर्मसेल्य क न करेंगे क्योंकि इस मूल्यपर जितना वे बेचना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें ग्राहक मिल जायेंगे। इसीप्रकार यहभी प्रदर्शित किया जासकता है कि मूल्य ४५ रुपये प्रतिमनसे कम नहीं होसकता। मानलीजिए मूल्य ४३ रुपये मन है। इस मूल्य पर विक्रेता १,००० मन बेचना चाहते हैं और ग्राहक ३,००० मन लेना चाहते हैं।

इस मूल्य पर मागसे पूर्ति कम होनेके कारण ग्राहकोकी प्रतिस्पर्धाके फलस्वरूप मूल्यमें ४३ रुपये मनसे अधिक होनेकी प्रवृत्ति हो जायेगी। मूल्य बढ़नेसे माग कम होती चली जायेगी और पूर्ति बढ़ती चली जायेगी। यह क्रिया तबतक बन्द न होगी जबतक कि मूल्य ४५ रुपये मन नहीं होजाता। ग्राहकोमें प्रतिस्पर्धा द्वारा मूल्य बढ़ने और विक्रेताओंमें प्रतिस्पर्धाके कारण मूल्य घटनेकी प्रवृत्ति होजाती है। सन्तुलन उस मूल्यपर स्थापित होताहै जिसपर कि सीमान्त विक्रेता बेचनेके लिए उद्यत होजाते है। सीमान्त विक्रेता वह विक्रेता है जो किसी विशेष मूल्य पर केवल बेचने मानके लिए तैयार हो पाता है और सीमान्त ग्राहक वह ग्राहक है जो किसी विशेष मूल्य पर खरीदने मानके लिए तैयार हो पाता है। इस प्रकार हर मूल्यके लिए सीमान्त विक्रेता और सीमान्त ग्राहक होंगे। सन्तुलन उस मूल्य पर स्थापित होगा जो उस मूल्यके सीमान्त विक्रेताओं और सीमान्त ग्राहकोको अभीष्ट होगा। कारण यह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें एक बाजारमें एकही वस्तुका एकही मूल्य होना आवश्यक है।

ज्यामितिकी सहायतासे सन्तुलन क्रियाको निम्नलिखित ढंगसे दर्शाया जा सकता है:



‘म ख’ रेखापर भूतय दिखाया गया है और ‘म क’ रेखापर भाग तथा पूर्ति । भाग रेखाका आकार ‘द, द’ रेखाके समान होगा और पूर्ति रेखाका ‘प, प’ रेखाके समान क्योंकि मूल्यके घटनेसे भाग बढ़ती जाती है और पूर्ति घटती है । सन्तुलन, ‘ग’ स्थान पर स्थापित होगा, जिस स्थानपर ये दोनो रेखाएँ परस्पर एक दूसरेको काटती हैं । इस चित्रमें भाग रेखा नीचेकी ओर गिर रही है और पूर्ति रेखा ऊपर की ओर चढ़ रही है । परन्तु ऐसीभी स्थिति होसकती है कि पूर्ति रेखाभी नीचेकी ओर गिर रही हो । ऐसा तब होता है जब किसी वस्तुके उत्पादनमें व्ययका क्रमागत ह्रासनिदम लागू हो रहा हो । उससमय इन रेखाओंका आकार इसप्रकार होगा :



परन्तु अबभी सन्तुलन उनी स्थानपर स्थापित होगा जिसपर ये दोनो रेखाएँ आपसमें एक दूसरेको काटती हों ।

अल्पकाल, एकाधिकार और मूल्य

एकाधिकारसे हमारा अभिप्राय विक्रेताओंके एकाधिकारसे है अर्थात् वस्तु-विशेष का बाजारमें केवल एकही विक्रेता हो। जब एकही वस्तुके दो विक्रेता हो तो उसे द्वयाधिकार कहते हैं और जब दो से अधिक थोड़ेसे विक्रेता हो तो उसे बहवाधिकार कहा जाता है।

एकाधिकारमें विक्रेता पूर्ति अथवा मूल्यमें से एकका नियन्त्रण करसकता है। यदि वह कृत्रिम नियन्त्रणों द्वारा पूर्तिमें कमी करता है तो वस्तुका मूल्य उस स्थितिसे अधिकही होगा जबकि वह पूर्ण पूर्तिको बाजारमें उपस्थित होने देता है। एकाधिकारी विक्रेताका उद्देश्य अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करना होता है। वह मागकी मोच इत्यादिका अध्ययन करके मूल्य इसप्रकार निश्चित करताहै कि उसे अधिकतम शुद्ध लाभ मिलसके। मूल्य बढ़ाने से मागमें कमीतो अवश्य होतीहै परन्तु जब तक मागकी इस कमीसे होनेवाली हानि अधिक मूल्यके कारण मिलनेवाले लाभसे कम रहती है तबतक मूल्य बढ़नेमें उसका श्रेय निहित है। यदि मूल्य वृद्धिके कारण मागमें कमी आजानेसे होनेवाली हानि मूल्य-वृद्धिसे मिलनेवाले लाभके परिमाणसे अधिकहो तो ऐसी परिस्थितियों में एकाधिकारीके कुल शुद्ध लाभमें कमी आजायेगी। अतएव उसको अधिकतम शुद्ध लाभ उस मूल्यपर प्राप्त होगा जहापर मागकी कमी से होनेवाली हानि मूल्य वृद्धिसे होनेवाले लाभके सम हो। मानलीजिए किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई पर एकाधिकारी की लागत ३ रूपए है और विविध मूल्योंपर बिकनेवाली मात्राए इसप्रकार है :

मूल्य प्रत्येक इकाई	लागत प्रत्येक इकाई	लाभ प्रत्येक इकाई	विक्री की मात्रा	कुल शुद्ध लाभ
१८)	३)	१५)	३००	४,५००)
१६)	३)	१३)	५००	६,५००)
१४)	३)	११)	७००	७,७००)
१२)	३)	९)	९००	८,१००)
१०)	३)	७)	१,१००	७,७००)

५)	३।	४)	१,३००	१,५००)
६)	३।	३)	१,५००	४,५००)

जब भागकी तासिका उपरिनिर्लिखित प्रकारसे हो तो अधिकतम लाभकारी मूल्य १२ रुपये हैं क्योंकि इस मूल्यपर उसे अधिकतम शुद्ध साम प्राप्त होता है।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य

हम लिख चुके हैं कि प्रतिस्पर्धा उससमय अपूर्ण समझी जाती है जब ग्राहक वस्तु विशेषको न्यूनतम मूल्यपर बेचनेवाले विक्रेतासे नहीं लेते हैं। कई ग्राहक किसी विशेष विक्रेतासे वस्तु अधिक मूल्य देकर भी लेनेकी इमलिए उद्यत रहते हैं क्योंकि वह विक्रेता वस्तुके साथ साथ कुछ ऐसी सेवाएँभी ग्राहको को उपलब्ध करता है। जो उनको अभीष्ट हैं। इसके उदाहरण हम प्रतिस्पर्धाके अध्यायमें दे चुके हैं। उसी अध्यायमें यह भी बताया जा चुका है कि बहुधा विक्रेता लोग बिज्ञापन तथा व्यापार चिह्नो द्वारा ग्राहकोके मनमें वास्तविक या काल्पनिक गुणोंके कारण अपनी वस्तुके लिए विशेष श्रद्धा उत्पन्न करनेमें समर्थ होजाते हैं। इस कारण भिन्न भिन्न चिह्नो वाली एकही वस्तुका न्यूनतम मूल्य लिया जासकता है। ऐसी विशेष चिह्नवाली वस्तुका विक्रेता एकाधिकारीके समान अपनी वस्तुका मूल्य निश्चित तो करसकता है परन्तु उस वस्तुका प्रतिस्थापन करनेवाली वस्तुओंका अस्तित्व उसके द्वारा निश्चित मूल्यपर बिकनेवाली वस्तुकी मात्राको नियन्त्रित किये रहता है। यदि इस वस्तुको बेचनेवाले थोड़ेसे ही विक्रेता हो और उनमें से एक विक्रेता अधिक मात्रामें बेचने के लिए अपनी वस्तुका मूल्य कम करदे तो उसके प्रतिस्पर्धी भी अपने ग्राहक लोभने के भय से अपना मूल्य कम कर देनेकी सोचेंगे। ऐसा होनेपर वह मूल्यको कम करके भी अपनी वस्तुकी मात्रामें अधिक मात्रामें वृद्धि करनेमें समर्थ न हो पायेगा। इसके प्रतिरिक्त अपूर्ण प्रतिस्पर्धाकी दशामें भागकी लोच पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा की अपेक्षा बहुत कम होती है। अतएव वस्तुको पहिलेसे अधिक मात्रामें बेचनेके लिए मूल्यमें अधिक कमी करनी पड़ती है। इन कारणोंसे ऐसी वस्तुका एक बार ऐसा मूल्य स्थापित होजानेसे जिसपर कि वह पर्याप्त मात्रामें बिक रही हो विक्रेता लोग मूल्य परिवर्तनसे बहुत धवरत हैं अन्यथा विक्रेताओं में मूल्य घटानेकी प्रति-

स्पर्धा यहातक बढ़ सकती है कि अन्ततोगत्वा सभीको हानि उठानेके कारण पश्चात्ताप करना पड़। इसलिए ऐसी वस्तुओंके मूल्य प्रायः दीर्घकालके लिए स्थापित होजाते हैं।

बाजार-मूल्य और सामान्य-मूल्य

बाजार-मूल्य माग और पूर्तिके सन्तुलनसे स्थापित होता है। ऊपरकी पक्तियों में यह दिखलाया जाचका है। परन्तु डम प्रकरणमें यह मानलिया गयाया कि किसी निश्चित उपभोग कालके लिए पर्याप्त मात्रामें उपभोग वस्तुएँ उपलब्ध हैं। दीर्घ काल में स्थापित होनेवाले मूल्यको सामान्य मूल्य या प्राकृतिक मूल्य कहते हैं। यह केवल बाजारमें उपस्थित माग और पूर्तिके सन्तुलनसे नहीं परन्तु उत्पादन और उपभोगके सन्तुलनसे स्थापित होता है। उत्पादनका सम्बन्ध उत्पादन-व्यय से होनेके कारण इस सन्तुलनके अध्ययनके लिए हमें उत्पादन-व्ययको ध्यानमें रखना होगा। इसके अतिरिक्त उत्पादक उत्पादन कार्यमें लाभ प्राप्त करनेकी इच्छा से सलग्न होता है। इसलिए हमें उत्पत्तिसे प्राप्त होनेवाली उत्पादककी आयपर औरभी ध्यान देना होगा। इस सम्बन्धमें सीमान्त उत्पादन-व्यय तथा सीमान्त-आयकी परिभाषाओंसे परिचय प्राप्त करना होगा। किसी वस्तुकी एक और इकाईके उत्पादनसे कुल व्ययमें जो वृद्धि होतीहै उसे सीमान्त व्यय और किसी वस्तुकी एक और इकाई बेचनेसे कुल आयमें जो वृद्धि होतीहै उसे सीमान्त आय कहते हैं। ये परिभाषाएँ नीचे दीहुई तालिकाओंसे भलीप्रकार समझमें आजायेंगी :

उत्पत्ति की मात्रा इकाइया	उत्पादन-व्यय प्रत्येक इकाई (रुपय)	कुल उत्पादन व्यय (रुपये)	सीमान्त उत्पादन-व्यय (रुपये)
१	१०	१०	...
२	५	१५	५
३	७	२१	५

४	७।	२८।	७।
५	८।	४०।	१२।
६	९।	५४।	१४।
७	१०।	७०।	१६।
८	११।	८८।	१८।

एक इकाईके उत्पन्न करनेके अनन्तर दूसरी इकाई उत्पन्न करनेके लिए ६ रुपये अधिक व्यय करना पड़ते हैं। इसलिए ६ रुपया दूसरी इकाईका सीमान्त उत्पादन व्यय हुआ। इसीप्रकार अगली इकाईया उत्पन्न करनेके अनन्तर छठी इकाई उत्पन्न करनेके लिए हमें १४ रुपये अधिक व्यय करने पड़ते हैं। इसलिए १४ रुपया छठी इकाईका सीमान्त उत्पादन व्यय हुआ।

अब आयको ले लीजिए :

वस्तु की मात्रा इकाईया	मूल्य प्रत्येक इकाई (रुपये)	कुल आय (रुपये)	सीमान्त आय (रुपये)
१	१८।	१८।	...
२	१६।	३४।	१४।
३	१४।	४८।	१०।
४	१२।	६०।	६।
५	१०।	७०।	२।
६	९।	८४।	४।
७	८।	९६।	२।
८	७।	१०८।	२।

तीन वस्तुओंके अनन्तर चौथी वस्तु बेचनेसे उत्पादकको ६ रुपये अधिक प्राप्त होतेहैं इसलिए ६ रुपये चौथी वस्तुकी सीमान्त आय हुई। इसीप्रकार ६ वस्तुओंके बेचनेके उपरान्त सातवी वस्तु बेचनेसे २ रुपये अधिक आय हुई। इसलिए २ रुपये सातवी वस्तुकी सीमान्त आय हुई।

स्मरण रहे कि सीमान्त उत्पादन व्यय और सीमान्त आय वस्तुकी प्रत्येक इकाईके लिए निर्धारित किये जासकते हैं।

औसत उत्पादन-व्यय और औसत आय

औसत उत्पादन-व्यय निकालनेके लिए कुल व्ययको कुल उत्पन्न वस्तुओंकी मात्रासे और औसत आयको निकालने के लिए कुल आयको कुल वस्तुओंकी मात्रासे भाग दे दिया जाता है। स्पष्ट है कि औसत आय और मूल्य एकही समान होंगे।

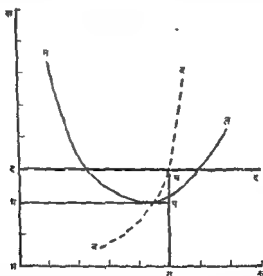
यदि किसी वस्तुके उत्पादनमें व्ययका क्रमागत-ह्रास-नियम लागू हो रहा हो तो उस वस्तुकी अधिक मात्रामें उत्पत्ति किए जानेपर सीमान्त उत्पादन व्यय कम होता जायेगा और उस वस्तुके व्ययका क्रमागत-वृद्धि-नियम अनुपालन करनेपर अधिक मात्रामें उत्पत्ति होने पर सीमान्त उत्पादन व्ययभी अधिक होता जायेगा।

यदि अल्पकाल में निर्धारित मूल्य द्वारा उत्पादकको हानि हो रही हो या पथेष्ट लाभ प्राप्त न हो रहा हो, तो वह भविष्यमें होनेवाली पूर्तिकी मात्राको भविष्यकी मागके अनुसार न्यूनाधिक करनेका प्रयत्न करके अधिकसे अधिक लाभ उठानेकी चेष्टा करेगा।

दीर्घ कालमें मूल्यका सन्तुलन उससमय होगा जबकि सीमान्त उत्पादन व्यय और सीमान्त उपयोगिता सम होजाये अथवा जब सीमान्त उत्पादन व्यय और माग द्वारा निर्धारित मूल्य सम होजाये। प्रत्येक उत्पादकका चरम उद्देश्य अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करना अथवा अपनी हानिको न्यूनतम करना होता है। यह उसी समय होसकता है जबकि सीमान्त उत्पादन व्यय और सीमान्त आय सम होजायें क्योंकि जबतक सीमान्त आय सीमान्त उत्पादन व्ययसे अधिक रहेगी, उत्पादक अधिक मात्रामें उत्पन्न करके कुल लाभको बढ़ानेमें अथवा कुल हानिको घटाने में समर्थ होसकेगा। ज्यामितिकी परिभाषामें कहा जासकता है कि उत्पादक उस बिन्दु तक उत्पन्न करता रहेगा जिसपर कि सीमान्त उत्पादन व्यय रेखा और सीमान्त आय रेखा परस्पर एक दूसरेको काटती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और पूर्ण एकाधिकार तीनों स्थितियोंमें दीर्घकालीन पूर्ति-इम नियम द्वारा नियमित रहेगी।

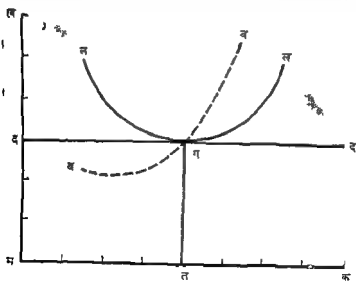
यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगी तो उत्पादक बहुतसे होंगे और सबके सब एकही

मूल्यपर बेचेंगे। यह मूल्य सब उत्पादकोंकी कुल पूर्ति और सब ग्राहकोंकी कुल मागसे निर्धारित होगा। यदि इस प्रकारसे निर्धारित मूल्य सीमान्त उत्पादन व्यय से अधिक होगा तो नये उत्पादक लाभ उठानेकी इच्छामें इस वस्तुको उत्पन्न करना आरम्भ करदेंगे अथवा पुराने उत्पादक अधिक मात्रामें वस्तु उत्पन्न करके अधिक लाभ उठानेकी चेष्टा करेंगे। इसप्रकार वस्तुकी अधिक मात्रामें पूर्ति होनेसे मूल्य कम होने लगेगा और सन्तुलन उससमय स्थापित होगा जब प्रत्येक उत्पादकका सीमान्त उत्पादन व्यय और वस्तुका मूल्य समान हो जायेगा। सीमान्त उत्पादन व्यय का सीमान्त आयके सम होना अनिवार्य है अतएव पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें मूल्यभी इन दोनोंके बराबर होगा। इस सम्बन्धको नीचे दिये गये रेखाचित्र द्वारा दिखाया गया है।



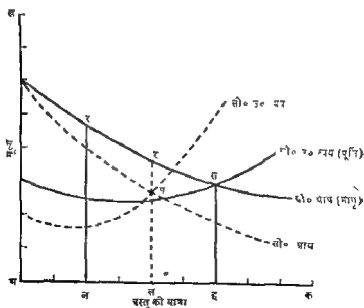
म क रेखा वस्तुका परिमाण बताती है और म स रेखा पर उसका मूल्य, आय और व्यय सूचित किये गये हैं। द द रेखा मागकी रेखा है। जैसाकि पहिले बताया जा चुका है पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें प्रोसत आय वस्तुके मूल्यके बराबरही रहती है। प्रत्येक बिजेताकी सीमान्त आयभी मूल्यके ही समान होती क्योंकि वह अपनी

उत्पत्तिकी प्रत्येक इकाईसि मूल्यके समानही आय प्राप्त करता है। अतएव द द रेखा माग, सीमान्त आय और औसत आयकी द्योतक है। ल ल रेखा औसत व्ययकी रेखा है और व व रेखा तत्सम्बन्धी सीमान्त व्ययकी रेखा है। सीमान्त व्ययकी रेखा व व सीमान्त आयकी रेखा द द को ग बिन्दु पर काटती है। अतएव म त उत्पादनकी मात्रा होगी। इस परिस्थितिमें कुल उत्पादन व्यय म त प थ और कुल आय म त ग द होगी और प ग द थ अतिरिक्त लाभ होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी परिस्थितिमें यह अवस्था स्थायी नहीं रहसकती क्योंकि इसमें नये उत्पादको के आनेकी और पुराने उत्पादको के उत्पत्तिके परिमाणमें वृद्धि करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जावेगी। इसके फलस्वरूप उस वस्तुका मूल्य गिरने लगेगा और तबतक गिरता जायेगा जबतककि अतिरिक्त लाभ लुप्त न होजाये। यह उसी दशामें होगा जहापर औसत आय रेखा द द औसत व्यय रेखा ल ल पर स्पर्श रेखा बन जाती है। स्पष्ट है कि यह बिन्दु ल ल रेखा पर सबसे नीचा बिन्दु होगा और यहीपर सीमान्त व्यय रेखा भी औसत व्यय रेखाको काटेगी। इस परिस्थितिमें रेखाचित्र इस प्रकार का होगा :



एकाधिकारी को यह सविधा प्राप्त है कि वह अधिकसे अधिक लाभ उठानेके लिए न केवल उत्पत्तिकी मात्राको न्यूनाधिक करके उत्पादन व्ययको न्यूनाधिक

करसक्ता है परन्तु मात्राको न्यूनाधिक करके वस्तुके मूल्य तथा अपनी औसत आयको भी न्यूनाधिक कर सकता है। वह उत्पादन तो उतनी मात्रा में करेगा कि सीमान्त उत्पादन व्यय और सीमान्त आय सम होजायें। परन्तु वह उस मूल्य पर बेच मकेगा जहापर उसकी बिक्रीके लिए लायी गयी वस्तुका परिमाण मागके परिमाणके सम हो। यदि वह अधिक मात्रामें बेचना चाहताहो तो उसको कम मूल्य प्राप्त होसकेगा और कम मात्रामें बेचनेपर वह अधिक मूल्य प्राप्तकर सकेगा। यह मूल्य सदैव सीमान्त उत्पादन व्ययमे और फलतः सीमान्त आयमे अधिक होगा। एकाधिकारीको औसत आय सीमान्त आयमे सदैव अधिक होगी। ज्यामितिकी परिभाषामें एकाधिकारको दसामें सीमान्त आयरेखा औसत आय रेखा से सदैव नीचे रहेगी क्योंकि एकाधिकारीको अधिक बेचनेके लिए अपने मूल्यको कम करना पड़ता है। स्मरण रहे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी अवस्थामें एक उत्पादक अधिक मात्रा को भी पूर्वनिर्धारित मूल्यपर बेच सकता है। इसीलिए उसकी औसत आय रेखा और सीमान्त आय रेखा एकही होती हैं। नीचे दिये गये रेखाचित्रमें एकाधिकार की अवस्थामें मूल्य निर्धारण क्रियाको दिखाया गया है।



विविध रेखाएँ और उनके नाम ऊपर दिये गये हैं 'प' बिन्दु पर सीमान्त उत्पादन व्यय रेखा और सीमान्त आय रेखा परस्पर एक दूसरे को काटती हैं। एकाधिकारी को लाभ सम वस्तु की म ल मात्रा उत्पन्न करने में है और इस मात्रा पर उसका मूल्य ल र होगा जो माग द्वारा निर्धारित होगा। चित्र से विदित है कि एकाधिकारी का अधिकतम लाभ वस्तु को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचने में नहीं होता जैसा कि साधारणतया लोग समझते हैं। रेखाचित्र में मूल्य को ल र से ल' र' करने पर उसकी विक्री म ल' रह जायेगी। यहाँ पर उसकी सीमान्त आय उसके सीमान्त व्यय से अधिक है। अतएव अपने कुल लाभ को अधिकतम करने के लिए एकाधिकारी की प्रवृत्ति अपनी उत्पत्तिकी मात्रा म ल' से बढ़ाने की होगी और यह वृद्धि करने की प्रवृत्ति उस परिमाण तक बनी रहेगी जहाँ पर सीमान्त आय और सीमान्त व्यय सम हो जायें। रेखा-चित्र में यह 'प' बिन्दु है।

स्पष्ट है कि मूल्य बढ़ने से यद्यपि प्रत्येक इकाई पर लाभ अधिक होता है परन्तु कुल लाभ कम हो जाता है। इसी प्रकार म ल' से अधिक मात्रा उत्पन्न करने पर एकाधिकारी को तब तक लाभ मिलता रहेगा जब तक कि औसत आय या मूल्य औसत व्यय से अधिक रहेगा। परन्तु उसे अधिक से अधिक कुल लाभ म ल मात्रा उत्पन्न करने पर ही मिलेगा। रेखाचित्र के अनुसार म ह परिमाण तक एकाधिकारी को लाभ होता है परन्तु अधिकतम लाभ म ल परिमाण पर ही होगा। अतएव यदि एकाधिकारी ने म ल से अधिक मात्रा में उत्पत्ति कर ली हो तो उसका क्षे म उसको कम करके म ल तक लाने में होगा क्योंकि इस परिमाण के बाद सीमान्त व्यय सीमान्त आय से अधिक रहता है।

यदि यह मान लिया जाये कि एकाधिकारी की पूर्ति रेखा प्रतिस्पर्धी उत्पादकों के औसत उत्पादन व्यय की सहायता से बनायी हुई पूर्ति रेखा के समान होगी तो प्रतिस्पर्धी की दशा में उत्पत्तिकी मात्रा म ह और मूल्य स ह होगा। विदित है कि प्रतिस्पर्धी की स्थिति में एकाधिकार की स्थिति से उत्पत्तिकी मात्रा अधिक होगी और मूल्य कम।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता अपनी विशेष व्यापार चिह्नवाली वस्तु का अथवा बाजार के अपने भाग में एकाधिकारी सा होता है। इसलिए उसकी वस्तु के लिए माग रेखा के पूर्ववत् रहने पर सन्तुलन उसी प्रकार

स्थापित होनाहै जैसाकि एकाधिकारकी स्थिति में। अन्तर केवल इतना है कि इस स्थिति में नये उत्पादक उस वस्तुका प्रतिस्थापन करनेवाली वस्तुके निर्माणमें सलग्न होकर वस्तुकी पूर्ति पर प्रभाव डाल सकने हैं। एकाधिकारकी स्थितिमें ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि उस स्थितिमें स्थानापन्न वस्तुओंका अभाव मान लिया जाना है।

द्वयाधिकार तथा बहुवाधिकारकी परिस्थितिमें वस्तुका मूल्य साधारणतः तबतक निर्धारित नहीं किया जासकता जब तक कि उत्पादक आज़ारको भागोंमें विभाजित करके अपने विशेष भागमें वस्तु बचानेका अथवा वस्तुकी कुल उत्पत्तिमें से पहिलेसे ही निश्चित विशेष भागके उत्पन्न करनेका परस्पर समनुबन्ध न करने। इस स्थिति में प्रायः घातक प्रतिस्पर्धाके अनन्तर ऐसे उत्पादकों की हानिसे बचनेके लिए ऐसा समनुबन्ध करनाही पड़ता है।

सम्मिलित उत्पत्ति और मूल्य

कई एक वस्तुएँ सम्मिलित रूपमें ही उत्पन्न की जासकती हैं; पृथक् पृथक् नहीं। जैसे गेहूँ और भूसा एकही साथ उत्पन्न होने हैं। ऐसी सम्मिलित उत्पत्तिकी दशामें प्रत्येक वस्तुका सीमान्त या औसत उत्पादन व्यय निकालना कठिन होजाता है। इस प्रकार सम्मिलित दशामें उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंका सन्तुलन उस समर्थ स्थापित होगा जबकि उन वस्तुओंकी उत्पत्ति उस मात्रामें होगी कि उन वस्तुओंमें मिलनेवाली सीमान्त आय मिलकर उनके सम्मिलित सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होजाय। यदि उनमें किसीभी वस्तुकी मागमें परिवर्तन होना है तो उन सबकी उत्पत्तिकी मात्रामें परिवर्तन द्वारा नया सन्तुलन स्थापित होगा।

सम्मिलित माग

कभी कभी दो या दो से अधिक वस्तुओंकी माग साथ साथ घटती बढ़ती है। ऐसी स्थितिमें उनके मूल्यभी साथ ही साथ घटते बढ़ते हैं। परन्तु यदि उनमेंसे एक वस्तुका मूल्य उस वस्तुकी पूर्तिमें न्यूनता या आधिक्यके कारण बढ़े या घटे तो

दूसरीके मूल्यमें पहिलीसे विपरीत दिशामें परिवर्तन होगा। चाय की पूर्ति अधिक होने से चायका मूल्य कम होगा। परन्तु खाडकी पूर्ति पूर्ववत् रहने पर उसकी माग बढनेसे उसका मूल्य अधिक होजायेगा। इसके अतिरिक्त यदि सम्मिलित माग वाली दो वस्तुओं में से पहिलीका केवल एकही प्रयोग हो और दूसरीके बहुतसे प्रयोग हो तो मागके परिवर्तनसे पहिली वस्तुके मूल्यपर दूसरी वस्तु के मूल्यसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति प्रायः उस समय देखभलेमें आतीहै जब उपभोग्य वस्तुकी मांग बढनेसे उसके उत्पादन में काम आने वाले साधनोंकी माग भी बढती है। पावरोटी की माग बढने से गेहूँ और पावरोटी बनानेवालोंकी माग बढेगी। परन्तु गेहूँ के पावरोटी बनानेके अतिरिक्त औरभी बहुतसे प्रयोग होनेके कारण उसके मूल्यमें विशेष परिवर्तन न होगा। परन्तु रोटी बनानेवालों का श्रम विशिष्ट और कुशल होनेके कारण उसका मूल्य बहुत बढ जायेगा। अर्थात् उनकी मजूरी अधिक होजायेगी।

एक वस्तु के भिन्न भिन्न मूल्य

कभी कभी उत्पादक विशेषकर एकाधिकारी भिन्न भिन्न प्रकारके ग्राहकोसे या भिन्न भिन्न बाजारों में एकही वस्तुके भिन्न भिन्न प्रयोगोंके लिए भिन्न भिन्न मूल्य लेते हैं। जैसे कई उत्पादक अपने देशमें वस्तु महंगी और विदेशमें सस्ती बेचते हैं। बिजली का किराया रोशनीके लिए पृथक् और औद्योगिक प्रयोगोंके लिए पृथक् दरसे लिया जाता है। उत्पादक का प्रयत्न यह रहता है कि जिस बाजारमें मागकी लोच कम हो और सीमान्त आय बड़ी शीघ्रतासे गिरती चली जातीहो उस बाजारमें वस्तु कम मात्रामें बेचे। इसके विपरीत जिस बाजारमें माग तथा उसकी लोच अधिकहो उसमें सीमान्त आयभी अधिक होती है। उस बाजारमें वह वस्तुको अधिक मात्रामें बेचता है। दोनों बाजारों में वह अपनी बिक्रीको इसप्रकार विभाजित करेगा कि उसकी दोनों बाजारोंमें सीमान्त आय उसके सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होजाये।

प्रतिस्थापना

प्रतिस्थापना का महत्व

आधुनिक अर्थशास्त्रमें प्रतिस्थापनाको विशेष महत्व प्राप्त है। तटस्थ रेखाओं द्वारा अर्थशास्त्रीय समस्याओं का विश्लेषण प्रचलित होनेके कारण पुराने सीमान्त उपयोगिता विश्लेषण का लोपता होता जा रहा है। तटस्थ रेखाओंके अध्यायमें हम देख चुके हैं कि हिक्स इत्यादि अर्थशास्त्री सीमान्त उपयोगिताके स्थापनपर सीमान्त स्थानापन्नताकी दृढ़ता प्रयोग करने हैं।

वास्तवमें प्रतिस्थापना और तटस्थ-स्थितिके नियम भिन्न भिन्न नहीं हैं; परन्तु एकही नियमके दो भिन्न भिन्न नाम हैं। तटस्थ-स्थितिका नियम सन्तुलनकी अवस्थामें लागू होता है और प्रतिस्थापना का नियम सन्तुलनसे भिन्न अवस्थामें।

प्रतिस्थापना और तटस्थ-स्थिति

७

मनुष्यकी आवश्यकतायें बहुत हैं। परन्तु हर आवश्यकता को तृप्त करनेके लिए भिन्न भिन्न प्रकारके साधन भी हैं। इस प्रकारके साधन जो एकही आवश्यकताको तृप्त करनेमें एक दूसरेका प्रतिस्थापन कर सकते हैं, स्थानापन्न साधन कहे जा सकते हैं। जब किसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए इस प्रकारके स्थानापन्न साधन उपलब्ध हों और उनमें से प्रत्येक साधन प्रचलित मूल्योपर एकही बंसी तृप्ति देते-वाला हो तब उनमेंसे किसी एकका भी प्रयोग करनेके लिए मनुष्य तटस्थता रहता है। इनमें से किसी सामानका प्रयोग करनेकी ओर उसकी विशेष प्रवृत्ति नहीं होती। यह तटस्थ स्थितिका नियम है। परन्तु ससारकी आर्थिक स्थिति सदैव एकसी नहीं रहती। समय समयपर उनमें परिवर्तन होते रहते हैं और उपलब्ध साधनोंमें से कोई-एक उसके सापेक्ष मूल्यमें कमीके कारण अन्य सबसे उत्तम होजाता है और

इस कारण वह अन्य सब साधनों का प्रतिस्थापन करने लगता है। यह प्रतिस्थापना का नियम है।

दो प्रकार की स्थानापन्न वस्तुएँ

प्रतिस्थापन करनेवाली वस्तुएँ या साधन दो प्रकारके होते हैं। मूल्यों को ध्यानमें रखने हुए कुछतो प्रयोग की जानेवाली वस्तुके समान अथवा उससे अधिक तृप्ति-दायक होती हैं। जैसे विद्युत-शक्ति और मिट्टीका तेल दोनों प्रकाशका गुण रखनेके कारण एक दूसरेका प्रतिस्थापन करसकते हैं परन्तु विद्युत-शक्ति, उनके मूल्यको ध्यानमें रखते हुए अधिक तृप्ति प्रदान करती है। कभी कभी एक वस्तु किसी विशेष उद्देश्यके लिए उत्तम होती है और उसका प्रतिस्थापन करनेवाली दूसरी वस्तु किसी दूसरे उद्देश्यके लिए, जैसे मनुष्य के लिए गेहूँ उत्तम है परन्तु घोड़ों के लिए चने।

मूल्योंका ध्यान रखतेहुए कुछ वस्तुएँ प्रयोग कीजाने वाली वस्तुसे कम तृप्ति देती हैं। जैसे शुद्ध धी और वनस्पति धी। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य विवश होकरही करता है स्वतन्त्रतासे नहीं। शुद्ध धी का मूल्य बहुत बढ़जाने के कारण प्रयोग भलेही वनस्पति धी का प्रयोग प्रारम्भ करदें परन्तु जिनकी आय पर्याप्त है वह शुद्ध धी का ही प्रयोग करेंगे। अथवा उत्तम वस्तुकी पूर्तिमें कमीके कारण भी हीन वस्तुओं का प्रयोग आवश्यकसा होजाता है। जैसे हमारे देशमें अन्नकी न्यूनता के कारण बहुतसे लोग गेहूँ के स्थान पर जौ, चने इत्यादि को प्रयोगमें लान लग गये हैं। ऐसी घटिया वस्तुओंकी एक उपयोगिता यहभी है कि बहुत से लोग जो उत्तम वस्तुके बहुमूल्य होनेके कारण उसका प्रयोग करनेमें असमर्थ थे, मूल्य कम होजाने से घटिया वस्तुका प्रयोग करसकते हैं। बहुतसे लोग जौ धी का प्रयोग न कर सकते थे, वनस्पति धी का प्रयोग करने लग गये हैं।

प्रतिस्थापना और मूल्य

स्पष्ट है कि किसी वस्तुका प्रतिस्थापन करनेवाली वस्तुओं का अस्तित्व उस वस्तुके

मूल्य पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। बाजार-मूल्य किसी वस्तुकी पूर्ति और मागवे पारस्परिक मनुगन्तसे निर्धारित होता है। पूर्तिसे हमारा अभिप्राय केवल उम वस्तुकी पूर्तिमे ही नहीं बरन् उन सभी वस्तुओंकी पूर्तिमे है जो उर्मा आवश्यकता की तृप्त करनेकी सामर्थ्य रखती हैं। जिसे वह वस्तु तृप्त कर रही हो अर्थात् उस वस्तुका प्रतिस्थापन कर सकती हो। इसप्रकार किसी वस्तुका प्रतिस्थापन करने वाली वस्तुओंका अस्तित्व उम वस्तुकी पूर्ति बढ़ाकर पूर्तिमें निम्नानुसार उस वस्तुका मूल्य कम कर देता है। किन्तु यह अनिवार्य नहीं है कि ऐसी स्थानापन्न वस्तुओंकी समस्त पूर्ति वस्तुविशेषकी पूर्तिपर प्रभाव डाले ही। हो सकता है कि ऐसी स्थानापन्न वस्तुओंका प्रयोग अन्य आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए भी होता हो अथवा पहिली वस्तुका प्रयोग करनेवाले उस वस्तुका अन्य वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापन हितकर न समझते हो और ऐसी स्थानापन्न वस्तुओंके होतेहुए भी पहिली ही वस्तुका प्रयोग करते रहें। अतएव ऐसी स्थानापन्न वस्तुओंकी पूर्तिका उम वस्तुकी पूर्तिपर केवल आंशिक प्रभावही पड़ेगा और उसी अंशके अनुपातमें उम वस्तुका मूल्यभी कम होगा।

सौमान्त स्थानापन्नता

जब हम आर्थिक उद्देश्योंके वाढल्य और उन्हें सिद्ध करनेके साधनोंकी न्यूनताके सिद्धान्तकी स्वीकार कर लते हैं तो प्रतिस्थापना का महत्व औरभी अधिक हो जाता है क्योंकि इसकी सहायतासे हम साधनोंकी न्यूनताको सापेक्ष रूपसे कम कर सकते हैं। मनुष्य का उद्देश्य उपलब्ध साधनों द्वारा अधिकसे अधिक तृप्ति प्राप्त करना है और साधनोंके पारस्परिक प्रतिस्थापनसे हम ऐसी अवस्थाको प्राप्त कर सकते हैं कि विविध साधनोंको इस अनुपातमें प्रयोग करें, जिससे हमें अधिकतम तृप्ति मिले। इस अनुपात में किसीभी प्रकारका परिवर्तन होनेपर हमें प्राप्त तृप्तिमें ह्रास ही होगा। यह सत्य है कि किसी एकवस्तु अथवा साधनका उमसे संबंध मित वस्तु अथवा साधन द्वारा प्रतिस्थापन कियाजाना सम्भवता प्रतीत नहीं होता विशेषकर उस अवस्थामें जबकि प्रतिस्थापन के अनन्तर भी हमें पहिलेके समानही तृप्ति पाने की इच्छा हो। परन्तु किसी वस्तु अथवा साधनकी सौमान्त वृद्धि का किसी सर्वथा

भिन्न वस्तु अथवा साधनकी सीमान्त वृद्धि द्वारा, सम तृप्ति की उपलब्धि का नियन्त्रण होतेहुए भी, प्रतिस्थापन कियाजाना असम्भव नहीं। ऐसातो सदैव होता ही रहता है।

प्रतिस्थापना और उपभोग

घरेलू आय-व्ययके सम्बन्धमें हम समसीमान्त उपयोगिता नियमका उल्लेख करही चुके हैं। मनुष्य अपनी सीमित आयको अपने उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए विविध प्रकार के साधनों अथवा वस्तुओंपर व्यय करता रहता है। और इस व्ययमें उसे कुछ तृप्ति प्राप्त होनी रहती है। परन्तु उसका लक्ष्य अपनी सीमित आयमें अधिकतम तृप्ति प्राप्त करना है। इस लक्ष्यकी सिद्धिके लिए वह एकवस्तु या साधनका दूसरी वस्तु या साधनके स्थानपर प्रतिस्थापन करता रहता है। एक समय आता है जबकि प्रत्येक वस्तु या साधनपर किये जानेवाले सीमान्त व्ययसे प्राप्त होनेवाली तृप्ति सम होजाती है। यह वह स्थितिहै जिनमें उसे अधिकतम तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य तटस्थ अवस्थापर पहुचनेके लिए प्रतिस्थापना द्वारा अपने विविध प्रकारके व्यय न्यूनाधिक करता रहता है।

प्रतिस्थापना और उत्पादन

प्रतिस्थापना का सिद्धान्त केवल घरेलू आय-व्ययसे अधिकतम तृप्ति प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है वरन् हर प्रकारकी आर्थिक घटनाओंका प्रतिस्थापना से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वस्तुओंका पारस्परिक विनिमय प्रतिस्थापना का ही रूपान्तर है। उत्पादन और वितरणमें तो प्रतिस्थापनासे बहुतही काम पड़ताहै। इस स्थानपर इतना कहदेना आवश्यक है कि प्रतिस्थापनासे हमारा अभिप्राय आयः सीमान्त प्रतिस्थापना सेही होता है। उत्पादन को ने सीजिए। किसीभी उत्पादन के साधन का किसीभी उत्पादन की योजनासे पूर्णतया लोप करना सम्भव नहीं परन्तु उनमें से किसी एकके विशेष अंशका किमी दूसरेके विशेष अंशसे प्रतिस्थापन किया जा सकता है। जब किसी साधनकी पूर्ति न्यून होने लगतीहै तो उसका मूल्य बढ़ जाने

के कारण उसका प्रतिस्थापन करनेवाले साधन का प्रयोग आरम्भ होने लगता है। पहिले साधनोंकी माग कम होनेसे उसका मूल्य गिरने लगता है और स्थानापन्न साधनकी माग बढ़नेसे उसका मूल्य बढ़ने लगता है और प्रतिस्थापन तबतक होता रहता है जबतक कि उक्त साधनों द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिकी मात्राओं और उनके मूल्योंमें एवसा अनुपात नही होजाता है।

वैसेभी उत्पादक अधिकतम उत्पत्ति करनेके लिए प्रयुक्त साधनोंके पारस्परिक अनुपातमें परिवर्तन करतेही रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण उत्पादन विधिमें परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनोंका आधार किसी साधन विशेषकी सीमान्त-वृद्धि द्वारा प्राप्त होनेवाली उत्पत्तिकी मात्रा है। जबतक किसी साधन विशेषसे सम्बन्धित सीमान्त उत्पत्तिकी मात्रा अन्य साधनों से सम्बन्धित सीमान्त उत्पत्ति की मात्रासे अधिक रहती है, उस साधन विशेषका अधिकाधिक मात्रामें प्रयोग किया जाता है और अन्य साधनोंका कम या उतना ही। यह क्रिया तबतक समाप्त नही होती जबतक हर साधनोंके सीमान्त प्रयोगसे प्राप्त होनेवाली उत्पत्तिकी मात्रा सम नही होजाती।

प्रतिस्थापना और वितरण

यदि प्रतिस्थापना उत्पादनमें काम आनेवाले विविध साधनोंकी मात्रापर प्रभाव डालती है तो इसप्रकार कीगयी उत्पत्तिके वितरण पर अवश्यही प्रभाव डालेगी। जिन साधनोंका प्रयोग कम होता आरहा है, उनके भागमें कमी आती जायेगी। यदि धर्मके स्थानपर पूजाका प्रयोग अधिक होने लगेगा तो धर्मजीवियों को धैर्य के रूपमें मिलनेवाला उत्पत्तिका भाग पहिलेसे कम होजायगा और पूजापतियों को ध्याजके रूपमें मिलनेवाला भाग अधिक।

प्रतिस्थापना को एक अन्य दृष्टिसे इसप्रकार भी देखा जासकता है। किसीभी वस्तु अथवा साधनको भिन्न भिन्न प्रकारके प्रयोगों में लगाया जासकता है। इस वस्तु अथवा साधनकी मात्राका इन भिन्न भिन्न प्रयोगों में इसप्रकार वितरण किया जाता है कि प्रत्येक प्रयोगसे प्राप्त होनेवाली सीमान्त तृप्ति या उत्पत्ति एकही जैसी होजाय। उदाहरणके लिए भूमिको अनेक कार्योंमें लगाया जासकता है। उसपर

खेतीकी जासकती है, मकान बनवाया जासकता है अथवा सड़क बनवाई जासकती है। इन भिन्न भिन्न प्रयोगोंमें भूमि का वितरण इसप्रकार होगा कि हर प्रयोगसे प्राप्त होनेवाली सीमान्त तृप्ति एकसी होजाये।

प्रतिस्थापना की विरोधी शक्तियाँ

इसप्रकार तटस्थ स्थिति और प्रतिस्थापना द्वारा मनुष्यका आर्थिक जीवन सगठित होता रहता है। कभी कभी यह नियम स्वयंही हमारे अनजाने में अपना कार्य करते रहते हैं। ऐसा प्रायः वस्तुओंके उपयोगके सम्बन्धमें होता है। कभी कभी हमें सोच समझकर इनका आश्रय लेना पड़ता है। ऐसा प्रायः वस्तुओंके उत्पादनके सम्बन्धमें करना पड़ता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यह नियम सदैवही अपना कार्यकर पाते हैं। इनका विरोध करनेवाली शक्तियोंका भी अभाव नहीं। मनुष्यके स्वभावको ही ले लीजिए। यह सुगमतासे परिवर्तित होनेवाला वस्तु नहीं। मनुष्य जब किसी वस्तुका प्रयोग दीर्घकाल तक करता रहता है तो उसके स्थानपर किसी दूसरी वस्तुका प्रयोग करना उसके लिए बहुत कठिन होजाता है; चाहे दूसरी वस्तु के प्रयोगमें उसका लाभही क्यों न हो और ऐसाभी असम्भव नहीं कि समय समय पर उसके स्वभावमें जो स्वयं परिवर्तन होते रहते हैं, वे प्रतिस्थापना के कार्यका विरोध करने लगें। इसके अतिरिक्त सब मनुष्योंके स्वभावभी एकही जैसे नहीं होते। ऐसे मनुष्योंकी भी कमी नहीं जो एक दूसरेका प्रतिस्थापन करनेवाली दो वस्तुओंमें से किसी एकके प्रति विशेष धृढ़ रहते हों और जबतक उनके मूल्योंमें बड़ाभारी अन्तर न पड़जाय, उसका प्रयोग बन्द न करें। कभी कभी प्रतिस्थापना द्वारा जोड़ासा ही लाभ प्राप्त होनेके कारण लोग इस क्रियाको आलस्यवश टाल जाते हैं। इसीप्रकार उत्पादनमें भी प्रतिस्थापना पूर्णरूप से कार्य नहीं करपाती। बहुतसे उत्पादक साहमसे वंचित होते हैं और अधिक कुशल उत्पादन विधियोंको प्रयोगमें लानेसे हिचकिचाते हैं। अथवा यदि मूल्योंमें वृद्धि होनेके कारण उत्पादक पर्याप्त लाभ उठा रहाहो तो प्रतिस्थापना से मिलनेवाले छोटे मोटे लाभोंकी ओर ध्यानही नहीं जाता।

आर्थिक सन्तुलन

मूल्यों का पारस्परिक सम्बन्ध

समस्त आर्थिक पद्धतिका भलीभांति विश्लेषण करनेसे यह स्पष्ट रूपसे विदित होजाता है कि हर वस्तु या सेवाका मूल्य अन्य वस्तुओं या सेवाओंके मूल्योंसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमें सम्बन्धित रहता है अर्थात् हमारी आर्थिक पद्धति परस्पर सम्बन्धित मूल्योंकी पद्धति है और इन मूल्योंका पारस्परिक सन्तुलन उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित होता है। यह आवश्यक नहीं है कि क्रय-विक्रय की वस्तुएँ उपभोग्य पदार्थ ही हों। केवल इतना आवश्यक है कि जन-समुदाय को उनके लेनेकी चाहें और विभिन्न वस्तुओं अथवा वस्तुसमूहों के लिए चाहेंके न्यूनाधिक होनेका निश्चय किया जासके। स्मरण रहे कि चाहकी न्यूनाधिकता वस्तुओंके मूल्यपर निर्भर नहीं रहती अर्थात् किसी वस्तुके लिए चाहका उसके मूल्यसे कोईभी सम्बन्ध नहीं होता।

वस्तुओं के मूल्य उपभोक्ताओं की मायपर निर्भर रहते हैं और उपभोक्ताओं की माय उत्पादनके साधनोंके मूल्य तथा उनके उत्पादन कार्यमें प्रयुक्त मात्रापर निर्भर रहती है। इसप्रकार न केवल उपभोग्य पदार्थोंके मूल्योंमें ही पारस्परिक सम्बन्ध होता है बल्कि उत्पादनके साधनों द्वारा प्राप्त सेवाओंके मूल्यभी इन मूल्योंसे सम्बन्धित रहते हैं। वास्तवमें उत्पादनके साधनों द्वारा प्राप्त सेवाओंके मूल्योंका निर्धारणभी उसी प्रकार माग और पूर्तिके सन्तुलनसे होता है जैसे कि अन्य वस्तुओं का। परन्तु उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त किये जानेवाले उत्पादनके साधनोंकी माग और पूर्तिमें कुछ विशेषताएँ होती हैं। उत्पादकोंकी उत्पादनके साधनोंके लिए माग उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए नहीं होती बल्कि इसलिए होती है कि वह इनके प्रयोग द्वारा कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न करना चाहता है जो कि अन्य लोगोंकी किमी

आवश्यकताकी पूर्ति करेंगे। वह उत्पन्न वस्तुको बेचकर प्राप्त आयसे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। यदि उत्पन्न वस्तुके लिए माग बढ़ जाती है तो उसकी उत्पादनके साधनोंकी मागमें वृद्धि होना आवश्यक हो जाता है। उत्पादक को उत्पादनके साधनोंका मूल्य निर्धारित करते समय उनके द्वारा उत्पन्न वस्तुके मूल्यका ही सहारा लेना पड़ता है। उत्पन्न वस्तुके मूल्य जाने बिना उत्पादकको उत्पादनके साधनोंका क्या मूल्य देना चाहिए, यह निश्चय करना सम्भव नहीं। इसप्रकार यहाँ अन्य वस्तुओंकी माग उनके लिए उपभोक्ताओंकी न्यूनाधिक चाहपर निर्भर है और इस चाहकी न्यूनाधिकता ही उन वस्तुओंके सापेक्ष मूल्यों तथा भागकी मात्राको निर्धारित करती है। उत्पादनके साधनोंके मूल्य तथा उनकी मागकी मात्राके निर्धारण करनेमें उनके द्वारा उत्पन्न वस्तुके मूल्यको विशेष महत्व प्राप्त है। इसके अतिरिक्त विविध साधनोंके मूल्योंका परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहनाभी विशेष रूपसे ध्यानमें रखना चाहिए क्योंकि किसीभी एक साधन बिनायका मूल्य अन्य साधनोंके मूल्योंसे इतने घनिष्ट रूपसे सम्बन्धित है कि उसका पृथक् निर्धारण करना सम्भव नहीं।

मूल्यों का सन्तुलन

इसकारण सन्तुलनके विश्लेषण कार्यको तीन भागोंमें विभाजित करनेकी प्रथा अर्थशास्त्रियों में चली आ रही है।

- (१) पहिले भागमें केवल वस्तुओंके विनिमयके साधारण सन्तुलनका ही विश्लेषण किया जाता है।
- (२) दूसरे भागमें किसी विशेष उत्पादन की मस्याओंका और:
- (३) तीसरेमें उत्पादनके साधारण सन्तुलन का।

विनिमयके साधारण सन्तुलनके सिद्धान्तके प्रथम निर्माता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बालरस थे। मान लीजिए कि विनिमय करनेके लिए हमारे पास केवल दो वस्तुएँ क और ख हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा या तो क की पूर्ति और ख की माग या ख की पूर्ति और क की मागका होना ही सम्भव हो सकता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थितिमें सन्तुलन उस मूल्यपर स्थापित होगा जबकि क की पूर्ति क की मागके

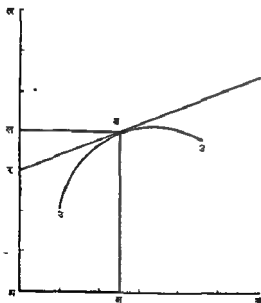
सम और फलस्वरूप ख की पूर्ति ख की मागके सम होजायेगी। स्मरण रहे कि इन दो वस्तुओं में से एक (यहां ख ले लीजिए) को मूल्यके मापकके रूपमें माना जा रहा है। इस प्रकार यदि दो वस्तुओंमें विनिमय कार्य सम्पन्न हो रहा हो तो हमें केवल एकही वस्तुका मूल्य, और यदि तीन में यह कार्य हो रहा हो तो दो वस्तुओंका मूल्य, निकालना होगा। साधारणतया कहा जा सकता है कि जितनी वस्तुओंमें विनिमय-कार्य सम्पन्न हो रहा हो उनसे एक कम मूल्योंका मालूम करना आवश्यक है क्योंकि मूल्य उन वस्तुओंमें से एकको मापक मानकर ही निर्धारित किये जाते हैं। यदि विभिन्न वस्तुओंके मूल्य हमें मासूमहों तो किसी व्यक्ति विशेषकी उनके लिए न्यूनाधिक चाहता आशय लेकर हम यह मालूम कर सकते हैं कि जिन वस्तुओंसे वह व्यक्ति बचित है, उनकी वह अपेक्षित मात्रा में पूर्ति करनेके लिए तैयार है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकी प्रत्येक वस्तुके लिए माग और पूर्ति निकालकर हम प्रत्येक वस्तुकी कुल माग और पूर्ति साधारण जोड़ द्वारा निकाल सकते हैं। यदि विभिन्न वस्तुओंके मूल्य इसप्रकार स्थापित होजायें कि प्रत्येक वस्तुकी माग उसकी पूर्तिके सम होजाये तो ऐसी स्थितिको सन्तुलनकी स्थितिके नामसे पुकारा जाता है और जबतक हम इस स्थितिको प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक कुछ वस्तुओंके मूल्य घटते और कुछके बढ़ते रहते हैं। सन्तुलनकी स्थितिमें हमें प्रत्येक वस्तुकी माग और पूर्तिमें समता होनेके कारण इतनी सामग्री उपलब्ध होजाती है कि गणितशास्त्रकी सहायतासे हम प्रत्येक वस्तुके अज्ञात मूल्यको मालूम करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। यह सन्तुलन स्थायीभी हो सकता है और अस्थायी भी। इसके स्थायी होनेके लिए परमावश्यक है कि इसके भंग होतेही इसप्रकार की स्वयंभू शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जो हमके पुनः स्थापन की भरसक चेष्टा करें अर्थात् यदि मूल्य सन्तुलनाभीष्ट मूल्योंसे अधिक होने लगे तो ये शक्तियां उन्हें कम करनेमें ससन्न होजायें। और यह कार्य तभी सम्पन्न हो सकता है, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी दशा में मूल्योंके बढ़तेही पूर्तिकी मात्रा मागसे अधिक होजाये। उसी प्रकार मूल्योंके कम होनेसे मागका पूर्ति की मात्रासे अधिक होना आवश्यक है। अर्थशास्त्री हिकसाने मूल्योंमें परिवर्तन होनेवाले कारणों में माग अथवा पूर्तिपर पड़नेवाले प्रभावोंको आय-प्रभाव तथा स्थानापन्न-प्रभावमें विभाजित किया है। किसी वस्तुका मूल्य कम होनेके कारण लोग उसका अधिक प्रयोग करना आरम्भ कर देनेहैं और दूसरी वस्तुओंका कम।

यह हुआ मूल्यके कम होनेका स्थानापन्न प्रभाव। इस प्रभावसे उस वस्तुकी माग अधिक और पूर्ति कम होती है। किसी वस्तुका मूल्य कम होनेका यह अर्थभी हो सकता है कि खरीदनेवालों की आयमें वृद्धि हुई और बेचनेवालों की आयमें न्यूनता। मान लीजिए कोई व्यक्ति उस वस्तुपर मूल्य कम होनेसे पहिले १० रुपये खर्च करसकता था। मूल्य कम होनेसे वह उस वस्तुकी उतनीही मात्रा अब १० रुपये से कम खर्च करके प्राप्तकर सकता है। मूल्य कम होनेसे पहिले और बादके व्ययके अन्तरको उसको आय-वृद्धि मान लीजिए। यदि इस वृद्धिको वह उसी वस्तुकी अधिक मात्रा खरीदनेमें प्रयुक्त करता चाहता है तो उस वस्तुकी मागमें आय-प्रभाव द्वाराभी वृद्धिही होगी और बेचनेवाले भी अपनी आयकी कमीको पूरा करनेके लिए उसकी अधिक मात्रामें पूर्ति करेंगे। और यदि इस प्रभाव द्वारा माग और पूर्तिमें एकही जैसी वृद्धिही तो अन्ततोगत्वा केवल स्थानापन्न प्रभावही मागको बढ़ानेका कारण होगा, आय-प्रभाव नहीं। किन्तु यदि वह वस्तु घटियाहै और उसका अधिक मात्रामें प्रयोग इस व्यक्तिको अभीष्ट नहीं; तो होसकता है कि वह आय-प्रभाव द्वारा प्राप्त आयकी वृद्धिको किसी दूसरी वस्तुके खरीदनेमें प्रयोग करे और इसप्रकार उस वस्तुकी मागमें आय-प्रभाव द्वारा तनिकभी वृद्धि न हो। हम देखते हैं कि आय-प्रभावसे पूर्तिमें तो वृद्धि होगी ही। इसकारण उस वस्तुका मूल्य और भी कम होजाने की सम्भावना है।

संस्था का संतुलन

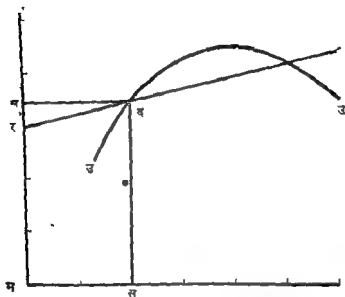
मनुष्य केवल विनियम द्वाराही उन वस्तुओंको जो उसके पासहैं, देकर अन्य वस्तुएं जो उसके पास नहीं हैं और जिन्हें प्राप्त करनेकी उसकी इच्छाहै, प्राप्त नहीं कर सकता। इस क्रियाको पूरा करनेके लिए दूसरा साधन उसके पास अपनी वस्तुओं की उत्पादन द्वारा नयी वस्तुओं में परिवर्तन करलेना है। स्पष्टहै कि ऐसा वह तभी करेगा जबकि उत्पादन द्वारा उसे साधारण विनियमसे अधिक लाभ मिलने की आशाहो अर्थात् जब उत्पादन द्वारा परिवर्तित वस्तुओंका विनियम-साध्य मूल्य परिवर्तनके पश्चात् अधिक होजाये। उत्पादनका कार्य आधुनिक संसारमें विशेष संस्थाओं द्वारा हुआ करता है। उनके चलानेवाले उद्योगपति होते हैं। वे उत्पादन के साधनोंके प्रयोग द्वारा उत्पादन कार्यमें सलग्न होतेहैं और इन साधनोंसे प्राप्त

सेवाओं को नयी वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। इसलिए ऐसी उत्पादन-संस्था का मुख्य उद्देश्य उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उनके द्वारा प्राप्त वस्तुओं को बेच कर साधनों तथा उत्पन्न वस्तुओं के कुल मूल्य में अधिक से अधिक अन्तर पैदा करना है। ऐसी संस्था के सन्तुलन की अवस्था प्राप्त करने का विवेचन हिक्म इस प्रकार करता है। मान लीजिए कि एक उत्पादन के साधन 'क' को एक वस्तु 'ख' में परिवर्तित करने के कार्य में एक संस्था ससम है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है और क साधन और 'ख' वस्तु दोनों के मूल्य निश्चित रूप से ज्ञात हैं, उत्पादन कार्य संस्था के लिए उस समय तक लाभदायक है जब तक कि 'ख' वस्तु द्वारा प्राप्त कुल मूल्य उसके उत्पादन में प्रयुक्त 'क' साधन पर व्यय किये गये कुल मूल्य से अधिक है। संस्था का श्रेय 'ख' वस्तु की उतनी मात्रा उत्पन्न करने में है जितनी वस्तु में प्राप्त कुल मूल्य और साधन पर व्यय किये गये कुल मूल्य में अधिकतम अन्तर हो। देशाशास्त्र की सहायता से सन्तुलन की स्थिति को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। मान लीजिए हम 'म, क' मूल्य रेखा पर साधन की प्रयुक्त मात्रा दिखाते हैं और 'म, ख' मूल्य रेखा पर इस मात्रा के प्रयोग से प्राप्त वस्तु की मात्रा दिखाने हैं। मान लीजिए प्रयुक्त



साधन की मात्रा 'म, स' है और उसके प्रयोग से प्राप्त उत्पन्न वस्तु की मात्रा 'स, व' है। 'म, ल' को 'स, व' के सम बनाकर उससे 'ल, र' इतना काट लीजिए जिससे कि 'ल, र' द्वारा वस्तु की उतनी मात्रा दिखायी जा रही हो, जिसका कि मूल्य प्रयुक्त साधन 'म, स' के मूल्य के सम हो। तब 'म, र' वस्तु की उस मात्रा का चोटक है जो

संस्था को अधिक प्राप्त होती है और इसका कुल मूल्य उत्पादन व्यय और कुल प्राप्त आयके अन्तर का शेषक है।



संस्थाके सन्तुलनके लिए आवश्यक है कि 'म, र' अधिकतम हो और मदा लाभ (न कि हानि) का शेषक हो। यह अवस्था तभी प्राप्त होसकती है जब कि 'र, ब' रेखा उत्पादन रेखाको दो या अधिक स्थानोंमें काटनेके स्थानपर केवल एकही स्थान 'ब' पर स्पर्श ही करे। गणितशास्त्र की सहायतासे यह सिद्ध किया जासकता है कि यह अवस्था केवल उस समय प्राप्त होसकती है जब कि उत्पादनके साधनका मूल्य उसके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिके सम होजाये अथवा उत्पन्न वस्तुका मूल्य उसके सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होजाये। इसके अतिरिक्त 'म, र' के अधिकतम होनेके लिए यहभी आवश्यकहै कि जिस स्थानपर 'र, ब' रेखाका उत्पादन रेखाके सम्पर्क हो उस स्थानपर उत्पादन-रेखा 'म, स' मुख्य रेखाकी ओर उभरी हुईसी हो। साधारण शब्दोंमें इसका अर्थ यह होगा कि सन्तुलनकी स्थिति उससमय प्राप्त होतीहै जबकि सीमात्त उत्पत्तिका क्रमशः कमहोना आरम्भ होजाये अथवा सीमान्त उत्पादन-व्ययकी क्रमशः वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त सन्तुलनकी अवस्था प्राप्त होने

पर यहभी आवश्यक है कि औसत उत्पत्तिका ह्रास होरहा हो अथवा औसत उत्पादन-व्ययकी वृद्धि।

सस्याके सन्तुलन प्राप्त करनेकी स्थितिको ह्रिक्सके अनुसार दो प्रकारसे दर्शाया जासकता है। एक तो :

- १ जिससमय साधनका मूल्य उसके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिके मूल्य के सम होजाये।
- २ सीमान्त उत्पत्तिका ह्रास होना आरम्भ होजाये।
- ३ औसत उत्पत्तिका ह्रास होना आरम्भ होजाये।

और दूसरे :

- १ जब वस्तुका मूल्य उसके सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होजाये।
- २ सीमान्त उत्पादन-व्ययकी क्रमशः वृद्धि होना आरम्भ होजाये।
- ३ औसत उत्पादन-व्ययकी वृद्धि होना आरम्भ होजाये।

प्रायः उत्पादनके साधनो अथवा उत्पादन-विधियोंके छोटे छोटे प्रसोमें अवि-
भाज्य होनेके कारण और अधिक मात्रामें उत्पत्ति करनेसे उत्पादन-व्ययमें बाह्य
अथवा अभ्यान्तरिक वचतोके कारण उत्पत्ति की क्रमशः वृद्धि (अथवा उत्पादन-
व्यय का क्रमशः ह्रास) होजाता है और जबतक उत्पत्तिकी वृद्धिसे उत्पादन-व्यय
का ह्रास होता रहेगा, सस्याका व्यवस्थापक उत्पत्तिकी मात्राको बढ़ानेकी ही चेष्टा
करता रहेगा। परन्तु ससारमें उत्पादनके साधनोका बाहुल्य नहीं; न्यूनता है और
यदि हम वस्तु उत्पन्न करनेवाले साधनोमें से एक साधनका प्रयोग तो अधिकाधिक
मात्रा में करते चले जायें परन्तु अन्य साधनोकी मात्रा में तनिकभी परिवर्तन न करें
अथवा कम मात्रामें परिवर्तन करें तो उत्पादन का क्रमशः ह्रास अथवा उत्पादन-
व्ययकी क्रमशः वृद्धि होना शुरू होजाती है। यदि यहभी मानलिया जाये कि किसी
विशेष सस्याको उत्पादनके सब साधन अधिकाधिक मात्रामें प्राप्त करनेमें कोईभी
आपत्ति नहीं तो भी उत्पत्तिकी मात्रा बढ़ जानेपर सस्याके प्रबन्ध-कार्यकी कठि-
नाइयोके कारण सीमान्त उत्पादन-व्ययमें वृद्धिका होना समय आनेपर अनिवार्यसा
होजाता है। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति आनेपर व्यवस्थापक उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि
करना बन्द करदेगा। परन्तु यदि सीमान्त उत्पादन-व्यय अपनी न्यूनतम अवस्थासे
थोड़ाही अधिक हो तो हो सकताहै कि उस अवस्थामें सीमान्त-उत्पादन-व्यय औसत

उत्पादन-व्ययसे कमहो और यदि सस्था वस्तुको सीमान्त-उत्पादन-व्ययके सम मूल्य पर बेचेतो उसे हानि होगी। इसी कारण सस्थाके सन्तुलनके लिए न केवल सीमान्त-उत्पादन-व्ययका बढ़ना आरम्भ होजाना ही आवश्यकहै बल्कि औसत उत्पादन-व्ययका भी।

उद्योग और उसका सन्तुलन

एकही प्रकारकी वस्तु उत्पन्न करनेवाली ऐसी बहुतसी सस्थाओंके समूहको उद्योग कहते हैं। यदि किसी उद्योगमें सलग्न सस्थाओंको उसके समानही उत्पत्तिकारक अन्य उद्योगमें सलग्न सस्थाओंसे अधिक लाभ प्राप्त होरहा हो तो पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी दृष्टिसे उस उद्योगमें नयी सस्थाएँ स्थापित होनेकी सम्भावनाहै और इसके विपरीत यदि उसमें कम लाभ प्राप्त होरहा हो तो उसमें मलग्न कुछ सस्थाओंके बन्द होजाने की सम्भावना है। इसकारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दृष्टिसे किसी उद्योग को सन्तुलन की अवस्था उससमय प्राप्तहोगी जबकि उस उद्योगमें सलग्न सस्थाओंकी सख्यामें और प्रत्येक सस्थाकी उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि अथवा ह्रासकी कोई भी सम्भावना न हो। स्मरण रहें कि एकाधिकारकी स्थितिमें औसत तथा सीमान्त उत्पादन व्यय का ह्रास होता रहनेपर भी सन्तुलनकी अवस्था प्राप्त होना सम्भव है। परन्तु इस स्थितिमें भी सस्था एकदम बढती ही नहीं चलीजाती। कही न कही तो उसे अपनी उत्पादनकी मात्रा बढानेसे रुकनाही पड़ेगा। यदि इस सम्बन्धमें कि उसे अधिकसे अधिक कितनी मात्रामें उत्पादन करना चाहिए, बढ़तेहुए सीमात उत्पादन व्ययसे सहायता नहीं मिलपाती तो उत्पन्न वस्तुके बाजारके सीमित प्रसारसे तो मिल सकती है। वास्तवमें बाजारकी सीमा और सीमान्त उत्पादन व्यय दोनों साथ साथ कार्य-शील रहते हैं।

उत्पादन और उसका सन्तुलन

वास्तविक आर्थिक संसारमें साधारण मनुष्य और सस्थाओंके व्यवस्थापक दोनों प्रकारके व्यक्ति मिलते हैं। साधारण मनुष्य उपभोग्य वस्तुओं अथवा उत्पादनके

साधनो दोनोका लेन-देन करतेहैं और इसीप्रकार व्यवस्थापक भी। साधारण मनुष्य उपभोग्य वस्तुएँ खरीदताहैं तो निजी उत्पादनके साधनोको बेचता है। सस्याग व्यवस्थापक उत्पादनके साधन खरीदताहैं तो उपभोग्य वस्तुओको बेचता है। सेवाओ का लेन-देन केवल साधारण मनुष्यो द्वारा होता है और अर्थनिर्मित वस्तुओका केवल मस्यागो द्वारा। इन विभिन्न वस्तुओके विभिन्न बाजार होतेहैं और सन्तुलन उन मूल्यपर स्थापित होताहैं जिसपर कि प्रत्येक वस्तुकी माग और पूर्ति सम हो जाये। केवल उत्पादनके साधनोके मूल्योमें सन्तुलनके सम्बन्धमें कुछ कहना शेष है। सस्याके सन्तुलन की विवेचना करने हुए हम देखही चुकेहैं कि किसी साधनके मूल्य का उस साधनकी सीमान्त उपयोगिता अथवा उत्पत्तिके मूल्यके सम होना आवश्यक है, क्योंकि यदि सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य साधनके मूल्यसे अधिक होगा तो उस साधनका अधिक प्रयोग करनेसे व्यवस्थापककी आयमें उत्पादन-व्ययसे अधिक वृद्धि होगी और इससे व्यवस्थापकको उसका प्रयोग बढ़ानेकी प्रेरणा प्राप्त होगी। दूसरे सन्तुलन-प्राप्तिके लिए यहभी आवश्यकहै कि प्रत्येक साधनकी प्रत्येक इकाईका एकही जैसा मूल्यहो, अन्यथा व्यवस्थापक अधिक मूल्यवाली इकाइयोके स्थानपर कम मूल्यवाली इकाइयोका प्रयोग करना आरम्भ करदेगा और इसकारण उस साधनके बाजारका सन्तुलन भग होजायेगा। हम देखचुकेहैं कि साधारण वस्तुओके बाजारमें भी सन्तुलन प्राप्त करनेके लिए यह आवश्यकहै कि वस्तुकी प्रत्येक इकाई का एकही मूल्य हो।

इसके प्रतिरिक्त यहभी आवश्यकहै कि विभिन्न साधनोके मूल्य और उनके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पादन शीलतामें एकही जैसा अनुपात होना चाहिए। अर्थात् यदि किसीभी साधनकी सीमान्त उत्पादन शीलता को उसके मूल्यसे भाग दियाजाये, तो फल हरबार एकही होना चाहिए चाहे साधन कोईभी हो। गणितशास्त्रकी भाषामें कहाजा सकताहै कि -

$$= \frac{\text{साधन 'क' की सीमान्त उत्पादनशीलता}}{\text{साधन 'क' का मूल्य}} = \frac{\text{साधन 'ख' की सीमान्त उत्पादनशीलता}}{\text{साधन 'ख' का मूल्य}}$$

$$= \frac{\text{साधन 'क' की सीमान्त उत्पादनशीलता}}{\text{साधन 'य' का मूल्य}}$$

$$= \dots\dots\dots$$

इसीप्रकार जितनेभी साधनोंका प्रयोग किया जा रहा हो। कारण यह है कि एक साधनसे सम्बन्धित यह अनुपात अन्य साधनोंसे सम्बन्धित इसी प्रकारके अनुपातोंसे अधिक होजाता है तो व्यवस्थापकको उम साधनका और अधिक प्रयोग करनेसे लाभ प्राप्त होता है।

अन्तमें सन्तुलनके लिए यहभी आवश्यक है कि किसीभी साधनकी उन समस्त इकाइयोंका जो बाजारभाव या उससे कम मूल्यपर प्राप्त होरही हों, उत्पादन कार्य में प्रयोग कियाजाये। क्योंकि यदि ऐसी इकाइयोंका प्रयोग न कियाजायेगा तो उन के स्वामी उनका मूल्य कमकरके स्थापित सन्तुलनको भंग करदेंगे।

प्राप्त करनके लिए कुछ न कुछ उद्योग करना पड़ता है। स्वाभाविक था कि वस्तुओं के मुख्य गत्वकी खोजमें सर्वप्रथम इन्हीं अत्यन्त गुणाकी ओर दृष्टि जाती और राजतक मूल्यवत् जितनभी मिद्धान्त निमाण कियगय ह उन सबमें केवल गणितप्रधान अथशाम्भ्रको छोड़कर इन्हीं दा में से किमी एक्को मूल्यका मुख्य कारण निर्धारित करन की चेष्टा कीगयी है।

मूल्य का श्रम सिद्धान्त

पाश्चा य ग्रन्थसाम्प्रती विशपकर ग्रन्थो विद्वान एडम स्मिथक। अपन साम्प्रका जन्मदाता मानत ह। परन्तु इस महापुरुषस पहिलभी आर्थिक समस्याए हुआही करत। थी आर लोग उनपर विचार कियाही करत थ। मयक सम्बन्धमें भी ऐसा ही हुआ है। पश्चिममें अवतक धर्म और धार्मिक संस्थाओंका बोलबाला रहा तबतक मूल्यका न्याय और औचित्यमें सम्बन्धित किता जानाथा अर्थात् यदि किसीकी वस्तुका मूल्य न्याय-युक्त और उचित नह। ना ऐसा मूल्य पानवाला व्यक्ति अपराधी समझा जाताथा तब उम उचित दंड दिया जाताथा। परन्तु न्यायाधीशोंके मनमें प्रश्न उठा कि मूल्यके उचित तार न्याय युक्त हानकीभी तो काट कर्माटी हानी चाहिए। कुछ समयतक व तार परम्पराको कसौटी मानते रह परन्तु जब अपराधिवान अपन बचावके लिए यह कहता आरम्भ किया कि अमुक वस्तुका मूल्य मैं इसलिए अधिक लियाहै कि मुझे उसे प्राप्त करनके लिए अधिक श्रम करना पडा था तो मूल्यक उम मिद्वान्तकी नींवपडी जिसे हम श्रम-मिद्वान्तके नामसे पुकारते हैं। एडम स्मिथम पदवर्ती ग्रन्थसाम्प्रियामें टा मिद्वान्तक अनु-यायी पता लाक करीभा आते हैं। डमीनगृह बरीदान बीड और निकालग आरय तुरोंड यदि साम्प्रो किया वस्तुका अपराधिवान का उमक मूल्यका साम्प्र-विन कारण मानत थ। एडम स्मिथका श्रम मिद्वान्तका परिपापर होनहुत भी यशस्व पदवर्ती साम्प्रियान्त मिद्वान्तका एकदिवस तबका प्रयत्न किया। यद्यपि इस प्रयत्नमें वह असफल रह पर तु उनक मूल्यमें सम्बन्ध रखनवान मिशराराग कोई न कोई वाक्य ऐसा मिल जाताहै किम्व आधरपर उत्तर परवर्ती अथ-शास्त्रियान मूल्यक नय मिद्वान्त बनानका प्रयत्न किया है।

राष्ट्र की सम्पत्ति नामर ग्रपनी पुस्तकमें वह निखन है किमी वस्तुका मूल्य स हमारा अभिप्राय दो प्रकारके मूल्यसे जाना है। एकतो उस वस्तुका औपयामिक मूल्य और दूसरा उसका विनिमय-माध्यम मूल्य। व वस्तुएँ जिनका औपयामिक मूल्य अविचलनम होता है उनका विनिमय-माध्यम मूल्य प्रायः बुद्धिभी नहीं होता। पानीम अधिः उपयोगी वस्तु कठिनताम ही मिलती परन्तु इससे बदलमें किसी वस्तुको पाना प्रमम्भवमा ही है। हीर मनुष्य जीवनक लिए तनिक भी उपयोगी नहीं परन्तु उनकी विनिमय-माध्यम शक्ति अपार है।

इतना कहकर एडम स्मिथन औपयामिक मूल्यको तो निम्नाजनि दे दी और उसका उपरान्त विनिमय-माध्यम मूल्यका नत्वानुसन्धान की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। उनका मतानुसार किसी वस्तुके विनिमयमाध्यम मूल्यका कारण श्रम ता है ही परन्तु कभीतो वह उस वस्तुके प्राप्त करने में जा श्रम करना पड़ता है उस मूल्य का कारण और माप मानने ह जैसे इस दृष्टान्तम विदित है कि यदि एक पछीके गिनार करतमें शिकारी नागाको एक भुगवे गिनार करतसे दुगुना श्रम करना पड़ तो एक पछीके बदलमें दो भुग मिलन चाहिए तथा कभी वह वस्तुके बदलमें जितना श्रम प्राप्त किया जायवे इस श्रममें श्रमका प्रयोग करतह अर्थात् वस्तु लकर जितना श्रम काड मनुष्य हमारा लिए करनको उद्यत हाजाता है उस उस वस्तुके मूल्यका कारण और माप मानन ह। इस मापके अनुसार यदि एक भुग दस शिकारियाँ पट भर सकताह और एक पछी केवल एक शिकारी का तो एक भुगके बदलमें पाच पछी ता अवश्य ही मिलन चाहिए। कोई सा भी श्रम खलीजिए श्रम वस्तुआक वास्तविक मूल्यका कारण तो ह ही। इन्ध केवल नाममात्रके मूल्यका श्रोतक ह। इसम तनिकभी मन्देह नहीं।

रिकार्डोन एडम स्मिथके प्रथम मापको ठीक माना है और मार्थसन द्वितीय मापको। रिकार्डोका मत था कि उपयोगिता मूल्यके लिए आवश्यक भलही हो पर वह मूल्यका माप नहीं है। विनिमय-माध्यम मूल्यका केवल एक माप है और वह है वस्तुओंमें खपा हुआ श्रम।

समाजवादके प्रबलक काल मार्क्सन स्मिथ और रिकार्डो दोनोंमे प्रेरणा लेकर मूल्यके श्रम-सिद्धांतको औरभी पुष्ट करनका प्रयत्न किया। वस्तुओं के वास्तविक मूल्यका कारण श्रम तो ह ही। परन्तु उसके मतानुसार पूँजीभी संचित श्रमके

अतिरिक्त और कुछ नहीं। मार्क्सने एक नये सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जिसे 'अतिरिक्त-मूल्य' के नामसे पुकारा जाता है। अतिरिक्त मूल्यका सृजन इमप्रकार होता है। किसी वस्तुका भूतपूर्व उसकी निर्माणमें जिनका श्रम करना पड़ा हो, उसमें निर्यागित होता है पर श्रमजीवीको केवल उननाही मूल्य मिलता है जितना कि श्रमके सृजन अर्थात् श्रमिकके पालनपोषण और रहनसहन पर लगाये गये श्रमके बराबर हो। वस्तुके मूल्य और श्रमजीवीको दिये गये मूल्यमें जो अन्तर होता है उसीका नाम अतिरिक्त मूल्य है। मूल्य उस श्रममें निर्धारित किया जाता है जो किसी समाजकी आर्थिक और औद्योगिक स्थितिके अनुसार आवश्यक हो।

उत्पादन-व्यय सिद्धान्त

श्रम सिद्धान्तके प्रतिपक्षियोने यहपि श्रमको मूल्यका मुख्य कारण तथा माप ठहराया है परन्तु वे भी उत्पादनके अन्य साधनों भूमि, पूँजी इत्यादिके अस्तित्वको स्वीकार करते ही रहे। एडम स्मिथने तो यहभी मान लिया कि उनका श्रम-सिद्धान्त केवल अत्यन्तही असम्भ्य समाजों पर लागू होता है। सम्भ्यताके प्रादुर्भावके अनन्तर हमें भूमि तथा पूँजी द्वारा प्राप्त सेवाओंको भी मूल्यका ही अद्य माननेका आदेश होता है। रिकार्डों का मत भी एडम स्मिथमें भिन्न नहीं है। और तो और पूँजीपतियोंके कट्टर विरोधी कार्ल मार्क्सने भी पूँजी और भूमिके अस्तित्वको तो मानाही है परन्तु वह भूमिको प्रकृतिकी देन और पूँजीको संचित श्रम मानकर उन्हें श्रमद्वारा उत्पन्न किये गये मूल्यमेंसे किसी भी भागका अधिकारी नहीं मानता।

श्रम सिद्धान्तके सशोधनकी चेष्टा करते हुए सीनियरने विचार प्रकट किया कि भूमि और श्रमके अतिरिक्त एक तीसरा उत्पादनका साधन है जिसके द्वारा पूँजीका सृजन होता है। इस साधनका नाम उगने उपभोग-व्याक्षेप रखा और उत्पादन-व्यय में न केवल श्रमके वृष्ट बल्कि उपभोग-व्याक्षेपकी वदनाको भी सम्मिलित किया। मिलने जोखिम एक और साधन जोड़ा और इमप्रकार श्रमका वृष्ट, उपभोग-व्याक्षेप की वेदना और जोखिम तीनों उत्पादन-व्यय और मूल्यके कारण माने जाने लगे। मार्शलने व्यवस्था और क्लार्कने उद्योग-माहमको भी उत्पादनका साधन माना है। मार्शलने उत्पादन-व्ययकी व्याख्यामें एक और भी सशोधन किया। उनका कहना

हैं कि इन विविध माधना को व्यवस्थापन या उद्योगपति एकरित करना है। इन्हें एकरित करके लिए उस भूमिपतिता कर, श्रमजीवीका भजुरी पूजोपतिको व्याज और अपन आय को लाभ देना पड़ता है और वह इन्हें देता है द्रव्यके रूपमें। पण्डित बरके। इसा उद्योग-उत्पादन-व्ययको आकने समय हमें कष्ट, वेदना जोमिम व्याजिने मान पर उतर सौदित मरना है। आगना मान देना चाहिये। प्रभाकरा अगनामि उद्योग और वादना हम मिदालन में यम मगापन किया कि मलय उत्पादन-व्ययपर निभर नया बलिक पुनः उत्पादन व्ययपर निभर जाना है।

• श्रम और उत्पादन व्यय मिदालनो की नुटिया

१ विनिमय माध्यम भूतमके मिदालनका मुख्य काम यह है कि वस्तुभावे विनिमय अनुपातम पास्परिक विनिमय और इस अनुपातमें समय समय पर होतबाल परिवर्तना का भलीप्रकार बहिष्प्राप्ति देना दे। स्पष्ट है श्रम मिदालन इस काममें सफल नहा पाता।

२ भिन्न भिन्न प्रकारके श्रमम भेद जाना है। कुशल, गुरुकुल और अकुशल श्रम एकत्र प्रकारके नहा है। श्रम-मिदालन के मानन म यह भेदभेद भिन्नाना है।

३ एमो वस्तु जो मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य उपयोग नहा चाह किन्तु श्रमम उत्पन्न काजाय कभीभा मूल्यदान नहा पापाती।

४ श्रम मिदालन केवल वस्तुभाकी पूतिकी ओर ध्यान देना है। मागकी ओर नही।

५ किसी वस्तुकी न्यूनताभी उसके मूल्यका एक कारण मानोइतानी है। इस कारणक अनुसार तो श्रम उत्पत्ति द्वारा इस न्यूनताको कम करके मूल्य मूलनके स्थानपर मूल्य-मागका कारण बनता है।

६ यहभा माननाहो पड़ता कि श्रमक अनिश्चितभी श्रम उत्पादनके माधन है ही। इसालए वचन श्रमका मूल्यका कारण और माप तो नही बनसकता।

उत्पादन व्यय मिदालन द्वारा इस नुटिका दूर करनका प्रयत्न कियागया है। परंतु यह मिदालनभी श्रम-मिदालनकी तरह उसकी आय नुटियाग नुटित है। इसके

प्रतिरिक्त, उद्योग-साधन जो गिराव डालादि अभिन्न वस्तुओं का परस्पर जोड़ना सम्भव है। और यदि भागनका अनुसरण करना हम इनका द्रव्य के रूप में मूल्य निर्धारण करने का प्रयत्न करते हैं तो मूल्य द्वारा ही मूल्य के कारण और भाग की जिज्ञासा तक प्रवृत्त नहीं होत व्यर्थ है। इसके अनिर्वक्त कई एक वस्तुएं साथ साथ उत्पन्न होती हैं इसलिए उनमें प्रत्येक का उत्पादन-यथ निर्धारित करना कठिन हो जाता है।

सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त

इन वृत्तियों को दूर करने के लिए जीव मन हर्मंड में, मैंगरन अम्प्लिसम और वालरमन म्विजर्नल में मूल्य की सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त का प्रचलित किया। इस सिद्धान्त के अनुसार मूल्य वस्तु का मूल्य किसी कार्य के लिए उसकी सीमान्त उपयोगिता के तुल्य होता है। यह सिद्धान्त पूर्ण के स्थान पर मांग को अधिक महत्व प्रदान करता है। बीजर ग्रामवाचक और विकसनीय इस सिद्धान्त के बड़े बड़े अनुयायियों में हैं।

एक समय न आपयोगिक मूल्य और विनिमयसाध्य मूल्य में पारस्परिक विरोध की शक्यता थी। मूल्य के महानुसार विनिमयसाध्य मूल्य औपयोगिक मूल्य में अधिक महत्व की महत्ता क्योंकि कोई भी मनुष्य अधिक उपयोगी वस्तु देकर कम उपयोगी वस्तु लेने के लिए उद्यत न होगा। इसी तरह औपयोगिक मूल्य विनिमयसाध्य मूल्य में कम भी नहीं हो सकता क्योंकि देनवाला उपयोगिता की हानि सहन नहीं करता तो लेनवाला भी नहीं करेगा। इसलिए इन दोनों मूल्यों में समानता का होना आवश्यक है, परन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं। कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता न केवल भिन्न पुरुषों के लिए भिन्न होती है बल्कि एक ही पुरुष के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों और भिन्न भिन्न समयों में भिन्न हो सकती है। उपयोगिता घटती बढ़ती रहती है। विनिमयसाध्य मूल्य किसी एक समय पर घटना घटना नहीं है और इस वस्तु की उपयोगिता न बराबर नहीं बल्कि उस वस्तु की उस समय की सीमान्त उपयोगिता के बराबर होता है। सीमान्त उपयोगिता हम देखते हैं कि किसी वस्तु के बाहुल्य और बर्तन में सम्बन्धित है। इसलिए इस सिद्धान्त के अनुसार यह भी आवश्यक नहीं कि मूल्य न केवल उपयोगिता बल्कि उसके माध्य

न्यूनतापर भी निर्भर है क्योंकि जिन वस्तुओं की न्यूनता होगी उनकी सीमान्त उपयोगिता और फलन मूल्य भी अधिक होगा और जिन वस्तुओं का बाहुल्य होगा, उनकी सीमान्त उपयोगिता और फलन मूल्य भी कम होगा। इसी कारण होरे बहुत मूल्य है और दोनों का कुछ भी मूल्य नहीं।

मार्शल ने इन सिद्धान्तों के पारम्परिक विरोधकों मिटान की कोशिश की। उनके मतानुसार न तो रेबन उपयोगिता और न केवल उत्पादन-व्यय ही वस्तु दोनों मिलकर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने हैं। मूल्य, माग तथा पूर्ति दोनों पर निर्भर है। माग का सीमान्त उपयोगिता का प्रभाव पड़ता है और पूर्ति पर उत्पादन-व्यय का और इस मूल्य निर्धारण का यहाँ हमें दोनों का एक ही जैसा महत्व प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मार्शल ने अल्पकालीन और दीर्घ कालीन मूल्य में भेद किया, उनके मतानुसार अल्पकाल में तो सीमान्त उपयोगिता का प्रभाव प्रबल रहता है और दीर्घकाल में उत्पादन-व्यय का।

प्राधुनिक अर्थशास्त्री भी मूल्य के लगभग इसी सिद्धान्त को मानते हैं। केवल उत्पादन-व्यय और सीमान्त उपयोगिता को सम्भार पारमै सन्तुष्ट किया गया है। प्राचीन काल में हम देख चुके हैं उत्पादन-व्यय को श्रम, उपाध-व्याप, जालिम आदि उत्पादन के साधनों से होने वाले कष्ट वेदना इत्यादि से सम्बन्धित करने की परिपाटी थी। प्राधुनिक अर्थशास्त्री हम परिपाटी में विद्वान नहीं रहते। उनका कहना है कि प्राथमिक साधनों की समार में न्यूनता है। उनके द्वारा सिद्ध किया जानेवाले मनुष्यी उद्देश्यों को बाहुल्य है। जब किसी एक साधन को हम किसी विशय उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो उसके द्वारा सिद्ध होनेवाले दूसरे एक अथवा एकसे अधिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती। यदि हमारा उद्देश्य उस साधन द्वारा अपनी आवश्यकताओं को नृत्त करनेवाली वस्तुएं उत्पन्न करना था तो उन वस्तुओं का उत्पादन-व्यय उन वस्तुओं द्वारा निर्धारित किया जाये जो हम उस साधन द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं वस्तु हमने नये की प्रयत्न किसी भी साधन के अन्य प्रयोगों का त्याग उस साधन की विशेष प्रयोग में होनेवाले उत्पादन-व्यय है। इसे अवसर-व्यय, तुलनात्मक-व्यय या वैकल्पिक-व्यय के नामों से पुकारा जाता है। ये व्यय वस्तुओं की पूर्ति पर उनकी न्यूनता या आधिक्य को घटा बढ़ाकर मूल्य पर प्रभाव डालते हैं। चूंकि किसी साधन विशेष का किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में प्रयोग उस

वस्तुकी माग देखकर ही किया जाता है इसलिए पूर्ति और तुलनात्मक-व्ययभी परस्पर-विरोधी मागों द्वारा ही निर्धारित होता है।

उपयोगिताको मागका मूल कारण तो माना ही जाता है परन्तु उपयोगिताका सम्बन्ध है मनोविज्ञानमें और मनोवैज्ञानिक इच्छाओं इत्यादिकी निर्बलता और प्रबलताको ठीक मापना सम्भव नहीं है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि प्रत्येक इच्छा किसी दूसरी इच्छासे न्यून या अधिक है। इसमें लाभ उठाकर पैरेटो, हिक्स आदि श्रृंखलाश्रितियों ने अपने शास्त्रमें इच्छाओंकी निर्बलता और प्रबलताके तुलनात्मक परिमाण, वस्तुओं और साधनोंके स्थानापन्नकी योजनाओंका प्रयोग किया है। इसका विवेचन हम पीछे कर चुके हैं।

उत्पादन के साधन—भूमि

उत्पादन का अर्थ

साधारणतया उत्पादनका अर्थ किसी वस्तुको उत्पन्न करना होता है। परन्तु किसी वस्तुकी सर्वथा नवीन सृष्टि नहीं होसकती, उसके निर्माणके लिए जिन मूल द्रव्य-दानाकी आवश्यकता पड़तीहै वह सबकेसब हमको प्रकृतिद्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्राकृतिक सामग्रीकी अनन्त प्रचुरतासे अभ्यवस्था करके उसको इच्छित रूप देना उत्पादन कहलाना है। हम कह सकनेहैं कि मनुष्य उत्पन्न नहीं करता, केवल वस्तुओं वा व्यवस्थानुक्रम इसप्रकार बदल देताहै कि वह उसकी तत्कालीन आवश्यकताके अनुसार इच्छामार्गके तमके आर्थिक अनुकूल होजाती है। अपन शारीरिक श्रम मस्तिष्क श्रमवा उरभोग-आक्षेपकी सहायतासे मनुष्य वस्तुएँ उत्पन्न नहीं करता बल्कि उन वस्तुओंमें पूर्वनिहित उपयोगिताका उत्पन्न करता है। इस स्थानपर यह कहना भी अनुचित न होगा कि आधिरू दृष्टिमें उत्पादन त्रिया उस समस्तक समाप्त नहीं होती जबतक कि वस्तु उसका प्रयोग करनेवाले के पास नहीं पहुँच जाती। इस कारण उत्पादन त्रियाओंमें केवल कृषि, उद्योग-धंधे और वाहतो द्वारा वस्तुओंका उत्पन्न करनाही नहीं बरन् ऐसी वस्तुओंका उनके प्रयोग करनेवाला तत्काल पहुँचाने का प्रबन्ध करनाभी सम्मिलित है।

हम देखचुके हैं कि मनुष्य अपने धर्मद्वारा केवल वस्तुओं की अपनी इच्छामार्गके अनुकूल बना सकता है अर्थात् आर्थिक दृष्टिसे उनकी उपयोगितामें वृद्धि करसकता है। यह उपयोगिता अनन्त प्रकारसे बढ़ायी जासकती है। अर्थशास्त्रियोंने इस उपयोगिताकी वृद्धिसे भिन्न भिन्न दृष्टियोंसे देखा है। कुछ सोचनेने उपयोगिताको रूप, स्थान तथा समय परिवर्तन द्वारा बढ़ाना सम्भव माना है। रूप-परिवर्तन द्वारा, प्राकृतिक सामग्री को इसप्रकार का रूप देदिया जाता है, जिससे वह मनुष्यको,

उच्छ्रायोंके समकूल होजाती है। जैसे वषामका रूप बदलकर मूत कातना, मूतका रूप बदलकर कपड़ा बनाना। स्थान-परिवर्तन द्वारा वस्तुओंको उस स्थानसे जहा पर उनकी उपयोगिता तनिक भी नहीं होनी अथवा कम होतीहै, उस स्थानपर पहुंचा दिया जाताहै, जहा उनकी उपयोगिता होनी है, जैसे कोयला खानसे नगर तक यात्रा उपभावना तक पहुंचा दियाजाना है। वास्तवमें यातायातका उद्देश्य स्थान-परिवर्तन द्वारा उपयोगितामें वृद्धि करना है। समय-परिवर्तन द्वारा वस्तु-ओंको उस समय उपलब्ध कियाजानता है जिस समय वास्तवमें उनकी आवश्यकता होती है। प्रत्येक पजीपति जिसने उपभाग-व्याप्रेष द्वारा धनका संचय किया है, वर्तमान कालमें उसे ऋणमें डेकर समय-परिवर्तन द्वारा धनकी उपयोगिता बढ़ाता है। लेनवालेके लिए धनकी उपयोगिता वर्तमानमें है और देनेवालेके लिए भविष्य में। जिसने उपयोगिताके उत्पादनको तीन वर्गोंमें विभाजित किया है। एकतो ऐसी उपयोगिताका उत्पादन जो भौतिक वस्तुओंकी उपयोगितामें वृद्धि करता है दूसरे जो मनुष्यकी शिक्षा द्वारा प्राणी मात्रके लिए उसकी उपयोगितामें स्थायी रूपसे वृद्धि प्राप्त कीमते व्यक्तित्वगत मज्राए जिनके कारण मनुष्यके वैशाल इत्यादि में कोई स्थानी रूपसे वृद्धि ना नहीं होती किन्तु न्यायिक कालके लिए मुख्य मिता है या दुःख का निवारण होजाता है। तीडा विलास, मनोरंजनकी बहुतसी क्रियाए इस कोटिमें शामिल की जासकती है। इस दृष्टिमें ऊपर उद्यानपतिही उत्पादन नहीं किन्तु नाचने अथवा गानवाला भी उ शहर मानेजाने ह।

अन्य अर्थशास्त्री भौतिक तब अभीष्ट उपयोगिता केवल दो ही काटियामें उपयोगिताका विभाजित करते हैं। प्रथमकोटिमें वस्तुआ और द्वितीय श्रेणीमें सेवाओंकी गुणना कीजाती है।

उत्पादन के साधन

उत्पादनके साधनके विषयमें विचारकाका एकमन नहीं रहा है। प्राचीन अर्थशास्त्री उत्पादनके केवल दो-मूल कारण मानतेथ—भूमि और श्रम। पत्नीके मतानुसार धनका पिता और माँसे तत्त्वज्ञ जिमशब्दार्थ कि भूमि उसकी भाभा है। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो इत्यादिने पूँजीका महत्वतो स्वीकार किया ह परन्तु उसे उत्पा-

दनका साधन नहीं माना है। तुराँ, मोनियर और मित्रने पृथीको उत्पादन करनेका साधनतो मानलिया परन्तु भूमि और श्रमके समान स्वतन्त्र साधन नहीं। 'भूमि' का कहनाथा कि वास्तवमें उत्पादनके मापन दो ही है—भूमि तथा श्रम। पृथी उत्पादनके लिए आवश्यक है परन्तु वह भूमि और श्रमके समकक्ष नहीं। मापनमें एक नौधा साधन व्यवस्था अथवा मन्त्रागन माना है। उस समय उत्पादनके पात्र साधन वतलाये जाते हैं—भूमि श्रम पृथी व्यवस्था और उद्योग माह्य। व्यवस्था और उद्योग-माह्यमें कुछ विद्वान भेद करने हैं और कुछ नहीं।

कुछ विद्वानोंने जिनमें बीजर नामक जर्मन विद्वानका नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है, विशिष्ट और अविशिष्ट केवल दो ही वर्गोंमें उत्पादनके साधनोंका विभाजन किया है। विशिष्ट साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग केवल किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। बीजरके मतानुसार भूमि विशिष्ट साधन है परन्तु श्रम और पूँजी अविशिष्ट साधन हैं क्योंकि उनका प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस कारण अविशिष्ट साधनों के सम्बन्धमें सा उद्देश्यों के वाह्य और उनको मिश्र करने के साधनों की न्यूनता और उसके फलस्वरूप वैज्ञानिक उत्पादन-व्ययका प्रश्न उत्पन्न होता है परन्तु विशिष्ट साधनों के सम्बन्धमें उनके द्वारा मिश्र होने वाले उद्देश्यों की एकता के कारण वैज्ञानिक उत्पादन-व्ययका प्रश्न उत्पन्न सम्भव नहीं है। साधारणतया यन्त्र उपकरण तथा अधनिर्मित वस्तुएँ सापेक्ष रूपमें कच्ची सामग्रीसे अधिक अविशिष्ट हूँदा करती हैं।

आधुनिक अर्थशास्त्री न पहिल वर्गीकरणमें विश्वास रखते हैं और न दूसरे में। उनके मतानुसार उद्योगपति ही उत्पादनका मन्त्र अथवा अभिवर्ती है। भूमि श्रम, पूँजी इत्यादि केवल उत्पादन-सामग्री के रूपमें उसके सामने आते हैं और इनके प्रयोग द्वारा वह अपने कनिष्ठ उद्देश्यों की सिद्धि का इस प्रकार प्रयत्न करता है कि उसे न्यूनतम उत्पादन-व्यय उठाना पड़े। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह एक साधन के स्थान पर दूसरे का परिस्थापन करता रहता है। हम पहिले देखते चुके हैं कि इन साधनों के विभिन्न जातीय होने पर भी इनका भीमान्त्र प्रतिस्थापन किया जा सकता है।

उत्पादन के साधनों के उपर्युक्त वर्गीकरणों के तर्क-संगत न होने पर भी पाठ्य पुस्तकों में भूमि, श्रम, पूँजी, व्यवस्था इत्यादिको पृथक् पृथक् मानने की ही परम्परा

चनीभानी है। इसी परम्पराका अनुसरण करतेहुए इस स्थानपर भी उनका अलग अलग विवेचन किया जा रहा है।

भूमि

भूमि उत्पादनमें प्राकृतिक महयागियाका अवलिया जाना हैं। इसप्रकार पृथ्वी, वनस्पति खनिज समुद्र, पवन नदी भील जलवायु आदि सभीको भूमिमें सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक साधना अथवा भूमिको अन्य साधनोंसे भिन्न श्रेणीका माना जाताहै क्योंकि भूमिमें कुछ एस विशिष्ट गुणोंकी कल्पना कीगयी है जा अन्य साधनामें नहीं मिलत। उनमें से मुख्य गुण निम्नलिखित हैं

(१) भूमिका क्षतफल न्यूनाधिक नहीं किया जासकता अर्थात् वह सीमित है।

(२) भूमि अविनाशी है।

(३) वह अचल है।

(४) वह मनुष्यास प्राप्य है।

• आधुनिक अर्थशास्त्री भूमिके इन विशिष्ट गुणोंमें विश्वास नहीं करते। भूमिको सीमित कहना उतनाही उचित अथवा अनुचितहै जितना कि अन्य भौतिक पदार्थों का। आर्थिक दृष्टि से भूमिको सीमित नहीं कहाजा सकता। बजर भूमिको कृषिके योग्य बनाया जासकता है। कम उत्पादक भूमिको उन्नत किया जासकता है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष भूमि-भाग का महत्व केवल उसकी उत्पादक शक्ति परही नहीं बल्कि उस भूमि भाग की स्थितिपर भी निर्भर है और यातायात के साधनामें उत्ती करके बुरीम बुरी स्थितिको भी उत्तम बनाया जासकता है। इसकारण भूमिको सीमित मानना उचित नहीं। इसके अतिरिक्त भूमिके अन्तर्गत जिन उत्पादनोकी गणना कीजाती है वेभी कईप्रकार से प्रयुक्त होसकते है और उन्हें एक प्रयोगसे हटाकर दूसर प्रयोगमें लगाया जासकता है। इसकारण न ता वे सीमित ही हैं और न अचल। इसीप्रकार प्राकृतिक साधनाएं हम लाभ ता अवश्य उठा सकतहैं किन्तु उद्योग साधको उठानके लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना पडता है। प्राकृतिक शक्तिया अपन स्वतन्त्र रूपमें मनुष्यकी आवश्यकताओं को पूर्तिके लिए अधिकतर अनुपयुक्त हाती ह, अपन उपयोगमें लानके लिए मनुष्यको उन्हें एक

वरदेनसे उत्पत्तिका दुगना होना सम्भव नहीं। उत्पत्ति दुगनेसे कम ही रहेगी। इस प्रवृत्तिका ज्ञान वृद्धि द्वारा कुछ समयके लिए निरोध किया जासकता है, परन्तु अन्ततोगत्वा श्रम तथा पूजीव अधिकधिक उपयोगम प्राप्त उत्पत्ति की मात्रामें ह्रास अनिवार्य है। इसकारण प्राचीन ग्रन्थशास्त्री विशेषकर माल्थस जीवन-स्तर का सुरक्षित रखनके लिए गन्तवि निरोधके लिए विशेष आग्रह किया करते थे। माल्थसके जनसंख्या सिद्धान्तका विवेचन हम अगल अध्यायमें करेंगे।

वास्तविक जगत्में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उत्पत्ति की मात्रामें वृद्धि ही होती चली जा रही है और गत गौ ढङ्गों वषमें तो इस मात्रामें आवश्यकजनक वृद्धि हुई है। इस वृद्धिका कारण कृषि-सम्बन्धी अनमन्धान तथा आविष्कार हैं जिनमें फसलोका चक्रेनुवर्तन कृषिमें राममानवालयन्त्राका निर्माण नयी नयी खादोका आविष्कार तथा अधिक उत्पादन बीजाकी उपलब्धि है। रिकार्डोंके मतानुसार इसप्रकार की उन्नतियों दो वर्गोंमें विभाजित की जासकती हैं। एक तो वे जो पृथ्वीकी उत्पादन शक्तिको बढ़ाती हैं, जिनमें फसलाका चक्रेनुवर्तन और उत्तम खादें सम्मिलित की जासकती हैं। दूसरे वे जो कृषिके यन्त्र इत्यादि को उन्नत करके श्रमके न्यून व्ययसे अधिक उत्पत्ति उपलब्ध करती हैं। इनमेंसे पहिल प्रकार की उन्नतियों द्वारा हम उत्पत्तिके वृद्धिमान नियम के प्रभावमें सुरक्षित रहसकते हैं और यदि ये उन्नतियाँ जियाजान तथा निम्नतर हों तो कृषिमें प्राप्त उत्पत्तिमें वृद्धिमान होती है और इतिहास साक्षी है कि आजतक ऐसा होता रहा है। परन्तु कम उत्पादक भूमियाँ पुरे कृषिका जिया जाना अथवा अधिक उत्पादक भूमियोंपर कम उत्पत्ति प्राप्त हानपर भी अधिकारिक श्रम और पूजीका लगाया जाना उत्पत्तिके वृद्धिमान नियमके अन्तर्गत हानकी गवाही है। इस सम्बन्धमें इतना बह देना आवश्यक है कि इस सिद्धान्तका मकेन प्राप्त उत्पत्तिका मात्राकी मात्रा है। उक्त मौद्रिक मन्थकी शर नहीं।

दूसरे प्रकार की उन्नतियोंका परिणाम यह होता है कि कृषि-राशमें गन्तव्य लागाकी मन्थामें क्या होती चली जाती है। जब एक मनुष्यके श्रममें एक कुटुम्बके लिए खाद्य-सामग्री उत्पन्न होपाती था तो अबिकतर तोषोरा गावोंमें रहना और किसान होना आवश्यक होता था। परन्तु जब यन्त्राकी सहायतासे एक मनुष्य तीन चार, कुटुम्बोंके लिए खाद्य-सामग्री उत्पन्न कर सकता है तो कृषि करनेवाला

की मर्यादे अनुपातमें कमी तथा नगरामें रहनवाला की मर्यादमें वृद्धि होना स्वाभाविक है।

इस मिद्धान्तका विवेचन प्रायः कृषिमें प्राप्त उत्पात्तिके सम्बन्धमें ही किया जाता है। परन्तु इसका कार्यक्षेत्र कृषितक ही सीमित नहीं। खाना जलाशया, वनों इत्यादिसे प्राप्त उत्पात्तिकी माध्यामों भी अधिक-अधिक श्रम और पूँजीका व्यय करने पर उमागत लाभही होता बना जाना है। खानों भूमिकी तरह प्रकृति-प्रदत्त अवश्य है परन्तु दाना समकल्प नहीं। लगातार कृषिमें लुप्त होनवाली भूमिकी उत्पादक शक्तिका प्राकृतिक कारणही से पुनरुत्थान होता रहता है। खानामें स्थित सम्पत्तिकी एववार पूर्णतया समाप्त करदेन पर उसकी पुनः सृष्टि नहीं होती। खानाके सम्बन्धमें उत्पात्तिका उमागत लाभ इसप्रकार काय करता है कि अल्पतः मुलभ सम्पत्तिके समाप्त होनपर बाल्य प्राप्त होनेवाली उत्पत्ति पर श्रम और पूँजीका अधिक व्यय करना ही पडता है।

जलाशयोसे मछलिया प्राप्त कीजाती है। जलाशया और भूमिमें यह अन्तर है कि मनुष्यन वर्गोंके अनुसन्धान और अनुभवके अन्तर कृषिमें प्राप्त उत्पात्तिकी पूर्ति पर न्यूनताधिक नियन्त्रण प्राप्त करलिया है। परन्तु जलाशयाम प्राप्त मछलियाके सम्बन्धमें वह अभी ऐसा कहा करपाया है। नदी नालाम प्राप्त मछलियोंकी पूर्तिका तो थोडा बहुत नियन्त्रण कियाभी जासकता है परन्तु समुद्रामे प्राप्त मछलियाकी पूर्तिपर मनुष्यका तनिकभी बल नहीं। जलाशया और खानोंमें यह भेद है कि खाना की सम्पत्ति एववार निकाल ननपर वह मर्दके लिए समाप्त होजाती है परन्तु मछलिया पकडनवाल स्थानापर यदि कुछ समयके लिए मछलिया पकडना बन्द करदिया जाय तो वे स्थान फिर मछलियाम भरपूर ऋजाते है।

परिवर्तनीय अनुपात का मिद्धान्त

आधुनिक अर्थशास्त्री उपात्तित उमागत लाभ मिद्धान्तका कुछ अन्य दृष्टिसे दगम है। किसीभी उत्पादक क्रिया को चलानेके लिए हमें एकमे अधिक उत्पादनक साधनाकी आवश्यकता होती है। कृषिमें उत्पात्ति प्राप्त करनेके लिए हम केवल भूमि ही नहीं अपितु श्रमभी आवश्यक है। कपडा बुननेके लिए केवल श्रमही

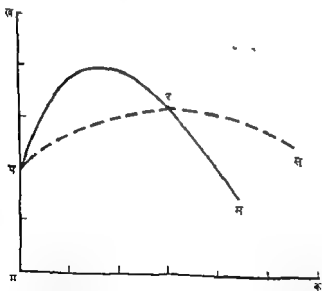
वल्कि कपडा बुनने के यन्त्रादि भी जरूरी हैं। कभी कभी तो भिन्न भिन्न साधनोंको निश्चित अनुपातमें एकत्रित करना पड़ता है। परन्तु प्रायः इस अनुपातमें परिवर्तन किया जासकता है। माधुनिक अर्थशास्त्रियां वा विचार हैं कि यदि हम अन्य साधनोंको स्थायी रखकर किसी साधन विशेषकी मात्राको बढ़ाने चलेजायें तो एक समय ऐसा आता है कि उस साधन द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रा क्रमागत ह्रास होने लगता है। उदाहरणके लिए हम पूँजीकी मात्रा में तो परिवर्तन करने चलेजायें परन्तु श्रम और भूमिको स्थायी रखें तो हमें उत्पत्तिमें नमिक ह्रास प्राप्त होगा। परन्तु कभी कभी साधन विशेषके अधिकाधिक प्रयोगसे प्राप्त उत्पत्तिमें ह्रास होनेसे पूर्व कुछ काल तक वृद्धि भी होनी गृहीत है और फिर कुछ काल-तक न वृद्धि न ह्रास। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों निपमोनों केवल एकही सिद्धान्त का अंग मानते हैं जिसे वे उत्पत्तिके परिवर्तनीय अनुपातके सिद्धान्तका नाम देते हैं।

जबकि उत्पादन कई साधनोंके परस्पर सहयोगसे सम्भव होता है तब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनीय होने हैं। यदि उत्पादनके साधनोंमें किसी विशेष परिमाण की स्थायी मानलिया जाये, तो इस परिमाणके उपयोगसे प्राप्त उत्पत्तिको कुल उत्पत्ति कहा जाता है। इस उत्पत्तिका उन साधनोंकी मर्यादा में भाग देने पर सीमान्त उत्पत्ति प्राप्त होती है। उत्पादन-साधनोंमें एक इकाईकी वृद्धि करने पर स्वल्प या कुल उत्पत्तिमें वृद्धि होगी उसे सीमान्त उत्पत्ति कहा जाता है। सीमांतकार साधनाके उस परिमाण वा व्यय कुल व्यय होगा। उस कुल व्ययकी साधनोंकी मर्यादा में भाग देने पर सीमान्त व्यय प्राप्त होता है और एक इकाईकी वृद्धि करनेके फलस्वरूप कुल व्ययमें होनेवाली वृद्धिसे सीमान्त-व्यय प्राप्त होता है। हम पहिले सिद्ध चुके हैं कि सीमान्त वस्तु वह वस्तु है जिसका उपयोग किसी उपयोगमें विचारधीन हो। सीमान्तकी कल्पना उगी अवस्थामें हो सकती है जबकि किसी वस्तुके उपयोगमें परिवर्तन निरन्तर हो रहे हो या जब वे परिवर्तन बहुत बड़े और अविभाज्य न हो। उदाहरणके लिए यदि कोई व्यवसाय पांच श्रमिक बढ़ाना निश्चित करना है तो उनका श्रम सीमान्त श्रम, उन्हें द्वारा सम्भव उत्पत्ति सीमान्त उत्पत्ति और उनके उपयोगके लिए बियागया धन सीमान्त व्यय होगा।

यह आवश्यक नहीं है कि दुन, सीमान्त और सीमान्त उत्पत्ति साथ साथ घटे वढ़ें। वह पूर्वक पूर्वक घट वढ़ सकती है। उत्पत्ति-ह्रास नियमके आरम्भिक रूपमें यह

ब्रान स्पष्ट नहीं, की नि ह्याम औसन उत्पातिमें ह्याहें या सीमाना उत्पातिमें। आधुनिक यन्त्रास्त्री सीमाना उत्पातिक ह्याम नियम का ही दृष्टिगत रखना अधिक्त समाधान समझा है क्योंकि सीमाना उत्पाति यन्त्रास्त्री नि सीमा विना उच्च परिश्रित हाता है।

उत्पादनकी वृद्धिसे अर्थशास्त्रमें उच्च उत्पत्ती उत्पादक मन्त्राग्रे परिमाणमें परिवर्तन करने हैं = परन्तु उनमें एक परिमाणका ज्या का त्याग करने हत है स्पष्ट है कि फलभा समानपातिक न हाग। यदि कुछ उत्पादन साधनाका समान भागमें बढ़ाया जाय और कुछका बसाहा करने दियाजाय ना किमी शिन्तुव अनन्तर उपति अनुपातिक उच्च जान होगी। उत्पातिक उच्च नियमका परिवर्तनीय अनुपातका नियम कहते हैं। रक्षाशक्ति की सहायताम इस नियमका इसप्रकार दिवाया जासकता है



मान लीजिए किसी उद्योगमें अन्य सब उत्पादनके साधन स्थायीहैं, केवल एक ही साधन परिवर्तनीय है। 'म' क' रेखा पर उच्च साधनके परिमाणमें परिवर्तनको और 'म, स' रेखा पर उसके प्रयोगसे प्राप्त उत्पातिक मानाको दिखाकर प, स और

‘प,म’ क्रमशः सीमान्त उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति दोनोंक रेखाएँ प्राप्त की जाती हैं। रेखाओंके आकारमें विदित है कि आरम्भमें तो सीमान्त तथा औसत उत्पत्ति बढ़ती हैं, इसके अनन्तर सीमान्त उत्पत्ति घटना आरम्भ कर देती है, परन्तु औसत उत्पत्ति बढ़तीही जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जबकि सीमान्त और औसत उत्पत्ति सम होती हैं। चित्रमें यह बिन्दु ‘र’ से अंकित किया गया है। इस बिन्दुके अनन्तर सीमान्त उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति दोनों लगातार गिरतीही चली जाती हैं परन्तु सीमान्त उत्पत्ति अधिक वेगसे गिरती है कुछ अर्थशास्त्रियोंमें ‘र’ बिन्दुको भी उत्पत्ति की मात्राके अनुपाततः कम होनाका प्रदर्शक माना है।

उत्पत्तिके परिवर्तनीय अनुपातके नियममें यह मान लिया जाता है कि जिस उत्पादनके साधनोंका प्रयोग किया जा रहा है वे सभी समरूप हैं। इसके अतिरिक्त यह नियम मूलतया यत्र-विज्ञान का नियम है। और इसकारण अर्थशास्त्रके लिए इसका महत्व परोक्ष रूपमें ही है। ग्रहता विदित ही है कि इसके लागू होनेके लिए कम से कम एक साधन स्थायी होना चाहिए और उनके विनियोगका अनुपात बढाना होना चाहिए। :-

सर्वोत्तम विनियोग का सिद्धान्त

जब उत्पादनके सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं अर्थात् उनमें से प्रत्येकको घटाया बढ़ाया जा सकता है तो सर्वोत्तम विनियोगका नियम लागू होता है। अर्थशास्त्रमें इस नियमका प्रयोग तीन प्रकारकी समस्याओंको सुलझानेके लिए किया जाता है

- (१) उद्योगकी सम्पुल्लभ अवस्था निर्धारित करनेके लिए।
- (२) जनसंख्या की सर्वोत्तम मात्रा निर्धारित करनेके लिए।
- (३) उत्पादनके साधनोंको विभिन्न उपयोगों तथा उद्योगोंमें विभक्त करनेके लिए।

उद्योग संस्था उस बिन्दुपर सर्वोत्तम आकार और संतुलन अवस्था प्राप्त करती है जिसपर कि इसके औसत और सीमान्त व्यय सम हो जाते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में संस्था को घटाने बढ़ानेमें हानि होगी। औसत व्ययसे सीमान्त व्यय, ऋचा, गृह, पर संस्थाका घटाना आवश्यक होगा क्योंकि अन्यथा औसत-व्यय बढ़ना जायेगा

और यदि भीमान्न व्यय भीमन व्ययमे नीचा है तो उसे बढ़ानेका प्रलोभन मिलना रहेगा। क्योंकि बढ़ानेमे भीमन-व्यय कम होता जायेगा। प्रत्येक स्थितिमें मर्यादो विम्बता प्रसा मनुष्या इन्द्रेणी आताथा पनी मही है। मनुष्यानी मर्यादा जरी मम प्राण होनी है अर दोनो मम होजावे न और पनी मर्यादामे स्थिति होनी है। जैसाकि मनुष्यनके अध्यायमें विम्बन रूपमें बताया गया है।

उत्पादनके साधनाका विभिन्न उपयोग और उद्योगोंमें सर्वात्म्य विभाजन उम समय होनाहै जराकि प्रत्येक साधनकी प्रत्येक उपयोगमें सीमान्त उत्पत्ति बराबर होनीहै क्याकि अन्यथा कुछ ध्यानापर विभाजनमें घटकर करनेसे उत्पत्ति बढ़ सकती है। परन्तु सर्वोत्तम विभाजनका अर्थ नो यहहै कि उसमें किसीभी प्रकारका परिवर्तन होनेसे लाभ प्राप्त होनेकी कोईभी आशा न हो। उत्पादनके साधनों का विनियोग इसप्रकार निर्धारित होताहै कि उनमें परस्पर प्रतिस्थापना उस समय तक चलती रहतीहै जबतक कि किसी दिग्गुण विनियोगमें और परिवर्तन करनेसे कोई लाभकी आशा न रहे अर्थात् जब सब साधनोंकी सीमान्त उत्पत्ति सम होजाये। इसीप्रकार कितना और कौनसा साधन किम प्रयोग या उद्योगमें लगना चाहिए, इस बातसे निश्चित कियाजाता है कि उस साधनके सीमान्त प्रयोगमें किन्तु रूपमें जो उत्पत्ति होसकती थी उसका महत्व प्रस्तुत उपयोगमें अधिकहै अथवा कम, इसी कारण बोलिन्गने इस नियमको समान लाभका नियमभी कहा है। उसका कहनाहै कि प्रत्येक उत्पादनके साधन अथवा सेवाके लिए व्यवसाय विशेषमें कुछ लाभ प्राप्त होते रहते हैं। सम्पूर्ण लाभोंको दृष्टिगत रखतेहुए जिस विभाजन-द्वारा उत्पादन कियाये प्रत्येक मजदूरीकी परम्पर समान लाभ मिले वही सर्वोत्तम विभाजन है।

साधनों की अविभाज्यता

उत्पादन से कम से सबसे बड़ी कटिनाई अविभाज्यताओं द्वारा उत्पन्न होती है। अविभाज्यताएँ दो प्रकारों में पैदा होती हैं। एक तो कुछ साधन किसी विशेष कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में लगाए नहीं जा सकने और कुछ एक विशेष अनुपात में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। बहुतमी मशीनें किसी विशेष मात्रा में ही उत्पत्ति कर सकती हैं अथवा किसी विशेष गति में ही चल सकती हैं। ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम विनियोगों की समस्या

बड़ी कठिन होजाती है। कुछ अविभाज्यताएँ विज्ञापन और विक्रय सम्बन्धी भी हैं और बहुतसी अथसम्बन्धी भी। उनको इच्छानुसार घटाया बढ़ाया नहीं जासकता। वनानिक गवेषणा इत्यादि कुछ ऐसी वस्तुएँ नहीं कि उनपर जितना व्यय कीजिए उसी अनपातम फल प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि किसी बड़ वनानिकवे ज्ञानका लाभ उठाने के लिए जितना व्यय करना पड़े उसे कम लाभ मामली वनानिकको सबोझाके लिए व्यय करके उठाया जासके। अथवा सम्भव नहीं है कि मामली वनानिकपर किया गया व्यय व्यर्थ ही है।

अविभाज्यताएँ दो प्रकारसे कठिनाइयाँ उपस्थित करती हैं। एक तो विनियोगकी समानुपातकता नष्ट करके और दूसरे साधनाकी गतिशीलता नष्ट करके। गतिशीलता नष्ट होनेसे प्रतियोगिता अपण होने लगती है और सर्वान्त्रिक विनियोग अथवा विभाजनक लिए पूरा प्रतियोगिता और समानुपातकता दोनों आवश्यक हैं।

आर्थिक साधन—श्रम

श्रम की परिभाषा

यह तो स्पष्ट ही है कि मारा उत्पादन मानव-प्रयास का फल है। यद्यपि ताम्ब्रक दृष्टिसे ऐसा सोच जासकता है कि किसी प्रागैतिहासिक कालमें मानव आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतया प्रकृति द्वारा और अनायास ही होती रही होगी। परन्तु इतिहास किसी ऐसे कालका साक्ष्य नहीं है। प्रकृति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु कृतज्ञता के लिए मनुष्यको प्रयास और परिश्रम करना ही पड़ता है। हमका प्रमाण हम प्रागैतिहासिक कालीन यन्त्र तन्त्र तथा बला कौशलके रूप में पाते हैं।

हमारी जितनी भी नियाए होती हूँ हम उन सभीका प्रयास अथवा श्रमके अन्तर्गत मान सकत हूँ फिरभी सर्वप्रामाण्य में श्रमको इस विस्तृत अर्थमें स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने उस प्रकारके प्रयासको श्रमकी कोटिमें रखा है जो किसी प्रकारके लाभकी प्राप्तिमें किया जाये। उपयोगी और अनुपयोगी श्रमका भेद अर्थशास्त्रके इतिहासमें काफी पुराना है। फिजियोनोमिस्ट ने केवल कृषिगत श्रमको मार्भक माना है। ऐडम स्मिथ ने उत्पादक और अनुत्पादक श्रमका भेद करनेहुए बतलाया है कि जिस श्रमके फलस्वरूप वस्तुओंकी उत्पत्ति हो, वह उत्पादक है, किसी अन्य प्रकारका श्रम व्यर्थ है। श्रमका यह भेद बहुत दिनोत्तरक माना जाता रहा। परन्तु भिन्नके अन्तर्गत इसकी बड़ी आलोचना हुई क्योंकि उत्पादक और अनुत्पादक श्रममें सेवाश्रम कोई स्थान नहीं दृष्टा जाता था। परन्तु यह कहना कठिन है कि सेवाएँ सुखकी उत्तम साधक नहीं हैं जितनी कि वस्तुएँ। टॉसिंग का मत है कि वह सभी श्रम जिसके फलस्वरूप उपयोगिता की सृष्टि हो, उत्पादक है और उसकी परिभाषाके अनुसार उपयोगिता वह है जिसके द्वारा हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो

श्रमकी माग कई बातों पर निर्भर है। अन्य सहयोगी उत्पादन साधनों की उपलब्ध मात्रासे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। उत्पादन रीतियों में परिवर्तनके साथ साथ इसमें परिवर्तन होने रहते हैं। किसी विशेष उद्योग धंधे में श्रमकी माग उस उद्योग-धंधे की उत्पत्तिके लिए मागकी लांचसे सम्बन्धित है। श्रमकी पूर्ति श्रम-जीवियों की-संख्या और फलस्वरूप कुल जनसंख्या, काम करनेके घंटों तथा श्रम-जीवियों की कुशलता पर निर्भर है।

जन-संख्या

यद्यपि माल्थसके पहिले भी पैटी तथा गाडविन आदिने जन-संख्या तथा आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थामें उसके प्रभावपर कुछ विचार कियाथा, पर विस्तृत रूपसे जन-संख्या का आर्थिक महत्व दर्शानेवाले पहिले व्यक्तिगणोंमें माल्थस का ही नाम अधिक प्रसिद्ध है। संक्षेपमें, उनका मत इसप्रकार है कि जन-संख्या की स्वाभाविक वृद्धि-दर बहुत तीव्र है। अनेक प्राकृतिक और मानुषी कारण उसे अपनी स्वाभाविक तीव्र गतिमें निरुद्ध करते हैं फिरभी जिस दरमें मनुष्यके जीवन-निर्वाह की सामग्री बढ़ती है, उसकी अपेक्षा जन-संख्या की वृद्धि-दर अधिक ही रहती है। यदि जन-संख्या की वृद्धि-दर २, ४, ८, १६ इसप्रकार मानें तो उत्पादन-वृद्धि की दर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ इसप्रकार होंगी। कहा नहीं जासकता कि कहातक माल्थस का अभिप्राय यहथा कि जन-संख्या और उत्पादनकी सापेक्ष वृद्धि-दरोंमें ठीक ठीक उपनिमित्तित सम्बन्ध है और कहातक उसने गणित का सहाय केवल इन दोनो द्वाारा भारी अन्तरवा स्पष्ट और प्रभावपूर्ण शब्दामें प्रकट करनका लिए लिया। जाकुछ भी हो इन दोनो दरोंका सम्बन्ध गणित-मुलभ शुद्धतामें मापना असम्भव है। वास्तवमें अपनी पुस्तक जन संख्या पर निरुद्ध के पहिले मस्करणमें ता उसने अपना मत बहुतही अप्रामाणिक रीतिमें प्रतिपादित किया है। दूसरे सम्बन्धमें उसने बहुत कुछ सुधार हुए दृग्गम अपने मतका प्रतिपादन किया है। परन्तु उसका मुख्य प्रमाण विभिन्न देशोंमें सकलित एनिहासिक सामग्री है।

यदि हम यह मानलें कि जन-संख्या और उत्पादन की वृद्धिके दरोंमें अनिवार्य अन्तरहै तो इस निष्कर्षपर पहुंचेंगे कि किसी समय ससारमें जन-संख्या इतनी बढ़

कुछ लोगोंने यहभी आपत्ति उठाई है कि जन-उत्पत्ति-वृद्धिकी दर जिस प्रकार माल्थस सिद्धान्तमें मापी जाती है, वह सदोष है। उनके अनुसार आवश्यक बात यह है कि किम दरसे एक दीहुई जन-संख्या पुनर्जीवित ररी जाती है और यह बात जनन-शक्तिपर निर्भर होगी।

अन्य विचारकों ने यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि जन-संख्याकी वृद्धि अथवा ह्रास, जिन कारणासे होता है, उनके आधारपर कहा जासकता है कि सदैव वृद्धिशील जन-संख्या का भय निर्मूल है। वातावरण, जीवन-स्तर, मजूरी की दर, ये सभी बातें जन-संख्याकी वृद्धि-दर निर्धारित करती हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का यहभी मत है कि जन-संख्याकी वृद्धि-दर घनिकोमें कम और निर्धनो में अधिक होती है। सीमियरने यह दिखाया है कि जब जन-संख्या बहुत बढ़ने लगती है अथवा जब एक स्थानमें अधिक घनी होजाती है तो अपनेआप कुछ विरोधी शक्तियोंका प्रोद्गर्भ होता है जो जन-संख्याकी वृद्धिको रोकती हैं। इनमें उठते हुए जीवन-स्तर और नयी ग्रहणनी हुई इच्छाओंका बहुत महत्व है। प्रश्न यह नहीं कि किसी देशकी जन-संख्या घटायी जाये या बढ़ायी जाये। समस्या यह है कि अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत जन-संख्याका विसप्रसार सामञ्जस्य किया जाये कि आर्थिक सम्पत्तता सर्वोत्तम बिन्दुपर रहे। कहनेका अभिप्राय यह है कि किसी दीहुई अर्थ-व्यवस्थामें एक विशेष परिमाणमें श्रमकी आवश्यकता होती है और एक विशेष आकारकी जन-संख्या सर्वोपयुक्त होसकती है। उससे छोटी जन-संख्या उतनीही व्यर्थ है जितनी उससे बड़ी। अर्थ-व्यवस्था और उत्पादनके साधन यदि बढ़लजायें तो उसीके अनुसूप जनसंख्याका आकारभी बदलना पड़ेगा। इस सामञ्जस्यमें जन-संख्याका केवल आकारही महत्वपूर्ण नहीं है बरन् जन-संख्या का घनत्व, व्यक्तियोंके गुण और उसका स्वरूप और संयोजन भी आवश्यक है।

जैसाकि सर्वोत्तमताके सिद्धान्तमें अनिवार्य है जन-संख्याके इस सिद्धान्तका व्यवहार कोई सर्वोपरि उद्देश्य मान लेनेपर ही होता है। यह उद्देश्य प्रति व्यक्ति, सर्वाधिक आय मानाजाता है। इसके अनुसार जिस बिन्दुपर जन-संख्या और अन्य उत्पादनके साधनोंका इस प्रकार सामञ्जस्य होजाये कि प्रत्येक व्यक्तिकी आय सर्वाधिक हो, वही उमका सर्वोत्तम बिन्दु है।

कुछ लोगोंने अन्य सिद्धान्तभी निश्चित किये हैं। उनके अनुसार यदि जीवन

की दृष्टिसे देखें तो सर्वाधिक जीवनाशा, सामाजिक दृष्टिसे देखें तो सर्वाधिक भ्रवकाण और सामान्य हित एवं सम्पन्नता, युद्धकी दृष्टिसे देखें तो सर्वाधिक सुरक्षा इत्यादि उद्देश्य सर्वोत्तम जन-संख्याके ही सक्ते हैं।

जन-संख्या में परिवर्तनों का महत्व

माल्थस और अन्य विचारकांक्षे मताकी जा विवचना हमने की है, उसमें मानव-हित और आर्थिक सम्पन्नताके लिए उचित जनसंख्याका विवेचना महत्व है, यह बहुत कुछ स्पष्ट होगया है। माल्थसके अनुसार तो दृग्दृष्टता-निवारण का उपायही यही है कि जन-संख्याको संकुचित करनेका भरसक प्रयत्न किया जाये, यद्यपि अन्य बहुतसे विचारको ने माल्थसके चर्चा उपायोंका समर्थन नहीं किया है (उन्होंने गर्भनिरोध के कृत्रिम उपायोंकी ही अधिक उपयोगिता मानी है) पर उन्होंने भी माल्थसके सिद्धान्तका महत्व स्वीकारही किया है। इस तथ्यसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि मताका उद्भव और उनका प्रसार बहुत कुछ तत्कालीन परिस्थितियोंमें प्रभावित होता है। जिस समय माल्थसने अपना मत प्रचलित किया था, जन-वृद्धि का भय अधिक था और उपायका अर्थशास्त्रमें जनसंख्या पर वृद्धि और आर्थिककी दृष्टिसे अधिक विचार हुआ। परिस्थितियोंमें परिवर्तन होने पर स्थायी और हान-शील जन-संख्याकी ओर भी विचारका ध्यान गया। जन-संख्याकी पुरानी अवृत्ति श्रमजीवियोंकी प्रवस्था तथा मजूरीकी दरके दृष्टिकोणसे करनेकी ओर थी। सामान्य रूपसे कहा जा सकता है कि सामाजिक आर्थिक सम्पन्निके परिमाणके सम्बन्धमें ही जन-संख्या का महत्व अधिकतर देखागया है। आर्थिक परिवर्तन और प्रगति के सम्बन्धमें भी जन-संख्याका देखनेकी प्रथा प्रचलित नहीं है।

वृद्धिशील जनसंख्या

कुछ लोगोंके मतमें जनसंख्या का सम्पूर्ण भाग और पूजा लगानेके अवसरों पर प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिसे वृद्धिशील जन-संख्याका प्रथम और स्पष्ट प्रभाव तो सम्पूर्ण भाग और पूजा लगानेके अवसरोंको बढ़ाना है। वृद्धिशील जन-

संख्यामें व्यय और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी और साथही भविष्यकी धिन्ताके कारण बचत और इसलिए पूजा निर्माण भी। यदि हम वितरण-रीतिकी अपूर्णताओको छोड़ दें, तो यह फल तभी प्राप्त होसकता है जब वृद्धिशील जन-महत्याके साथ साथ नवीनताओकी गति और श्रमजीवियोंकी उत्पादन-शक्ति बढ़े। पर जन-संख्या और नवीनताओका सम्बन्ध सरल नहीं। एक ओर तो बढ़ती हुई जनसंख्याके कारण पूजा लगानेके अवसरोंके बढ़जाने से उद्योगपतियोंको नवीनताएँ अपनानेका अधिक लोभ होताहै पर दूसरी ओर ह्रासशील जनसंख्याका भी यही प्रभाव होसकता है। मन्दी होनेके कारण उद्योगपतियोंको थमकी बचत करनेवाले उपाय ढूँढने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त वृद्धिशील जनसंख्याका एक प्रभाव श्रमका मूल्य घटादेना होसकता है। और उम स्थितिमें मेशीनरीके स्थानपर श्रमका उपयोग अधिक होने की सम्भावना है। आधारतया कहा जासकता है कि यदि बेकार उत्पादनके साधन न हों, तो वृद्धिशील जन-संख्या सामाजिक और आर्थिक हितकी बाधक और इसकारण बड़े बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनोंका मूल होगी।

ह्रासशील जन-संख्या

प्राफेसर हेनमनके मतानुसार आर्थिक प्रगतिके मुख्य तीन कारण हैं—एक आविष्कार, दूसरा नवीन साधनों तथा भूभागोंका पता लगना और तीसरा जन-संख्या। यदि जन-संख्या ह्रासशील हो तो पूजाका निर्माण कम होगा और इसकारण आर्थिक प्रगति रुकेगी। प्रसारके अवसर जितनेही कम होंगे, प्रगति उतनीही कम होगी। पर जैसा रिकाडों ने पहिलेही कहाथा, प्रगतिशील सीमा केवल भौगोलिक अथवा जन-संख्या सम्बन्धी वस्तु नहीं है। आर्थिक आवश्यकतासे भी उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसा हमने अभी देखा है, जनसंख्याकी दर और आर्थिक प्रगति का सम्बन्ध बड़ा जटिल है। सामान्य रूपसे यह कहसकते हैं कि यदि हम प्रगतिका मोह छोड़ दें, तो जन-संख्याकी दर स्थायी रखनी होगी और वृद्धिशील जन-संख्याकी अपेक्षा ह्रासशील जनसंख्या वांछनीय होगी। पर प्रगतिकी इच्छा रहतेहुए ह्रासशील जन-संख्याका प्रभाव बुरा ही है।

कुशलता

हम लिख चुके हैं कि श्रमकी पृति श्रमजीवियोंकी कुशलता परभी निर्भर है। श्रमकी कुशलताके मुख्य मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

१ व्यक्तिगत। कुशलताके लिए दो गुणावी सर्वोपरि आवश्यकता होती है। एक तो सम्यक् और परिश्रमकी क्षमता और दूसरे समझदारी। जिस व्यक्ति श्रमवा जानिमें लगातार काम करते चल जान का स्वभाव है उसके अधिक कुशल होनेकी सम्भावना है और समझदारीकी बमस कम उत्पादन उन विभागोंके लिए जहाँ संयोजन और निपटवका अधिक काम पड़ता है आवश्यकता है।

२ बातावरणगत। बातावरणसे हमारा तात्पर्य उन दशांशों है जिनमें श्रम-जीवी जीवन-यापन करता है अथवा जिनमें वह उत्पादन-कार्य करता है। जीवन-यापनकी दशाएँ कुछ तो ऐसी हैं जो उत्पादन प्रणालीही से सम्बन्धित हैं और कुछ उससे स्वतन्त्र हैं। जलवायुका प्रभाव एक ऐसा कारण है जो स्वतन्त्र रूपसे श्रमकी कुशलता निर्दिष्ट करता है। प्रसिद्ध विद्वान हार्टमनने जलवायुका स्वास्थ्य और श्रम-कुशलतासे बड़ी ध्यान दे सम्बन्ध बतलाया है।

उत्पादन-प्रणालीसे सम्बन्धित दशाएँ दो प्रकारकी हैं—एक तो वे जो श्रमिकोंके कार्य, स्थान इत्यादिमें और दूसरी वे जो श्रमिकोंके जीवन-यापनसे सम्बन्ध रखती हैं। पहिलीके अन्तर्गत कार्य स्थानमें रोसनी, तापमान, सफाई इत्यादिका उचित प्रबन्ध काम करनेके अटे बीध न होना, कामका उचित नियन्त्रणदि। यह सब उत्पादन-प्रणालीसे श्रमिकोंके जीवन-यापनकी दशाएँ उत्पन्न होती हैं, मजदूरीका कम होना, जिसके फलस्वरूप श्रमजीवियोंके लिए उचित घरका न होना, उचित खाना न मिलना तथा अन्य अनुविधाओंका होना और उनके बच्चोंके लिए उचित शिक्षा की कोई व्यवस्था न होना, ये बातें ध्यान देने योग्य हैं।

३ समाजगत। श्रमजीवियोंकी कुशलताका कारण मजदूरीका कम होना तथा तदुत्पन्न शिक्षा, स्वास्थ्य-कर बातावरण एवं व्यापक दरिद्रता है। इस सम्बन्धमें यह लिख देना भी अनुचित न होगा कि कुछ लोगोका यह भी भ्रम है कि श्रमिकोंकी कुशलताही उनके अन्य पारिश्रमिकका कारण है।

श्रमकी विभाजन द्वाराभी अधिक कुशल बनाया जा सकता है। श्रम विभाजनसे

हमारा तात्पर्य यह है कि किसी वस्तुके बनानेमें जितने और जिस प्रकारके श्रमकी आवश्यकता है, वह एकही व्यक्तिके ऊपर न छोड़कर कई व्यक्तियों या वर्गोंमें बांट दिया जाये। श्रमविभाजन कई प्रकारका होसकता है।

१ व्यक्तिगत। जब विशेष गुणाने आगार-र कुछ कार्य-विशेष केवल कुछ व्यक्तिगति लिए सुरक्षित करदिये जाने हैं तब हम उसे व्यक्तिगत श्रमविभाजन कहते हैं। यह सम्भव होसकता है कि एकही व्यक्ति अथवा परिवार कृषि, सुता और बुनने के कार्य करे पर यदि य व्यापार भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें बांट दिये जायें ता श्रमकी बचन होगी। इसप्रकार का श्रमविभाजन वर्गगतभी होसकता है। जब समाजके आर्थिक कार्य विभिन्न जन-वर्गोंमें बंटजाने हैं तो उसे वर्गगत श्रमविभाजन कहते हैं, उदाहरणके लिए वर्तमान फैक्ट्री प्रणालीमें श्रमका विभाजन बहुत कुछ व्यक्तिगत है। मध्ययुगीन योरोपकी अर्थ व्यवस्थामें कला-कौशल विभिन्न वर्गोंमें बंट चुका था, जिन्हें मित्र या गोष्ठिया कहते थे उस प्रकारके श्रमविभाजनको वर्गगत कहेंगे।

२ प्रतियोगत। एकही कार्यको जब कई छोटे-छोटे कार्योंमें बांट दिया जाता है और प्रत्येक उपविभागकी भिन्न भिन्न व्यक्ति सम्भालते हैं तो उसे हम प्रतियोगत श्रमविभाजन कहते हैं। ऐडम स्मिथ इसीकी विशेष चर्चा करते हैं। उन्होंने पिन बनानेका उदाहरण दिया है जिसमें २१ उपविभागों का वर्णन किया है। पिन पर दोषी बनानेका कार्य एक व्यक्ति-मगूह करता है, उसपर शोक दूसरा बनाता है, उन्हें पुरेलाग तीमरा करता है, पैक चौथा करता है। इसप्रकार अनेक उपविभागोंमें बंट कर अनेक मनुष्यों द्वारा पिनका निर्माण होता है। कोईभी कार्य कहानक विभाजित अथवा उपविभाजित होसकता है इसकी कोई सीमा नहीं। उत्पादन-प्रतिया का अधिकाधिक भाग और उपविभागोंमें बंटने चले जाना वर्तमान उत्पादन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है।

३ भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत। जब आर्थिक व्यापार बना बौशल, उद्योग अथ विशेष विशेष क्षेत्रोंमें बंट जाने हैं तो उन उद्योगोंमें उपयोगी श्रमका भी इन्हीं क्षेत्रों में विभाजन होसकता है। इस प्रकारके विभाजनको भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत विभाजन कहते हैं। उदाहरणार्थ, भारतमें सूती करडेके कारणसे अधिकतर दक्षिण में, चीनीके उभरमें और पटसनके उत्तर पूर्वमें है। इसप्रकार के श्रम विभाजनके

कई कारण होसकते हैं। मुख्यतः कुछ निम्न उद्योगोंमें दक्ष श्रमिकावा किसी क्षेत्र विशेषमें रहना या उस उद्योगके लिए आवश्यक कच्ची सामग्रीका उस क्षेत्र या उसके निकट मिलना महत्वपूर्ण कारण हैं।

श्रमविभाजन के लाभ

१ समयकी बचत। श्रमविभाजन द्वारा समय बहुत बचाया जासकता है। इस के कई कारण हैं। एक कार्यके कई भागोंका जब एकही व्यक्ति करताहै तो उसे एक भागके अनन्तर दूसरे भागकी तैयारी करनेमें थोड़ा समय लगता है। श्रम विभाजन द्वारा यह समय बचजाता है। इससे व्यक्ति यदि एकही खादकी पूरा कार्य करे तो कार्यकी बदलती आवश्यकताओंके अनुसार उसे विभिन्न प्रकार की सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी। इसमें कार्यकी निगलना दूसरीहै और बहुत कुछ समयभी व्यर्थ जाता है। कार्यका धनक भागमें बांटने से यह समय बचजाता है परन्तु समयकी बचतना सबसे बड़ा कारण यहहै कि एकही प्रकारके कार्यको करने रहनेसे अभ्यासकी अधिकताके कारण उस कार्यको करनेकी गति तीव्र होजाती है।

२ कौशलकी वृद्धि। यह तो ज्ञातही है कि श्रमविभाजनके द्वारा धर्म अधिक कुशल होजाता है। जब कार्य धनके उपविभागमें बंट जाताहै तो कार्यप्रणाली बहुत कुछ बनबत होजाती है। सभी व्यवस्थामें अभ्यासके कारण गति तीव्र हो सकती है। परन्तु यदि कौशलका अथवा कामका कम समयमें ही नहीं बरन् अधिक सुन्दर कर सकनेकी क्षमताहै तो इस क्षमतामें वृद्धिके ब्याप्तपर ह्रास ही होगा।

३ नवीन आविष्कारों की सम्भावना। श्रमविभाजन द्वारा कार्य कई भागोंमें बंट जाताहै, इसकारण कार्य करनेवाले का कार्यके उस विभागको अत्यन्त सूक्ष्मता पूर्वक देखने, समझनेका अवसर मिलताहै और इसप्रकार उसके सुधार संभवता उसमें नवीन अनुसन्धानकी सम्भावना बढजाती है। श्रमविभाजनसे उस प्रकारके आविष्कारोंकी सम्भावना अधिक होजाती है जो यात्रिक हों, क्योंकि इसके कारण उत्पादनमें धर्मके ब्याप्तपर धनके प्रयोगमें सुविधा होतीहै और यही कारणहै कि पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्थामें श्रमविभाजन बड़ा महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। एकही कार्यकी अथवा किसी कार्यके एक छोटेसे विभागको बारबार दुहरानेसे वह

कार्य यन्त्रवत् होजाती है और कुछनो इस बार बार के दुहरानेमे ऊपर और कुछ बार बार देखनेमे यांत्रिक सिद्धान्त यांत्रिक स्पष्ट होजानसे कार्य करनेवाला उस कार्यके यन्त्र द्वारा होमकन के उपाय सोचन लगता है। इसप्रकार एक नये यन्त्र या—यन्त्रि श्रम बचानके एक नये साधनका आविष्कार होजाता है।

श्रमविभाजन उमी अवस्थामें सम्भवहै जब उत्पादनका धन मात्र परिमाण पर्याप्त विस्तृत हो। बहुत छोट परिमाणमें उत्पादन होनापर कार्य इतना अधिक नहीं होता कि उन्हें इनके व्यक्तिगतमें बाटाजाय और दूसरे कार्यका श्रमक भाग तथा उपविभागमें बाटनेमें समग्र श्रम और धन दोनोंकी अधिक आवश्यकता पडती है। इसकारण श्रमका अधिकाधिक विभाजन मर्दव उत्तरातर वृद्धिशील और बड़े पैमानमें उत्पादनसे सम्बन्धित होता है।

श्रमविभाजनकी सीमारखा बाजारका विस्तार है। इस बचनका आधार श्रम-विभाजन और उत्पादन-परिमाणका सम्बन्ध है। उत्पादन जितनेही विस्तृत परिमाणमें होगा श्रमविभाजन उतनाही अधिक लाभप्रद होगा। परन्तु यदि इस उत्पादनकी खपतके लिए सुदूरव्यापी और विस्तृत बाजार न हो, तो उत्पादनको अनिवार्यतः मरुचित करना पडगा और तदनुसार श्रमविभाजन कमसे कम लाभप्रद होनेके कारण मरुचित होता जायगा। इस सम्बन्धमें यह कहदेना अनुचित न होगा कि जब उत्पादन-मुन्यनया न्य-विनयके लिए होता है और मानवीय आवश्यकताय और उपयोगितायामें उसका सम्बन्ध नष्ट होजाता है उमी समय मशीनोंका प्रभुत्व मानवजीवन और समाजव्यवस्था पर सर्वोपरि होजाता है। और ऐसी ही अवस्थामें श्रमविभाजनका रूप और सीमारखा बाजारके विस्तारमें निश्चित होते हैं।

उत्पादन के माधन—पूँजी

अधिकतर विचारवान पूँजीवा श्रमका एकरूप माना है और भविष्य श्रम, भूत श्रम इत्यादि नाम दिये हैं। कुछ लोगान इस भूमि और श्रम दोनों का मिश्रित रूप मज्जा है। प्राचीन ग्रंथशास्त्रियों ने पूँजीका मुख्यतया श्रमिका का काममें लगाये गये नवनवाले कोषके रूपमें देखा है, जिसमें उन्होंने मशीनरी इत्यादिका भी सम्मिलित किया है।

उत्पादनका एक रूपतो बहने जिसमें उत्पादन और उपभोगके बीचमें कमसेकम समयका अन्तर पड़ता है और इसकारण इस प्रणालीमें भूमि और श्रमके प्रतिनिधित्व किसी अन्य माधनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। स्पष्ट है कि इस प्रणालीमें भूमि और श्रमका सम्बन्ध एक दूसरेमें सीधा होगा। इस प्रणालीको हमें अपरोक्ष प्रणाली कहेंगे। उदाहरणके लिए मछुआको लीजिए जो हाथसे मछली पकड़ता है। उत्पादनकी यह प्रणाली होमजता है कठिनही और मछलिया बहुत कम पकड़ी जायें तथापि इसमें कमसेकम प्रतीक्षाकी आवश्यकता है और भूमि (नदी अथवा समुद्र) तथा श्रमके अनिवार्य अन्य किसी साधनकी सहायता की आवश्यकता नहीं। योड़ी देखें लिए कल्पना कीजिए कि कोई आदमी एक जालका आविष्कार करता है। अब यदि मछली पकड़नेकी प्रणाली बदलती है और हाथसे बजाय जालकी सहायता से मछली पकड़नी है तो इसकेलिए यह आवश्यक है कि या तो मछली पकड़नेवाला स्वयम् मछली पकड़नेका काम छोड़कर जाल बुननेका कामकरे और जाल तैयार होनेपर मछली पकड़ना आरम्भ करे अथवा मछली पकड़नेवाला किसी दूसरे आदमी से जाल बुनवाये और जाल तैयार होनेके समय तक उसके जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध करे। दोनों अवस्थाओंमें यह आवश्यक है कि जाल तैयार होनेतक प्रतीक्षा करनेकी क्षमता उत्पादक वर्गमें हो—यद्यपि कुछ अवकाश-काल उसे उपलब्ध हो। और अधिक दृष्टिसे अवकाश-काल का अर्थ हुआ वर्तमान आवश्यकताओं से अधिक उत्पत्ति। इस अवस्थामें श्रमविभाजन आवश्यक है। अवकाश-काल और श्रम-

विभाजनका सम्बन्ध इतना घनिष्ट है कि यह कहना कठिन है कि इनमें कौन मुख्य है, कौन गौण पर अवकाश-कालके बिना श्रमविभाजन सम्भव नहीं दीसता।

इस उदाहरणमें जालको हम पूँजी कहेंगे और यदि जालके उत्पादन क्रमको ध्यानमें रखें तो कुछ बातें बहुत स्पष्ट समझमें आती हैं। पहिली तो यह कि जाल स्वयं श्रम और भूमिसे निर्मित एक वस्तु है। इसप्रकार वह उत्पादनका प्राथमिक साधन नहीं होसकता। किन्तु वह मनुष्यकी कोई आवश्यकता प्रत्यक्षतः पूरी नहीं करता और इसकारण वह अन्य उत्पादित वस्तुओंमें मिला है। उसकी विशेषता यह है कि वह उत्पादन-कार्यमें सहायक है। दूसरी बात यह है कि यह सहायता मुख्यतः इस रूपमें है कि वह श्रम और भूमि का सम्बन्ध बदल देता है और उसे अपरोक्षसे परीक्षा बनादेता है। इसका फल यह होता है कि उत्पादन-काल दीर्घ होजाता है। इस प्रकार हम इस त्रिजंघपर पहुँचते हैं कि पूँजीमूलक उत्पादन प्रणाली वह है जिसमें उत्पादन-काल विस्तृत होता चला जाता है। यह तथ्य श्रम विभाजनके कारण अधिकतर छिपा रहता है।

उत्पादनकाल और उसकी दीर्घता

उत्पादन-काल और उसकी दीर्घताका अभिप्राय समझनेका आवश्यक है। ऊपर यह आये है कि पूँजीके द्वारा उत्पादन और उपभोगका अन्तर बढ़जाता है। इसतरह उत्पादन-काल का अर्थ हम यो करसकते हैं : वह काल जो किसी वस्तुके निर्मित होनेके आरम्भसे अन्ततक लगता है। उत्पादन-काल की यह व्याख्या आस्ट्रियन अर्थशास्त्री बैमबावरके आधारपर है और उन्हींके आधारपर हमने उपरिलिखित पूँजीकी विवेचना भी की है। परन्तु हम व्याख्याकी कठिनाई यह है कि विभिन्न वस्तुओंके निर्माणकी आरम्भ और समाप्ति भिन्न भिन्न समयपर होगी। इसके अतिरिक्त वस्तुओंका आरम्भ और उनकी समाप्ति कब हुई यह भी कहना कठिन होगा। बैमबावर ने इन कठिनाइयोंको दूर करनेके लिए औसत उत्पादन-काल माना है पर यह औसत भी बहुतकुछ इच्छाश्रित एवं काल्पनिक ही होगा। डा० हायेक ने इस प्रश्नको सुलझानेका प्रयत्न किया है : पहिले उन्होंने उत्पादन सामग्री और उत्पत्तिकी परिभाषा दी है।

‘विभी भी अवधि-विशेष में जितने भी उत्पादनके स्थायी उपकरणों की सेवाएं उपलब्ध हैं, उनकी सेवाओंके समूहकी शुद्ध उत्पादन-सामग्री कहेंगे। जब स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकारके उपकरणोंकी सेवा प्राप्त होनीहै तो उसे मिश्रित उत्पादन सामग्री नहोंगे।’ उस अवधि विशेषमें उत्पादन सामग्रीके प्रयोगद्वारा उत्पत्ति प्राप्त करनेकी क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र की परिभाषामें हम उत्पादन कहते हैं। उत्पत्तिसे अभिप्राय है उत्पादन सामग्रीके प्रयोगद्वारा उपभोगता को उपलब्ध सेवाओं द्वारा। प्रत्येक उत्पादन निम्न और उत्पत्तिके बीच जो काल बीतताहै उसेही उत्पादन-अवधि कहेंगे। ये अवधिया भिन्न भिन्न प्रकारके उत्पादनके अनुसार भिन्न होंगी और इनमें एकरूपता भयवा समानताकी कल्पना व्यर्थ है। आदर्श रूपसे दो प्रकारकी परिस्थितिया हो सकती हैं : एक तो ये कि किसी एक समयमें उत्पादनके उपकरणोंका उपयोगहो और फिर बहुत कालतक सेवाएं मिलती रहें, जैसे कोई मनुष्य पेड़में एक डाली तोड़ते और फिर बहुत दिनतक उसका प्रयोग छड़ीके रूपमें करता रहें। दूसरी ये कि बहुत कालतक उत्पादन-उपकरणोंका उपयोग करते जायें और उनका फल एकमात्र ही एकक्षणमें उपलब्ध हो। पर जैसा हमने कहा ये आदर्श परिस्थितिया हैं और वास्तवमें इन्हीं दोनोंके बीचकी विभिन्न दशाएं मिलती हैं।

हमने ऊपर कहा कि पूँजी उत्पादन प्रणालीमें उत्पादन-अवधि बड़ जाती है। अब प्रश्नहै कि इसप्रकार की प्रणाली क्या अपनायी जाती है। आदिक दृष्टिसे इसका एकही उत्तर होमकता है और वह यह कि उत्पादन अवधिके बढ़नेके साथ साथ उत्पादनभी बढ़जाता है। उपरी तौरपर देखनेसे यह अर्थार्थ सा लगभगता है कि आविष्कारों और नवीनताओंके द्वारा उत्पादन-काल घटनेके स्थानपर और बड़ जाये। पर ध्यानपूर्वक देखनेसे इस बातकी यथार्थता स्पष्ट होजावेगी—अहातक आविष्कार (जिनका पदार्थगत रूप पूँजी होती है) धर्म और भूमिका सम्बन्ध अपरोक्षमें परोक्ष करदेते हैं, वे अनिवार्यतः उत्पादन-अवधि बड़ा देने हैं। महा यह बात समझ लेनी है कि जब हम उत्पादन-अवधिके बड़जाने की बात कहतेहैं तो हमारी दृष्टिमें तुलनाके लिए उत्पादनकी वह प्रणाली है जिसको हमने ऊपर अपरोक्ष कहा है। यह सदैव सम्भवहै कि दो पूँजीवादी प्रणालियों में से एक कम और दूसरी अधिक समय लेनेवाली हो।

उत्पादन अवधि और उत्पादनशीलता

उत्पादन अवधिके बढ़नेसे उत्पादनशीलता बढ़जानेके कुछ कारणहैं। अधिकतर ऐसा होताहै कि उत्पादनके कुछ उपकरण ऐसे होनेहैं, जिनका उपयोग प्रस्तुत काल में नहीं होरहा होता। यदि हम उनका उपयोग करें तो उत्पादनमें वृद्धि अवश्य होगी। पर उनके उपयोगके लिए कुछ अन्य उत्पादक साधनो और सेवाश्रोत्री आवश्यकता होगी, जिन्हें हमें अन्य उत्पादन कार्योंसे हटाकर प्रस्तुत उत्पादन कार्य में लाना पड़ेगा। इसका फल यही होगा कि उत्पादन काल बढ़ जायेगा। दिकसेल ने ऊनी वातको इस ढंगसे कहाहै कि पूँजीमूलक उत्पादनके साधनोकी दो कोटिया होतीहैं प्रस्तुत श्रम और भूमि तथा संचित भूमि और श्रम। संचित भूमि और श्रमकी कुछ सेवाएँ सदैव अमूल्य होतीहैं और इसकारण प्रस्तुत भूमि और श्रमका उपयोग जब उत्पादनके लिए किया जाताहै तो संचित श्रम और भूमिका सहयोग भी प्राप्त होने पर उत्पादन अवश्य अधिक होता है।

इनके प्रतिरिक्त दीर्घकालीन उत्पादन-प्रक्रियामें बहुतसे उन पूरक उपकरणों की सेवाएँ उपलब्ध होसकती हैं जो अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रियामें इसलिये अप्राप्य होगी कि उनकी आवश्यकता अन्य वस्तुओंके उत्पादनमें होती है।

परन्तु कालकी दीघता और उत्पादनशीलता के पारस्परिक सम्बन्धका वास्तविक रूप समझनेके लिए उत्पादन वृद्धि तथा उसमें आविष्कारोका भाग समझना आवश्यक है। हमन ऊपर अपरोक्ष उत्पादन-प्रणालीका जो उदाहरण लियाथा, उसमें देखाथा कि मछलियाँके उत्पादनकी वृद्धिका वास्तविक कारण जालका आविष्कार था। उत्पादन अवधिका बढ़जाना इस आविष्कारके उपयोगका अनिवार्य परिणाम था। इस दृष्टिसे देखनेपर वृद्धिका वास्तविक कारण आविष्कार है और क्योंकि आविष्कारके उपयोगमें समय अवश्य अधिक लगगा इसकारण दीर्घकालीन उत्पादन प्रक्रिया अवश्य अधिक उत्पादनशील होगी। परन्तु आविष्कार उसी समय अपनाये जासकते हैं जबवे उत्पादनके लिए लाभकारी हों। लाभकारी होनेका अनिवार्य यहहै कि वर्तमान भूमि और श्रमसे सापेक्ष रूपमें कम व्ययशील हो। इस प्रकार मशीनरी वर्तमान श्रमकी बचत करती है। कल्पना कीजिए कि किसी उत्पादन उद्योग को आविष्कार द्वारा कोई नया उत्पादन का साधन उपलब्ध होगया है।

श्रमकी वचन अथवा प्रतिस्थापना दो प्रकारसे हो सकती है। एक तो उद्योगश्रमना निमाण बढ़ादे और प्रस्तुत श्रम और भूमि उतनीही रख, दूसर कुछ प्रस्तुत श्रम घटा दे। दूसर शब्दोंमें या तो कम श्रमसे पहिलेही जितना उत्पादन कर अथवा उनसे श्रमसे पहिलेसे अधिक उत्पादन कर। इस विद्वन्मन्य स्पष्ट है कि प्रत्येक देशमें पूनी (मंथोनरीक रूपमें आविष्कार) केवल श्रमका प्रतिस्थापन करती है।

पूजी की वकल्पिक परिभाषा

हम देखते हैं कि पूजीक प्रयोगका अर्थ उत्पादन बान को बढ़ा देना है। इसकारण इस बीचमें जब वस्तुएँ तैयार नहीं हुईं श्रमिकोंके जीवन-निर्वाहका प्रबंध होना आवश्यक है। पूजी मूलक उत्पादन प्रणालीमें इसीकारण प्रायः पूजीको श्रमजीवियोंको अग्रिम पारिश्रमिक प्राप्त करानेवाला अथवा जीवन निर्वाह कोष माना जाता है। इसी दृष्टिसे पूजीकी एक दूसरी परिभाषा भी दी जाती है। पूजी उत्पादक साधना सवाया और उपकरणों की वह कोटि है जो अस्थायी और अनित्य हो। आर्थिक दृष्टिसे इसका यह अभिप्राय हुआ कि जिनके वतमान और भविष्य उपयोग में ग्युनाधिक लाभ होसकता हो और जिनके रक्षणके लिए श्रमकी आवश्यकता होती हो। पूजीकी पहिली और इस परिभाषामें कोई मौलिक भेद नहीं है। यद्यपि पूजीका उद्भव अवकाश और आविष्कार द्वारा होता है फिर भी उत्पादनमें उसका रूप अनिवार्यतः कालवृद्धि का होता है और इसप्रकार पूजी कालाश्रित हो जाती है। कालाश्रित हानिसे वह अवश्य अस्थायी होगी और अस्थायी वस्तुके होनेसे उसके संरक्षणकी भी आवश्यकता होगी।

विभिन्न प्रकार की पूजी

१ स्थायी और प्रत्यावर्तनीय। स्थायी पूजीकी परिभाषा इस प्रकार है उत्पादन-प्रक्रियामें जिस पूजीका एकही रूपमें अधिक काल तक व्यवहार हो सके, वह स्थायी पूजी है। मंथोनरी, फैक्ट्रीकी इमारत इत्यादि स्थायी पूजीके उदाहरण हैं। यद्यपि इनकेभी कई उपयोग होसकते हैं और पर्याप्त समय मिलनेपर इनको एक

उपयोगसे दूसरे उपयोगमें लगाया जासकता है पर कालविशेष में इनको किसी दूसरे उपयोगमें प्रयुक्त करना सम्भव नहीं है और उत्पादनमें इनके द्वारा एकही प्रकारकी सेवा मिल सकती है। दूसरे एकबार इनका निर्माण होजाने पर इनकी सेवा-धारा बहुत कालतक अविरत चलनी रहती है। प्रत्यावर्तनशील पूजी उस पूजीको कहते हैं, जो उत्पादन प्रक्रियामें अनेक रूपोंमें काम आसके और एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें सुविधापूर्वक लगायी जासके। इसके उदाहरण, कच्ची सामग्री, नकद पूजी और मजूरी कांष हैं। इसी विभेद को भावमेंने दूसरे प्रकारमें और दूसरे नामोंसे स्थापित किया है। स्थायी और प्रत्यावर्तनशील पूजीको उन्होंने एकरस और परिवर्तन-शील पूजी कहा है।

स्थायी और प्रत्यावर्तनशील पूजीका उत्पादन कार्यमें पारम्परिक अनुगत तथा एकबा दूसरेमें परिवर्तित होजाना बहुत प्राचीन कालमें अर्थशास्त्रियोंके विचार का विषय रहा है। यहतां स्पष्टही है कि स्थायी पूजी की वृद्धिका अर्थ प्रत्यावर्तनशील पूजीकी हानिही होगा। इसीकारण म्किडोने मैशीनरी पर अपने विचार प्रकट करतेहुए कहाहै कि मैशीनरीकी वृद्धिका प्रभाव सदैव श्रमजीवियोंके लिए हानिपर होगा। इनके अतिरिक्त इन दोनोंके पारस्परिक अनुगतका व्यापारचरित धनिष्ट सम्बन्धही और कुछ विद्वानोंके मतमें प्रत्यावर्तनशील पूजी जब तीव्रगतिय स्थायी पूजीमें परिवर्तित होनेलगे तो सकटका आरम्भ समझना चाहिए।

२. निर्जा, सामाजिक और राष्ट्रीय पूजी। निजी पूजीमें हमारा अभिप्राय उस पूजीसे है जिसका स्वामित्व व्यक्तिगत हो। जैसे फँकट्रीकी इमारत, मैशीनरी इत्यादि। सामाजिक पूजी वह पूजीहै जिसका स्वामित्व पूरे समाजको प्राप्तहो जैसे म्यूनििसिपल और प्रान्तीय सड़को आदिका स्वामित्व। राष्ट्रीय पूजीका प्रयोग किसी राष्ट्र की सम्पूर्ण निजी तथा सामाजिक पूजीको प्रकट करनेके लिए कियाजाता है।

३. भौतिक और वैयक्तिक पूजी। भौतिक पूजी वह पूजी है जिसका पार्थिव रूप होना आवश्यक है और जिसे हस्तान्तरित किया जासकता है। वैयक्तिक पूजी से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेषकी योग्यता अथवा कुशलता से है। इसको हस्तान्तरित करना सम्भव नहीं। पहिली प्रकारकी पूजीमें अत्यचिक्किमके उपकरणोंका और दूसरी प्रकारकी पूजीमें उसकी व्यक्तिगत योग्यताका उदाहरण दिया जासकता है।

४ उत्पादन तथा उपभोग-पूजी। पहिली प्रकारकी पूजीमें कच्ची सामग्री, मैशीनरी, उपकरण इत्यादि वस्तुओंको सम्मिलित किया जा सकता है, जिनका कि उत्पादन-क्रियामें उपयोग होता है और दूसरी प्रकार की पूजीमें साधन पदार्थों, कपड़ों और मकानोंका जो प्रत्यक्ष रूपमें मनुष्य की आवश्यकताओं की तुष्टि करते हैं।

५ पारिश्रमिक पूजी तथा सहायक पूजी। पहिली प्रकार की पूजीका प्रयोग श्रमजीवियों को पारिश्रमिक देनेके लिए किया जाता है और दूसरी प्रकारकी पूजी उत्पादन कार्यमें उनकी सहायता करती है। मैशीनरी, कच्ची सामग्री, उपकरण इत्यादि इसके मुख्य उदाहरण हैं।

पूजी और वचन

पूजीका निर्माण उससमय होता है जब उत्पादन उपभोगसे अधिक हो। दूसरे शब्दों में पूजीका निर्माण और ग्राह्य वचन द्वारा होता है। वचनका अर्थ अर्थशास्त्रमें आयको वर्तमान व्ययसे हटाकर भविष्य व्ययमें लगाना है। वचन एक ओर तो किसी व्यक्ति अथवा समाजकी वचन करनेकी शक्तिपर निर्भर रहती है और दूसरी ओर वचन करनेकी इच्छा पर। वचन करनेकी शक्ति उत्पादनमें वृद्धि अथवा उपयोगमें ह्रास होनेसे बढ़ती है। इसका आधार किसी देश विशेषमें मिलने वाली प्राकृतिक सामग्री तथा अन्य उत्पादन-साधन हैं। वचन करनेकी इच्छा पूजी के निर्माण द्वारा लाभ प्राप्त करनेकी आशा तथा भविष्यके लिए प्रबन्ध करनेकी क्षमतापर निर्भर है। सन्तानके लिए कुछ सम्पत्ति छोड़ जानकी लालसा भी इस इच्छाको पुष्ट करती है। आधुनिक विद्वानोंके अनुसार वचनका परिमाण समाजकी आयपर निर्भर रहता है और आयका परिमाण इस बातपर कि वस्तुतः किनने मनुष्य उद्योग यंत्रोंमें उचित पारिश्रमिकपर लगे हुए है और कितना बेकार अथवा अनुचित पारिश्रमिक पर काम कर रहे हैं।

पूजी का संरक्षण

पूजीके संरक्षणसे हमारा तात्पर्य मुख्यतया उसके द्वारा पुनः उत्पादनके प्रबन्धसे है।

पूजीके पुनः स्थापन और सरक्षण का प्रबन्ध तीनप्रकार से होसकता है। प्रत्यक उपयोगमें एक कोपे इम बातके लिए रखा जाताहै कि उसके द्वारा आवश्यकता पडनेपर मशीनरी तथा अन्य स्थायी पूजीकी मरम्मत होमके। दूसरे समाजकी आय तथा प्रस्तुत परिश्रम और भूमिका उपयोग दो मुख्य भागोंमें बटा रहता है। एकतो उपभोग्य वस्तुएं बनानेमें और दूसरे उत्पादक वस्तुएं अथवा स्थायी पूजी उत्पन्न करनेमें। उद्दीहरणके लिए नमाजको मछलिया प्राप्त होती रहें, इमकेलिए यही आवश्यक नहीं कि कुछलोग मछलिया पकडते रहें परन्तु यहभी आवश्यक है कि कुछलोग जालभी बनाते रहें ताकि जब प्रस्तुत जाल ध्वंश होजायें तो नये जाल बनकर उनका ध्यान लेसकें। इसका यह अर्थ हुआ कि सामाजिक आयका विभाजन प्रस्तुत और भविष्य उपभोगके बीच किसी उचित अनुपातमें होना चाहिए। जो आय भविष्य उपभोगके लिए उपयुक्त होतीहै, उसेही हम बचत कहने है।

सामाजिक अवकाशनों भी बचतका आधार माना जासकता है। इसीके द्वारा आविष्कार सम्भव है। आविष्कारा द्वारा न केवल पूजीका सरक्षण ही होता है वरन् उसरी उत्पत्ति भी होती है। अवकाशके अभावमें बचतभी सम्भव न होगी।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिलने पूजीके सम्बन्धमें निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित किये है :

१ उद्योग सदैव पूजीके द्वारा सीमित होता है। इमका अभिप्राय यहहै कि समाज को कालविशेषमें जितनी पूजी उपलब्ध होगी, उद्योगका विस्तारभी वही तक होसकेगा।

२ पूजी बचतका परिणाम है। बचत और पूजीके सम्बन्धमें ऊपर विवेचन किया जाचुका है।

३ जो कुछभी उत्पादन द्वारा प्रप्तुन होताहै उस सभीका उपभोग होता है। इसप्रकार बचन और पूजीभी व्यय और उपभोगका रूप है।

४ वस्तुओंके लिए माग श्रमके लिए माग नहीं है अर्थात् यदि किसी समयमें समाजको अधिक वस्तुया की आवश्यकता होतो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे अधिक श्रमजीवियों की भी आवश्यकता होगी। इसप्रकार मिलके अनुसार अधिक माग और अधिक व्ययका परिणाम अनिवार्यत यह नहीं होसकता कि समाजमें बेकारी की कमी हो।

व्यवस्था

व्यवस्था की आवश्यकता

यद्यपि उत्पादनके लिये साधन व्यवस्थाका, विक्रमेल आदि अनेक अर्थशास्त्रियोंने मार्शलसे मतभेद प्रकट करतेहुए, स्वतन्त्र रूप माननमे इन्कार कियाहै परन्तु फिर भी वर्तमान समयकी उत्पादन-प्रणालीमें श्रम और पूँजीको उत्पादन-क्रियाओंमें संयोजित करनेका कार्यभी महत्वपूर्ण होगया है। उत्पादनका क्षेत्र और परिमाण जितनाही विस्तृत होता जायेगा, श्रमकी उचित देखभाल, श्रमजीवियोंके पारस्परिक सम्बन्धका उचित प्रबन्ध, उनके कार्यकी जाच इत्यादि कार्य आवश्यक होने जायेंगे। व्यवस्थासे तात्पर्य उन प्रबन्धोंमें है जो उत्पादनार्थ भूमि, श्रम और पूँजी के सामग्री उपयोगके लिए आवश्यक हैं और पूँजीमूलक उत्पादन प्रणालीमें व्यवस्थाको बहुत अधिक महत्व प्राप्त होजाता है। वास्तवमें उत्पादनमें भूमि, श्रम और पूँजीको किसप्रकार सम्बन्धित किया जाये और किस प्रणालीमें एक दूसरेको सर्वोत्तम सहयोगी बनाया जाये, यही व्यवस्थाका अभिप्राय है। मार्शल व्यवस्थाके अन्तर्गत उद्योग-माहससों भी रखता है और उसका अनुसरण करतेहुए कुछलाग व्यवस्थासे उद्योगपतियोंकी कार्यकुशलता, दृढ़ता, दूरदर्शिता तथा अन्य आवश्यक गुणोंका अर्थ सेते है। उद्योग-माहससे तात्पर्य उद्योगपतिकी उम्र विशेषतामे है जिस के फलस्वरूप वह उद्योगकी हानि लाभ तथा अनिश्चितताका सामना करनेको उद्यत होता है। इसप्रकार नवीन आविष्कारोंतथा अन्य प्रकारकी नवीनताओंका उत्पादन में उचित प्रयोग इसी साहस द्वारा सम्भव होता है। संक्षेपमें व्यवस्थाएक अथवा उद्योगपतिके मुख्य कार्य ये हैं:

- (१) उद्योगके आवार तथा परिमाणका निश्चय करना।
- (२) श्रम और पूँजीके सम्बन्धोंको बनाये रखना।

(३) क्रय-विक्रय, पूजी तथा उत्पादन-परिमाणके सम्बन्धमें निश्चय करना ।

(४) उत्पादन-साधन किममात्रा और किस अनुपातमें प्रयुक्त होंगे, इसका निर्णय करना वास्तवमें व्यवस्थापकके सब कार्योंका सार यह है कि उसे निर्णय करना पड़ता है कि क्या, कितना और किस भाति उत्पादन करना है और किसप्रकार उसे बेचना है ।

बड़े परिमाण में उत्पत्ति

हम लिख चुके हैं कि व्यवस्थापक अथवा उद्योगपति का मुख्य कार्य उद्योगके आकार तथा परिमाण का निर्णय करना होता है । उत्पादनका परिमाण विस्तृत करने में उत्पादन-कौशलमें बहुत वृद्धि होमक्ती है और साधारणतया बड़े बड़े उद्योगोंको छोटीसे कही गई इन लाभ प्राप्त होता है । इसीकारण पूँजीमलक उत्पादन-प्रणाली की प्रवृत्ति बड़े बड़े उद्योगोंको स्थापित करनेकी तरफ रहती है । बड़े परिमाण में उत्पत्ति करनेसे दोषकार के लाभ प्राप्त होते हैं । मार्गल एम्को आन्तरिक और दूसरेको बाह्य लाभ कहता है । आन्तरिक लाभ वे हैं जिनको केवल बड़े परिमाणमें उत्पत्ति करनेवाले उद्योगविशेष ही उठासकते हैं । इसके अनतिरिक्त कुछ ऐसेभी लाभ हैं जो पूर्ण उत्पादन प्रणालीको प्राप्त होते हैं । बाह्य लाभ उद्योगधन्यो के स्थानविशेष में एकत्र होजाने में प्राप्त होनेवाली सुविधाएँ हैं । उद्योगधन्यो के एक स्थानपर एकत्र होनेमें पहिला लाभ तो यह है कि उन स्थानकी उद्योग-कुशलता बढ-गत होजाती है । बहुतसी बातें बच्चे बिना सिखाये सीखजाते हैं । हर एकको उस स्थानकी विशेष कला सीखनेके लिए सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं क्योंकि वहापर उस कलाके विशेषज्ञ रहते हैं । इस स्थानीकरणसे दूसरा लाभ यह है कि उन स्थानपर बहुत से सहायक उद्योगोंके विकासका भी अवसर रहता है । प्रायः देखनेमें आया है कि जहा एक मुख्य उद्योग स्थापित हुआ वहा अथवा उसके आस पास उसमें सम्बन्धित अनेक सहायक उद्योग विकसित होजाते हैं । तीसरा लाभ यह है कि विशेषज्ञ श्रम-जीवियोंको नौकरी मिलनेके अनेक अवसर प्राप्त होने रहते हैं । इसकारण उन्हें जीविकाके सम्बन्धमें चिन्ता नहीं रहती । एक उद्योगपतिके साथ न बननेपर बिना किसी विशेष झगड़के दूसरे उद्योगमें स्थान मिलजाता है । इन लाभोंके अतिरिक्त

उद्योगोंके एकत्र होनेमें नये नये आविष्कारोंकी सम्भावना रहती है। कुछतो इस लिए कि उस स्थानपर बहुतसे विशेषज्ञ रहते हैं, उनका सहयोग और स्पर्धा दोनों ही आविष्कारोंके लिए सहायक होत हैं और कुछ इसलिए कि उद्योगोंके एकत्र होने से मूल्यवान् और बहुनहीं विनिष्ट प्रकारके यन्त्रोंका प्रयोग सम्भव होता है।

बड़े परिमाणमें उद्योग होनेसे दो प्रधान आन्तरिक लाभ प्राप्त होते हैं। पहिला कच्चे माल तथा अन्य उपकरणोंकी वचन और दूसरा निपुणताका अधिक उपयोग। यद्यपि आरम्भमें अधिक परिमाणमें उत्पात्ति करनेसे अधिक माल श्रमजीवियों और व्ययकी आवश्यकता होती है पर हर दृष्टिसे इन सबकी वचन होती है। अर्थात् इनका उपयोग कम मूल्यमें होता सम्भव होता है। बहुतसा माल इकट्ठा मगवानेमें बड़े उद्योगपतियों का बरनेमें कुछ अधिक लाभप्रद स्थिति प्राप्त होजानी है। वह दूर से और अच्छेसे अच्छा माल मगवा सकता है। अधिक माल खरीदनेपर मूल्य कम देना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वह विनिष्ट और मूल्यवान् यन्त्रोंका प्रयोग कर सक्ता है। छोटे उद्योगोंको स्थायी पूँजी निस्तृत करनेका अवसर कठिनाईसे मिलता है क्योंकि स्थायी पूँजी सदैव श्रमकी वचन करती है और इसकारण उत्पादन को स्थायी पूँजी बढानेके लिए अपना उत्पादन बढाना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे यन्त्रों जिनका प्रयोग किसी कार्यके एक छोटे भागके लिए होता है। ऐसे यन्त्रोंका लाभ केवल बड़े बड़े उद्योग और कारखानोंही उठा सकते हैं। कारण यह है कि श्रम विभाजन और श्रमविनिष्टता और निपुणताका पूरा लाभ बड़े बड़े उद्योगोंमें ही मिल सकता है। यह बात हम श्रमविभाजनकी चर्चा करत हुए समझ चुके हैं। विशेषज्ञों का ज्ञान और सेवाओंका लाभ उठानेके लिए उद्योगपतियों को उन्हें अधिक वेतन देना पड़ता है। अधिक वेतन बड़े बड़े कारखानोंही गुविधा और लाभपूर्वक देसकत हैं। इसकारण छोटे उद्योगोंमें इन सेवाओंमें वचितही रहजात है। आधुनिक उत्पादन पद्धति का एक बड़ा आधार आविष्कार और नवीनता है। उत्पादन-प्रणालीमें नवीनताओंका समावेश करनेकी क्षमताके अभावमें वर्तमान आर्थिक व्यवस्था जीवन्तहीन होने लगती है। बड़े परिमाणमें उद्योग होता है तो उसमें वैज्ञानिक अनुसन्धान आदि करानेका अवसर मिलता है। वैज्ञानिक अनुसन्धान व्यय-साध्य काम है और जबकि छोटे उत्पादन का क्षेत्र बड़ा न हो, इसका कोई सुचारु रूप असम्भव है। यही नहीं, नये आविष्कारोंका, नयी उत्पादन रीतियों और अच्छे यन्त्रोंका उप-

योगभी छोटे छोटे उद्योगधन्धे नहीं करसकते। अधिक परिमाणमें उत्पादनकी कुछ अनिवार्य हानियाँ भी हैं। बड़े उद्योगोंका उत्पादन आवश्यकतासे बहुत अधिक होगा। इसकारण मन्दीके समय जब बिजली बहुत कम होजाती है, ऐसे उद्योगोंको बहुत हानियाँ सहनी पड़ती हैं। बहुत अधिक स्थायी पूँजी लगे रहनेका अर्थ यह है कि बहुत ऐसे व्यय जो स्थायी हैं बिना उद्योग बन्द किये घटाये नहीं जासकते। उत्पादन-परिमाण कम हो या अधिक, ऊँचा वेतन पानेवाले पदाधिकारियोंको अलग नहीं किया जासकता, यद्यपि उससमय उनकी सेवाश्राकी आवश्यकता न हो। इसके अतिरिक्त जहाँ बड़े बड़े उद्योग नये आविष्कारोंसे लाभ उठासकते हैं वहाँ उन्हें हानि भी होसकती है, क्योंकि आविष्कार शीघ्रतापूर्वक भी होसकते हैं और इस दशामें उनको अपना नेमें पुरानी स्थायी पूँजीको क्षति होगी। पर यह हानि सामाजिक दृष्टिमें अधिक है भिन्न भिन्न उद्योगोंको दृष्टिमें कम, क्योंकि नये आविष्कारोंका वे पेटेन्ट राइट खरीद सकत हैं और इसप्रकार वे उनका उपयोग स्थगित रखसकते हैं। फिर भी यह निर्विवाद है कि उद्योग अपनेही नियमांस बद्ध होते हैं और उनमें परिवर्तन-शीलता तथा गत्यात्मकताका अपेक्षाकृत अभाव होता है। यह भी न भूलना चाहिए कि जहाँ बड़े उद्योग प्रत्येक विभागका सुचारु वैज्ञानिक प्रबन्ध करसकते हैं, ऊँचे वेतन देकर शिक्षा और अनुभव प्राप्त कुशल प्रबन्धक रखसकते हैं, वहाँ उत्पादन क्षेत्रके विस्तारके साथ प्रबन्ध और नासन-व्यय बढ़ता चलाजाता है। तब फिर यहाँ भी आवश्यक होजाता है कि छोट पदाधिकारियों पर निर्णय और अन्य महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वके कार्य छोड़े जायें। इसप्रकार उद्योगोंको बड़ी हानि होजाने की सम्भावना रहती है।

व्यवस्था के रूप

बड़े परिमाणमें जब उत्पत्ति होती है तो उसका स्वामित्व और प्रबन्ध एक व्यक्ति के वशकी बात नहीं रहती। एक तो उत्पादन व्यवस्थाकी एग्रेगामित्व रीतिमें पूँजीकी संदेव कठिनता रहती है क्योंकि इसप्रकारके उद्योगोंको बैंक ऋण कठिनतासे देने हैं। दूसरे स्वामीका अधिक दायित्व असीमित होता है। इन कारणोंसे बड़े बड़े उद्योगोंके व्यवस्था आकृति, साम्मिलन पूँजी-कम्पनी और कारपोरेशन के रूपमें

अधिकतर होती है। महकरी समितिया भी व्यवस्था का एक रूप हो सकती है। पर बहुत बड़ उद्योगों में यह रूप सफलतापूर्वक काम अपनाया गया है।

साभदारी में दो या दोसे अधिक व्यक्ति उद्योग के साथ साथ स्नामी होते हैं। उन दाना के बीच समनुबन्ध हो जाता है जिसके आधार पर यह निश्चित होता है कि प्रत्येक साभोदार कितना रुपया अथवा पूँजी व्यापार में लगायगा उसके और क्या क्या उत्तरदायित्व तथा अधिकार होंगे तथा लाभ में उसका कितना भाग रहेगा। साभोदारा के बीच पूँजी नकदी और सेवा तीनों का विभाजन होमकता है। और एसा भी होमकता है कि कुछ साभोदार केवल पूँजी लगायें और कुछ केवल सेवाएँ। साभोदारों के समनुबन्ध में अधिकतर साभोदारों के उत्तरदायित्व मान निश्चित कर दिया जाता है और उद्योग के लाभ और उनकी स्थायी पूँजी में उनका भाग उनकी पूँजी के अनुपात में बाँट दिया जाता है। साथ ही अधिकतर समनुबन्धों में यह स्पष्ट तथा निश्चित कर दिया जाता है कि उद्योग में हानि हानि पर जिस साभोदार को हानिका कितना भाग भरना पड़ेगा। आमतौर पर राजनियमों द्वारा सरकार समनुबन्धों का पालन करती है। पर यदि कोई साभोदार अपनी भाग न चुका सके तो राजनियमों द्वारा हर साभोदार अपनी सारी व्यक्तिगत सम्पत्ति के मूल्य के बराबर हानि पूरी करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जायगा।

- साभदारी में प्रत्येक साभोदार उद्योग सम्बन्धित कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। यदि एक साभोदार कोई वस्तु किसी मूल्य पर खरीद लेता है तो मूल्य देने के लिए सभी साभोदार उत्तरदायी होंगे चाहे वह खरीद उन्हें पसंद हो अथवा नहीं। यह दूसरी बात है कि उद्योग के नाम पर कोई व्यापारिक बातचीत करने में पहिले सभी साभोदार एक दूसरे से सलाह लें। पर यदि वे ऐसा न कर सकें अथवा यदि उनमें परस्पर मतभेद हो तो इसके कारण दूसरा तथा जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व में कोई भेद नहीं पड़ता। साभदारी का एक और भी रूप होता है। इससे ऐसा होता है कि कुछ साभोदार सीमित उत्तरदायित्व के साथ उद्योग में साभोदार होमकते हैं। घटा होने पर ऐसे साभोदारों को उनके भाग के अनुपात में ही हानि भरनी पड़ती है। एसी अवस्था में प्रायः तीन शर्तें लगाई जाती हैं। (१) उद्योग में उनका भाग नकद के ही रूप में हो सेवाओं के रूप में नहीं (२) उद्योग के नाम में उनका नाम न आवे और (३) वह उद्योग के नाम पर किसी प्रकार का लनदेन न करे।

साभेदारीसे कई लाभ हैं। इस व्यवस्था द्वारा अधिक पूजी उपलब्ध होसकती है। सभी साभेदार कुछ न कुछ पूजी लगाते हैं और इसके अतिरिक्त बँकोसे भी सुगमतासे ऋण मिलजाता है। दूसरी बात यहहै कि इसप्रकार उद्योग को विभिन्न प्रकारकी योग्यताधोका लाभ मिलता है। इसके साथ इसप्रकार की व्यवस्थामें व्यवस्थित व्यापारका बहुत कुछ स्वरूप बना रहता है।

- साभेदारी प्रथाकी कुछ हानिया भी हैं। इसमें पूजी प्राप्ति करनेकी क्षमता अपेक्षाकृत कम रहती है। माधारणतया यह होताहै कि उद्योग बढ़नेपर और फलतः पूजीकी अधिक आवश्यकता होनेपर साभेदारोंकी सरया बढ़ानी पडती है। इस दशामें प्रबन्धमें भी कठिनाई होनीहै और अधिक सरया होनेके कारण आपसमें मतभेद भी बहुधा हुआ करता है। मतभेदाका यदि निपटारा न होसका तो साभेदारी ही समाप्त करनी पडती है। इसके अतिरिक्त किसीभी साभेदारको यह अधिकार नहीं होता कि उद्योगमें वह अपना भाग बिना साभेदारोंकी सहमतिके अन्य किसी को बेच दे। इसकारण अलग होनेके लिए या तो वह अन्य साभेदारोंके भागोंको खरीदले या स्वयं अपने भागोंको उनके हाथ उनके इच्छित मूल्यपर बेचदे अथवा साभेदारी ही समाप्त कर दीजाये। इसके अतिरिक्त साभेदारोंकी एक दूसरेके कार्यके लिए सहमति तथा उनका असौमित्र ऋणदायित्व भी इस व्यवस्थाका दोष पूर्ण बनाते हैं।

सम्मिलित पूजी कम्पनीसाभेदारी और कारपोरेशनके मध्यकी अवस्था है। इसमें दोनों प्रकारकी व्यवस्थाओंकी विशेषताएँ मिलती हैं। सम्मिलित कम्पनीके स्वामीके ऊपर ऋण तथा अन्य दायित्व उत्पन्नही होतेहैं, जितने साभेदारीमें। भेद इतनाहै कि साभेदारीमें स्वामित्वका अधिकार एक समनुबन्धके आधार पर होता है और सम्मिलित पूजी कम्पनीमें स्वामित्व पूजी बाजारमें खरीदे जासकनेवाले हिस्सों द्वारा प्राप्त कियाजाता है। जिन लोगोंके पास हिस्सा है, उनके द्वारा निर्वाचित सचालकोंकी समितिके हाथमें प्रबन्ध और शासनका कार्य होता है। इस प्रकारकी व्यवस्थाको सीमित ऋण-दायित्वको छोड़कर और वे सारे लाभ होनेहैं जो कारपोरेशन द्वारा प्राप्त होसकने हैं।

कारपोरेशन राजनियम द्वारा कुछ विशेष उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए निर्माणित सस्था होती हैं। आरम्भिक कारपोरेशन व्यापारी नहीं थे। वे धार्मिक दानपुण्यके

अथवा शिक्षा सम्बन्धी थे। वे राजाज्ञा अथवा सरकारी दानपत्र द्वारा स्थापित किये जाते थे और राजेच्छासे उन्हें कुछ विशेषाधिकार और सरक्षा मिलती थी। मध्ययुगके शिल्प-सङ्घ सबसे प्रथम कारपोरेशनोमें से हैं जिनकी गणना व्यापारिक कारपोरेशनोमें की जासकती है। इसप्रकार की व्यवस्थामें यह होता है कि कुछ मनुष्य राज्यकी एक प्राथना पत्र भेजते हैं जिसमें एक राजाज्ञाकी प्रार्थना की जाती है, जिसके द्वारा उन्हें कारपोरेशनके रूपमें व्यापार करनेकी आज्ञा दी जाये। अगर प्राथना स्वीकृत होजाती है तो व्यापार चालू कर दिया जाता है। कारपोरेशन की विशेषता यह है कि यद्यपि यह कई व्यक्तियोंसे मिलकर बनता है और अनेक प्रकारके बाड, स्टॉक, शेयर तथा अन्य प्रकारके ऋण-माधनोके द्वारा पूजी इकट्ठा करता है, फिर भी उसका दायित्व सीमित रहता है। शासनकी दृष्टिमें यह एक व्यक्ति माना जाता है।

कारपोरेशन पूजीकी दृष्टिसे व्यवस्थाका अत्यन्त उत्तम रूप है। पर इन रूपमें धोका करनेके अवसर बहुत रहते हैं। कारपोरेशनके अधिकतर दोष डाइरेक्टर या अन्य कर्मचारियोंकी कपट-नीतिके कारण होते हैं। बहुत बड़ी होजाँने पर कारपोरेशन के चलानेका व्यय आवश्यकतासे अधिक बढ जाता है। और फिर बड़े बड़े कारपोरेशनोसे बे हानियाँ तो हैं ही जिनकी चर्चा हम बड़े परिमाणमें उत्पादन के सम्बन्धमें करवायें हैं।

उत्पादन-व्यय

उत्तम व्यवस्था का उद्देश्य न्यूनतम उत्पादन-व्ययमें अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करना होता है। उत्पादन-व्ययकी प्राचीन तथा आधुनिक परिभाषाओंका विवेचन हम इस पुस्तकमें भिन्न भिन्न स्थानोपर कर चुके हैं। विषय महत्वपूर्ण है इसकारण पुनश्चिन्ता का दोष होनेपर भी उत्पादन-व्ययका एकत्रित विवरण आवश्यक प्रतीत होता है। ओं कुछभी उत्पादनमें काममें आये उसे हम लागत कहते हैं और उसके फलस्वरूप जिन वस्तुओंका उत्पादन हो उन्हें हम उत्पत्ति कहेंगे। जो मूल्य हमें लागतके लिए देना पड़े वह उत्पादन-व्यय है। व्यय की आवश्यकता इसकारण हाती है कि सारी वस्तुएँ, सारे उत्पादनके साधन मनुष्यको प्रकृति द्वारा अनायास

ही नहीं मिल जाते। इसप्रकार उत्पादन-व्यय अन्ततोगत्वा इस बातसे निश्चित होता है कि इच्छित वस्तुके निर्माणमें जो श्रम करना पड़ा है, उसका क्या मूल्य है। उत्पादन केवल रूप-परिवर्तन मात्र करता है। श्रम और अन्य सामग्रीके एकरूप की जो उपयोगिता हम समझते हैं यदि उसके किसी दूसरे रूपकी उपयोगिता हमारी समझमें अधिक है तो पहिले रूपको हम दूसरे रूपमें परिवर्तित करनेका प्रयत्न करेंगे। इस प्रयत्न का अर्थ यह होगा कि हम पहिले रूपका नाश कर दें और इसका कारण स्पष्ट है कि एक उपयोगिताका बलिदान करकेही हम दूसरी उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। जबतक कुछ वस्तुएँ अपने प्राप्त रूपमें बिल्कुल ही उपयोगिता "हीन" न हों, उत्पादन सदैव व्यय-साध्य होगा। बलिदानकी हुई उपयोगिताको मापनकी कई रीतियाँ हो सकती हैं। इन्हीं रीतियोंको लेकर अर्थशास्त्रियोंमें कुछ मतभेद हैं, व्ययके स्वरूपके सम्बन्धमें कोई मौलिक मतभेद नहीं है। एक रीतिके अनुसार उत्पादन-व्ययके मापनके लिए पहिले हमें देखना चाहिए कि उनके निर्माणके लिए उत्तुरदायी व्यक्ति अथवा वगैरों को किन किन वस्तुओंको खरीदना पड़ता है और किन किन मूल्यों पर। इन सब मूल्योंका जोड़ही उत्पादन-व्यय होगा। इस रीतिमें दो प्रकारकी कठिनाईयाँ हैं, एक तो यह कि इस बातका निर्णय कठिन है कि कौनसी वस्तुएँ उत्पादक गिनी जायें। कुछ लोगाने भूमि, धन और पूँजी, कुछने व्यवस्था और उद्योग-साहसभी और अन्यने केवल श्रमको उत्पादक माना है और इन्हींके मूल्योंको वास्तविक उत्पादन-व्यय माना है। कुछ लोग इन सूचीमें यातायात, बीमा, पिसावट आदिके व्ययको भी सम्मिलित करते हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि कुछ उत्पादक सेवाएँ भी हैं और उनका मूल्य निश्चित नहीं हो पाता। इसप्रकार लाभ इत्यादि भी व्ययमें सम्मिलित करना पड़ता है और यह कुछ तर्कोंके विरुद्ध है।

मार्शलन वास्तविक और मौद्रिक व्ययका भेद किया है। उनकी परिभाषाके अनुसार सभी प्रकारके श्रम जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे किसी वस्तुके निर्माणमें आवश्यक हैं तथा आवश्यक पूँजीके लिए कीगयी प्रतीक्षा—ये दोनों साथ साथ उस वस्तुके निर्माणका गैरार्थ व्यय होंगे। हर प्रकार का श्रम और पूँजी उपलब्ध करने के लिए जितने द्रव्यकी आवश्यकता है उसको उत्पादन व्ययका मौद्रिक माप कहेंगे। अब कठिनाई यह है कि विभिन्न कारखानोंके उत्पादन व्ययमें अन्तर पड़सकता है।

ऐसी अवस्थामें किसीका व्यय मूल्यना निर्धारक माना जावे। मार्शलने इस कठिनाईका समाधान प्रतिनिधि उद्योग मस्याकी कल्पना द्वारा किया है। प्रतिनिधि उद्योग सस्था वह है जिसकी व्यवस्था न बहुत अच्छी और न बहुत बुरी हो। इस प्रतिनिधि मस्याका जो व्ययही उमीकों उत्पादन-व्यय माना जा सकता है। परन्तु वास्तविक व्ययकी कल्पनाही व्यर्थ है। किसी वस्तुके निर्माणमें कितना कष्ट उठाना पड़ा इसका कोई सर्वमान्य मापदण्ड नहीं हो सकता। मापनेकी दूसरी रीति यह है कि उत्पादनके लिए उठाये गये कष्टको न मापकर उन वस्तुओंको मापनेकी चेष्टा कीजाय जो उसी उत्पादन साधनसे बन सकती थी, पर बनायी नहीं गयी। इस मतका आधार यह है कि एवही उत्पादन-साधनसे कई वस्तुएँ बन सकती थी। इसप्रकार किसी सेवा अथवा साधनको उत्पादनके लिए उपयोगमें लाकर बहुतसी वस्तुओंका बर्तमान करना पड़ता है। जब हम एक सेवाको किसी उपयोगमें लाते हैं तो उसका अर्थ यही हुआ कि अन्य उपयोगोंमें लानेका अवसर जाता रहा। इसप्रकार कोई वस्तु बनाकर जिन वस्तुओंके निर्माणका त्याग कियागया, इन्हीं अन्य वस्तुओंका मूल्य उस वस्तुका उत्पादन-व्यय हुआ। उत्पादन-व्ययके मापनेका यह सिद्धान्त अवसर अथवा वैकल्पिक व्यय कहलाता है। यद्यपि वैकल्पिक व्ययका सिद्धान्त आज प्रायः सभी लोग मानते हैं परन्तु यह निश्चित करना कठिनसा है कि एक उत्पादन के साधन या उत्पादनके साधनके सहयोगसे दूसरी कितनी वस्तुएँ बन सकती हैं। फिर इन विभिन्न वस्तुओंके मूल्योंका द्रव्यमें परिवर्तित करनेपर मौद्रिक व्ययही धार्मत्विक वस्तु रहजायेगी, वैकल्पिक वस्तुएँ और अवसर केवल निरर्थक कल्पना मात्र होंगे। इसप्रकार मार्शलके वास्तविक व्यय और आधुनिक वैकल्पिक व्ययमें कोई अन्तर नहीं रह जायेगा।

उत्पादन-व्ययके सम्बन्धमें सामाजिक व्ययका विवेचन कर देना भी आवश्यक है। बहुतसे ऐसे व्यय हैं जो किसी विशेष उत्पादन सस्थाको नहीं करने पड़ते। वरन् इनका भार सम्पूर्ण समाजको सहना पड़ता है। उदाहरणके लिए यदि कोई मस्या कुछ श्रमजीवियोंको हटादे तो उनके जीवन-निर्वाहका व्यय किसी उद्योग मस्याको भले ही न देनापड़े, पर समाजको अवश्य देना पड़ता है। इसीप्रकार उद्योगोंमें दुर्घटना बढ़जाने से, मन्दगी और घुएँसे, नकली चीजोंके बनानेसे और अत्यधिक विज्ञापन बाजीसे जो हानियाँ होती हैं, हो सकती हैं कि वे किसी उद्योग विशेषको न सहनी पड़ें।

पर समाज इनसे नहीं बचसकता । यह सामाजिक व्यय है ।

व्ययका विश्लेषण करतेहुए अर्थशास्त्रियोंने कई प्रकारके व्यय माने है । प्रत्येक वस्तुके बनानेमें जितना व्यय हुआ, उसकी जितनी वस्तुएँ बनीहैं उनसे गुणा करेंतो गुणनफल कुल व्यय होगा । दूसरी रीतिसे यही बात इसप्रकार कही जासकती है कि प्रत्येक उत्पादनके साधन और सेवाका उपयोग करनेमें जितना व्यय हुआ है, उसे यदि प्रयुक्त साधनों और सेवाओंकी कुल सरयासे गुणा करदें तो गुणनफल कुल व्यय होगा । कुल व्यय उत्पत्तिके अनुसार घटता बढ़ता रहेगा परन्तु उत्पत्तिके शून्य होनेपर भी कुल व्यय शून्य न होगा ।

उत्पत्तिकी सहायसे यदि कुल व्ययका भाग दियाजाये तो भागफल औमत व्यय होगा । औमत-व्ययभी उत्पत्तिके अनुसार घटता बढ़ता रहता है ।

कुल उत्पत्तिमें यदि वृद्धि करें तो उस वृद्धिके अनुसार कुल व्ययमें वृद्धि होती है । व्यय-वृद्धिको यदि उत्पत्ति-वृद्धिसे भागदें तो भागफल सीमान्त व्यय होगा । माननीजिए उत्पत्ति पच्चीससे तीस इकाई होगयी और कुल व्यय पचाससे पचपन रूपया होगया तो $\frac{25}{20} = 1.25$ सीमान्त व्यय होगा ।

ऐसे व्ययजो उत्पत्तिके साथ नहीं घटते बढ़ते, स्थायी व्यय कहलाते हैं । मशीनों और इमारतोंकी देखरेख, मैनजरों और कुछ अन्य श्रमजीवियोंपर व्यय उत्पत्तिका परिमाण घटानेसे परिवर्तित नहीं होता । परिवर्तनशील व्यय वहहै जो उत्पत्तिके परिमाणके साथ घटता बढ़ता रहता है । अविभाज्य व्यय कुछ ऐसे व्ययहैं जो यदि सस्था बन्दही कर देने का निश्चय न कर लियाजाये, तो सस्थाका हर दशामें करने पड़ेंगे । अविभाज्य व्ययका छोड़कर अन्य व्यय पूरक व्यय कहलाते हैं ।

हमने सीमान्त व्ययकी परिभाषा करतेहुए कहाहै कि यह व्यय उत्पत्तिमें वृद्धि करनेका व्यय है । इसकारण केवल परिवर्तनशील व्ययसे सम्बन्धित है । स्थायी और परिवर्तनशील व्ययका विभेद केवल अभ्यकालकी दृष्टिसे कियाजाता है । दीर्घकाल में उत्पत्ति बढ़ाने या घटानेसे स्थायी व्ययमें भी अन्तर आयेगाही ।

उद्योग धन्धों का अभिनवीकरण

अभिनवीकरण का अभिप्राय

अलिल विरव आर्थिक सम्मेलन १९२७ म उद्योग धन्धोंके अभिनवीकरण की परिभाषा इसप्रकार कीगयी थी

‘यह वह साधनहै जिसके द्वारा उद्योग धन्धोंकी उत्पादन विधि और संगठनमें श्रम तथा सामग्रीका न्यूनतम अपव्यय होता है। इसमें श्रमका वैज्ञानिक संगठन, उत्पादन-सामग्री तथा उत्पन्न वस्तुओंका भाननयन, उत्पादन की क्रियाओंका मरल बनाना और यातायात तथा विरुय प्रणालीको उन्नत करना इत्यादि सम्मिलित है।’

वर्तमान शताब्दीमें औद्योगिक संगठनको निर्धारित करनेवाली शक्तियोंमें महान् परिवर्तन हुए हैं। इनमेंसे मुख्य बाजारोंका विस्तार, उद्योग धंधोंमें विज्ञानका प्रयोग, श्रमजीवियोंकी शक्तिका वर्धन, प्रवन्धको तथा स्वाभियोंका पार्थक्य और मदभाव्य नीतिका पतनोन्मुख होना है। अभिनवीकरणका अभिप्राय इन परिवर्तनोंसे समझ धूमकर कियेगये नियन्त्रण द्वारा समन्वय प्राप्त करना है। अभिनवीकरण के दो पक्ष हैं। एकतो स्वतन्त्र तथा परस्पर प्रतिस्पर्धी उद्यमोंको एक दूसरेसे सम्बन्धित करके उनमें आवश्यक एकता स्थापित करना और दूसरे प्रत्येक उद्यमकी उत्पत्ति, अर्थवहन, कर्मचारी मजल और वितरण इत्यादिको कुशलतापूर्वक संगठित करना।

अभिनवीकरण के मुख्य अंग

निर्धारित कार्यक्रम, पुनर्व्यवस्था तथा विकास, ये तीन अभिनवीकरणके प्रधान अंग हैं। कार्यक्रम को निर्धारित करनेमें प्रथम स्थान वर्तमान तथा भावी बाजारों की जाच को दियाजाता है और उपभोक्ताओंके स्वभाव, रुचि इत्यादि पर निर्भर माग

की लोचका ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्योंकि इसीके आधारपर वस्तुका मूल्य न्यूनाधिक किया जाता है। बाजारोंकी जाचसे किसप्रकार की वस्तुको किस मात्रामें उत्पन्न करना चाहिए, उत्पादनविधि में कौन कौनसे परिवर्तनोंकी आवश्यकता है, भिन्न भिन्न कौशलवाल श्रमजीवियोंकी कितनी सख्यामें नियुक्ति कीजाये, कितने बच्चे माले तथा पूजीकी आवश्यकता हागी, आदि उत्पादनसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओंका निर्णय करनेमें सहायता मिलती है। आय-व्यय-लेखे (बजट) द्वारा नियन्त्रण पद्धतिसे यह निर्णय अत्यन्त सरल होजाता है, क्योंकि व्यक्तिगत नियन्त्रण के स्थानपर अब आकड़ों द्वारा नियन्त्रण होता है। इस नियन्त्रण पद्धतिके कई लाभ हैं :

(१) अत्यधिक उत्पत्तिके करनेकी सम्भावना कम रहती है। क्योंकि उत्पत्तिका प्रत्याशित वित्रीमें समन्वय किया जासकता है।

(२) उत्पादनके प्रत्येक विभागके उत्पादन-व्यय, कार्यक्रमका अनुमानित तथा वास्तविक खर्चों और कार्योंकी तुलना द्वारा नियन्त्रण किया जासकता है। -

(३) इसके द्वारा विवेन्दीकरणमें सहायता मिलती है, क्योंकि प्रत्येक विभागकी आर्थिक क्षेत्रमें स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करनेकी अवधि निश्चितकर दीजाती है।

(४) इसके द्वारा विभिन्न भागोंमें पारस्परिक सहयोग स्थापित किया जासकता है।

वित्री की मात्राका भलीप्रकार अनुमान करलनेमें उत्पादनके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उसमें वस्तु निर्माण करनेके लिए उचित सस्थाओंकी स्थापना और उनके लिए आवश्यक श्रम, ग्रंथ, निरीक्षण, नियन्त्रण इत्यादि का अनुमान करना कठिन नहीं होता। यहतो निश्चितही है कि अधिक मात्रामें उत्पत्ति करनेसे उत्पादन व्ययमें कमी की जासकती है परन्तु यह कमी केवल वर्तमान सस्थाओंके एकीकरण से नहीं बल्कि उत्पत्तिका कुशलतम सस्थाओंमें समाहरि करनेसे प्राप्त होसकती है। अभिनवीकरण द्वारा इस समाहार को प्राप्त करनेकी चेष्टा कीजाती है। इसकारण वर्तमान सस्थाओंके पुनः समूहणके लिए निम्नलिखित सुधारोंकी आवश्यकता होती है -

(१) अकुशल सस्थाओंको बन्दकरके उत्पादन कार्यको कुशलतम सस्थाओं द्वारा करवाना; क्योंकि इसप्रकार उन सस्थाओंकी पूर्ण उत्पादन शक्तिका प्रयोग होसकेगा।

(२) उत्पादन-व्यय को कम करनेके लिए नवीनतम यन्त्रों अथवा उपकरणोंका प्रयोग करना ।

(३) वैज्ञानिक अनुसन्धान विभागोंका स्थापित करना ।

(४) वस्तुओंके अतिरिक्त माननयन द्वारा उत्पादन व्यय कम करना ।

(५) नियन्त्रण यद्धतिमें परिवर्तन करके उपयुक्त नियन्त्रकोंका चुनाव करना ।
अभिनवीकरण नवयुवकों द्वाराही सुचारुरूप से किया जा सकता है । वृद्धावस्थामें नये औद्योगिक बनावरणका भलीप्रकार से अध्ययन करनेका उत्साह नहीं रहता परन्तु शक्तिशाली होनेके कारण वृद्ध प्रबन्धक लोग नवयुवकोंको उत्तरदायित्वपूर्ण स्वातंत्र्य न दिये करते, अभिनवीकरणकी दृष्टिसे यह उचित नहीं । तीसरे चालीस वर्षकी आयुके लोगोंको अपनी योग्यता दिखानेके लिए अधिक प्रयत्न मिलने चाहिए ।

अभिनवीकरण के लाभ तथा हानियाँ

भय प्रकट किया जाता है कि अभिनवीकरणके कारण एकाधिकारोंका सृजन होगा और एकाधिकारी मनमाने मूल्य लेकर उपभोक्ताओं का अहित करेंगे । परन्तु अभिनवीकरणका उद्देश्य तो कुशलपूर्वक उत्पादन द्वारा मूल्योंका कम करना है न कि अधिक । आगिक अभिनवीकरणके कारण कई लोगोंकी हानि अवश्य होती है । यदि एक उद्योग धन्धे द्वारा उत्पन्न वस्तुएँ किसी दूसरे अभिनवीकृत उद्योग धन्धेमें बच्चे मालके रूपमें प्रयुक्त होती हैं तो दूसरे उद्योग धन्धे वालोंको पहिले उद्योग धन्धे वालों की वस्तुएँ खरीदनेका एकाधिकार प्राप्त होजायेगा और वह इस अधिकार का दुरुपयोग करके पहिले उद्योग धन्धे वालोंकी हानि करसकते हैं ।

अभिनवीकरण द्वारा बेकारी फैलनेकी सम्भावना है । श्रमकुशल मनुष्योंके बन्द कर देने से और उत्पत्तिके नियन्त्रण तथा यन्त्रोंके नवीकरणमें कुछ लोगोंका अनावश्यक होजाना अनिवार्य है । अभिनवीकरण द्वारा अन्ततोगत्वा उत्पादन-व्यय और फलस्वरूप मूल्यमें कमी होनेसे मागमें वृद्धि होगी और इसकारण उत्पत्तिकी मात्रा बढ़ानेके लिए अधिक लोगोंको नियुक्त करनेकी आवश्यकता होगी । परन्तु प्रारम्भमें तो कुछ लोगोंको बेकारीकी पीड़ा सहन करनी ही पड़ेगी । इस समस्याको सुलझानेके

लिए बेकारीकी वृत्ति देनी होगी या श्रमके समयको कमकरके लोगोंको बेकारीसे बचाना होगा। इसीप्रकार पूँजीपतियों को भी आरम्भमें हानि होगी।

एव प्रसिद्ध विद्वेषज्ञ मिस्टर वावी ने अभिनवीकरणके लाभ और हानियाँ इसप्रकार एकत्रित की हैं। पुनरुत्तिके दोषकी चिन्ता न करतेहुए उनका उल्लेख किया जा रहा है।

लाभ

(१) उत्पत्तिका कुशलतम मस्याप्रोमें समाहार।

(२) वस्तुनिर्माण का विकेन्द्रीकरण।

(३) वस्तुनिर्माण का माननियन।

(४) युन्नाका नवीकरण।

(५) शक्तिका मित्रव्यय।

(६) प्रबन्ध विषयक व्ययकी कमी।

(७) अन्यधिक मात्रामें उत्पत्तिका अभाव।

(८) बिक्रीका समाहार।

(९) निरर्थक भाडा इत्यादिकी बचत।

(१०) पूँजी-उपलब्धिका सीक्य।

(११) अधिक अनुसन्धान।

(१२) अधिक मात्रामें वस्तुका क्रय।

(१३) पूर्ति और मागका समन्वय इत्यादि।

हानियाँ :

(१) अकुशल मस्याओंका अधिक भूत्यपर क्रय।

(२) अतिरिक्त उत्पादन शक्तिका नाश।

(३) अधिक मात्रामें उत्पत्ति करनेके कारण भूल में हानिवाली हानि।

(४) आरम्भिक व्ययकी अधिकता।

(५) सगठनकी कठिन समस्याएँ।

(६) योग्य प्रबन्धका अभाव।

(७) मरकारी हस्तक्षेपकी सम्भावना।

(८) बेकारीमें वृद्धि।

- (६) पूजा प्रभत्व ।
- (१०) अर्थसम्बन्धी छल-कपट ।
- (११) एकाधिकारोकी स्थापना ।
- (१२) आश्रित अभिनवीकरणके दोष ।
- (१३) अव्यवितगत नियन्त्रण इत्यादि ।

वैज्ञानिक प्रवन्ध का अर्थ तथा उद्देश्य -

उन्नीसवीं शताब्दीमें व्यवस्थापक उत्पादन-व्ययमें कमी करनेकी इच्छासे उद्योग-शालाओकी इमारतों, यन्त्रों इत्यादिपर होनेवाले व्ययकी ओरही वैदल ध्यान देते थे । परन्तु वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें ही श्रमजीवीके कौशलमें वृद्धि करके उत्पादन-व्यय कम करनेकी चेष्टा कीजाने लगी । श्रमजीवीकी उत्पादनशक्ति में वृद्धिकरके उत्पादन-व्यय को कम करनेवाली पद्धतिको वैज्ञानिक प्रवन्धका नाम दिया जाता है । टेलरके मतानुसार श्रमजीवीकी क्षमता बढ़ानेके लिए निम्नलिखित प्रयत्नोक्त किया जाता आवश्यक है

- (१) प्रत्येक कार्यका करनेके लिए वैज्ञानिक ढंगोका निकालना ।
- (२) प्रत्येक श्रमजीवीकी योग्यताके अनुसार उसे उपयुक्त कार्यमें लगाना ।
- (३) श्रमजीवियोंका उत्पादन कार्य में पूर्ण सहयोग प्राप्त करना ।

वैज्ञानिक प्रवन्धका सबसे महत्वपूर्ण अंग कार्यक्रम की पहिले से ही निर्धारित कर देना है । इस कार्यको चलानेके लिए एक पृथक विभाग स्थापित करनेकी आवश्यकता है । प्रतिदिन श्रमजीवीको उसके द्वारा किये जानेवाले काम तथा उस कामको करनेके लिए उपयुक्त विधि तथा लगनवाले समयका काम आरम्भ होनेसे पहिलेही गता लगजाना चाहिए । कार्यक्रमतामें वृद्धिकी दृष्टिसे सर्वप्रथम श्रमजीवीके स्वास्थ्यकी ओर ध्यान देना चाहिए । अकालके कारण मालूम करके उन्हें दूर धरने का प्रयत्न करना आवश्यक है । अकाल अधिक श्रम करनेके कारण कार्यक्षमता में अवलतिके रूपमें प्रकट होती है । इसके कारण उत्पत्तिवी भाग्यमें न्यूनताही नहीं आती बल्कि दुर्घटनाओं के होनेकी सम्भावनाभी बढ़ जाती है । अकाल अधिक समय तक अविरत श्रमके कारण तथा विधामके अभावके कारण होती है । इसके

अतिरिक्त श्रमजीवीकी शारीरिक अवस्था तथा उसके खानपान से इसका धनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए श्रमजीवीके विश्रामके लिए समय समय पर प्रबन्ध कर देना चाहिए। उद्योगशालामें वातावरणको आरोग्यविज्ञान के नियमोंके अनुसार शुद्ध एवं पवित्र बनानेका प्रयत्न करना चाहिए ताकि श्रमजीवी स्वस्थ रहें और उनके शारीरिक बलमें वृद्धि हो। कार्यकी नीरसताको भी दूर करनेकी आवश्यकता है। सभ्य समय पर श्रमजीवीके कार्यमें परिवर्तन कर देना चाहिए। कार्य करनेके समयमें कमी कर देनी चाहिए। किसीभी कार्यको करनेके लिए श्रमजीवीका चुनाव उसके शारीरिक तथा मानसिक बलके आधारपर करना चाहिए। कुछ लोगोंको एकरूपता और पुनरावृत्ति प्रिय होतीहै और कुछको नहीं। इसकारण कुछतो नीरसतासे पीड़ित होते हैं और कुछ उमीमें आनन्दका आस्वादन करते हैं।

उद्योगशालाके वातावरणके माननयनके पश्चात् वस्तु-निर्माण विधिका माननयन आवश्यक है। वस्तुका माननयनभी अधिक मात्रामें कम उत्पादन-व्ययसे उत्पत्ति करनेके लिए आवश्यक सा ही समझा जाताहै परन्तु यह कार्य वैज्ञानिक प्रबन्धसे सम्बन्धित नहीं। वैज्ञानिक प्रबन्धका क्षेत्र वस्तु-निर्माण-विधिके माननयन तकही सीमित समझा जाता है। वस्तु-निर्माण-विधिके माननयनमें उस विधि में प्रयोग किये जानेवाले यन्त्रों, उपकरणों इत्यादिका माननयनभी सम्मिलित है। माननयन गत्याध्ययन तथा समयाध्ययन द्वारा किया जाता है। गत्याध्ययनमें श्रमजीवीकी गतियोंको सरल बनानेका प्रयत्न किया जाता है। उसके उठन बैठनेके ढंग में परिवर्तन किये जाते हैं। सामग्री रखनेके स्थानोंको ऊँचा नीचा किया जाता है। इस सम्बन्धमें टेलरका फावडोपर और गिन्वर्यका ईटोपर अध्ययन प्रसिद्ध है। टेलर ने फावडकी महायत्नासे अधिकतम कौशल द्वारा अधिकतम बोझ उठानेकी मात्रा निश्चितकी थी और फिर भिन्न भिन्न प्रकारकी सामग्री उठानेके लिए फावडाके आकारको निर्धारित किया था। इसीप्रकार गिन्वर्यन ईंटें लगानेवालों को ईंटें पहचान उनके रखने तथा लगानकी विधिमें परिवर्तन प्रस्तुत किये थे। परिणाम यह हुआ कि टेलरके परिवर्तनाके कारण प्रत्येक श्रमजीवीकी बोझ उठानेकी दैनिक शक्तिमें ४३ टनकी वृद्धि हुई अर्थात् वह अब १६ टन के स्थानपर ५९ टन बोझ दिन भरमें उठाने लगा। इसीप्रकार गिन्वर्यके परिवर्तनोंके अनन्तर प्रत्येक कार्यकर्ता ६५० ईंटें प्रतिघटा लगाने लगा जबकि वह पहिले केवल १२० ईंटें प्रतिघटा लगा

पाता था। कहा जाता है कि गिल्बर्थने एक समय एक लड़की को गोल डिब्बोपर बागुज चिपकाते देखा। वह शीघ्रतम कार्य करनेवाली लड़की बतायी जाती थी और ४० सैंकिण्डोमें २४ डिब्बे तैयार कर लेती थी। गिल्बर्थ ने उस लड़कीके सामग्री रखनेके स्थान और लड़की की कार्यशैलीमें कुछ परिवर्तन सूचित करनेका साहस किया और इन परिवर्तनोंके कारण वही लड़की २० सैंकिण्डो में २४ डिब्बे पहिलेके समान श्रमसे ही तैयार करनेमें सफल हुई।

इसप्रकार गत्याध्ययन करके किसी कार्यको करनेके लिए एक प्रामाणिक विधि निश्चित करली जाती है और तदनन्तर इस विधिके प्रत्येक अंगको कमसे कम समय में पूरा करनेके लिए समयका अध्ययन विधा जाता है। प्रत्येक कार्यको कमसे कम समयमें करनेके समयको एकत्रित करके कुल कार्यको करनेके लिए कमसे कम समय निकाल लिया जाता है।

कार्य-कौशलमें वृद्धिके लिए श्रमजीवीको भजूनी देने के ढंगोंमें इसप्रकार के परिवर्तन करना कि श्रमजीवीको नन मनमें कार्य करने में तत्पर होनेके लिए प्रोत्साहन मिले वैज्ञानिक प्रबन्धकी दृष्टिसे आवश्यक समझा जाता है। इन विविध ढंगोंका विवरण भजूनीके अध्यायमें किया जायगा।

वैज्ञानिक प्रबन्ध के दोष

- १. हममें सन्देह नहीं कि कार्य करनेकी विधिको उत्तम बनानेसे कार्य करना सुगम हो जाता है और उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि की जा सकती है। परन्तु समयाध्ययन और गत्याध्ययन द्वारा श्रमजीवीको श्रमके रूपमें ही परिणत कर दिया जाता है। इसकारण वस्तुनिर्माण में उसके व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यको पूर्णतया नष्ट कर दिया जाता है। हम देख चुके हैं कि उत्पादन-विधिके माननयनके लिए वस्तुका माननयन भी आवश्यक है। बहुतसे लोगोंका विचार है कि यद्यपि इस माननयन द्वारा वस्तुकी उत्पत्तिकी मात्रा में वृद्धि की जा सकती है परन्तु उसके गुणोंमें अवनति हो जाती है। वैज्ञानिक प्रबन्ध के प्रतिपादकोंकी धारणा है कि इन आलोचनाओंमें कुछ सत्य बसेली हो परन्तु व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यका नाश किये बिनाभी वैज्ञानिक प्रबन्ध सम्भव है और यह अवश्य करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा श्रम और शक्ति के व्यय में बचत और श्रम-

जीवीके कौशल एवं उपाजन शक्तिमें वृद्धि होसकती है। इसीप्रकार बहुतसे लोगो के मतानुसार वस्तुकी मात्रामें माननयन द्वारा वृद्धिकरके भी उसके गुणोंमें वृद्धि करना सम्भव है। कार्यकौशलमें अत्यधिक वृद्धि होनेसे बेकारी फैल सकती है। इस प्रकार श्रमजीवी वैज्ञानिक प्रबन्धको श्रमकी दृष्टिसे देखते हैं। परन्तु उत्पादन-व्ययमें कमी होनेसे वस्तुके मूल्यमें कमी होजाती और फलस्वरूप कालान्तरमें माग में वृद्धि होनेसे बेकारी फैलनेकी सम्भावना नहीं रहती।

वैज्ञानिक प्रबन्धके कारण श्रमके विनिष्टीकरणसे श्रमजीवियोंकी पराधीनता औरभी अधिक होजातीहै और इसकारण उत्पादक उत्पत्तिका अधिकतर भाग स्वयं लाभके रूपमें ले सकते हैं। इसके विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबन्धकोका कहनाहै कि मजूरीमें अन्याययुक्त कमी न होनेदेना उनके कार्यक्रमका एक अंग है। इसके अतिरिक्त सामूहिक भौदा करनेकी शक्तिका श्रमिक सघोंके संगठनों द्वारा पैदा करना वैज्ञानिक प्रबन्धके प्रतिकूल नहीं। वैज्ञानिक प्रबन्धके केवल श्रमजीवियों और व्यवस्थापकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करनेके इच्छुक हैं।

श्रमजीवीको एक नहीं बहुतमे निरीक्षकोंके आधीन होकर कार्य करना पड़ता है। वैज्ञानिक प्रबन्धके अनुसार निरीक्षकोंमें किसी विशेष योग्यताका होना आवश्यक है। इसकारण श्रमजीवी प्रत्येक निरीक्षकको शिक्षक समझकर उससे अपने कार्यके विविध अंगोंके सम्बन्धमें शिक्षा प्राप्त करसकता है। वैज्ञानिक प्रबन्धका उद्देश्य उत्तम वस्तु उत्तम विधिसे अधिकतम मात्रामें पैदा करना है और अकुशलता को राष्ट्रीय अपराध समझ लेनेपर वैज्ञानिक प्रबन्धको प्रचलित करना ही प्रत्येक उत्पादकका परम कर्तव्य है।

आर्थिक पद्धतियाँ

पूजीवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद

पूजीवाद का अर्थ

पूजीवादका उद्भव सामन्तवादके विरुद्ध प्रतिक्रियाके रूपमें हुआ था। पंद्रहवीं शताब्दी ईसवी में रोमका हाब्सबर्ग अष्ट होनेके कारण योरोपकी व्यापारिक तथा राजनैतिक एकता भंग होचुकी थी। केन्द्रीय शासनका अभाव था और समाजका संगठन सामन्तिक ढंगसे होचुका था। प्रत्येक व्यक्तिका समाजमें स्थान निश्चित था। शिक्षार्थीके द्वारा शिक्षककी, कमियेके द्वारा ग्रामाधीश की, ग्रामाधीशके द्वारा - प्रान्ताधीश की और प्रान्ताधीशके द्वारा राजाकी कीजानेवाली सेवाओं और उनके स्थानपर मिलनेवाले पुरस्कार उनमेंसे प्रत्येकको भलीप्रकार से विदित होतेथे और उनमें परिवर्तन असम्भव था। उत्पादन प्रायः तात्कालिक उपभोग अथवा वस्तु विनिमयके लिएही कियाजाता था। वस्तुका निर्माण और व्यापार प्रायः शिल्प मस्थाके हाथमें था, जिनके स्वामियोंका श्रम-पूर्ति, कच्चे-मालका प्रयोग और वस्तुओं के मूल्य निश्चिन करनेके पूर्णाधिकार प्राप्त थे। यातायातका सुप्रबन्ध न होनेके कारण तथा चोर डाकूओंके भयसे व्यापार अधिकन होपाता था। तेरहवीं-पंद्रहवीं ईसवी के लगभग व्यापारके पुनरुज्जीवन में सामन्तवादको भारी धक्का लगा। व्यापार का पुनरुत्थान होनेके साथ साथ व्यापारियों और अध्याध्यक्षोंका प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने सामन्त कुलीन तन्त्र और सामन्त प्रणाली द्वारा वस्तु निर्माण तथा वस्तु-व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धोंका विरोध करनेके लिए एक नये वाद की नींव डाली और इस वादको उदारवादके नामसे पुकारा गया। इस वादके अनुसार समाजका कल्याण व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामें ही निहित है। आर्थिक क्षेत्रमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अर्थ जन-समुदायकी उत्पादन सम्बन्धी तथा व्यापारिक योजनाओंमें सरकारी हस्तक्षेपका अभाव था। क्योंकि आर्थिक सिद्धान्तोंके पूर्ण

रूपेण कार्यान्वित होनेपर अधिकतम उत्पत्ति और न्याययुक्त वितरणका होना प्राकृतिक समझा जाता था। ऐसा विश्वास किया जाना था कि उद्योग स्वातन्त्र्यके प्राप्त होनेपर प्रत्येक व्यक्तिको अपने भौतिक कल्याणके लिए अधिकतम प्रयत्न करनेका प्रोत्साहन मिलेगा और पूर्ण प्रतिस्पर्धाले भाग्य और पूर्तिकी शक्तियों द्वारा उत्पत्ति और मूल्य निश्चित होंगे। आधुनिक पूँजीवाद उदारवादके इन्हीं सिद्धान्तों पर अवलम्बित है। पूँजीवाद वह आर्थिक प्रणाली है जिसके अनुसार उद्योगी पूर्ण प्रतिस्पर्धाले स्थितिमें अधिकतम लाभ कमानेके लिए बिना रोक टोक अग्रसर हो सकता है।

पूँजीवाद के लक्षण

पूँजीवादियोंका विश्वास है कि व्यक्तिगत कल्याणमें ही सामाजिक कल्याण निहित है। इनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्तिको प्रकृतिकी ओर से कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिनका प्रयोग करनेके लिए उसका पूर्णतया स्वतन्त्र होना आवश्यक है। इन अधिकारोंमें मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) निजी सम्पत्तिपर स्वामित्वाधिकार—निजी सम्पत्ति दो प्रकारकी हो सकती है। एक तो उपभोग्य वस्तुओंकी और दूसरी उत्पादक वस्तुओंकी। उत्पादक वस्तुओंको अर्थशास्त्रीय परिभाषामें उत्पादनके साधनोंके नामसे पुकारा जाता है। इन्हीं उत्पादनके साधनोंका स्वामित्व व्यक्तिगत रूपमें लोगोंको प्राप्त होना पूँजीवादके अनुसार आवश्यक है। उपभोग्य वस्तुओंमें स्वामित्वाधिकार तो समाजवादके अनुसार ही व्यक्तिगत रूपमें ही जन-समुदायको प्राप्त होंगे परन्तु उत्पादनके साधनों पर प्रभुत्व पूरा समाजका होगा।

(२) उद्योग-स्वातन्त्र्य—उद्योगी लोग अपनी निजी सम्पत्ति का प्रयोग किसीभी धर्ममें लाभ कमानेकी इच्छामें करते हैं। इस प्रकार के प्रयोगसे हानि होनेकी सम्भावनाका भयभी उन्हें ही उठाना पड़ता है। अपना उत्पादन-कार्य चलानेके लिए उन्हें न्यून अथवा अधिक मागमें उत्पत्ति करनेकी और अपनी वस्तुओंके मूल्य निश्चित करनेकी पूरी स्वतन्त्रता होनी है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह विरोधी हो अथवा ग्राहक, व्यवस्थापक या अथवा श्रमजीवी अपने आपको किसीभी

प्रकारके समनुबन्धमें बद्ध करनेके लिए कोईभी नहीं रोक सकता जबतक कि वह समनुबन्ध प्रचलित विधानके विरुद्ध न हो।

(३) लाभ प्राप्ति का उद्देश्य—केवल निर्वाह मानके लिए पर्याप्त मात्रासे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी इच्छा पूजोपादके अनुसार मनुष्यमें स्वाभाविक रूपसे वर्तमान है, सम्पत्ति प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पादनके लिए श्रेष्ठतम प्रोत्साहन है। लाभ प्राप्त करनेके लिए उत्पादक अधिकतम प्रयत्न करेगा और अत्यन्त सावधानीसे काम लेकर अपने उद्यमको सफल बनानेकी चेष्टा करेगा।

(४) पूर्ण प्रतिस्पर्धा द्वारा स्वतन्त्र बाजारमें मृत्यु, लाभ और उत्पादन-व्यय स्थिरता प्राप्त करने हैं—व्यवस्थापकोमें परस्पर प्रतिस्पर्धा द्वारा मूल्य कम होते हैं परन्तु उपभोक्ताओंमें परस्पर प्रतिस्पर्धा द्वारा मूल्य बढ़ते हैं। इसीप्रकार श्रमजीवियों में परस्पर प्रतिस्पर्धाके कारण मजूरी घटती है और पूजीपतियोंमें परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण मजूरी बढ़ती है। परन्तु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति तभी प्राप्त होसकती है जबकि पूजी और श्रम गणितीय हो, सब लोगोंमें मोक्ष करनेकी शक्ति सम हो और एकाधिकार का अभाव हो।

(५) मजूरी भुगतान प्रणाली—पूजीपति उद्यम की जोखिम उठाने हैं और इस कारण अपने आपको प्राप्त लाभका अधिकारी मानते हैं। वे श्रमको केवल उत्पादित व्ययका एक अंग मानते हैं और इसकारण इस व्ययको न्यूनतम रखनेकी इच्छासे श्रमजीवी को कमसे कम मजूरी देना चाहते हैं। परन्तु श्रमजीवी अपने जीवन-स्तर को उत्कृष्ट करनेके लिए अधिकतम मजूरी लेनेका इच्छुक रहता है। इसकारण श्रमजीवियों और पूजीपतियोंमें एक विरोध सा खड़ा होना है।

(६) विनिमय विधि—विनिमयके लिए वस्तुओंके मूल्य द्रव्यके रूपमें परिणत करदिये जाते हैं। धातु मुद्राओंके अनिवार्य सरकारी अथवा बैंकोंके मोटो और हुशियों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। बैंक साख-मृजन द्वारा उद्योग धन्वोंका अपेक्षा अर्थवाहन करते हैं।

(७) अभिनवीकरण तथा वैज्ञानिक प्रवन्ध—पूजीपति अपने मुख्य उद्देश्यकी उपलब्धि के लिए उत्पत्तिकी मात्रा बढ़ाने और उत्पादन-व्यय कम करनेमें निरन्तर तत्पर रहते हैं। वैज्ञानिक प्रवन्धके नियमों द्वारा संस्थाओंका प्रवन्ध, उत्पादन विधिका अभिनवीकरण, नच्चे मालका अधिक मात्रा में और फलतः सस्ते मूल्य पर

त्रय और वस्तु विक्रयके लिए नये नये बाजारोंकी खोज इत्यादि उनके उद्देश्योंके साक्षात्कारमें सहायता देते हैं।

पूजीवाद का विकास

पूजीवादका भी अन्य वादोंकी तरह क्रमशः विकास हुआ है, यह हम देख ही चुके हैं कि पूजीवादका श्रीगणेश करनेवाले योरोपके व्यापारी थे। अठारहवीं शताब्दी ईसवीके मध्यसे लेकर बड़ी बड़ी कर्मशालाओंकी स्थापना प्रारम्भ हुई। नये नये यन्त्र निकाले गये। बड़े परिमाणमें उत्पत्ति कीजाने लगी। यातायातके साधनोंमें आश्चर्यजनक उन्नति हुई। बाजारोंके प्रसारमें इतनी वृद्धि हुई कि वह ससारव्यापी हो गये। यह काल औद्योगिक पूजीवादका था। गत महायुद्धके कालसे अभिनवीकरण और वैज्ञानिक प्रबन्धके सिद्धान्तोंके प्रयोग द्वारा उत्पत्तिकी मात्रामें गगनचुम्बी वृद्धि हुई परन्तु इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा और बाजारोंकी स्वतन्त्रतामें न्यूनता आने लगी। छोटी-छोटी सस्थाओंको मिलाकर बृहत् सस्थाओंका संगठन होने लगा और इन सस्थाओंका अर्थवाहन करनेवाली सस्थाओंको विशेष महत्त्व प्राप्त होने लगा। इसकारण हम युगको अर्थवाहन पूजीवादका युग कहते हैं। अब इस युगकी प्रवृत्ति सरकारी पूजीवादकी ओर है। व्यापारिक अपकर्षों की रोकथाम, युद्धकालमें राष्ट्रीय उत्पत्तिका नियन्त्रण श्रमजीवी सघोंके बढतहुए प्रभावके कारण सरकार का मूल्य, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा इत्यादिके विषयमें उत्तरदायित्व स्वीकार करना, सरकारद्वारा ऐसे उद्योग धन्धोंकी स्थापना जिनका निजी उद्यम द्वारा स्थापित होना असम्भव है, उपभोक्ताओंके हितका बड़े बड़े एकाधिकारों में संरक्षण इत्यादि इस प्रवृत्तिके मुख्य कारण हैं। सरकारी पूजीवादमें सरकार यातायातके साधनों, बैंक, मुख्य मुख्य प्राकृतिक सामग्रियां इत्यादिमें स्वामित्वके अधिकार ग्रहण कर लेती है। कई एक वस्तुओंके उत्पादनमें विशेषकर मादक वस्तुओं और युद्ध सामग्रियोंमें सरकार को एकाधिकार प्राप्त हो जाता है और अन्य उत्पादनके क्षेत्रोंमें सरकार भी अपनी राजस्व नीति द्वारा हस्तक्षेप करती रहती है। सरकारी पूजीवाद और सरकारी समाजवाद का प्रायः एकही अर्थमें प्रयोग किया जाता है। कई लेखक सरकारी समाजवादको यह विशेषता बतलाते हैं कि सरकारी समाजवादमें उद्योग धन्धोंका

राष्ट्रीकरणही मुख्य तथा अन्तिम उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्यकी उपलब्धि के लिए आरम्भमें मौलिक उद्योग धन्धोंमें स्वामित्व तथा नियन्त्रण के अधिकार सरकार ग्रहण करलेती है।

मार्क्सवाद

मार्क्सवादका मुख्य उद्देश्य पूँजीवादी उत्पादन पद्धतिकी बड़ी आलोचना करना, पूँजी-पतियों द्वारा श्रमजीवियोंके शोषण और इस पद्धतिका अन्तर्निहित कारणों द्वारा नाश सिद्ध करना है। मार्क्सके अनुसार सम्पत्ति-सृजन पद्धतिमें नये आविष्कारों द्वारा हरसमय परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनोंके कारण सामाजिक सम्बन्धोंमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। इस उत्पादन कार्यमें भाग लेनेवाले लोग भिन्न भिन्न वर्गोंमें विभाजित होजाते हैं। प्राचीनकालमें स्वामियों तथा सेवकों और आधुनिक कालमें पूँजीपतियों और श्रमजीवियोंके पृथक् पृथक् वर्ग देखनेमें आते हैं। वर्गोंके प्रत्येक सदस्यके हितोंमें एकता इस वर्गीकरणकी जड़ है। प्रत्येक वर्ग उपपन्न आयका अधिकतम अंश प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है और इसकारणसे ही बलवान तथा दीन वर्गोंमें संघर्ष होता है जिसमें दीन वर्ग बलवान वर्गकी शक्ति और सम्पत्ति को नष्ट करनेकी ताकतमें रहता है। समाजका इतिहास इसप्रकार के संघर्षोंमें परिपूर्ण है। पूँजीवादके प्रभुत्वकालमें उत्पादनके साधनोंका स्वामित्व तो थोड़ेसे पूँजीपतियोंको प्राप्त होता है और सर्वसाधारण समाजका अधिकांश श्रमजीवियोंके रूप में अपना श्रम बेचकर जीविका पाता रहता है। श्रमजीवी वर्गका पूँजीपतियों द्वारा शोषण सिद्ध करनेके लिए मार्क्सने अतिरिक्त मूल्यके सिद्धान्तकी रचना की। मूल्यके श्रम-सिद्धान्तके अनुसार किसी वस्तुका मूल्य उसे उत्पन्न करनेके लिए आवश्यक श्रम से निर्धारित होता है। पूँजीपति श्रमजीवियोंको केवल निर्वाह-मात्रके लिए मजूरी देकर उनसे इतना श्रम करवाते हैं कि उसके द्वारा उत्पन्न वस्तुओंका बाजार मूल्य उनकी मजूरीसे अधिक होता है। इन अतिरिक्त मूल्यको पूँजीपति हड़प करलेते हैं। परन्तु इसप्रकार अनुचित आय का वे लोग प्रायः उपभोग नहीं करपाते हैं। श्रमजीवियोंके हाथमें ऋण-शक्तिकी न्यूनताके कारण अत्यधिक उत्पत्तिका सकट विद्यमान होनेलगता है। आरम्भमें तो नये बाजारोंकी उत्पत्ति, भोवबिलासकी वस्तुओंका

उत्पादन और उधारपर वस्तुओंकी बिक्री इत्यादि ढंगोंसे इस सकटको स्थगित करने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु अन्तमें श्रमजीवियोंके स्थानपर यन्त्रोंके प्रयोग, एकाधिकारोंकी स्थापना और विदेशी बाजारोंकी खोजके कारण न केवल पूँजीपति शक्तियोंमें मूढ़ छिड़ जाता है वरन् मुट्ठीभर पूँजीपतियों और अगणित श्रमजीवियों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मार्क्सका विश्वास था कि इस संघर्षमें अन्ततोगत्वा विजय श्रमजीवियोंकी ही प्राप्त होगी है। पूँजीपतियोंकी पराजय होनेपर उत्पादन के साधनोंका स्वामित्व समाजको प्राप्त हो जाता है और उत्पादन, लाभ प्राप्ति के लिए नहीं परन्तु लोकहितके लिए किया जाता है।

मार्क्सवाद की शाखाएँ

मार्क्सवाद जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का भी नाम दिया जाता है, कई शाखाओंमें विभाजित है। उनमें से दो मुख्य शाखाएँ विकासवादी समाजवाद और धार्मिककारी समाजवादके नामोंसे प्रसिद्ध हैं।

समाजवाद

विकासवादी समाजवादी वर्गोंमें संपत्तिके अस्तित्वको तो स्वीकार करते हैं परन्तु इसे विशेष महत्व प्रदान नहीं करते। मार्क्सवादियोंके समान ये लोग भी श्रमको ही मूल्य-मूल्यका चरम कारण स्वीकार करते हैं और भूमि-पर ध्याज और लाभमें सृष्ट मूल्यका विभाजन न्याययुक्त नहीं मानते। लाभप्राप्तिके उद्देश्यसे उत्पादन इन लोगों की दृष्टिमें सर्वथा त्याग्य है क्योंकि उत्पादक लोग प्रायः छोड़ी मात्रा में उत्पत्ति करके अधिक मूल्यपर बेचते हैं नकि अधिक मात्रा में उत्पत्ति करके कम मूल्य पर। इसका समर्थन समाजवादी पर्याप्त भूमि, श्रम इत्यादिके होते हुए भी उपभोग के लिए अपर्याप्त मात्रा की उपलब्धि और मूल्य उच्च रखने के लिए वस्तुओंको जान-बूझकर क्रियेय नाशके उदाहरणों द्वारा करते हैं। इनके मतानुसार तो उत्पादन विधिको उन्नत करनेवाले ऐसे आविष्कार जिनके कारण सामंती मात्रा में कमी होने की सम्भावना हो, प्रचलित होनेसे पीछे ही रोकी लिये जाते हैं। समाजवादी प्रोतस्पघी

में भी विश्वास नहीं रखते। उनका विचार है कि प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन तथा वितरण में भारी अपव्यय होता है जिसके कारण प्रतिस्पर्धा केवल अनावश्यक ही नहीं किन्तु स्पष्टतया हानिकारक है। इसके अतिरिक्त एकाधिकारों के प्रभुत्व ने प्रतिस्पर्धा के रहे सहे कार्य को तो वैसे भी भट्ट भट्ट कर दिया है। वादावर एकाधिकारियों को पूर्णरूप से नियन्त्रण होने से मूल्यों का प्रति और माग द्वारा निर्धारित होना अब स्वप्न सा ही प्रतीत होता है। उद्योग धन्धों के बान्धविक स्वामी अब उद्योगपति नहीं किन्तु मर्त्य बहन करने वाली बड़ी बड़ी मस्याएँ हैं और स्वतन्त्र उद्यम केवल घोषवाक्य मात्र रह गया है। इस कारण शर्न, शर्न, उत्पादन कार्य सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। राष्ट्रीय उत्पादन समझौते और मुख्य मुख्य उद्योग धन्धों का स्वामित्व प्राप्त कर लेना चाहिए। विशेष कर यातायात के साधनों, युद्ध-सामग्री, वैको, प्राकृतिक सामग्री तथा उत्पादक वस्तुओं का संचालन मस्या उत्पादन-कार्य सम्हालना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। छोटे परिमाण में उत्पत्ति तथा कृषि इत्यादि का प्रबन्ध भी महयोग समितियों द्वारा होना आवश्यक समझा जाता है। इन लोगों का विश्वास स्वामित्व और संचालन कार्य के सर्वथा केन्द्रीकरण में नहीं परन्तु उसके स्थानीय, प्रांतीय और केन्द्रीय सार्वजनिक मस्याओं में विभाजित करने में है। इन सब के कार्य को परस्पर सम्बन्धित करने के लिए राष्ट्रीय योजना समितिकी स्थापना आवश्यक है। यह समिति उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों की आवश्यकताओं का अनुमान करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विभिन्न मात्रा में उत्पादन करने का निश्चय करेगी। उत्पादक मस्याओं के पारस्परिक महयोग तथा व्यापक वितरण द्वारा समाजवादी व्यापारिक अपकर्षों तथा उत्पत्तियों का अन्त करके उनके कारण होने वाले सकटों से समाज की रक्षा करने की आशा बाधते हैं। उत्पात्तिकी वृद्धि करना समाजवादियों की पूजादियों ने भी अधिक प्रिय है।

साम्यवाद

क्रान्तिकारी जिन्हें प्रायः साम्यवादी भी कहते हैं और विकासवादी समाजवादियों के आर्थिक सिद्धान्तों में तो विशेष अन्तर भी नहीं परन्तु साम्यवादी अनुक्रमिक समाज सुधार में विश्वास नहीं रखते। वे हिंसक क्रान्ति द्वारा पूँजीपतियों से शक्ति तथा

सम्पत्ति छीन लेनेके पक्षपाती है। साम्यवादी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्व देना इतना आवश्यक नहीं समझते जितना कि समाजवादी। राजनैतिक दृष्टिमें समाजवादी लोकतन्त्रवादके और साम्यवादी अधिनायकवादके समर्थक हैं।

आर्थिक उन्नति और पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम

आर्थिक उन्नतिको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमके अनुसार प्राप्त करनेकी चेष्टा करनेवाली आर्थिक पद्धतिको प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्सने अपनी पुस्तक 'बड़ा अपकर्ष' में समाजवादका ही रूपान्तर माना है। हम देखचुके हैं कि समाजवादी इस पद्धतिके प्रतिपक्षी हैं परन्तु दोनोंको एक मानना बड़ी भूल है। समाजके आर्थिक जीवनके नियन्त्रणमें विश्वास पुरातनकालसे चलाआता है। पुराने नीतिशास्त्रोंमें तत्कालीन समाजके आर्थिक जीवनका जो विवरण मिलताहै, उसके आधारपर यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उस समयभी जीवन नियमबद्ध था। इसीप्रकार समय समय पर बुद्धिमान लोगोंने वास्तविक समाजोंमें नियन्त्रणके अभावके दोषोंको सुधारनेके लिए नियन्त्रित काल्पनिक समाजोंका निर्माण कियाहै। आधुनिक राष्ट्रों में संरक्षण नीतिके अनुकरणकी प्रथा आर्थिक जीवनका नियन्त्रण नहीं तो और क्या है? अर्वाचीन कालमें पूण प्रतिस्पर्धा और यदभाव्य नीतिके विरुद्ध प्रतिक्रियाके रूपमें नियन्त्रण नीतिका पुनर्जन्म हुआ है। मनुष्य जीवनको सुखी बनानेके लिए उसके भौतिक आधारका विज्ञानकी सहायतासे विस्तृत करना आवश्यक है और उत्पत्तिकी मात्राको अधिकतम करना, आर्थिक पद्धतिको स्थिर बनाना तथा राष्ट्रीय आयके न्याययुक्त वितरण द्वारा आयमें साम्याभावका दूरकरना इस विस्तारको प्राप्त करनेके साधन हैं; परन्तु इन साधनोंका प्रयोग उसी अवस्थामें सम्भव है जब जनसमुदायक आर्थिक जीवनका नियन्त्रण करके निर्धारित कार्यक्रमके अनुसार उसे उन्नत करनेका प्रयत्न किया जाय। इस कार्यक्रमके अनुसार राष्ट्रकी प्रथम समस्या, उद्यम अथवा उद्योग धन्धको जन समुदायकी आवश्यकताओंकी अधिकतम सृष्टिके लाभार्थ उपलब्ध सामग्री द्वारा अधिकतम उत्पादन करनेवाली पूर्ण पद्धतिको केवल सहयोगी अंगमात्र मानाजाता है। उत्पादन और उपभोग का सन्तुलन स्थापित कियाजाता है। भिन्न भिन्न समस्याओंके कार्यक्रमको परस्पर समन्वित करनेके लिए तथा

आवश्यक सन्तुलन स्थापित करनेके लिए एक केन्द्रीय संस्थाका होना आवश्यक है। संक्षेपमें कुशल उत्पादन स्थिर आर्थिक जीवन और व्याप्युक्त वितरण इस कार्यक्रमके मुख्य उद्देश्य है।

कुशल उत्पादन करनेके लिए उपयुक्त उद्योग धन्धोंका चुनाव, उनका उपयुक्त स्थानीकरण, अच्छे माल, श्रम, पूँजी इत्यादिकी आवश्यक पूर्ति इन साधनोंका कुशलतम संस्थाओंमें विभाजन और फिर इन संस्थाओंका मितव्ययिता की दृष्टिसे संगठन करना आवश्यक होना है। उद्योगधन्धोंके स्थानीकरणके सिद्धान्तोंका तथा अभिनवीकरण और वैज्ञानिक प्रबन्ध द्वारा संस्थाओंके संगठनका विवेचन इस पुस्तकके अन्य अध्यायोंमें मिलता है।

आर्थिक जीवनमें स्थिरता वस्तुओंके मूल्योंमें स्थिरता आनेसे उपलब्ध होसकती है। उसे प्राप्त करनेके साधनोंका विवेचन द्रव्यकी ऊर्ध्वशक्ति वाले अध्यायमें किया गया है। इस स्थानपरकेवल इनका उल्लेख करदेना पर्याप्त है कि वस्तुओंके मूल्यों में उतारचढ़ाव को न्यूनतम करना राष्ट्रोंकी द्रव्य-नीतिका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और इस कार्यमें तभी सफलता प्राप्त होसकती है जब इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो।

व्याप्युक्त वितरण

वितरणके व्याप्युक्त होनेसे हमारा अभिप्राय श्रमजीवियों को प्राप्त होनेवाले राष्ट्रीय आयके भागकी आनामें वृद्धि करनेसे है। यह वृद्धि एकतो श्रमजीवियों की उत्पादन शक्तिमें उचित शिक्षा द्वारा वृद्धि करके प्राप्त होसकती है। इसके अतिरिक्त नौकरीमें नैरन्तर्य देकर, श्रमजीवियोंके सामाजिक स्थान, मजदूरी तथा गतिशीलता में वृद्धि करके, कार्य करनेके समयको कम करके तथा कार्य-स्थानके वातावरणको उन्नत करके भी यह अवस्था प्राप्तकी जासकती है। नौकरीमें नैरन्तर्य अत्यन्त आवश्यक है। उत्पादन कार्यमें श्रमकी उत्तनीही आवश्यकता है जितनी अन्य साधनोंकी। इसकारण श्रमजीवियोंको भी समाजमें वही स्थान मिलना चाहिए जो अन्य साधनोंके स्वामियोंको मिलता है। इसके लिए श्रमजीवियों की सौदा करनेकी शक्तिमें श्रमिक मण्डल की स्थापना द्वारा वृद्धि करना आवश्यक है। इसके

अतिरिक्त उद्योग-धन्धोंके संचालन कार्यमें श्रमजीवियों का भी हाथ होना चाहिए। उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होनेके साथ साथ श्रमजीवीकी मजदूरीमें वृद्धि होनी चाहिए। यन्त्रोंके अधिकाधिक उपयोगके कारण श्रम करनेके स्थानका वातावरण उन्नत अवश्य हुआ है परन्तु श्रमके कारण होनेवाली थकावटमें वृद्धि हुई है। उत्पादन विधिमें उन्नति होनेके कारण श्रम करनेके घंटोंको उत्पत्तिकी मात्रामें कमी किये बिनाही कमकिया जासकता है। श्रमकी गतिशीलता बढ़ानेके उद्देश्यसे न केवल एक स्थानमें दूसरे स्थानपर जानके लिए बरन् एक व्यवसायसे दूसरे व्यवसायको अपनानेके लिए सुगमता प्राप्त होनी चाहिए।

उत्पादन विधिमें परिवर्तनोंके कारण माग और पूर्तिका पूर्ण समन्वय न होनेसे थोड़ी बहुत बेकारीका किसीभी समाजमें रहना अनिवार्य है। यदि समाज किसी व्यक्तिको श्रम करनेका अवसर देकर आजीविका कमानेके योग्य नहीं बनाता तो समाजका यह प्रयत्न व्यर्थ है कि उस व्यक्ति को निर्वाह मात्रके लिए जीवन सामग्री दे। इसके लिए बेकारी बीमा करवाना आवश्यक है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस कार्यश्रमको व्यावहारिक रूपमें परिणत करने और इसकी मफलताके लिए उचित वातावरण उत्पन्न करनेका उत्तरदायित्व किसे सौंपना चाहिए। सरकारको समाजके प्रतिनिधिके रूपमें इस कार्यको अपने हाथमें ले लेना चाहिए। सरकार इस उत्तरदायित्वका विकेन्द्रीकरण स्थानीय और प्रान्तीय संस्थाओंके सृजन द्वारा करसकती है। केन्द्रीय संस्था योजनाको तैयार करने, इसको कार्य रूपमें परिणत करनेका प्रबन्ध करने, स्थानीय तथा प्रान्तीय संस्थाओंके कार्यमें परस्पर सहयोग स्थापित करना इत्यादिका उत्तरदायित्व लेसकती है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय और स्थानीय संस्थाओंमें श्रमविभाजन समाजवादियोंके मतानुसार किसप्रकार होना चाहिए, इसका विवेचन पहिले होचुका है। व्यक्तिगत प्रयत्नमें विश्वास रखनेवाले अर्थशास्त्री पूँजीवादों संस्थाओंका सरकार द्वारा इसप्रकार नियन्त्रण करनेका मत प्रकट करते हैं कि वे स्वार्थसिद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा द्वारा अन्य संस्थाओंको हानि न पहुँचा सके किन्तु सहयोग द्वारा अपना तथा जनसाधारण का उपकार करनेके लिए त्विदम होजाये।

राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय का अर्थ

किसी देशके निवासियोंके हितार्थ किसी निश्चित समयके भीतर उत्पन्न की गयी वस्तुओं तथा सेवाओंको उस देशकी राष्ट्रीय आयके नामसे पुकारा जाता है। मार्शलके राष्ट्रीय आयकी परिभाषा इसप्रकार की है। 'किसी देशमें प्राप्त श्रम तथा पूँजीद्वारा वर्षभर में उसकी प्राकृतिक सामग्रियोंके विविध प्रकारकी स्थूल तथा सूक्ष्म वस्तुएँ, जिनके अन्तर्गत विविध प्रकारकी सेवाएँ भी घानी हैं, उत्पन्न की जाती हैं। इन उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओंकी मात्रा का नामही उस देशकी राष्ट्रीय आय है। आयको प्रायः द्रव्यके रूपमें परिणित करके दिखानेकी प्रथा प्रचलित है। स्मरण रहे कि उत्पादन सामग्रियोंके व्यवहारेमें आनेके कारण प्रतिवर्ष उसके मूल्यमें आ ह्रास हो जाता है उसको उस वर्षमें उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओंके कुल मूल्यमें निहालकर मध्य अवधि मूल्यको ही राष्ट्रीय आय माना जाता है।

ऐसाभी होमरना है कि एक देशके वासियोंने किसी अन्य देशमें भूमि, उत्पादन सम्पत्तियों अथवा अन्य उत्पादनके साधनोंपर स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो और इस कारण विदेशमें उत्पन्न की गयी वस्तुओं तथा सेवाओंपर उनका अधिकार हो। इस प्रकारकी उत्पत्ति का भी पहिले देशकी आयमें गणना करनेकी प्रथा है। इसीप्रकार पहिले देशमें उन साधनों द्वारा प्राप्त उत्पत्तिको जिनके स्वामी अन्य देशके वासी हों, उन देशकी राष्ट्रीय आयमें निहाल देना चाहिए।

इन सम्बन्धमें यह कह देना भी आवश्यक है कि पिछरे राष्ट्रीय आयकी मार्शल द्वारा दी गयी परिभाषामें मतभेद प्रकट जाता है। मार्शलके अनुसार तो एक ओर वर्षभर में उत्पन्न की गयी वस्तुओं और वृत्त सेवाओंकी सूची बना ली जाए और दूसरी ओर सद्योत्पन्न पूँजीमें होनेवाले ह्रासकी सूची। इन दोनोंका अन्तरही राष्ट्रीय आय का

परिमाण है। परन्तु फिशरके मतानुसार राष्ट्रीय आयमें केवल उन वस्तुओं और सेवाओंकी गणना होनी चाहिए जिनका कि वर्षभर में उपभोग किया जाता है। इस प्रकार यदि हम किसी वर्षमें एक मकान बनवायें तो मार्शलके मतानुसार उस मकान का कुल मूल्य उस वर्षकी राष्ट्रीय आयमें शामिल करना चाहिए। परन्तु फिशरके मतानुसार मकानके केवल उस अंशका मूल्य शामिल करना चाहिए जिसका कि वर्षभर में प्रयोग किया गया है। तबकी दृष्टिसे फिशरकी परिभाषा अधिक मराहतीय प्रतीत होती है, परन्तु इसके व्यावहारिक प्रयोगमें इतनी कठिनाइयाँ हैं कि राष्ट्रीय आयका परिमाण मापन करनेके लिए प्रायः मार्शलकी ही परिभाषा काममें लायी जाती है।

राष्ट्रीय आय की माप-विधि

राष्ट्रीय आयका परिमाण मापने समय इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वही वस्तुके मूल्यकी दो या दो से अधिक बार गणना न होजाये। ऐसा होनेकी सम्भावना इसकारण रहती है कि एक उद्योग धन्धे द्वारा उत्पन्न वस्तुएँ किसी दूसरे उद्योग धन्धेमें बच्चे मालकी तरह काम आती हैं। सूत कातनेवाली संस्थाओं द्वारा उत्पन्न किया हुआ सूत कपड़ा बुननेवाली संस्थाओंके लिए कच्चा मालही तो है। यदि एक वर्षमें उत्पन्न सूत उसी वर्षमें उत्पन्न कपड़ोंमें परिणत होजाता है तो राष्ट्रीय आय में कपड़ोंके मूल्यकी गणना करलेने पर सूतके मूल्यकी गणना नहीं करनी चाहिए।

पीगूके मतानुसार राष्ट्रीय आयको आकते समय केवल उन वस्तुओं और सेवाओंकी गणना करनी चाहिए जिनका कि द्रव्यके रूपमें मूल्य निकालकर लत देन होता है। परन्तु उन्होंने स्वयं स्वीकार करलिया है कि उनके मतमें बहुतसी त्रुटियाँ हैं। त्रय-विनय कीजानेवाली और न कीजानेवाली वस्तुआ और सेवाओंमें कोई स्वभाव-सिद्ध अन्तर नहीं होता और प्रायः एक प्रकारकी वस्तुओं और सेवाओंका दूसरे प्रकार में परिणत होना असम्भव नहीं। यदि कोई मनुष्य किरायेके मकानमें रहता है तो उस मकानमें प्राप्त होनेवाली सेवाओंका राष्ट्रीय आयमें समावेश होता है परन्तु यदि वह मकान उमड़ा अपना हो तो नहीं। इसीप्रकार यदि कोई मनुष्य बिनामूल्य प्राप्तिये अपनी या अपने कुटुम्बिकोंकी सेवा करता है तो उसके मूल्यकी राष्ट्रीय आयमें गणना

नही होती परन्तु यदि वही सेवा वेतन लेकर किसी दूसरेकी बीजाये तो उसकी राष्ट्रीय आयमें गणना होगी। बिना वेतन प्राप्त किये लोक-सेवाके लिए कियेगये राज-नीति, ज्ञान-विज्ञान इत्यादिसे सम्बन्ध रखनेवाली सेवाओंको भी राष्ट्रीय आयमें सम्मिलित नहीं किया जाता। कारण यह है कि इसप्रकार की सेवाओंके मौद्रिक मूल्यका अनुमान करना कठिन है। कृषिद्वारा उत्पन्न उन वस्तुओंका जिनको कुछ अपन उपभोगके लिए रखकर मंडीमें नहीं बेचना, राष्ट्रीय आयमें सम्मिलित करना ही उचित समझा जाता है। परन्तु आवश्यक आवड न मिलनेके कारण कृषि प्रधान देशोंकी राष्ट्रीय आयको ठीक ठीक मापना मुश्किल नहीं। कमसेकम वास्तविक आयका आकीर्ष आयमें अधिक हानातो निश्चितही है।

सरकार द्वारा प्राप्त सेवाओंकी गणनाभी कठिनाइयोंसे खाली नहीं। आन्तिके समयमें भी यह निश्चित करना कठिन है कि उन सेवाओंका कितना अग देशके उत्पादन कार्यको सुचारु रीतिसे चलानेके लिए आवश्यक था और इसलिए उसका मूल्य उत्पन्न वस्तुओंके मूल्यमें प्राप्ता जा चुननेके कारण दोबारा न मापना चाहिए। शुद्ध-सामग्रीको राष्ट्रीय आयमें सम्मिलित करनेका ही अवतक उचित समझा जाता है। राष्ट्रीय आय प्रायः व्यय के लिए मापनेकी प्रथा है। वस्तुओंका यदि व्यय भरमें क्रय-विक्रय हुआ तो उनका विक्रय-मूल्य अथवा उनका उत्पादन-व्यय उनके मौद्रिक मूल्यका छोक है।

वैकल्पिक माप-विधियाँ

उत्पादन कार्य उत्पादनके साधनोंसे सम्पन्न होता है। उत्पादन कार्यमें साधनोंकी निष्पत्ति उन साधनोंके स्वामियोंको भूमि-कर, बहन व्याज, लाभ इत्यादि देकर बीजाती है। साधनोंके स्वामियोंको इसप्रकार प्राप्त कुल आय उन-साधनों द्वारा उत्पन्न कुल उत्पत्तिके मूल्यके सम होती है। किसीभी सत्त्वा द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का मूल्य या तो उपभोक्ताओंसे मिलता है या दूसरी सम्थाओंसे। और इसप्रकार प्राप्त कुलमूल्य एतत् भूमि-कर, वेतन, व्याज लाभ आदि देनेमें, दूसरे व्यय सम्थाओं से वस्तुएं खरीदनेमें और तीसरे प्रकार के व्ययको पूरा करनेमें व्यय किया जाता है। इसप्रकार प्राप्त कुल मूल्यका उपरिलिखित तीन व्ययोंके समान होना आवश्यक

है। हिसाब किताबके वहीखातोमें इस आय व्ययको सम दिखाया जाता है। यदि व्यय आयसे अधिकहै तो दोनोंका अन्तर हानिके रूपमें दिखाकर आय व्ययको सम करदिया जाताहै। वस्तुओं और सेवाओंके मूल्य तथा उत्पादनके साधनोंके स्वामियोंको दियेगये भुगतानमें समता होनेके कारण किसी देशके वासियोंकी मौद्रिक आय मालूम करनेमें भी उस देशकी राष्ट्रीय आय मालूम की जासकती है। चूँकि इस प्रकार राष्ट्रीय आयकी गणना करनेमें भूलचूक की कम सम्भावना है। यह आयभी दो ढंगसे मालूमकी जासकतीहै। एक ढंगतो यहहै कि आय-कर देनेवाले और आयकर न देनेवाले लोगोंकी आयको जोड़लिया जाय और दूसरा ढंग यहहै कि विभिन्न प्रकारके उत्पादन सम्बन्धी कार्योंमें भाग लेनेवालों की मर्यादा तथा आय मालूम कर लीजाये। परन्तु यह ध्यान रखना आवश्यकहै कि बिना सेवाकिये प्राप्त आय, वृद्धावस्थाके कारण प्राप्त सरकारी वृत्ति, युद्ध-ऋणसे प्राप्त व्याज और छल कपट से पायीहुई आय इत्यादिकी गणना नहीं करनी चाहिए।

राष्ट्रीय आयको आबनेका एक ढंग यहभी होसकताहै कि प्रत्येक सन्ध्या या उद्योग धन्धे द्वारा उत्पन्न कीगयी वस्तुओंकी मात्राके मूल्यमें से उस वस्तुओंकी मात्राका मूल्य निकाल दिवाजाये जिनका कि उस सन्ध्या या उद्योग धन्धोमें प्रयोग कियागया है। परन्तु यह ढंग आजतक व्यावहारिक दृष्टिसे असफलमा रहा है।

राष्ट्रीय आय और भौतिक कल्याण

राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्रकी उत्पत्तिका परिमाण होनेके कारण उस राष्ट्रके भौतिक कल्याणकी द्योतक होसकती है परन्तु इसके द्रव्यके रूपमें परिणत करदेने से ऐसा होनेकी भी सम्भावनाहै कि वस्तुआकी उत्पत्तिकी मात्रामें तो तनिकभी वृद्धि न हो, फिरभी उनके मूल्यमें वृद्धिके कारण राष्ट्रीय आयके मौद्रिक रूपमें वृद्धि होजाये। इसकारण एक-वर्ष या राष्ट्रकी आयकी किसी दूसरे वर्ष या राष्ट्रकी आयसे तुलना करतेसमय इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि वस्तुआके मूल्यमें होनेवाले परिवर्तनोंके प्रभावको निकाल दियागया है। ऐसा तभी होसकता है जबकि हम दूसरे वर्ष या राष्ट्रमें उत्पन्न वस्तुओंको द्रव्यके रूपमें परिणत करने समय उन्ही मूल्योंका प्रयोग करें जो पहिले वर्ष या राष्ट्रमें प्रचलित थे। दो राष्ट्राकी राष्ट्रीय आयकी

तुलना तो औरभी कठिन है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय आयको मौद्रिक रूपमें निकालते समय अपने निजी द्रव्यका प्रयोग करता है। एक राष्ट्रके द्रव्यको विदेशी विनिमयकी दरकी सहायतासे दूसरे देशके द्रव्यमें परिणत करनेसे भी तुलना सम्भव नहीं क्योंकि विदेशी विनिमयकी दरपर राष्ट्रकी उत्पत्तिके केवल उस थोड़ेसे अंशका प्रभाव पड़ना है जिसका बि. आयात-निर्यातके लिए क्रय-विक्रय होता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न राष्ट्रोंके लोगोकी रुचियोंमें अन्तर होनेके कारण उनमें उत्पन्न वस्तुओंकी मात्रा एवं गुणोंमें भी अन्तर होनेकी सम्भावना है। इसीप्रकार एकही राष्ट्रके लोगोकी रुचियोंमें समय समयपर परिवर्तन होमकता है और यदि यह भी मान लिया जाये कि उपभोगोंकी रुचियाँ तथा आवश्यकताएँ दोनो राष्ट्रों या वर्षों में एकसी ही थी तो भी उनके द्वारा उपभोग कीजाने वाली वस्तुओंके समूहमें मूल्य-परिवर्तनोंके कारण परिवर्तन होनेकी सम्भावना है। किसी वस्तुका मूल्य न्यूनाधिक होनेसे आय तथा स्थानापन्न प्रभावों द्वारा उन वस्तुओंके समूहमें उस वस्तुकी मात्रा के न्यूनाधिक होनेका विवेचन पहिले किया जा चुका है।

राष्ट्रीय आय द्वारा हम यहाँ मान्य कर सकते हैं कि अमुक राष्ट्र या वर्षमें उत्पत्तिकी मात्रा अमुकथी परन्तु इस मात्राको उत्पन्न करनेके लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, इस बातका ज्ञान राष्ट्रीय आयके आँकड़ोंसे नहीं होता। दो राष्ट्रोंमें राष्ट्रीय आयकी मात्रा एकसी होनेपर भी उसके द्वारा प्राप्त भौतिक कल्याणमें भिन्नताका होना असम्भव नहीं क्योंकि होसकता है कि उस मात्राकी प्राप्तिके लिए उनमें से एकको दूसरेसे अधिक श्रम अथवा समयका व्यय करना पड़ा हो। अथवा एक राष्ट्रमें किसी वस्तुके प्राकृतिक बाहुल्यके कारण उस वस्तुकी प्राप्ति बिना मूल्य दिये सम्भव होनेसे लोगोंके भौतिक कल्याणमें तो वृद्धि होगी, यद्यपि उस वस्तुकी राष्ट्रीय आयमें गणना करना सम्भव नहीं।

राष्ट्रीय आयकी वृद्धिकी मात्राको भौतिक कल्याणकी वृद्धिकी मात्राका द्योतक मानने में एक औरभी अड़चन है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आयकी मात्रा बढ़तीजाती है, वैसे वैसे उसकी वृद्धिसे प्राप्त होनेवाले भौतिक कल्याणकी मात्रामें सीमान्त उपयोगिता के क्रमशः ह्रासका नियम लागू होनेके कारण कमी होती जातीजाती है। राष्ट्रीय आय यदि १०० करोड़ रुपये में बढ़कर १५० करोड़ रुपये होजाये तो भौतिक कल्याण में वृद्धि अवश्य होगी परन्तु जब राष्ट्रीय आय १५० करोड़ रुपये से बढ़कर

२०० करोड़ रुपये होजाये तो इस ५० करोड़ रुपये की वृद्धिसे भौतिक कल्याणमें उतनी वृद्धि न होगी जितनी कि उस ५० करोड़ रुपये की वृद्धिमें हुईथी, जब आय १०० करोड़ से १५० करोड़ रुपये हुईथी।

राष्ट्रीय आयकी गणना करनेके लिए विभिन्न प्रकारकी पूँजीका वर्षके आरम्भ तथा अन्तमें मूल्य आकना पड़ता है। मूल्य आकनके लिए कोई एक निश्चित विधि नहीं है। इसकारण विविध प्रकारकी विधियोंका प्रयोग करनेसे राष्ट्रीय आयकी गणनामें भारी भ्रान्त होना असम्भव नहीं।

राष्ट्रीय आय मापने के लाभ

इन सब श्रुतियोंके होतेहुए भी राष्ट्रीय आयकी गणना नितान्त निष्फल नहीं। इसके द्वारा निरपेक्ष उत्पत्तिकी मात्राका नहीं नों कमसेकम सापेक्ष उत्पत्तिकी मात्राका तो पता चलसकता है और इसकारण दो राष्ट्रा या वर्षोंमें तुलनाकी जासकती है। राष्ट्रीय आयके मौद्रिक रूपका निकासनाभी कई कारणोंसे आवश्यकता है। इसमें हम यह मालूम करसकते हैं कि राष्ट्रीय आयका कितना अंश उपभोग्य पदार्थोंकी उत्पत्तिके रूपमें था और कितना उत्पादन-मामग्रीके रूपमें। मौद्रिक रूप द्वारा हम यहभी ज्ञान प्राप्त करसकते हैं कि राष्ट्रीय आयका कितना अंश व्यवस्थापकोंको, कितना पूँजीपतियों को, कितना भूमि-स्वामियोंको और कितना श्रमजीवियोंको मिला—अर्थात् इस आयका वितरण किसप्रकार से हुआ? भूमि-कर, मजदूरी, व्याज तथा लाभ इत्यादि उत्पादनके साधनोंको मिलनेवाले राष्ट्रीय आयके भागोंकी मात्रा निश्चित करनेके लिए समय समयपर भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंका सृजन होतारहा है। उनका विवेचन आगामी अध्यायोंमें कियाजायेगा। इस स्थानपर केवल इतना बत देना आवश्यकहै कि अन्य वस्तुओंके समानही उत्पादनके साधनोंका भी मूल्य होना है और यह मूल्य उसीप्रकार निर्धारित होताहै, जैसे अन्य वस्तुओंका मूल्य। इसके निर्धारणकी क्रियाका हम किसी अन्य स्थानपर मनीप्रकार विवेचन करचुके हैं। हम देखचुके हैं कि पूर्तिकी ओरसे वस्तुके सीमान्त उत्पादन-अर्थको और मागकी ओरसे सीमान्त उपयोगिताको महत्व दियाजाता है। इसीप्रकार उत्पादनके साधनों के स्वामियोंको भी साधन-विशेषके उत्पादनके लिए विभिन्न प्रकारका व्यय करना

पड़ता है और वह अपने साधनको उसके सीमान्त-उत्पादन-व्ययमें कम मूल्यपर देने के लिए उद्यत नहीं हो सकता। इसलिए पूँतिकी ओरसे उस साधनका सीमान्त उत्पादन-व्ययही उसके मूल्यको निर्धारित करता है। आगे चतकर हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न मिद्धान्त इस उत्पादन व्ययकी भिन्न साधनोके लिए भिन्न भिन्न प्रकारसे गणना करते हैं। परन्तु गणना चाहें किमीभी ढंगमें हा, इसमें मन्देह नहीं कि साधन विनापके मूल्यको निर्धारित करनेमें उसके सीमान्त उत्पादन-व्ययमें सहायता लेनी पड़ती है। हम यहभी देख चुके हैं कि मूल्यके सीमान्त-उत्पादन वय सिद्धान्तमें यह दावा कि यह मिद्धान्त केवल वस्तुओंकी पूँतिको महत्व प्रदान करती थी, मागकी नहीं। मागका मूल्य निर्धारणकी क्रियामें स्थान देनेके लिए उपयोगिताके क्रमशः ह्रास नियममें सहायता लेकर सीमान्त उपयोगिताको वस्तुओंके मूल्यका कारण और माप ठहराया गया था। वस्तुओंकी माग इसलिए होती है कि उनसे उपयोगिता प्राप्त होती है। उत्पादनके साधनोकी माग इसलिए होती है कि उनके नियोगमें उत्पादन होता है। अन्य साधनोकी मात्रामें परिवर्तन कियेबिना किसी साधन विनापकी मात्रामें वृद्धि करने रहनेमें उससे द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रामें क्रमशः ह्रास होना लगता है। कोईभी व्यवस्थापक उस साधनकी मात्रामें तबतक वृद्धि करता रहेगा जबतक कि उसके द्वारा प्राप्त उत्पत्तिका मूल्य उस साधनकी वृद्धिकी मात्रापर नियम्य व्ययके सम नहीं हो जाता। साधनकी उस इकाईको जिसे कोई व्यवस्थापक किसी विनाप मूल्यपर उत्पादन कार्यमें नियुक्त करनेके लिए केवल उद्यतमात्र ही हायाना है सीमान्त इकाई कहते हैं और इस इकाई द्वारा प्राप्त उत्पत्ति की मात्राके मूल्यको उन साधनकी सीमान्त उत्पत्ति कहते हैं। अन्य साधनोको जोका लो रक्कड़ साधन विनापकी मात्रामें एक और इकाईकी वृद्धि करनेसे उत्पत्तिकी मात्रामें जो वृद्धि प्राप्त होती है उसके मूल्यको भी उस साधनकी सीमान्त उत्पत्ति कहा जा सकता है। जिसप्रकार वस्तुकी सब इकाइयोंका मूल्य सीमान्त इकाईसे प्राप्त होनवाली उपयोगिताके सम होता है, उसीप्रकार साधनकी सब इकाइयोंका मूल्य उनकी सीमान्त इकाईसे मिलनवाली उत्पत्तिके मूल्यके भी सम होता है।

हम देख चुके हैं कि वस्तुओंके मूल्यके सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्तमें कई एक दोष थे। साधनोके मूल्यके सीमान्त उत्पत्ति सिद्धान्तमें उससेभी अधिक दोष हैं। उत्पादन के लिए चारो साधनोका सहयोग आवश्यक है। किसी एकही साधन द्वारा वस्तुओं

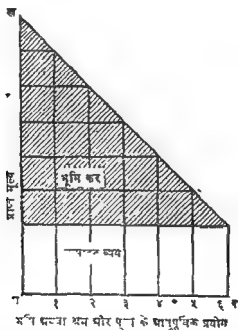
का उत्पादन सम्भव नहीं। इसकारण साधन विशेषकी मात्रामें वृद्धिसे प्राप्त होने वाली अधिक उत्पत्तिको उनी साधनकी उत्पत्ति मानना तर्कयुक्त नहीं क्योंकि उसमें अन्य साधनोंका सहयोगभी वर्तमान है उत्पत्ति अधिकतम प्राप्त करनेके लिए साधनोंको विशेष अनुपातमें एकत्रित करना आवश्यक है। ऐसी दशामें एकही साधनकी मात्रामें वृद्धि करनेसे इस अनुपातको भंग करनेके कारण उत्पत्तिकी मात्रा में वृद्धिके स्थानमें ह्रास होनेकी भी सम्भावना है। इसकारण कईएक अर्थशास्त्रियोंके विचारमें साधन विशेषकी मात्राको न्यूनाधिक करना सम्भवही नहीं, क्योंकि किसी काममें प्रयोजित उत्पादन-विधिकें अनुसार चारों साधनोंको विशेष अनुपातमें एकत्रित करनेमें ही प्राप्त होसकता है अन्यथा नहीं। इसकारण साधन-विशेषकी मात्रा को न्यूनाधिक करके उसकी सीमान्त उत्पत्ति मानूम करना सम्भवही नहीं। ऐसाभी होसकताहै कि साधनविशेष की किसी विशेष समस्यामें सीमान्त उत्पत्ति तो कमहो किन्तु पूरे उद्योगमें अधिक मात्रामें उत्पत्ति करनेसे प्राप्त होनेवाली मितव्ययिताके कारण अधिक। इसकारण जबतक उत्पत्तिकी क्रमशः वृद्धिका नियम लागू होता रहताहै तबतक सीमान्त उत्पत्तिनिर निश्चित रूपसे मालूम करना कठिन है। साधनों के मूल्यका सीमान्त उत्पत्ति मिटाने केवल उनकी मागकी ओर ध्यान देताहै, पूर्ति की ओर नहीं। मूल्यको सम्यक् रीतिसे निश्चित करनेके लिए हमें माग और पूर्ति दोनोंको एकही सा महत्व देना होगा। किसी उत्पादनके साधनका मूल्य किसी अन्य वस्तुके मूल्यके समानही उससमय सन्तुलनकी अवस्था प्राप्त करेगा जबकि उस मूल्यपर उत्पादन-व्यय द्वारा निश्चित उस साधनकी पूर्ति, सीमान्त उत्पत्ति द्वारा निश्चित उस साधनकी मागक सम होजायेंगी।

भूमि-कर

रिकार्डों का भूमि-कर मिद्दान्त

अर्थशास्त्रकी भाषामें भूमि-कर उम पुस्तकारको बहाजाना है जो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक साधनोंके स्वामियोंको इन साधनोंके उत्पादन-कार्यमें सहायता देनेके फलस्वरूप प्राप्त होता है। रिकार्डोंके मतानुसार भूमि-कर भूमिद्वारा प्राप्त उत्पत्ति-की उस मात्राको कहते हैं जो भूमिपतियोंका भूमिकी प्राकृतिक तथा मनातल दक्षिणों का उपयोग करनेकी अनुमति प्रदान करनेके बदल दी जाती है। रिकार्डों और उसके अनुयायियोंका विश्वास था कि किसी देशमें कुल उपलब्ध भूमिका कृषिके उपयोगमें लाया जाना आवश्यक नहीं है। आरम्भमें तो केवल अधिक उत्पादन भूमि पर खेती की जाती है क्योंकि उसमें प्राप्ति उत्पत्तिकी मात्रा जन-समुदायकी आवश्यकताओंको तृप्त करनेके लिए पर्याप्त होती है। परन्तु जनसंख्यामें वृद्धि होनेपर अधिक उत्पादक भूमि अपर्याप्त माना में उपलब्ध होनेके कारण, अधिक मात्रा में उत्पत्ति प्राप्त करनेके लिए अधिक उत्पादक भूमि परही अधिकारिक मात्रा में श्रम और पूँजी का व्यय करना होगा, अथवा कम उत्पादक भूमिके भागोंपर कृषि करनी होगी। दोनों स्थितियोंमें पहिलके समानही श्रम और पूँजी लगानेपर प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रा में कमी आने लगेगी अर्थात् सीमान्त उत्पादन व्ययमें वृद्धि होने लगेगी। हम देख चुके हैं कि उत्पत्ति का मूल्य उसके सीमान्त उत्पादन व्ययमें निर्धारित होता है, इसलिए कृषिकी उत्पत्तिका मूल्यभी उस उत्पादन व्यय द्वारा निर्धारित होगा जो न्यूनतम उत्पादक भूमिपर कृषि करनेके लिए उठाना पड़ना है अथवा श्रम तथा पूँजी-के निम्नतम प्रयोगपर कियेगये व्ययके सम होगा। सीमान्त कृषक अन्य कृषकोंके प्रतिस्पर्धिक कारण अपन सीमान्त उत्पादन व्ययमें अधिक मूल्य नहीं लसकता और इसकारण सीमान्त भूमि या श्रम और पूँजीके सीमान्त प्रयोगपर कोई कर नहीं

मिलता। इसी कारण रिकार्डोंने उत्पादन व्ययमें भूमि-कर का समावेश न होनेके सिद्धान्तकी रचना की। मूल्य तो निर्धारित होता है सीमान्त भूमि अथवा थम और पूँजीके सीमान्त प्रयोगसे जिस पर कोई कर नहीं मिलता। इस कारण अधिक उत्पादक भूमिभागों पर अथवा पूँजी और थमके अधिक लाभदायक प्रयोगों पर कर मिलता है क्योंकि उनके उत्पादन व्यय तो सीमान्त उत्पादन व्ययकी अपेक्षा कम होते हैं परन्तु बाजारभाव सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होते हैं। फलतः भूमि-कर उत्पादकोंकी बचत है और यह मूल्य द्वारा निर्धारित होता है न कि वह स्वयं मूल्यको निर्धारित करता है। रक्षाशास्त्रकी म्हायनामें भूमि-कर उसी प्रकार



दिखाया जा सकता है जैसेकि उपभोक्ताकी बचत। 'म' क मुख्य रेखापर भिन्न-प्रकारकी उत्पादक भूमि अथवा पूँजी और थमकी क्रमशः प्रयुक्त मात्राएँ दिखायी जाती हैं और 'म,ख' रेखापर प्राप्त उत्पत्तिका मूल्य। उत्पत्तिकी उपलब्ध मात्रामें क्रमशः ह्रास होता जाता है जैसेकि उपभोक्ताकी बचतमें उपलब्ध उपयोगिताका

क्रमशः ह्राम होता जाता था। प्रत्येक प्रकारकी भूमि अथवा थम और पूजीके प्रयोगपर व्यय तो एकसा होता है परन्तु उपज तथा उत्पत्तिकी मात्रामें अन्तर होनेके कारण कुल प्राप्त मूल्यमें अन्तर होता है, जिस भागको रखाया द्वारा अर्जित किया गया है वह प्राप्त भूमि-कर का घातक है।

भूमि-करके अस्तित्वकी व्याख्या इसप्रकार भी की जासकती है। मान लीजिए किनी भूमिपतिके पास भिन्न भिन्न उत्पादन शक्तिवाले भिन्न भिन्न भाग हैं और वह उनपर स्वयंसे कृषि नहीं करना परन्तु उन सबको आमाभिषयाका कृषि करनेके लिए देता है। अधिक उत्पादक भूमि भागापर अधिक उत्पत्ति होगी और कम उत्पादक भूमि भागापर कम यद्यपि उन सबपर एकसा ही थम तथा पूजीका प्रयोग किया जाता है। अथवा कम उत्पादक भूमिभागापर अधिक थम और पूजीका प्रयोग करके भी सबपर एकसी ही उत्पत्तिकी मात्रा उत्पन्न की जासकती है। इसकारण अधिक उपजाऊ भूमिवाला आसामी न्यूनतम उत्पादक भूमिमें अधिक प्राप्त होनेवाली उत्पत्तिकी मात्राको भूमिपतिको भूमि-करके रूपमें देनेके लिए उद्यत होजायेंगे क्योंकि इसमें उनकी कुछ भी हानि नहीं। मान लीजिए कि अधिकतम उत्पादक भूमिपर ८० मन गेहूँ उत्पन्न होता है और अन्य भागापर क्रमशः ७०, ६०, ५०, ४० मन। विभिन्न भूमि-भागमें इस अवस्थामें भूमिपतिको ४०, ३०, २०, १० मन गेहूँ भूमि-करके रूपमें प्राप्त होगा।

इससे स्पष्ट है कि किमी विशेष आसामीके हानि लाभके व्योरेमें भूमि-करको, व्ययके रूपमें दिखाना ही पड़ेगा। अर्थात् उसके उत्पादन व्ययमें भूमि-करभी एक अगके रूपमें शामिल होगा और इसकारण उसके लिए मूल्यका एक अग होगा। परन्तु उपभोक्ताओंसे लिया जानेवाला मूल्य सीमान्त उत्पादन व्यय द्वारा निर्धारित होता है और हम देखचुके हैं कि सीमान्त उत्पादन व्यय उस भूमि अथवा थम और पूजी के उस प्रयोगपर होनेवाले व्ययको कहते हैं जिसने कोई भूमि-कर प्राप्त नहीं होता। इसकारण भूमि-कर भिन्न भिन्न उत्पादन शक्तिवाली भूमियों अथवा थम और पूजीकी मात्राओंके भिन्न भिन्न प्रयोगपर होनेवाले व्ययको एकसा बना देता है अर्थात् भूमि-करके कारण प्रत्येक आसामीको एकसा ही उत्पादन व्यय उठाना पड़ता है यद्यपि भिन्न भिन्न आसामियोंको मिलनेवाली भूमियोंकी उत्पादनशक्ति एकसी नहीं होती।

रिकार्डो के सिद्धान्त की आलोचना

रिकार्डोके भूमि-कर सिद्धान्तकी कई आलोचनाएँ की गयी हैं। इस सिद्धान्तके मुख्य अंग दो हैं। एक तो यह है कि भूमि-कर किसी भूमिकी प्राकृतिक स्थिति अथवा सनातन उत्पादन शक्तिके कारण प्राप्त होनेवाला सापेक्ष अतिरिक्त लाभ है और दूसरे ऐसी भूमियोका अस्तित्व जिनसे भूमि-कर प्राप्त नहीं होता।

कई लोगोंका विचार है कि भूमिकी उत्पादन शक्ति सनातन नहीं। उसमें ह्रास होता रहता है और थम सवा पूँजीके प्रयोगसे उसका पुनर्नवीकरण किया जाता है। इस प्रकार श्रम और पूँजीके व्ययसे प्राप्त भूमिकी स्थायी उन्नतिका उसकी प्राकृतिक शक्तियोंसे भेद करना असम्भव हो जाता है। भूमिकी उत्पादन शक्ति सनातन हो अथवा न हो परन्तु भूमिमें कुछ भुण ऐंसे अवश्य होते हैं जो अन्य साधनोंमें नहीं होते। रिकार्डोका सकेत इन गुणोंकी ओर था। स्थायी उन्नतिके लिए किये गये भुगतानोंका रिकार्डो ने भी भूमि-करमें सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया है। इस दृष्टिसे एडम स्मिथने भूमि-करका रिकार्डोसे अधिक उपयुक्त परिभाषा की है। उनके मतानुसार भूमि-कर कुछ तो किसी समाजकी सामान्य परिस्थितिपर निर्भर है और कुछ भूमिकी प्राकृतिक एवं कृत्रिम उत्पादन शक्तिपर। कृत्रिम उत्पादन शक्तिसे स्थायी उन्नति द्वारा और समाजकी सामान्य परिस्थितिमें जन-संख्यामें वृद्धि द्वारा भूमि-करपर पड़नेवाले प्रभावकी ओर सकेत है।

कुछ लोगोंके विचारानुसार यह सत्य नहीं कि सर्वप्रथम अधिकतम उत्पादक भूमि परही कृषि-कार्य प्रारम्भ किया जाता है और फिर धनैः धनैः क्रमशः कम उत्पादक भूमियोंपर। बरिष्ठ वास्तवमें प्रायः कम उत्पादक भूमिभागोंका उपयोग पहिले किया जाता है और अधिक उत्पादक भूमिभागोंका उसके बाद। सिद्धान्तकी सिद्धिके लिए इस तथका कोई महत्व नहीं है। केवल भूमिभागोंकी उत्पादन शक्ति में भिन्नताके अस्तित्वकी आवश्यकता है। जबतक यह भिन्नता विद्यमान है तबतक अधिक उत्पादक भागोंको भूमि-कर प्राप्त होता रहेगा।

ऐसा भी कहा जाता है कि ससारमें कोईभी भूमिभाग उपलब्ध नहीं जिसके प्रयोग के लिए कुछ न कुछ भूमि-कर प्राप्त न होता हो। मिलके अनुसार इसका कारण यह हो सकता है कि भूमि-कर प्राप्त न करनेवाले भागोंका भूमि-कर प्राप्त करने

वाले भागमें सम्मिश्रण होनेके कारण प्राप्त औसत भूमि-करमें न्यूनता आजाती है। यहभी सम्भव है कि भूमि-करके रूपमें किया जानेवाला भुगतान केवल उस भूमिकी श्रम और पूँजी द्वारा कीगयी उद्यतिका ही पुरस्कार मान है। इसके अतिरिक्त यदि यहभी मानलिया जाय कि भूमि चाहे किसीभी प्रकारकी हो उसको उपयोगमें लानेके लिए आसानी भूमिपतिका कुछ न कुछ करके रूपमें देता है तो भूमि-कर वचित भूमिमें खिटाडोंवा अभिप्राय उस भूमिमें था, जिससे प्राप्त उत्पत्ति केवल उत्पादन व्ययका पूरा करनके लिए पर्याप्त न हो। उत्पादन-व्ययमें भूमिपतिका दिया जानेवाला करभी सम्मिलित करलिया जाता है परन्तु ऐसी भूमिमें ऐसी कोई भी प्राप्ति नहीं होती जिस अवश्यास्त्रकी परिभाषामें भूमि-कर कहा जाता है और इस दृष्टिमें उसे हम भूमि-कर वचित भूमि कह सकते हैं।

किसी विशेष भूमि भागका भूमि-कर ज्ञात करनेके लिए भूमि-कर वचित भूमि की उत्पत्ति आवश्यक नहीं। उस भूमि भागपर श्रम और पूँजीके सीमान्त प्रयोग द्वारा प्राप्त उत्पत्ति भूमि-कर वचित भूमिसे प्राप्त उत्पत्तिके सम है। कुल उत्पादन व्यय मालूम करनेके लिए श्रम और पूँजीकी सीमान्त मात्रासे प्राप्त उत्पत्तिकी सीमान्त मात्राके सम लगायीगयी कुल मात्राओंसे गुणा कर देना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक मात्रापर कियागया व्यय सीमान्त मात्रामें प्राप्त उत्पत्तिके सम होता है। इस उत्पादन व्ययमें कृषककी मजूरीभी सम्मिलित है। उत्पत्तिकी कुल उपलब्ध मात्रा इन उत्पादन व्ययमें अवश्यनी अधिक होगी क्योंकि सीमान्त मात्रामें पहिले प्रयोगकी जानेवाली श्रम और पूँजीकी मात्राओंसे क्रमशः अधिक उत्पत्ति प्राप्त होती है। उत्पत्तिकी कुल उपलब्ध मात्रा और कुल उत्पादन व्ययमें अन्तरकी मात्रा भूमिपति को भूमि-करके रूपमें दी जा सकती है। कृषकको इसमें कोई आपात न होगी क्योंकि वह श्रम और पूँजी के सीमान्त प्रयोगसे मिलनवाली मजूरीसे सन्तुष्ट है और इसकारण वह सीमान्त प्रयोगसे पहिलेके प्रयोगोंके लिए भी उतनीही मजूरीपर श्रम करता रहता है। इसके अतिरिक्त भूमिके वैयक्तिक प्रयोग हो सकते हैं। एक प्रयोगके लिए वही भूमिभाग भूमि-कर वचित भूमि हो सकती है और दूसरे प्रयोगके लिए भूमि-कर प्राप्त करनेवाली भूमि। इसकारण यहभी हो सकती है कि प्रत्येक भूमिभागको उस प्रयोगमें लाया जा रहा हो जिसके कारण कि उससे भूमि-कर प्राप्त होना हो। इस सम्बन्धमें यह उल्लेखनीय है कि एक कृषिफलके लिए प्राप्त भूमि-कर दूसरे कृषिफलके

मूल्यपर प्रभाव डालसकता है। गेहूँ की माग बढ़नेसे गेहूँ उत्पन्न करनेवाली भूमि का भूमि-कर बढ़ने लगेगा और इसकारण गन्ना उत्पन्न करनेवाली भूमिका गेहूँ उत्पन्न करनेमें प्रयोग किया जाने लगेगा। गन्ने की पूर्तिको स्थित रखनेके लिए गन्ना उत्पन्न करनेके लिए कम उत्पादक भूमिभागोंको प्रयुक्त किया जायेगा और इसकारण गन्नेके मूल्यमें भी वृद्धि होगी। इसप्रकार गेहूँ उत्पन्न करनेवाली भूमिके भूमि-करमें वृद्धिका गन्नेके मूल्यमें समावेश होता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न फसलोंमें प्रतिस्पर्धाके कारण हरप्रकार की भूमिसे भूमि-कर प्राप्त होता रहता है।

भूमि-कर का आधुनिक सिद्धान्त

आधुनिक धर्मशास्त्री भूमि-कर का सापेक्ष लाभके रूपमें अस्तित्व मानते हैं परन्तु उनका विचार है कि सापेक्षताके सिद्धान्त द्वारा हम केवल इतना कहसकते हैं कि अधिक उत्पादक भूमिका कम उत्पादक भूमिसे भूमि-कर अधिक होना चाहिए। अर्थात् रिकार्डों का सिद्धान्त केवल इतना सिद्ध करना है कि उत्तम वस्तुका मूल्य निम्न वस्तुसे अधिक होना चाहिए। मूल्य क्यों अधिक होना चाहिए इसका उत्तर इस सिद्धान्तसे नहीं मिलता क्योंकि यदि सब भूमि भागोंकी उत्पादन शक्ति समान हो होनी तो रिकार्डोंके मतानुसार किसीभी भूमि भागके प्रयोगके लिए भूमि-कर न देना पड़ता। आधुनिक सिद्धान्तके अनुसार भूमि भागोंके समान रूपमें उत्पादक होनेपर भी भूमि-कर का अस्तित्व सम्भव है क्योंकि भूमि-कर अधिक उत्पादक भूमि भागोंकी सापेक्ष न्यूनताका नहीं बल्कि भूमिसे प्राप्त होनेवाली वस्तु विशेषकी सापेक्ष न्यूनताका परिणाम स्वरूप है। भूमि-कर तबतक सनातन रूपमें विद्यमान रहेगा जबतक कि भूमिसे उत्पन्न होनेवाली किसी वस्तुकी माग उस वस्तुकी पूर्तिसे अधिक है क्योंकि मागमें आधिक्यके कारण वस्तुके मूल्यमें वृद्धि होगी और भूमि-पतियोंको मूल्यमें वृद्धिके कारण पहिलेसे अधिक आय भूमि-करके रूपमें प्राप्त होगी। मूल्यमें वृद्धिके कारण पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें अप्रयुक्त भूमिभागोंको प्रयोगमें लाकर या प्रयुक्त भूमिभागोंमें थम और पूँजीकी अधिक मात्रा लगाकर पूर्ति बढ़ाने की चेष्टा की जायेगी और पूर्ति बढ़नेपर भूमि-करकी प्राप्ति बन्द हो जायेगी। इस सिद्धान्तमें कम उत्पादक भूमियोंको केवल इतना महत्त्व प्राप्त है कि उनसे कम

उत्पत्ति मिलनेके कारण पूर्तिमें कमी आजाती है और इसकारण प्राप्त भूमि-कर की मात्रामें वृद्धि होजाती है।

भूमि-करको इस दृष्टिमें देखनेमें उसे केवल भूमि तथा अन्य प्राकृतिक देनसे सम्बन्धित करनेकी आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि इसप्रकार के अतिरिक्त लाभ अन्य उत्पत्तिके साधनोंको भी उनके द्वारा उत्पन्न वस्तुओंकी पूर्तिमें मापेन्यूनताके कारण प्राप्त होने रहते हैं। मार्शलन ऐसे अतिरिक्त लाभको आभाम करोकी उपाधिदी थी। हम पहिले देखचुके हैं कि भूमि-करका इस दृष्टिसे देखने पर भूमिके वैकल्पिक प्रयोगाके अस्तित्वके कारण भूमि-करके मूल्यमें समावेश होने की तनिकभी गवा नहीं रहती।

कहा जाता है कि भूमि-करका आधुनिक सिद्धान्त सामान्य उत्पादन व्यय और अतिरिक्त लाभमें भेदभाव पर आधारित है। सामान्य उत्पादन-व्यय उत्पादनके साधनोंके उस सामान्य मूल्यपर निर्भर है जो साधन विशेष की आवश्यक मात्रामें पूर्ति करदे। साधारणतया यह मूल्य उस साधनकी कार्यक्षमताको पूर्णरूपेण स्थिर रखनेके लिए पर्याप्त होना चाहिए। उस साधन विशेष द्वारा उसमें अधिक प्राप्त होनेवाली आयको अर्थशास्त्र की परिभाषामें 'कर' कहा जासकता है चाहे यह अधिक आय प्राकृतिक गुणों अथवा स्थितिके कारण प्राप्त हो, चाहे किसी आकस्मिक लाभ के रूपमें और चाहे एकाधिकारके लाभके रूप में।

• भूमि-करको इस दृष्टिमें देखनेमें आभास-करो की कल्पनाभी व्यर्थही सिद्ध होती है। आभाम करका प्रयोग मार्शलन उत्पादनके साधनोंकी उस आयको दिखानेके लिए किया था जो उनको उनकी पूर्ति अस्थायी रूपमें सीमित होनेके कारण होती है। मार्शलका कहनाथा कि भूमिको प्राप्त होनेवाले अतिरिक्त लाभ तथा अन्य साधनोंको प्राप्त होनेवाले अतिरिक्त लाभमें भेद है क्योंकि भूमिकी पूर्ति प्रकृतिकी देन होनेके कारण निश्चित है और अन्य साधनोंकी पूर्ति मनुष्य द्वारा न्यूनताधिक की जासकती है। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री भूमिकी पूर्तिको अन्य साधनोंकी पूर्तिसे अधिक सीमित नहीं स्वीकार करते। उनके मतानुसार यदि किसी विशेष समय और स्थानपर अन्य साधनोंकी पूर्तिमें वृद्धि सुगम रीतिमें होसकती है तो अन्य-समय और स्थानपर भूमि की। इस भेदभाव को मिटा देनेसे भूमि-कर तथा आभास करोंमें केवल इतना भेद है कि भूमि-कर अन्य करोंसे अधिक स्थायी है।

कृषि-सम्बन्धी समुन्नति और भूमि-कर

कृषिसे सम्बन्ध रखनेवाली समुन्नतिका भूमि-कर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर रिकार्डोंके सिद्धान्तके अनुसार दो प्रकारसे दिया जासकता है। यदि अधिक उत्पादक भूमिको औरभी उन्नत कियाजाये तो भूमि-करमें वृद्धि होगी और यदि निम्न कोटिकी भूमिको उन्नत कियाजाये तो भूमि-करमें कमी होगी। परन्तु आधुनिक सिद्धान्तके अनुसार दोनों अवस्थाओंमें भूमि-करमें न्यूनताही रहेगी क्योंकि किसीभी प्रकारकी भूमिको उन्नत करनेका अर्थ उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि द्वारा पूर्तिको बढ़ाना होगा। पूर्ति बढ़नेमें मूल्य कम होगा और मूल्य कम होनेसे भूमि-करभी कम होगा। केवल अधिक उत्पादक भूमियोंको उन्नत करनेसे उत्पत्तिकी मात्रामें अधिक वृद्धि होगी और इसकारण भूमि-कर अधिक गिरेगा और कम उत्पादक भूमियोंको उन्नत करनेकी चेष्टासे उत्पत्तिकी मात्रामें कम वृद्धि होगी और इसकारण भूमि-करमें भी अधिक न्यूनता न होगी।

अबतक भूमि-करको भूमिके सम्बन्धमें ही प्रयुक्त किया जा रहा था। इस गव्दका प्रयोग इमारतोंके सम्बन्धमें भी कियाजाता है। जिस भूमिपर इमारत खड़ीहै उसके कारण प्राप्त होनेवाला करतो पारिभाषिक भूमि-कर है जो उस भूमिकी भली बुरी स्थितिके कारण प्राप्त होता है। नगरोंके उस भागमें जहां कि व्यापार होता है, इत करोंकी मात्रा अधिक होतीहै परन्तु इमारतसे प्राप्त होनेवाला कर इमारत बनाने या खरीदनेके लिए व्यय कीगयी पूँजीका व्याज है, भूमि-कर नहीं। इसीप्रकार खानोंसे प्राप्त कर में भूमि-कर के अतिरिक्त भी कुछ अंश होताहै कारण यह कि खनिज पदार्थको एकबार निकाल लेनेपर खानके मूल्यमें स्थायी रूपमें ह्रास होजाना है। इसकारण खानोंके करमें उनकी स्थिति तथा समृद्धिके लिए प्राप्त कर के अतिरिक्त खनिज पदार्थको निकाल लेनेके लिए भी कुछ भुगतान सम्मिलित होता है। कई भूमिभागोंसे एकही समयमें दो अथवा दो से अधिक प्रकारके कर प्राप्त होसकते हैं। होसकताहै कि कोई भूमिभाग अधिक उत्पादक भी हो, उसकी स्थिति भी सुन्दरही और वहां जलशक्ति भी सहजमें उपलब्ध हो। इसप्रकार की भूमिसे उत्पादन शक्ति, स्थिति और जलशक्ति तीनोंके लिए तीन प्रकारके कर प्राप्त होने लगे।

मजूरी (पारिश्रमिक) और उसके सिद्धान्त

मजूरी की परिभाषा

मजूरी श्रमजीवी द्वारा कियेगये श्रमका मूल्यहै और इसकारण मजूरीका निर्धारणभी श्रमकी पूर्ति और भागके सन्तुलनसे उसीप्रकार होताहै जैसे कि अन्य वस्तुओंके मूल्यका। केवल श्रमबाजारकी उन विशेषताओंको ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है जिनका विवेचन हम बाजारके अध्यायमें करचुके हैं।

मजूरीके विभिन्न सिद्धान्तोंका उल्लेख करनेके पूर्व यह स्पष्ट करदेना आवश्यक है कि अर्थशास्त्री इस शब्दका प्रयोग विभिन्न अर्थोंमें करते हैं। मीट्रिक मजूरीसे उनका अभिप्राय द्रव्यकी उम मात्रासे है जो श्रमजीवीको किसी निश्चित समयतक श्रम करनेके पारिश्रमिकके रूपमें मिलतीहै और वास्तविक मजूरीसे वस्तुओं और सेवाओंकी उम मात्राका जो उम मिलेहुए द्रव्य द्वारा खरीदी जासकती है। इसके अनिश्चित श्रमजीवीको किसी विशेष उद्योग धन्धेमें काम करनेसे कुछ ऐसी सुविधाएं और असुविधाएँ भी प्राप्त होतीहैं जो केवल उसी उद्योग धन्धेसे सम्बन्धित होती हैं। श्रमजीवीकी वास्तविक आयको आकते समय इन सुविधाओं और असुविधाओंकी गणनाभी अवश्य करलेनी चाहिए क्योंकि होसकताहै कि एक उद्योग धन्धेमें दैनिक मजूरी तो अधिक हो परन्तु काम वर्षमें केवल छेमासक ही मिलता हो और दूसरेमें दैनिक मजूरी तो कमहो परन्तु काम वर्षभर मिलता रहता हो। इसकारण पहिले उद्योग धन्धेमें काम करनेवाले की वार्षिक आय दूसरे उद्योग धन्धेमें काम करनेवाले मजूरीकी वार्षिक आयसे कम होसकती है। इसीप्रकार कुछ उद्योग-धन्धोंके स्वामी अपने श्रमजीवियोंके रहनेका तथा उनकी सन्तानके सुचारु शिक्षण इत्यादिवा भी प्रबन्ध कर देते हैं। ऐसे उद्योग-धन्धोंमें मीट्रिक मजूरी कम होनेपर भी वास्तविक आय अधिक होसकती है।

— मजूरी का लोह सिद्धान्त

मजूरीवे लोह सिद्धान्तके जन्मदाता फ्रांसके अधिभूतवादी अर्थशास्त्री थे। तत्कालीन फ्रांसमें कृषक लोगोकी दशा अत्यन्त शोचनीय थी। उनके परिश्रम द्वारा उत्पन्न सम्पत्तिकी मात्रामें उतनी उनके पास शेष छोड़ी जातीथी जो केवल उनके जीवित रहनेके लिए पर्याप्त मात्रा में होतीथी बाकी मानाको सरकार कर लगाकर ललेती थी। अधिभूतवादी अर्थशास्त्रियोंने समझा कि प्रकृतिका नियमही है कि देचारे कृषको को जीवित मान रहनेके लिएही वृत्ति प्राप्त हो। यदि सरकार करभी न लगाय ताभी कृषकोको प्राप्त उनकी उपजके भागमें वृद्धि तो अवश्य होगी परन्तु इसका फलस्वरूप उनकी जन्मदर में भी वृद्धि होगी। इसका कारण कृषकाकी जन-संख्या बढ़ जायगी और प्रत्येक कृषकका प्राप्त होनेवाला भाग फिर पहिलेके समानही होजायगा। जर्मनीके समाजवादी अर्थशास्त्रियोंने इस नियमकी त्रियान्विति को पूजा मूलक आर्थिक पद्धतिमें भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया। उनके मतानुसार जब तक मूल्य भाग और पूर्ति द्वारा निश्चित होनेरहें, तबतक पूजा तथा भूमिपति कुल उत्पत्तिकी मात्रामें श्रमजीवियोंको केवल क्षुधातिवारणके लिए देकर शेष माना को स्वयं ग्रहण करते चलेजायेंगे। इनमें से कुछके मतानुसार मजूरीका केवल दारिद्र्य जीवनको मूल्यमे बचानेके लिए पर्याप्त माना में होना आवश्यक है। उन्होने अपने सिद्धान्तको लोह सिद्धान्तका नाम दिया। कुछका विचारया कि मजूरी नैतिक अथवा दृष्टिमे सम्बन्ध रखनवाली धारणाया द्वारा जो लाभाकी हविषा नया रीति शिवाश्रयपर निर्भर है, निश्चित होती है। इन्होंने अपने सिद्धान्तको वास्तव सिद्धान्त कहना उचित समझा। प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री एडम स्मिथका मजूरीवे लोह अथवा वास्तव सिद्धान्तसे मतभेद था। उसके अनुसार मजूरीका केवल जीवित मान रहनेने मूल्य पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। वह अधिकभी हानिकरनी है परन्तु स्थायी रूप में उसका जीवितमान रहनेके लिए अथर्षाण होना सम्भव नहीं क्योंकि श्रमजीवी और उनके कुटुम्बका जीवित रखना श्रमकी पूर्तिके लिए आवश्यकही है। इसकारण वस्तुआ और सेवाआकी उस मात्राका जिसके द्वारा श्रमजीवी केवल अपने आपको और अपने कुटुम्बको क्षुधा ग्रहणमे सुरक्षित रखसके, एवं सीमा मानलेना चाहिए जिसमें कम मजूरीका होना सर्वेके लिए सम्भव नहीं।

दनमें सहायता देना है जिनका मौद्रिक मूल्य होता है। कोईभी व्यवस्थापक किसी विशेष श्रमजीवीको उसके नियोगके कारण प्राप्त उत्पत्तिसे अधिक मजुरी नहीं देता। हम यह भी जानते हैं कि यदि अन्य उत्पादनके साधनामें परिवर्तन किये बिना श्रमजीविका अधिकधिक मात्रामें नियोग करते चले जायेंगे तो उनके नियोग द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रामें क्रमशः हास होता चला जाता है। इसप्रकार व्यवस्थापक सीमान्त श्रमजीवीको उसके नियोगके कारण प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राके मूल्यसे अधिक मजुरी तो देगा नहीं। परन्तु हम यह भी जानते हैं कि एकही बाजारमें एकही समय पर एकही वस्तुका एक मूल्य होना भी आवश्यक है। इसकारण सब श्रमजीवियोंको वही मजुरी मिलनी जा सीमान्त श्रमजीवी को। इसप्रकार सीमान्त श्रमजीवी द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राके मूल्यसे मजुरी निर्धारित करनेवाले सिद्धान्तको मजुरीका सीमान्त उत्पत्ति सिद्धान्त कहते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें मजुरी सीमान्त श्रम द्वारा उत्पत्तिके मूल्यसे न अधिक हो सकती है और न न्यून। यदि सीमान्त श्रमजीवी द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राका मूल्य मजुरीसे अधिक हो तो व्यवस्थापकके दृष्टिकोणसे एक ओर श्रमजीवीको नियुक्त करनेमें लाभ होगा। यदि मजुरी सीमान्त श्रमजीवीकी उत्पत्तिकी मात्राके मूल्यसे अधिक हो तो एक श्रमजीवीकी उत्पत्तिसे व्यवस्थापक उसके नियोगसे होनेवाली हानिको बचासकता है।

इन सब सिद्धान्तोंमें गुण भी हैं और दोष भी। मजुरीके केवल जीवित मात्र रहने के लिए पर्याप्त मान इनका सिद्धान्त तभी पूर्णतया लाभ हो सकता है जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। भूमिकी अत्यन्त न्यूनता हो और जनसंख्या पूरे वेगसे बढ़ती चली जा रही हो। परन्तु व्यवहारमें इन तीनोंमें से एकभी पूर्णरूपेण अपना प्रभाव नहीं दिखाता पाता है। परन्तु इस सिद्धान्तमें इतना सत्य अवश्य है कि उत्पादन कार्यमें अन्य साधनोंकी अपेक्षा जनसंख्याकी न्यूनताको मजुरी निर्धारित करनेमें विशेष महत्व प्राप्त है। मजुरीकोष सिद्धान्त हमारा ध्यान इस सत्यकी ओर आकृष्ट करता है कि वास्तविक मजुरी अर्थात् वह वस्तुएँ और सेवाएँ जिनका श्रमजीविया द्वारा उपभोग होता है वर्तमान कालमें भियोग्य श्रम द्वारा ही नहीं परन्तु भूतकालमें स्त्रियोग्य श्रमसे भी उत्पन्न की गयी थी। इस सिद्धान्त द्वारा मजुरीके श्रमजीवियोंको प्राप्त होनेकी विधि से भी हम परिचित हो जाते हैं। परन्तु वास्तविक मजुरीपर प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूप से प्रभाव डालनेवाले कारणोंका इस सिद्धान्तसे तनिकभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता।

इसीप्रकार मजूरी कोषको सदैवके लिए स्थिर मानना भी भूल है। राष्ट्रीय धायमें परिवर्तन होनेसे इसमें परिवर्तन होनेरहते हैं। इसका समर्थन इस बातसे होताहै कि आर्थिक दृष्टिसे उच्चतिथील देशोंमें प्रायः मजूरी बढ़ीही रहतीहै क्योंकि श्रमजीवियोंके नियंत्रणके लिए उपलब्ध पूँजीमें वृद्धि होती रहती है। बहुतसे अर्थशास्त्री जो सीमान्त उत्पात्ति सिद्धान्त और मजूरी कोष सिद्धान्तमें एकता सिद्ध करनेका प्रयत्न करतेहैं क्योंकि दोनोंके अनुसार श्रमजीवियोंकी सख्यामें वृद्धि होनेके कारण उनकी मजूरीमें कमी होनेकी सम्भावना है। सीमान्त उत्पात्तिके सिद्धान्तका विवेचन हम अन्य स्थानपर कर चुके हैं। इस स्थानपर केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि श्रमजीवी द्वारा प्राप्त उत्पात्ति केवल श्रमजीवीकी कुशलता परही नहीं परन्तु अन्य साधनोंके कुशल प्रयोग परभी निर्भर रहती है। इन साधनोंमें परिवर्तनके कारणभी श्रमजीवीकी उत्पादन शक्तिमें परिवर्तन होसकता है। कई एक अर्थशास्त्रियोंने श्रमजीवी वर्गको राष्ट्रीय उत्पात्तिका केवल संपाधिकारी मात्र ठहराया है। उनके कथनानुसार अन्य साधनोंके अधिकार पहिलेसे ही निश्चित तथा अग्रिम हैं। उनका भुगतान दिये जानके अनन्तर जो न्यय रहताहै वह श्रमजीवी वर्गका भाग है और कुशलतामें वृद्धिका सम्पूर्ण लाभ इसी वर्गको मिलता है। इस सिद्धान्तको मजूरीया संपाधिकार सिद्धान्त कहते हैं।

मजूरी का आधुनिक सिद्धान्त

आधुनिक अर्थशास्त्री श्रमकी पूर्ति, माग तथा मूल्यमें सन्तुलनके स्थापित होनेको ही मजूरी का पूर्ण सिद्धान्त मानते हैं। किसी विशेष समय पर अन्य साधनोंकी मात्राको परिवर्तनरहित रखनेसे किसी विशेष मूल्य पर श्रमकी सम्पूर्ण पूर्तिका नियाग सम्भव होसकता है। इस मूल्यको सन्तुलन मूल्य कहते हैं। इस मूल्यपर श्रमकी माग और पूर्ति सम होजाती है। इस माग और पूर्तिमें समय समय पर परिवर्तन होते रहतेहैं और इनके कारण नये नये सन्तुलन स्थापित होते रहते हैं।

पूर्तिकी दृष्टिसे किसी उद्योगधन्धेमें किये जानेवाले प्रयास तथा श्रमको और श्रमजीवीके जीवन स्तरको विशेष महत्त्व प्राप्त है। श्रम कार्य करने की अधि, कार्यकी आकृष्टता तथा मात्रा, कार्यस्थानके वातावरण, शिक्षण-व्यय

और नौकरीके नैरन्तर्यसे न्यूनाधिक रोचक होसकता है। जीवन स्तर प्रचलित रुढियोसे निर्धारित होता है। इसीप्रकार मागकी दृष्टिसे उत्पत्ति महत्वपूर्ण-है और उत्पत्ति कार्य कोशल पर निर्भर है। इन सबका उचित स्थानपर विवेचन कर देने में पूर्व यह कह देना आवश्यक है कि माग और पूर्तिके द्वारा निर्धारित मूल्योंका एकसा होनाभी पीगूके मतानुसार आवश्यक नहीं। मजूरीकी प्रवृत्ति किसी विशेष बिन्दुकी ओर नहीं होती। परन्तु वह दो बिन्दुओंके मध्यवर्ती प्रदेशमें अनिश्चित सी रहती है। सीमान्त उत्पत्ति द्वारा निर्धारित व्यवस्थापकोका बिन्दु उस अधिकतम मजूरीका द्योतक है जो व्यवस्थापक देसकते हैं श्रमकी न्यूनाधिक रोचकता तथा जीवनस्तर श्रमिक द्वारा स्वोक्त न्यूनतम मजूरीकी बिन्दुके द्योतक है। सन्तुलनका बिन्दु इन दो बिन्दुओंके मध्यमें कहीपर होगा। उसका स्थान व्यवस्थापको और श्रमजीवियों की सापेक्ष सौदा करनेकी शक्ति पर निर्भर रहता है। श्रमजीवियोंके अधिक शक्तिशाली होनेपर मजूरी उनकी सीमान्त उत्पत्तिके लगभग होगी और व्यवस्थापकाके अधिक शक्तिशाली होनेपर उनके जीवन स्तरपर होनेवाले व्ययके आसपास। अल्पकालमें मजूरी ऊपर बहेगये प्रकारसे निश्चित होती है परन्तु दीर्घकाल में माग और पूर्तिमें परिवर्तनोंके कारण श्रमकी कार्य कुशलतामें और फलस्वरूप मजूरीमें भी परिवर्तन होनेकी सम्भावना रहती है।

प्राचीन धर्मशास्त्री विशेषकर रिकार्ड और उसके अनुयायी ऐसा विश्वास प्रकट करतेथे कि मजूरीमें स्थायी रूपसे वृद्धि होना असम्भव है क्योंकि इस वृद्धिके कारण जनसंख्या और फलतः श्रमकी पूर्तिमें वृद्धि होनेके कारण मजूरी फिर मौलिक स्तरको प्राप्त करलेती है। परन्तु श्रमजीवियों की कार्य-कुशलताके फलस्वरूप उनके मजूरी-स्तर में भी वृद्धि होसकती है। मजूरीमें वृद्धि होनेसे जीवन-स्तर में भी स्थायी रूपसे उत्थष्टता आसकती है और इसके कारण कार्य कुशलतामें और भी वृद्धि होसकती है। उनके मतसे ठीकी मजूरी द्वारा उपलब्ध मितव्ययिताके सिद्धान्तका आविष्कार हुआ। इस सिद्धान्तके अनुसार अधिक मजूरी देनेसे किसी वस्तुके उत्पादन-व्ययमें श्रमके व्ययको कम किया जासकता है क्योंकि अधिक मजूरी देनेसे श्रमजीवियोंकी कार्य-कुशलतामें सापेक्ष रूपमें अधिक उत्थति होनेसे उत्पात्तिकी मात्रामें वृद्धि होगी और इसकारण मजूरी अधिक होतेहुए भी वस्तुकी प्रत्येक इकाईपर होनेवाले व्यय में कमी होगी। मार्शलके विचारमें तो किसीभी व्यवसायमें मजूरी कोशल स्तरसे

उस समय तक कम होती है जबतक कि मजूरीमें वृद्धि करनेमें कार्य कौशल में सापेक्ष रूपमें अधिक उन्नति होती रहती है। यह उन्नति कम मजूरी पानवाले श्रम-जीवियों की मजूरीमें वृद्धि करनेसे तो अवश्यम्भावी है क्योंकि उम वृद्धिका आहार वस्त्र और निवासस्थान आदिको श्रष्ट वनानके लिए प्रयोगमें लाया जाना निश्चितमा ही है। परन्तु श्रमजीवियोंकी सामाजिक स्थितिमें उन्नति होनेके अनन्तर कीगयी मजूरीमें वृद्धि पूरवत् लाभदायक नहीं होती क्योंकि अब इस वृद्धिका अधिकांश भागवित्तम पर खर्च हानकी सम्भावना है। इसप्रकारका व्यय कमसे कम पत्रिक समान प्रत्यक्ष रूपमें उत्पादन शक्तिपर प्रभाव नहीं डालता। स्मरण रह कि मजूरीमें वृद्धि हमारा अभिप्राय मौद्रिक मजूरीमें वृद्धि नहीं किन्तु श्रमिक की वास्तविक आयमें वृद्धि है और यह कई प्रकारमें की जा सकती है। बवल माद्रिक मजूरीमें वृद्धि करनेसे नही। मौद्रिक मजूरी पूरवत् रहने देकर भी श्रमजीवीके लिए अधिक अवकाश श्रष्ट आहार तथा निवासस्थान उत्तम शिक्षा और इसीप्रकारकी अन्य सुविधाओंका जो उनकी वाय क्षमता बढानमें सहायता दें प्रबन्ध करनेका अथवा उस आयमें वृद्धि करनेका ही होगा।

हम स्थानपर हम यह बात जरूरतना आवश्यक समझते हैं कि पूर्णिकी दृष्टिसे मजूरी स्तरक उस समय उन्नतनम हानकी सम्भावना है जबकि किसी विदाय समय पर श्रमकी पूर्ति बवल उतनाही जितनी उस समय उपलब्ध उत्पादनके अन्य साधनसे अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करनेके लिए आवश्यक है। जबतक श्रमकी पूर्ति इस मात्रासे कम होगी ना उसकी मात्राम वृद्धि होकर भी मजूरीकी वृद्धि हानकी सम्भावना है।

जीवन-स्तर और मजूरी

जीवन स्तर और मजूरीमें परस्पर काय कारणके सम्बन्धको सभी अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं परन्तु इनमेंसे कौनसा काय और कौनसा कारण है उसपर मतभेद नही। हम देखही चुके हैं कि जीवन स्तर का कायदुर्गलता का कारण भी मान्यता प्राप्त है और यह भी। इसकारण मजूरी जो उत्पादन शक्तिपर निर्भर रहती है, किसी समयपर जीवन स्तर का फल हो सकती है और किसी अन्य समयपर

कारण। व्यवहारमें भी देखनेमें आताहै कि कई व्यवसायोंमें मजूरी इसकारण अधिक होतीहै कि उनमें काम करनेवाले श्रमजीवियों का जीवन-स्तर और फलस्वरूप कार्यक्षमता अधिक है। परन्तु अन्य व्यवसायोंमें विशेषकर सार्वजनिक पदाधिकारियों को मजूरी इसलिये अधिक दी जातीहै कि उनका जीवन-स्तर उच्च हो। परन्तु वे विद्वान भी जो जीवन-स्तरको 'उत्पादन शक्ति फलन' मजूरीका फल मानते हैं, स्वीकार करतेहैं कि दीर्घकालमें जीवन-स्तर जनसंख्या पर प्रभाव डालकर श्रमकी पूर्तिमें परिवर्तनों द्वारा मजूरीके न्यूनाधिक होनेका कारण होसकता है। यदि जीवन-स्तरको सुगुनित रखनेके लिए श्रमजीवी सन्नति निरोध आदि उपायोसे श्रमकी पूर्तिमें न्यूनता उत्पन्न करनेमें सफल होसके तो श्रमद्वारा प्राप्त भीमान्न उत्पत्तिमें वृद्धि होनेके कारण मजूरीमें भी वृद्धि होसकती है। पाश्चात्य देशोंके श्रमजीवियों ने कुटुम्बको सीमित रखकर जीवन-स्तर पतनकी प्रवृत्तिको रोकनेका प्रयत्न किया है।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मजूरी

उपरिलिखित सिद्धान्तोंकी केवल पूरा प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें सिद्धान्तित सम्भवहै परन्तु श्रम-बाजारमें इस स्थितिका प्राप्ति करनेके पथमें अनेक बाधाएँ हैं। सबसे पहिले गतिशीलताकी ही लेनीजिए। श्रमजीवीको एकस्थानसे दूसरे स्थानपर जानेके लिए, विशेषतः विवाहित श्रमजीवीको, प्रायः उसकी मजूरीमें आजातीत वृद्धिका प्रतीकभनभी उद्यत करनेमें असमर्थ सिद्ध होता है। यातायातके साधनोंमें प्राश्चर्यजनक उत्तिके कारण गतिशीलता करनेपर भी प्रतिस्पर्धाकी मजूरी समीकरण शक्ति पूर्णतया कार्य नहीं करपाती, एक व्यवसायको छोड़कर दूसरों को अपना तो और भी बठिन है। इसीकारण केरतम ने अप्रतिस्पर्धी युद्धोंके सिद्धान्तकी रचना की थी। उसके मतानुसार उत्पादक वर्गका इसप्रकार युद्धमें विभाजित किया जानसता है कि प्रत्येक युद्धके सदस्योंमें परस्पर तो प्रतिस्पर्धा सम्भवहै परन्तु एक युद्ध की दूसरे युद्धसे नहीं। सत्यभी है कि शिक्षित श्रमजीवीकी शिक्षित श्रमजीवीसे अभी प्रतिस्पर्धा हानकती है जब वह स्वयं शिक्षित होजाय। परन्तु शिक्षा प्राप्त करनेकी मुविधाएँ बढ़ जानेपर भी यह कार्य इतना सहज नहीं।

एकही युद्धके सदस्योंमें भी कार्यबौद्धि का एकमात्र होना सम्भव नहीं। कुछ

सदस्य दूमराम अवित्र कुशल होग। यदि सबको एकसी मजूरी दीजाय तो अधिक कुशल श्रमजीवियोंका उनके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे कम मजूरी मिलेगी और कम कुशल श्रमजीवियोंका उनकी सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे अधिक। अधिक कुशल लोग वायस्थापकी घमकी देकर अपनी मजूरी सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे कम करवा लें और कम कुशल लोगोंका व्यवस्थापक उत्पत्तिका भय देकर मजूरी उनके सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे कम करदेगा और इसप्रकार एकही मूल्यके सदस्याकी भिन्न भिन्न मजूरी होगी। इस भिन्नतारीख्यास्या अर्थशास्त्रियोंके इस प्रकार की है कि प्रतिस्पर्धाके कारण मजदूरगलनम श्रमजीवियों को तो एकसी मजूरी मिलती है। यदि इस मजूरीको प्रमाण मान लियाजाय तो अधिक कुशल श्रमजीवी अपनी अपनी कुशलताके अनुसार मजूरी प्राप्त करवानेहें अथवा प्रतिस्पर्धा द्वारा समकुशल श्रमजीवियों की मजूरी एकसी होनेके अनिश्चित उनका कुशलताके अनुसार वर्गीकरणभी होजाता है। या तो फिर एकही मूल्यके सदस्योंमें क्या असम्बन्धित श्रम करनेवालोंमें परास्परमें प्रतिस्पर्धा विद्यमान है नहीं? क्योंकि व्यवस्थापक भी ना निश्चित नहीं करपा कि उन्हें इसप्रकार का श्रम करनेवाले एक और श्रमजीवीकी नियुक्ति करनी चाहिए अथवा उसप्रकार का श्रम करनेवाले की। व्यवस्थापक तथा श्रमजीवियोंमें मगठनके कारणनी श्रमवाजारामें पूर्ण प्रतिस्पर्धा काय कील नहीं होपत्ती। व्यवस्थापक लोग व्यवस्थापक संपाको स्थापित करने श्रमजीवियों को उनके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे कम मजूरी देनेका प्रयत्न करतेहें और यदि श्रमजीवी इस मजूरीपर काम करना स्वीकार करतेहें मजूरी के बढानेके लिए आग्रह करें ता व्यवस्थापक सघ द्वारताल की घोषणा करदेते हैं। व्यवस्थापकोंके पास तो श्रमजीवी सहन करनेके लिए पर्याप्त मात्रामें पूजी होतीहै परन्तु श्रमजीवियोंको यह माभाष्य प्राप्त नहीं होता। उन्हें अन्तर्में व्यवस्थापकोंके भाग भुक्ताहो पडता है। उनके इस दोष-यका दूर करनेके लिए श्रमजीवियोंको श्रमजीवी सघा द्वारा मगठित करनेका प्रयत्न कियागया है। यदि व्यवस्थापक सघ श्रमजीवियोंको उनके सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे कम मजूरी देना निश्चित करनेहें तो श्रमजीवी सघ हडतालकी घोषणा करदेते हैं। मजूरी इसकारण व्यवस्थापक और श्रमजीवी सघोंके तुलनात्मक सघयस निर्धारित होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धासे नहीं। श्रमजीवी सघ अथवा व्यवसायमें नये लोगोंके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगाकरभी पूर्ण

प्रतिस्पर्धाके कारण होनेवाले पूति परिवर्तनोंका नियन्त्रण करनेमें सफलता प्राप्त करलेंते हैं। सुशिक्षित और विशिष्ट श्रमजीवियोंके सघ विशेष रूपसे शक्तिशाली होते हैं।

इस स्थानपर यह कह देना आवश्यक होगा कि व्यवस्थापक और श्रमजीवी सघों की सहायतासे प्रतिस्पर्धा द्वारा निश्चित मजूरी-स्तरसे कम अथवा अधिक मजूरी देने खेनेकी शक्ति सीमित है। मान लीजिए कि व्यवस्थापक सघ अपने उद्देश्यकी पूर्ति करनेमें सफल होजाते हैं। मजूरी प्रतिस्पर्धा द्वारा निश्चित स्तरसे कम होनेके कारण व्यवस्थापकों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। नये व्यवस्थापक नयी सत्याओं को स्वर्णित करदेंगे और श्रमकी मागमें वृद्धि होनेसे मजूरी फिर बढ़जायेगी। यदि श्रमजीवी सघ प्रतिस्पर्धा द्वारा निश्चित मजूरी स्तरमें अधिक मजूरी प्राप्त करलेंते हैं तो व्यवस्थापकोंके लाभमें कमी होगी। इस कमीसे बचनेके लिए उनके पास तीन प्रतिकार हैं। पहिलाना यह कि वे श्रमके स्थानपर पूजोकी प्रतिस्थापना करनेकी चेष्टा करेंगे। श्रमकी मागमें कमी होनेके कारण मजूरी कम होजायेगी अथवा लाभ में कमी आनेसे बहुतसे व्यवस्थापक अधिक लाभप्रद धन्धोंमें पूजोका परिवर्तन कर लेंगे। इसकारण भी श्रमकी मागमें कमी होगी। ऐसामी होसकता है कि व्यवस्थापक उत्पन्न वस्तुके मूल्यमें वृद्धि करके उच्च मजूरीके भारको उपभोक्ताओंके कन्धों पर डालनेका प्रयत्न करें, परन्तु यह तभी सम्भव है जब वस्तु विशेषकी माग लोचरहित हो अन्वया उच्च मजूरीके कारण श्रमजीवियोंकी बेकारीमें वृद्धि होनेकी ही सम्भावना है। इसकारण सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम मजूरी श्रमजीवियोंका हित करनेके स्थान हानिकर होसकती है। वे श्रमजीवी जिनकी सीमान्त उत्पत्तिकी मात्राका मूल्य इसप्रकार निश्चित न्यूनतम मजूरीसे कम है, उत्सृष्ट करदिये जायेंगे और सबके लिए बेकार रहेंगे। परन्तु न्यूनतम मजूरी प्रायः स्वेदपूर्ण श्रम लेनेवाले उद्योग-धन्धोंमें काम करनेवालोंके लिए ही निश्चित कीजाती है। ऐसे उद्योग धन्धों द्वारा निर्मित वस्तुओंके मूल्यमें वृद्धि करना प्रायः सम्भव होता है। इसकारण व्यवस्थापक मजूरीमें वृद्धिका भोभ उन वस्तुओंका उपभोग करनेवालोंके कन्धोंपर डालनेमें सफल होपाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मजूरी श्रमजीवियोंके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्यको उपयुक्त स्तरपर स्थित रखनेके लिए पर्याप्त न हो तो उसमें वृद्धिके कारण उत्पादन-शक्तिमें वृद्धि होनेसे वास्तविक उत्पादन-व्ययमें कमी हो

सकती है और यदि व्यवस्थापन असामान्य लाभ उठाकर श्रमजीवियों का शोषण कर रहा तो भी मजूरी अधिक कर देने पर उनके द्वारा प्राप्त श्रमकी भागमें कमी होनेकी सम्भावना नहीं है।

नये आविष्कार और मजूरी

नये नये आविष्कारों द्वारा उत्पादन विधिमें नाना प्रकार के परिवर्तन आते हैं मजूरी पर मिश्रित सा प्रभाव पड़ता है। आविष्कृत यन्त्र या नये श्रमरी वचन करनेवाले होने हैं या पूँजी की। श्रमकी वचन करनेवाले यन्त्रों के प्रचलित होनेसे प्राप्त श्रमकी मात्रा आवश्यकतासे अधिक हो जाती है और पूँजी की वचन करनेवाले यन्त्रों के प्रचलित होनेसे पूँजी की मात्रा आवश्यकतासे अधिक हो जाती है। पहिली अवस्थामें मजूरी कम होगी और दूसरीमें ज्यादा। अधिकतर यन्त्र, श्रम और पूँजी दोनों की वचन करते हैं। मजूरी पर उन यन्त्रों की प्रतिनिधता प्रतिकूल होगी जो पूँजीसे श्रमकी अधिक वचन करते हैं। दीर्घकालमें आर्थिक प्रगति श्रमजीवियों की वास्तविक मजूरीमें वृद्धि का ही कारण होगी, क्योंकि अधिक उत्पादनकारी यन्त्रों के आविष्कृत होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और इस कारण श्रमजीवियों को मिलनेवाला राष्ट्रीय आय के भागमें निरपेक्ष रूपमें तो अवश्य ही वृद्धि होगी। सापेक्ष रूपमें उनका भाग पहिलेसे भी कम हो सकता है क्योंकि यदि उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि अधिक हो तो पूँजीपति ही हड़प लेंगे तो श्रमजीवियों को थोड़ा ही अन्न प्राप्त होगा।

मजूरी-भुगतान

मजूरी का भुगतान दो प्रकारसे किया जाता है। एक तो समयके अनुसार और दूसरे उत्पत्तिकी मात्राके अनुसार। पहिली अवस्थामें श्रमजीवी को प्रतिघंटे अथवा प्रतिदिनके श्रमकी निश्चित मजूरी दी जाती है और दूसरी अवस्थामें एक ऐसे श्रमजीवी को मजूरी जो न अत्यन्त कुशल हो न अत्यन्त अकुशल, उसके द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राकी सहायतासे निश्चित कर ली जाती है और उसे सामाजिक मानकर अधिक उत्पादन करनेवालों को अधिक और न्यून उत्पादन करनेवालों को कम मजूरी दी

जाती है। भुगतानके इन दोनों ढंगोंको एकत्रितभी किया जासकता है। न्यूनतम मजूरी तो समयके अनुसार निश्चित की जासकती है और फिर उत्पत्तिकी मात्राके अनुसार मजूरी पूरकके रूपमें दी जासकती है। कभी कभी श्रमजीवियों को प्राप्त लाभका कुछ भाग घाट दियाजाता है। यह सब ढंग श्रमजीवियोंको प्रोत्साहन देने के हैं। श्रमजीवियोंको उत्पत्तिकी मात्राके अनुसार मजूरी भुगतानका ढंग प्रायः प्रिय नहीं होता, क्योंकि उनके मतानुसार व्यवस्थापक उन्हें अधिक मजूरी कमाने कर प्रामाणिक मजूरी कम करदते हैं।

हड़ताल अथवा हारतालसे होनेवाली हानिको रोकनेके लिए श्रमजीवियों और पूँजीपतियोंके आपसी झगड़ोंको निपटानका कार्य सौमनस्य स्थापन सभाओं और पंचोंको सौंपा जाता है। पंचनिर्णय उसी दशामें सफल होसकता है जबकि पंच स्वयं दोनों दलोंके विश्वासका पात्र हो।

व्याज और उसके सिद्धान्त

शुद्ध तथा मिश्रित व्याज

पाश्चात्य देशोंमें जब औद्योगिक क्रान्ति हुई तो उद्योगधन्योंके व्यवस्थापक तथा प्रबन्धक प्रायः पूजीपतिही थे। इसकारण तत्कालीन अर्थशास्त्रियों ने व्याज और लाभको एकही समझकर लाभको पूजीसे सम्बन्धित करनाही उचित समझा। परन्तु सन् १८५० में सीमित दायित्व विधानके पाम होनेके अनन्तर सयुक्त पूजी कम्पनियों का प्रादुर्भाव हुआ और पूजी उधार लेकर उद्योगधन्योंको स्थापित करना अथवा व्यापार चलाना सम्भव हो गया। पहिले व्यवस्थापक अथवा उद्योगपति का पूजीपति होना आवश्यक था। अब वह पूजी ऋणके रूपमें प्राप्तकर अपना कार्य चला सकता था। इसकारण व्याज और लाभमें भेद करनेकी आवश्यकता हुई। शुद्ध व्याज का तात्पर्य उस भुगतानमे है, जो उद्योगपति द्वारा पूजीको उत्पादनके साधनके रूपमें सेवा प्राप्त करनेके लिए पूजीपतिको दिया जाता है। वास्तवमें पूजीपतिको किये जानेवाले भुगतानमें शुद्ध व्याजके अनिरिक्त उसके द्वारा प्राप्त कई अन्य सेवाओंके परितोषणका अंश भी सम्मिलित होता है। पूजी ऋणपर देनेके लिए ऋणदाताको कई प्रकारके कष्ट तथा आपत्तियाँ उठानी पड़ती हैं। ऋण का हिसाब किताब रखनेके लिए वहीखाते रखने पड़ते हैं। दिये हुए ऋणकी उद्योग धन्योके सकल न होनेपर अथवा ऋणीके अलकपट के कारण भी न मिल सकनेकी सम्भावना रहती है। इन सब कारणोंसे मिश्रित व्याजकी दर बहुत अधिक होनेपर ऐसाभी होसकता है कि शुद्ध व्याजकी दर बहुत अधिक न हो। ऋणदाता इसप्रकार की आपत्तियोंसे अपने आपकी बीमा कम्पनियों द्वारा सुरक्षित करसकते हैं; परन्तु बीमा कम्पनियोंको दिया जानेवाला अधिक शुल्क शुद्ध व्याजमें सम्मिलित करना आवश्यक होजाता है। यही कारण है कि उस ऋणके व्याजकी दरमें जिसमें कि परिश्रम आपत्ति इत्यादिके अंश सम्मि-

लित होने हैं, भिन्न भिन्न स्थानोपर ही नहीं परन्तु एकही स्थानपर भिन्न भिन्न व्यवसायो और भिन्न भिन्न पुरुषोंके लिए उनकी जोखिम तथा साखके अनुसार भिन्नता होनी है। परिधम और जोखिमके लिए प्राप्त अशको निकाल देनेके बाद शुद्ध ब्याजका पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाकी दशामें एकही बाजारमें एकही होना न्याययुक्त है। कठिनता यह है कि परिधम और जोखिमके लिए प्राप्त अशका पृथक करना इनका सरल नहीं, जितना कि प्रतीत होता है।

ब्याज की दर

समय समय पर शुद्ध ब्याजकी दरमें भी माग तथा पूर्तिमें परिवर्तनोंके कारण परिवर्तन होते रहते हैं। अल्पकालमें इस दरमें परिवर्तन ऋण लेनेवाले व्यवस्थापक इत्यादि लोगोंकी आवश्यकताओं और ऋण देनेवाले बैंको इत्यादिके सामर्थ्यमें दिन प्रतिदिनके परिवर्तनों पर निर्भर रहते हैं। परन्तु दीर्घकालमें इनका सम्बन्ध उद्योग धन्धों द्वारा माग और वास्तविक बचतकी पूर्तिसे होता है। मागमें वृद्धि, जनसङ्ख्या में वृद्धि होनेके कारणभी होसकती है और पूर्तिमें वृद्धि जनसङ्ख्या की चिरकाल तक जीवित रहनेकी आशामें वृद्धि होनेके कारण भी। क्योंकि इस दशामें लोग भविष्यके लिए अधिक बचत करनाही उचित समझेंगे। ऐसाभी विचार प्रकट किया जाता है कि दीर्घकालमें शुद्ध ब्याजकी दरकी गिरनेकी ओरही प्रवृत्ति है क्योंकि पूँजी की पूर्तिमें उसकी मागसे अधिक वृद्धि होती रहती है। प्राचीन अर्थशास्त्रियोंकी भविष्यवाणीके अनुसार यद्यपि इस प्रवृत्तिका युद्ध तथा व्यापारकी मन्दी इत्यादिसे निरोध होता है, फिरभी एकसमय ऐसा आनेवाला है जबकि शुद्ध ब्याजकी दर न्यूनतम होजायेगी। यो तो शुद्ध ब्याजके दरका शून्यावस्थाको प्राप्त करनाभी असम्भव नहीं यदि प्रत्येक व्यक्ति बचत करनेकी ही ठानले और लोगोंकी आवश्यकताओंमें उस वेगसे वृद्धि न हो जिससे कि पूँजीमें, तो होसकता है कि उद्योगपति बिना ब्याजकी पूँजीभी स्वीकार करनेसे इन्कार करदे परन्तु व्यवहारमें कभी ऐसा हुआ नहीं। न्यून दरके कारण बचतकी मात्रामें कमी होजाती है और माग बढ़ने लगती है। पूँजीका बाहुल्य होनेपर लोग इसके लिए अधिक उत्पत्तिप्रद प्रयोग निकाल लेते हैं। नये नये आविष्कारों द्वारा होनेवाले उत्पादन-विधिके परिवर्तनों

द्वारा व्याजकी दरपर प्रभाव पड़ताहै इन आविष्कारोंके प्रयोगके लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। इसकारण पूँजीकी मागमें वृद्धि होनेसे व्याजकी दरमें भी वृद्धि होनेकी सम्भावना रहती है। परन्तु नवीनताया का प्रयुक्त विद्याज्ञान जमी दशामें सम्भवहै, जबकि उनसे अधिक उत्पत्ति प्राप्त होनेकी आशाहो। दीर्घ कालमें उत्पत्तिमें वृद्धि होनेके कारण लोगोंकी पूँजी संचय करनेकी शक्ति बढ़ती है और फलस्वरूप उसकी पूर्तिमें मागमें अधिक वृद्धि होती है। इसलिए होसकताहै कि अन्तमें उत्पादन विधिमें उन्नति व्याजकी दरके गिरनेका कारण बने।

व्याजकी दरवा हमारे आर्थिक अथवा सामाजिक जीवनमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। हम देखचुके हैं कि हमारा भौतिक उत्पादन हमारी राष्ट्रीय आय तथा हमारी उत्पत्ति की मात्रापर निर्भर है। व्याजकी दर कम होनेसे उद्योगपतिको उत्पादन कार्यमें अधिक-अधिक पूँजीका प्रयोग करनेकी प्रेरणा मिलती है और पूँजीका अधिक प्रयोग होनेके कारण उत्पत्तिकी मात्रामें भी वृद्धि होती है। उत्पादक पुरानी उत्पादन विधियोंको तिलाञ्जलि देकर नयी नयी उत्पादन विधियोंको अपनाते हैं। इसके प्रतिरिक्त पुरानी मस्वादाओंकी उत्पत्ति बढ़नेके साथ साथ नयी सस्थाएँ स्थापित होने लगती हैं। व्याजकी वस्तुओंके उत्पादन-व्ययका एक अंश है। इसमें कमी होने से उत्पादन-व्ययमें कमी होतीहै और उत्पादन-व्ययमें कमी होनेसे वस्तुओंके मूल्यमें कमी। फलस्वरूप उनकी माग बढ़तीहै और उसे पूरा करनेके लिए नयी सस्थाओंका स्थापित करना अनिवार्य होजाता है। हम भलीप्रकार जानतेहैं कि उद्योग धन्योंमें काम करनेवाले श्रमजीवियोंको ऐसी वस्तियोंमें रहना पड़ताहै जो मनुष्य तो मनुष्य पशुओंके भी रहनेके योग्य नहीं। व्याजकी दर गिरनेसे उनके लिए अच्छे मकान बनावे जानेकी सम्भावना है। जहातक राष्ट्रीय आयके वितरणका सम्बन्धहै, व्याज की दरके अधिक होनेसे राष्ट्रीय आयका अधिक-अधिक पूँजीपतियोंको प्राप्त होताहै परन्तु इसके लून होनेसे श्रमिकोंको। क्योंकि प्रायः ऐसा देखनेमें आताहै कि जिन कारणोंसे व्याजकी दरमें वृद्धि होतीहै उन्ही कारणोंसे श्रमजीवियोंकी जीविकामें ह्रास होता है। इसकारण व्याजकी दर बढ़नेपर राष्ट्रीय सम्पत्तिके अन्यायपूर्ण वितरण होनेकी सम्भावना है।

शुद्ध व्याजकी सामान्य दर किसप्रकार निर्धारित होतीहै इसकेलिए आजतक विभिन्न सिद्धान्त निर्मित किये जाचुके हैं। हम देखचुके हैं कि शुद्ध व्याज पूँजीका

मूल्य है और अन्य मूल्योकी भांति पूजाकी माग और पूतिके सन्तुलनसे निर्धारित होता है। प्रस्तुत सिद्धान्तोमें से कुछ मागको महत्त्व प्रदान करते हैं और कुछ पूति को।

पूजी की उत्पादनशीलता और व्याज

शुद्ध व्याज इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूजाकी सहायतासे श्रमकी उत्पादन शक्ति में यन्त्र उपकरण इत्यादि उत्पादन सामग्रीद्वारा वृद्धि होती है क्योंकि इन उपकरणों की सहायतासे श्रमिक द्वारा प्रप्त उत्पत्तिकी मात्रा उस समयसे अधिक होती है जब कि उसे यह उपकरण अलभ्य थे। कालें मैगर ने उत्पादन कार्यमें प्राप्त पूजाकी सेवाओंका औरभी गम्भीर विम्लेषण किया है। उनका कथन है कि अन्तमें उपभोग कीजानेवाली वस्तुओंको उत्पन्न करनेके लिए कच्ची सामग्रीको कई एक मध्यवर्ती अवस्थाओंमें से होकर जाना पड़ता है। उदाहरणके लिए कपासको ही ले लीजिए। पहिले इसे कातरर सूत बनाया जाता है, फिर सूतसे कपडा और अन्तमें कपडेसे वस्त्र जिनका उपभोग किया जाता है, पूजाकी सहायतासे उत्पादक लोग इन मध्यवर्ती वस्तुओंको उत्पन्न करनेके लिए लगनेवाले समयकी अवधि तक उनको उत्पन्न करनेके लिए श्रमिकोंको प्रयुक्त करनेकी सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और शुद्ध व्याज पूजा से प्राप्त इस सेवाका शुल्क रूप है। बाहमबावर्क ने भी व्याज दिये जानेके कारण बतलाते हुए मैगर का समर्थन किया है। उनका मत है कि पूजाकी सहायता लेकर किसी वस्तुको मध्यवर्ती अवस्थाओंमें से निकालकर उत्पन्न करनेसे उस वस्तुकी उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होजाती है। इन सिद्धान्तोंकी विशेषता यह है कि ये उत्पादन कार्यमें समयके अक्षका भी समावेश करदेते हैं। पूजाकी सहायतासे वस्तुओंके उत्पादनको विलम्बित किया जासकता है और श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण द्वारा कुल उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि की जासकती है और यही वृद्धि व्याजका माधार है। यदि व्याजका कारण पूजासे प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राको मान लिया जाय तो व्याजका माप पूजाके सीमान्त प्रयोगसे प्राप्त उत्पत्ति होगी। इस प्रकार इन सिद्धान्तोंको व्याजका सीमान्त उत्पत्ति सिद्धान्त कहना अनुचित न होगा। अतः इनमें वही गुण और दोष विद्यमान हैं, जिनका विवेचन हम अन्य स्थानपर करचुके हैं।

उपभोग-व्याक्षेप, वट्टा और व्याज

पूर्तिकी दृष्टिसे व्याजका उपभोग-व्याक्षेप तथा वट्टा सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं। सीनियरका मतथा कि व्याज पूजीपतिको उपभोग-व्याक्षेप द्वारा उपभोगकी तृष्णा तृप्त न करनेके प्रयत्नका पुरस्कार भान है। उपभोग-व्याक्षेप द्वारा वचन करनेके लिए पूजीपतिको कष्ट सहन करना पड़ताहै जिसकेलिए उसको व्याजका प्रसोभन दियाजाना आवश्यक है। सीनियरसे पहिले मिल इत्यादिने उपभोग-व्याक्षेप करनेके लिए कियेगये प्रयत्न को श्रम मानकर इसी सिद्धान्तको श्रम सिद्धान्त का नाम दिया था। उपभोग-व्याक्षेप में कष्टका समावेश होनेके कारण यह आलोचनाकी जानेसगी कि इस शब्दका प्रयोग उचित नहीं; क्योंकि वचतका अधिकांश ऐसे घनीलोगों द्वारा कियाजाता है जो अपनी आयको उपभोग्य सामग्री पर खर्च करती नहीं पाने अंतर इसकारण उन्हें वचत करनेके लिए तनिकभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मार्गसने उपभोग-व्याक्षेपके स्थान पर प्रतीक्षा शब्दको और कैनन ने मचय को प्रयुक्त करनेकी सम्मतिदी है। बाहम शब्दके वट्टा सिद्धान्तका सकेत वर्तमानकाल और भविष्यकाल में परस्पर वट्टेसे है। मनोवैज्ञानिकों का कथनहै कि प्रत्येक प्राणी किसी वस्तुका वर्तमानमें ही उसके पास होना उस वस्तुके भविष्यमें उसे मिलनेसे अधिक श्रेयस्कर समझताहै क्योंकि मनुष्य स्वभावतः वर्तमानमें उपभोगको भविष्यमें उपभोगसे वरीयता देता है। पूजीपति वे लोगहै जिनके पास वर्तमानमें बेचनेके लिए वस्तुएँ हैं क्योंकि उन्हें उनकी वर्तमानमें आवश्यकता नहीं है। माननीजिए उन वस्तुओं का वर्तमानमें मौद्रिक मूल्य १०५ रुपये और वर्ष भरके अनन्तर भविष्यमें केवल १०० रुपये अनुमान कियाजाता है। उस पूजीपतिको ऐसेभी मनुष्य मिल जायगे जिन्हें उन वस्तुओंकी वर्तमानमें ही आवश्यकताहै और जो साल भरके अनन्तर १०५ रुपये देनेका वचन देकर उन वस्तुओंको प्रसन्नता से वर्तमानमें ही ग्रहण करलेंगे पूजीपति को भी देनेमें बाधा न होगी क्योंकि जिन वस्तुओंके मूल्य वह सालभरके अनन्तर १०० रुपये अनुमान करता है उसके उसे १०५ रुपये दियेजाने का वचन दिया जा रहा है। अथवा इसप्रकार कह लीजिए कि वर्ष भरके अनन्तर भविष्य उसके लिए वर्तमान होजायेगा परन्तु तबभी देनेमें उसकी हानि नहीं क्योंकि वर्तमानमें भी तो उसके लिए उन वस्तुओं का मूल्य १०५ रुपये ही है।

इस सिद्धान्तकी इसप्रकार भी व्याख्या की जासकती है। वर्तमानमें पूजीपति से १०० रुपये लेनेके लिए हमें साल भरके अनन्तर उसे १०० रुपयोंसे अधिक लौटा देनेका वचन देना होगा क्योंकि इस सिद्धान्तके अनुसार हाथमें १०० रुपये भविष्यमें मिलनेवाले १०० रुपयोंसे अधिक मूल्यवान् है। उमके अनुमानसे वर्तमानके ६५ रुपये भविष्यके १०० रुपयोंके समहो तो ऋण लेनेवालेको ६५ रुपये लेकरही भविष्यमें १०० रुपये देनेका वचन देना होगा अन्यथा पूजीपति ऋण देनेके लिए उद्यत न होगा।

वाह्यबावर्क के सिद्धान्तसे मिलना जुलता फिन्सरका समयवरीयता सिद्धान्त है। इसके अनुसार समारमें दो प्रकारके मनुष्य मिलते हैं। एक तो वे जो वृद्धावस्थामें पारिवारिक उत्तरदायित्व बढने तथा उपागम शक्तिमें ह्रास होनेके कारण भविष्य में मिलनेवाली आयको अधिक वाञ्छनीय समझते हैं। ऋणों की पूर्ति और उनका पूर्तिमूल्य इन लोगोंकी समयवरीयतासे निर्धारित हागा। कुछ ऐसेभी लोग हागे जो भविष्यमें अपनी आयको बढानेके लिए अथवा अपनी सस्थाओं इत्यादि को विस्तृत करनेके लिए वर्तमानमें ऋण लेनेके इच्छुक हागे। ये लोग ऋणोंकी माग और उनका मागमूल्य निर्धारित करते हैं।

इसप्रकार पूर्तिकी ओरसे व्याजकी दर लोगोंकी मर्च्य करनेकी इच्छा तथा शक्ति पर निर्भर है। जितनीही लोगोंमें यह इच्छा तथा शक्ति प्रबल होगी, उतनीही उस व्याजकी दरभी कम होगी जो लोगों को वचत करनेका प्रलोभन देनेके लिए आवश्यक होगी। दर उतनी होनी चाहिए जो सीमान्त वचत करनेवाले को प्रलोभन देनेके लिए पर्याप्त हो।

मागकी ओरसे यह दर पूजीकी उत्पादनशक्ति पर निर्भर है। उत्पादक लोग अन्य साधनोंके स्थानपर पूजीकी प्रतिस्थापना उस समय तक करते रहते हैं, जबतक कि पूजीकी सीमान्त उत्पत्ति अन्य साधनोंकी सीमान्त उत्पत्तिके सम नहीं हो जाती। परन्तु पूजीका अधिवाधिक प्रयोग होनेके कारण उसकी सीमान्त उत्पत्ति में ह्रास होता चला जाता है और इसकारण व्याजकी दर उतनी होना आवश्यक है जो सीमान्त लेनेवालेको पूजीके न्यूनतम उत्पत्ति करनेवाले भागको ऋणके रूपमें लेनेका प्रलोभन दे सके। सन्तुलन उस दरपर स्थापित होजाता है जिसपर कि पूजी की माग और पूर्ति दोनों सम होजाती हैं।

व्याज और द्रव्य-वरीयता

कीन्स के मतानुसार व्याजकी दर एक शुद्ध द्रव्यात्मक घटना है और द्रव्यकी पूर्ति और मागसे निर्धारित होती है। द्रव्यकी पूर्तिमें उमका तात्पर्य द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रासे है जिसमें सरकारी द्रव्यके अनतिरिक्त बँकोंका मात्र द्रव्यभी सम्मिलित है। द्रव्यकी माग जन-समुदायके उस स्वभावसे निश्चित होती है जिसे उन्होंने द्रव्य-वरीयताका नाम दिया है। प्रत्येक प्राणी अपनी सम्पत्तिके कुछ अंशको या तो द्रव्यके रूपमें रखना इच्छुक होता है या कमसे कम इस रूपमें कि वह स्वेच्छानुसार पुरस्तही उसे द्रव्यके रूपमें परिणत कर सके, इसके उमने चार कारण बताये हैं

(१) आय—उद्देश्य, प्रायः मनुष्यकी आय तो निश्चित विधियोंपर प्राप्त होती है परन्तु व्यय दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। इसकारण कुछ द्रव्य सदैव उसे अपने पास रखना पड़ता है। (२) व्यापार—उद्देश्य, व्यापार में द्रव्यका व्यय तो पहिले करना पड़ता है और प्राप्ति धन धन विनी हानिके अनन्तर होती रहती है। इस कारण व्यापारी लोगोंको कुछ सम्पत्ति द्रव्यके रूपमें रखना आवश्यक होजाता है। (३) पूर्वावधारणा—उद्देश्य, कई व्यय प्रसम्मात् करन पड़जाते हैं। कभी कभी व्यापारी लोगोंको अकस्मात् लाभ प्राप्त करनेके अवसर मिलजाते हैं। द्रव्यका अभाव होनेपर ऐसे अवसरोंपर हानिकी सम्भावना रहा करती है। (४) सट्टेका उद्देश्य—सट्टा करनेके लिए भी द्रव्यके रूपमें सम्पत्ति रखना अनिवार्य सा ही है।

इन उद्देश्योंकी शक्ति आयकी मात्रा परही निर्भर नहीं बरन् इस बातपर भी निर्भर है कि वह आय कितने कितने समयके अनन्तर प्राप्त होती है। आर्थिक व्यवस्थाकी प्रगति मन्दी अथवा चढ़ाईकी ओर होनेका भी इस शक्तिसे घनिष्ठ सम्बन्ध है।

कीन्स के मतानुसार व्याजकी दर पूँजीका वह मौद्रिक मूल्य नहीं है जो पूँजीकी उत्पादन-शक्ति द्वारा निर्धारित माग और उपभाग-व्याप्ति द्वारा कृत वचन प्रत्यापूर्तिमें सन्तुलन स्थापित करता है परन्तु वह मौद्रिक मूल्य है जो सन्तुलन तो स्थापित करता है परन्तु यह सन्तुलन लोगोंकी द्रव्यके रूपमें सम्पत्तिको अपने आधीन रखनेकी इच्छाके कारण द्रव्यकी माग और द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रामें होता है। इसका अर्थ

यह हुआ कि यदि व्याजकी दर कम होजाये तो लोगोको अपनी सम्पत्तिका द्रव्यके रूप में रखनेकी इच्छा को पूरा करनेके लिए कम हानि उठानी पड़ेगी। अथवा सम्पत्ति का द्रव्यके रूपमें न रखकर उद्योगपतियोंको ऋण पर देनेसे अपनी इच्छा को दवाने के लिए उन्हें व्याजके रूपमें कम पुरस्कार मिलेगा। इसकारण वे द्रव्यके रूपमें अपनी सम्पत्ति रखना उचित समझेंगे। फलतः द्रव्यकी माग द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रा से अधिक होगी। इसके विपरीत यदि व्याजकी दर बढ़जाय तो उपलब्ध द्रव्यकी कुछ मात्रा ऐसी शेष रहेगी जो कोईभी अपने पास द्रव्यके ही रूपमें रखनेके लिए उद्यत न होगा। इससे स्पष्ट है कि कीन्सके अनुसार द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रा द्रव्यकी पूर्ति है और सम्पत्तिकी वह मात्रा जो लोग द्रव्यके रूपमें रखनेके इच्छुक हो, द्रव्यकी माग है और इन दोनोंमें व्याजकी दरसे सन्तुलन स्थापित होता है।

ध्याज और पूँजी की उत्पादनशीलता

इस स्थानपर यह उल्लेख आवश्यक होगा कि कीन्सके सम्पत्तिको द्रव्यके रूपमें रखनेके पहिले उद्देश्यकी सहायतासे कीन्ससे पहिलेही वेकस्टीडने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न कियाया कि ध्याज प्राप्त करनेके लिए पूँजीका उत्पादक होना आवश्यक नहीं है अर्थात् पूँजी उत्पादन-शक्तिसे वंचितभी होती तोभी उसे ऋणपर देनेके लिए व्याज प्राप्तही होता। इस ससारमें दो प्रकारके मनुष्य मिलते हैं। एकतो वे जिन्हें आय तो निश्चित समयपर प्राप्त होती है परन्तु व्यय दिन प्रतिदिन अथवा अनियमित ढंगसे भिन्न भिन्न अवसरोपर करना पड़ता है। दूसरे वे जिनको जीवनभर अपने व्ययको चतानेकी सामग्री आरम्भसे ही द्रव्यके रूपमें लभ्य होती है। पहिले प्रकारके मनुष्योंकी जीवनभर में उपाजित आय जीवनभर किये जानेवाले व्ययके सम होसकती है परन्तु अल्पकालमें व्यय आयसे अधिकभी होसकता है। इसकारण अल्पकालमें उन्हें ऋण लेनेकी आवश्यकता रहती है। दूसरे प्रकारके मनुष्य जीवन भरकी आवश्यकताओंको सन्तुष्ट करनेके लिए वस्तुओंको तो खरीद नहीं सकने इस कारण उनके पास कुछ द्रव्य बेकारही पड़ा रहता है। पहिले प्रकारके मनुष्यों को ऋण लेनेमें साध है और दूसरे प्रकारके मनुष्योंको ऋण देनेमें यदि लाभ नहीं तो कमसे कम हानिभी नहीं है। यही कारण है कि प्रायः ऋण देनेवालो की देनेकी इच्छा

उतनी तीव्र नहीं होती है जितनी कि ऋण लेनेवालोंकी लेनेकी इच्छा। इन दोनों इच्छाओंकी तीव्रताको सम करनेके लिए लेनेवाले देनेवालोंको कुछ प्रलोभन देते हैं। इसी प्रलोभनका नाम व्याज है।

व्याज इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूजोकी माग पूजोकी पूति से सदैव अधिक रहती है। व्याज पूजोका मूल्य होनेके कारण उपलब्ध पूतिको अथवा कि युक्त माग के सम कर देता है। पूतिकी तुलनात्मक न्यूनताके कारण पूजोका किसी विशेष उद्देश्यके लिए नियोग करनेसे उस पूजोका अन्य उद्देश्योंके लिए नियोग असम्भव हो जाता है। इसकारण व्याज द्वारा यह निर्णय करनेमें सहायता मिलती है कि पूजोका किन उद्देश्योंके लिए नियोग किया जाना चाहिए। आर्थिक दृष्टिसे प्रतिस्पर्धी नियोगों में से वह नियोग श्रेष्ठतम समझा जायगा जिसमें पूजो लगानेसे अधिकतम लाभ प्राप्त होनेकी आशा हो। सामाजिक दृष्टिसे भी वह नियोग श्रेष्ठतम है या नहीं यह निर्णय करना अर्थशास्त्रका नहीं बल्कि समाजशास्त्र इत्यादि अन्य शास्त्रोंका विषय है।

लाभ

शुद्ध और मिश्रित लाभ

उत्पादन कार्यको सुचारु रूपसे चलानेके लिए व्यवस्थापको अथवा उद्योगपतियों की आवश्यकता होती है। ये लोग अन्य उत्पादनके साधनोंको एकत्रित करके उत्पादन कार्यमें सलग्न करने हैं। उत्पत्तिकी भविष्यमें होनेवाली भागका अनुमान लगाकर उसके आधारपर उत्पत्तिकी मात्रा निर्दिष्ट करते हैं। आर्थिक क्षेत्रमें अगुओंका रूप धारण करके नयी उत्पादन-विधियोंका प्रयोग करते हैं और नयी नयी वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। इन सब कारणासे उन्हें ऋणपर पूँजी देनेवालोंसे अधिक जोखिम उठानी पड़ती है जिसके पुरस्कारके रूपमें उन्हें लाभ प्राप्त होता है। अर्थ-शास्त्री शुद्ध लाभ और मिश्रित लाभमें भेद करते हैं। मिश्रित लाभमें शुद्ध लाभ के अनतिरिक्त व्याज तथा मजदूरीके अंशभी सम्मिलित होते हैं। कई एक उद्योगपति अपने उद्यममें निजी पूँजीका भी प्रयोग करते हैं। इस पूँजीको यदि वे ऋणमें देदेते तो उन्हें व्याज प्राप्त होता। इसकारण उद्योगपतियोंको प्राप्त कुल लाभमें से इस व्याजकी मात्राको निकाल देना आवश्यक है। इसीप्रकार प्रत्येक उद्योगपतिको उद्यमके निरीक्षण आदिका कार्य करनाही पड़ता है। यदि उसका अपना उद्यम न होता तो वह प्रबन्धकके रूपमें इस कार्यके लिए वेतन पाता। इसकारण कुल प्राप्त लाभमें से उद्योगपतिको प्रबन्धकके रूपमें मिल सकनेवाले वेतनको भी निकाल देना चाहिए। शेष बची हुई मात्रा उद्योगपतिके जोखिम उठाने तथा उद्योग-साहम करने का पुरस्कार है और उसे शुद्ध लाभ कहा जाता है।

लाभ का भूमि-कर सिद्धान्त

प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री वाकरका मतथा कि लाभकी मात्रा ठीक उसीप्रकार

निश्चित होती है जैसे भूमि-कर की। किसी विशेष उद्योग धन्धे में होने वाला उत्पादन-व्यय उस उद्योग धन्धे की सीमान्त सस्था के उत्पादन-व्यय से निश्चित किया जाता है और इस उत्पादन व्यय के सम मूल्य पर उत्पन्न वस्तु बाजार में बिकती है क्योंकि सीमान्त सस्था सीमान्त भूमि के समान केवल अपने उत्पादन-व्यय को ही पूरा कर पाती है। सीमान्त सस्था से ऊपर की सस्थाओं की उनके व्यवस्थापकों में अधिक योग्यता के कारण उत्तम व्यवस्था होनी है और उनके उत्पादन-व्यय प्रत्येक व्यवस्थापक के कार्यक्षमता के अनुसार कम होते हैं। वे सीमान्त सस्था के उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित मूल्य पर भी वस्तु बचकर उत्पादन की बचत के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं। अपने मन्त्री पुष्टि के लिए वावरने एक ऐसे व्यवस्थापक की वन्दना की है जिसे सन्निव भी लाभ प्राप्त न होता हो। ऐसे लोग व्यर्थ ही उत्पादन कार्य में सलग होने का कष्ट लेते हैं। परन्तु उनकी सस्थाओं का आर्थिक दृष्टि से महत्त्व है क्योंकि उस उद्योग धन्धे द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का मूल्य इसी प्रकार की सस्थाओं के उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होता है। इसी कारण वावरने इन सस्थाओं को सीमान्त सस्था माना है। इनमें ऊपर व सस्थाएँ जिनको मार्शल ने प्रतिनिधि सस्था कहा है। यह सस्था न तो वावर की सीमान्त सस्था के समान ऐसी ही होती है कि इसके व्यवस्थापकों को कुछ लाभ ही प्राप्त न हो और न बड़ी बड़ी समृद्ध सस्थाओं के समान ऐसी कि इसके व्यवस्थापक बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हों बल्कि ऐसी जो दीर्घकाल से तो स्थापित हो, सामान्य योग्यता से उसका प्रबन्ध हो रहा हो, सामान्य उत्पादन-विधि को प्रयुक्त कर रही हो और अधिक मात्रा में उत्पन्न करने की सामान्य मितव्ययिता इसे प्राप्त हो रही हो। ऐसी सस्थाओं में ऊपर वे सस्थाएँ होती हैं जिनके व्यवस्थापक अत्यन्त योग्य होते हैं और अपनी योग्यता की सहायता से बड़ बड़े लाभ प्राप्त करते हैं और इनसे भी ऊपर उन दिव्यताओं की सस्थाएँ होती हैं जिनके लाभ की सीमा बाधना ही असम्भव है।

हम देखते हैं कि बाजारमात्र तो निश्चित होता है सीमान्त सस्था के उत्पादन-व्यय से। इस कारण सीमान्त सस्था से ऊपर की सस्थाएँ उन व्यवस्थापकों की योग्यता के अनुसार ठीक उसी प्रकार लाभ उठाती हैं जिस प्रकार सीमान्त भूमि में ऊपर की भूमिओं को उनकी उत्पादनशक्त के अनुसार भूमि-कर प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार लाभ की योग्यता का कर कहना अत्युचित न होगी।

इस सिद्धान्तके अनुसार वस्तुओंका मूल्य निर्धारित करनेमें भूमिकरके समानही लाभका तनिवभी हाथ नहीं क्योंकि मूल्य निर्धारित करनेवाली सीमान्त सस्याके उत्पादन-व्ययमें लाभका अभाव होता है। इसके विपरीत लाभ स्वयं मूल्यसे निर्धारित होता है, क्योंकि मूल्य गिरनेसे सीमान्त सस्याए तो बन्द होजाती हैं और उनका स्थान थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त करनेवाली सस्याए ग्रहण कर लेती हैं। परोक्ष रूप में भलेही लाभका मूल्योपर प्रभाव पड़ सकना सम्भव होसकता है। क्योंकि अपनी योग्यताके कारण अधिक लाभ उठानेवाले व्यवस्थापक उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि करके उत्पादन-व्ययमें कमीशः हास होनेकी सम्भावनाका लाभ उठानेके उद्देश्यसे अपनी विप्री वढानेके लिए सीमान्त सस्याके उत्पादन-व्ययसे कम मूल्यपर बन्नु बेच सकते हैं।

प्राचीन अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार वाकरकी लाभसे वञ्चित सस्याका अस्तित्व असम्भव था क्योंकि कोई भी व्यवस्थापक तबतक व्यर्थही अपनी योग्यता एवं धन का व्यय करनेके लिए उद्यन न होगा जबतक कि उसे किसी विशेष उद्योग धन्धेमें प्राप्त होनेवाले औसत लाभके मिलनेकी आशा न हो। इसके अतिरिक्त उनका यह भी विश्वास था कि किसीभी व्यवस्थापकको किसीभी उद्योग धन्धेमें उसमें प्राप्त होनेवाले औसत लाभसे अधिक लाभ प्राप्त नहीं होसकता। अल्पकालमें भलेही कोई व्यवस्थापक इम औसत लाभसे न्यून अथवा अधिक लाभ प्राप्त करले परन्तु दीर्घकालमें औसत लाभसे कम लाभ प्राप्त करनेवाली सस्याए स्वयंही बन्द हो जायेंगी और यदि प्राप्त लाभ औसत लाभसे अधिक होगा तो पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें नयी सस्याए उम उद्योग धन्धे की ओर आकर्षित होगी जिनकी स्थापनासे लाभ पुनः अपने प्राकृतिक स्तरपर आजायेगा। इसप्रकार नयी सम्प्राप्तीकी स्थापना अथवा पुरानी सस्याओंका लोप होनेसे प्रत्येक उद्योग धन्धेमें मिलनेवाले औसत लाभ में एक सन्तुलन सा स्थापित होजायगा।

इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक उद्योग धन्धेमें कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होनेकी आशा से प्रेरित होकर व्यवस्थापक उन धन्धेकी ओर आकृष्ट होंगे परन्तु यहभी सत्य नहीं कि उस उद्योग धन्धेमें मिलनेवाले औसत-लाभका स्तर इतना स्थिर होगा जितना कि प्राचीन अर्थशास्त्री मानते थे। और भिन्न भिन्न सस्याओंके लाभमें उतार चढाव तो स्वाभाविक ही हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य अथवा औसत लाभ

का निश्चय करना इतना भरल नहीं जितना कि प्राचीन अर्थशास्त्री समझते थे। व्यवस्थापकों की बुद्धि एवं योग्यता में अन्तर होनेके कारण मित्र मित्र सस्थाओंके लाभोंमें अन्तर होना आवश्यक सा है। इस कठिनाई को मार्शल ने प्रतिनिधि सस्थाकी कल्पना द्वारा दूर करनेकी चेष्टाकी थी। इस सस्थाको प्राप्त होनेवाले लाभको उस उद्योग धन्धेमें मिलनेवाला सामान्य लाभ मानना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह कह देना अनुचित न होगा कि बाबरकी लाभ-वचित सस्थाका अस्तित्व भी इतना असम्भव नहीं जितना कि प्राचीन अर्थशास्त्री और उनके अर्वाचीन अनुयायी मानते हैं। किसी सन्ध्यामें एकबार नियुक्त पूजोक्त, विद्योक्त, स्थायी रूपमें नियुक्त पूजोक्त किसी अन्य उद्योग धन्धेमें परिवर्तन कठिन होजाता है। इसकारण लाभ के अभावकी स्थितिमें भी कई सन्ध्याएं उत्पादन कार्य बन्द नहीं करती। इसी प्रकार कई व्यवस्थापक केवल अपनी नियुक्त पृथीपर ध्याज प्राप्त करकेही सन्तुष्ट होजाते हैं। इसके अतिरिक्त यहभी आवश्यक नहीं कि कोई सस्था मर्दवके लिए लाभ-वचिन सस्थाही रहे। प्रत्येक उद्योग धन्धेमें नित नयी सन्ध्याएं स्थापित होती रहती हैं। बहुतसी सन्ध्यायी सक्टा से अस्त होजाती हैं, बहुतसी पतनोन्मुख होती हैं। ऐसी सन्ध्यायाको लाभ प्राप्त नहीं होता परन्तु कालांतरमें इनमें से बहुतसी कुछ लाभ उपार्जन करने योग्य होजायेंगी और अन्य अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगी और उनका स्थान अन्य सन्ध्याएं ग्रहण करलेंगी।

किन्तु मार्शलके अनुसार किसी उद्योग धन्धेमें पूजोक्त विनियोग उस उद्योग धन्धे की प्रतिनिधि-सन्ध्याके उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होता है। इस उत्पादन-व्यय से उस प्रतिनिधि सन्ध्याको प्राप्त होनेवाला सामान्य लाभभी सम्मिलित होता है और मूल्यभी इसी प्रतिनिधि सन्ध्याके उत्पादन व्यय द्वाराही निर्धारित होता है। इसकारण सामान्य लाभभी मूल्य में शामिल होता है। प्रतिनिधि सन्ध्यासे अधिक कुशल सन्ध्याओंको प्राप्त अतिरिक्त लाभका मूल्यमें समावेश सम्भव नहीं।

जोखिम और लाभ

एक और सिद्धान्तके अनुसार शुद्ध लाभ केवल वह पुरस्कार है जो उद्योगपतिको सन्ध्या स्थापित करनेकी जोखिम उठानेके लिए प्राप्त होता है। नाइट ने जोखिम

भी दो प्रकारकी बताई है। एकनो वह जोखिम जिसके कारण होनेवाली हानिकी गणना गणितशास्त्रके नियमा द्वारा निश्चित रूपसे की जासकती है और इस कारण उससे बचनेके लिए बीमा इत्यादि साधनोका उपयोग किया जासकता है। बीमाके कार्यके लिए विशेष सस्थाए होतीहैं और उनको दियागया अधिक शुल्क व्यवस्थापकके उत्पादन-व्ययमें सम्मिलित करलिया जाता है। परन्तु दूसरी जोखिम इस प्रकारकी होती है कि उसके कारण होनेवाली हानिकी गणना असम्भव होतीहै क्योंकि मनुष्य त्रिकालदर्शी तो है नहीं कि भविष्यमें होनेवाली सब घटनाओं का पूर्णरूपसे वर्तमान में ही ज्ञान प्राप्त करले। इस प्रकारकी जोखिमसे होनेवाली हानि की गणना करनेमें गणितशास्त्रभी असमर्थ है और इसकारण उससे बचाव का कोईभी साधन नहीं। नाइटने इस प्रकारकी जोखिमको अनिश्चितताका नाम दियाहै और उनका मतहै कि शुद्ध लाभ व्यवस्थापकको इस अनिश्चितता रूपी जोखिम उठानेका पुरस्कार मात्र है। यदि अनिश्चिततान होती तो लाभका अभाव होता।

व्याज का प्रगतिशील सिद्धान्त

इस सिद्धान्तका जन्मदाता प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री क्लार्क था। उसने अर्थ व्यवस्थाके दो भेद किये हैं। एकतो स्थिर और दूसरा प्रगतिशील। स्थिर अर्थ-व्यवस्था वहहै जिसमें जनमर्या और पूजीमें किसीभी प्रकारकी वृद्धि नहीं होती; नये आविष्कारोका अभाव रहता है; उत्पादन रीतिया ज्यों की त्यो रहती हैं। संश्लेषमें स्थिर अर्थ-व्यवस्थामें परिवर्तनोका अभाव रहता है। यद्यपि ऐसी व्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थितिमें उत्पादनके साधन गतिशील होनेहैं फिरभी गति का अभाव रहताहै क्योंकि प्रत्येक व्यवसायमें श्रम और पूजीकी उत्पादन-शीलता सम होती है। इस प्रकार की स्थिर अर्थ-व्यवस्था में क्लार्कके मतानुसार शुद्ध लाभका अस्तित्व असम्भव है और सम्पूर्ण उत्पत्ति श्रम और पूजी द्वाराही होतीहै और श्रमजीवियों एव पूजीपतियोंमें उसका वितरण होजाता है। ऐसी स्थितिमें लाभ का प्रश्नही नहीं उठता। पूर्ण प्रतिस्पर्धाके कारण मजूरी और व्याज श्रम और पूजी द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिके बराबर होते हैं। श्रमजीवियों और पूजीपतियों

में वितरित होनेके अनन्तर राष्ट्रीय आयका कोईभी अतिरिक्त भाग शेष नहीं रहता जिसका कि लाभके रूपमें वितरण किया जा सके। परन्तु क्लार्क की मतया कि कोईभी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं होती। जनसंख्या और पूँजीमें वृद्धि, उत्पादन रीतियोंमें उन्नति, औद्योगिक व्यवस्थाने रूपोंमें और उपभोगनाओंकी आवश्यकताओंमें परिवर्तन प्रत्येक अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाये रखनेके मुख्य कारण है। उद्योगपति का कर्तव्य अथ-अर्थव्यवस्था में होनेवाले इन्हीं परिवर्तनोंसे सम्बन्धित है। उसे अपने कर्तव्य-पालनके लिए साधारण धर्मिकोंके समान धर्म नहीं करना पड़ता बल्कि उसका अस्तित्व धर्म और पूँजीको उत्पादनशील बनानेके लिए आवश्यक होता है। धर्म और पूँजीको उचित अनुपातमें संयोजित करनेसे ही उनकी उत्पादनशीलतामें वृद्धि होजाती है और यही बड़ी-टूई उत्पत्ति उद्योगपति को उसके साहसके बदले लाभके रूपमें प्राप्त होती है। उदाहरणके लिए नये नये आविष्कारों को उत्पादन कार्यमें प्रयुक्त करनेके लिए साहसकी आवश्यकता होती है। जो उद्योगपति किसी नवीनताका सर्वप्रथम प्रयोग करनेके लिए उद्यत होजाता है वह उस प्रयोग द्वारा प्राप्त अधिक उत्पत्तिकी मात्राको लाभके रूपमें पाता है। शर्न, शर्न अन्य लोगभी उस नवीनताका प्रयोग करने लगते हैं और उसे प्राप्त होनेवाला लाभ न्यून अथवा शून्य होजाता है।

द्रव्य

द्रव्य की आवश्यकता

आधुनिक आर्थिक व्यवस्थामें द्रव्यका एक विशेष स्थान है। यह कहना अति-शयोक्ति न होगा कि यदि हमारे बीचसे द्रव्यको उठालिया जाय तो हमको अपने आर्थिक कार्योंके सम्पादनमें बहुत कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा और आर्थिक व्यवस्थाभी अव्यवस्थित होजायगी। कुछ साधारण उदाहरणोंसे हम इस स्थितिको समझा सकते हैं। अनेक लोग अपनी आजीविकाके लिए वृत्ति करते हैं और उनको द्रव्यके रूपमें आय मिलती है। यदि द्रव्यका प्रयोग समाजमें न होता तो यह आय वस्तुओंके रूपमें दी और लीजाती। इससे लेनवाले और देनेवाले दोनोंको परेशानी उठानी पड़ती। यदि कोई मजदूर कपड़ेके कारखानेमें कार्य करता है तो कारखानेका मालिक उसकी मजदूरी कपड़ेके रूपमें दे सकता है। परन्तु मजदूरको कपड़ेके अतिरिक्त भोजन की सामग्री, रहनेका स्थान इत्यादि अनेक वस्तुओंकी आवश्यकता है। अतएव उसको अतिरिक्त कपड़ेके बदले इन वस्तुओंको प्राप्त करना पड़ेगा। स्थिति और भी द्विपक्ष होजाती है जबकि हम एक अध्यापकका मामला लेते हैं। विश्व विद्यालय का अध्यापक कारखानेके मजदूरकी तरह कोई ऐसी वस्तु तो बनाता नहीं जो उसको पारिश्रमिकके रूपमें दी जा सके। तब फिर रजिस्ट्रार प्रथमा कोषाध्यक्ष किस प्रकार उसको पारिश्रमिक दे। यही होमकला है कि विद्यार्थियोंसे कहा जाय और सरकारसे भी प्रार्थना की जाय कि वह भिन्न भिन्न वस्तुओंके रूपमें फीस और आर्थिक सहायता विश्वविद्यालयोंको दें और इन्हींका किसी प्रकार अध्यापकोंमें तथा विश्व-विद्यालयके अन्य कार्यकर्ताओंमें वितरण हो। द्रव्यके प्रयोगसे इसप्रकार की कठिनाइया उत्पन्न नहीं होती हैं। इसीप्रकार उत्पत्तिके कार्योंके लिए अनेक आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है। यदि उत्पात्ति का क्षेत्र बढ़ा हो तो इन साधनोंकी बड़ी मात्रा

में आवश्यकता होती है। द्रव्यके द्वारा इन साधनोंके इकट्ठा करनेमें बहुत सुगमता होती है। यदि द्रव्य नहीं तो उत्पादका को कच्चा माल, मशीन, मजदूर इत्यादि साधनोंको उपयुक्त मात्रामें कारखानामें एकत्र करनेमें बहुत असुविधा होती। जब हम बाजार जानते तो अपने माथ द्रव्य खोजते हैं और भिन्न वस्तुओंके भिन्न भिन्न परिमाणमें माप लें हैं। यदि द्रव्य नहीं तो हम कार्यमें बड़ी रकावट पैदा होजाय। इस प्रकार हम आजकल अपनी वचनभी द्रव्यके रूपमें करते हैं और भविष्यमें इसके बदले आवश्यक वस्तुएं लेते हैं। द्रव्यके अभावमें हमको इस प्रकार की वस्तुओंका ही संचय करना पड़ता। इनको रखरखा प्रयत्न करना पड़ना, टूट, फूट, सड़ने-गलने और बिगड़नेसे बचाना पड़ता अर्थात् नडी भ्रष्ट और उनभनमें पक्षना पड़ता। हमलांग आजकल द्रव्यके प्रयोगके इतने अभ्यस्त हुए हैं कि हम अनुमानही नहीं कर सकते हैं कि द्रव्यके बिना हमको कितनी असुविधाएं होती। आर्थिक विकासमें एक समय था, जबकि समाजमें द्रव्य नहीं था और आर्थिक कार्य बिना इसकी सहायता के हाथ थे।

वस्तु विनिमय की प्रथा

हम इस बात की आर्थिक व्यवस्थाकी कल्पना कर सकते हैं जिसमें द्रव्यकी आवश्यकता हो न पड़े। यदि किसी कुटुम्बक लोग स्वयंही अपनी आवश्यकताओंकी वस्तुओं का उत्पन्न करें तो उनका द्रव्यकी आवश्यकता नहीं जान पड़ेगी। इसी प्रकार समाजकी इस प्रकारकी व्यवस्था होजाय कि समाजके प्राणी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार राज्यके अलग-अलग उद्योग करें और राज्यके द्वाराही उनकी आवश्यकताओंके वितरण हो तोभी शायद द्रव्यकी आवश्यकता न जान पड़े। वास्तवमें इस प्रकारकी आर्थिक व्यवस्थाओंके उदाहरण बहुत कम पाये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना कुटुम्ब अपनी आर्थिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए कम या अधिक मात्रा में दूसरोंपर निर्भर रहता है। उसको अपनी वृत्ति भववा वस्तुओंके बदले दूसरोंकी वृत्ति और वस्तुएं प्राप्त करनी पड़ती हैं। इस प्रकार के धातन-प्रदानको हम विनिमय कहते हैं। द्रव्यके बिना जो विनिमय होता है उसको अद्वय-वदलकी प्रथा कहते हैं। प्राचीनकाल में इसी प्रथा द्वारा लोग एक दूसरेसे वस्तुओं अथवा सेवाओंका

विनिमय करके अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति करलेते थे। आजभी अनेक असभ्य जातियाँ हैं जिनमें द्रव्यका चलन नहीं है और जो कुछभी विनिमयका कार्य उनमें पायाजाता है वह अदल बदलकी प्रथा परही निर्भर है। खेतीके कार्यमें कहीं कहीं अभी तक मजदूरको अनाजके रूपमें पारिश्रमिक दियाजाता है। विदेशी व्यापारमें भी राज्योंके बीच आपसमें इसप्रकार की स्वीकृतियाँ होती हैं जिनके अनुसार एक राज्यकी कुछ वस्तुएँ किसी निश्चित परिमाणमें दूसरे राज्यकी अन्य वस्तुओंके निर्धारित परिमाणमें बदल लीजाती हैं।

विनिमय का माध्यम

यदि हम अदल-बदलकी प्रथाका विश्लेषण करें तो हमको इसमें अनेक कठिनाइयाँ और असुविधाएँ दिखलाई देनी हैं। एक कठिनाई यह है कि अदल-बदलकी क्रियाके चरितार्थ होनेसे पहिले इस प्रकारके दो व्यक्तियोंका मिलन हो जिनको एक दूसरेकी वस्तुओंकी आवश्यकता हो। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि किसी किसानके पास गेहूँ है और वह उसके बदलेमें कपड़ा चाहता है। अब उसको एक ऐसे व्यक्तिको ढूँढना पड़ेगा जिसको गेहूँकी आवश्यकता हो और जिसके पास देनेके लिए अतिरिक्त कपड़ा हो। इस कार्यमें समयकी बरबादी होती है और परेशानीभी होती है। प्राचीनकालमें बड़े बड़े मेलोंके लगनेका शायद एककारण यहभी रहा हो कि मेलेमें सभी तरहकी वस्तुएँ एक स्थानपर इकट्ठा होती हैं और इससे अदल बदलके कार्यमें सुविधा होती है। अबहम यह बतानेकी चेष्टा करेंगे कि द्रव्यके प्रयोगसे किस प्रकार इस असुविधाको दूर किया गया है। पूर्वलिखित उदाहरणका विस्तार करतेहुए कल्पना कीजिए कि जिस जुलाहेके पास कपड़ा है उसको किमानके गेहूँकी आवश्यकता नहीं है परन्तु उसको तेल चाहिए। यहभी मान लीजिए कि तेलीको गेहूँ चाहिए। स्पष्ट है कि यदि किसान अपने गेहूँके बदले तेलीमें तेल प्राप्त करले तो वह तेलको पुनः जुलाहेको देकर कपड़ा प्राप्त करसकता है। यह एक गेहूँके बदले तेल प्राप्त करनेकी बीचकी विनिमयकी क्रिया बड़े महत्वकी है। गेहूँ और कपड़ेका एक दूसरेसे प्रत्यक्ष विनिमय न होकर तेलके माध्यम द्वारा हुआ। किसानको तेलकी सहायता से कपड़ा प्राप्त करनेमें सुविधा प्राप्त हुई। विनिमयके यहांपर दो भाग

होजाते हैं। पहिला गेहूँ का तेलमें विनिमय और दूसरा तेलका कपड़ेमें विनिमय। तेल यहापर विनिमयके माध्यमका काम कर रहा है। किसानको तो तेलकी आवश्यकता नहीं है परन्तु वह उसको कपड़ा प्राप्त करनेके लिए ही लेता है। यही क्रिया आजकल द्रव्य द्वारा होती है। इसको क्रय-विक्रय कहा जाता है। किसान अपने गेहूँ को द्रव्यमें विनिमय (विक्रय) करता और द्रव्यको पुनः कपड़ेमें विनिमय (क्रय) करता है। आजकल हम द्रव्यको मुद्रा नोट और बैंक-धरोहरके रूपमें पाते हैं। परन्तु एक व्यापक अर्थमें कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त उदाहरणमें तेलसे भी द्रव्य का ही काम लिया जा रहा है। अतः जिससमय समाजने किसी माध्यम द्वारा विनिमय करना आरम्भ किया उसी समयसे द्रव्यका मूल्यपात होगया। बादमें द्रव्य कई रूपमें भिन्न भिन्न समाजोंमें प्रयोगमें आया और विकसित होकर आजकल मुद्रा, नोट और बैंक धरोहरके रूपको प्राप्त हुआ। इस विकासकी कथाको हम आगे लिखेंगे।

मूल्य का माप-दंड

वस्तु-विनिमयकी प्रथामें एक कठिनाई और भी है। कितने तेलके लिए कितना गेहूँ दिया जाय और कितने तेलके बदले कितना वस्त्र मिल सकता है इस हिसाबके बिना अदलबदलकी क्रिया सम्पादित नहीं हो सकती है। एक वस्तुके एक इकाईके परिमाण के विनिमयमें जितनी परिमाणमें दूसरी वस्तु मिल सकती है उसको हम पहिली वस्तुका अर्थ कहेंगे। यदि एकसेर गेहूँके बदले आधासेर तेर मिल सकता है तो गेहूँका अर्थ आधासेर तेल हुआ और यदि एकसेर तेलके विनिमयसे दो गज कपड़ा मिल सकता है तो तेलका अर्थ दो गज कपड़ा हुआ इत्यादि। स्पष्ट है जितनी भी वस्तुएँ विनिमयके निमित्त हैं उन सबके सम्बन्धमें प्रत्येक वस्तुका अर्थ स्थापित किये बिना अदलबदलका कार्य पूरा नहीं हो सकता है। हम इस कठिनाईके गुरुत्वका अद्वयत्व की व्यवस्थामें अनुमानही नहीं कर सकते हैं क्योंकि आजकल प्रत्येक वस्तुके अर्थको हम द्रव्यके रूपमें प्रकट करते हैं जिसको हम उस वस्तुका मूल्य कहते हैं। जैसे एक सेर गेहूँका मूल्य आठ आना, एकसेर तेलका मूल्य दो रूपया, एक गज कपड़ेका मूल्य एक रूपया इत्यादि। परन्तु जिस समाजमें द्रव्यका प्रयोग न होता हो उसमें तो

प्रत्येक वस्तुका अर्थ अन्य सभी वस्तुओं में निर्धारित करना पड़ता है। इसमें विनिमयके कार्यमें असुविधा होजाती है। यह असुविधा दूर होसकती है यदि समाजके लोग किसी एक वस्तुको प्रामाणिक मानकर अन्य वस्तुआका अर्थ उसी एक प्रामाणिक वस्तुके परिमाणमें प्रकट करें। उदाहरणके लिए कल्पना कीजिए किसी समाजने गेहूँको प्रमाण-वस्तु मानलिया और अन्य वस्तुओंके अर्थको गेहूँके रूपमें प्रकट करने की प्रथाको स्वीकार करलिया। किसीसमय विशेषमें मान लीजिए एकसेर तेलका अर्थ दोसेर गेहूँ और एक गज कपड़ेका अर्थ एकनेर गेहूँ तो हम कह सकतेहैं कि एकसेर गेहूँके बदले दोसेर तेल मिलसकता है अगला एकसेर तेलके बदले प्राधागज कपड़ा मिलसकता है। इसीप्रकार यदि सभी वस्तुओंका अर्थ गेहूँके रूपमें ज्ञातहै तो बड़ी सुगमतासे एक वस्तुका अर्थ दूसरी वस्तुके परिमाणमें जाना जासकता है और वस्तु विनिमयके कार्य अधिक सुविधाके साथ होसकते हैं। यह आवश्यक नहींहै कि गेहूँ विनिमयका माध्यम हो। विनिमयकी प्रथा बदलबदलकी हीरहें परन्तु वस्तुओंका अर्थ गेहूँ द्वारा निर्धारित हो। यहापर गेहूँसे मूल्य-दण्डका कार्य लिया जा रहा है। आजकल भी द्रव्यसे यह कार्य लिमाजाता है अतएव हम कहसकते हैं कि जब लोग एक वस्तुका अर्थ सीधे दूसरे वस्तुके परिमाणमें प्रकट न कर किसी अन्य प्रामाणिक वस्तुके व्यवधानसे निर्धारित करने लगतेहैं यह प्रामाणिक वस्तु द्रव्यका कार्य करने लगती है। यह कहना कठिनहै कि समाजमें द्रव्यका आगमन विनिमयके माध्यमके रूपमें हुआ अथवा मूल्यके माप-दण्डका कार्य सम्पादित करने के निमित्त हुआ। द्रव्यके दोनो धर्म बड़े महत्वके हैं। ऐसाभी होसकता है कि किसी समाजमें द्रव्यका प्रयोग प्रारम्भमें विनिमयके माध्यमके लिए और किसीमें मापदण्ड के लिए हुआ हो। आधुनिक समाजमें द्रव्यके द्वारा दोनो कार्य साथ साथ सम्पादित होते हैं। द्रव्यके रूपमें किसीभी वस्तुका मूल्य प्रकट किया जाताहै और उसके माध्यमसे विनिमयका कार्यभी होता है। प्राचीन कालमेंभी तत्कालीन द्रव्यसे सम्भवहै दोनो कार्य एक साथही सम्पादित करनेकी प्रथा चल पड़ीहो उदाहरणार्थ गेहूँके रूपमें मूल्य प्रकट कियाजाय और उसीके माध्यमसे वस्तु-विनिमयका कार्य हो।

— जब किसी प्रामाणिक वस्तुके द्वारा अन्य वस्तुओंका मूल्य प्रकट किया जाने लगता है तो इनका हिसाब-किताब उस प्रामाणिक वस्तुके रूपमें करने और रखनेसे बहुत सुविधा होती है। इस अर्थमें द्रव्य द्वारा वस्तुओंका मूल्यांकन होताहै, हिसाब रखा

जाता है और चुकता किया जाता है। उपभोक्ताके सामने जब भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य द्रव्यके रूपमें रहता है और द्रव्यके रूपमें ही उसको आय मिलती है तो उसकी भिन्न भिन्न वस्तुओंके मूल्योंकी तुलना करके उनको भिन्न भिन्न मात्राओं में लेनेकी सुगमता रहती है। इसीप्रकार से यदि उत्पादकाका उत्पत्तिके माधनोका मूल्य मालूम हो और उसकी सहायतामें बनायी हुई वस्तुओंका मूल्य भी, तो वह इनके आधारपर अपने उद्योग धन्धाकी उत्पत्तिकी मात्रा और उत्पादनकी रीतिको इसप्रकार से निश्चित करना प्रयत्न करेगा जिसमें उसका अधिकतम लाभ हो। द्रव्यकी सहायताके बिना इसप्रकारके गणित करनेमें बहुत श्रमविधा हो जाती है।

कालयापन माप-दण्ड

मूल्यके माप-दण्डका कार्य करनेके कारण द्रव्य द्वारा ऋण और उधार सम्बन्धी कार्य भी सुगम हो जाते हैं। श्रान्तन की आर्थिक व्यवस्था में ऋण और उधारके बिना काम नहीं चलता है। द्रव्यके रूपमें ऋण लेनेसे बड़ी सुविधा होती है। मान लीजिए किमी किसानका बच खरीदना है। द्रव्यके रूपमें ऋण पानसे वह बड़े ऋणमत्ता है और उसकी सहायतामें उसका जो आय होती है उससे ऋण चुकता कर सकता है। यदि द्रव्यका प्रयोग न रहना तो किमी बेलवालम उसको बेल उधार में ले लना पड़ता और यह भी निश्चय करना पड़ता कि भविष्यमें किस वस्तुको कितने परिमाणमें देकर वह ऋण हासकता है। यह भ्रमटका काम है। अतएव द्रव्यहीन समाजमें लेन देन का कार्य सीमित मात्रा में ही हो सकता है। द्रव्यके रूपमें ऋण लेने और वापस करने में सुभीता रहता है। इसीप्रकार हम दुकानदारोंसे अनेक वस्तुएँ उधार लेते हैं और भविष्यमें द्रव्य द्वारा उसका भुगतान करते हैं। दुकानदारोंको भी भरोसा रहता है कि उनको जो द्रव्य मिलेगा उससे वह बिक्रीकी अथवा अपनी उपभोगकी वस्तुएँ प्राप्त कर सकेंगे। इसप्रकार द्रव्यके द्वारा भविष्यके लेन देन सम्बन्धी कार्य सुगमतासे सम्पादित होने रहते हैं। लोग समझते हैं कि अन्य वस्तुओंकी अपेक्षा द्रव्यके अर्थमें परिवर्तन कम होता है। अतएव द्रव्यसे कालयापन माप-दण्डका काम भी लिया जा सकता है। यहापर हम यह भी कह देना चाहते हैं कि द्रव्यके अर्थमें सदैव स्थिरता नहीं रहती है। समय समयपर परिवर्तन होनेसे भिन्न भिन्न व्यक्तियोंको आर्थिक

लाभ अथवा हानि होती रहती है। इस विषयपर हम आगे के अध्यायों में अधिक प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे।

द्रव्य और वचन

हमलोग अपनी सायरा कुछ भाग विविध प्रयोजनोंके निमित्त वचन चाहते हैं। इस वचनका भूमि, भवन, आभूषण, शेर और उपकरणोंके रूपमें भी परिवर्तन किया जासकता है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अथवा मन्थारों वचनका कुछ न कुछ भाग अवश्यही द्रव्य-रूपमें रखना पड़ता है। इसका प्रधान कारण द्रव्यकी मूलभूत कय-शक्ति है। वचनको द्रव्यके रूपमें रखनेसे उसको किसीभी मदमें सुगमतासे व्यवस्था जासकता है। यदि वचनको अन्य किसी रूपमें रखाजाय तो उसको सुगमता से अन्य कार्योंमें नहीं लगाया जासकता है। उदाहरणके लिए यदि मनुष्यने अपनी वचनसे भूमि मील लेली। अब यदि तीर्थयात्रा करनेके लिए रथको गावद्वयकता पड़े तो उसको भूमि बेचनी पड़ेगी और सम्भवहै कि जिस बालमें उसको भूमि बेचनी पड़े उस अवसरपर भूमिका मूल्य गिर गयाही और उसको हानि उठानी पड़े। यदि वह अपनी वचनको द्रव्यके रूपमें बैंकमें रखे होता तो उसको अधिक मुविधा होती। भिन्न भिन्न प्रकारकी सम्पत्तियोंमें भिन्न भिन्न मात्रामें मूलभूत कय-शक्ति होती है। द्रव्य ही एक ऐसी सम्पत्तिहै जिसमें यह गुण सबसे अधिक मात्रामें पायाजाता है। इसको हम द्रव्यही वा द्रवत्वगुण भी कहसकते हैं।

द्रव्य के प्रकार

आधिक इतिहासमें ज्ञात होनाहै कि भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न समयोंपर भिन्न भिन्न वस्तुएँ द्रव्यका काम करचुकी हैं। गाय, बकरी, खाल-तम्बाकू, चाय, कोडिया, सोना और चादी इत्यादि अनेक पदार्थोंका प्रयोग द्रव्यके लिए हुआ है। जिस समाजमें जो वस्तुएँ अधिक लोचरिय हुई होगी, उन्हीमें द्रव्यका कार्य लेनेकी प्रवृत्ति हुई होगी। कारण स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु बनाताहै जिसकी माग सीमितहो तो उसको वस्तुके विनिमय कार्यमें कठिनता होगी। परन्तु यदि

यह पहिले उस वस्तुको किंगी लोकप्रिय वस्तुसे विनिमय करते तो लोकप्रिय वस्तु की सहायनासे उसको अपनी आवश्यकताकी वस्तुओंको प्राप्त करनेमें सुविधा होगी और यह लोकप्रिय वस्तु विनिमयके माध्यम अर्थात् द्रव्यका कार्य करने लगेगी।

ज्ञाने सन्तैः कुछ वस्तुएं अनुभवसे द्रव्यके कार्योंके लिए अधिक उपयुक्त बात होने लगी। यदि अन्नको द्रव्य माना गया तो अनावृष्टिके वर्ष द्रव्यके परिमाणमें कमी होजाती है और सुवृष्टिके वर्ष प्रचुरता। इसप्रकार द्रव्यके परिमाणमें अधिक मात्रामें परिवर्तन होने लगना है जोकि वाछनीय नहीं होना। इसके प्रतिरिक्त अन्न द्रव्यको सुरक्षित रखनेका प्रयत्न करनाभी एक समस्या होजाती है। इसीप्रकार यदि गाय, बकरी इत्यादि पशुओंसे द्रव्यका कार्य लियाजाय तबभी अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। यदि किसी मत्स्यमय रोगके कारण पशु मरने लगे तो द्रव्यके परिमाणमें भी क्षति होनी जायगी। इसके प्रतिरिक्त गाय भ्रष्टा बकरी भिन्न आकार प्रकार और रंगरंग की होती हैं। किसप्रकार का प्रामाणिक माना जाय? इसीप्रकार अन्य वस्तुओंमें भी द्रव्यके रूपमें काममें सानेके लिए कुछ न कुछ ऋट्टिया ज्ञान होने लगी। अनुभवके आधार पर धातुएं उत्तम भी सोना और चादी द्रव्यके कार्योंके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। अतएव अन्ततोगत्वा सभी समाजोंमें इन्हीं वस्तुओंसे द्रव्यका काम निराद्वाने लगा।

धातु-द्रव्य

सोने और चादीमें अनेक गुण हैं जिनके कारण इन धातुओंका प्रयोग द्रव्यके लिए होता प्राया है। इनमें एक प्रधान गुण यह है कि ये सभीको प्रिय पदार्थ हैं। हम पहिले ही बता चुके हैं कि जो पदार्थ लोकप्रिय होगा उससे द्रव्यका कार्य लेनेमें सुगमता होगी। सोने और चादीमें एक गुण यह भी है कि ये बहुमूल्य धातुएं हैं अतएव इनके छोटे परिमाणमें अधिक मूल्य निहित रहना है। इससे यह लाभ होता है कि अधिक परिमाणमें द्रव्य संचय करनेके लिए अधिक स्थानकी आवश्यकता नहीं होती है और एक स्थानसे दूसरे स्थानको द्रव्य भेजनेमें भी सुगमता होती है। सोना और चादी बहुत टिकाऊ पदार्थ हैं। ये बहुत धीरे धीरे घिसते हैं और युगों तक रखे रहनेपर भी इनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता है। अतएव भविष्य

के लिए इनके रूपमें बेसठके मूल्य संचित रखा जासकता है। सोने चादीके छोटे छोटे टुकड़े किये जासकते हैं। सगी टुकड़ोंमें सादृश्य होता है और छोटे छोटे टुकड़ों का कुल मूल्य उस बड़े टुकड़ेके बराबर होता है जिसके वे टुकड़े हैं। यह गुण प्रत्येक वस्तुमें नहीं पाया जाता है। उदाहरणके लिए यदि बकरीको द्रव्य माना जाय तो उसके अलग अलग हिस्सोंमें प्रयात् टांग, पृष्ठ, सिर, इत्यादिमें बहुत असमानता पायी जाती है। सोने और चादीको पिघलाकर मुद्राके रूपमें परिवर्तित किया जासकता है, सोने चादीमें एक गुण यह भी है कि ये न तो इतने बड़े परिमाणमें पाये जाते हैं कि इनके बड़े मूल्यकी मुद्रा इतनी बड़ी हो कि उसको लेजानेमें असुविधा हो और न इतने कम परिमाणमें पाये जाते हैं कि कम मूल्यकी मुद्रा इतनी छोटी हो कि उसको जेबमें ढूँढना भी एक समस्या हो जाय। अधिक टिकाऊ होनेके कारण सोने चादीकी किसी समय विशेषकी, उत्पत्तिकी मात्रा उनके कुल संचित परिमाणका एक छोटा सा भाग होती है। अतएव यदि किसी वर्ष खानासे अधिक और किसी वर्ष कम सोना चादी प्राप्त हो तो इसके कारण सोने चादीके कुल परिमाणमें अधिक अन्तर नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियोंके विचारमें इस गुणके कारण इन धातुओंके और इन धातुओंसे बनी मुद्राओंके मूल्यमें कम अस्थिरता रहती है।

मुद्रा

प्रारम्भ में समाजमें सोने चादी सभी प्रकारके छोटे बड़े टुकड़ोंसे विनिमयका कार्य किया जाता था। इनमें धातुकी शुद्धता और टुकड़ोंके तौलको ज्ञात करनेकी समस्या होती थी। इस समस्याका समाधान राज्यकी ओरसे हुआ। राज्य द्वारा इस बात का निश्चय हुआ कि किन किन धातुओंमें द्रव्यका कार्य लिया जाना चाहिए। तत्पश्चात् राज्य की ओरसे टकसालें खोलोगयी जहाँ इन धातुओंकी निर्धारित तौलों की मुद्रायें ढाली जाने लगी। इनमें धातुकी शुद्धता और तौलको प्रमाणित करनेके लिए राज्यकी मोहर लगायी गयी और बनावटी नकली मुद्रासे लोगोंको सावधान करनेके लिए वार्षिक मुद्राओं को विशेष आकार प्रकारसे बनानेकी चेष्टा की गयी।

दो प्रकारकी मुद्राओंका प्रयोग हुआ जिनको हम प्रामाणिक और साकेतिक मुद्रा कहेंगे। प्रामाणिक मुद्रा वह है जिसका अर्थ उस मुद्रामें (वर्तमान) स्थित धातुके परि-

माणके अर्धके बराबर हो। यदि मुद्राको गना दिया जाय तो धातुके टुकड़ेका उतना ही अथ होगा जितना कि उम मुद्राका था अर्थात् दोनोंकी क्रयशक्ति समान होगी। इसका प्रधान कारण यह है कि प्रामाणिक मुद्राके सम्बन्धमें लोगोंको स्वतन्त्रता रहती है कि वह किसी परिमाणमें प्रामाणिक धातुको टुकड़ातमें ले जाकर उसकी प्रामाणिक मुद्राएँ ढलवा सकते हैं और उनको गलाकर फिरसे अमुद्रित रूपमें परिवर्तन कर सकत हैं। अथ यदि प्रामाणिक मुद्राकी न्यय शक्ति उसमें स्थित धातुकी नय शक्ति से अधिक हो तो लागू उम धातुको मुद्राके रूपमें रखना चाहेंगे और यदि मुद्राकी अपेक्षा धातुना अथ अधिक हो तो मुद्राका गला डालेंगे। इसप्रकारके बदलाव-बदलाव से दोनोंका मूल्य समान रहेगा।

इसके प्रतिकूल साकेतिक मुद्राका अर्थ उसमें स्थिति धातुके अर्धनं कहीं अधिक होता है। यदि हम साकेतिक मुद्राको गला डालें तो उसमें जो अमुद्रित धातु प्राप्त होगी उसका अर्थ उतना नहीं होगा जितना कि उसका मुद्राके रूपमें था। साकेतिक मुद्राका प्रयोग अधिकतर छोटे मूल्यके विनिमय कार्योंके लिए होता है। अतएव इन मुद्राओंको तावा, गिलट जैसे अल्पमूल्य धातुमें बनाते हैं। इसप्रकार की मुद्राओंकी ढलाई राज्य स्वयं करना है जिसमें कि इनके परिमाणपर नियन्त्रण रहे और मुद्राका अर्थ धातुके अर्थसे अधिक बना रहे।

राज्य द्वारा निर्मित और अंकित मुद्राको चलनमें एक विनिष्ट स्थान प्राप्त हो जाता है। इस द्रव्यको लेनदेने इन्कार नहीं किया जा सकता। इसप्रकार के द्रव्यना हम राज प्रामाणिक ग्राह्य द्रव्य कहेंगे अर्थात् ऐसा द्रव्य जहाँ कि राज्यसे प्रमाणित होना के कारण सभीको ग्राह्य हो जाता है। यदि हमें किसी महाजन या दुकानदारको ऋण अथवा मूल्य चुकाना है तो हम इस प्रकारके द्रव्य द्वारा चुका सकते हैं और दुकानदार अथवा महाजन उसको अंगीकार करनेको न्यायतः बाध्य किया जा सकता है, हाँ, एक बात यह है कि प्रामाणिक मुद्राएँ किसी भी परिमाणमें दी जा सकती हैं और साकेतिक मुद्राएँ एक सीमित परिमाण तक। भारतमें रुपया प्रारम्भमें प्रामाणिक मुद्रा था अतएव यह अपरिमित मात्रा में ग्राह्य था। सन् १८६३ के पश्चात् इसका पद साकेतिक मुद्रा हो गया परन्तु यह अभी तक अपरिमित मात्रा में ग्राह्य है। अठन्नी से नीचे की जितनी भी मुद्राएँ हैं वे एक रुपये की सीमा तक ही वैध रूप में ग्राह्य हैं। साकेतिक मुद्राको सीमित मात्रा में ग्राह्य करना कारण यह है कि अधिक मूल्यके

लिए साकेतिक मुद्रा देने और लेनेमें अगुविधा होती है।

प्रामाणिक मुद्रा द्रव्यके सम्बन्धमें इस बातकी स्वतन्त्रता रहतीहै कि कोईभी व्यक्ति किसीभी परिमाणमें सोना अथवा चादी राज्यकी टकमालमें लेजाकर उनको प्रामाणिक मुद्राओंमें ढलवा सकता है। अतएव चलनमें प्रामाणिक मुद्राका परिमाण प्रधानतः देशवासियोंद्वाराही निश्चित होता है। परन्तु साकेतिक मुद्राओंके सम्बन्धमें ऐसा नही होता है। इनका टकन राज्य द्वाराही जाना है। इसका कारण यहहै कि साकेतिक मुद्राका मूल्य उसमें स्थित धातुके मूल्यमें अधिक होताहै और इस सम्बन्धको बनाय रखनके लिए इसके परिमाणको सीमित रखनकी आवश्यकता होती है। यदि लागूका इस बातकी स्वतन्त्रता दही जाय कि वह जिस परिमाणमें चाहें उस परिमाणमें साकेतिक मुद्राभाङ्गलवा सकनहै तो इन मुद्राओंके अतिरिक्त मूल्य और धातु मूल्यका विषमताके अन्तर्गत लाभका प्राप्त करनके लिए लोग बहुत बड़े परिमाणमें इस प्रकारकी मुद्राओंका ढलवात जिसमें इनकी क्रय शक्ति गिरन लगनी। साकेतिक मुद्राओंकी आवश्यकता कम मूल्यवाले व्यापारोंके सम्बन्धमें ही होनी है। अतएव इनका एक बड़े परिमाणमें टकन करना अपायप्रदानही है। चकि राज्य द्वारा साकेतिक मुद्राओंका टकन होताहै अतएव इस कारणसे जो लाभ जानाहै वह राज्यकापमें ही जाता है।

मुद्रा-टकनमें तात्तलगतहै। इस व्यवस्थाको जिसे मुद्राटकन शूलक कहतेहै किन्हा दशोंमें राज्यक कांफसे ही पूरा किया जाताहै अर्थात् जो व्यक्ति सोना अथवा चादी मुद्राकनके निमित्त लाताहै उससे काउ शूलक नही लियाजाता है। किन्ही देशोंमें मुद्राकन-शूलक नियोजितहै। यदि राज्य मुद्राकन-शूलकमें अधिक मात्रामें शूलक लगाय तो इससे उनको जो प्राप्ति हानीहै उसका मुद्राकन लाभ वृद्धिके है। प्राचीनकालमें राजा लोग कभी कभी मुद्रामें नियमित परिमाणसे कम धातु रखकर अपना स्वाध मित्र करते थे। इस प्रकारकी मुद्राका पद प्रामाणिक मुद्रासे घटकर साकेतिक मुद्राक समानही होजाता है। यह अवैध बाय है।

एक बड़े कालतक मुद्रा रूपमें ही द्रव्य चलनमें रहा। परन्तु आधुनिक कालमें कुल द्रव्यकी तुलनामें मुद्रा द्रव्यका परिमाण बहुतही कम रहगया है। प्रामाणिक मुद्रा तो अब किसीभी देशमें चलनमें नही पायीजाती है। धातुका बना द्रव्य केवल साकेतिक मुद्राके रूपमें ही चलनमें है और इसका परिमाण कुल द्रव्यके परिमाणके

सामने बहुत कम है। आधुनिक कालमें द्रव्य अधिकतर नोट और साख-द्रव्यके रूप में अधिक मात्रा में चलनमें पाया जाता है। अतएव अब हम इनका विवेचन करेंगे।

नोट

कागजपर छप्टुए द्रव्यको हम नोट कहते हैं। आधुनिक कालमें नोट छापनेका कार्य राज्य स्वयं करता है अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा करवाना है। नोटोंको राज प्रमाणित ग्राह्य द्रव्यका पदभी प्राप्त है। नोटका इस पदतक पहुचनेका एक बड़ा इतिहास है। संक्षेपमें प्रारम्भमें नोट धात्विक द्रव्यके स्थानापन्नके रूपमें काममें लाया गया। धात्विक द्रव्यको बड़े परिमाणमें एक स्थानसे दूसरे स्थानकी लज्जातमें व्यय, असुविधा और भय रहता है। अतएव धात्विक द्रव्यको किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा संस्था के पास धरोहरके रूपमें रखकर उसके स्थानमें कागजकी रसीदों द्वारा विनिमयके माध्यमका कार्य लेनेकी प्रथा चल पड़ी। जिस व्यक्ति अथवा संस्थाके पास धात्विक द्रव्य रखा जाता था वह धरोहर रखनवालाको एक लिखित पत्र देते थे जिसके अनुसार वह पत्र-वाहकोका उसपर लिखित धातु-द्रव्य देनेकी प्रतिज्ञा करते थे। आधुनिक नोटोंमें भी इस प्रकारका वाक्य लिखा रहता है 'मैं वाहको.. रुपये देनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ और उसमें रिजर्व बैंक (जो भारतका केन्द्रीय बैंक है) के गवर्नरके हस्ताक्षर रहते हैं। इस प्रकारके लिखित प्रतिज्ञा-पत्र व्यापार और लेनेदेने की सुविधा के लिए मित्र मित्र मूल्योंवाले बनाये जात लगे। आजकल भी एक रुपया, दो रुपये पांच रुपये, दस हजार और सौ रुपयेके नोट चलनमें हैं। आधुनिक नोटोंके इतिहास का यही श्रीगणेश है।

जो व्यक्ति अथवा संस्था इस कार्यकी करने लगी उसको अनुभवम ज्ञान हुआ कि जो धात्विक द्रव्य उनके पास धरोहरके रूपमें रखा रहता था उसका कुछ हिस्सा उनके पास निगचेष्ट पड़ा रहता है क्योंकि उनके दिये गये सभी प्रतिज्ञा-पत्र धात्विक द्रव्यमें परिवर्तन कराये जानेके लिए एक साथही नहीं समर्पित किये जाते थे। अर्थात् कुछ नोट (इन प्रतिज्ञा-पत्रोंका अब हम नोटोंके नामसे ही सम्बोधित करेंगे) बराबर चलनमें रहते थे। उदाहरणके लिए यदि किसी संस्थाने दस लाख रुपये (धात्विक) की धरोहरके स्थानपर दस लाख रुपयेके नोट चलनमें डाल दिये तो इन नोटोंका

कुछ भाग तो चलनमें रहताथा और कुछ भाग धात्विक द्रव्यमें परिवर्तित होनेके लिए इस सस्याके पास आताथा। यदि नोटोंका आधा भाग चलनमें रहे और आधा परिवर्तनके लिए लायाजाये तो सस्याको पाच लाख रुपया तो परिवर्तनके कार्यके लिए अपने पास रखना पड़ेगा और दूसरे पाच लाख रुपये उसके पास निश्चेष्ट और निरर्थक पड़े रहेंगे। इस बेकार पड़ेहुए द्रव्यसे सस्याने (जिसको अब हम बैंक के नाममें सम्बोधित करेंगे क्योंकि जैसा आधे चलकर बताया जायगा कि इस प्रकारके कार्य करनेवालो सस्यायें बैंक बनगयी) अपना लाभ बनानेकी मुक्ति ढूँढ निकाली। हम जानतेहैं कि अनेक ऐसे व्यक्ति होतेहैं जिनकी चालू-आय चालू-व्यय को पूरा करनेमें पर्याप्त नहीं होनी है। ऐसे व्यक्ति ऋण लेकर अपना काम चलाने का प्रयत्न करतेहैं और व्याज देनेको भी उद्यत रहते हैं। यदि इस प्रकारका कोई व्यक्ति बैंकके पास ऋण लेनेके लिए पहुंचगया और बैंकने उसको ऋण देना स्वीकार करलिया तो उस व्यक्तिको व्यय करनेके लिए रुपया मिलगया और बैंकको भी व्याजके रूपमें आमदनी होगयी। अब हमको यह देखनाहै कि इस ऋण लेन-देन के कार्यसे द्रव्यके परिमाणपर क्या प्रभाव पडा? मान लीजिए इस व्यक्तिको बैंकने १० हजार रुपया ऋण दिया। इस ऋणको दो प्रकारसे दिया जासकता है। एक रीति यह है कि जो पाच लाख रुपया बैंकके पास निश्चेष्ट पडा हुआ है उसमें से १० हजार रुपया निकालकर दे दिया जाय। ऐसा करनेसे यह रुपया चलनमें आजायगा और जो दस लाख रुपयेके नोट पहिलेसे ही चलनमें है, उनका धात्विक द्रव्यका आधार बैंकके पास १० लाख रुपयेसे कम होकर ९ लाख ९० हजार रुपया रहजायेगा अर्थात् नोटके परिमाणसे बैंकमें स्थित धात्विक द्रव्यका परिमाण कम होजायेगा। दूसरी रीति यह है कि बैंक दस हजार रुपयांकी नोटोंकी गड्डी उस व्यक्तिको दे। ऐसा करनेपर १० हजार रुपयांके प्रतिगुणित नोट चलनमें आजायेंगे जिनके आधारके लिए उंम परिमाण का धात्विक द्रव्य बैंकके कोषमें नहीं है अर्थात् चलनमें इस बैंक द्वारा प्रचलित १० लाख १० हजार रुपयेके नोट होंगे और बैंकके पास धात्विक द्रव्य केवल १० लाख रुपया होगा। दसवीं रीतियोंके अन्तर्गत मुख्यतः यह है कि ऋण देने के परस्पर चलनमें १० हजार रुपयांकी वृद्धि होजाती है और नोटोंका आधार धात्विक कोषगत प्रतिशत अनुपातसे कम होजाता है। बहापर हमको बैंककी एक सन्तिका पता चलताहै कि वह अपनी ऋण नीतिसे द्रव्यके परिमाणमें परिवर्तन कर

सक्षता है। अनेक बैंकोंने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने लाभ के लिए इतनी प्रचुरतासे नोट चलाने में डाल दिया कि उनको बदलने के लिए उनके पास धात्विक द्रव्य बहुत अपर्याप्त मात्रा में रह गया। नोटा के बदल धात्विक द्रव्य न दे सकने के कारण अनेक बैंक फेल होगये और उनको अपनी व्यवसाय बंद करना पड़ा। बैंकों के पतन ज्ञानसे आर्थिक कार्यों में भी गड़बड़ी आजाती है। भ्रमाज्ञा को इस गड़बड़ी से बचाने के लिए नाट छापने और प्रचलित करने का काम राज्यने अपने हाथ में लीया अथवा केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया। इन नोटा का राज-प्रमाणित ग्राह्य द्रव्य का पद भी मिल गया।

विनिमय साध्य नोट

प्रारम्भ में नोट विनिमय साध्य थे अर्थात् उनको प्रचलित करने वाले बैंकों को मागने पर उनके बदल धात्विक द्रव्य देने को बाध्य रहता पड़ता था। इन बैंकों द्वारा प्रचलित नोटा का राज-प्रमाणित ग्राह्य द्रव्य का स्थान ॥ प्राप्त था नहीं। अतएव इन नोटा को विनिमय-साध्य बनाय रखने के लिए इनको पर्याप्त मात्रा में मुद्रा कोष रखना पड़ता था। जब राज्य अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा नोटा का प्रचलन हानि लगा और इन नोटा को राज-प्रमाणित ग्राह्यता का पद भी प्राप्त होगया इसपर भी प्रारम्भ में ये नोट प्रामाणिक मुद्रा अथवा धातु में एक निश्चित दर पर विनिमय साध्य बने रहे। राज्य अथवा केन्द्रीय बैंक को अपने मुद्रा अथवा धातु कोष को इतने परिमाण में रखना पड़ता था जिससे नोटा का इनमें विनिमय करने की माग का वे पूरा कर सकें।

नोटा के पीछे कितना कोष रखा जाय इस सम्बन्ध में दो प्रधान मत रहते हैं। एक मत को बरेंसी सिद्धान्त और दूसरे को बैंकिंग सिद्धान्त कहते हैं। बरेंसी सिद्धान्त के अनुसार नोटा के पीछे सत-प्रतिष्ठान प्रामाणिक द्रव्य का कोष रहना चाहिए जिससे नोटा पर जनता का विश्वास बना रह और प्रत्येक अवस्था में नोटा के बदले प्रामाणिक द्रव्य दिया जा सके। बैंकिंग सिद्धान्त के अनुसार प्रामाणिक-द्रव्य कोष का परिमाण सचित नोटा के परिमाण के बराबर होना ही आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी नोट एकद्वारगी ही प्रामाणिक द्रव्य में परिवर्तित होने के लिए नहीं लाये जाते

है। इसके प्रतिरिक्त आशिक कोष रखनेसे द्रव्यके परिमाणमें लोच रहती है। व्यवहारमें नोटोंके प्रचलनका आधार बेकिंग मिद्दान्त ही है।

नोटोंके परिमाणका कुछ भाग प्रामाणिक द्रव्यके आधारपर स्थित रहता है। कितना भाग किनके आधारपर रहे इस सम्बन्धमें दो मुख्य रीतियां व्यवहारमें लायी जाती हैं। एक रीति जिसका प्रमुख उदाहरण इंगलैण्ड रहा है, यह है कि साख द्रव्यके आधारपर जितने नोट प्रचलित किये जाय, उनका परिमाण राजनियमसे निश्चित कर दिया जाय। उसके ऊपर जितनेभी नोट हों उनमेंही परिमाणमें प्रामाणिक मुद्रा अथवा धातु रखा जाय। इस नियमके अनुसार वर्तन से जबतक साखपत्र के आधार पर प्रचलित नोटोंका परिमाण निर्धारित सीमा तक न पहुँच जाय तबतक इसका परिमाण बड़ी सुगमतासे साथ बढ़ाया और घटाया जा सकता है। परन्तु जब इसका परिमाण निर्धारित सीमा पर पहुँच जाता है तो उसके पश्चात् नोट-द्रव्य के परिमाणको बढ़ानेकी आवश्यकता होनेपर उसी परिमाणमें प्रामाणिक धातु-द्रव्य की आवश्यकता हो जाती है जिसके फलस्वरूप द्रव्यमें लोच कम हो जाती है। दूसरी रीति प्रधानतः संयुक्त राज्य अमेरिकामें वर्तनी गयी है। इसके अनुसार जितनाभी नोट-द्रव्य संचालित किया गया है उसके एक निर्धारित भागसे कम अनुपातमें प्रामाणिक द्रव्य कोष न रहे और दो भाग साख-पत्रके आधारपर रह सकता है। इसको अनुपातिक-कोष-पद्धति कहते हैं। उदाहरणके लिए यदि २५ प्रतिशत नोट द्रव्यके पीछे प्रामाणिक द्रव्य-कोष रखना अनिवार्य हो तो ७५ प्रतिशत साख-पत्रके आधार पर संचालित किया जा सकता है। इस पद्धतिके अनुसार नोट संचालित करनेसे नोटोंके परिमाणमें अधिक सुगमतासे वृद्धिकी आसक्ति है। प्रामाणिक द्रव्यकी एक इकाई कोषमें आनेपर चार इकाई तक नोट संचालित किये जा सकते हैं परन्तु साथ ही साथ उस आधारपर कोषमें एक इकाई प्रामाणिक द्रव्यके ह्रास होनेपर चार इकाई नोटोंको चलाने वापिस लेना पड़ेगा।

अविनिमय-साध्य नोट

आधुनिक कालमें नोट अविनिमय-साध्य होगया है अर्थात् इसके बदलेमें राज्य प्रामाणिक धात्विक द्रव्य देनेकी बाध्य नहीं है। प्रारम्भमें जब नोट चलानमें आया

उम समय नोटमें जनताका विश्वास उत्पन्न करने और बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक प्रतीत होता था कि उनको संचालित करनेवाली संस्था उसके बदले एक निर्धारित मात्रा सोने अथवा चांदीकी प्रामाणिक मुद्राओं अथवा अमुद्रित रूपमेंही सोना चांदी देनेको बाध्य हो। माने-चांदीका द्रव्य सम्बन्धी मूल्यके साथ साथ स्वाभाविक मूल्यभी होना है। अन्यथा लोगोंकी ऐसी धारणा होगयी थी कि नोटकी कय शक्ति उम प्रामाणिक मुद्राके अन्तर्गत है या उसके बदलेमें प्राप्त होसकती है। इसी धारणाके अनुसार प्रारम्भमें नाट विनिमय-माध्य बनाये गये। कभी कभी युद्धकाल में नोटकी इसप्रकारकी विनिमय माध्यता हटाभी लीजानी थी परन्तु अनुकूल अवस्था लौट आनेपर विनिमय माध्यता पुनः स्थापित करदी जाती थी। सनैः सनैः लोगोंकी यह धारणा बढ़ान लगी कि नाटकी ऋण-शक्ति सोने-चांदीके अवीन है जब उन्होंने देखाकि धात्विक द्रव्यमें अविनिमय साध्य तोटसे भी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जासकती हैं तो उनकी समझमें आनेलगा कि नोटमें विश्वास बनाये रखनेके लिए मूल बात यह है कि वह अन्य वस्तुओंमें विनिमय साध्य बना रहे अर्थात् उसके विनिमयमें अन्य वस्तुएं प्राप्त होनी रहें। द्रव्यसे हम यही चाहतेहैं कि उसकी सहायतासे हमको वांछित वस्तुओंको प्राप्त करनेमें सुविधा हो। जबतक द्रव्य से यह कार्य होता रहताहै तबतक द्रव्य किंय पदार्थ का बना हुआहै इसका विशेष महत्व नहीं है। वह चाहे मान का, चाहे चमड़ेका और चाहे कागजका ही बना हुआ क्यों नहो, यदि उसके बदलेमें हमको अन्य वस्तुएं मिल सकतीहैं तो द्रव्यका कार्य चतता रहता है। इस विवेचनाके आधारपर हम एक महत्वपूर्ण निर्णयपर पहुंचते हैं। वह यहकि द्रव्यकी ऋण-शक्ति अर्थात् अन्य वस्तुओंको प्राप्त करनेकी शक्ति उस पदार्थपर अवलम्बित नहींहै जितने उसका निर्माण हुआ है। वन रूपे का नोट जिस कागजपर छापा गयाहै उसकी निजी ऋण-शक्ति लगभग कुछभी नहींहै परन्तु नोटकी ऋण-शक्ति तो बहुत है। कागज का नोट जिसकी स्वयकी कोई कय शक्ति नहीं और जिसके बदलेमें द्रव्याधिकारी सोना-चांदी देनेको उद्यत नहीं किस कारणसे ऋण-शक्तिशाली होजाता है, उसका विवेचन बहुत महत्वपूर्ण है। एक कारण यहहै कि हम द्रव्यको अपने आर्थिक कार्योंमें लानेके इतने अभ्यस्त होगये हैं और हमारी आर्थिक पद्धति इतनी द्रव्यमयी होसकयी है कि बिना द्रव्यके हम एक पगभी आगेको नहीं बढसकते हैं। अतएव किसी प्रकारकीभी द्रव्य-क्षयो नही

हमको उसका प्रयोजन है, उसका मूल्य और उसकी ऋय-शक्ति इस प्रयोजनसे उत्पन्न होजाती है। इसके अतिरिक्त राज्य-नियमोंके द्वारा प्रमाणित होनेके कारण हम इसको अस्वीकार नहीं करसकते हैं। अतएव जबतक राज्यकी प्रतिष्ठा है और उसका दबदबा है तबतक उसके द्वारा प्रमाणित द्रव्य मूल्यवान रहेगा। यह दूसरी बात है कि उसका क्या मूल्य होगा परन्तु कुछ न कुछ मूल्य अवश्यही रहेगा। इस प्रसंगमें यह बातभी समझमें आजाती है कि द्रव्यमें विश्वास बनाये रखनेके लिए आवश्यकता इस बातकी है कि उसकी ऋय-शक्ति बनीरहे और उसमें स्थिरताभी रहे। यदि नोट द्रव्यमें इनदोनों बातोंका समावेश रहे तो इससे अधिक नोटसे प्राप्त करनेके लिए कुछ और बाकी नहीं रहजाता है। द्रव्यके मूल्यमें स्थिरताका महत्व-और अस्थिरताके उत्पन्न होजानेके कारणोंकी विवेचना हम द्रव्यके अर्थके अध्यायमें करेंगे। यहापर इतना लिखदेना पर्याप्त है कि अविनिमय-साध्य नोट द्रव्यकी ऋय-शक्तिको बनाये रखनेके लिए द्रव्याधिकारियों को विशेष प्रबन्ध और नियन्त्रण करनेकी आवश्यकता होती है।

विनिमय-साध्य नोट पद्धतिमें द्रव्याधिकारियोंको आर्थिक स्थितिके अनुसार द्रव्यके परिमाणको व्यवस्थित करनेमें कठिनाता पडती है, अविनिमय-साध्य नोट पद्धतिमें द्रव्यके परिमाण को उत्पत्ति, व्यापार इत्यादिके अनुकूल बनानेमें सुविधा रहती है। परन्तु इस पद्धतिमें एक आशंका यह है कि सोने चांदीकी शृंखलासे मुक्त होकर द्रव्य का परिमाण इतनी प्रचुरतासे बढ़ादिया जाय जिससे द्रव्य स्फीतिकी अवस्था उत्पन्न होजाय। आर्थिक इतिहाससे पता चलता है कि युद्धकालमें और अन्य आर्थिक संकटोंके अवसरोपर प्रायः राज्य बहुत बड़े परिमाणमें अविनिमय साध्य नोट छापकर चलनमें डालदेते हैं जिससे द्रव्यकी ऋय-शक्ति का ह्रास हो जाता है और आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न होजाती है। इससे इस निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए कि यह पद्धति ही दोषयुक्त है। आवश्यकता इस बातकी है कि बहुत सोच समझकर इस द्रव्य-पद्धतिको व्यवहारमें लाया जाय।

साख-द्रव्य

साख-द्रव्यमे हमारा अभिप्राय उस द्रव्यसे है जिसको बैंकके द्वारा हस्तान्तरित किया

जाना है। इस द्रव्यका सम्पन्न बँकोंमें है। हम बँकमें राखा जमा करते हैं। वह हमारी धरोहर है जिसको हम चेकमें वापस लेमक्ते हैं। एक धरोहर चातू-हिस्सा वाली है तोहें जिसको बँकोंमें विना पूर्वसूचनाके वापस लिया जासक्ता है। दूसरी प्रकारकी धरोहर एक निर्धारित मरदके लिए बँकके पास जमाकी जातीहै जिसको साधारणतः उस समयके बीतने परही वापस मागाजा सक्ता है। इस धरोहरको द्रव्यके रूपमें बाबमें खाने का किया चेक द्वारा होती है। चेकके द्वारा धरोहर रखने वाला बँकको आदेश देताहै कि वह उसके धरोहरमें से चेकमें लिखी रकम नामावित व्यक्तिको अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्तिको दे दे। चेकके द्वारा धरोहरके अन्तर्गत कोईभी रकम सुनिश्चापूर्वक दी जासक्ती है। इसप्रबन्धमें धनको खानेकी आशङ्काभी नहीं रहतीहै क्योंकि वहतो बँकमें सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त चेकद्वारा सरलतासे जेबमें लजायी जासक्ती है। यदि कोई व्यक्ति चेकके रूपमें अपना पादना स्वीकार करताहै तो उसके मूलमें साख और विश्वास रहता है। चेक तो मात्र-प्रमाणित द्रव्य नहीं है। यही होसक्ताहै कि जिस व्यक्तिने चेक दियाहै उसका नामपर चेकमें धरोहर जमा नहो अथवा उपयुक्त मात्रामें नहो। अतएव जब हम चेक स्वीकार करतेहैं ना हमका अर्थ यह हुआ कि हम चेक देनेवालेकी साखपर विश्वास रखने हैं। इसी कारण हमने इस द्रव्यको साख-द्रव्यका नाम दिया है।

साख-द्रव्य का सृजन

हम एक द्वारा बना उपनती द्रव्यके परिमाणका हस्तान्तरित नहीं करसक्ते हैं जिसका तबत परास्पर रूपमें रखा है। यदि हम बँकोंके सेनीदेनी के लेखोंको देखें तो हमका पता लगताहै कि इनमें दीगयी धरोहरका कुल परिमाण राज्यद्वारा प्रचलित द्रव्यके परिमाणसे कईगुना अधिक पाया जाताहै जबकि उस द्रव्यका एक बड़ा हिस्सा बँकोंमें जमा नहीं कियाजाता है। इससे यह ज्ञात होताहै कि बैंक स्वयं भी साख-द्रव्यका सृजन करते हैं। यह कार्य दोप्रकार से होता है। जब बैंक ऋण देतेहैं तो ऋण लेनेवालेकी अधिकार देदेते हैं कि वह बैंकपर ऋणके परिमाण तक—चेकलिख सकताहै और बैंक उनचेकका भुगतान करदेगा। जिसप्रकार बँकमें धरोहर रखनेवाला अपनी धरोहरको बैंक द्वारा वापस लेसक्ता है अथवा हस्तान्तरित

करसकता है उसीप्रकार ऋण लेनेवाला भी ऋणकी मात्रा तक चेक द्वारा रुपया प्राप्त करसकता है। कल्पना कीजिए मोहनको इलाहाबाद बैंकने १०००, रुपया ऋण देना स्वीकार किया। अब मोहन १००० रुपया तकका भुगतान चेकके रूपमें करसकता है। इस द्रव्यसे भी विनिमयके माध्यमका कार्य उसीप्रकार सम्पादित होताहै जिसप्रकार धात्विक अथवा नोट-द्रव्य द्वारा होता है। ऋण देनेसे बैंकने १००० रुपयेके परिमाणका साख-द्रव्य चलनमें डालदिया और अब इस ऋणका भुगतान होजायगा तो यह द्रव्य चलनसे हट जायगा। ऋण देनेसे बैंकको व्याज मिलताहै अतएव बैंक ऋण देकर अपने ऊपर देनीका भार बढ़ाते हैं। इसप्रकार हम देखतेहैं कि जब जब बैंक नया ऋण देतेहैं तब तब साख-द्रव्यकी सृष्टि होती है। यदि पुराने ऋणके भुगतानमें नये ऋणका परिमाण अधिकहो तो चलनमें साख-द्रव्य की वृद्धि होगी। इसके प्रतिकूल यदि नये ऋणसे पुराने ऋणकी भुगतानकी मात्रा अधिकहो तो साख-द्रव्यका संकुचन होगा।

सिवयूरिटिया मोल लेकरभी बैंक, साख-द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि करसकते हैं। जिस मूल्यकी सिवयूरिटिया हो उतनाही हिमाव सिवयूरिटिया बेचनेवाले व्यक्तिमें अथवा सत्याप्रोके नाम अपने खातेमें जमाकर बैंक उनको अधिकार देतेहैं कि वे उस परिमाण तक बैंकपर चेक लिख सकते हैं। इसीप्रकार अन्यकी सम्पत्ति मोल लेकर भी बैंक सम्पत्तिके बेचनेवालोंके नाम बैंकमें धरोहर जमा करदेते हैं जिसको चेक द्वारा हस्तान्तरित किया जासकता है। जब जब बैंक सिवयूरिटिया अथवा अन्य प्रकारकी सम्पत्तिका संग्रह करते हैं तब तब साख-द्रव्यकी सृष्टि होती है।

अब प्रश्न यह होताहै कि जितना धात्विक और नोट-द्रव्य बैंकके पास जमा किया जाताहै उससे अधिक मात्रामें बैंक किसप्रकार साख-द्रव्यको अवलम्बन देसकते हैं। हम पहिलेही लिखआये हैं कि साख-द्रव्य राज-प्रामाणित द्रव्य नहींहै और बैंकोंको सदैव इसके बदले राज-प्रामाणित द्रव्य देनेको प्रस्तुत रहना पड़ता है। वास्तवमें बात यहहै कि बैंकोंके द्वारा जिस परिमाणमें साख-द्रव्यका सृजन होताहै वह सबका 'एक सायही राज-प्रामाणिक द्रव्यमें परिवर्तित होनेके लिए नहीं लायाजाता है। बैंकोंमें जो धरोहर रखा जाताहै उसका साधारणतः केवल कुछही भाग राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें वापस कियाजाता है शेष भाग बैंकोंमें ही पड़ा रहता है। इसीप्रकार ऋण देकर और सिवयूरिटिया मोल लेकर जिस साख-द्रव्यकी सृष्टि होतीहै उसका

भी कुछ भाग तो राज-प्रामाणित द्रव्यमें मागा जाता है और शेष भाग बैंकोंमें ही एक आसामीसे दूसरे आसामियोंके नामपर जमा होता है। उदाहरणके लिए मोहनने ये जो ५००० रुपये इलाहाबाद बैंकमें ऋण लिया था उसमेंसे यदि वह बैंक द्वारा ५०० रुपये रामको हस्तान्तरित करता है और राम उस बैंकको अपने नामपर बैंकमें जमा करता है तो रामके नाममें ५०० रुपयेकी धरोहर जमा हो जाती है। अब यदि इस धरोहरमें से राम ५० रुपयेका बैंक श्यामको देता है और श्याम उस बैंकको बैंकमें जमा करनेके लिए भेज देता है तो बैंकके खातेमें रामकी धरोहरमें ५० रुपये को घटाकर श्यामकी धरोहरमें ५० रुपये जोड़ दिया जाता है। इसप्रकार राज-प्रामाणित द्रव्यको बैंकोंके कोषसे निकाले बिनाही लेन-देन का काम चलता रहता है।

इस विवेचनसे यह नहीं समझलेना चाहिए कि कुल साख-द्रव्य इसीप्रकार एक व्यक्ति अथवा संस्थाके नामसे अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थानोंके नामपर बैंकोंके खातों में विधरता रहता है। इसका कुछ अंश तो अवश्यही राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें मागा जाता है। अनेक व्यक्तियोंका बैंकोंमें हिसाब नहीं रहता है। अतएव इनको जो बैंक मिलते हैं उनको खेला जाता है। इसके अतिरिक्त सभी लोग बैंक लेना स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे घोड़ी, नार्डी, सेवक, दूधवाला। इस प्रकारके लोगोंको धात्विक अथवा मोटाके रूपमें ही इनका वाचना देना पड़ता है। इन कार्योंके लिए बैंकोंमें राज-प्रामाणित द्रव्य लेना पड़ता है।

अनुभवके द्वारा बैंकोंको पता चल जाता है कि समय समयपर कुल साख-द्रव्यका कितना भाग राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें मागा जाता है। यदि पाचवा भाग मागा जाय तो बैंकोंको कुल साख-द्रव्यका २० प्रतिशत राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें रखना पड़ेगा और यदि दसवा भाग मागा जाय तो बैंकोंको केवल १० प्रतिशत इस रूपमें रखना होगा। इस विवेचनसे हमको यह भी ज्ञान हो जाता है कि बैंक किस सीमा तक साख-द्रव्यकी सृष्टि कर सकते हैं। बैंक जिस परिमाणमें साख-द्रव्यकी वृद्धि करते हैं उसी परिमाणमें वे अपने को राज-प्रामाणित द्रव्य देनेवाले देनेदार बनाते रहने हैं। अब चूंकि बैंकोंके पास राज-प्रामाणित द्रव्य सीमित परिमाणमें रहता है अतएव वे अपरिमित परिमाणमें साख-द्रव्य चलानमें नहीं डाल सकते हैं। यदि साख-द्रव्यके स्वामी उसका दसवा भाग राज-प्रामाणित द्रव्यमें मागते हैं तो जितना राज-प्रामाणित

द्रव्य बैंकोंके पासहै उसके दसगुने तक साख-द्रव्यके सृजनकी सीमा होजायगी । इससे अधिक सृजन करनेपर बैंक राज-प्रामाणित द्रव्य देनेमें असमर्थ होजायगे । इससे यह परिणाम निकलताहै कि बैंकोंकी साख द्रव्य सृजनकी शक्ति दो मुख्य बातोंपर निर्भर रहती है । एक तो यहहै कि उनके पास राज-प्रामाणित द्रव्यका कोष कितनाहै और दूसरा इस द्रव्यका साख-द्रव्यसे क्या अनुपात आवश्यक है ।

किसी समयविशेषमें साख-द्रव्य किस परिमाणमें होगा यह केवल पूर्वोक्त दो बातोंपर ही निर्भर नहीं करता है । यदि आर्थिक अवस्थामें मन्दी छायेहो तो ऋणकी मांग घटजाती है अतएव साख-द्रव्यका परिमाणभी घटजाना है अधिक सक्कटकाल में बैंकभी ऋणदेना पसन्द नहीं करते हैं । केन्द्रीय बैंकभी अपने उपकरणोंके प्रयोग से साख-द्रव्यके परिमाणको नियन्त्रित करते रहते हैं ।

द्रव्य पद्धतियां

द्रव्य पद्धतियों के प्रकार

भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न समयोंमें भिन्न भिन्न द्रव्य-पद्धतियोंका चसन रहा है। इनको हम दो मुख्य विभागोंमें बांट सकते हैं। पहिले विभागमें धात्विक द्रव्य-पद्धतियां हैं और दूसरे विभागमें अविनिमयमाध्य द्रव्य-पद्धतियां। धातु-पद्धति में केवल एक धातु सोना अथवा चादी प्रामाणिक माना जासकता है अथवा दोनो धातु साथ साथ प्रामाणिक माने जासकते हैं। पहिलेको एक धातु-पद्धति और दूसरेको द्विधातु-पद्धति कहते हैं। एक धातु पद्धतिमें सोना अथवा चादी प्रामाणिक द्रव्यके काममें लाये जाते हैं। इनमेंसे स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति स्वयं तीन रूपमें रही है:

- १ स्वर्ण-मुद्रा-पद्धति।
- २ अमुद्रित स्वर्ण-पद्धति।
- ३ स्वर्ण-विनिमय-पद्धति।

चादीवाली द्रव्य-पद्धतिके भी इसीप्रकार तीनरूप होसकते हैं। परन्तु व्यवहारमें यह मुद्रा पद्धतिके रूपमें ही रही है। भारतमें १८३५ से १८६२ तक यही पद्धति रही है। द्विधातु पद्धतिके भी दोभाग किये जासकते हैं। एक स्थिति तो शुद्ध द्विधातु-पद्धतिकी है जिसमें सोना और चादी दोनोंकी मुद्राओंको प्रामाणिक माना जाता है और दोनोंकी ठलाई अमर्यादित परिमाणमें होती है, दूसरी अवस्था यह है जिसमें दोनो धातुओंकी मुद्रायें चलनमें तो रहती हैं किन्तु केवल सोनेकी मुद्राओंको अमर्यादित परिमाणमें ढलवाया जासकता है। चादीकी मुद्राओंका स्वतन्त्र रूपसे ढलवाना बन्द करदिया जाता है। इस प्रकारकी द्विधातु-पद्धतिको हम अपूर्ण द्विधातु-पद्धति कहेंगे।

द्विधातु-पद्धति

किसी समय यूरोप और सयुक्तराज्य अमेरिकामें द्विधातु-पद्धतिको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परन्तु अब इसका द्रव्य सम्बन्धी विवेचनमें नामभी नहीं लिया जाता। अतएव हम इस पद्धतिका विवेचन संक्षेपमें ही करेंगे। इस पद्धतिमें राज्यकी ओर से दोनो धातुओंकी प्रामाणिक मुद्राओंको अनमर्यादित रूपमें ढलवानेका प्रबन्ध रहता है और दोनोंकी टकसाली दरभी राज्यद्वारा निर्धारित रहती है। द्विधातुवादी लोगोंने अनुसार सोने और चादीकी सम्मिलित वार्षिक उत्पत्तिमें इतनी घटबढ़ नहीं होती जितनीकि केवल चादी अथवा सोनेकी उत्पत्ति में। अतएव द्विधातु द्रव्य-पद्धतिमें द्रव्यके परिमाणमें और उसके विनिमय-मूल्यमें भी इतनी अस्थिरता नहीं होनेपावेगी जितनीकि एकधातु द्रव्य पद्धतिमें। यह तर्क ठीक नहीं है। पहिले तो सोने-चादी की उत्पत्तिमें एकही दिशामें परिवर्तन होनेकी सम्भावना रहती है। इसके अतिरिक्त द्रव्यके मूल्यमें परिवर्तन केवल सोने अथवा चादीके परिमाण परही अवलम्बित नहीं रहता और जैसा हम 'द्रव्यका विनिमय-मूल्य' नामक अध्यायमें बतायेंगे, द्रव्यके विनिमय-मूल्यका आधार केवल उसका परिमाण ही नहीं होता।

कहा जाता है कि द्विधातु-पद्धतिमें सोने-चादीके वार्षिक मूल्यमें स्थिरता लानेकी सम्भावना रहती है जिनके फलस्वरूप सोनेवाली द्रव्य-पद्धतिके देशों और चादीवाले द्रव्य-पद्धतिके देशोंकी विदेशी विनिमयकी दरमें स्थिरता आनेकी सम्भावना हो जाती है। इस प्रभावको द्विधातुवादी क्षतिपूरक सिद्धान्त द्वारा सिद्ध करते हैं। मानलीजिए द्विधातु पद्धतिके अन्तर्गत किसी कालमें सोने और चादीकी वार्षिक दर इस प्रकारकी है कि सोनेकी एक मुद्राका मूल्य उसी तोलकी २० चादी की मुद्राओंके बराबर है, और यह भी मानलीजिए कि उस कालमें बाजारमें भी यही दर है। अब यदि बाजारमें चादीके प्रचुर मात्रामें आ जानेके कारण सोने और चादीके मूल्यका अनुपात १ : २० से घटकर १ : २१ हो गया तो क्षतिपूरक सिद्धान्तके अनुसार यह बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। चूँकि चादी अमुद्रित रूपकी अपेक्षा मुद्रित रूपमें अधिक मूल्यवान होगी है और सोना मुद्रित रूपकी अपेक्षा अमुद्रित रूपमें अधिक मूल्य रखता है, अतएव लोग चादीको तो मुद्राओंके रूपमें परिवर्तित करने लगेंगे और सोनेकी मुद्राओंको पिघलाकर अमुद्रित रूपमें रखेंगे। इसका परिणाम

यह होगा कि बाजारमें चादीका परिमाण कम और सोनेका अधिक होनेसे उनमें १: २० वा अनुपात पुनः स्थापित होने लगेगा। इस तर्कमें कुछ सार अवश्य है परन्तु सोने और चादीके पारस्परिक मूल्यको बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक है कि अनेक देशोंमें द्विधातु-पद्धति चलनमें हो और ये देश सहकारितासे सोने और चादीकी टंकमाली दर नियत करें और उसको बनाय रखनेके लिए चेष्टा करें। यदि विशेष कारणसे किसी एक धातुका मूल्य और उसकी माग गिरती जा रही है, तो टंकमाली दरमें भी परिवर्तन करना आवश्यक होजायेगा।

द्विधातुवादमें एक विशेष त्रुटि यह है कि जब जब सोने और चादीके टंकमाली और बाजार दरमें भिन्नता आजाती है तब तब उस धातुकी मुद्रा जिसका बाजारमें अधिक मूल्य रहता है, चलनसे लुप्त होने लगती है और चलनमें वही मुद्रा रहजाती है जिसका बाजारभाव गिरगया हो। इसप्रकारकी परिस्थितिमें चलनमें कभी केवल चादीकी ही और कभी केवल सोने की ही मुद्रायें पायीजाती हैं।

ग्रेशम-नियम

इंग्लैंडके एक वाणिज्य-मंत्री सर टॉमस ग्रेशमने इस सुध्वन्धमें एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिसको ग्रेशम-नियम कहते हैं। इसके अनुसार जब अच्छी और बुरी दोनों प्रकारकी मुद्राओंका चलन हो, तो अच्छी मुद्राएं चलनसे लुप्त होने लगती हैं और बुरी मुद्राएं चलन में रहजाती हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखीगयी है कि लोग पूरी तौलवाली नयी मुद्राओंका संग्रह करते हैं, उनको पिघलाते हैं अथवा दूसरे देशोंमें भेजते हैं अतः उनमें स्थित धातुका मूल्यही मान्य होता है और चलनमें पुरानी, घिसी अथवा कटी हुई मुद्राएं रहजाती हैं। द्विधातुवादमें जिस धातुकी बाजार दर गिरजाती है उस धातुकी मुद्रातो चलनमें रहती है और जिस धातुकी दर टंकमाली धातुसे अधिक रहती है उसकी मुद्राएं चलनमें लुप्त होने लगती हैं।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति

एक धातु-पद्धतिमें स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। २० वर्ष

पहिले तक यह पद्धति प्रायः सभी उन्नतिशील देशोंमें किसी न किसी रूपमें व्यवहार में रही है। आजभी अनेक व्यक्ति इसके समर्थक हैं। अतएव हम इस पद्धतिकी निवेचना कुछ विस्तारसे करेंगे। वैसेतो सोनेकी मुद्राएँ प्राचीन कालमें भी अनेक देशोंमें रहीहैं परन्तु पद्धतिके रूपमें इसका विकास इंग्लैंडमें १९वीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें हुआ और इस शताब्दीके समाप्त होते होते ससारके अनेक देशोंने इसे अपना लिया।

स्वर्ण-मुद्रा-पद्धति

प्रारम्भमें स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति स्वर्ण-मुद्रा-पद्धतिके रूपमें चलनमें रही। ऐसी पद्धति में राज्य द्वारा निर्धारित तौलकी सोनेकी मुद्रा प्रामाणिक निश्चित करदी जातीहै और जनसाधारण को स्वाधीनता रहतीहै कि वे किसीभी परिमाणमें राज्यकी टक-सालमें अमुद्रित सोनेकी प्रामाणिक मुद्राएँ ढलवा सकते हैं। इन मुद्राओंको पिघला कर अमुद्रित रूपमें रखनेकी और सोनेके प्रायात निर्यातकी स्वतन्त्रता रहती है। चलनमें जो अन्य प्रकारका राज्य प्रमाणित द्रव्य, साकेतिक मुद्रा अथवा नोटके रूपमें रहताहै, हमारे बदलेमें राज्य एक पूर्वनिर्धारित दरसे स्वर्णमुद्रा देनेकी बाध्य रहता है जिसके लिए उसे स्वर्णमुद्राकोप रखना पड़ता है।

इस प्रकारकी पद्धतिका काल प्रथम महायुद्धके पहिलेका मानाजाता है। युद्ध कालमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त प्रायः सभी राज्योंने स्वर्ण-मुद्रा-पद्धति के चलनको स्थगित करदिया था। नोट और साकेतिक मुद्राएँ अविनिमय-साध्य होगयीं। युद्धकालमें और युद्धके पश्चात् अनेक देशोंकी द्रव्य-पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होगयीं थीं। अतएव इनके पुनर्निर्माण कार्यकी आवश्यकता पड़ी। दो अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-सम्मेलन सन् १९२० और सन् १९२२ में ब्रुसेल्स और जिनेवामें हुए जिनमें स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति का पुनरुद्धार करना निश्चित हुआ।

अमुद्रित-स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति

युद्धकालकी एवं युद्धपूर्वकी स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिमें कुछ त्रुटियाँ पायीगयीं थीं। एकतो यहकि सोनेकी मुद्राओंको ढलवानेमें व्यय होता है। आर्थिक साधनोंको इस कार्यमें

लगाना पड़ता है। दूसरे, चलनमें रहनेके कारण, घिसनेसे भी धातुकी हानि होती है। तीसरे, यह कि इस पद्धतिके अन्तर्गत द्रव्यके परिमाणको आधिक परिस्थितिके अनुकूल बनानेमें कठिनाई होती है। अनुभवसे यह भी ज्ञात हुआ कि देशके भीतर चलनके कार्योंके लिए स्वर्ण-मुद्राकी कोई आवश्यकता नहीं होती, विनिमयके कार्योंके लिए कागजकी बनी मुद्रा अर्थात् नोटसे भी काम चलसकता है जैसा कि युद्धकालमें हुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन की विपमता दूर करनेके लिए धातुकी मुद्राकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अतएव युद्धकालके बाद जो स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति प्रचलित हुई उसको अमुद्रित स्वर्ण-पद्धतिका नाम दिया गया। इसके अन्तर्गत चलनेमें तो नोट और साकेतिक मुद्राएँ रही, परन्तु इनके बदलेमें द्रव्याधिकारी स्वर्ण-मुद्राएँ देनेको बाध्य नहीं थे। स्वर्ण मुद्राके स्थानपर अमुद्रित स्वर्ण एक निर्धारित दरसे दिया जाता था। किसी किसी देशमें इसप्रकार का प्रबन्ध हुआ कि स्वर्ण एक विशेष परिमाणसे कम परिमाणमें नहीं दिया जाता था। इसका यह उद्देश्य था कि द्रव्याधिकारियोंके पास जो स्वर्णकोष जमा रहता था उसका प्रयोग देशके भीतरके कार्योंके लिए नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्योंके लिए किया जाये। अमुद्रित स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति स्वर्ण-मुद्रा-पद्धति से कम व्यवहारी हुई। परन्तु स्वर्णकोष की आवश्यकता तो इसमें भी बनी रहती है और द्रव्यका परिमाण भी इस कोषसे सलग्न रहता है।

• स्वर्ण-विनिमय-द्रव्य-पद्धति

युद्धकालके बाद कुछ देशोंने स्वर्ण-विनिमय-पद्धतिको ग्रहण किया। इस पद्धतिवाले देशोंको न तो स्वर्ण मुद्राओंको चलनमें लाना पड़ता है और न अन्य प्रकारके द्रव्यके बदलेमें अमुद्रित सोना देना पड़ता है। देशके द्रव्यके बदलेमें राज्य किसी ऐसे देशके द्रव्यको देनेकी प्रतिज्ञा करता है जिसमें स्वर्ण-मुद्रा अथवा अमुद्रित-स्वर्ण-पद्धतिका चलन हो। भारतमें प्रथम महायुद्धके पूर्व एक प्रकारसे स्वर्ण-विनिमय-द्रव्य-पद्धति थी। रुपयेके बदले भारत सरकार १ शि० ४ पे० की दरसे स्टर्लिंग (इंग्लैंडका द्रव्य) देनेको उद्यत रहती थी और स्टर्लिंग सोनेकी मुद्रामें परिवर्तनशील था। इसप्रकार की द्रव्य-पद्धतिमें अप्रत्यक्ष रूपसे स्थानीय द्रव्यके बदलेमें एक निर्धारित दरपर सोना मिल सक्ता था। इस पद्धतिको कार्यान्वित करनेके लिए राज्यको स्वर्ण-पद्धति

घाले देशके द्रव्यका कोष उस देशमें जमा करना पड़ताहै जिसमेंसे अपने देशवासियों को स्थानीय द्रव्यके बदलेमें विदेशी द्रव्य दिया जासके। भारत सरकार इस कार्यके लिए इंग्लैंडमें एक स्टलिंग-कोष रखती थी।

स्वर्ण-विनिमय द्रव्य-पद्धति अन्य दो प्रकार की स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतियोंसे कम व्यय वालीहै क्योंकि इसमें सोनेकी मुद्राओंके चलवानेका व्यय नहीं होता और मुद्राके धिमेनसे घातुकी हानिभी नहीं होती। अतएव इस पद्धतिको पिछड़ेहुए अथवा हारे हुए देशोंने प्रहृण किया। मितव्ययिताही इसका एकमात्र गुण है। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक त्रुटियाँ एव आपत्तियाँ हैं। पहिल तो, जबतक कोईभी देश स्वर्ण-द्रव्य अथवा समुचित स्वर्ण-पद्धतिवाला न हो, तबतक स्वर्ण-विनिमय-द्रव्य पद्धतिको चलनमें लायाही नहीं जासकता। इसीसे पता चलजाताहै कि यह पद्धति स्वतन्त्र नहीं होसकती। इसकी पराधीनता उस द्रव्यसे होजाती है जिसको इसके द्रव्याधिकारी देनेका वचन देते हैं। यदि विदेशी पद्धति स्वर्ण-पद्धतिसे अलग करदी गयी तो स्वर्ण-विनिमय द्रव्य-पद्धतिका स्वयमेव अन्त होजाता है। इसके अतिरिक्त यदि विदेशी द्रव्य-पद्धतिके स्वर्णाधारको छोड़नेके कारण उसके मूल्यमें ह्रास होजाय, तो स्वर्ण-विनिमय-मुद्रा-पद्धतिवाल देशमें जो विदेशी द्रव्यका कोष रहताहै, उसका मूल्य में भी हास हाजाता है। सन् १९३१ में जब इंग्लैंडने अमुद्रित-स्वर्ण-पद्धतिका त्याग किया उसी समयसे भारतकी द्रव्य-पद्धति स्वर्ण-विनिमय-द्रव्य-पद्धतिमें बदल कर केवल स्टलिंग-विनिमय-द्रव्य-पद्धति रहगयी और स्टलिंगके मूल्यमें ह्रास हान के कारण हमारे स्टलिंग कोषको भी भारी क्षति पहुची।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति के गुण और दोष

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिका एकगुण यह बताया जाताहै कि चूँकि इस पद्धतिमें द्रव्य या तो सोनका बताया जाताहै अथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपमें सोनेमें एक निर्धारित दर पर विनिमय शील रहताहै। अतएव जनताका इस पद्धतिपर विश्वास बनारहता है। पूर्वकालमें जबकि किसी मूल्यवान पदार्थसे बनेहुए द्रव्यकी ही अच्छा द्रव्य समझा जाताथा इस तर्कमें कुछ सार रहाहोश परन्तु प्राधुनिककालमें तो हम देखतेहैं कि द्रव्यके कार्यको सम्पादित करनेके लिए यह आवश्यक नहींहै कि द्रव्य सोने जैसी बहु-

मूल्य धातुका बनाहो। जहातक विश्वासका प्रश्नहै, जबतक द्रव्यके बदलमें अन्य वस्तुएं और सेवाएं मिलती रहेंगी, तबतक उस द्रव्यमें विश्वास बनारहेगा। अतएव विश्वास बनाये रखनेके लिए द्रव्यकी ऋय-शक्तिको बनाये रखनाहै न कि उसको सोनेका बनाना।

यहभी कहा जाताहै कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत द्रव्य-स्फीतिका भय नहीं रहता और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें भी अधिक परिवर्तन नहीं होता। चूँकि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिमें द्रव्यका परिमाण सोनेके परिमाणसे सलग्न रहताहै और सोनेका परिमाण सहसा प्रचुरतासे बढ़ाया नहीं जासकता, अतएव यह ठीक प्रतीत होताहै कि इस पद्धतिमें एकवारगी द्रव्य-स्फीतिकी आशंका नहीं रहती। परन्तु यदि सभी स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिवाले देश सोनेका भाव बढ़ा दें तो उत्तनेही परिमाणके स्वर्ण-कोष के आधारपर वह अधिक नोट प्रचलितकर द्रव्य-स्फीतिकी अवस्था उत्पन्न करसकते हैं। जहातक इस पद्धतिमें द्रव्य-मूल्यकी स्थिरताका प्रश्नहै उसका खडन हम १६२६-१६३२ के विश्वव्यापी आर्थिक मकटके उदाहरणसे करसकते हैं। सन् १६२६ के बाद मूल्य-स्तर गिरनेलगा और द्रव्यका विनिमय-मूल्य बढ़नेलगा जबकि सत्तारके सभी राज्योंमें स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति प्रचलित थी। इससे हम इस परिणामपर पहुँचतेहैं कि द्रव्यका विनिमय मूल्य केवल द्रव्यके परिमाणपर ही अवलम्बित नहीं रहता बल्कि इसको निर्धारित करनेमें अन्य कारणोंका भी हाथ रहताहै जिनका विवेचन हम 'द्रव्य का विनिमय-मूल्य' वाले अध्यायमें करेंगे।

इस पद्धतिमें एक बड़ा लाभ यहहै कि विदेशी-विनिमयकी दरमें स्थिरता आजाती है। यदि अनेक राज्य अपने अपने द्रव्यमें सोनेका भाव निर्धारित कर दें और इस भावपर वशोकटंक माना बेचने और मोल लेनेको बद्ध हो और सोनेके आयात-निर्यातपर कोई प्रतिबन्ध न लगायें, तो ऐसी स्थितिमें स्वर्ण-द्रव्यवाले देशोंके द्रव्यमें विदेशी विनिमयकी दर स्वयमेव निर्धारित होजायेगी और उसमें बहुत कम परिवर्तनकी आशंका रहेगी। उदाहरणके लिए मान लीजिए भारत और इंग्लैंडमें स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिका चयनहै और भारत सरकार एकतोले सोनेका मूल्य १०० रुपया निर्धारित करतीहै और इंग्लैंडकी सरकार एकतोले सोनेका मूल्य १५० शि०। ऐसी अवस्थामें स्वयमेव भारत और इंग्लैंडकी विदेशी विनिमय-दर १ रु० = १ शि० ६ पे० हुई। इस दरको 'टकसाली विनिमय-दर' कहते हैं। जबतक भारत और

इंग्लैंडकी सरकार सोनेके इस निर्धारित भावको बनाये रखेगी, तबतक विदेशी विनिमय-दर १ रु० = १ शि० ६ पे० के आसपास रहेगी। आसपास इसलिए कहा गयाहै कि व्यवहारमें एक सकुचित सीमाके अन्तर्गत जिसको स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात मर्यादा कहतेहैं, इस दरमें परिवर्तन होसकता है। सोनेको एक देशसे दूसरे देश भेजनेमें जो व्यय होताहै और उस अवधिमें जो व्याजकी हानि होती है, उससे इस मर्यादाकी सीमा निर्धारित होती है। उदाहरणके लिए यदि १ रु० के मूल्यके सोनेको भारतसे इंग्लैंड भेजनेमें १/४ पे० व्यय होताहै तो स्वर्ण-आयात और निर्यातकी मर्यादा १ शि० ६ १/४ पे० और १ शि० ५ ३/४ पे० हुई और इन दो देशोंमें विनिमयकी दर इस मर्यादाके बाहर नहीं जासकती।

विदेशी विनिमयके प्रकरणमें स्वर्ण-पद्धतिको अन्तर्राष्ट्रीय कहाजाता है क्योंकि जो जो राष्ट्र इस पद्धतिको ग्रहण करतेहैं उनमें वस्तुतः एकही प्रकारका द्रव्य हो जाता है, चाहे विभिन्न देशोंमें उस द्रव्यके भिन्न भिन्न नाम हों (साबरिन, फ्राक, डालर आदि)। अब हम यह बतानका प्रयत्न करेंगे कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति वाले देशोंके द्रव्योंकी विनिमय-दर स्वर्ण-आयात और निर्यातकी मर्यादाके अन्दरही क्यों रहती है। मान लीजिए इस द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय लेनी देनेकी सम्बन्ध में भारत इंग्लैंडका ऋणी बनजाता है और तदनुसार भारतवासियों की इंग्लैंडके द्रव्य स्टालिगकी माग बढ़जाती है। यदि माग इतनी बड़ीहुई है कि १ शि० ६ पे० प्रति रु० के हिसाबसे उसकी पूर्ति नहीं होपाती तो विदेशी-विनिमयके विजेता एक रु० के बदलेमें १ शि० ६ पे० से कम परिमाणमें स्टालिग देने लगेंगे। जब यह दर गिरते गिरते १ शि० ५ ३/४ पे० पर पहुँच जातीहै तो इससे नीचे जानेपर भारत से सोनेका निर्यात प्रारम्भ होजायेगा। इसका कारण यहहै कि भारत-सरकार एक रु० के बदलेमें इतने परिमाणमें सोना देनेकी बाध्यहै कि जिसमें से भारतसे इंग्लैंड भेजनेका व्यय निकालकर इंग्लैंडमें १ शि० ५ ३/४ पे० मिलसकते हैं। अब यदि विदेशी विनिमयके विजेता एक रु० के बदलेमें उक्त स्टालिगसे कमदे तो यहाके ऋणी वर्गको सरकारसे सोना लेकर इंग्लैंड भेजनेमें अधिक लाभ होगा। अतएव १ शि० ५ ३/४ पे० से नीची विदेशी-विनिमय-दर नहीं होने पायेगी।

इसके प्रतिकूल यदि लेनी देनेकी मदोंके सम्बन्धमें इंग्लैंडका भारतके प्रति दायित्व अधिकहै तो रु० की माग अधिक होने लगेगी और रु० की विदेशी-विनिमय दर

१ सि० ६ पे० से ऊची उठने लगेगी। परन्तु १ सि० ६ १/४ पे० पर पहुँचने पर यह वृद्धि रुक जायेगी, क्योंकि इससे ऊँची होने पर इंग्लैंड में भारतको सोना भेजना सस्ता पड़ेगा इसका कारण यह है कि इंग्लैंड से भारतको सोना भेजने का व्यय जोड़कर १ सि० ६ १/४ पे० में इतना मोना इंग्लैंड बासियोंको अपनी सरकार में मिल जाता है जिससे उनको भारत में १ रु० प्राप्त होता है। अतएव वे एक रु० प्राप्त करने के लिए १ सि० ६ १/४ पे० से अधिक स्टर्लिंग नहीं देंगे। १ सि० ६ १/४ पे० की मर्यादा भारतके लिए स्वर्ण-आयात मर्यादा हुई।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति के व्यावहारिक नियम

उपरोक्त व्याख्यासे यह सिद्ध होता है कि स्वर्ण-द्रव्य पद्धति वाले देशों की विदेशी विनिमय-दर स्वर्ण-आयात-निर्यात मर्यादाके अन्तर्गत रहती है। इस पद्धतिके अनुयायी महभी बताते हैं कि सोनेके आयात और निर्यातसे अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनी का सन्तुलन भी यथार्थ होता है। इस सन्तुलनको पुनः प्राप्त करनेके लिए जो आर्थिक क्रियाएँ इन देशों में चरितार्थ होती हैं, उनके आधार पर स्वर्ण द्रव्य पद्धति के व्यावहारिक नियम बनाय गये हैं जिनका पालन करना इन देशों का धर्म होता है। मान लीजिये भारतको लेनी देनी की विषमताके कारण इंग्लैंडको पर्याप्त मात्रा में सोना भेजना पड़ा। चूँकि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति में द्रव्यका परिमाण सोनेके कोष से सम्बद्ध रहता है, अतएव सोनेके आधारकी क्षति होनेके कारण चलन में द्रव्यके परिमाण में भी कमी आ जायेगी। यह कमी निर्यात क्रिये सोनेके मूल्यसे वही अधिक होगी क्योंकि प्रचलित द्रव्यका आंशिक मूल्य ही स्वर्णके रूप में कायम रहता है। यदि कोष में एक स्वर्ण मुद्राके आधार पर चलन में पाँच नोट प्रचलित हैं तो कोष में एक मुद्राकी क्षति होने पर सोना और चलन में स्थित द्रव्यका अनुपात बनाये रखनेके लिए पाँच नोटोंको चलन से निकालना पड़ेगा। (यथापर हमने यह मान लिया है कि कोष में अतिरिक्त सोना नहीं है) अब यदि भारतसे इंग्लैंडको सोना निर्यात होने लगा तो यहाँ चलन में द्रव्यका संकुचन होने लगेगा। इसके फलस्वरूप यहाँ के आय-स्तर और मूल्य-स्तर बिस्तरे लगेगे। आय का स्तर गिरनेसे यहाँ के लोग इंग्लैंड में उतने परिमाण में सामान नहीं मोल ले सकेंगे जितना पहिले लिया करते थे। अतएव भारत में

इंग्लैंड की वस्तुओंका आयात कम होजायेगा। इसके अतिरिक्त मूल्य-स्तरमें कमी आनेके कारण भारतकी वस्तुओंकी माग इंग्लैंडमें बढ़ने लगेगी। भारत अधिक मात्रा में स्टलिंग उपार्जन करने लगेगा और उसकी स्टलिंगकी मागमें कमी आने लगेगी। इसप्रकार भारत और इंग्लैंडके बीच सेनोदेनी का सन्तुलन ठीक होने लगेगा। इस सन्तुलनको बायम लानेकी क्रियाके विवरणको पूरा करनेके लिए हमको, इंग्लैंडमें सोनेके आयातका नया आर्थिक प्रभाव पडा इसका भी विस्तरेषण करना पड़ेगा। इंग्लैंडमें जो सोना पहुँचा उसके आधारपर चलनमें द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि आ जायेगी। इसके परिणामस्वरूप वहाके आय-स्तर और मूल्य-स्तरमें वृद्धि होने लगेगी। आय-स्तरमें वृद्धि होनेसे इंग्लैंड आसे भारतसे अधिक मात्रामें सामान मोल लेने लगेगे और मूल्य-स्तरमें वृद्धि होनेके कारण इंग्लैंडकी वस्तुओंका निर्यात भारत को कम मात्रामें होगा। इससेभी भारत और इंग्लैंडके बीच सेनोदेनीके सन्तुलनको पुनः प्राप्त होनेमें सहायता मिलेगी।

अब हम स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके व्यावहारिक नियमोंका प्रतिपादन करसकते हैं। पहिला नियम यहहै कि जिस देशसे द्रव्य-सम्बन्धी सोनेका निर्यात होताहै, उस देश के द्रव्य-प्रबन्धक द्रव्यके परिमाणको सकुचित करनेकी नीतिका अवलम्बन करें और जिस देशमें इस सोनेका आयात होनाहै वहाके द्रव्य-प्रबन्धक द्रव्यके परिमाणका विस्तारकरें। दूसरा नियम यहहै कि जिस देशसे सोना बाहर गयाहो, उस देशमें लागत आय और मूल्य-स्तरोंमें कमी आने दीजाये और जिस देशमें सोना आयाहै उस देशमें लागत, आय और मूल्य-स्तरोंमें वृद्धि होने दीजाये। इस प्रवृत्तिको कार्यान्वित करनेके लिए स्वर्ण निर्यातवाले केन्द्रीय बैंक अपनी व्याजकी दर बढ़ा देते हैं और स्वर्ण-आयात वाले देशके केन्द्रीय बैंक व्याजकी दर कम करदेते-हैं।

उपरोक्त विवेचनसे एक बात तो स्पष्ट होजाती है कि स्वर्ण द्रव्यवाले देशोंकी विदेशी विनिमयकी दरकी स्थिरता को बनाये रखनेके लिए और सेनोदेनीके सन्तुलनको प्राप्त करनेके लिए अपनी आर्थिक व्यवस्थामें द्रव्य-सकुचन और द्रव्य स्फीति का प्रादुर्भाव और उससे उत्पन्न आर्थिक अस्थिरता को स्वीकार करना पड़ता है।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके गुणोंकी विवेचना करनेपर पता चलताहै कि इन गुणोंमें अपवादभी विद्यमान है। इन अपवादोंके अतिरिक्त इस पद्धतिमें प्रधान त्रुटि यह

है कि हमने अन्तर्गत द्रव्यके परिमाणको बढ़तती हुई आर्थिक स्थितिके अनुकूल करनेमें सुविधा नहीं रहती है। हम ऊपर बता चुके हैं कि इस पद्धतिवाले देशोंको विदेशी विनिमयकी दर बनाये रखनेके लिए एक बड़ा मूल्य देना पड़ता है और यह मूल्य आन्तरिक आर्थिक व्यवस्थामें अस्थिरता उत्पन्न कर देता है।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति का अन्त

सन १६३१ में इसलैडने स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिकी परित्याग किया और धीरे धीरे सभी देशोंने इसका अनुसरण किया। इसके तीन प्रधान कारण हैं। एक कारण यह है कि इस पद्धतिके निर्बाधित रूपसे चलनेके लिए जिस आर्थिक वातावरणकी आवश्यकता होती है, वह वातावरण प्रथम महायुद्धके बादकी आर्थिक पद्धतिमें न प्राप्त हो सका। दूसरा कारण यह है कि इस कालमें अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनी की विषमता इतनी अधिक होगयी कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति उसके भारको सहन करनेमें असमर्थ प्रतीत होने लगी और तीसरा कारण यह था कि कोईभी देश अपनी आर्थिक व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-पद्धतिके नियमोंके आधीन करनेको प्रस्तुत नहीं था।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके ठीक प्रकारसे कार्य कर सकनेके लिए यह आवश्यक है कि सोनेके आयात और निर्यातका पूरा प्रभाव इन देशोंकी आन्तरिक आर्थिक स्थितिपर पड़ने दिया जाये और आय, लागत तथा मूल्यके स्तरोंको तदनुसार बढ़ाया अथवा घटाया जाये। परन्तु इस कालमें जिन देशोंसे सोना बाहर जाने लगा, उन देशोंने इस आशका से कि उनमें बेकारी और आर्थिक मन्दी न आजाये द्रव्यके परिमाण और मूल्य-स्तरोंमें कमी नहीं आने दी। और जिन देशों को सोना प्राप्त हुआ, उन देशोंने भी द्रव्य-स्फीति की आशका से द्रव्यके परिमाण एवं मूल्य-स्तरोंमें वृद्धि नहीं होने दी। इसके अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्थामें भी महायुद्धके पहिलेकी स्थिति नहीं रह गयी थी जिसमें लागत व्यय और मूल्योंको सुगमतासे वृद्धि जा सके। मजदूर सघ और एकाधिकारियोंका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। स्वर्ण-पद्धतिमें अन्तर्राष्ट्रीय लेनीदेनी का सन्तुलन बनाये रखने का मार्ग केवल मुक्त-द्वार व्यापार-नीति है। परन्तु इस कालमें साहूकार देशों ने ऋणी देशोंसे वस्तुओंके रूपमें अपना पावना लेनेसे इन्कार कर दिया और सोनेके रूपमें लेनेका आग्रह किया। ऋणी देशोंने

अपनी विदेशी देनदारी कम करनेके लिए आयात-कर लगाकर आयातका परिमाण घटानेकी चेष्टाकी और साहूकार देशोंने भी इसके प्रत्युत्तरमें आयात-नरोक्की स्थापना और वृद्धि करदी। इसके फलस्वरूप एक देशसे दूसरे देशोंको आयात निर्यातके परिमाणोंमें परिवर्तन होनेसे जो सन्तुलन होनेकी प्रवृत्ति होती थी, उसका विरोध होने लगा।

इस कालमें अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनके परिमाणमें भी बहुत वृद्धि हुई। इसका एक कारण यहथा कि यूरोपके कई देशोंको जो युद्धके कारण गिरी अवस्थामें थे, सम्पन्न राज्योंने (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका) आर्थिक निर्माण कार्यके लिए ऋण दिया। इसका कारण यहथा कि अल्पकालीन पूँजीमें व्याजकी दरमें अममानताके कारण अथवा आर्थिक दुरावस्थासे रक्षाके निमित्त बहुत क्षीघ्रतासे बड़ी मात्राम एक देश से दूसरे देशको भेजी जानेकी प्रवृत्ति होन लगी थी। इसके अतिरिक्त युद्ध सम्बन्धी ऋण और क्षतिपूरक धनको देनेका परिमाणभी बहुत बढ़गया था। इन कारणोंने स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिपर बहुत भार पड़ने लगा जिसका वहन करना उसके लिए दुष्कर होगया।

युद्धके पश्चात् प्रत्येक देशको अपने स्वार्थकी ही चिन्ता थी। सभीको आर्थिक साधनोंको पूर्ण रूपसे काममें लाकर राष्ट्रीय आयको बढ़ाना और जीवन-स्तरको ऊँचा करना था। अतएव विदेशी विनिमयकी दरकी स्थिरताकी अपेक्षा आर्थिक स्तरकी स्थिरताको अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जानेसगा था। यही कारणथा कि जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके व्यावहारिक नियमोंकी अवहेलना होने लगी। अर्थशास्त्रियों और राज्य-अवन्धको को यह विश्वास होगया कि स्वर्ण पद्धति प्रतिवन्धोंके अन्तर्गत आर्थिक विकास और स्थिरता प्राप्त करनेमें बहुत कठिनाईयाँ हैं।

अविनिमय-साध्य प्रवन्धित द्रव्य-पद्धति

~ द्रव्य-पद्धतिमें एक विशेष गुण यह होना चाहिए कि उसको सुगमतासे आन्तरिक आर्थिक व्यवस्थाके अनुकूल बनाया जासके। स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिमें यह बात पर्याप्त मात्रामें नहीं पायी जाती। इसीकारण अविनिमयसाध्य द्रव्य-पद्धतिको अधिक

महत्त्व दिया जाने लगा। इस पद्धतिके अन्तर्गत द्रव्यका परिमाण सोनेके कोपक परिमाणमें सम्बन्धित नहीं रहता। यह सोनेकी मृत्खनाओंसे मुक्त होजाती है, सन् १६३१ से पहिलेभी युद्ध इत्यादि आर्थिक सक्कोंके अवसरोपर अनेक देशोंने स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिका त्याग करदिया था। परन्तु यह त्याग सकटकासीन ही था। सन् १६३१ के बाद सदेवके लिए इस पद्धतिका त्याग करदिया गया है। जब द्रव्य के परिमाणको इसप्रकार स्वतन्त्र करदिया गया तो उसका प्रबन्ध और नियन्त्रण अन्य आर्थिक उद्देश्योंके अन्तर्गत करना आवश्यक होजाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति प्रबन्धित नहीं थी। प्रबन्ध तो उसमेंभी करना पड़ता था परन्तु औधुनिक प्रबन्धित द्रव्य-पद्धतिकी अपेक्षा उसमें प्रबन्धकी मात्रा और उद्देश्यमें अन्तर है। स्वर्ण द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत इस प्रकारका प्रबन्ध करना पड़ताथा कि द्रव्यका परिमाण सोनेमें विनिमययोग्य बनारहे और विदेशी विनिमयकी दरमें स्थिरता बनी रहे। इन्हीं उद्देश्योंके आधारपर द्रव्य-नीति का प्रयोग कियाजाता था। प्रबन्धित द्रव्य-पद्धतिमें प्रबन्धके उद्देश्य दूसरे प्रकारके हैं। कुछ अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार द्रव्यका इसप्रकार प्रबन्ध कियाजाये कि वह आर्थिक क्रियामें एव सम्बन्धोंमें विकार न उत्पन्न करे अर्थात् वह तटस्थ रहे। यह निर्विवरदहै कि आर्थिक कार्योंमें द्रव्यका उपयोम होनेमें आर्थिक व्यवस्थाके भिन्न भिन्न अवयवोंका सम्बन्ध उसी प्रकारका नहीं रहसजना जैसाकि अदल-बदल प्रवाके अन्तर्गत रहता था। अर्थात् द्रव्यका अपना निजी प्रभावभी आर्थिक सम्बन्धोंपर पड़ता है। तदर्थ द्रव्य-नीतिके मतानुसारियोंका कहनाहै कि आर्थिक अस्थिरताओंका प्रधान कारण यहीहै कि द्रव्य और वित्तोपकर साख-द्रव्यता परिमाण आर्थिक सम्बन्धोंमें व्याघात पहुँचाकर आर्थिक प्रगतिमें अस्थिरता उत्पन्न करदेता है। अतएव यदि द्रव्यका प्रबन्ध इसप्रकार किया जाये कि द्रव्यमें आर्थिक कार्य लेंते रहनेपरभी आर्थिक सम्बन्ध उसी प्रकारके बनेरहें जैसाकि द्रव्यहीन आर्थिक पद्धतिमें होनेतो इसप्रकार द्रव्यकी तटस्थता बनी रहेगी। सैद्धान्तिक रूपमें यदि हम द्रव्यकी तटस्थता की नीतिको महत्त्वपूर्ण मानभी लें तो भी व्यवहारमें द्रव्यका इसप्रकार प्रबन्ध करना कि वह पूण रूपसे तटस्थ रहे, बहुत कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त यह मानलेना भी असंगत जानपड़ता है कि द्रव्य—हीन आर्थिक व्यवस्थामें जो सम्बन्ध उसके विविध अवयवों में स्थापित होजाते थे, उनको बनाये रखनेसे आर्थिक प्रगति अविवरोध रूपसे होती रहेगी।

प्रबन्धित द्रव्य-पद्धतिके कुछ अनुयायी चाहते हैं कि द्रव्यका प्रबन्ध इसप्रकारसे किया जाये कि उससे आर्थिक साधनोंको पूर्णरूपसे बराबर काममें लगाकर पूर्ण नियोग की स्थितिमें स्थिरताका समावेश किया जाये। यह एक महत्वाकांक्षा है। परन्तु दुःख इस बातका है कि हमारी सारी आर्थिक व्याधियाँ और अस्थिरताएँ द्रव्य जनित नहीं हैं। अतएव यह आशा करना कि द्रव्यका इसप्रकार प्रबन्ध किया जासकता है कि सभी आर्थिक क्रियाएँ अवरोध रूपसे अग्रसर होती रहें, मृग मरी-चिकाएँ समाप्त हों। तथापि प्रबन्धित द्रव्य-पद्धतिमें आशा की जाती है कि यह अपनी अस्थिरताओं को आर्थिक अस्थिरताओं के ऊपर न लाददे और जहातक सम्भव हो, अपनेको आर्थिक अवस्थाके अनुकूल रखतेहुए अन्य आर्थिक उपचारोंको कार्यान्वित करनेमें सहायता प्रदान करे।

कुछ अन्य अर्थशास्त्री प्रबन्धित द्रव्य-पद्धतिसे यह आशा करते हैं कि इसके अन्तर्गत मूल्य-स्तरोंकी स्थिर बनानेकी सुविधा होगी। ये लोग यह मानते हैं कि द्रव्यके विनिमय मूल्य और वस्तुओंके मूल्य-स्तरोंमें स्थिरताका समावेश होनेपर आर्थिक स्थिरता प्राप्त करनेमें सहायता मिलेगी। इनके मतमें एक अच्छी द्रव्य-पद्धतिसे यही आशा करनी चाहिए। अब हमको यह विचार करना है कि मूल्य-स्तरोंमें स्थिरता लाना कितना वांछनीय है और यदि नहीं तो क्या यह स्थिरता द्रव्य-नीति द्वारा प्राप्त होसकती है।

यह तो सभी लोग माननेको तैयार होंगे कि वस्तुओंके मूल्य-स्तरोंमें अधिक मात्रामें उलटफेर होनेके कारण आर्थिक विपमताएँ उत्पन्न होजाती हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्य हमारा मापदण्ड भी है। अतएव इसके विनिमय-मूल्यमें अधिक मात्रामें अस्थिरता उत्पन्न होजाना (जो कि मूल्य-स्तरोंमें बदलाव हो जानेपर अवश्यम्भावी है) भी हमको वांछित नहीं है। परन्तु इससे इस परिणामपर नहीं पहुँच जाना चाहिए कि हमको प्रत्येक अवस्थामें मूल्य-स्तरोंकी स्थिरता वांछनीय है। सन् १९२९-३२ के विश्वव्यापी आर्थिक अपकण्डसे पूर्व कुछ वर्षोंतक मूल्य-स्तरोंमें स्थिरता वर्तमान थी। फिरभी यह आर्थिक संकटको न रोक सकी। इसका प्रधान कारण यह था कि इस कालमें नवीन आविष्कारों और वैज्ञानिक प्रबन्धोंके प्रयोगसे उत्पादन-व्यय घटने लगा था और मूल्योंमें स्थिरताके कारण सामग्री का बढ़ने से पूँजीका लगाव अत्यधिक मात्रामें होने लगा। इससे हम इस परिणामपर

पहुँचते हैं कि जब पूर्वोक्त कारणोंसे उत्पादकता की वृद्धि हो और प्रति इकाई लागत व्यय कम हो जाये, तो मूल्य-स्तरमें भी कमी आनी चाहिए। ऐसा न होनेपर आर्थिक सम्बन्धोंमें अन्तर हो जाता है जिससे आर्थिक व्यवस्थामें गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि जिन लोगोंकी बचो हुई आय होती है उनको वैज्ञानिक उन्नतिमें उत्पादकतामें जो वृद्धि होती है उसका लाभ सभी मिल सकता है जब मूल्य-स्तरमें कमी आये।

यदि हम बातको मान भी लिया जाये कि मूल्य-स्तर को द्रव्य-नीति द्वारा स्थिर रखनेका प्रयत्न करना चाहिए तो प्रश्न यह होता है कि किस स्तरपर स्थिर रखना चाहिए। भारतमें मूल्य-स्तर इस समय बहुत ऊँचा है। सभी लोग चाहते हैं कि इसमें कमी हो, परन्तु यह बताना बहुत कठिन है कि किस स्तर तक कमी की जानी चाहिए जिससे समाजका अधिकतम धोम हो। इसी प्रकार जब १९२६-३२ की आर्थिक मन्दीके अवसरपर प्रबन्धित द्रव्य-पद्धति द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड मूल्य-स्तरको बढ़ानेका प्रयत्न कर रहे थे, हम बातपर एकमत नहीं था कि मूल्य-स्तरको किस स्तर तक बढ़ाकर स्थिर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम अगले अध्यायमें बतावेंगे, मूल्य-स्तर अनेक मूल्योंका औसत मात्र है। अतएव प्रश्न यह होता है कि क्या औसत मूल्य-स्तरको स्थिर रखनेसे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जायगा। सूचक अंक (जिससे द्रव्य-स्तर का गणित किया जाता है) बनानेमें ही अनेक कठिनाइयाँ सामना करना पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त सूचक अंकोंके समान रहनेसे यह परिणाम नहीं निकलता कि मूल्य-स्तरोंमें और उनके आपसके सम्बन्धोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उदाहरणके लिए यदि एक वस्तुका मूल्य २५ प्रतिशत बढ़ गया और दूसरी वस्तुका मूल्य २५ प्रतिशत घट गया तो औसत मूल्य-स्तर तो समान रहेगा परन्तु इन दो वस्तुओंके मूल्योंके सम्बन्धोंमें परिवर्तन होनेसे इनके उत्पादन और मागमें परिवर्तन की प्रवृत्ति हो जायेगी। वास्तवमें समस्या औसत मूल्य-स्तरको स्थिर रखनेकी नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न मूल्योंका आपसमें ठीक ठीक सम्बन्ध ज्ञात करना और उस सम्बन्धको स्थिर बनाये रखना है। आर्थिक विषमताओं और अस्थिरताओंका एक प्रधान कारण यही है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओंके मूल्य असम्बन्धित हो जाते हैं। इनके कारणोंको जानना और इनको ठीक प्रकारसे सम्बन्धित करना ही सबसे कठिन कार्य है।

अब प्रश्न यह है कि क्या हम एक विशिष्ट द्रव्य-पद्धति और द्रव्य-नीति द्वारा मूल्य-स्तरमें स्थिरता लासकते हैं। पहिली बात तो यह है कि मूल्य-स्तर केवल द्रव्य द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है। जैसा कि 'हम द्रव्यका विनिमय-मूल्य' नामक अध्यायमें बतायेंगे, द्रव्यके अतिरिक्त और भी अनेक विचारणीय विषय हैं जिनमें मूल्य-स्तर सम्बन्धित है। उदाहरणके लिए, यदि मूल्य-स्तरमें गिरनेकी प्रवृत्ति देखकर द्रव्यके प्रबन्धकर्ता द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि करें परन्तु जिनको इस द्रव्यकी प्राप्ति होती है वे लोग अथवा सस्याएँ इस द्रव्यको काममें न लाकर सचिन करने लगे तो इससे मूल्य-स्तरके ह्रासमें रोकथाम नही हो सकेगी, अतः हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि केवल द्रव्यके संचालनमें ही परिवर्तन करनेसे मूल्य-स्तरमें परिवर्तन अथवा स्थिरता आना अनिवार्य नहीं है। और जब हम मूल्य-स्तरमें नहीं बल्कि विविध मूल्योंके सम्बन्धोंको ठीक करके उनमें स्थिरता लाना चाहते हैं तब तो द्रव्य द्वारा यह कार्य और भी कठिन हो जाता है।

अभी तक द्रव्य-शक्तिप्रयोग और द्रव्य-प्रबन्धको ने द्रव्यके आर्थिक अवस्थाके सम्बन्ध और निया-प्रतिन्याके विषयमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया है। विशेष कर केन्द्रीय बैंक जिसे द्रव्य-नीतिको आर्थिक अवस्थाके अनुकूल बनाने का भार सौंपा गया है, अभी तक द्रव्य-नियन्त्रणके उपकरणों को इस अवस्था तक नहीं ला सका है जिससे उसको इस महत्वपूर्ण कार्यमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। परन्तु प्रायः देशके केन्द्रीय बैंक अपने उत्तरदायित्व को समझनेकी चेष्टा कर रहे हैं और अनेक उपकरणाकी कार्यक्षमता भी बढ़ा रहे हैं और धारणा की जाती है कि निकट भविष्यमें यह सस्या जहा तक द्रव्य-पद्धति और द्रव्य-नीति द्वारा आर्थिक स्थिरता की समस्याका समाधान हो सकेगा है, वहा तक यथाशक्ति सहायता करनेका प्रयत्न करेगी।

अविनिमयसाध्य द्रव्य-पद्धतिके सम्बन्धमें अनेक आलोचनाएँ सुनी जाती हैं। यह खेदका विषय है कि भूतकालमें सकलकालके समयही द्रव्य-पद्धतियाँ अविनिमय-साध्य बनायी गयी और अनेक देशोंमें इस पद्धतिके अन्तर्गत द्रव्य-स्फीति की समस्या उत्पन्न हुई। अतएव यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि इस पद्धतिको जन-साधारण आर्थिक सकल और द्रव्य-स्फीतिसे सम्बन्धित करता है। यही कारण है कि इस प्रकार की पद्धतिमें वह विश्वास नहीं रहता जो स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिमें रहता है।

परन्तु इसमें द्रव्य-पद्धतिका दोष नहीं है, यदि दोष है तो द्रव्य-प्रबन्धकोका जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया। उचित प्रकारसे प्रबन्ध होनेपर इस पद्धतिमें अनक गुण पाये जाते हैं। एकतो यह है कि इस पद्धतिमें लागन-द्रव्य बहुत कम रहता है। सोना चादी बहुमूल्य वस्तुएँ हैं। इनकी अन्य आर्थिक कार्योंमें भी आवश्यकता रहती है। इस पद्धतिके अन्तर्गत बहुतसा सोना चादी जो द्रव्यके काममें आता था अब दूसरे कामोंमें लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस पद्धतिको आर्थिक अवस्था-आवे अनुकूल बनानेमें अधिक सुविधा और स्वतन्त्रता रहती है। हम देख चुके हैं कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति जाने देनाको इस प्रकारकी सुविधा और स्वतन्त्रता बहुत कम मानामें रहनी है।

द्रव्य का विनिमय-मूल्य

मूल्य और विनिमय-मूल्य

एक वस्तुमें अन्य वस्तुओंको बदलनेमें प्राप्त करनेकी जो शक्ति होती है उसको हम उस वस्तुका विनिमय-मूल्य कहेंगे। यदि एक सेर गहूके बदलमें दोगज कपड़ा मिल सकता है तो एकसेर गहूका विनिमय-मूल्य दोगज कपड़ा और एकगज कपड़ेका विनिमय-मूल्य आधासेर गहू हुआ। हम पहिल अध्यायमें बता चुकेहैं कि यदि सभी वस्तुओंके विनिमय-मूल्यका एकही वस्तुके परिमाणमें प्रकट किया जानवे, तो इससे आर्थिक क्रियाओंमें बहुत सुविधाएँ प्राप्त होजाती हैं। आर्थिक विकासमें यही हुआभी है। समाजने द्रव्यके रूपमें वस्तुओंका विनिमय-मूल्य प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया। इसप्रकार जो सम्बन्ध स्थापित हुआ उसको हम मौद्रिक मूल्य कहते हैं अर्थात् विनिमय-मूल्य द्रव्यके रूपमें प्रकट कियाजाना है तो वह मौद्रिक मूल्य कहा जाता है। जिस वस्तुने द्रव्यका काम लियाजाता है उसको एक ठोका भद प्राप्त होजाता है। द्रव्यके विकासके सम्बन्धमें हम देखचुके हैं कि किसप्रकार सोनेचादी ने द्रव्यके रूपमें काममें लायजानके कारण एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। आधुनिक कालमें तो अधिकतम द्रव्य कागजका बना हुआ है अथवा केवल बेंचोंके खातामें दर्ज है। उसका कोई निब्र का मूल्य नहीं है। फिरभी उसकी इतनी माग्यता है। अन्य आर्थिक वस्तुओं और द्रव्यके बीच एक बड़ा भेद यह है कि अन्ततोगत्वा अन्य आर्थिक वस्तुओंके अन्तर्गत कुछ ऐसे गुण निहित हैं जिनमें हमारी कोई न कोई आवश्यकताको तृप्त करनेकी शक्ति होती है। गेहू, दूध, लकड़ी इत्यादि वस्तुएँ इसका उदाहरण हैं, जिनमें कुछ ऐसे नैसर्गिक गुण वर्तमान हैं जिनके उपभागसे हमको तृप्ति मिलती है। इन्हीं गुणोंके आधारपर उनकी उपयोगिता ठीकीहुई है। परन्तु आधुनिक द्रव्यमें कोई इस प्रकारकी तात्त्विक विशेषता नहीं है जिसके कारण

हम उसको उपयोगी समझते हैं। हम द्रव्यकी भाग्यता तभीतक करेंगे जबतक उसके विनिमयसे हमको अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होसकें अर्थात् जबतक द्रव्यकी क्रय-शक्ति बनी रहे। इससे यह तात्पर्य निकलताहै कि द्रव्यकी कोई स्वतः उपयोगिता नहीं है बल्कि उसकी उपयोगिता उन वस्तुओंकी उपयोगितापर निर्भरहै जो उसके विनिमयसे प्राप्त होसकती हैं। यही एक प्रधान भिन्नता द्रव्य और अन्य आर्थिक वस्तुओंके बीचहै, जिसके कारण हम द्रव्यको एक पृथक् वर्गमें रखते हैं।

द्रव्य का विनिमय-मूल्य

अभी हमने बताया कि अन्य वस्तुओंके विनिमय-मूल्यको द्रव्यके रूपमें प्रकट किया जाताहै और उसको उन वस्तुओंका मौद्रिक मूल्य धरवा केवल मूल्य कहा जाता है। द्रव्यका भी विनिमय-मूल्य होता है। द्रव्यकी इकाईसे जिस परिमाणमें वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होसकती हैं, वही द्रव्यका विनिमय-मूल्य है। द्रव्यके विनिमय-मूल्यसे जो वस्तुएं प्राप्त होनीहैं, उसको हम द्रव्यका विनिमय-मूल्य कहेंगे। संक्षेपमें हम कहसकते हैं कि द्रव्यका विनिमय-मूल्य उसकी क्रय-शक्ति है। द्रव्यकी एक इकाई से हमें किस परिमाणमें अन्य वस्तुएं मिलसकती हैं, यह उन वस्तुओंके मूल्य-स्तरपर निर्भर करता है। यदि मूल्य-स्तरमें वृद्धि होजाये तो द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें बढी आजायेगी और यदि मूल्य-स्तरमें बढी होजाये, तो द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें वृद्धि होजायेगी। अर्थात् मूल्य-स्तर और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें प्रतिलोम सम्बन्ध है।

यदि हम ध्यानसे देखेंतो हमको ज्ञात होताहै कि द्रव्यके विनिमय-मूल्यका निर्धारण इतनी सरलतासे नहीं होता है। उदाहरणके लिए, यदि सूचक-श्रमकी सहायतासे हमें यह ज्ञात होताहै कि मूल्य-स्तरमें वृद्धि होगयी तो क्या इससे यह परिणाम निकाला जासकता है कि सभी मनुष्योंके लिए द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें उसी अनुपातमें कमी होगयी। वास्तवमें ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक वस्तुका मूल्य किसी समय विशेषमें एकही अनुपातमें नहीं घटता बढता और प्रत्येक मनुष्य एकही प्रकारके वस्तु-समुच्चयको नहीं मोल लेता। अतएव ऐसा होसकता है कि जब सूचक-श्रम मूल्य-स्तरमें वृद्धि बतातेहैं तो सभी मनुष्योंके द्रव्यका विनिमय-मूल्य एकही अनुपातमें नहीं घटता। यदि कोई मनुष्य केवल उन्ही वस्तुओंको मोल लेता

है जिनका मूल्य राज्य द्वारा निर्धारित और नियन्त्रित है तो उसके लिए द्रव्यका विनिमय-मूल्य पूर्ववत्ही रहेगा और एक दूसरा व्यक्ति जो अनियन्त्रित वस्तुओंको भी मोल लेता है जिनके मूल्यमें वृद्धि आगयी हो, तो उसके द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें कमी आजायेगी। इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यका कोई ऐसा एकाकी विनिमय-मूल्य नहीं होसकता जो सभी व्यक्तियोंके द्रव्यके सम्बन्धमें समान रूपसे लागू हो। सैद्धांतिक रूपसे कहा जासकता है कि द्रव्य द्वारा अनेक प्रकारकी वस्तुएँ और सेवाएँ मोलली जासकती हैं, अतएव द्रव्यका विनिमय-मूल्य उन सभी वस्तुओंके मूल्यपर अवलम्बित रहना चाहिए। इस प्रकारके सूचक-अंक प्राप्तभी कियेजाते हैं जो सभी वर्गोंकी प्रतिनिधि वस्तुओंके आधारपर गणित कियेजाते हैं। परन्तु इस प्रकारके सूचक-अंकोसे जो द्रव्यका विनिमय-मूल्य इंगित होता है उसका व्यवहारमें अधिक महत्व नहीं होसकता क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकारकी वस्तुओं और वस्तु-समुच्चयोंके मूल्यसे प्रभावित होते हैं। अतएव व्यावहारिक उपयोगिता और आर्थिक विश्लेषणके लिए भी द्रव्यका विनिमय-मूल्य हमको भिन्न भिन्न वस्तु-वर्गों और सेवा-वर्गोंके रूपमें निकालना पड़ेगा।

सूचक-अंक

किसी समय विशेषमें द्रव्यका विनिमय-मूल्य क्या है उसको व्यक्त करना दुष्कर कार्य है क्योंकि द्रव्यसे विविध प्रकारकी वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त होसकती हैं। परन्तु द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें तापेक्ष परिवर्तनको जानना सम्भव है। उदाहरणके लिए यदि हम यह जानना चाहें कि सन् १९४८ की तुलनामें सन् १९४६ में द्रव्यका विनिमय कम है या अधिक, और कितनी मात्रामें तो इसका हिसाब सूचक-अंकोकी सहायतासे लगाया जासकता है। सूचक-अंकोसे मूल्य-स्तरोंमें औसत बदलाव मापा जाता है और इसके अनुलोम-अंकोसे द्रव्यके विनिमय-मूल्यके परिवर्तनको गणित करलिया जासकता है। उदाहरणके लिए यदि १९४२ की अपेक्षा १९४४ में मूल्य-स्तर दुगना हो गया है (यदि १९४२ के सूचक-अंकको १०० मानलिया तो १९४४ का सूचक २०० होगा) तो हम कहसकते हैं कि १९४४ में १९४२ की अपेक्षा द्रव्यका विनिमय-मूल्य आधा रह गया (यदि १९४२ में द्रव्यका मूल्य १०० मान

लिया जाय, तो १९४४ में ५० रह जायेगा)।

सूचक-अव निकालनेके पूर्व इस बातका निश्चय कर लेना पड़ता है कि किस काल को प्रामाणिक बाल माना जाये जिससे अन्य कालोंकी तुलनाकी जा सके। कुछ काल स्वयमेव प्रामाणिक प्रतीत होने लगते हैं। उदाहरणके लिए सन् १९३६ (सितम्बर से पूर्व) प्रामाणिक बन गया है क्योंकि इसके बाद ही द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया था। प्रामाणिक काल ऐसा होना चाहिए जिसमें युद्ध, आर्थिक उत्कर्ष-अपकर्ष आदि प्रकारकी असाधारण घटनाएँ न घटी हों। आधुनिक कालमें ४-५ वर्षोंके औसतको प्रामाणिक तल माननेकी प्रथा चसपड़ी है। प्रामाणिक काल स्थिरकर लेनेके पदधातु हमको उन वस्तुओं और सेवाओंकी एक ऐसी सूची बनानी पड़नी है जिसके आधारपर सूचक-अव बनाये जायेंगे। जिस प्रयोजनके लिए सूचक-अव और तत्सम्बन्धित द्रव्यके विनिमय-मूल्यको जाननेकी आवश्यकता हो, उसीसे सम्बन्धित वस्तुएँ भी होनी चाहिए। उदाहरणके लिए यदि हम किसानोंके द्रव्य विनिमय-मूल्यमें बदलाव जानना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं वस्तुओंकी सूचीमें रखना पड़ेगा जिनका उपयोग किसान लोग साधारणतः करते हैं। इन वस्तुओं और सेवाओंकी एक लम्बी सूची होगी। अतएव सूचक-अवोंकी प्राप्ति करनेके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन वस्तुओंमें से कुछ ऐसी छान ली जायें जो सब का प्रतिनिधित्व कर सकें। इन वस्तुओंकी संख्या बहुत कम नहीं होनी चाहिए, नगानो इनको प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकेगा। जितनी अधिक सराहो, उतना अच्छा है। परन्तु इतनी अधिक भी न हो कि कार्य सामर्थ्यके बाहर हो जाये। अब इन्हीं छँटी हुई वस्तुओंका मूल्य मालूम करना है। यदि पूर्वोक्त उदाहरणके अनुसार हमें १९४४ की १९४२ से तुलना करनी है तो हमको इन दोनों वर्षोंमें जो इन वस्तुओं का मूल्य रहा हो, उसको मालूम करना पड़ेगा। इसमें बहुत सावधानीकी आवश्यकता है। पहिले तो हमें किसी भी वस्तुके जिस प्रकारको एक वर्षमें लेते हैं, उसी प्रकारको दूसरे वर्षमें भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि १९४२ में तो शुद्ध धी का मूल्य लिया जाये और १९४४ में वनस्पति धी का। इसके अतिरिक्त जिस प्रकारका मूल्य एक वर्षमें लिया गया हो, उसी प्रकारका मूल्य दूसरे वर्षमें भी लेना चाहिए। एक वर्षमें थोक भाव और दूसरे वर्षमें फुटकर भाव लेनेपर सूचक-अवोंमें असुद्धता आ जायेगी। साधारणतः सूचक-अव थोक मूल्योंके आधारपर बनाये जाते

हे क्योंकि इन मूल्योंका इकट्ठा करना सुगम होता है। परन्तु जीवन-स्तरके सम्बन्ध में जाननेके लिए फुटकर भाव अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि उपभोक्ता वर्ग इसी भावपर सामान मोललेता है। जब इसीप्रकार छँटी हुई वस्तुओंके दोनो वर्गोंके मूल्य ज्ञात होगये, तो इनके पश्चात् गणितका कार्य आरम्भ होजाता है। पहिला काम है, प्रत्येक वस्तुका सापेक्ष मूल्य गणित करना। इसके लिए, प्रामाणिक वर्षमें प्रत्येक वस्तुका मूल्य १०० इकाई मानकर दूसरे वर्षमें उस वस्तुके भावका सापेक्ष अंक प्राप्त कियाजाता है। उदाहरणके लिए, यदि लकड़ीका भाव १९४२ में २ रुपये मन हो और १९४४ में बढ़कर २ रुपये ८ आने मन होगया हो, तो २ रुपयेको १०० इकाई मानकर २ रुपये ८ आनेको १२५ इकाईसे सूचित करेंगे। इसीप्रकार सभी वस्तुओंके सापेक्ष मूल्यके अंक निकाल लिये जायेंगे। इन सापेक्ष-अंकोमें भिन्न भिन्न वस्तुओंके मूल्योंमें बदलाव जानाजाता है। परन्तु हमको औसत बदलाव मालूम करना है अतएव हम इनका औसत निकाल लेंते हैं। यही औसत सूचक-प्रब है। नीचे दीगयी तालिकामें सूचक-अंकोको गणित करनेकी रीति दीगयी है

सन् १९४२				सन् १९४४		
१	२	३	४	५	६	७
मान	वस्तुएं	मूल्य	गुण	मूल्य	सापेक्ष मूल्य	१. × ६. गण
अंक						
२०	चना	४ आ. सेर	१००	६ आ सेर	१५०	१५००
६	बाजरा	५ "	१००	५ "	१००	६००
५	लकड़ी	२ रु मन	१००	२ १/२ रु मन	१२५	६२५
१	पड़	३ आ सेर	१००	६ आ सेर	२००	२००
३	घांतीजीडा	५ रु	१००	६ रु	१२०	३६०
२५	५			कुल	६९५	३२८५

$$\frac{\text{साधारण सूचक-अंक ६९५}}{५} = १३९$$

$$\frac{\text{सप्रभाव सूचक-अंक ३२८५}}{२५} = १३१$$

इस उदाहरणमें १३६ साधारण सूचक-अंक हैं अर्थात् १६४२ की अपेक्षा १६४४ में मूल्य-स्तरमें ३६ प्रतिशत वृद्धि हुई। साधारण सूचक-अंकोको प्राप्त करनेमें हम प्रत्येक वस्तुको समान मान लेते हैं। परन्तु वास्तवमें प्रत्येक वस्तुका मान हमारे लिए बराबर नहीं होता और प्रत्येक वस्तुमें बदलाव होनेसे हम समान रूपसे प्रभावित नहीं होते। उदाहरणके लिए यदि दियासलाईका मूल्य ५० प्रतिशत घट जाये और गेहूँका मूल्य ५० प्रतिशत बढ़ जाये तो औसत मूल्य-स्तर तो इनदो वस्तुओंका समान ही रहेगा परन्तु जितना व्यय हमारा गेहूँमें अधिक होगा उतनी वृद्धि दियासलाईके मूल्यमें कमी होनेसे नहीं होगी। इस दोषको दूर करनेके लिए सप्रभाव सूचक-अंककी गणना की जाती है। ऊपरके उदाहरणमें कोष्ठक (१) में पाँचो वस्तुओंका मान-अंक दिया है। यह मान अंक साधारणतः अनुमानके आधारपर निर्धारित किया जाता है और कभी कभी प्रत्येक वस्तुपर व्ययके अनुपातसे निर्धारित किया जाता है। सप्रभाव सूचक-अंक प्राप्त करनेके लिए सापेक्ष मूल्य-गुणो (कोष्ठक ६) को प्रत्येक वस्तुके मान-अंकसे गुणा कर गुणनफलको जोड़कर मान-अंकोंके योग से भाग दिया जाता है। भजनफल सप्रभाव सूचक-अंक है। ऊपरके उदाहरणमें यह अंक १३१ है। स्पष्ट है कि सप्रभाव सूचक-अंक साधारण सूचक-अंकसे अधिक उपयोगी होता है।

सूचक-अंकोका प्रयोग सावधानीसे करना चाहिए। ये भिन्न भिन्न प्रयोजनोंके लिए बनाये जाते हैं। प्रतिनिधि वस्तु-वर्गके बदलावसे, नवीन वस्तुओंके आ जानेसे धातु और रुचिमें बदलाव होनेसे, वस्तुओंके महत्वमें बदलाव हो जाने से, सूचक-अंक यथार्थताको प्रकट करनेमें पूर्णरूपसे सफल नहीं हो पाते। फिर भी आधिक विश्लेषणके कार्यमें और तुलनात्मक कार्यमें इनका बहुत महत्व है।

द्रव्य के विनिमय-मूल्य का पारिमाणिक सिद्धान्त

यह न जानी हुई बात है कि द्रव्यका विनिमय मूल्य कभी स्थिर नहीं रहता। यह कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस सम्बन्धमें अनेक मत हैं। एक सिद्धान्त जो बहुत लोकप्रिय रहा है और जिसको आधुनिक रूपमें प्रतिपादन करनेका श्रेय अमेरिकाके अर्थशास्त्री गोफेसर फिजरको प्राप्त है, द्रव्यके

विनिमय-मूल्यमें बदलावको द्रव्यके परिमाणसे सम्बन्धित करता है। अतएव इस सिद्धान्तको द्रव्यका पारिमाणिक सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार अन्य बातें समान रहनेपर, द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होनेसे मूल्य-स्तरमें वृद्धि और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें कमी होजायेगी और द्रव्यके परिमाणमें कमी होनेसे मूल्य-स्तर में कमी और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें वृद्धि होजायेगी। इस सिद्धान्तकी निम्न-लिखित समीकरणके रूपमें प्रदर्शित किया जाताहै :

द्रव्यका परिमाण \times चलनका औसत वेग

$$= \text{मूल्य स्तर} \times \text{कुल व्यापार।}$$

द्रव्यके परिमाणमें धात्विक द्रव्य, नोट और साख-द्रव्य सभी सम्मिलित हैं। किसी समय विशेषमें द्रव्यका परिमाण स्थिर रहता है। परन्तु किसी कालावधिमें जैसे एक वर्ष, उसी द्रव्यमें अनेकवार वाम लिया जासकता है। उदाहरणके लिए यदि किसी ममाजमें चलनमें ३० करोड़ रुपयाहै और उसकी सहायतासे सालभरमें ३०० करोड़ रुपयेका आर्थिक व्यवसायोंमें लेनदेन हुआ, तो औसतन प्रत्येक रुपया १० बार चलनमें आया। इसको हम द्रव्यका चलन-वेग कहते हैं। पूर्वलिखित समीकरणमें द्रव्यका परिमाण \times चलनका औसत वेगमें यह तात्पर्य निकला कि सालभर में कितना रुपया लिया और दियागया। जितना रुपया लिया और दियागया होगा, वह उस व्यापारसे सम्बन्धित होगा, जो द्र-व्य द्वारा कार्यान्वित हुआ होगा और इसकुल व्यापारके एक औसत मूल्य अथवा मूल्य-स्तरकी कल्पना की जासकती है। अब यदि कुल व्यापारके परिमाणको औसत मूल्यसे गुणा करदें, तो कुल व्यापारका मूल्य निकल आयेगा। सालभर में जितना रुपया लिया और दियागया होगा, वह इसकुल व्यापारके सम्बन्धमें ही रहा होगा। अतएव इस समीकरणके दो भागोंका परिमाण अवश्यही बराबर होगा। इस समीकरणको सुगम भाषामें इसप्रकार कहसकते हैं: किसी कालावधिमें जितना द्रव्य लिया दिया जाताहै उसका परिमाण कुल द्रव्य सम्बन्धी व्यापारके मूल्यके बराबर होगा।

इस समीकरणसे एक दूसरा समीकरण प्राप्त होताहै जोकि महत्वपूर्ण है। उसका रूप निम्नलिखित है :

$$\frac{\text{मूल्य स्तर}}{\text{व्यापार}} \approx \text{द्रव्य} \times \text{वेग}$$

इस समीकरणमें यह तात्पर्य निकलता है कि यदि मूल्य-स्तरमें परिवर्तन होगया हो, तो हमको उसके कारणोंकी खोजनेके लिए द्रव्यका परिमाण अथवा उसका वेग अथवा व्यापारकी मात्रा अथवा इन सभीके सम्बन्धोंके परिवर्तनका अध्ययन करना पड़ेगा द्रव्यके पुराने परिमाणिक सिद्धान्तके अनुसार मूल्य-स्तर केवल द्रव्यके परिमाणपर अवलम्बित माना जाता था। परन्तु आधुनिक कालमें इस सिद्धान्तके अन्तर्गत द्रव्यके परिमाणके अतिरिक्त उसके चलनका वेग और उसमें सम्पादित होनेवाले व्यापारके परिमाणको भी सम्मिलित किया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त के कुछ अनुयायी यह मानते हैं कि दीर्घकालमें द्रव्यका औसत वेग और व्यापार की मात्रामें अधिक परिवर्तन नहीं होता है और यदि होता भी है, तो उसका सीधा सम्बन्ध मूल्य-स्तरसे नहीं होता। अब यदि हम चलनके वेग और व्यापारकी मात्रा पर ध्यान न दें तो, यदि मूल्य-स्तरमें वृद्धि होगयी है तो उसका कारण द्रव्यके परिमाणमें वृद्धिही होसकता है, इस प्रकारके तर्कमें अनाह त्रुटि या एव अन्वय है। पहिले तो यह मानलेना कि द्रव्यका वेग और व्यापारकी मात्रा समान रहेगी भ्रममत् है। इन दोनोंमें भी परिवर्तन होता रहता है जिससे मूल्य-स्तर प्रभावित होता है और मूल्यके प्रभावित होनेसे ये दोनोंभी प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्य के परिमाणमें जो परिवर्तन होता है उसका पूरा प्रभाव मूल्य स्तरपर न पड़ने देनेमें भी इनका हाथ रहता है। उदाहरणके लिए कल्पना कीजिए कि आर्थिक मन्दीका अवसर है तथा मूल्य-स्तर नीचे गिर गया है और इसलिये आवश्यकता इन स्तरको ऊँचा करनेकी है। अब यदि द्रव्य प्रबन्धक द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि कर दें तो यह अनिवार्य नहीं है कि मूल्य-स्तर अवश्य ऊँचा होजायेगा। आर्थिक मन्दीके अवसर पर निरुत्साहकी भावना रहती है। अतएव यह होसकता है कि नया द्रव्य क्रियाशील न बनकर बेकार संचित पड़ा रहे। यदि ऐसा हुआ तो द्रव्यके प्रसारसे मूल्य-स्तर ऊँचा नहीं उठने पायेगा। इसके अतिरिक्त यदि समाजके साधन बेकार पड़े हों तो जैसे जैसे नया द्रव्य पूँजीके रूपमें तगाया जायेगा वैसे वैसे उत्पादन कार्यमें भी वृद्धि होने लगेगी। यदि द्रव्यके परिमाणमें वृद्धिके साथ साथ उत्पत्तिके परिमाण में भी वृद्धि होती रहे तो मूल्य-स्तरमें अधिक वृद्धि नहीं होने पायेगी। जब सभी आर्थिक साधन पूर्णरूपसे काममें नियुक्त हों, तभी द्रव्यके परिमाणमें वृद्धिके फलस्वरूप उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि न होनेके कारण मूल्य-स्तरमें भी वृद्धि होने लगेगी।

यदि द्रव्यके प्रसारमें मूल्य-स्तरमें वृद्धि होजाती है तो मूल्य-स्तरमें वृद्धिके कारण उत्पत्तिकी मात्राको बढ़ानेमें प्रोत्साहन भी मिलता है। मूल्य-स्तरमें वृद्धि होनेके कारण चलनके औसत वेगमें भी वृद्धि होसकती है। इसका प्रधान कारण यह है कि जब मूल्य-स्तरमें वृद्धिके कारण लाभकी मात्रा बढ़ने लगती है तो उत्पादक वर्ग अपने संचित द्रव्यको भी पूँजीके रूपमें लगाने लगते हैं। उपभोक्ताभी इस आशकासे कि कहीं भविष्यमें अधिक मूल्य-वृद्धि न होजाये, वर्तमानकालमें ही अपने द्रव्यको वस्तुओंमें बदलनेकी चेष्टा करने हैं। इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवसायका परिमाण और द्रव्यके चलनका वेग दोनोंका मूल्य-स्तरसे घनिष्ट सम्बन्ध है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यवसायकी वृद्धिके कारण व्यवसायी वैकोसे अधिक परिमाणमें द्रव्यकी प्रायश्चना करते हैं और यदि उनकी प्रायश्चना स्वीकार हुई, तो इससे द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होजाती है। इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यका परिमाण कारण न होकर कार्य बनजाता है।

वास्तवमें बात यह है कि मूल्य-स्तर और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें परिवर्तन करने में पूर्वोक्त समीकरणके चारो अवयवोंका हाथ रहता है। प्रत्येक अवयव एक दूसरे से घनिष्ट रूपसे सम्बन्धित है, वह उनपर अपना प्रभाव डालता है और स्थिति उनसे प्रभावित होता है। यह प्रभाव भिन्न भिन्न आर्थिक अवस्थाओंमें भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्रत्येक अवयवमें बदलावके अपने निजी कारण भी होते हैं। उदाहरण के लिए, उत्पत्तिकी मात्रा बढ़ानेके लिए, उत्पत्तिके साधन चाहिए, धन चाहिए, लाभ की आशा होनी चाहिए इत्यादि।

संक्षेपमें हम यह कहसकते हैं कि किसरके समीकरणसे हमको इतना तो अवश्य ही ज्ञात होजाता है कि यदि मूल्य-स्तरमें कमी या वृद्धि हुई, तो हमको कारणकी खोज कहा करनी चाहिए। परन्तु जिन चार बड़े आर्थिक अवयवोंकी ओर सकेत मिलता है, वे वास्तवमें किसप्रकार एक दूसरेको प्रभावित करतेहुए द्रव्यका विनिमय-मूल्य निर्धारित करते हैं, इस विषयपर अधिक प्रकाश नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि द्रव्यका जो विनिमय-मूल्य इस समीकरणमें निहित है वह द्रव्य की वास्तविक कय-शक्ति नहीं है क्योंकि द्रव्यका लेनदेन केवल उपभोगकी वस्तुओं और सेवाओंके लिए ही नहीं बल्कि ऋणकी अदायगी, सिव्यूरिटी इत्यादि साख-पत्रोंकी मोल लेनेमें और सट्टेके काममें भी होता है। अतएव इस समीकरणके

अन्तर्गत जो मूल्य-स्तर हैं उसमें प्रत्येक प्रकारके द्रव्य-विनिमय-सम्बन्धी व्यवसाय निहित हैं जैसाकि पहिले बताया जा चुका है, इस प्रकारके मूल्य-स्तरमें कोई वास्तविकता नहीं होती है।

द्रव्य का सचयन सिद्धान्त

केम्ब्रिज विश्वविद्यालयके कुछ अर्थशास्त्रियोंने द्रव्यके पारिमाणिक सिद्धान्तको दूसरेही रूपमें प्रतिपादित किया है। इनके विचारमें द्रव्यकी माग उसको अपने पास रखनेके लिए होती है। द्रव्यको अपने पास रखनेमें वस्तुओं और सेवाओंपर अपना अधिकार बना रहता है। व्यक्ति और संस्थाएँ अनेक प्रयोजनोंके लिए द्रव्य का सचय करते हैं और इस सचयकी मात्रा आर्थिक अवस्थाके अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। यदि द्रव्यके परिमाणमें परिवर्तन न हुआ हो तो द्रव्यको अधिक मात्रामें सचय करनेका अभिप्राय हुआ कि उसके व्ययको कमकरना अर्थात् चलनके वेगमें कमी आजाता। इसके प्रतिकूल सचयकी मात्रामें कमी करने से अभिप्राय होता है व्यय अधिक मात्रामें करना अर्थात् चलनके वेगको बढ़ाना। इसप्रकार हम देखते हैं कि चलनके वेगमें और सचयकी मात्रामें अनुलोम सम्बन्ध है।

जितना द्रव्य चलनमें रहता है, वह किसी न किसीके पास रहता ही है। किसी समय विशेषमें जो मूल्य-स्तर रहता है उसके हिसाबसे इस द्रव्यके परिमाण द्वारा वस्तुओं और सेवाओंके कुछ परिमाण पर अधिकार रहता है। सुविधाके लिए हम मान लेते हैं कि वस्तुओं और सेवाओंका वह परिमाण जिसपर समाजका अधिकार द्रव्यके रूपमें रहता है वार्षिक उत्पत्तिका एक अंश है। इस अंशको हम 'अ' कहेंगे और कुल वार्षिक उत्पत्तिको 'उ' कहेंगे। स्पष्ट है कि कुल द्रव्यकी जयनक्ति 'अ उ' होगी, द्रव्यकी एक इकाई का विनिमय-मूल्य अउ/द्रव्यका परिमाण होगा और मूल्य-स्तर द्रव्यका परिमाण/अउ होगा। इस सम्बन्धको एक समीकरणके रूपमें प्रकट किया जाता है जिसको केम्ब्रिज-समीकरण कहते हैं। इस समीकरणके अनेक रूप हैं। एक सुगम रूप निम्नलिखित है:

$$\text{मूल्य-स्तर} = \frac{\text{द्रव्य का परिमाण}}{\text{अ उ}}$$

यदि लोग यह चाहते हैं कि वे द्रव्यके रूपमें अधिक मात्रामें वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकार रखें, तो वे द्रव्यके सचयमें वृद्धि करने लगेंगे जिसके फलस्वरूप व्यय के परिमाणमें कमी आजानेके कारण मूल्य-स्तर नीचे गिरने लगेगा। और यदि वे द्रव्यके रूपमें पहिलेने कम मात्रामें वस्तुओं और सेवाओंपर अधिकार रखना चाहते हैं तो वे अपने सचयको व्यय करने लगेंगे जिससे मागमें वृद्धि होगी और मूल्य-स्तरमें भी वृद्धि होने लगेगी। साधारणतः यह देखा गया है कि आर्थिक उत्कर्षके समय द्रव्यके सचयको मात्रामें कमी करनेकी प्रवृत्ति होती है जिससे मूल्य-स्तरमें वृद्धि होने लगती है और आर्थिक अपकर्षके कालमें द्रव्यका सचय बढ़ने लगता है जिससे मूल्य-स्तर घटने लगता है।

यदि द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होजाये परन्तु समाजके लोग पहिलेके परिमाणमें ही द्रव्यके रूपमें वस्तुओं और सेवाओंपर अपना अधिकार बनाये रखना चाहें तो तात्कालिक मूल्य स्तरके हिसाबसे उनके पास अतिरिक्त द्रव्य जमा हो जायेगा जिसको वे व्यय करने लगेंगे जिससे मूल्य-स्तरमें वृद्धि होने लगेगी। यह वृद्धि तबतक होती रहेगी जबतक मूल्य-स्तर इतना ऊँचा न होजाये जहापर बड़े हुए द्रव्यके परिमाणसे पूर्वोक्त मात्रामें ही वस्तुओं और सेवाओंपर अधिकार हो। द्रव्यके परिमाणमें कमी होजानेसे विपरीत प्रवृत्ति होगी। इसप्रकार द्रव्यके सचयन सिद्धान्तके अनुसार भी द्रव्यके परिमाणमें कमी और वृद्धि होजानेसे मूल्य-स्तर और उसके सम्बन्धित द्रव्यका विनिमय-मूल्य प्रभावित होता है।

इस सिद्धान्तके अनुयायी यह नहीं कहते हैं कि द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होजाने से उसी अनुपातमें मूल्य-स्तरमें भी वृद्धि होजायेगी क्योंकि यदि समाजमें बेकार आर्थिक साधन पड़े हों तो उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि भी हो सकती है और लोग द्रव्यके रूपमें कितने परिमाणमें वस्तुओं और सेवाओंपर अधिकार रखना चाहते हैं, इस निश्चयको भी बदल सकते हैं।

द्रव्यके पारिमाणिक सिद्धान्तका जो यह दूसरा रूप द्रव्य-सचयन सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित किया गया है इसमें एक विशेष बात यह है कि यह हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट करता है कि लोगोको द्रव्यकी माग क्यों होती है और इस मागमें परिवर्तन होनेसे किसप्रकार मूल्य-स्तर प्रभावित होता है परन्तु इस प्रकारके प्रतिपादनमें उसी प्रकारकी श्रुतिप्राप्त जो फिस्करके समीकरणके अन्तर्गत पायी गयी है। केम्ब्रिज समी-

करणभी मूल्य-स्तरके सम्यन्धमें उन अवयवोंकी ओर इंगित करताहै जिनपर मूल्य-स्तर निर्भर करता है। परन्तु विविध आर्थिक अवस्थाओंमें इन अवयवोंका सम्बन्ध किमप्रकार बदलताहै और एक दूसरेको प्रभावित करनेहुए द्रव्यके विनिमय मूल्यका निर्धारित करताहै इसका पर्याप्त विश्लेषण इस सिद्धान्तमें भी नहीं पाया जाता है। इसके अनिरिक्त इस समीकरणवाला मूल्य-स्तरभी उपभोगकी वस्तुओं और सेवाओंके ऊपर द्रव्यके विनिमय-मूल्यका नहीं बनाता क्योंकि द्रव्यका सचय अथ प्रयोजनोंके निमित्तभी होता है।

उपर्युक्त विवेचनसे हम इस परिणामपर पहुँचतेहैं कि मूल्य-स्तर और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें कयो और किमप्रकार परिवर्तन होजाता है। इसका पूरा पूरा पता लगाना एक गहन विषय है। आर्थिक अवस्था बदलती रहती है। लोगोंके निष्पत्ति बदलते रहते हैं। उनकी वृत्तियों मात्रा और पद्धतियोंके प्रयोगकी मात्राओंमें भी परिवर्तन होने रहतेहैं अतएव उपभोगकी वस्तुओंकी और उत्पादक वस्तुओंकी माग और पूर्तिमें भी परिवर्तन होतरहते हैं। द्रव्यका परिमाण और व्याजकी दर जो उसको प्राप्त करनेके लिए देनी पड़तीहै, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। इन सभी परिवर्तनोंका प्रभाव मूल्य-स्तर और द्रव्यके विनिमय मूल्यपर भी पड़ता है। भिन्न भिन्न आर्थिक अवस्थाओंमें इन आर्थिक अवयवोंमें किस प्रकार परिवर्तन होताहै इसका विवेचन हम 'आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्ष' नामक अध्यायमें करेंगे। निम्नमें आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षके कारणाका विश्लेषण किया जायेगा और तत्सम्बन्धी द्रव्यके विनिमय-मूल्य परभी अधिक प्रकाश पड़गा।

द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें परिवर्तन का प्रभाव

हम ऊपर लिख आयेहैं कि सभी वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य समान परिमाणमें घटता और बढ़ता नहीं है। जिस कालमें मूल्य-स्तर बढ़ने लगताहै उससमय कुछ ऐसे मूल्य होतेहैं जो शीघ्रतासे और पर्याप्त परिमाणमें बढ़जाते हैं और कुछ ऐसे मूल्य होतेहैं जो कुछ समयवाचिके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगतेहैं और कुछतो बिल्कुल नहीं बढ़ते। इसीप्रकार जब मूल्य-स्तर गिरने लगताहै तो कुछ वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य तुरन्तही गिरजाता है और कुछ मूल्य धीरे धीरे गिरतेहैं और कुछ

पूर्ववत् रहते हैं। भिन्न भिन्न मूल्योंके इसप्रकार आचरणमें आर्थिक स्थिति तथा भिन्न भिन्न वर्गोंपर भिन्न भिन्न प्रकारका प्रभाव पड़ता है। प्रायः यह देखा गया है कि आर्थिक उत्कर्षके कालमें मूल्य-स्तर बढ़ा रहता है। प्रारम्भमें लागत-व्यय जिसमें पारिश्रमिक, व्याज, किराया आदि शामिल हैं, तुरन्तही नहीं बढ़ते हैं। अतएव उत्पादक वर्गोंकी लाभकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे वे उत्पत्तिके कार्यमें अधिक पूँजी लगानेको उत्साहित होते हैं और राष्ट्रीय आयमें वृद्धि होने लगती है। परन्तु इस कालमें जिन वर्गोंकी आयमें उस अनुपातमें वृद्धि नहीं हुई हो जिस अनुपातमें मूल्य-स्तरमें वृद्धि हुई है, उन वर्गोंके व्यक्तियोंकी वास्तविक आय कम हो जाती है। उदाहरणके लिए यदि मजदूरोंके जीवन-स्तरवाली वस्तुओंके मूल्य-स्तरमें ७५ प्रतिशत वृद्धि हुई हो परन्तु उनके पारिश्रमिकमें केवल २५ प्रतिशत वृद्धि हो तो इस वर्गको आर्थिक क्षति होगी। इसके साथ एक बात और ध्यानमें रखन योग्य है कि जिस कालमें मूल्य-स्तरमें वृद्धि होनेके कारण लाभकी मात्रा बढ़ी रहती है उस कालमें उत्पादक वर्ग अपने उद्योग धर्मोंमें भी वृद्धि करता है। अतएव मजदूरोंमें बेकारी कम हो जाती है जिससे मूल्य-स्तरमें वृद्धिसे जो क्षति हो जाती है उसकी कुछ भरणमें पूर्ति हो जाती है। परन्तु जिन लोगोंकी आयमें कुछभी वृद्धि नहीं होती है जैसे कि किसान, इनकी आर्थिक क्षति सबसे अधिक होती है। लाभकी वृद्धिके कारण श्रमिकोंके मूल्यमें भी वृद्धि हो जाती है। अतएव इस वर्गको भी मूल्य-स्तरमें वृद्धिके कालमें लाभ होता है। इस कालमें साहूकार वर्गको क्षति होनी है और ऋणी वर्गके ऋणोंका भारमें कमी हो जाती है। इसका कारण यह है कि द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें ह्रास होनेके कारण मूलधन और व्याजकी वय-शक्ति कम हो जाती है। ऋणी लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओंको बढ़तुल्य मूल्यपर बेचकर अधिक मुक्तमूल्यमें ऋण हो सकते हैं। उदाहरणके लिए, यदि किसी किसानने १०० रु० ऋण ऐसे कालमें लिया हो, जब गेहूँका मूल्य २ रु० प्रतिमन हो तो उसको ५० मन गेहूँ बेचनेपर १०० रु० प्राप्त होने। अब यदि ऋण चुकानेके समय गेहूँका भाव १० रु० प्रतिमन हो, तो वह केवल १० मन गेहूँ बेचकर उक्त ऋण हो सकता है। कहा जाता है कि द्वितीय महायुद्धके समय और उसके पश्चात्के कालमें वृद्धि होनेके कारण भारतवर्षमें अनेक किसानोंने अपने ऋणका भार बहुत कुछ हलका कर लिया है।

इसके विपरीत जब मूल्य-स्तर गिरने लगता है तो उत्पादन वर्गोंकी लाभकी मात्रा

गिरने लगती है क्योंकि लागत-व्ययको तुरन्तही कम नहीं किया जा सकता। जिन व्यक्तियों अथवा व्यक्तिवर्गों की आय उसी अनुपातमें नहीं घटती है जिस अनुपातमें मूल्य स्तरमें ह्रास होता है, उनके आर्थिक क्षेत्रमें वृद्धि होगी। परन्तु जब मूल्य-स्तर में अधिक कमी आने लगती है तो उत्पादक वर्ग अपने उद्योग धन्धोंकी मात्रामें कमी करने लगते हैं। अनेक आर्थिक साधन बेकार हो जाते हैं। अतएव केवल उन्हीं व्यक्तियोंको लाभ हो सकता है जो पुराने पारिथमिकके हिसाबसे काममें बने रहें, जैसेकि स्थायी राज-कर्मचारी, बल कारखानोंके इंजीनियर इत्यादि जिन्हें कम मात्रा में उत्पत्ति होनेपर हटाया नहीं जा सकता। इस कालमें श्रमिकोंके मूल्य गिरानेसे श्रमिकोंको हानि होती है। नष्टका भार बढ़ जाता है। साहूकार वर्गको लाभ होता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यके विनिमय मूल्यमें अधिक मात्रामें कमी अथवा वृद्धि होनेसे भिन्न भिन्न वर्गोंपर भिन्न भिन्न प्रकारका प्रभाव पड़ता है जिससे वास्तविक आयके वितरणमें भी परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि एकही व्यक्ति अनेक वर्गोंका सदस्य रहता है। एक मरचारी कर्मचारी एकही साथ श्रमिक और साहूकारभी हो सकता है और भिन्न भिन्न वृत्तियोंमें भिन्न भिन्न प्रकारसे प्रभावित होता है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि पूँजीवादके अन्तर्गत आय और सम्पत्तिके वितरणमें बहुत असमानता होनेके कारण यदि द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें परिवर्तन होनेके कारण इस असमानता में कमी आसके तो इसप्रकार का परिवर्तन समाजके हितके निमित्त होगा। उत्पत्ति के परिमाण और आर्थिक साधनोंकी पूर्ण नियुक्ति के दृष्टिकोणसे कहा जाता है कि मूल्य-स्तरमें वृद्धिकी प्रवृत्ति अधिक वाछनीय है क्योंकि यदि मूल्य-स्तरमें कमी आगयी तो इससे आर्थिक अपवर्ष और मन्दीका संचार होने लगेगा जिससे राष्ट्रीय आयमें कमी और बेकारी उत्पन्न हो जाती है। यह एक बहुत गहन और पेचीला प्रश्न है कि समाजके हितके लिए मूल्य-स्तरमें ह्रास, वृद्धि अथवा स्थिरता रहनी चाहिए। हम इतना कहना चाहेंगे कि भिन्न भिन्न आर्थिक अवस्थाओंमें भिन्न भिन्न प्रकारका मूल्य-स्तर वाछनीय रहेगा। इस विषयपर भी हम 'आर्थिक उत्कर्ष और अपवर्ष' वाले अध्यायमें कुछ प्रकाश डाल सकेंगे।

साख और माख-पत्र

सर्वाधिक आर्थिक प्रणालीमें बैंकोंको एक विनिष्ट स्थान प्राप्त है। पाश्चात्य देशोंमें तो बैंकाका और आर्थिक कार्योंका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है कि कुछ अर्थ-शास्त्रियोंके मतानुसार आर्थिक सम्यक्ताका एक प्रधान कारण बैंकजनित होता है। प्राचीनकालमें उद्योग धन्धे छोटे परिमाणमें किये जाते थे और व्यापारभी सीमित रहता था। अतएव बैंकोंका अधिक कार्य और महत्व नहीं था। परन्तु अर्थमविभागमें वृद्धि होनेसे, आर्थिक नियन्त्रणके विनिष्ठीकरणसे कल-कारखाने, विद्युत्गन्धि और यातायातके त्वन्तिगामी साधनोंके प्रयोगमें उत्पत्ति और व्यापार की मात्रामें बहुत वृद्धि होगी है। इन कार्योंको सुगमतासे सम्पादित करवानेके लिए विनिष्ट सम्भाषाशी भी आवश्यकता होने लगी। इसी सम्बन्धमें बैंको और अपने-प्रकारके साख-पत्राका भी विकास होन लगा।

उत्पत्ति और व्यापारके कार्य सालके बिना चल नहीं सकते हैं। किसीभी किसान, दुकानदार और कारखानेके मालिकको लेनीजिए। हम देखते हैं कि अपने कार्यके निमित्त उनको पयम ऋण लेना पड़ता है और अपनी बनायी हुई वस्तुओंको भी माल के आधारपर (अर्थात् उधार) बेचना पड़ता है। भारतवर्षमें अनेक प्रकारके लोग उधार देनेका कार्य करते हैं जिनमें महाजन, माहूकार, सराफ, चेटी, नानावती और काबुली इत्यादि नामोंसे पुकारा जाता है। जमीन्दार और दुकानदार भी इस कामकी करते हैं। आधुनिक कालमें यह कार्य अधिकतर बैंको द्वारा सम्पादित होने लगा है।

उधार चाहे द्रव्यके रूपमें अथवा वस्तु रूपमें दिया जाय, साखपर ही अवलम्बित रहता है। बिना माखके कोई व्यापारी बिना तत्त्वज्ञ मूल्य लिये अपना सामान

हस्तान्तरित नहीं करेगा और न कोई बैंक अथवा महाजन उधार देगा। साख-सम्बन्धी बायोकी वृद्धिके कारण अनेक प्रकारके साख-पत्रोंकी सृष्टि होगयी है। नोट-द्रव्यभी एक प्रकारका साख-पत्रही है। यदि हम नोटोपर लिखा लेख पढ़ें तो उसमें केन्द्रीय बैंककी ओरसे उसके गवर्नरका हस्ताक्षरयुक्त प्रतिज्ञापत्र रहताहै कि वह मागनेपर नोट-वाहकको उसपर मिछाहुआ रुपया देगा। आधुनिक कालमें नोट के अविनिमय साध्य होनेके कारण इस प्रतिज्ञाका कोई महत्व नहीं रहगया है परन्तु पूर्वकालमें नोटोंके बदले चादोंके रुपये दियेजाते थे। आजकल भी नोटोंके अन्तर्गत सरकार और केन्द्रीय बैंककी साख है। बैंकभी एक महत्वपूर्ण साख-पत्र है। इसके द्वारा बड़ीसे बड़ी रकमभी स्थानान्तरित अथवा हस्तान्तरित की जासक्ती है। जिस व्यक्ति अथवा मस्थाकी बैंकमें धरोहर जमा है अथवा जिसको बैंकने ऋण देना स्वीकार करलियाहै वह बैंक द्वारा बैंकको आदेश देताहै कि बैंक बैंकपर लिखीहुई रकमको बैंकपर नामांकित व्यक्ति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तिको देदे। बैंक तो द्रव्य नहीं है। इसको जो व्यक्ति द्रव्यके स्थानमें स्वीकार करताहै उसका आधारभी साखही है। कभी कभी बैंक बैंकके बदलेमें रुपया देनेसे इन्कार करदेते हैं क्योंकि बैंक लिखनेवाले की बैंकके पास पर्याप्त मात्रामें धरोहर नहीं रहती है।

हुंडी एक विशेष प्रकारका साख-पत्रहै जिसका प्रयोग देशी और विदेशी व्यापार में होता है। इसके द्वारा वस्तुओंका विज्ञेता उनके माल लेनेवाले को आदेश देताहै कि वह उनका मूल्य एक निर्धारित काल (साधारणतः तीन महीने) के बाद उसको अथवा उसके बैंकके पाम जमा करदे। जब श्रेता इस हुंडीपर अपने-हस्ताक्षर करके उसको स्वीकार करलेताहै तब इस स्वीकृत हुंडीको बैंकमें भुनाया जासक्ता है। आगे चलकर हम बतायेंगे कि बैंक किसप्रकार इन हुंडियोंको भुनाकर अपनीभी आम करतेहैं और व्यापारके लिए द्रव्य प्रदान करते हैं। कभी कभी जब एक बैंक दूसरे बैंकसे ऋण लेताहै अथवा सवटके समय एक बैंक दूसरे बैंककी महाप्रता करता है तो इस सम्बन्धमें जिस प्रकारके साख-पत्रका प्रयोग होताहै उसको हम बैंककी हुंडी कहसक्ते हैं।

दीर्घकालके लिए पूजी प्राप्ति करनेके लिएभी अनेक प्रकारके साख-पत्रोंका मूलन हुआ है। इनमेंसे मुख्य विविध प्रकारके शयर, बोंड और डिबेंचर कहलाते हैं। बोंड और डिबेंचर ऋण-सूचक साख-पत्र है। यदि किसी कम्पनी अथवा सरकार

को दीर्घकाल के लिए ऋणकी आवश्यकता होती है तो वह इनको बेचती है। इनको मोल लेनेवालोंको एक निर्धारित दरमें व्याज दिया जाता है। शंयर स्वामित्व-सूचक साख-पत्र है। इनको मोल लेनेवालों को शंयर बेचनेवाली कम्पनियोंमें स्वामित्व का अधिकार रहता है और इनको सामाज्य मिलता है।

बैंकों का विकास और उनके कार्य

प्राथमिक बैंकोंके व्यापारी, स्वर्णकार और साहूकार-ये तीन पूर्वज बताये जाते हैं। प्राचीन कालमें बड़ी बड़ी व्यापारी कोठिया हुआियोका व्यापार करती थी और विदेशी व्यापारकी व्यवस्था करती थी। कुछ पाश्चात्य देशोंमें लोग धार्मिक द्रव्य स्वर्णकारोंके पास सुरक्षाके लिए जमा करते थे जिसके आधारपर शनैः शनैः नोट और साख-द्रव्यकी सृष्टि हुई। साहूकार ऋण देनेका कार्य करते हैं। प्राधुनिक बैंकोंमें यह तीनों कार्य निहित हैं। इन प्रधान कार्योंके अतिरिक्त अन्य कार्योंके द्वारा भी बैंक समाजकी सेवा करते हैं। वैसे तो बैंकोंके अनेक प्रकार हैं। परन्तु इनके दो बड़े वर्गीकरण किये जा सकते हैं। एकको तो हम व्यापारिक बैंक कहेंगे जो मध्यकालीन ऋणमें सम्बन्धित हैं। दूसरे वर्गका सम्बन्ध दीर्घकालीन पूँजी इकट्ठा करने और उसको उन्नतिके कार्योंके लिए प्रस्तुत करनेमें है। इनमें व्यापारिक बैंकोंमें अधिक प्रगतिशीलता होती है।

प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्तियों और संस्थाओंके पास चालू-व्यय करनेके बाद कुछ द्रव्य बच जाता है जिसको उनको वर्तमान कालमें आवश्यकता नहीं रहती है। इसके कुछ भागकी उनको निकट भविष्यमें आवश्यकता पड़ती है और कुछ भागकी दीर्घकाल तक आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीप्रकार ऐसे व्यक्ति और संस्थाएँ होती हैं जिनकी अपने आर्थिक कार्योंके लिए अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋणकी आवश्यकता रहती है। बैंकोंके द्वारा इन दोनों प्रकारके लोगोंका कार्य सिद्ध होता है। छिनरी हुई छोटी मोटी सभी प्रकारकी बचत बैंकोंमें धरोहरके रूपमें जमा होती है। सबको चालू हिस्सा कहते हैं जिसका धन कभीभी बिना पूर्व सूचना के चेक द्वारा वापस लिया जा सकता है अथवा हस्तान्तरित किया जा सकता है। इसपर बैंक माधारणतः व्याज नहीं देते हैं फिर भी लोग चालू हिस्सामें धरोहर दम

लिए रखतेहैं कि भुगतान सम्बन्धी अनेक सुविधाओंके साथ साथ रुपया बैंकमें सुरक्षित रहना है। दूसरी प्रकारकी धरोहरको हम दीर्घकालीन धरोहर कह सकतेहैं ओ कि एक निर्धारित समयके लिए बैंकके पास छोड़दी जातीहैं और उस समयमें पूर्व धायम मागनेके लिए बैंककी स्वीकृतिकी आवश्यकता होती है। इस प्रकारके धरोहरपर बैंक व्याज देते हैं। धरोहर रखनेका कार्य बैंकका एक प्रधान कार्य है। इस कार्यके सम्पादनमें बैंक बचन करनेमें प्रोत्साहन देतेहैं और बचत करनेवालों को व्याज देकर उनकी आयमें भी वृद्धि करते हैं। बैंकके न हानपर समाजकी बचतका कुछ हिस्सा अवश्यमेव बैंकके धरोहरों में पड़ा रहता जो न बचत करनेवालोंकी आय में वृद्धि करता और न समाजके आर्थिक कार्योंमें लगने पाता। बैंकोंके द्वारा बैंक संचित पड़ा हुआ द्रव्य प्रचालित होता है। इस प्रचालनका कार्य बैंक विविध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों अथवा मस्थानोंको दृष्टि देकर हुडिया भुनाकर और निष्पूरितिया खरीदकर सम्पादन करते हैं। इससे उत्पादन कार्य और व्यापारमें वृद्धि होती है। ऋण देकर और अन्य प्रकारके भी धरोहर द्रव्यको आर्थिक कार्योंमें लगाना यह बैंकका दूसरा प्रधान कार्य है।

बैंक केवल दूसरीकी धरोहरको ही प्रचालित नहीं करतेहैं परन्तु जैसाकि हम साख-द्रव्यके सम्बन्धमें लिख आयेहैं वे एक नय प्रकारके द्रव्यका भी सृजन करतेहैं और उसकोभी आर्थिक कार्योंके लिए उपलब्ध करते हैं। हम देखचुके हैं कि इस साख-द्रव्यके प्रयोगसे धात्विक द्रव्यकी बचत होजाती है और मोने चादीका एक बड़ा भाग द्रव्यके कार्यसे निकलकर अन्य आर्थिक कार्योंके लिए उपलब्ध होजाता है। प्रागतिशील आर्थिक कार्योंके लिए प्रगतिशील द्रव्य-पद्धतिभी चाहिए। साख-द्रव्यका समावेश करनेसे द्रव्य-पद्धतिमें यह गुण आजाता है। यहापर हम यहभी लिखदेना चाहतेहैं कि बैंकोंकी इस साख द्रव्य सृजन करनेकी शक्तिका बहुधा दुरुपयोगभी होजाता है। कुछ अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार आर्थिक अस्थिरताओंका एक प्रधान कारण साख-द्रव्यकी अस्थिरतामें सम्बन्धित किया जासकता है। अतएव इस साख-द्रव्यमें प्रबन्ध और नियन्त्रणकी आवश्यकता रहती है। यह कर्तव्य केन्द्रीय बैंकका है और उस प्रकरणमें हम उन उपायों और उपकरणोंकी विवेचना करेंगे जिनका प्रयोग आधुनिक केन्द्रीय बैंक करते हैं।

बैंकोंके द्वारा द्रव्यको एक स्थानसे दूसरे स्थानोंमें भेजा जासकता है। बैंक अपने

आसामियोंकी विविध प्रकारसे सेवा और सहायताभी करते हैं। उनके बैंक और लाभांशका धन वसूलकर उनके नामपर जमा करते हैं। उनके आदेशानुसार उनकी श्रीमा-किस्त अदा करते हैं। उनके शेयर, बोंड इत्यादि प्रकारके साख-पत्रोंकी खरीदने और बेचनेका प्रबन्ध करते हैं। उनके आभूषण, जवाहरात और वसीयत-नामा इत्यादि सकेय पत्रोंको सुरक्षित रखनेका प्रबन्ध करते हैं। अपने साख-पत्र द्वारा विदेश-यात्रामें दूसरे देशोंके द्रव्यको प्राप्त करनेमें सहायता करते हैं। अन्त-राष्ट्रीय व्यापारमें विदेशी हुडियोंको अपने आसामियोंकी ओरसे स्वीकार करके प्रोत्साहन देनेहैं। इन कार्योंके लिए बैंकोंकी कमीशन मिलता है।

बैंकों की लेनी-देनी

बैंक समय समयपर अपनी आर्थिक स्थितिका विवरण एक लेख-पत्रके रूपमें देते हैं जिनके एक भागमें उसकी देनदारोंकी भिन्न भिन्न मुद्दे दीजाती हैं और दूसरे

देनी की मदें	लेनी की मदें और सम्पत्ति
प्राप्त हिस्सा पूजी २,००,००० रु	बैंकमें स्थित और
रक्षा कोष २००,००० रु	केंद्रीय बैंकमें स्थित
धरोहर २०,००,००० रु	धरोहर २,४०,००० रु.
स्वीकृतिया ४०,००० रु	अन्य बैंकोंमें जमा
अन्य मदें ६०,००० रु	तथा वसूल न हुए
कुल २५,००,००० रु	बैंक १०,००० रु
	तुरन्त देय और अल्प-
	कालीन ऋण १,००,००० रु.
	भुनाई हुडिया २,००,००० रु
	लगा पूजी ४,५०,००० रु
	उधार १२,००,००० रु
	स्वीकृतिया ६०,००० रु.
	सम्पत्ति (मकान,
	फर्नीचर इत्यादि) २,४०,००० रु.
	कुल २५,००,००० रु.

भागमें बैककी सम्पत्ति और पावनेकी मदें दीजानी है। इस तंत्री-देनीके लेखमें बैककी आर्थिक-स्थिति और उसके कार्यका भी बोध होना है। पिछले पृष्ठपर दीगयी तालिकामें लेनी और देनीकी मुख्य मदें दीगयी हैं और उनके अपने कल्पित आकड़ेभी दिये गये हैं :

अब हम इन मदोंका भक्षित विवरण और उनके महत्वकी विवेचना करेंगे। प्राप्त-हिस्सा पूजा बैककी वह पूजी है जो उसके हिस्सेदारोंने शेयरके मूल्यके रूपमें दी है। यह देनदारी बैकके अपनेही हिस्सेदारोंके सम्बन्धमें है। परन्तु यह तुरन्त देय देनदारी नहीं है। बैकको खोलनेके लिए पर्याप्त पूजीकी आवश्यकता होती है। इससे बैकपर विश्वास रहता है। भारतवर्षमें एक निर्धारित पूजी इकट्ठा किए बिना बैक अपना कार्य आरम्भ नहीं करसकते हैं। रसा-कोष बैकके लाभका वह संचित भाग है जो उसके हिस्सेदारोंको न देकर एक कोषके रूपमें बैकमें जमा रहता है। यह देनदारी भी बैककी अपने हिस्सेदारोंके प्रति है। खर्चके समय और आसामियोंमें विश्वास बनाये रखनेके लिए इस कोषसे सहायता मिलती है। धरोहर देनदारीकी सबसे बड़ी मद होती है इसमें राज-प्रामाणित द्रव्यमें रखी धरोहर तथा बैकों द्वारा सृजित साख-द्रव्य भी शामिल है। यह देनदारी बैककी अपने धरोहर चालाके प्रति है। चालू धरोहरको मागनेपर तत्काल राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें देना पड़ता है। अपनी इस ऋण-शोधन क्षमताको बनाये रखनेके लिए बैकको पर्याप्त भागमें नकदी रखनी पड़ती है। हुडियोंको अपने आसामियोंके निमित्त स्वीकार करनेके कारण बैक हुडियोंके मालिकका देनदार बनजाता है परन्तु अपने आसामियों से वह उतनीही रकमका सेनदार भी रहता है। अतएव यह मद लेनीकी मदोंके साथभी दिखायी गयी है। अन्य छोटी मोटी देनदारियोंकी मदें भी होती हैं जो कि बैकको अपने व्यवसायके सम्बन्धमें स्वीकार करनी पड़ती हैं।

बैककी सम्पत्ति और लेनीकी मदोंमें नकदीको प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसका लेखा राज-प्रामाणित द्रव्य-मुद्रा और नोटके रूपमें बैकमें ही रहता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैकमें भी किसी बैककी जो धरोहर है उसकोभी बैक नकदी ही समझता है क्योंकि वह इसी रूपमें मागी जासकती है। अन्य बैकोंमें जमा धरोहर और वह बैक जो अन्य बैकोंसे वसूल करनेके निमित्त पड़े हुए है, नकदीके ही रूपमें है। नकदी बैककी सबसे अधिक द्रव्य-सम्पत्ति है। इसके परिमाणपर बैककी ऋण-

शोधन क्षमता प्रधान रूपमें अवलम्बित रहती है। अतएव बैंकोको अपनी घरोहर की देनदारीका एकभाग इस रूपमें रखना पड़ता है। इसका परिमाण बैंक अपने अनुभवके आधारपर जानसकते हैं। बैंक इस मदको अधिक परिमाणमें नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि इससे उनको कोई आय नहीं होती है। अतएव कुछ अदूरदर्शी बैंक नकदी इतने कम परिमाणमें रखते हैं कि वे अपने घरोहर रखनेवालों को राज-प्रामाणित द्रव्य देनेमें असमर्थ होजाते हैं जिसके फलस्वरूप उनको अपना व्यापार बन्द करनेको बाध्य होता पड़ता है। इस परिस्थितिसे बचनेके लिए अनेक देशोंमें राज-नियम द्वारा इस मदका न्यूनतम परिमाण निर्धारित करदिया जाता है। यदि किसी बैंकमें नकदीका अनुपात कम होनेलगे तो लोग उसको मदिग्ध दृष्टिसे देखने लगते हैं।

बैंक कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों और सस्याओंको नाम-मात्र व्याजपर इस शर्तपर ऋण देने हैं कि वह मागनेपर तुरन्तही अथवा कुछ दिनोंकी नोटिस मिलनेपर (एक दिनसे सप्ताह दिनतक) इस रकमको लौटा देंगे। इस प्रकारका ऋण प्रधानतः स्टोक-एक्सचेंजमें सम्बन्धित लेनदेनके कार्यमें लिया जाता है। इस प्रकारके ऋणमें बहुत प्रवृत्ति रहती है अर्थात् आवश्यकता पड़नेपर थोड़े समयके अन्दर बैंकको यह द्रव्य वापस मिल सकता है। बैंक, हुड्यो भुनानेका भी काम करते हैं। साधारणतः इन हुडियोंकी अवधि तीन महीनेकी होती है। बैंक हुड्योकी रकमका वर्तमान मूल्य हुड्योके स्वामीको देते हैं और अवधि पूरी होनेपर पूरा मूल्य वसूल करलेते हैं। इन दो मूल्योंका जो अन्तर होता है वही बैंककी आय है। इन हुडियोंमें अपनी सम्पत्ति रखनेसे बैंकको एक यह सुविधा होती है कि आवश्यकता पड़नेपर बैंक इन भुनायी हुई हुडियोंको केन्द्रीय बैंकके पास दुबारा भुनाकर अपनी देनदारी पूरी करसकता है। लगी पूजोका आशय बैंक द्वारा मोल लीगयी सरकारी सिक्कूरिटिया, बीड, डिबेंचर और कभी कभी औद्योगिक सिक्कूरिटिया भी है। इन सिक्कूरिटियोंसे बैंक को पूर्वलिखित मदमें अधिक आय होती है और आवश्यकता पड़नेपर इनको बेच कर अथवा केन्द्रीय बैंकके पास इनकी बन्धकके रूपमें रखकर द्रव्य प्राप्त होसकता है। परन्तु इस मदमें एक त्रुटि यह है कि इन सिक्कूरिटियोंका मूल्य वदमता रहता है। अतएव कभी कभी मूल्य घटजाने से हानि होनेकी सम्भावनाभी रहती है। अधिकतर बैंककी लेनोवी मदका सबसे बड़ा परिमाण उधारकी मदका होता है।

अपने आसामियोंको ऋण देकर बैंक उनसे व्याज वसूल करते हैं। इस मदमें सबसे अधिक आय होती है। परन्तु इस मदमें सबसे कम द्रवता और सबसे अधिक खतरा भी रहता है। इसके अतिरिक्त जितने बालके लिए ऋण दिया गया हो उससे पहिले आवश्यकता पड़नेपर भी बैंकको धन वापस नहीं मिलसकता है। अवधि पूरी होने परभी प्रायः ऋणी अवधि बढ़ानेकी प्रार्थना करते हैं। कुछ ऋणी ऋण-शोधनमें असमर्थ होजाने हैं। साधारणतः बैंक इसप्रकारके खतरेसे अपनी रक्षा करनेके लिए ऋणी लोगोंमें सोना, चादी, आभूषण और सिक्कुरिट्टी इत्यादि बन्धकके रूपमें रखवालेते हैं। व्यापारिक बैंक प्रायः थोड़ी अवधि (एक वर्षसे कम) के लिए ही ऋण देते हैं।

बैंकके लेनी-देनीके लेखके दोनो भागोंका योग बराबर होताहै क्योंकि इसका हिसाबही इस प्रकारसे रखाजाता है। परन्तु एक दूरदर्शी बैंकको अपनी सम्पत्ति और लेनीके मदोंके अनुपातपर धृष्टि रखनी पड़ती है। कुछ मदोंसे आय नहीं होती है परन्तु उनको रखना बहुत आवश्यक है। कुछ मदोंमें आय तो अधिक होनीहै परन्तु उनमें जोखिम अधिक रहता है। बैंकके प्रबन्धकको समय समयपर सभी मदोंको इस अनुपातसे बढ़ाने रहना पड़ताहै कि उनमें पर्याप्त मात्रामें द्रवता अर्थात् द्रव्य-विनिमय क्षमता रहे जिससे वह अपने देनदारोंकी भागोंको पूरी करनेमें समर्थ रहे और साथही साथ उन मदोंसे इतनी आयहो कि बैंक सम्बन्धी व्ययको चुकाकर हिस्सेदारोंके लिए पर्याप्त मात्रामें लाभभी बचा रहे।

केन्द्रीय बैंक

आधुनिक कालमें प्रायः सभी देशोंमें द्रव्य और बैंक पद्धतिका प्रबन्ध और नियन्त्रण करने और इनको आर्थिक स्थितिके अनुकूल बनाये रखनेकी चेष्टा करनेका कार्य केन्द्रीय बैंकको सौंपागया है। प्रथम महायुद्धके पश्चात् इस प्रकारके बैंकोंकी स्थापना दीघ्रतासे होनेलगी। प्रारम्भमें अनेक देशोंमें हिस्सेदारों वाले केन्द्रीय बैंकों की स्थापना हुई। परन्तु अब इन बैंकोंको राष्ट्रीय बैंकके रूपमें रखनेकी प्रवृत्ति होरही है। भारतके केन्द्रीय बैंक, रिजर्व-बैंक का भी राष्ट्रीयकरण होगया है। वैसे भी जब केन्द्रीय बैंक हिस्सेदारोंके स्वामित्वमें थे उनके प्रबन्ध करनेमें राज्यका हाथ

संदेह रहता था। उसकी नीति राज्यकी नीतिके अनुसारही बनायी जातीथी और व्यवहारमें लागीजाती थी। राज्यके आर्थिककार्योंमें अधिक भाग लेनेके कारण और आर्थिक योजनाके महत्वके कारणभी केन्द्रीय बैंकको राज्यका ही एक विभाग बनाना आवश्यक होगया।

केन्द्रीय बैंकसे यह आशा कीजाती है कि वह द्रव्य और बैंकोंके सम्बन्धमें इसप्रकार की नीतिको व्यवहारमें लाये जिससे द्रव्यका परिमाण आर्थिक अवस्थाके उपयुक्त हो, मूल्य-स्तरमें अधिक अस्थिरता न आने पावे और जहातक होसके, विदेशी विनिमय की दरमें भी स्थिरता बनी रहे। इस कार्यके सम्पादनके हेतु केन्द्रीय बैंकको नोटोंके छापने का एकाधिकार रहता है। आधुनिक कालमें राज-प्रामाणित द्रव्य अधिकांश मात्रामें नोटके रूपमें ही रहता है। अतएव नोटको चलनमें लाने पर अधिकार होनेमें और द्रव्य-पद्धतिके प्रबन्ध करनेका भार अपने ऊपर आजाने से केन्द्रीय बैंक का उत्तरदायित्व बहुत बढगया है। चूकि वर्तमान द्रव्य-पद्धतिमें साख द्रव्यका प्रभुत्व बढता जा रहा है अतएव उसपर नियन्त्रण करनेका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्धमें केन्द्रीय बैंक अनेक साधनों और उपकरणोंका प्रयोग करता है।

यदि बैंक आवश्यकतानुसार अधिक मात्रामें साख-द्रव्यका सृजन कर रहे हो तो केन्द्रीय बैंक उनकी गतिमें रोकथाम करनेकी चेष्टा करेगा और यदि आर्थिक कार्यों के लिए द्रव्य अपर्याप्त है तो केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकोंको अधिक मात्रामें साख-द्रव्य सृजन करनेके लिए उन्माहित करेगा। इस कार्यके सम्पादनके लिए केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित साधनोंका प्रयोग करते हैं :

(१) केन्द्रीय बैंकके व्याजकी दरमें परिवर्तन। हम जानतेहैं कि जब बैंक अपनी व्याजकी दर कम कर देने हैं तो उधारका परिमाण बढजानेसे साख-द्रव्यका परिमाण भी चलनमें बढजाता है और जब बैंक व्याजकी दर बढा देतेहैं तो साधारणतः उधार का परिमाण कम होजानेसे साख-द्रव्यके परिमाणमें भी कमी आजाती है। अब यदि केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकोंकी व्याजकी दरको पर्याप्त मात्रामें प्रभावित कर सके तो वह साख-द्रव्यके परिमाणको नियन्त्रण करनेमें भी-सफल हो सकेगा। केन्द्रीय बैंककी अपनी निजकी भी व्याजकी दर होतीहै जिसके हिसाबसे वह अन्य बैंकोंकी हृदियों को भुनाताहै अथवा उनको उधार देताहै। जिन देशोंमें केन्द्रीय-बैंकप्रणाली विवक्षित

होचुकी है वहा अन्य बैंकोकी व्याजकी दर और केन्द्रीय बैंककी व्याजकी दर साधारणतः एकही दिशामें बदलती है। अतएव यदि केन्द्रीय बैंक साख्द्रव्यकी मात्राको कम करना चाहता है तो वह अपनी व्याजकी दरको बढ़ादेता है और यह आशा करता है कि अन्य बैंकभी अपनी व्याजकी दर बढ़ा देंगे और इस प्रकार उधारकी मात्रा (जिस पर अधिकतर साख्द्रव्यका परिमाण निर्भर रहता है) घट जायगी। इसके प्रतिकूल यदि केन्द्रीय बैंक साख्द्रव्यके सृजनको प्रोत्साहित करना चाहता है तो वह अपनी व्याजकी दरको घटादेता है और आशा करता है कि अन्य बैंकभी उसका अनुकरण करेंगे और इसके फलस्वरूप उधारकी मात्रा बढ़ जायगी और अधिक साख्द्रव्य चलनमें आजायगा। केन्द्रीय बैंककी ये आशायें सभी अवस्थाओंमें पूर्ण नहीं होती है। यदि अन्य बैंकोके पास पर्याप्त नकदी है और उनको केन्द्रीय बैंककी सहायता की आवश्यकता नहीं है तो वे केन्द्रीय बैंकके व्याजकी दर बढ़ाने पर भी अपने व्याजकी दर पूर्ववत् रख सकते हैं अथवा उस अनुपातपर न बढ़ावें जिस अनुपातपर केन्द्रीय बैंक बढ़ाता चाहता है। इसीप्रकार जब केन्द्रीय बैंक अपनी व्याजकी दर कम करदेता है तो यह आवश्यक नहीं है कि अन्य बैंकभी पर्याप्त मात्रामें अपनी व्याजकी दर कम करदें। केन्द्रीय बैंकका कार्य लाभ-उपार्जनके लिए नहीं होता है अतएव वह व्याजकी दरको बहुत कम करसकता है। परन्तु अन्य बैंकतो लाभकी आशासे बैंकके कार्यको करते हैं। वे अपने व्याजकी दर इतनी कम नहीं करसकते कि उनको बैंकके व्ययको पूरा करके हिस्सेदारोंको उपयुक्त लाभ न प्राप्त हो। इसके प्रतिरिक्त यदि अन्य बैंक केन्द्रीय बैंककी इच्छानुसार व्याजकी दरको कम भी करदें तो यह आवश्यक नहीं है कि उधारकी मात्रामें वृद्धि हो ही जायगी। आर्थिक मन्त्रीके अवसर पर जबकि उत्पादकोंमें नैराश्य छाया रहता है व्याजकी दर कम होनेसे भी पूँजी लगानेकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अतएव व्यापारी लोग उधार लेतेही नहीं अथवा पर्याप्त परिमाणमें नहीं लेते हैं। इसी प्रकार आर्थिक उत्कर्षके अवसरपर जब मूल्य-स्तर और लाभ-स्तरमें बढ़नेकी प्रवृत्ति रहती है उस अवसरपर व्याजकी दरको बढ़ा देनेपर भी उधारकी मात्रामें कमी नहीं आती है। इसप्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय बैंक अपनी व्याजकी दरको घटाने और बढ़ानेमें प्रत्येक अवस्थामें साख्द्रव्यके परिमाणको नियन्त्रित करनेमें सफल नहीं होता है।

(२) साधारणतः केन्द्रीय बैंक अपने बैंक सम्बन्धी कार्यों द्वारा अन्य बैंकोके साथ

प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। परन्तु यदि उनको किसी समस्याका सामना करना हो तो वह खुले तोरपर इन कार्योंमें भाग लेसकता है। हम इस साधनको 'खुले हाटकी क्रियाएँ' कहेंगे। इसका आशय यहहै कि किसी असाधारण द्रव्य-सम्बन्धी अवस्था का प्रतिकार करनेके लिए केन्द्रीय बैंक बिना किसी प्रकारकी रुकावटके सिक्कूरिटियों को स्वयं निर्धारित मूल्यपर मोल लेसकता और बेच सकताहै और इस क्रिया द्वारा अन्य बैंकोको अपने साल-द्रव्यमें वृद्धि अथवा कमी करनेको वाध्य करनेकी चेष्टा करता है। इस खुले हाटकी क्रियाके मूलमें प्रधान बात यहहै कि व्यापारिक बैंक नकदीके आधारपर साल द्रव्यका सृजन करते हैं। यदि उनके पास नकदीकी मात्रामें वृद्धि होजाय तो वे साल द्रव्यमें भी वृद्धि करसकेंगे और यदि नकदीकी मात्रामें कमी आजाय तो उनको साल द्रव्यके परिमाणको घटाना पड़ेगा केन्द्रीय बैंक खुले हाटकी क्रियाके द्वारा व्यापारिक बैंकोके नकदीके कोषमें आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कमी करनेकी चेष्टा करताहै और आशा करताहै कि नकदीकी वृद्धि होनेसे साल द्रव्यके परिमाणमें भी कमी आजायेगी। इस स्थितिको लानेके लिए खुले हाटकी क्रियाके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा सिक्कूरिटियोंको पर्याप्त मात्रामें मोल लिया अथवा बेचा जाता है। यदि केन्द्रीय बैंक नकदीकी मात्रामें वृद्धि करना चाहताहै तो वह सिक्कूरिटियोंको मोल लेने लगता है। यदि व्यापारिक बैंक सिक्कूरिटियाँ बेंचें तो तुरन्तही उनके नकदीके परिमाणमें वृद्धि होजाती है। यदि केन्द्रीय बैंक राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें इन सिक्कूरिटियोंके रूपमें इन सिक्कूरिटियोंका मूल्य चुकाये तो इस परिमाणकी नकदी व्यापारिक बैंकोके पास आजायेगी। अथवा यदि केन्द्रीय बैंक अपने हिसाबमें इन बैंकोका धरोहरमें वृद्धि करदे तबभी इस धरोहरको व्यापारिक बैंक नकदीही समझते हैं। यदि अन्य बैंक अथवा संस्थाएँ केन्द्रीय बैंकको सिक्कूरिटियाँ बेचतीहैं तबभी प्राप्त मूल्यका कुछ न कुछ हिस्सा व्यापारिक बैंकोमें अवश्य जमा होजाता है जिससे उनके नकदीके कोषमें वृद्धि होती है। इसके प्रतिकूल सिक्कूरिटियोंके बेचनसे केन्द्रीय बैंक व्यापारिक-बैंकोकी नकदी अपने पास खींचने लगता है। यदि केन्द्रीय बैंक पर्याप्त मात्रामें आवश्यक मूल्यपर सिक्कूरिटियाँ बेचे अथवा मोलल तो वह बैंकोके नकदीके कोषको पर्याप्त मात्रामें प्रभावित करसकता है। परन्तु ऐसाभी होसकताहै कि केन्द्रीय बैंकके पास पर्याप्त मात्रामें बेचनेके हेतु सिक्कूरिटियाँ न हों। इसके अतिरिक्त यदि केन्द्रीय बैंक एक

और सिव्यूरिटिया बेचकर नकदीके कोषमें कमी जानेकी चेष्टा करें परन्तु दूसरी ओरसे व्यापारिक बैंक इन सिव्यूरिटियोंके आधारपर केन्द्रीय बैंकसे नकदी प्राप्त कर सकें तो खुले व्यापारकी क्रिया सफल नहीं होगी। अतएव सिव्यूरिटियोंको बेचनेके साथ साथ केन्द्रीय बैंकको अपनी न्यायकी दरमें भी वृद्धि करनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी अवश्यम्भावी नहीं है कि नकदीके कोषमें वृद्धि होनेके फलस्वरूप साल द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होही जायगी। आर्थिक मन्त्रीके अवसरपर बैंकोंमें बहुत नकदीका कोष बेकार संचित रहना है और केन्द्रीय बैंकभी इसमें वृद्धि करने को प्रस्तुत रहने है फिर भी चलनमें साथ द्रव्यके परिमाणमें विशेष वृद्धि नहीं होती है। इसका कारण यह है कि उधार लेनेवालों का पक्ष लाभ न होनेके कारण नये साल द्रव्यको उत्पत्तिके जायोंमें लगानेकी प्रवृत्ति नहीं रहना है। इसप्रकार हम देखते हैं कि खुले हाटकी त्रियाभी प्रत्येक अवस्थामें साल द्रव्यके प्रवन्धमें पूर्णरूपमें सफल नहीं होती है।

(२) समुक्त राज्य अमेरिकामें केन्द्रीय बैंकको यह अधिकार मिला हुआ है कि वह अपने सदस्य व्यापारिक बैंकोंको बाध्य कर सकता है कि वे अपनी देनदारीका एक न्यूनतम निर्धारित भाग नकदीके रूपमें रखें। इस अनुपातमें केन्द्रीय बैंक परिवर्तन भी कर सकते हैं और इस परिवर्तनके फलस्वरूप साल-द्रव्यके सृजनको प्रोत्साहित अथवा सङ्कुचितभी कर सकते हैं। उदाहरणके लिए व्यापारिक बैंकोंको अपनी देनदारीका २० प्रतिशत नकदीके रूपमें रखना पड़ना है तो वे किसीभी नकदीकी मात्रा के आधारपर अधिकसे अधिक पावगुने साल-द्रव्यका सृजन कर सकते हैं। परन्तु यदि केन्द्रीय बैंक इस अनुपातको घटाकर दस प्रतिशत करदे तो उनी नकदीकी मात्राके आधारपर दस-गुने साल-द्रव्यका सृजन होसकता है। इसके प्रतिकूल यदि इस अनुपातमें वृद्धि करदी जाय तो बैंकोंके साथ द्रव्यकी मात्रामें भी कमी करनी पड़ेगी। परन्तु यदि बैंकोंके पास अनिवारित नकदी प्रचुर मात्रामें है तो इस अनुपातमें वृद्धि होनेपर भी बैंक साल-द्रव्यके परिमाणको कम करनेको बाध्य नहीं होंगे। अनेक अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार अन्य देशोंके केन्द्रीय बैंकोंको भी अन्तःसाधनोंके साथ साथ इस साधनका प्रयोगभी साखने नियन्त्रणके सम्बन्धमें करना चाहिए।

इन तीन साधनोंके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि केन्द्रीय बैंकको अन्य बैंकों पर अपने ऊँचे और सम्मानित पद का भौतिक प्रभावभी डालना चाहिए। यदि

देशमें द्रव्य-सम्बन्धी दुरावस्था उत्पन्न होनेकी आशकाहो तो केन्द्रीय बैंकको चाहिए कि अन्य बैंकोका ध्यान इस ओर आकर्षित करे और उनको उचित सलाह दे। केन्द्रीय बैंक कहातक इस कार्यमें सफलहो सकेगा यह केन्द्रीय बैंकके सामर्थ्य, प्रभाव और अन्य बैंकोके साथ उसका किसप्रकार सम्बन्ध है, इन बातोंपर निर्भर रहेगा।

केन्द्रीय बैंक राज्य-सम्बन्धी आर्थिक कार्यभी करते हैं। आधुनिक कालमें राज्य, कर द्वारा देशकी आयका एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है और इन आयको व्यय करता है। ऋण लेकरभी राज्य देशके द्रव्य सम्बन्धी कार्योंमें हस्तक्षेप करता है। अतएव यह आवश्यक होजाताहै कि राज्यके इस प्रकारके द्रव्य-सम्बन्धी कार्य केन्द्रीय बैंक द्वारा सम्पादित हों। केन्द्रीय बैंक राज्यकी आयको अपनेपास धरोहर के रूपमें रखता है। राज्यके ऋणका प्रबन्धभी केन्द्रीय बैंक करते हैं। अन्य देशोंसे जो राज्यका द्रव्य-सम्बन्धी लेनदेन होताहै वहभी केन्द्रीय बैंक द्वाराही किया जाता है।

केन्द्रीय बैंकको बैंकोका बैंकभी कहते हैं। इस रूपमें केन्द्रीय बैंक अपने पास अन्य बैंकोकी धरोहर रखते हैं। किसी किसी देशमें बैंकोको एक न्यूनतम धराहर केन्द्रीय बैंकके पास रखनी पड़ती है। भारतमें शेडयूटड बैंक (जिनकी पूंजी और संचित कोष ५ लाखसे अधिक हों) को अपनी तत्काल देय धरोहरका ५ प्रतिशत और दीर्घकालिक धरोहरका २ प्रतिशत रिजर्व बैंक (भारत का केन्द्रीय बैंक) के पास बनाये रखना पड़ता है। अमेरिकाके संयुक्त राज्यमें भी इसी प्रकारकी प्रथा है। अन्य देशोंमें अपनी सुविधाके लिए बैंक केन्द्रीय बैंकमें धरोहर रखते हैं। इस प्रकार बैंकोंकी धरोहरका एकीकरण और केन्द्रीयकरण होजाने से केन्द्रीय बैंक किसी बैंककी सङ्कटकी अवस्था पर आर्थिक सहायता करनेमें समर्थ होता है।

यदि बैंकोंपर सङ्कट आताहै तो वे अन्ततोगत्वा केन्द्रीय बैंककी धारण लते हैं। इसलिए केन्द्रीय बैंकको अन्तिम ऋणदाता कहाजाता है। केन्द्रीय बैंकको अधिकार रहताहै कि वह कुछ परिमाण तक सिक्कूरिटियोंके आधारपर नोट छाप सकता है। अतएव जब बैंकोवे ऊपर सङ्कट आताहै तो केन्द्रीय बैंक उनको भुनायीहुई हुडियों को फिरसे भुनाकर अथवा उनकी सिक्कूरिटियोंको बन्धकके रूपमें अपनेपास रखकर उनके आधारपर बैंकोको ऋण देकर उनकी सहायता करता है। भारतके रिजर्व बैंक का एक यहभी वर्तव्यहै कि वह समय समयपर बैंकोका निरीक्षण करता रहे,

उनको उचित सलाह दे और इसप्रकार सकट उत्पन्न होनेके कारणोंको प्रभावहित करता रहे।

केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकोंके लिए क्लियरिंग हाउसका कार्यभी करते हैं। क्लियरिंग हाउस एक ऐसी संस्था होती है जहापर बैंकोंको आपसी लेनी-देनीका भुगतान होता है। उदाहरणके लिए यदि लखनऊ शहरमें २० बैंक हैं तो प्रत्येक दिन प्रत्येक बैंकके पास अन्य बैंकपर लिखे हुए चेक जमा होंगे जिन्हें धमूल करनेके लिए उनको प्रबन्ध करना पड़ेगा। क्लियरिंग हाउससे यह कार्य बड़ी सुगमतासे हो जाता है। सभी बैंक क्लियरिंग हाउसमें अपना हिसाब रखते हैं। मान लीजिए लखनऊ इम्पोरियल बैंक क्लियरिंग हाउसका कार्य करता है। प्रत्येक बैंकका एक प्रतिनिधि अन्य बैंकों पर लिखे हुए प्राप्त हुए चेकोंको लेकर इम्पोरियल बैंक पहुंचेगा। मान लीजिए सेण्ट्रल बैंकके पास इलाहाबाद बैंकपर १००० रुपयेके चेक हैं और इलाहाबाद बैंकके पास सेण्ट्रल बैंकपर ८०० रुपयेके चेक हैं। अब ८०० रुपयेका तो आपसमें ही हिसाब हो जाता है। शेष २०० रुपयेका चेक इलाहाबाद बैंक सेण्ट्रल बैंकको क्लियरिंग हाउसपर दे देगा और क्लियरिंग हाउसके सातेमें इलाहाबाद बैंककी धरोहरमें २०० रुपये कम कर दिया जायगा और सेण्ट्रल बैंकके हिमाबमें २०० रुपये जोड़ दिया जायगा। इसीप्रकार अन्य बैंकोंकी भी आपसकी लेनी देनीका हिसाब हो जाता है। दूरके बैंकोंके सम्बन्धमें केन्द्रीय बैंक क्लियरिंग हाउसका काम सुविधापूर्वक कर सकता है क्योंकि इसके पास अन्य बैंकोंकी धरोहर रहती है।

अन्य बैंकोंकी तरह केन्द्रीय बैंकभी अनेक प्रकारके बैंक सम्बन्धी कार्य करता है। परन्तु विशेष उत्तरदायित्व और कर्तव्य हानेके कारण इसके कार्योंमें कुछ प्रतिस्पर्धा लगाये जाते हैं। यह किसी उद्योग धन्धे अथवा वाणिज्य व्यवसायमें भाग नहीं ले सकते हैं। बिना पूर्व स्वीकृत जमानतके ऋण नहीं दे सकते हैं। सब प्रकारकी हुज्जियों को नहीं भुना सकते हैं। धरोहर पर ब्याज नहीं देते हैं। इन प्रतिबन्धोंका अभिप्राय यह है कि केन्द्रीय बैंक को राष्ट्रीय बैंक होनेके कारण सदैव इस योग्य बना रहना पड़ता है कि वह न केवल अपनी ऋण शोधन-क्षमता बनाये रखे वरन् जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है भव्य अवसरपर अन्य बैंकोंकी सहायता करे। अतएव केन्द्रीय बैंक जोखिमके कार्योंमें अपना रुपया नहीं फसा सकता है।

केन्द्रीय बैंकसे आर्थिक व्यवस्थाको अस्थिरतासे बचानेमें बहुत कुछ आशा की

जाती है। जहातक द्रव्य-जनित अस्थिरता का सम्बन्ध है केन्द्रीय बैंक इस कार्यमें सहायता करसकता है परन्तु भविष्यमें किस प्रकारकी आर्थिक स्थिति होगी इसका पूर्वज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। भिन्न भिन्न आर्थिक अवयवोंके उपकरणों के आधारपर अनुमान लगाया जाता है और तब द्रव्य-नीति को आर्थिक अवस्थाके अनुकूल बनानेकी चेष्टा कीजाती है। केन्द्रीय बैंक इस सम्बन्धमें प्रबन्ध विशेष रूपसे गवेषणा कररहे है और अपने साधनों और उपकरणोंको भी उपयुक्त बनानेकी चेष्टा कररहे है। अभीतक इस कार्यमें अधिक सफलता प्राप्त नहीं होसकी है परन्तु आशा की जाती है कि भविष्यमें केन्द्रीय बैंक इस कार्यमें उत्तरोत्तर सफल होंगे।

विदेशी विनिमय

विदेशी विनिमय की आवश्यकता

आधुनिक कालमें कोईभी देश अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों और परिस्थितियोंसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकना है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूँजीके आयात और निर्यातके फलस्वरूप प्रत्येक देशमें अन्य देशोंके साथ लेनी देनीसे सम्बन्धित प्रश्न तथा सत्पाए उत्पन्न होजानी है। यदि सभी देशोंमें एकही प्रकारकी द्रव्य-पद्धति होती और एकही प्रकारका द्रव्य होनातो इस प्रकारकी लेनी देनीकी अनेक समस्या-श्रीका समाधान सुगमतासे होसकता। परन्तु वास्तवमें ऐसी स्थिति नहीं पायीजाती। प्रत्येक देशमें आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारणोंसे भिन्न भिन्न प्रकारके द्रव्य और द्रव्य-रीतिया विकसित हुई हैं। अतएव राज्यकी भीमा द्रव्यकी भीमाभी बन गयीहै एक देशका राज्य-प्रामाणित द्रव्य दूसरे देशमें द्रव्यके रूपमें काममें नहीं लाया जासकता। यदि सोनेकी मुद्राभी हो, तो एक देशकी मुद्रा दूसरे देशोंमें द्रव्यका काम नहीं देसकनी क्योंकि वहाँकी सोनेकी मुद्राकी मौल्य, सोने की सखता इत्यादि भिन्न होते हैं। एक देशकी सोनेकी मुद्रा अन्य देशोंमें द्रव्यके रूपमें नहीं बल्कि वस्तुके रूपमें स्वीकार कीजानी है। कागजका नोट तो केवल अपनेही देशमें द्रव्यका काम देसकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम भारत और पाकिस्तानमें देख सकनेहैं जिनमें दो द्वाई वर्ष पूर्व एकही प्रकारका द्रव्य था। अब पाकिस्तानके नये नोट और भारतके नये नोट भिन्न भिन्न प्रकारके होगये हैं और अपने अपने देशमें ही प्रामाणित मानेजाते हैं। अतएव यदि भारतवासियोंको पाकिस्तानमें मोल लीगयी वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य चुकानाहै तो उनको पाकिस्तानके द्रव्यकी आवश्यकता होगी और यदि पाकिस्तान वालोंको भारतमें प्राप्त वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य चुकानाहै तो उनको भारतके द्रव्यकी आवश्यकता होगी। दूसरे देशके द्रव्यको प्राप्त करनेके लिए उसका

मूल्य देना पड़ता है। विदेशी द्रव्यको विदेशी विनिमयभी कहते हैं और जिस मूल्यपर वह प्राप्त होता है उसको विदेशी विनिमयकी दर कहते हैं।

वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनीवा भुगतान वस्तु तथा सेवाके विनिमय द्वारा ही सम्पादित होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि देनदार देश अपने देशका द्रव्य लेन-दार देशको भेजे और जैसा हम भागे चलकर बनायेंगे, इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। अभी हमने बताया कि एक देशका द्रव्य दूसरे देशों में प्रामाणिक नहीं होता। सोने चांदीकी मुद्राएँ भी यदि देनदारी पूरी करने के लिए अन्य देशोंको भेजी जाती हैं तो उनको द्रव्य न कहकर हमको धातु-वस्तुही समझना चाहिए। जिनप्रकार चाय के निर्यातमें हम अपनी देनदारी चुका सकते हैं, वही सोने के निर्यातसे भी हो सकता है। परन्तु सोने के निर्यात और चाय अथवा अन्य वस्तुओं के निर्यातसे देन-दारी चुकाने में एक महत्वपूर्ण भिन्नता यह है कि सम्भव है लेनदार देशको हमारी वस्तुओंकी आवश्यकता न हो अथवा किन्हीं कारणोंसे वह इन वस्तुओंको स्वीकार करदे परन्तु जहाँतक सोनेका प्रश्न है उसको वह अवश्य स्वीकार करलेगा क्योंकि सोना एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमें प्रत्येक देशमें द्रव्यके रूपमें होता है और सम्भवतः होता रहेगा। सोने के निर्यातसे अन्य देशों के द्रव्य को प्राप्त करना सुगम होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनी का सामंजस्य

यदि दो देशों में कुल लेनी-देनी वस्तु तथा सेवा-विनिमय द्वारा ही चुकता की जाये तो भी इस बातकी आवश्यकता रहेगी कि दोनों देशों के द्रव्यका आपसका मूल्य जाना जाये क्योंकि अपने अपने देशकी वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य अपने ही द्रव्यमें प्रकट किया जाता है। अतएव किसी देशकी वस्तुओं के कितने परिमाण के विनिमयमें अपने देशकी वस्तुओंको कितने परिमाणमें दिया जाये इसका हिमाव बिना विदेशी विनिमय की दर निर्धारित निये नहीं हो सकती। यदि विनिमयकी दरमें बदलाव आजाये तो विदेशी पावनेको पूरा करने के लिए स्वदेशसे कम या अधिक मात्रा में वस्तुओंका निर्यात करना पड़ेगा। अतएव इस विषयका विवेचन करना कि विदेशी विनिमयकी दर किसप्रकार निर्धारित होती है, बड़े महत्वका है। वस्तुओंके मूल्य-निर्धारणके

प्रकरणमें माग और पूतिका महत्व समझाया जा चुका है। इसी माग और पूतिके मिद्धान्तका प्रयोग विदेशी द्रव्यके मूल्य अर्थात् विदेशी विनिमयकी दरको निश्चित करनेके सम्बन्धमें भी किया जा सकता है। पहिले हम यह बतायेंगे कि किसी देशकी विदेशी द्रव्यकी माग किन किन कारणान् होती है। इसका एक मुख्य कारण वस्तु-आवा आयात है। जिन देशोंसे हम वस्तुएं माग लेते हैं उनका मूल्य चुकानेके लिए हमें उन देशोंके द्रव्यकी आवश्यकता होती है। यदि आयातका परिमाण बढ जाये, तो विदेशी द्रव्यकी माग भी बढ जायेगी। पिछले दश-बीस वर्षोंसे भारतको बाहरसे घनाज मगाना पडा है अतएव विदेशी विनिमयकी माग भारतमें बढ गयी। दूसरे देशकी वस्तु-ओंके अतिरिक्त हम उनकी सेवाआका भी उाभोग करते हैं। इनका भी मूल्य चुकाना पडता है। इनमें प्र-मान सेवाएं विदेशी जहाजों, बीमा-कम्पनियों और बैंकों की सेवाएं हैं। इनका हिसाब चुकता करनेके लिए भी हमको विदेशी विनिमयकी माग रहती है। इन वस्तुओं और सेवाओंके अतिरिक्त सोने और चादीका भी आयात होता है। इस सम्बन्धमें भी इनदारी होनी है और विदेशी द्रव्यकी आवश्यकता पडती है। हम सभी बता चुके हैं कि सोनेचादी को धन्य वस्तुओं और सेवाओंसे विशिष्ट स्थान क्यों प्राप्त है। इसी कारणसे इसका हिसाब अलगही रखा जाता है।

यदि किसी देशके लोग अन्य देशमें विद्योपार्जन अथवा भ्रमण करनेके लिए जायें अथवा विदेशी सस्थाओंको दान भर्जें तबभी उनके विदेशी विनिमयकी आवश्यकता होगी। यदि विदेशी द्रव्य उधार लिया गया हो अथवा विदेशी पूजा अपने देशके उद्योग धन्यामें लगी हुई हो, तो उन विदेशियोंको व्याज और लाभांश देना पडता है। यदि राज्यने दूसरे देशों अथवा सस्थाओंसे ऋण लिया हो जैसा कि भारत सरकारने विश्वकोषमें लिया है तो उसपर व्याज देनेके लिए भी विदेशी विनिमय चाहिए। इसी प्रकार कभी कभी युद्धमें हारे हुए देशोंको क्षतिपूरक धन देना पडता है। इन सभी प्रकारकी अनन्तराष्ट्रीय देनदारियोंको चालू हिसाबकी देनदारी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त विदेशी विनिमयकी पूजीके हिसाबके सम्बन्धमें भी आवश्यकता पडती है। यदि किसी देशमें लगी हुई विदेशी पूजीको लौटाना पडे और विदेशमें लिए हुए ऋणकी अवधि पूरी हो जाने पर मूलधनका भुगतान करना पडे तो उन देशके द्रव्यकी आवश्यकता होती है। यदि किसी देशके निवासी अन्य देशोंके शेर, बौट और हुडिया खरीदकर उन देशोंके उद्योग धन्यों में अपनी पूजी लगाए

अथवा उनके बेचनेमें अपना धन रखना चाहें तोभी उनको विदेशी विनिमयकी आवश्यकता होती है।

इसीप्रकार अनेक मदोंसे किसी देशको विदेशी विनिमयकी प्राप्ति होती है। व्यापारिक वस्तुएँ, सोना और चादीके निर्यातसे तथा हमारे देशवासियोंको सेवाएँ देवने से उन देशोंको द्रव्य प्राप्ति होती है। यदि विदेशी लोग अपने देशमें पर्यटनके लिए आयें तो उनके व्ययसे भी उन देशोंका द्रव्य प्राप्त होता है। विदेशोंसे दानके रूपमें अथवा शक्तिपूरक धनके रूपमें भी विदेशी विनिमय प्राप्त होना है। विदेशोंको दिये हुए ऋणसे व्याज और विदेशोंमें लगी हुई पूँजीपर साभाशभी विदेशी विनिमयकी पूर्ति करता है। ये सभी लेनीकी मदें चालू हिसाबकी कहो जाती हैं। इसके अतिरिक्त लेनीकी कुछ मदें पूँजीसम्बन्धी हिमावमें रहती हैं। यदि किसी देशके निवासी अन्य देशोंके शेर, बौड़ इत्यादि साम्य पशुओंको बेच दें तो उनको अन्य देशोंका द्रव्य प्राप्त होजायेगा। इसीप्रकार ऋणकी अवधि पूरी होनेपर साहूकार देशको ऋणी देशका द्रव्य मिलजाना है।

यदि किसी देशकी चालू तथा पूँजीसे सम्बन्धित लेनी और देनीकी मदोंका ठीक ठीक हिसाब रखाजाये, तो इन दोनों पक्षोंका योग बराबर होगा। इसका कारण यह है कि यदि किसी कालमें किसी देशकी चालू हिसाबकी देनदारी अन्य देशोंके चालू हिसाबकी लेनदारोंसे अधिक हो तो वे देनदारोंके सम्बन्धमें यह समझना चाहिए कि यह खम उन देशोंके ऋणके रूपमें दी है। इसप्रकार हिसाब रखनेपर किसीभी देशकी अन्य देशोंसे लेनी और देनी बराबर होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय लेनी देनीकी मदोंमें व्यापारिक वस्तुओंके आयात और निर्यातको बहुत महत्वपूर्ण सम्झा जाता है। आयात और निर्यातकी वस्तुओंका मूल्य साधारणतः समान नहीं रहता है। इस प्रकारके वैषम्यको हम व्यापारिक विषमता कहेंगे। यदि किसी देशकी निर्यातकी वस्तुओंका मूल्य आयातकी वस्तुओंके मूल्यसे अधिक हो, तो कहा जाता है कि व्यापारिक विषमता उसके पक्षमें है और यदि आयात की वस्तुओंका मूल्य निर्यातकी वस्तुओंके मूल्यसे अधिक है, तो व्यापारिक विषमता उस देशके विपक्षमें होगी। पूर्वकालमें एक आर्थिक विचारधाराके अनुसार यदि किसी देश की व्यापारिक विषमता उसके पक्षमें हो, तो यह उस देशकी समृद्धिका ओतक समझा जाता था। वस्तुओंके निर्यात और आयातके मूल्यके भन्नरको दूसरे

देशोंमें सोने और चादीके रूपमें वसूल किया जानाया और धानुषोका यह सचय आर्थिक शक्तिवा छोनक समझा जाता था। यह धारणा वास्तवमें युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि जैसाकि हम लेनी देनीकी मदोंके सम्बन्धमें देखचुके हैं, व्यापारिक वस्तुओं के आयात और निर्यातके अनिश्चित सेदाओंका भी आयात नियमित होनाहै और अन्य प्रकारसे भी चालू हिमावकी लेनी देनी उत्पन्न होजाती है। भारतवर्षमें व्यापारिक विपमता हमारे पक्ष में ही रहैहै परन्तु हमारा देशतो समृद्धिशाली नहीं रहा है। इसका कारण यहहै कि हमको अप्रत्यक्ष आयातकी मदोंके रूपमें विशेषों को एक बड़ी रकम देनी पड़ती थी।

व्यापारिक विपमता-सिद्धान्त

विदेशी विनिमयकी दरको निर्धारित करनेके सम्बन्धमें एक मत यहहै कि यदि किसी देशकी व्यापारिक विपमता उसके पक्षमें हो तो उसके द्रव्यकी विदेशी विनिमय की दरमें वृद्धि होगी। अर्थात् विदेशी द्रव्यकी इकाईको प्राप्त करनेके लिए स्वदेश का द्रव्य कम परिमाणमें देना पड़ेगा और अन्य देशोंको इस देशके द्रव्यकी इकाई प्राप्त करनेके लिए पहिलेसे अधिक द्रव्य अपने देशका देना पड़ेगा। इसके प्रतिकूल यदि किसी देशकी व्यापारिक विपमता उसके विपक्षमें हो तो उस देशकी विदेशी विनिमयकी दर गिरने लगेगी अर्थात् इस देशको अन्य देशके द्रव्यकी इकाईके लिए पहिले से अधिक अपना द्रव्य देना पड़ेगा और अन्य देशोंकी उस देशके द्रव्यकी इकाई प्राप्त करनेके लिए पहिलेसे कम मात्रामें अपने देशका द्रव्य देना पड़ेगा। विदेशी विनिमय की दरमें इस प्रकार बदलाव होनेका कारण यह बनलाया जानाहै कि जब व्यापारिक विपमता किसी देशके पक्षमें होतीहै तो उस देशके द्रव्यकी माग बढ़जाती है और इस कारणसे उसको प्राप्त करनेके लिए अधिक विदेशी द्रव्य देना पड़ना है। और इसीप्रकार यदि व्यापारिक विपमता किसी देशके विपक्षमें होतीहै तो उस देशको विदेशी द्रव्यकी माग अधिक होजाती है अतएव उसके द्रव्यका विदेशी मूल्य अन्य द्रव्योंमें गिरने लगता है।

इस मतमें कुछ सार अवश्य है। यदि किसी देशमें अन्य देशोंके द्रव्यकी माग किसीभी कारणसे बढ़जाये और उस देशके पास उसकी पूर्तिके साधन नहींहो तो विदेशी

विनिमयकी दरमें गिरनेकी प्रवृत्ति होगी और यदि उस देशके द्रव्यकी माग अन्य देशोंमें बढ़जाये और अन्य देशोंको इस देशका द्रव्य उस परिमाणमें प्राप्त न होसके, तो अवश्यही इस देशके विदेशी विनिमयकी दरमें वृद्धि होने लगेगी (इस प्रकरणमें हमने यह मान लियाहै कि विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन होनेमें स्वतन्त्रता है; नियन्त्रित विदेशी विनिमयकी बात दूसरीही है जैसाकि हम आगे चलकर बतायेंगे।) परन्तु यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंतो पना चलताहै कि व्यापारिक विपमता और विदेशी विनिमयकी दरका सम्बन्ध पारस्परिक है। ऐसाभी होताहै कि किसी देशके निर्यात और आयातका परिमाण और मूल्य स्वयमेव विदेशी विनिमयकी दरसे प्रभावित होता है। वास्तवमें हमको इस बातकी ध्यानबीन करनी पड़तीहै कि अन्तर्राष्ट्रीय लेनी दनी को भदोंमें किन कारणोंसे परिवर्तन होरहा है। इन्ही कारणोंके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमयकी माग और पूर्तिके परिमाणमें वैषम्य उत्पन्न होजाताहै और विदेशी विनिमयकी दरमें भी परिवर्तन प्रारम्भ होजाता है। अतएव हम कहसकते हैं कि व्यापारिक विपमता सिद्धान्त समस्याकी गहराई तक न जाकर केवल ऊपरी कारणोंपर प्रकाश डालता है।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति और विदेशी विनिमय

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके गुण और दोषोंकी विवेचना करनेके प्रकरणमें हमने बतायाथा कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत विदेशी विनिमयमें स्थिरता रहती है। यदि दो स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिवाल देश अपने अपने देशोंमें सोनेका मूल्य अपने अपने द्रव्यके रूपमें निर्धारित करदें और उस मूल्यपर किसीभी परिमाणमें सोना बेचने और मोल लेनेके लिए प्रस्तुत रहें, तो इन दो देशोंके द्रव्यके बीच स्वयमेव एक विनिमय की दर निर्धारित होजायगी जिसका सम्बन्ध उन देशोंके प्रामाणिक द्रव्यमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे स्थित सोनेके परिमाण पर होगा। उदाहरणके लिए स्वर्ण-मुद्रा-पद्धति कालमें इंग्लैंडकी प्रामाणिक स्वर्ण-मुद्रा सावरेनमें ११३ ००१६ ग्रेन शुद्ध सोना रहताथा और अमेरिकाके संयुक्त राज्यकी प्रामाणिक स्वर्ण-मुद्रा डालर में २३. २२ ग्रेन शुद्ध सोना रहता था। अतएव एक सावरेनमें स्थित सोना

$\frac{११३ \ ००१६}{२३ \ २२} = ४ \ ८६$ डालरमें स्थित सोनेके बराबर हुआ। स्टलिंग और

डालरकी इस पारस्परिक दरको विदेशी विनिमयकी टक्काली दर अथवा विदेशी विनिमयकी सम-मूल्य दर कहते हैं। यहतो हुई आधारभूत दर, वास्तविक दर इस आधारभूत दरके आसपास ही रहती है। बात यहहै कि इंग्लैंडसे अमेरिकाको अथवा अमेरिकासे इंग्लैंडको सोना भेजनेमें जहाजका तथा अन्य कई प्रकारका व्यय होता है। मानलोजिए ११३ ००१६ ग्रैन सोनेके अमेरिकासे इंग्लैंड भेजनेका व्यय .०४ डालर अर्थात् ४ सेंट होता है। ऐसी अवस्थामें इंग्लैंड और अमेरिका के बीच विदेशी विनिमयकी दर ४ ६० डालरसे अधिक नहीं बढ़ने पायेगी और ४ ८२ डालरसे कम नहीं होने पायेगी। इसका कारण यहहै कि यदि इंग्लैंड वालोंकी डालर की माग इतनी बढ़गयी कि उनको एक पौंडमे ४ ८२ से कम डालर मिलने लगा, तो वे अपनी देनदारी सोनेके निर्यातसे करने लगेंगे अतएव ४ ८२ डालरकी दर इंग्लैंडके लिए स्वर्ण-निर्यात मर्यादा और संयुक्त राज्यके लिए स्वर्ण-आयात मर्यादा निर्धारित करती है। इसीप्रकार यदि संयुक्त राज्यमें पौंडकी माग इतनी बढ़जाये कि एक पौंड प्राप्त करनेके लिए ४ ६० डालरसे अधिक देनापड़े तो संयुक्त राज्यके देनदार अपनी देनदारीके भुगतानके लिए सोनेका निर्यात करने लगेंगे। अतएव ४ ६० डालर संयुक्त राज्यके लिए स्वर्ण-निर्यात-मर्यादा और इंग्लैंडके लिए स्वर्ण-आयात-मर्यादा होजाता है। वास्तविक विदेशी विनिमयकी दर इन्ही दो स्वर्ण आयात और स्वर्ण-निर्यात मर्यादाओंके भीतर रहती है। यदि डालरकी माग अधिकहो, तो विदेशी विनिमयकी दर ४ ८२ डालरके निकट रहेगी और यदि पौंडकी माग अधिक हो, तो विनिमयकी दर ४ ६० डालरके निकट रहेगी। इसी बातको हम दूसरी प्रकार से भी कह सकते हैं। यदि इंग्लैंडमें डालरकी माग बढ़ जाती है तो इंग्लैंडसे संयुक्त राज्यकी सोना भेजकर किसीभी परिमाणमें डालर प्राप्त किये जासकते हैं। जब विदेशी विनिमयकी दर १ पौंड = ४ ८२ डालर हांमयी तो इस भावपर डालरकी पूर्ति किसीभी परिमाणमें होसकती है। इसीप्रकार यदि संयुक्त राज्यमें पौंडकी माग बढ़गयी तो वहां से इंग्लैंडको सोना भेजकर किसीभी परिमाणमें पौंड प्राप्त किये जासकते हैं। जब विदेशी विनिमयकी दर १ पौंड = ४ ६० डालर पर पहुंच जाती है तो इस दरपर किसीभी परिमाणमें पौंडके मागकी पूर्ति सोनेके निर्यातसे होसकती है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिवाले देशों में सोने के आयात और निर्यात के फलस्वरूप विदेशी विनिमय की दर में विनिमय की सम-मूल्य दर के आस पास स्थिरता रहती है। स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति के प्रकरण में हम बता चुके हैं कि कभी कभी देशों को इस स्थिरता को बनाये रखने के लिए अपनी आर्थिक अवस्थामें अस्थिरता का समावेश करना पड़ता है। यही कारण है कि आधुनिक विचारधारा स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त हो सकने वाली स्थिर विदेशी विनिमय की दर का समर्थन नहीं करती ।

नियन्त्रित विदेशी विनिमय

जिस प्रकार सरकार देश की सीमा के अन्तर्गत वस्तुओं का मूल्य नियन्त्रित कर सकती है उसी प्रकार विदेशी मूल्य का भी नियन्त्रण कर सकती है। कभी कभी दो देशों की सरकार आपस में एकमत होकर विदेशी विनिमय की दर निर्धारित कर लेती हैं और इस प्रकार का प्रबन्ध करती हैं कि यह दर व्यवहार में बनी रहे। भारत वर्ष और इंग्लैंड के द्रव्य में सन् १९२६ से लेकर अब तक $१ \text{ रु०} = १ \text{ शि० } ६ \text{ पैसे}$ की दर बनी हुई है। सन् १९३१ के बाद इंग्लैंड के स्वर्ण-पद्धति छोड़ देने पर भी यही दर बनी रही। इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध के काल में संयुक्तराज्य और इंग्लैंड की सरकारों ने १ पा० का मूल्य ४ डास्टर के लगभग निर्धारित कर लिया और इस विनिमय की दर को बनाये रखा। इस प्रकार विदेशी विनिमय की दर को किसी विशेष स्तर पर बाध दिया जाता है। यदि यह दर आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल न हुई तो या तो दर को बदलना पड़ता है अथवा आर्थिक अवयवों में इस प्रकार का नया सम्बन्ध स्थापित होने लगता है (चाहे वह सम्बन्ध बाह्य हो अथवा अन्तर्गत) जिसमें इस प्रकार निर्धारित विदेशी विनिमय की दर बनी रहे।

विदेशी विनिमय की दर का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर, पूँजी के आयात और निर्यात पर और इनके द्वारा देश के भीतर के उद्योग धन्यो, वाणिज्य-व्यवसायों पर प्रभाव पड़ता है। अतएव इस दर को स्वाधीनतापूर्वक किसी भी मात्रा में बदलने देना आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से वांछित नहीं है। अविनिमय-साध्य पद्धति के अन्तर्गत विदेशी विनिमय में अस्थिरता आने की बहुत आसक्ति रहती है। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि विदेशी विनिमय से दो पक्षों का लगाव रहता है एक स्वदेशी और दूसरा विदेशी ।

कितीभी पक्षसे अस्थिरता उत्पन्न करनेवाली परिस्थितियाँ उत्पन्न होसकनी है। अतएव यह दोनो पक्षोंके हितमें है कि वे आपसमें विचार विमर्षके बाद विनिमयकी दरको निर्धारित करें और उनमें बदलाव करें। अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोषका भागोगन् जिसका वर्णन आगे चलकर किया जायेगा, इसी दृष्टिकोणको सामने रखकर किया गया है।

आर्थिक इतिहासमें ऐसे उदाहरण मिलतेहैं जबकि कोई देश विदेशी विनिमयका नियन्त्रण अपने निर्यात व्यापारको बढ़ाने अथवा आयात व्यापारको कम करनेके लिए करता है। यदि अन्य बातोंमें कोई बदलाव न होतो जो देश अपने द्रव्यके विदेशी मूल्यको घटाताहै अर्थात् विदेशी विनिमयका अवमूल्यन करताहै उससे उस की वस्तुओंके निर्यात व्यापारको प्रोत्साहन मिलताहै क्योंकि उसकी वस्तुओंका मूल्य अन्य देशोंके द्रव्यमें सस्ता होजाता है और उसका आयात व्यापार कम होने लगताहै क्योंकि विदेशी वस्तुओंका मूल्य उस देशके द्रव्यमें बढ़जाता है। इस प्रकारका लाभ स्थायी नहीं होसकता क्योंकि इससे अन्य देशोंपर जिसने इस देशका आर्थिक सम्बन्ध है, प्रभाव पड़ताहै और अपने आयात निर्यातकी रक्षाके लिए इतको भी अपने द्रव्य का अवमूल्यन करना पड़नाहै अथवा आयात-कर लगाने पड़ते हैं। इनका परिणाम यह होताहै कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका परिमाण घटने लगताहै और देशोंमें आपस में विद्रोहकी भावना उत्पन्न होजाती है। दो महायुद्धोंके बीचके कालमें इसप्रकार के बहुतसे उदाहरण मिलते हैं।

विदेशी विनिमयके नियन्त्रणकी पराकाष्ठा उस अवस्थापर समझी जातीहै जब कि देशमें विदेशी विनिमयका स्वतन्त्र हाट नहीं रहताहै और जितनाभी विदेशी द्रव्य उस देशको प्राप्त होताहै उसपर राज्यका अधिकार होजाता है। इस विदेशी द्रव्य का वितरणभी राज्यकी इच्छाके अनुसार होता है। द्वितीय महायुद्धक समयसे अनेक देशोंने इसप्रकार विदेशी विनिमयका पूर्णरूपसे नियन्त्रण किया और अभीतक यह नियन्त्रण चला आरहा है। भारतवर्षमें विदेशी विनिमयपर नियन्त्रण है। पूँजीके निर्यातके लिए विदेशी विनिमय नहीं दियाजाता है। विविध वस्तुओंके आयातके लिए बिना पूर्ण अनुमतिके विदेशी द्रव्य नहीं दियाजाता है। इसप्रकार हम देखतेहैं कि विदेशी विनिमयके नियन्त्रणके साथसाथ अन्तर्राष्ट्रीय लेनी देनीकी मदद भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमें नियन्त्रण कियाजाने लगा है।

द्वितीय महायुद्धके पूर्व जर्मनीने पहिले पहिले बड़ी मात्रामें विदेशी विनिमयके नियन्त्रणको एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया था। इसकी सहायतासे जर्मनी कुछ अशतक अपनी आर्थिक शक्तको वृद्धि करनेमें और विदेशी देनदारीके भारको कम करनेमें समर्थ हुआ था। जर्मनीमें जिस किसी व्यापारीको विदेशी द्रव्यपर अधिकार प्राप्त होताथा उसे वह अधिकार राज्य द्वारा निर्धारित सस्याको राज्य द्वारा निर्धारित दरपर बेचनेको बाध्य होना पड़ता था। इस प्रकारसे सचित्त विदेशी विनिमयका उपयोग राज्यकी अनुमतिसे ही होसकता था। राज्यकी समझमें जिन विदेशी वस्तुओं की अधिक उपयोगिता रहतीथी उन वस्तुओंके आयातके लिए विदेशी विनिमय प्रचुरतासे दियाजाता था और सस्ते भावपर दियाजाता था। जिस विदेशी वस्तुको राज्य अनावश्यक समझे उसके लिए यानो विदेशी विनिमय उपलब्धही नहीं होताथा अथवा उसको महंगी दरपर दियाजाता था। इसप्रकार एक विदेशी द्रव्यके भिन्न भिन्न प्रयोजनाके लिए भिन्न भिन्न दरोंका प्रयोग होता था।

विदेशी विनिमयक नियन्त्रणकी एक यह रीतिभी काममें लायीगयी थी कि जर्मनी के बाहर रहनेवाले लोगोंको जर्मनीके द्रव्य (मार्क) पर जो अधिकार प्राप्त होताथा उसको वे विदेशी विनिमयमें परिवर्तित करके वापस नहीं लेसकते थे। इस प्रकारका प्रतिबन्धित द्रव्य या तो जर्मनीमें ही व्यय किया जासकता था अथवा भविष्यमें वापस लेनेके निमित्त बही जमा किया जासकता था। इसका एक परिणाम यहहुआ कि विदेशोंमें जर्मनीके शेरर, बीड इत्यादि साख-पत्रोंके मूल्यमें कमी होनेलगी और कम मूल्यपर इन साख-पत्रोंको खरीदकर जर्मनीके विदेशी ऋणका भार हलका पड़गया।

विदेशी विनिमय नियन्त्रणक अन्तर्गत देशोंके बीच एक प्रकारका समझौताभी होनेलगा। जो देश इस समझौतेको स्वीकार करलेते थे, वे किसी कालावधिमें एक दूसरेसे एक निश्चित परिमाणमें वस्तुओंका आयात स्वीकार करलेने थे। परन्तु इन के मूल्यका मुगलान आयात और निर्यात करनेवाले व्यक्ति आपसमें नहीं करसकते थे। इनका हिसाब राज्यों द्वारा होना था। आयात करनेवाले व्यक्ति आयातकी वस्तुओंका मूल्य अपने द्रव्यमें राज्य द्वारा निर्धारित दैकमें जमा करदेते थे। इस कोषसे निर्यात करनेवाले व्यक्तियों द्वारा निर्यात कीगयी वस्तुओंका मूल्य देदिया जाता था।

इसप्रकार विदेशी विनिमयके नियन्त्रणसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बट्टेदेशीय न हो कर द्विदेशीय होनेलगा। इससे कुछ देशोको अवश्य लाभ हुआ परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके दृष्टिकोणसे आर्थिक वातावरण दूषित होनेलगा और विद्वेषकी मात्रा बढ़ने लगी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूँजीके लगावकी प्रगतिके लिए शुद्ध आर्थिक वातावरणकी आवश्यकता है जिसमें नियन्त्रण कमसे कम हो। इस उद्देश्यको सामने रख कर अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोषका स्थापना हुई है।

अविनिमयसाध्य द्रव्य-पद्धति और विदेशी विनिमय

हमने देखा कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत विदेशी विनिमयकी एक आधारभूत दर स्थापित होजाती है और वास्तविक दर इसके घासपास ही रहती है। अविनिमय-साध्य द्रव्य-पद्धतिवाले देशोंमें विनिमयकी दर किसप्रकार स्थिर होनीहै, इस सम्बन्ध में हम एक मिद्धान्तकी विवेचना करेंगे जिसको त्रय-शक्ति समाना सिद्धान्त कहते हैं। इस मिद्धान्तके अनुसार दो देशोंके द्रव्योंकी विनिमयकी दर उन द्रव्योंकी आन्तरिक त्रय-शक्तिपर निर्भर रहती है। उदाहरणके लिए, यदि किसी वस्तुवर्गको मोललेने के लिए समुक्त राज्यमें ४ डालर देने पड़तेहैं और उसी वस्तुवर्गको इंग्लैंडमें १ पाँड देकर खरीदा जासके तो ४ डालरकी त्रय-शक्ति १ पाँडकी त्रय शक्तिके बराबरहुई। तो यही इन द्रव्योंकी विनिमयकी दर होगी अर्थात् १ पाँड = ४ डालर। अब यदि किसी कारणसे इंग्लैंडका मूल्य स्तर दुगुना होगया और अमेरिकामें पूर्ववत्ही रहा तो अब एक पाँडकी त्रय शक्ति दो डालरके बराबर रहगयी। और इन दो देशोंकी विदेशी विनिमयकी दर अब १ पाँड = २ डालर होजायेगी।

स्वीडनके अर्थशास्त्री प्रोफेसर कैंसलने सन् १९१४-१९२३ के कालमें द्रव्य स्फीति जनिन मूल्य-स्तरों में परिवर्तन और विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन का विशेष रूपसे अध्ययन करके उनमें यह सम्बन्ध ज्ञात किया कि जैसे जैसे किसी देशके मूल्य-स्तरमें अन्य देशोंके मूल्य-स्तरों की अपेक्षा वृद्धि होनेलगती है वैसे वैसे उसके द्रव्य की विदेशी विनिमयकी त्रय-शक्तिका ह्रास होनेलगता है। प्रो० कैंसलने यह नहीं कहाहै कि दो द्रव्योंकी आधारभूत विनिमयकी दर उनकी आन्तरिक त्रय-शक्तिसे निर्धारित होती है। उनका कहना यहहै कि यदि किसी समय दो द्रव्योंके बीच कोई

सन्तुलित विनिमय की दर स्थापित होगयी है और फिर उनमें जो परिवर्तन होगा, वह उन देशोंके पारस्परिक मूल्य-स्तरोंके परिवर्तनका चोतक होगा अर्थात् विदेशी विनिमयका क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त मूल्य-स्तरोंके परिवर्तन पर न कि मूल्य-स्तरों पर चरितार्थ किया जाता है।

इस सिद्धान्तमें अनेक घुटिया और रुकावटें पायी जाती हैं। किसी समय विशेष में विदेशी विनिमयकी दरको समझनेके लिए हमको एक प्रामाणिक समयकी विनिमयकी दरको आधारभूत मानकर मूल्य-स्तरोंके परिवर्तन का अध्ययन करना पड़ेगा। पहिलेती समस्या उस समयको ज्ञात करनेकी है जिसको प्रामाणिक माना जाये। यदि यह समय दूर भूतकालमें हुआ तो इस कालान्तरमें अधिक प्रवृत्तियोंमें बहुत परिवर्तन होसकता है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या यह है कि किन वस्तुओंके मूल्य-स्तरोंके आधारपर विदेशी विनिमयकी दर सम्बन्धित है। यदि सभी वस्तुओंसे सम्बन्धित मूल्य-स्तरोंके आधारपर इस विषयकी विवेचना करें तो ज्ञात हाता है कि अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रविष्ट नहीं होती। उनका व्यापार देश के अन्दर ही होता है। ऐसी वस्तुओंके मूल्य-स्तरोंका विदेशी विनिमयकी भाग और पूर्तिपर प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रविष्ट होने वाली वस्तुओंके मूल्य-स्तरोंको लें तो इससे भी विदेशी-विनिमयकी दरपर प्रकाश नहीं पड़ता क्योंकि इन वस्तुओंके मूल्य-स्तरमें आयात-व्यय और आयात निर्यात-कर का हिमाव करलेंने पर तथा चालू विदेशी विनिमय की दरमें भिन्न भिन्न देशोंमें द्रव्यके रूपमें परिवर्तन करनेपर समानता आनेकी प्रवृत्ति होगी। इसके अतिरिक्त एक वस्तु एक विदेशी विनिमयकी दरपर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रविष्ट होजानी है और दूसरी दरपर वहासे हटजाती है। दो देशोंके मूल्य-स्तरोंमें समानता बनी रहनेपर भी विनिमयकी दरमें अन्तर होसकता है क्योंकि भिन्न भिन्न देशोंकी वस्तुओंकी माग का परिमाण केवल मूल्य-स्तर पर ही अवलम्बित नहीं रहता। मागके परिमाणमें अधिक मात्रामें परिवर्तन होजानेके कारण विदेशी विनिमयकी माग और पूर्तिमें अन्तर होजाता है और उसकी दरमें भी परिवर्तन होजाता है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमयकी दर पूँजीके आयात निर्यातसे और ऋण देनेके कारण से भी प्रभावित होती है। इन सम्बन्धोंमें क्रय-शक्ति समता सिद्धान्तसे कोई सहायता नहीं मिलती है।

वास्तवम जैसाकि हम ऊपर लिखआये है यदि विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन होनेकी पूर्ण स्वतन्त्रताहै तो जिन जिन कारणोंसे विदेशी विनिमयकी माग और पूर्ति प्रभावित होतीहै उन्ही कारणोंसे उसकी दरभी प्रभावित होगी। इन कारणोंमें अन्तर्राष्ट्रीय लेनी देनी की सभी मदें शामिल है। इन मदोंके परिमाण बदलने रहते हैं और ये विदेशी विनिमयकी माग और पूर्तिके परिमाणोंको भी बदलते रहते हैं। अतएव विदेशी विनिमयकी दरभी स्वतन्त्रतासे बदलती रहती है, कहाजाता है कि यदि विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन होने दियाजाये तो कोईभी देश अपनी द्रव्य-नीतिको अन्तर्राष्ट्रीय दबावोंसे स्वतन्त्र करके अपनी आर्थिक अवस्थाके अनुकूल बनानेमें अधिक समर्थ होगा। परन्तु हम देखतेहैं कि स्वतन्त्रता-पूर्वक बदलनेवाली विदेशी विनिमयकी दर वाछनीय नहीं समझी जाती। इसका प्रधान कारण यहहै कि इस प्रकारकी विदेशी विनिमयकी पद्धतिसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूँजीके लगावमें अनिश्चितता आजातीहै और सशयका समावेश होजाता है। आधुनिक आर्थिक नियामें वैसेभी पर्याप्त अनिश्चितता रहतीहै क्योंकि उत्पत्ति के धार्यमें समयका अन्तराव्य बढ़गया है और दूर देशोंके लिए उत्पादन करनेमें भी आसानी बनी रहती है अब यदि विदेशी विनिमयकी दरमें भी अधिक मात्रामें अस्थिरता होनेलगे तो इससे न केवल आयात-निर्यातकी वस्तुओंके मूल्य और उत्पत्तिमें अस्थिरता आजायेगी बल्कि जिन देशोंमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आर्थिक प्रगतिका प्रधान अंग है (जैसा कि इंग्लैंड में) उनकी आन्तरिक अवस्थामें भी अस्थिरता आ जायेगी। इसीप्रकार दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीके लगावको भी अबका पहुँचनेकी सम्भावना हंजाती है। हमने देखाकि राष्ट्र विदेशी विनिमयकी दरमें न तो स्वर्ण पद्धतिवाली दृढ़ता चाहते हैं और न स्वतन्त्र रूपसे बदलनेवाली चंचलता चाहते हैं। इसमें प्रतीत होताहै कि इन दोनोंकी मध्यस्थ नीति अधिक अनुकूल होगी अर्थात् विदेशी विनिमयकी दरमें न तो बड़ी मात्रामें अनपेक्षित बदलावहो और न ऐसाहो कि उसमें कोई परिवर्तन ही न किया जासके। इसके लिए कुछ अवन्ध करनेकी आवश्यकता पड़ती है।

विदेशी विनिमय-नियन्त्रण-कोष

सन् १९३१ के बाद स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति छोड़नेपर अनेक देशोंको इस प्रकार की

परिस्थिति का सामना करना पड़ा। विदेशी विनिमयकी दरमें अस्थिरता कम करनेके लिए इंग्लैंड, सयुक्तराज्य, फ्रान्स इत्यादि देशोंने एक विशेष कोषकी स्थापनाकी जिसको हम विदेशी विनिमय निम्नत्रण कोष कहें। यह कोष सरकार के आधीन रहताहै और इसका प्रयोग विदेशी विनिमयकी दरमें आकस्मिक बड़ी मात्रामें बदलाव रोकनेमें होता है। यह कोष स्वदेशी द्रव्य, विदेशी द्रव्य, सोना और ट्रेजरी बिलसे सम्पन्न रहता है।

कल्पना कीजिए किसी राजनैतिक सङ्कटके कारण अथवा और किसी कारणसे इंग्लैंडके लोग अपने धनको सुरक्षित रखनेके लिए अथवा लाभकी आशाने सयुक्त राज्यमें रखना चाहते हैं। इससे डालरकी मागमें अचानक बड़ी मात्रामें वृद्धि होजायगी। विदेशी विनिमयके हाटमें पर्याप्त डालर न होनेके कारण डालरके मूल्य में वृद्धि और पौडके मूल्यमें कमी होने लगेंगी। यहापर इंग्लैंड अपने विदेशी विनिमय कोषका प्रयोग करता है। वहमी विदेशी विनिमयके हाटमें उतर पड़ताहै और विदेशी विनिमयकी दरमें बड़ी मात्रामें परिवर्तन को रोकनेकी चेष्टा करता है। पूर्वोक्त अवस्थामें इंग्लैंडका विदेशी विनिमय कोष डालर बेचना प्रारम्भ करेगा क्योंकि डालरकी माग बढ़नेके कारण विनिमय दरमें परिवर्तन होनेकी आशका हुई है। हम पहिले लिख आयेहे कि इस कोषमें विदेशी द्रव्यभी रहता है। अतएव कोष अपने डालरको बेचने लगगा। यदि उसके पास पर्याप्त डालर न हों तो वह सयुक्तराज्य में चालू दरसे सोना बचकर डालर प्राप्त करेगा। मानीहुई बातहै कि यह कोष कहातक पौडको गिरनेमे बचा सकताहै, यह कोषके डालर उपलब्ध करनेकी शक्तिपर निर्भर है। परन्तु यहतो निश्चितहै कि कुछ प्रशतक कोष को अपने कार्यमें सफलता मिलेगा। और यदि विदेशामें पौडकी माग अचानक अधिक मात्रामें घटजानके कारण पौडके विदेशी विनिमय मूल्यमें अपेक्षित वृद्धि होनेलगे तो कोष स्वयं विदेशी द्रव्य खरीद लेगा और कोषमे पौड उपलब्ध करेगा। अपा दसके द्रव्यको उपलब्ध करना कठिन नहीं है। यदि कोषमें पर्याप्त पौड न हो, तो ट्रेजरी बिल बेचकर अथवा केंद्रीय बैंकसे उधारलेकर काम चलाया जासकता है। पौड बेचनसे कोषमें विदेशी विनिमयके परिमाणमें वृद्धि होजायेगी। यदि कोषकी विदेशी द्रव्यकी इनने परिमाण में आवश्यकता न हो तो कोष अतिरिक्त विदेशी द्रव्य से उस देशमें चालू भावपर सोना मोललेकर उसको अपने कोषमें जमा करसकता है।

इसी प्रकार विदेशी द्रव्य बेचनेसे कोपमें अपने देशका द्रव्य आवश्यकतासे अधिक परिमाणमें जमा होगया होतो अनिश्चित द्रव्यको केन्द्रीय बैंकसे सिक्कूरिटियो ग्रथवा ट्रेजरी बिलके रूपमें बदला जा सकता है।

इस प्रकारसे विदेशी विनिमयकी दरको प्रबन्धित करनेका यह आशय नहीं है कि उसमें कभी परिवर्तन ही न होने दिया जाये। यदि किसी देशमें मौलिक कारणोंसे आर्थिक मन्तुलन विकृत होजाये और वर्तमान विनिमयकी दर तत्कालीन आर्थिक परिस्थितिसे अमम्बद्ध होगयी हो, तो इस कोपने द्वारा विदेशी विनिमयकी दरको पूर्ववत् बनाये रखनेका हठ नहीं किया जायेगा। विनिमयकी दरको सन्तुलित होने दिया जायेगा और इस नयी दरमें अधिक परिवर्तन न होने देना कोपका कर्तव्य होगा। कहनेका अभिप्राय यह है कि विदेशी विनिमयमें जो परिवर्तन आर्थिक स्थितिके बदलनेसे है, उनको तो होने दिया जायेगा। परन्तु जो परिवर्तन अल्पकालीन विशेषकर सट्टे की भावनासे होजाते हैं उनको रोकनेकी चेष्टा की जायेगी।

हमने अभी बताया कि कोपकी सफलता उसकी पूँजीके परिमाणपर बहुत भ्रममें निर्भर करती है। परन्तु साथही साथ कोपके अधिकारियोंको सन्तुलित विदेशी विनिमयकी दरका पता चलाना चाहिए। यह एक बहुत कठिन काम है। कोई एक ऐसा सूचक आर्थिक अथवा नही है जिसके आधारपर सन्तुलित दरकी गणना की जा सके। साधारणतः इस बातको ध्यानमें रखा जाता है कि स्वीकृत विनिमय दर की सहायतासे देशको आर्थिक स्थिरता प्राप्त करनेमें सहायता मिले और उच्च दर को बनाये रखनेमें देशके सोनेके और विदेशी द्रव्यके कोपको विशेष क्षति न पहुँचे। इसके अतिरिक्त दर ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन की प्रवृत्ति न हो।

कोपको अपने उद्देश्यमें सफलता प्राप्त करनेके लिए यह भी आवश्यक है कि भिन्न भिन्न देशोंके कोप आपसमें सहयोगसे काम करें। विदेशी विनिमयकी दरसे कमसे कम दो दश नम्बन्धित है। यदि इन देशोंके कोप विपरीत नीतियोंका प्रयोग करें तो परिस्थिति और भी बिगड़ जायेगी। यही कारण है कि सन् १९३६ में फ्रान्स, संयुक्त राज्य और इंग्लैंडमें त्रिपक्षी ऐक्य हुआ जिसके अनुसार इनमेंसे कोईभी देश बिना दूसरेकी सम्मति प्राप्तिके विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन नहीं कर सकता था। बादमें इस ऐक्यमें और भी देश सम्मिलित हुए।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष और विश्ववैक

द्रव्य-कोष

हमने पिछले अध्यायमें बताया कि प्रथम और द्वितीय विश्व-युद्धके कालाभ्यन्तरमें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण बहुत दूषित होने लगा था। विदेशी विनिमयका नियन्त्रण, उसकी दरका प्रतिस्पादिक अवमूल्यन, द्विपक्षी व्यापार-ऐक्य और आयात-विरोधी कर लगाना—इसप्रकार की क्रियाएँ दृष्टिगोचर होने लगी थी। इनके फलस्वरूप आर्थिक सहयोगका स्थान आर्थिक विद्वेषने ले लिया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके परिमाण एवं मूल्यमें ह्रास होने लगा। अतएव द्वितीय महायुद्धके समाप्त होनेके पूर्वही इस बातका प्रयत्न किया जाने लगा कि युद्धके पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्योंके सम्पादनमें अधिक सुविधा प्राप्त होसके। इसके लिए दो योजनाएँ—एक योजना जो 'केन्स योजना' कहलाती है इंग्लैंडके विद्वानोंने बनायी और दूसरे 'व्हाइट योजना' संयुक्त राज्यके विशेषज्ञोंने बनायी। प्रत्येक योजनाके अन्तर्गत इस प्रकारके प्रस्ताव रखे गये जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय विकृतियाँ कमकी जासकें। इन दोनों योजनाओंके कुछ प्रस्ताव एक दूसरेसे मिलते जुलते थे और कुछ भिन्नभी थे। अतएव इन दोनों योजनाओंके आधारपर एक सम्मिलित योजना बनायी गयी जिसमें अधिक प्रस्ताव संयुक्तराज्यकी योजनासे लिये गये थे। यह सम्मिलित योजना बुलाई १९४४ में ब्रेटनवुड्स नामक स्थानमें एक अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-सम्मेलनके सामने रखी गयी जिसमें ४४ मित्र-राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंने भाग लिया। विचार-विमर्शके पश्चात् सम्मेलनने एक अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष और एक विश्ववैककी स्थापनाके लिए स्वीकृत धाराएँ संलब्धकी और उनको सम्मेलनमें भाग लेनेवाले राज्योंके पास हस्ताक्षरके लिए भेजा। २७ दिसम्बर १९४५ के दिन जबतक कि २८ ऐसे राज्योंकी स्वीकृतियाँ प्राप्त होचुकी थी जिनका चन्दा कोषके कुल परिमाण का ८० प्रतिशतके लगभग

था, ये स्वीकृत धाराएँ कार्यरूपमें परिणत होगयीं और अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोपकी स्थापना हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोपके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(१) अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-सम्बन्धी सहयोगको इस सस्था द्वारा प्रोत्साहन देना ।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी सन्तुलित रूपमें वृद्धि करनेमें सहायता देना जिससे सदस्य देशोंकी वास्तविक आय और उद्यमोंके स्तरमें वृद्धि और स्थिरता प्राप्त हो सके ।

(३) विदेशी विनिमयमें स्थिरता प्राप्त करवानेकी चेष्टा करना, सदस्य देशोंमें व्यवस्थित रूपसे विदेशी विनिमयका प्रबन्ध करना, प्रतिस्पर्द्धात्मक विनिमय-प्रवृत्तियोंको दूर करना ।

(४) सदस्य देशोंके बालू लेनदेनकी विभिन्न रूपोंमें चुक्ता करनेकी प्रणाली स्थापित करनेमें सहायता करना और इस प्रकारके विदेशी विनिमय नियन्त्रणको हटानेका प्रयत्न करना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें रुकावट उत्पन्न हो ।

(५) सदस्योंको कापसे द्रव्य उपलब्ध कराना जिससे कि वे बिना इसप्रकार के उपक्रमोंके प्रयोगसे जिनसे अपने देश और अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धिको भ्रूषण पहुँचे, अपने अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनकी विषमताको ठीक कर सकें और फलस्वरूप उनमें विश्वास उत्पन्न हो सके ।

(६) इन सब बातोंको ध्यानमें रखतेहुए सदस्योंकी अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनीके सन्तुलनकी हानिको यथाशीघ्र ठीक करना और कम करना ।

इस कोपकी कुल सम्पत्ति ८८० करोड़ डालर निर्धारित कीगयी थी, जिसका प्रधान भाग सदस्य देशोंके द्रव्यके रूपमें और शेष भाग सोनेके रूपमें रखनेका प्रबन्ध है । अप्रैल १९४८ तक इसको ७९० करोड़ डालरके बराबर द्रव्य प्राप्त होचुका था । प्रत्येक सदस्यका हिस्सा निर्धारित करदिया गया है । प्रत्येक सदस्य अपने भाग का २५ प्रतिशत भयवा अपने सोने और डालरके सचयका १० प्रतिशत जो भी कम हो, सोनेके रूपमें जमा करेगा और शेष भाग अपने द्रव्यके रूपमें जमा करेगा । सदस्योंमें से पांच बड़े हिस्सेवाले सदस्योंमें भयवतराज्यका २७५ करोड़, इंग्लैंडका १३० करोड़, रूसका १२० करोड़, चीनका ५५ करोड़ और फ्रान्सका ४५ करोड़ डालर निर्धारित किया गया । भारतका छठा नम्बर है और उसका हिस्सा ४० करोड़

हालर है। रूस अभी तक इस कोषका सदस्य नहीं बनाहैं अनएव इससमय भारत पाचवा बडा सदस्य है।

कोषके सदस्योंके हिस्सेका बहुत महत्व है। एकतो यहकि कोषके गवर्नरोंकी सभामें जिसमें प्रत्येक सदस्य देशको प्रतिनिधित्व प्राप्तहै, अपने हिस्सेके परिमाणके आधारपर मत देनेका अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य देशको २५० वोट और उसके ऊपर प्रत्येक एकलाख डालरके हिस्सेके पीछे एक वोट देनेका अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रारम्भके पाच बडे हिस्सेदारोंको कोषकी १२ सदस्योंकी कार्यकारिणी सभामें स्थायी स्थान प्राप्त है। परन्तु हिस्सेका सबसे बडा महत्व यहहै कि प्रत्येक सदस्य कोषसे किसीभी १२ महीनेकी अवधिमें अपने हिस्सेके २५ प्रतिशत परिमाण तकही अपने द्रव्यके बदले दूसर देशोंका द्रव्य प्राप्त करसकता है। उदाहरणके लिए, भारतका हिस्सा ४० करोड डालरहै तो भारतवर्ष किसीभी १२ महीनेकी अवधिके अन्दर इस कोषसे पर्याप्त मात्रामें रुपया जमाकरके १० करोड डालरतक प्राप्त करसकता है। इसके अतिरिक्त जब कोषमें किसी सदस्य देशका अपनी द्रव्य अपने हिस्सेके परिमाणसे दुपना जमा होजाता है तो इसकेबाद उस देशको कोषसे विदेशी विनिमय मोल लेनेका अधिकार नहीं रहजाता अर्थात् कोषके पाम किसीभी समयमें किसी सदस्य देशके हिस्सेके २०० प्रतिशतसे अधिक उसका अपना द्रव्य जमा न होना चाहिए।

कोष और विदेशी विनिमय की दर

जहातक किसी सदस्य देशके द्रव्यके विदेशी विनिमयकी दरका प्रश्नहै, प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार दियागया है कि वह स्वयमेव अपने द्रव्यका मूल्य सोनेमें अथवा सयुक्त राज्यके हालरमें निर्धारित करके उसकी सूचना कोषके अधिकारियोंके पास भेजदे। भारतने जो विदेशी विनिमयकी दर चली आरही थी, अर्थात् १३ ३३३ ६० = १ पी० (१.२० = १ शि० ६ पे०) उसीके आधारपर यह दर निर्धारितकी। इस हिमावसे एक रुपयेका विदेशी विनिमय ३० १७ सेंटके बराबर अर्थात् एक डालरका मूल्य ३ ३०८५ रुपया होताहै। इस हिसाबसे एक रुपयेका विनिमय-मूल्य ४ १४५१४२८५७ ग्रेन शुद्ध सोनेके बराबर होताहै। इसीप्रकार अनेक सदस्य देशों

ने दिसम्बर १९४६ तक अपने द्रव्यकी विदेशी विनिमयकी दरकी सूचना भेजदी और पहिली मार्च १९४७ से कोयने विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर दिया है। युद्धजनित समस्याओं और विदेशी विनिमयके नियन्त्रणके कारण यह आशा नहीं की जा सकती थी कि यह प्रारम्भिक दर बादमें भी अनुकूल रहेगी। अतएव प्रत्येक देशको अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़नेपर कोपको सूचना देकर १० प्रतिशत तक परिवर्तन कर सकता है। इससे अधिक मात्रामें परिवर्तनकी आवश्यकता होने पर कोपकी आज्ञा प्राप्त करनी पड़नी है। इसप्रकार हम देखते हैं कि इस प्रबन्धके अन्तर्गत विदेशी विनिमयकी दरमें केवल नियन्त्रित रूपसे बदलाव करना सम्भव है। इसका उदाहरण सितम्बर १९४६ का विदेशी विनिमय का अवमूल्यन है जिसके अन्तर्गत इंग्लैंड, भारत आदि देशोंने भिन्न भिन्न परिमाणमें ३०-५ प्रतिशत तक अपने द्रव्योंके विदेशी विनिमयकी दरमें कमी कर दी। स्टर्लिंग और डालरकी विनिमयकी दर ४०३ डालरसे गिरकर २८० डालर रह गयी। रुपयेका मूल्य ३०२२५ सेन्टसे गिरकर २१ सेन्ट रह गया अर्थात् एक डालरका मूल्य ४७६ रुपया हो गया।

कोपका उद्देश्य अन्तर्गत विदेशी-विनिमयके नियन्त्रणको हटाना है। परन्तु युद्धजनित समस्याओंके कारण सभी देशोंको एकबार ही इसको कार्यान्वित करनेमें कठिनाता होनेकी सम्भावनाको ध्यानमें रखते हुए यह स्वीकार किया गया कि कुछ समयतक सदस्य देश विदेशी विनिमयका नियन्त्रण कर सकते हैं। यदि किसी देश में लगातार बड़ी मात्रामें पूँजीका निर्यात होनेलगे तो ऐसी अवस्थामें भी विदेशी विनिमयके नियन्त्रणकी अनुमति है।

कोपसे किसी सदस्य देशको अन्य सदस्य देशोंका द्रव्य प्राप्त हो सकती है। जैसा कि पहिले बताया है कि इसका अधिकतम परिमाण निर्धारित कर दिया गया है। यह ध्यानमें रखनेयोग्य बात है कि कोप किसी देशकी विदेशी विनिमयकी हाटका स्थान ग्रहण नहीं कर रहा है। साधारणतः सभी देश अपनी अपनी अन्तर्राष्ट्रीय देनीका प्रबन्ध स्वयमेव पूर्ववत् ही करेंगे। यह कोपसे अन्य देशोंके द्रव्यकी प्राप्ति तथा करेगे जबकि उनके लिए अन्य द्वार बन्द होगये हों। कोपभी उनकी सहायता सीमित माना ही कर सकता है क्योंकि पहिले तो कोपके पाम विदेशी विनिमय सीमित है तथा दूसरे सबमे बड़ी बात यह है कि यदि किसी देशकी अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनीकी

विषमता प्रतिवर्ष बढ़तीही जा रही है और वह पर्याप्त मात्रामें विदेशी विनिमय उपाजित नहीं कर पा रहा है तो इसका आशय यह निकला कि उस देशका आर्थिक सन्तुलन विकृत होगया है। इसप्रकार देश को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय देनीकी पूर्तिके लिए कोपपर ही निर्भर न रहकर आर्थिक सन्तुलनकी चेष्टा करनी चाहिए। इस कार्यमें कोप इस प्रकारके सदस्यको उपयुक्त परामर्श देकर सहायता करेगा। वास्तव में इस परिस्थितिमें पड़े हुए देशको कोपपर ही निर्भर रहनेकी प्रवृत्तिको कम करने के लिए इसप्रकार का प्रबन्ध किया गया है कि जैसे जैसे कोपके पास ऐसे देशके द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होती रहेगी (अन्य देशोंके द्रव्य मोल लेनेके कारण) उनको अतिरिक्त वृद्धि (अर्थात् अपने हिस्सेके ऊपर) पर सोनेके रूपमें एक निर्धारित दरमें शुल्क देना पड़ेगा। इस शुल्ककी दर $1/2$ प्रतिशतसे आरम्भ होकर अतिरिक्त वृद्धिके परिमाण और अवधिके अनुसार ४ प्रतिशत तक हो सकती है। यदि किसी का द्रव्य कोपमें इतना अधिक और इतने अधिक समयमें जमा होगया है कि यह दर ४ प्रतिशत तक पहुँच गयी है तो कोप इस देशको आदेश देगा कि वह इस अवस्थाका ठीक करे। कोईभी देश कोपमें अपने अतिरिक्त द्रव्यको सोनेसे अथवा किसी अन्य विनिमयमाध्य द्रव्यमें पुनः मोल ले सकता है।

यदि कोपके पास किसी सदस्य देशके द्रव्यकी माग बहुत बढ़ जाये और काप सभी प्रार्थी देशोंकी माग पूरी करनेमें असमर्थ होता है इस प्रकारके द्रव्यको अपर्याप्त घोषित कर दिया जाता है और प्रार्थी देशोंको उनको आवश्यकतानुसार वाट दिया जाता है। कोप अपर्याप्त द्रव्यवाले देशके द्रव्यको मोना बेचकर अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त करनेकी भी चेष्टा करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोपके प्रबन्धमें सोनेकी विशिष्ट स्थान प्राप्त है। सोना इस कोपकी सबसे अधिक द्रव्य सम्पत्ति है जिससे किसी भी देशका द्रव्य प्राप्त किया जा सकता है भिन्न भिन्न देशोंके द्रव्योंकी आपसी विनिमयकी दरको निर्धारित करनेके लिए सोना माध्यमका कामभी करता है। क्योंकि प्रत्येक सदस्य देशके द्रव्यका मूल्य सोने (अथवा संयुक्तराज्य के डालर) के परिमाणमें निर्धारित रहना है। अतएव इस आधारपर भिन्न भिन्न द्रव्योंका आपसका विनिमय-मूल्य स्वयंही निर्धारित हो जाता है।

परन्तु सोनेके इस स्थानसे यह परिणाम निकलना ठीक न होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय

द्रव्य-कोषके अन्तर्गत द्रव्य-सम्बन्धी प्रबन्ध स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके समान है। इस नवीन योजनाके अन्तर्गत स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिकी स्थापना करना आवश्यक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी विनिमयकी दरमें १० प्रतिशत तक अन्तर किया जासकता है और कोषकी अनुमतिसे अधिक मात्रामें भी। यह सुविधा स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत नहीं पायीजानी। इसका अभिप्राय यह है कि इस नवीन प्रबन्धमें किसीभी देशको अपनी आन्तरिक व्यवस्थाको स्थिर विदेशी विनिमयकी दरके अधीन करनेकी आवश्यकता नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोषने अपना कार्य मार्च १९४७ से आरम्भ किया। अनेक देशों ने कोषसे सहायता प्राप्त की है। उदाहरणके लिए भारतने कोषसे १९४८-४९ में लगभग १० करोड़ डालरक विदेशी विनिमय (किसीभी १२ महीनेकी अवधिके अन्दर यह परिमाण भारतके लिए अधिकतम है) प्राप्त किया। सितम्बर १९४९ के अवमूल्यन का निर्णयभी कोषकी अनुमतिसे हुआ। कोषके कार्योंकी आलोचना करनेका अभी उपयुक्त समय नहीं हुआ है। युद्धजनित विकृतियोंका समाधान अभी तक नहीं हो सका है। अनेक देशोंमें विदेशी विनिमय नियन्त्रण बना हुआ है। भाषाका इस बात की है कि इस कोषका कार्य राजनीतिक परिस्थितियोंसे विशेष प्रकारसे प्रभावित न होजाये। इसके अतिरिक्त कोषके कार्योंकी मफलताके लिए यह आवश्यक है कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्योंभी उसके उद्देश्योंके अनुकूल हो।

विश्वबैंक

वैटन वुड्स द्रव्य-सम्मेलनमें आर्थिक निर्माण और उत्थानके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंककी स्थापनाकी योजनाभी बनायीगयी। इस बैंकके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(१) सदस्य देशके आर्थिक निर्माण कार्योंके लिए, युद्धमे क्षत देशोंके पुनर्उत्थान के लिए और पिछड़े हुए देशोंके उत्पादकता बढ़ानेके लिए पूँजी प्राप्त करवानेमें सहायता करना।

(२) विदेशी पूँजीपतियों को गारंटी देकर अथवा उनके साथ सहयोग देकर पूँजी लगानेकी प्रोत्साहित करना और यदि अन्य पूँजीपतियों से उचित हिसाबसे पूँजी न प्राप्त होसके तो अपनी पूँजीसे अथवा स्वयं पूँजी इकट्ठाकर उत्पादक कार्यों

के लिए उपलब्ध करना।

(३) सन्तुलित प्रकारसे दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी वृद्धि करवाना और सदस्योंकी उत्पत्तिके साधनोंकी उन्नतिके लिए और इसके द्वारा उनके जीवन-स्तरको ऊंचा करनेके लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीको प्रोत्साहितकर उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्लैनीदेनीके सन्तुलनको बनाये रखना।

(४) स्वयं अपने पाससे अथवा अपनी जमानतपर दियेगये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण का इस प्रकारसे प्रबन्ध करना कि अधिक उपयोगी बड़ी अथवा छोटी आवश्यक योजनाको प्रथम स्थान दियाजाये।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी लगानेसे उत्पन्न प्रभावांको ध्यानमें रखतेहुए अपना कर्तव्य पालन करना और युद्ध समाप्तिपर युद्धकालीन आर्थिक व्यवस्थाको शान्ति-कालीन व्यवस्थामें परिणत करनेमें सहायता देना।

विश्व बैंककी अधिकृत पूँजी १० अरब डालरहै जो अन्तर्राष्ट्रीय कोषकी भाँति सदस्य देशोंमें हिस्सेके रूपमें प्राप्त होनी चाहिए। भारतका हिस्सा ४० करोड़ है। प्रत्येक देशको अपने हिस्सेका केवल २० प्रतिशत (१८ प्रतिशत अपने द्रव्यमें और २ प्रतिशत सोनेके रूपमें) बैंकको देना पड़ता है। शेष ८० प्रतिशतको बैंक उधार लिएहुए अथवा गारंटी कियेहुए ऋणके भुगतानके लिएही माग सकता है।

बैंक जिस देशको पूँजी उधार देताहै अथवा जिस देशसे पूँजी प्राप्त करताहै, उसे उक्त देशकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। बैंक सदस्य देशोंकी सरकारकोही ऋण देता है। वहभी उसकी ऋणकमेटी से स्वीकृत कार्यक्रमोंके निमित्तही। अन्य सत्पाएँभी बैंकसे ऋण प्राप्त करसकती हैं यदि उनकी सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक, मूलभूत व्याज और अन्य व्यय देनेकी गारंटी लें। बैंकको इस बातका भी प्रबन्ध करना पड़ताहै कि जिस कार्यक्रमोंके लिए ऋण दियागया हो, वह उसी कार्यपर उचित ढंगसे लगाया जाये। बैंकका एक मुख्य कार्य यहभी है कि वह प्रार्थना करनेपर सदस्य देशोंमें यथार्थता-ज्ञात करनेवाले कमीशनको भेजे। प्रत्येक ऋणके सम्बन्धमें उसकी अवधि, व्याजकी दर और मूलभूत लौटानेका समय बैंक निश्चित करेगा। गारंटी कियेगये ऋणपर १० वर्षतक बैंक १ से १ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष ऋणी देशसे कमीशन लेगा।

विश्व बैंककी स्थापना जून १९४६ में हुई। तबसे इसने अनेक सदस्योंको ऋण

उपलब्ध किया है। भारतको भी अभीतक दो ऋण मिले हैं। पहिला ऋण १५ वर्ष के लिए, ३०४ करोड़ डालरका, रेलके विस्तारके लिए दिया गया। जिसपर तीन प्रतिशत व्याज और १ प्रतिशत कमीशन लगाया गया। दूसरा ऋण, १ करोड़ डालरका, भूमिसुधारके कार्योंके लिए अवतूबर १९४६ में प्राप्त हुआ। एक और तीसरे ऋण की बातचीत चलरही है।

इस प्रकारके अन्तर्राष्ट्रीय बैंककी अत्यन्त आवश्यकता थी। दो महायुद्धोंके अन्तर्कालीन समयमें अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीके लगावसे यह अनुभव हुआ कि इसकी व्यवस्था ठीक नहीं चलरही है। कभी विदेशी पूँजी बड़ी मात्रामें मिलजाती थी और कभी बिल्कुलही नहीं मिलती थी। अतएव एक इस प्रकारकी संस्थाकी आवश्यकता जान पड़ने लगीथी जो स्वतन्त्र दीर्घकालीन पूँजीके अन्तर्राष्ट्रीय वितरण और लगाव का ठीक प्रबन्ध करसके और उसको प्रोत्साहन भी देसके। इस कार्यमें विश्वबैंक बहुत उपयुक्त सिद्ध होगा। यह ध्यान देने योग्य बातहै कि विश्वबैंक अन्य पूँजी-पतियोंके विदेशमें पूँजी लगानका स्थान स्वयं नहीं लेना चाहता। बहुतो उनको गारंटी देकर और उनके साथ सम्मिलित होकर अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीके लगावको उत्साहित करना चाहता है। इस प्रकारके कार्योंको अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष नहीं करसकता क्योंकि उसको अपना धन द्रव रूपमें रखना पड़ताहै इन सभी कारणोंसे विश्वबैंक की स्थापनाका सभी देशोंने स्वागत किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष और विश्वबैंकके कार्योंका निकट सम्बन्ध है। किसीभी देशमें द्रव्यकी स्थिरताके लिए आवश्यकहै कि उसमें उत्पादक कार्योंकी वृद्धि कीजाय जिससे विदेशी व्यापारकी वृद्धि होकर ऋणी देश बैंककी देनदारी पूरी करसके।

अभी हमन बताया कि विश्वबैंकने गत तीन वर्षोंमें अनेक आर्थिक कार्योंके लिए अनेक सदस्योंको पूँजी उपलब्धकी है। विशेषकर पिछड़ेहुए देशोंको इस प्रकारकी पूँजीकी बहुत आवश्यकता है। परन्तु बैंकसे ऋण प्राप्त करनेकी शर्तें बड़ी कड़ी है। व्याजकी दरभी अधिकहै और ऋण वापस करनेकी अवधिभी शीघ्रही आरम्भ हो जाती है। इन बन्धनोंके कारण भारतके सदृश देशोंको बैंकसे पर्याप्त मात्रामें ऋण मिलनेकी आशा नहीं है। बैंकके प्रबन्धक कहतेहैं कि वे बैंककी पूँजीको जोखिममें नहीं डालना चाहते। अतएव उनको बड़ी सावधानी और गतर्कतासे छानबीन करनी पड़ती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता

प्रत्येक देश उन वस्तुओंके उत्पादनमें सलग्न रहता है जिनके उत्पन्न करनेके लिए उसके पास उपयुक्त सामग्री उपलब्ध रहती है। उपयुक्त सामग्रीमें भूमि की उत्पादन-शक्ति, निवासियों की कार्यकुशलता और संग्रहीत पूँजी की मात्रा इत्यादि सम्मिलित हैं। प्रत्येक देश इस सामग्री द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओंका, अपनी देशीय आवश्यकताओंके परिमाणतक ही नहीं बरन् उससे अधिक मात्रामें, उत्पादन करना चाहता है और निजी आवश्यकताओं को तृप्त करने के अनन्तर बची हुई मात्रा को दूसरे देशों द्वारा उत्पन्न उन वस्तुओंसे विनिमय करता है जिनके उत्पादनके लिए उसके पास उपयुक्त सामग्री नहीं, या अपर्याप्त मात्रामें है।

वस्तुओंके अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनके लिए पृथक् आर्थिक सिद्धान्त निर्माण करनेकी आवश्यकता इसलिए है कि उत्पादनके साधन श्रम, पूँजी इत्यादि एक देशसे दूसरे देशमें जानेके लिए उतने गतिशील नहीं होते जितने कि एक देशके एकभाग से दूसरे भागमें जानेके लिए। इसके कईएक कारण हैं। श्रमजीवी भाषा अथवा रहनसहन की शैलीमें भेद होनेके कारण अधिक वेतन पानेपर भी अपना देश छोड़कर दूसरेमें जानेसे हिचकिचाते हैं। इसीप्रकार पूँजीपति अपनी पूँजीका परदेशमें लगाना अधिक जोखिमपूर्ण समझते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक सरकारें मनुष्यों अथवा पूँजीके आयात-निर्यातपर नियन्त्रण लगा देती हैं।

उद्योग धन्धों के स्थानीकरण से सम्बन्ध

गोहलीन के मतानुसार तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका सिद्धान्त उद्योग धन्धोंके स्थानी-

करण सिद्धान्तका केवल एक विशेष रूप है, क्योंकि देखनेमें आता है कि एकही देशके भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें भिन्न भिन्न उद्योग धन्वों का स्थानीकरण हो जाता है। इसका कारण, चाहे वह भाग एवही देशका प्रान्त हो अथवा दूसरे देशका भाग, उत्पादन के साधनोंकी भिन्नताही है। बम्बईमें सूती कपड़ा बुननेके कारखाने इमलिए मिलते हैं कि उस प्रान्तमें कपास पैदा करनेके लिए श्रेष्ठतम भूमि पायी जाती है और वहां वा जलवायु वातने और बुननेके कार्यके लिए अधिक उपयोगी है। इसीप्रकार कश्मीरमें शालदुशाले इसलिए बुने जाते हैं कि यद्यपि वहां इनके लिए बच्चा माल अन्य स्थानोंमें मगाना पड़ता है परन्तु बुननेके कार्यमें कुशल थम पर्याप्त माना में मिल जाता है। यदि किसी प्रान्तमें कोई उत्पादन का साधन अधिक मात्रा में मिलता है तो स्वाभाविकही है कि उस प्रान्तमें उसका मूल्य कम होगा और जिस वस्तुके उत्पादनमें उस साधनका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है उसका उत्पादन-व्यय उस प्रान्तमें न्यूनतम होगा।

इसमें सन्देह नहीं कि पृथ्वीपर साधनोंकी प्राकृतिक विभिन्नताही उद्योग धन्वोंके स्थानीकरणका मुख्य कारण है परन्तु इस स्थानपर अन्य कारणोंका भी जो स्थानीकरणमें सहायता देते हैं, उल्लेख करना आवश्यक होगा। उत्पादन का उद्देश्य अन्तर्गोचरता उपभोगके लिए सामग्री उत्पन्न करना है। इसकारण यदि उत्पत्तिको उपभोगके स्थानतक पहुँचानेके लिए उत्पादकको इतना व्यय करना पड़े कि उपभोग के स्थानपर उस वस्तुको उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्वाका स्थापित करना अधिक लाभकारी हो तो उत्पादक ऐसाही करेगा। ईंट बनानेके कारखाने प्रायः उपभोग स्थानोंके पासही बनाये जाते हैं क्योंकि ईंटोंका भाड़ा उनके उत्पादन-व्ययसे कहीं अधिक होता है। बहुतसे बच्चे माल ऐसे होते हैं कि जिनका समस्त अथवा अधिकांश भाग वस्तुमें विद्यमान रहता है। जैसे ऊँक, ऊँकी कपड़ेमें। ऐसी वस्तुओंका प्रायः उपभोग-स्थान के पासही निर्माण करना श्रेयस्कर रहता है। बहुतसे माल ऐसे हैं जिनका बहुत थोड़ा अंश उत्पत्तिमें विद्यमान रहता है। कोयलेका तो तनिक अंशभी उत्पत्तिमें विद्यमान नहीं रहता। ऐसे मालोंको प्रयोगमें लानेवाले उद्योग धन्वे प्रायः उन स्थानोंपर स्थापित हो जाते हैं जहाँ यह माल मिलता है। इसके अतिरिक्त किसी-एक स्थानपर उद्योग धन्वोंके एकीकरणसे ही प्रायः बहुतसी ऐसी सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं जो उस स्थानको उद्योग धन्वोंके स्थानीकरणका केन्द्र बना देती हैं।

कुशल श्रमकी पर्याप्त मात्रामें हरममय उपलब्धि, यन्त्र इत्यादि बनानेमें अथवा सुधारनेके लिए सहायक धन्वो, तथा आयात निर्यातके साधनोका अस्तित्व इत्यादि सुविधाएँ ऐसे स्थानोंपर उद्योग धन्वोको आकर्षित करनेका कारण बनती हैं। कच्चे मालको उपभोग्य पदार्थोंके रूपमें परिवर्तित होनेसे पूर्व कई बीचकी श्रेणियोंमें से गुजरना पड़ता है और एक श्रेणीसे दूसरी श्रेणीमें परिवर्तित करनेके लिए पृथक् पृथक् धन्वे हूँ तेहें। सम्भव है कि इन पृथक् पृथक् धन्वोका किसी विशेष स्थानपर एकीकरण अधिक दृष्टिमें बाछनीय हों। कपास बेनने, कातने तथा कपड़ा बुननेके कारखाने पृथक् पृथक् होतेहैं। इनके एकीकरणसे कपड़ेके उत्पादन-व्ययमें कमी होनेकी सम्भावना है। इसीप्रकार कई यन्त्र ऐसे निर्माण किये जाते हैं कि उनके द्वारा अधिक मात्रामें उत्पत्ति करनेसे उत्पादन व्यय बहुतही कम होजाता है। इस प्रकार के उद्योग धन्वोका स्थानीकरण बड़ेबड़े उपभोग-स्थानोंके पास होजाता है और इनके द्वारा उत्पन्न वस्तुओंका वितरण देश अथवा ससारभर में होता है।

तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त भिन्न भिन्न देशोंमें वस्तु-निर्माणके उत्पादन व्ययमें अन्तर होनेका ही एक विशेष रूप है। प्राचीन अर्थशास्त्री वस्तुओंके मूल्यके अर्थ-सिद्धान्तके अनुयायी थे। हम देख चुके हैं कि आधुनिक विद्वानोंके मतानुसार सीमान्त-उत्पादन-व्यय मूल्यका आधार है और इसी सीमान्त उत्पादन-व्ययकी सहायतासे हम यह ज्ञान प्राप्त करनेमें सफल होसकते हैं कि प्रत्येक देश प्रत्येक वस्तुके उत्पादनके लिए उपयुक्त है। मानलीजिए कि दो देशोंमें केवल दो वस्तुओं का ही परस्पर विनिमय हो रहा है। भारत पाकिस्तानमें कपास मगाता है और उसके विनिमयमें पाकिस्तानको कपड़ा देता है। यह विनिमयका कार्य उसी अवस्थामें सम्पन्न होनेकी सम्भावना है जबकि इसके द्वारा दोनों देशोंका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो अर्थात् भारतको कपड़ा देकर कपास लेनेमें और पाकिस्तानको कपास देकर कपड़ा लेनेमें लाभ प्राप्त होता हो। आकड़ों द्वारा हम यह सिद्ध करनेका प्रयत्न करेंगे कि यह अवस्था सदैव उपलब्ध नहीं, यह केवल उसी समय उपलब्ध होती है जबकि एक देशमें केवल एक (भारतमें कपड़ा) और दूसरे देशमें केवल दूसरा

(पाकिस्तानमें कपास) वस्तुका ही सीमान्त उत्पादन-व्यय कमहो) मानलीजिए भारतमें कपासकी एक गाठका सीमान्त उत्पादन-व्यय २०० रु० और कपड़ेके एक थानका उत्पादन-व्यय १०० रु० है। इसके विपरीत पाकिस्तानमें कपासकी एक गाठ का उत्पादन-व्यय १०० रु० और कपड़ेके थानका सीमान्त उत्पादन-व्यय २०० रु० है। स्पष्ट है कि इस स्थितिमें दोनों देशोंका क्षेत्र इसमें है कि पाकिस्तान केवल कपास के उत्पादनमें उत्पादनके साधनोंका प्रयोग करके अधिकसे अधिक मात्रामें कपास उत्पन्न करे और भारत केवल कपड़ेके उत्पादनमें उत्पादनके साधनोंको समुचित अधिकसे अधिक कपड़ा पैदा करे। फिर दोनों परस्पर विनिमय करें। अथवा भारत को स्वयं कपास पैदा करनेमें अधिक उत्पादन व्यय उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान को स्वयं कपड़ा बुननेमें। ससारमें बहुतसी वस्तुओंका अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन इसी लिए होता है कि देनेवाले देशमें उस वस्तुका सीमान्त उत्पादन व्यय लेनेवाले देशमें निरपेक्ष रूपमें कम होता है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनका होना उस अवस्थामें भी सम्भव होसकता है जबकि एक देशमें दोनों वस्तुओंके सीमान्त उत्पादन व्यय दूसरे देशमें कम है। परन्तु उस देशको उनमेंमें केवल एकही वस्तुके उत्पादनमें अपने उत्पादनके साधनोंका प्रयोग करनेमें सापेक्ष रूपमें अधिक लाभ हावकी सम्भावना होती है। कारण यह है कि प्रत्येक देशमें उत्पादनके साधनोंकी मात्रा सीमित है। इसलिए उनके प्रयाग द्वारा अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी इच्छा से उस देशके उत्पादक उसी वस्तुके उत्पादनमें अपने साधनोंको प्रयुक्त करेंगे जिसमें कि उन्हें सापेक्ष रूपमें अधिक लाभ मिलनेकी आशा है। मानलीजिए भारतमें एक गाठ कपासका सीमान्त उत्पादन व्यय १०० रु० और कपड़ेके एक थानका सीमान्त उत्पादन व्यय ५० रु० है। यदि भारत दोनोंही वस्तुओंको अपनेही देशमें उत्पन्न करले तो कपड़ेके थान और कपासकी गाठका परस्पर विनिमय मूल्य २ : १ होगा अर्थात् २ थानोंके बदलेमें एकगाठ कपास मिलसकेगी। अब मानलीजिए पाकिस्तान में कपासकी एक गाठका सीमान्त उत्पादन व्यय १५० रु० और कपड़ेके एक थान का सीमान्त उत्पादन व्यय १०० रु० है। यदि पाकिस्तान दोनों वस्तुओंको अपने देशमें ही उत्पन्न करले तो उस देशमें कपड़ेके थान और कपासकी गाठका वि-
निमय ३ : २ के अनुपातमें होगा। अब यदि पाकिस्तान कपासकी २ गाठें उत्पन्न करके भारत भेजदे तो माड़ा, बीमा इत्यादि व्ययकी गणना न होनेपर हम कहसकते

है कि भारतमें उसे ३ के स्थानपर ४ कपड़ेके थान मिल सकेंगे। इसी प्रकार भारत यदि कपड़ेके ३ थान उत्पन्न करके पाकिस्तान भेजदे तो भाड़ा, बीमा आदिके व्यय की गणना न करनेपर उसे १ १/२ गांठके स्थानपर २ गांठ कपास मिलेगी। इससे सिद्ध हुआ कि यद्यपि भारतमें कपास और कपड़े दोनोंका सीमान्त उत्पादन व्यय पाकिस्तान की अपेक्षा कम है परन्तु उनका तुलनात्मक क्षेम कपड़ेके उत्पादनमें ही अपने साधनोंको प्रयुक्त करनेमें है। ऐसी स्थितिभी असम्भव नहीं है कि एक देश में दोनों वस्तुओंके सीमान्त उत्पादन व्यय दूसरे देशमें कम हो परन्तु फिर भी किसी एक देशको भी उनमेंसे एकही वस्तुको उत्पन्न करके दूसरेसे दूसरी वस्तु विनिमयद्वारा प्राप्त करनेमें तनिकभी लाभ न हो। मान लीजिए भारतमें कपड़ेके थानका सीमान्त उत्पादन-व्यय ५० रु० और कपासकी गांठका सीमान्त उत्पादन-व्यय १०० रु० है और पाकिस्तानमें क्रमशः ७५ रु० और १२० रु० है। भारत यदि दोनों वस्तुएं अपने देशमें उत्पन्न करे तो उनका पारस्परिक विनिमय २:१ के अनुपातमें होगा और यही अनुपात पाकिस्तानमें भी होगा। इसकारण न तो भारतको कपड़ा उत्पन्न करके उसके विनिमयमें पाकिस्तानमें कपास लेनेमें कोई लाभ है और इसीतरह न पाकिस्तानको कपास उत्पन्न करके भारतमें कपड़ा लेनेमें। इससे सिद्ध हुआ कि यदि एक देश किसी दूसरी वस्तुको और दूसरा किसी अन्य वस्तुको निरपेक्ष रूपमें कम उत्पादन-व्ययसे उत्पन्न कर सकता है तो उन दोनों वस्तुओंके अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन होनेकी सम्भावना है। इसके अतिरिक्त जब एक देश दोनों वस्तुओंको दूसरे देशकी अपेक्षा कम व्ययमें उत्पन्न कर सकता है तो भी उन देशोंमें अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन होनेकी सम्भावना है यदि एक वस्तुके उत्पादनसे सापेक्ष रूपमें दूसरी वस्तुके उत्पादनमें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। परन्तु यदि उत्पादन-व्यय ऐसे हों कि दोनों वस्तुओंका एकही देशमें उत्पन्न करनेपर भी उनका पारस्परिक विनिमय उसी अनुपातमें हो पाना हो जिस अनुपातमें कि एक वस्तु स्वयं उत्पन्न करके दूसरी वस्तु दूसरे देशसे विनिमय द्वारा प्राप्त करनेसे तो ऐसी अवस्थामें उन वस्तुओंके अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयकी तनिक भी सम्भावना नहीं है।

इस सम्बन्धमें इतना कहना आवश्यक है कि तुलनात्मक उत्पादन व्ययके सिद्धान्त का यह अर्थ नहीं कि जो वस्तु विनिमय द्वारा दूसरे देशसे प्राप्त की जाती है उसके उस देशमें उत्पादन का नितान्त अभाव हो। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा देश

उस वस्तुको उतनी मात्रामें उत्पन्न न करपाता हो, जिससे उसकी अपनी तथा दूसर दानकी सम्मिलित भाग पूरी होसके।

तुलनात्मक उत्पादन व्ययका सिद्धान्त उम स्थितिमें भी लागू होनाई जबकि एक देश बहुतसी वस्तुधाके विनिमयस किसी अन्य देशमें बहुतसी वस्तुएं प्राप्त कर रहा हो। इन स्थितिमें कहना सक्ताहै कि प्रत्येक देशसे निर्यात कीजानवाली वस्तुधाके उत्पादनमें उस देशमें आयात होनेवाली वस्तुधाकी अपेक्षा उस देशको आपेक्ष रूपमें अधिक लाभ हो रहा है।

अन्तमें यह कहदेना अनुचित न होगा कि तुलनात्मक उत्पादन व्यय सिद्धान्तको उत्पादन व्ययका द्रव्यके रूपमें परिवर्तित करके सिद्ध करना तर्क की दृष्टिसे दूषित है। मौद्रिक उत्पादन व्यय उत्पादनके साधनाको दियग्य मौद्रिक मूल्यका ही रूपान्तर है और इन साधनाका मौद्रिक मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी अनुपस्थितिमें वह न होता जो इस व्यापारकी उपस्थितिमें है। वास्तवमें अकेल उत्पादन व्ययका मौद्रिक रूपही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका कारण नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारभी इस रूपमें उनका कारण होसकता है। उत्पादन व्ययका वास्तविक प्रयत्न उत्पादनके साधनोंकी उस मात्रासे है जो वस्तु विशयके उत्पादनके लिए आवश्यक है। उन साधनाको उम वस्तु विशयके उत्पादनमें लगानसे किसी अन्य वस्तुके उत्पादनमें नहीं लगाया जासकता है। उस अन्य वस्तुको उत्पन्न न करनेस उस देशको जो हानि हुईहै वह वस्तु विशयका व्यय है जिसे अवसर व्यय अथवा वैकल्पिक व्ययभी बुझा जाताहै और यही व्यय तुलनात्मक उत्पादन व्यय सिद्धान्तका आधार है।

भाग की लोच और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

हम यह देखही चुकेहैं कि वस्तुधोवा अन्तर्राष्ट्रीय लनदेन उसी अवस्थामें सम्भवहै जबकि लनवाल औरदनवाल दोनों देशोका हित अपनी कुछ वस्तुएं देकर दूसर देशसे कुछ वस्तुएं लनमें हो। हम देखचुके हैं कि भारतमें कपास की गांठ और कपड़े धानका सीमान्त उत्पादन-व्यय क्रमशः १००२० और १००० हैं और पाकिस्तान में यही व्यय १५० और १००००० हैं, तो कपास पैदा करके भारतस कपड़ा लनमें पाकिस्तान को कपासकी २ गांठें देकर कपड़े के ४ थान मिलजाते हैं और स्वयं दोनों

वस्तु उत्पन्न करनेपर केवल कपड़ेके ३ थानोसे विनिमय होना सम्भव था। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयसे पाकिस्तानको अधिकसे अधिक कपड़ेके एक थान की अतिरिक्त प्राप्ति होनेकी सम्भावना है क्योंकि यदि कपासकी २ गाठोके विनिमय से भारतको कपड़ेके ४ से अधिक थान देने पड़ेंगे तो वह पाकिस्तानसे कपास लेनेके स्थानमें स्वयं उत्पन्न करना आरम्भ कर देगा। इसी प्रकार यदि पाकिस्तानको २ गाठोके बदलमें कपड़ेके ३ थानसे कम मिलेंगे तो वह कपड़ा स्वयं उत्पन्न करना आरम्भ कर देगा। इस एकथान में से भारत और पाकिस्तानको लाभके रूपमें प्राप्त अर्ध भारतकी कपासके लिए और पाकिस्तानकी कपड़ेके लिए मागकी लोचकी सहायतासे किम्मा आसकता है। यदि भारतकी कपासके लिए माग अधिक लोचदार है तो इस लाभका मुख्य अर्ध भारतको प्राप्त होगा। क्योंकि यदि पाकिस्तान अपनी दो कपासकी गाठाका विनिमय-मूल्य कपड़ेके तीन थानोसे थोडाभी अधिक करेगा तो भारत द्वारा कपासके लिए कुल मागमें भारी कमी आजाने से पाकिस्तानको इस विनिमय द्वारा प्राप्त होनेवाले कुल लाभमें भी भारी कमी होनेकी सम्भावना है। भारत द्वारा कपासके लिए माग कम लोचदार होनेसे लाभका मुख्य अर्ध पाकिस्तान को प्राप्त होगा और थोडा अर्ध भारत को। पाकिस्तानकी कपड़ेकी माग अधिक अथवा कम लोचमयी होनेसे यह अनुमान लगाया जासकता है कि कौनसा देश लाभ का मुख्य अर्ध प्राप्त करेगा और कौनसा अल्पार्ध। इस प्रकार वस्तुओंके उत्पादन-व्यय और उनकी मागकी लोचके आधारपर दो देशोंमें उनके पारस्परिक विनिमयके भाव निश्चित होनारहते हैं। समय समयपर इन भावोंमें परिवर्तन होते रहते हैं। यदि परिवर्तन मागमें परिवर्तन होनेके कारण हो तो वह देश जिसकी वस्तुओंकी माग बढ़जायी है अथवा जिसकी वस्तुओंकी मागकी लोच कम होजाती है, अधिकतर लाभ प्राप्त करता है। उत्पादन-व्ययमें परिवर्तन होनेसे लाभ-हानिका निर्णय करना इतना सुगम नहीं। क्योंकि होसकता है कि उत्पादन-व्यय बढ़नेसे यदि उस वस्तुकी माग अधिक लोचदार नहीं है तो पहिलेसे अधिक मूल्यभी प्राप्त होसके। इसीप्रकार उत्पादन-व्यय कम होनेपर प्राप्त मूल्यके कम होनेकी भी सम्भावना है। केवल इतना होसकता है कि मूल्य कम होनेसे उस वस्तुकी माग बढ़जाये और कुल प्राप्त लाभ पहिलेसे अधिक हो। इन भावोंमें परिवर्तन उस देशके लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो अपनी उत्पातिका अधिकांश दूसरे देशोंको भेजदेता है।

उन्मुक्त और संरक्षित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

उन्मुक्तता के लाभ

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्तका अर्थ यह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें प्रत्येक देश उन वस्तुओंके उत्पादनमें सलग्न होगा जिनको उत्पन्न करनेकी उसे अन्य देशोंकी अपेक्षा मापेक्ष रूपमें अधिक सुविधा प्राप्त होगी और अन्य वस्तुओंको जो उसे भाड़ा इत्यादिके व्ययकी गणनाके अन्तर्गत स्वयं उत्पन्न करनेकी अपेक्षा अन्य देशोंसे कम मूल्यपर मिल सकती है, उन देशोंसे मगवायेगा। इसप्रकार मसारके प्रत्येक देशमें मिलनेवाले उत्पादनके साधन ऐसी वस्तुओंके उत्पादनमें लगाय जायेंगे जिनकी वे अधिकतम उत्पात्ति करनेके योग्य होंगे। फलस्वरूप सब प्रकारकी वस्तुओंकी मसारमें अधिकतम उत्पात्ति होगी और प्रत्येक देश के निवासियोंकी वस्तुओंके रूपमें धन उच्चतम होगी। यह कार्य मुचारूपमें तभी चल सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उन्मुक्त हो।

इसके अनिश्चित विविध प्रकारके कच्चे माल सोहा, कोयला, कपास, पटमन इत्यादिका मसारके विविध भागोंमें ही मिलना अथवा उत्पन्न होना सम्भव है। मसारके अन्य भाग जिनको प्रकृति ऐसी वस्तुओंके उत्पन्न करनेकी शक्ति प्रदान नहीं की इन वस्तुओंको अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय द्वाराही प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा उन्हें इस प्रकारकी वस्तुओंसे बचिन रहना पड़ेगा। आधुनिक जीवन तथा रहन सहनके लिए इस प्रकारकी वस्तुओंकी अत्यन्त आवश्यकताको ध्यानमें रखते हुएभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका उन्मुक्त होना कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। श्रमविभाजन के भाभाका उल्लेख हो चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमविभाजन द्वारा समस्त मसारमें वस्तुओंकी उत्पात्तिकी मात्रा बढ़नेसे प्राप्त होनेवाले लाभ तथा उपलब्ध हो सकने हैं जबकि वस्तुओंका अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन वृत्रिम प्रतिबन्धों द्वारा न रोका जाये।

इसके अतिरिक्त यह तो स्पष्ट है ही कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके उन्मुक्त होनेसे किसीभी देशमें किसी अन्य देशसे आनेवाली वस्तुओंके मूल्य उस स्थितिकी तुलना में तो कमही होंगे जबकि उनके आयातपर कर लगादिये जायें। मूल्योंका कम होना उपभोक्ताओंके लिए हितकारी है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी उन्मुक्तताके कारण ऐसे एकाधिकारियोंका जो उप-भोक्ताओंके हितका ध्यान न रखतेहुए केवल अधिकतम लाभ प्राप्त करनेकी धुनमें उन्मुक्त रहतेहैं, स्थापित होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होजाता है।

सरक्षण

आय-कर और सरक्षण

जब वस्तुओंके आयात-निर्मातपर करों द्वारा प्रतिबन्ध लगादिये जातेहैं तो उसे व्यापारके सरक्षणका नाम दियाजाता है। आयात-निर्यात कर दो प्रकारके होते हैं। एक तो राजस्व-कर और दूसरे सरक्षण-कर। राजस्व-कर लगानेसे किसीभी देशका उद्देश्य प्रपन्ना राजकीय कार्य चलानेके लिए अधिक आय प्राप्त करना होता है और सरक्षण-करों द्वारा स्वदेशी उद्योग धन्धोंको विदेशी प्रतिस्पर्धाले सुरक्षित करके प्रोत्साहित करना। ये दोनों उद्देश्य परस्पर विरोधीहैं क्योंकि अधिकतम सरक्षण प्रदान करनेवाले कर वे करहैं जिनके किसी वस्तुके आयातपर लगा देनेसे उस वस्तु का आयात देशमें नितान्त बन्द होजाता है और इसकारण सरकारको तनिकभी आय प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत अधिकतम आय उन करोंसे प्राप्त होगी जिनके किसी वस्तुपर लगानेसे किसी वस्तुके आयातमें तनिकभी नहीं या बहुत थोड़ी कमी आती है।

सरक्षण के लाभ और हानिया

बहुतसे आधुनिक अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार सरक्षण-करोंका लगायाजाना कई अधिक अथवा अन्यायिक कारणोंसे वाञ्छनीय है। कहाजाता है कि किसी देशका किसी वस्तुकी पूर्तिके लिए किसी अन्य देशपर पूर्णरूपसे निर्भर करना उचित नहीं क्योंकि

युद्धके समय ऐसी वस्तुकी पूर्ति बन्द होजाने के कारण उस देशको हानि पहुचनेकी सम्भावना है। इसीप्रकार किसी विशेष व्यवसाय अथवा जन्तु-समुदायको सुरक्षित रखनेके लिए सुरक्षण-करोका समाना आवश्यक समझा जाता है। विशेषकर कृषकों की रक्षा इन बरोद्वारा करनेके लिए बहुतसे नीतिज्ञ अपना मत प्रकट करते हैं।

सुरक्षण-करा द्वारा सुरक्षित उद्योग धन्धोंमें उत्पात्तिकी मात्रा बढनेकी सम्भावना होजाती है। परन्तु यदि उत्पात्तिकी मात्रा बढनेसे वस्तुओंका आयात कम हो जाता है तो अल्प वस्तुओंका निर्यातभी कम होया और यदि किन्हीं विशेष उद्योग धन्धों में उन्नति होनेके कारण उत्पादनके माधनोंकी अधिक आवश्यकता होजाती है तो ये साधन अन्य उद्योग धन्धोंके लिए उपलब्ध नहीं रहने और उन उद्योग धन्धोंमें अवनति से होनेवाली हानि सुरक्षित धन्धोंमें होनेवाले लाभसे अधिक हासकती है।

सुरक्षण-करोकी सहायतामें उत्पन्न वस्तुओंकी गपतके लिए विदेशीके स्थानपर स्वदेशी बाजारकी स्थापना अथवा प्रसारकी सम्भावना है। परन्तु जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, स्वदेशी बाजारके प्रसारके साथ विदेशी बाजारका समुचित होतेजाना भी अनिवार्य है।

सुरक्षित उद्योग धन्धोंमें उन्नति होनेसे उनमें काम करनेवालोंके पास अधिक क्रय-शक्ति आनेके कारण उनके द्वारा उपभोग कीजानेवाली वस्तुओंके उत्पन्न करने वाले उद्योग धन्धोंमें भी उन्नति आने लगती है परन्तु निर्यात कीजानेवाली वस्तुओं को उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्धोंमें अवनति होनेसे उनमें काम करनेवालोंकी क्रय-शक्तिका ह्रास होनेके कारण उनके द्वारा उपभोग कीजानेवाली वस्तुओंको उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्धोंमें भी अवनतिका प्रादुर्भाव सुनिश्चित है। सुरक्षण-करोकी सहायतामें किसी देशमें निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंकी मात्रा उस देशमें आयात कीजानेवाली वस्तुओंकी मात्रासे अधिककी जासकती है। आयात कीजानेवाली वस्तुओंको कमकरना इसलिए अभीष्ट है कि विदेशी कृणोंके परिमाणमें अधिकाधिक वृद्धि न होती चलीजाये। परन्तु वस्तुओंके आयातमें ही केवल कमी करनेसे इस वृद्धिकी रोकना सम्भव नहीं है। सुरक्षण-करोके कारण लोगोंको विदेशोंमें कृण लेनेमें कोई बाधा नहीं आती। जबतक परीक्षा रूपमें आयात होनेवाली वस्तुओंकी मात्रा बढती रहती है तो अत्यक्ष रूपमें आयात होनेवाली वस्तुओंकी मात्रामें कमी करनेसे परिणाम केवल अत्यक्ष रूपमें निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंकी मात्रामें

कमी करना होगा। संरक्षण-करोका लगाना इसलिएभी उचित समझा जाता है क्योंकि अन्य देशोंने इस प्रकारके कर लगा रखे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कोईभी देश संरक्षण-कर लगाकर न केवल अपनीही अपितु अन्य देशोंकी भी हानि करता है। परन्तु इसका प्रतिकार यह नहीं है कि अन्य देशभी उसी प्रकारका कर लगाकर अपनी तथा उस देशकी औरभी अधिक हानि करनेका अपराध करें।

कई लोगोंका ऐसा विश्वास है कि संरक्षण-करो द्वारा देशीय श्रमजीवियोंको मिलनेवाले वेतनोंको अन्य देशोंमें इस वर्गको मिलनेवाले वेतनसे अधिक रखा जा सकता है। परन्तु दो देशोंमें श्रमजीवियोंको मिलनेवाले वेतनोंमें अन्तरको दूसरे देशके श्रमजीवियोंको अपने देशमें आनेसे प्रतिबन्ध द्वारा रोककरभी नदब स्थित रखा जा सकता है। संरक्षण-करोको विभिन्न देशोंमें विभिन्न वस्तुओंके उत्पादन-व्यय सम करनेके लिए प्रयुक्त करनाभी उचित समझा जाता है परन्तु यदि सारे मसालोंमें उत्पादन व्यय एकसे होजायेंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जो इनमें अन्तरके आधारपर ही होता है, जडसे मिटजायेगा। इसके प्रतिरिक्त अधिकतम उत्पादन व्ययवाले उद्योग धंधोंको अधिकतम संरक्षणकी आवश्यकता होगी। अर्थात् उत्पादन के साधनोंका कुशलतम प्रयोग करनेकी चेष्टा करना निर्वर्ण्य होजायेगा।

संरक्षण-करोके प्रभाव दो प्रकारके होते हैं। एक ओर तो उपभोक्ताओंको मूल्य में वृद्धि होनेके कारण हानि सहन करनीपड़ती है और दूसरी ओर उत्पत्तिमें वृद्धि होनेसे उनकी वास्तविक आयमें वृद्धि होती है। यदि उत्पत्तिकी मात्रामें महत्तम वृद्धि के सापेक्ष मूल्योंमें लघुतम वृद्धि हो तो संरक्षण-कर देशके लिए हितकारीही होगा और यदि मूल्योंमें महत्तम वृद्धिके साथ उत्पत्तिमें लघुतम वृद्धि हो तो संरक्षण-कर उस देशके लिए हानिकारक होगा। जहांतक मूल्योंमें वृद्धि होनेके कारण उपभोक्ताओंकी हानिका सम्बन्ध है, इसमें तो सनिकमी सन्देह नहीं कि उन्हें हानि होती है और इस हानिको निश्चित रूपसे आकाश जासकता है परन्तु सुरक्षित उद्योग धंधोंमें उत्पत्तिकी मात्राकी वृद्धिको वृद्धि मानलेना उचित नहीं। इस वृद्धि में से अन्य उद्योग धंधोंकी उत्पत्तिमें संरक्षण-करोके कारण जो कमी हुई है, उसका निकासनाभी आवश्यक है। ऐसा करनेपर प्रतीत होगा कि संरक्षण-करोके कारण लाभकी अपेक्षा हानि अधिक होनेकी सम्भावना है।

संरक्षण-करोका लगायाजाना किसी विशेष उद्योग धंधेमें वर्तमान बेकारीकी

समस्याको सुलझानेके लिए अत्यन्त लाभकारी बताया जाता है। व्यापारकी उन्मुक्तता के पक्षपातीभी यह माननेके लिए तैयार हैं कि किसी विशेष उद्योग धन्धेका संरक्षण करो द्वारा पुनरुत्थान किया जासकता है क्योंकि संरक्षणकी सहायतासे उत्पात्तिकी मात्रामें वृद्धि होना अनिवार्य है। परन्तु यदि संरक्षण करो द्वारा किसी विशेष उद्योग धन्धेकी बंकारी तो दूर होजाये और अन्य उद्योग धन्धोंमें बंकारी बढजाये तो बर लगाना विफलमा रहैगा क्योंकि उनके लगानेसे हमारा उद्देश्य कुल बंकारी को दूर करताया न कि उस विशेष उद्योग धन्धेकी बंकारीही का। ऐसामी असम्भव नहीं कि निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंको उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्धों में काम करनेवाले लोगोंकी सरखा उन लोगोंसे अधिकहो जिनको सुरक्षित उद्योग धन्धोंमें नया काम मिला है। ऐसी स्थितिमें तो संरक्षण-कर स्पष्टतया हानिकारक है।

अन्तमें आर्थिक तथा भौद्योगिक दृष्टिसे निम्नोक्त देशोंमें उद्योग धन्धोंको स्थापित करनेके लिए संरक्षण-करोंका प्रयोग आवश्यक माना जाता है विशेषकर ऐसे उद्योग धन्धोंका उनके जीवनकालमें तो संरक्षण होना ही चाहिए, कारणकि ससारके बहुतसे देशोंकी भौद्योगिक उन्नति केवल इस वानपर निर्भर है कि उन्होंने उद्योग-धन्धे स्थापित करनेका कार्य सर्वप्रथम आरम्भ कर लिया था और इसकारण उत्पादन-कार्यमें अन्य देशोंमें शक्ति कुशलता प्राप्त करली है। ऐसामी होसकता है कि अन्य देशोंके पास उन्ही वस्तुओंका उत्पन्न करनेके लिए अधिक साधनहो परन्तु उन साधनोंका यदपि प्रयोग इनलिग्न होपाता हो क्याकि उन साधनोंके प्रयोगके लिए स्थापित उद्योग धन्धों द्वारा उत्पन्न कीहुई वस्तुआपर आरम्भमें पुराने चिरकालसे स्थापित उद्योग धन्धों द्वारा उत्पन्न कीहुई विदेशी वस्तुओंसे अधिक उत्पादन व्यय पडता है। इसकारण उन्मुक्त व्यापारके होनसे ऐसे उद्योग धन्धोंको स्थापित करना असम्भव होजाता है। ऐसे उद्योग धन्धोंको विदेशी प्रतिस्पर्धाले कुछ फालक लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य समझा जाता है। इस दशामें भी संरक्षण केवल ऐसे उद्योग-धन्धोंको ही देना चाहिए जो प्रौढ अवस्था प्राप्त करनेपर अपने पैरोपर खड़े होनेकी क्षमता प्राप्त करलेंगे। ऐसा कहाजाता है कि एकबार संरक्षण प्रदान करनेपर ये शिशु उद्योग धन्धे कभीभी प्रौढ नहीं होपाने। इनका जीवनकाल बढताही चलाजाता है और एकबार लगाए संरक्षण-करोंका राजनीतिक तथा अन्य कारणोंसे हटाना कठिन होजाता है। अस्थायी रूपमें नियुक्त कियेगये संरक्षण-करोंका स्थायी रूपमें परि-

वर्तित करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यदि उद्योग धन्धोंकी कुछ सस्थाएं संरक्षण करोंका आश्रय लिए बिनाही जीवित रहनेकी क्षमता प्राप्त कर लेती हैं तो बहुतसी ऐसी मस्याएँ भी संरक्षणके कारण स्थापित हो जाती हैं जिनके संरक्षणके हटानेही नष्ट हो जानेकी सम्भावना है। इसकारण उनके व्यवस्थापक संरक्षणके हटानेका सदैव विरोध करते हैं। संरक्षण-रुकोके विरुद्ध इन युक्तियोंमें भलेही सत्य ही और सत्य है भी परन्तु पिछड़े हुए देशोंकी औद्योगिक उन्नति भी तब तक सम्भव नहीं जब तक उनमें स्थापित उद्योग धन्धोंकी शैशव अवस्थामें भलीप्रकार रक्षा न की जाये। इसकारण औद्योगिक दृष्टिसे उन्नत देशोंमें उन्मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का होना भलेही आवश्यक हो परन्तु कम उन्नत देशोंकी उस समय तक संरक्षण करों की गरण लेनीही पड़ेगी जब तक वे भी औद्योगिक दृष्टिसे उन्नत नहीं हो जाते जिसनेकि उनके प्रतिस्पर्धी अन्य देश।

संरक्षण और डम्पिंग

संरक्षणके विरुद्ध अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंके अनुसार इनकी कड़ी प्रालोचना की जाने पर भी आधुनिक ससारमें कोई विरलाही देश ऐसा होगा जिसने संरक्षणकी नीतिको न अपनाया हो। इस नीतिके धपनानेसे एक प्राथिक घटनाका प्रादुर्भाव हुआ है जिसने संरक्षणकी नीतिको और भी परिपुष्ट होनेमें सहायता दी है। इस घटनाको 'ट्रेजरी' में डम्पिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा कई प्रकारसे की जाती है। जबकि किसी सुरक्षित उद्योग धन्धेमें उत्पत्तिकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसकी खपत देशमें नहीं हो पानी तो बाह्य मात्राको बेचनेके लिए उत्पादक लोग उस वस्तुको विदेशी बाजारों में उस मूल्यपर बेचना स्वीकार करनेते हैं जो भाड़ा इत्यादिकी गणना कर लेनेके बाद भी देशमें उसी वस्तुके प्रचलित मूल्यसे कम होता है। डम्पिंगकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार की गयी है कि विदेशी बाजारों में उस वस्तुको उसके उत्पादन-व्यय से भी कम मूल्यपर बेचा जाता है और इन मूल्यपर बेचनेसे होनेवाली हानिको स्वदेशी बाजारों में अधिक मूल्यपर बेचनेसे होनेवाले लाभ द्वारा पूरा किया जाता है। डम्पिंग, संरक्षण-नीतिकी पुष्टि दो प्रकारसे करता है। एक जिस देशमें वस्तुओंका इस प्रकार निर्यात किया जाता है उस देशके उत्पादक अपने उद्योग धन्धोंकी इस अनु-

चित प्रतिस्पर्धाले रक्षा प्राप्त करनेके लिए सरक्षण-करोका लगायाजाना आवश्यक समझते हैं। दूसरे निर्यात करनेवाला देशभी इस मयसे कि विदेशी बाजारमें सस्ते मूल्यपर बिकी हुई वस्तु दुबारा स्वदेशमें न लौट आये, उस वस्तुके आयातपर सरक्षण-कर लगा देते हैं।

इस सम्बन्धमें इतना कह देना आवश्यक न होगा कि डम्पिंगकी नीतिका अनुसरण उससमय तक नहीं किया जा सकता जबतक स्वदेशमें उस वस्तुके उत्पादकोंको उसके उत्पादनकी एकाधिकार प्राप्त न हो क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें सब मूल्य माग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होंगे और इसकारण उत्पादक स्वदेशमें वस्तुका मनमाना मूल्य लेनेमें असमर्थ रहेंगे। एकाधिकार केवल उसीसमय प्राप्त नहीं होता जबकि उस वस्तुको उत्पादन करनेवाला एकही उत्पादक हो। ऐसाभी होसकता है कि बहुतसे उत्पादक मिलकर उस वस्तुको निश्चित मूल्यसे कम मूल्यपर न बेचने का समनुबन्ध कर लें अथवा उस वस्तुको निश्चित मात्रासे अधिक उत्पत्ति करनेपर प्रतिबन्ध लगा लें।

निर्यात और आर्थिक सहायता

कभी कभी कई देशोंकी सरकारें अपने देशकी औद्योगिक उन्नतिके हित वस्तुओंके निर्यातपर आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इसके कारण उत्पत्ति तथा निर्यात की मात्रामें वृद्धि होती है। अधिक निर्यातके कारण विदेशी बाजारमें वस्तुका मूल्य कम होजाता है और देशी बाजारमें बढ़जाता है। इस प्रकारकी आर्थिक सहायता और सरक्षण-करो द्वारा दीगयी सहायतामें कोई विशेष अन्तर नहीं। उन के सब गुण और दोष इस प्रकारकी सहायतामें भी विद्यमान हैं।

अन्तमें हमें यहभी उल्लेख कर देना चाहिए कि डम्पिंग अथवा निर्यातके लिए दीगयी आर्थिक सहायताके प्रतिकारके रूपमें सरक्षण-करोका लगाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं क्योंकि साधारणतया इन करोंद्वारा आयात होनेवाली वस्तुओंका रोकना सम्भव नहीं जबतक कि करोंके परिमाण ही अत्यन्त अधिक न कर दिये जायें। परन्तु प्रत्येक स्थितिमें सरक्षण-करो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजनको घटका लगानेकी सम्भावना है जिसके कारण वस्तुओंकी उत्पत्तिकी मात्रामें कमी होनेसे प्रत्येक

देशकी हानि होना निश्चित है। सम्भव है कि किसी विशेष स्थितिका मुलभाव सरक्षण-करो द्वारा होमकता हो परन्तु कौन जानता है कि इनके दुरुपयोगके कारण न्यामके स्थानपर हानि हो।

व्यापारिक समनुबन्ध

अर्थशास्त्रकी परिभाषामें व्यापारिक समनुबन्धसे हमारा अभिप्राय उन समनुबन्धोंसे है जो आयात-निर्यात-करोंमें सम्बन्ध रखते हो। इस प्रकारके समनुबन्धोंमें केवल दो अथवा दो में अधिक देश अपने आपको समनुबद्ध करसकते हैं। इस प्रकारके समनुबन्धोंमें एक धारा प्रायः ऐसी पायी जाती है जिसके द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि दोनों देश परस्पर एक दूसरेमें कैसा व्यवहार करेंगे। विशेषकर तीन प्रकार की धाराएँ इस व्यवहारको सुनिश्चित करनेके लिए काममें लायी जाती हैं। समता की धाराके अनुसार यह निश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक देश दूसरे देशके निवासियों और वस्तुओंसे उसी प्रकारका व्यवहार करेंगे जो वे अपने देशके निवासियों और वस्तुओंसे करते हैं। 'जैसी लेनी वैसी देनी' की धाराके अनुसार यह निश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक देश दूसरे देशके निवासियों और वस्तुओंसे उसी प्रकारका व्यवहार करेगा जैसा कि दूसरा देश पहिले देशके निवासियों और वस्तुओंसे करता है। श्रेष्ठतम व्यवहार किये जानेवाने राष्ट्रकी धाराके अनुसार समनुबद्ध देश परस्पर उससे बुरा व्यवहार नहीं करसकते जो वे किसी अन्य देशसे कर रहे हैं।

साम्राजिक वरीयता से हमारा अभिप्राय उन व्यापारिक समनुबन्धोंमें है जो ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशोंको परस्पर समनुबद्ध करते थे। इन समनुबन्धों द्वारा साम्राज्यके भीतरही उत्पन्न कीगयी वस्तुओंके आयातपर साम्राज्यके बाहरसे आनेवाली वस्तुओंसे कम कर लगाया जाता था। ओटावा में कीगयी १९३२ की भारी साम्राज्य-सभामें इस प्रकारके साम्राज्यीय पक्षपात दिखानेकी प्रथाको भलीप्रकार पुष्ट किया गया था। इसी सभामें भाग लेकर भारतने साम्राज्यीय पक्षपातको सिद्धान्त-को स्वीकार किया था।

आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्ष

आर्थिक प्रगति

पहिले अध्यायमें हमने बताया था कि हमारे सभी प्रकारके आर्थिक कार्योंका चरम लक्ष्य समाजके आर्थिक क्षेत्रमें वृद्धि करना है। प्रत्येक मनुष्य, कुटुम्ब अथवा समाज इस बातके लिए प्रयत्नशील रहता है कि वह अपने साधनोंकी वृद्धि करे और उन साधनोंका इस प्रकारसे उपयोग करे कि उसको न्यूनतम लागत-व्ययसे अधिकतम वस्तुएं प्राप्त हो सकें। आर्थिक क्षेत्रमें वृद्धि प्राप्त करनेके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक साधनोंकी पूर्ण-नियुक्ति बनी रहे और इस पूर्ण-नियुक्तिके फलस्वरूप जिन वस्तुओं और सेवाओंकी उत्पत्ति होती है, उनका समुचित वितरण हो।

आर्थिक दृष्टिकोणसे हम उस देशको प्रगतिशील कहते हैं जिसमें जन-संख्याके साथ साथ उत्पत्तिके परिमाणमें वृद्धि होती हो; उत्पत्तिकी क्रिया इसप्रकार की हो कि किसी दिग्गम्य परिमाणकी वस्तुओंकी बनानमें उत्पादन-व्ययकी मात्रा कम होती रहे अथवा दिग्गम्य साधनोंसे उत्पत्तिके परिमाणमें वृद्धि होती रहे; वस्तुओं और सेवाओंका स्वरूप उत्कृष्ट होता रहे; जीवन-स्तरमें वृद्धि होती रहे और लोगोंको भौतिक सुख और क्षम प्राप्त करनेके लिए स्वास्थ्य और अवकाश मिलता रहे।

सन् १५० वर्षोंके आर्थिक इतिहाससे पता चलता है कि इस कालावधिमें अनेक पारिवात्य देशोंमें आर्थिक प्रगति बहुत वेगपूर्वक हुई है। इस प्रगतिका सूत्रपात अठारहवीं शताब्दीके दूसरे भागमें इंग्लैंडकी औद्योगिक क्रान्तिसे हुआ। प्रगतिका मुख्य कारण शिल्प कला विज्ञानकी उन्नति है। इस कालमें बहुतसे नये नये आविष्कार हुए। मशीन, वाष्प-शक्ति और विद्युत्-शक्तिके प्रयोगसे उत्पादन-क्रियामें बहुत वृद्धि हुई। श्रम-विभाग और विशिष्टीकरणको प्रोत्साहन मिला। सड़कें, नहरें, मोटर, रेल, जहाज इत्यादि यातायातके साधनोंमें भी वृद्धि हुई। साख और बेकके

प्रयोगसे और मिश्रित पूजीवादी कम्पनियोंके स्थापनसे उत्पत्ति और व्यापार प्रोत्साहित हुए। सबसे बड़ी बात यह हुई कि पूजीके संचय और उसके लगावमें बहुत वृद्धि हुई। बिना पूजीकी वृद्धिके आर्थिक प्रगति असम्भव है। भेषज्य और शल्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विद्याकी वृद्धिसे रोग और मृत्यु सख्यामें कमी हुई और आयुमान में वृद्धि हुई।

आर्थिक प्रगति ससारके सभी देशोंमें समान रूपसे नहीं हुई। अनेक देश अभी तक बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां जीवन स्तर बहुत नीचा है। मुख्य धंधा खेती है जो कि पुराने ढंगपर ही कीजानी है। बचत और पूजीका लगाव बहुतही कम परिमाणमें है। औद्योगिक कला विज्ञान पिछड़ा हुआ है। जापान को छोड़कर एशियाके सभी देशोंको स्थिति इसीप्रकार की है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिकामें भी इनप्रकार के अनेक देश हैं। परंतु शनैः शनैः इन सभी दशाका कम या अधिक मात्रामें उद्योगीकरण हो रहा है और प्रगतिशील दशाके आविष्कारोंसे लाभ उठानकी प्रवृत्ति हो रही है। इसके प्रतिकूल कुछ देशोंमें जहां पिछले सौ दशकों वषार बड़े वेगसे साथ और बड़ी मात्रामें उद्योगीकरण का विकास और विस्तार हुआ, कुछ शिथिलताके आभास का अनुमान किया जाता है। कुछ लोगोंका विचार है कि इन देशोंमें आर्थिक विकास चरमवर्धामें पहुँच चुका है। जन सख्याकी वृद्धि रुक गयी है। रेल जहाज विजली के सामानके आविष्कारोंकी सम्भावना कम है। पिछड़े हुए देशोंमें उद्योगीकरण के कारण मशीनसे बनी हुई वस्तुओंके निर्यात व्यापारमें भी कमाई आनकी सम्भावना है। इन सभी कारणोंसे कुछ अर्थशास्त्री इस परिणामपर पहुँचे हैं कि समुक्त राज्य जैसे देशोंमें अब आर्थिक प्रगतिमें मन्दी आनकी आशंका है। इस प्रकरणमें हम इस विचारपूर्ण विषयका विवेचन नहीं कर रहे कि क्या वास्तवमें कुछ देशोंमें इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी है कि वहां वर्तमान परिमाणका पूर्णरूपसे पूजीके रूपमें लगानकी सम्भावना नहीं रह गयी है। हमारा अभिप्राय केवल इतनाही बतलाना है कि कुछ पाश्चात्य देशोंमें आर्थिक प्रगति बड़े वेगसे हुई है।

आर्थिक चक्र

परन्तु इस प्रकारकी आर्थिक प्रगति अविरत तथा अविरोध रूपसे नहीं हुई है। समय

समयपर इसमें व्याघात हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कानूनन आर्थिक विकासमें वृद्धि होतीजाती है। पूँजीके लगावमें वृद्धि होतीहै, आयमें, उत्पत्ति और नियोगकी मात्रामें भी वृद्धि होती रहती है। परन्तु सहसा इस क्रममें कुछ विघ्न उत्पन्न होजाने है। आर्थिक अवयवोंमें कुछ ऐसी विकृतिया उत्पन्न होजाती हैं कि उत्पादक वर्गको पूँजीके लगावकी मात्रा कम करनी पड़ जातीहै जिसके फलस्वरूप उत्पत्तिके साधनमें बेकारी फैलने लगतीहै; आय और उत्पत्तिके परिमाणमें कमी आने लगतीहै और आर्थिक कार्य-स्तरमें शिथिलता आजाती है। कुछ कालके बाद शान्ति शान्ति पुनः परिस्थिति बदलती है। पूँजीके लगावके कार्यको फिरसे प्रोत्साहन मिलताहै और उत्पत्तिके साधनकी मात्रा और उनकी आयमें वृद्धि होने लगती है। इसप्रकार से आर्थिक उत्कर्ष होने लगता है। परन्तु दुर्भाग्यवश इस उत्कर्षके अन्तर्गत कुछ दमप्रकार की विषमताएँ उत्पन्न होजाती हैं कि उत्कर्षका अन्त होजाता है और फिर अपकर्षका समावेश होजाता है। इसप्रकार हम देखतेहैं कि आर्थिक प्रगतिके उत्कर्षके बाद अपकर्ष और अपकर्षके बाद उत्कर्ष और पुनः अपकर्ष लहरोके सदृश आते जाते रहते हैं। इस लहरके समान ऊपर नीचे उठने और गिरनेकी आर्थिक गति को हम आर्थिक चक्र कहेंगे। गत २०० वर्षोंकी आर्थिक प्रगतिके इसप्रकार के आर्थिक चक्र विशेषकर अधिक औद्योगिक देशोंमें स्पष्ट रूपसे अनुभव हुए हैं। हमारे कहने का प्रयोजन यह नहीहै कि २०० वर्ष पूर्वकी आर्थिक पद्धतिके किसी प्रकारके सकट नहीं आये अथवा कम औद्योगिक देशोंमें आर्थिक सकट कम मात्रामें आते हैं। प्राचीन कालके आर्थिक सबट आधुनिक आर्थिक सकटाने भिन्न प्रकारके थे और उनके कारण सुबोध होतेथे। भूकम्प, बाढ़, दुर्भिक्ष, युद्ध इत्यादि कारणोंसे ही प्राचीन कालके आर्थिक सकट सम्बन्धित हैं। ये कारण स्पष्ट प्रतीत होजाते हैं। हमारे शास्त्रोंने छे प्रकारके सकटोंका वर्णन किया है।

अति वृष्टिर्नावृष्टः मूयका शलभाः शुकाः ।

प्रत्यासन्नश्च राजानः पडेतारीतयः स्मृताः ॥

अर्थात् बहुत वर्षा जिसके कारण बाढ़ आजाती है; वर्षाका बिलकुल न होना अर्थात् सूखा पडना जिससे दुर्भिक्ष होजाता है; टिड्डीदल, तोते जो कि फसल पेड़ पौधोंको हानि पहुँचातेहैं और राजाओंका निरुद्ध होना जिससे युद्धकी आशंका रहतीहै ये छे सकट बताये गये हैं।

परन्तु आधुनिक कालके आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षके कारण बाहरसे नहीं परन्तु आर्थिक प्रगतिके अन्तर्गतही उत्पन्न होते रहते हैं। आर्थिक अवयवोंके सम्बन्धोंमें स्वयमेव कुछ इसप्रकार की विषमता वा प्रादुर्भाव होजाता है जिससे कि आर्थिक अस्थिरता कभी उत्कर्ष और कभी अपकर्ष बनी रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूँजीवादी आर्थिक पद्धति, जिसका चलन लाभकी आशापर केन्द्रित रहता है, के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होजाती हैं कि आर्थिक सञ्चय अनिवार्यसा होजाता है। १९२९-१९३३ का विश्वव्यापी सकट इतना उग्र हुआ कि अर्थशास्त्रियोंका ध्यान विशेष रूपसे इसके विश्लेषणकी ओर आकृष्ट हुआ। गत १५-२० वर्षोंमें इस विषयपर बहुत खोजपूर्ण कार्य हुआ है।

वैसेतो आर्थिक प्रगतिमें छोटी बड़ी अनेक प्रकारकी लहरें पायी गयी हैं परन्तु जिन लहरोंको अधिक महत्व प्राप्त है उनकी अवधि ७ वर्षसे ११ वर्षतक है अर्थात् इस अवधिके भीतर एक आर्थिक चक्र पूरा होजाता है। आर्थिक चक्रका एक प्रति-रूप नीचे दिया जाता है



क स्थानसे ग स्थान तक पहुँचनेपर एक आर्थिक चक्र पूरा होता है।

आर्थिक चक्रको चार भागोंमें विभक्त किया जाता है :

- (१) उत्थान
- (२) उत्कर्ष
- (३) अपकर्ष
- (४) गत

आर्थिक चक्र गतसे निकलकर उत्थानके पथपर आरम्भ होता है। उत्थानमें प्रगति उत्पन्न होन लगती है और आर्थिक क्रियाओंमें उत्कर्ष व्याप्त होजाता है।

कुछ समयके बाद उत्कर्षका अन्त होजाता है और अपकर्ष आरम्भ होजाता है जोकि बढ़ते बढ़ते आर्थिक व्यवस्थाको गर्तमें पटक देता है। फिर धीरे धीरे आर्थिक चक्र गतिमें निवलकर उत्थानकी ओर अग्रसर होताहै और फिर पूर्ववत् वही क्रम चलता रहता है। अतएव इस विषयके विवेचनमें इसी समस्याका समाधान करना पड़ता है कि क्या कारणहै कि आर्थिक क्रियाएँ क्रमशः इन चारों परिस्थितियों में चक्कर लगाती हुई अग्रसर होती हैं।

आर्थिक अवस्थामें इसप्रकार का परिवर्तन अनेक अवयवोंमें दृष्टिगोचर होता है। इस विषयसे सम्बन्धित, उत्पत्ति, आय और नियोग, मुख्य तीन अवयव हैं जिनके आकड़ोंसे भी चक्रवत् परिवर्तन का बोध होता है उत्कर्ष कालमें आर्थिक साधनोंकी अधिक काम मिलताहै अतएव नियोगके परिमाणमें वृद्धि होती है। उत्पत्तिके परिमाण में भी वृद्धि होतीहै और आयभी बढ़ती है। ये तीनों अवयव एक दूसरेसे सलग्न हैं। कुछ अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार नियोगके आकड़ासे आर्थिक अवस्थाका निरूपण ठीक प्रकारसे होसकता है। अपकर्षकी अवस्थामें आर्थिक साधनोंमें बेकारी आरम्भ होनेलगती है और गर्तकी अवस्थामें बेकारी चरम सीमापर पहुँचजाती है।

बेकारी

इस प्रकरणमें हम बेकारीके विषयमें पाठका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करना चाहते हैं विशेषकर श्रमजीवियोंकी उम्र बेकारीकी ओर जिसका परिमाण १९२६-१९३३ के आर्थिक मंदकालमें मण्डल राज्य, इंग्लैंड इत्यादि औद्योगिक देशोंमें बहुत बढ़गया था। वैसातो बेकारी अनेक कारणोंसे उत्पन्न होजाती है। यहापर हम यहाँ लिखदेना चाहतेहैं कि बच्चे, बूढ़े, अपाहिज और जो उद्यम करनाही न चाहते हों इसप्रकार के लोगोंके सम्बन्धमें बेकारीका प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। वे लोग बेकार सभसे जातेहैं जो उद्यम करनेको उद्यतहैं परन्तु उनको कामही न मिलरहा हो।

कुछ इस प्रकारके उद्योग घन्चे होतेहैं जिनको 'मौसमी' कहा जासकता है। उदाहरणके लिए भारतवर्षमें चीनीके कारखानोंमें काम करनेवाले श्रमजीवियोंको साधारणतः नवम्बरसे मईके महीनेतक काम रहता है। उसके बाद वे बेकार हो

जाते हैं। परन्तु इस प्रकारकी बेकारीका पूर्व ज्ञान रहता है अतएव इसका प्रबन्ध किया जा सकता है। फँसन और रुचिमें परिवर्तन होनेसे भी कुछ व्यवसायोंमें अवनति होजाती है और बेकारी आजाती है। परन्तु आशाकी जाती है कि नये उद्योग-धन्धोंमें काम बढ़ जानेसे कुल बेकारीमें वृद्धि नहीं होगी। इसीप्रकार श्रम-निवारक मशीनोंके प्रयोगसे और उद्योग धन्धोंके वंजनीकरणसे भी बेकारी होजाती है। इस सम्बन्धमें भी यह आशा कीजाती है कि यह बेकारी दीर्घकालिक नहीं होगी। पहिले जिन उद्योग धन्धोंमें मशीनोंका प्रयोग हुआ हो अथवा वंजनीकरण हुआ हो उनमें उत्पादक-धन्यमें कमी होनेके कारण मूल्यमें भी कमी आनेकी प्रवृत्ति होगी और इसके फलस्वरूप मागमें वृद्धि होनेसे उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होगी जिससे अधिक श्रमजीवियोंकी भी नियुक्ति होगी। यदि इन वस्तुओंकी मागमें पर्याप्त वृद्धि न भी हो तुबभी मूल्यमें कमीके कारण उपभोक्ताओंको जो बचत होगी उसको वे वस्तुओंमें व्यय करेंगे जिससे उन उद्योग धन्धोंमें वृद्धि होगी और श्रमजीवियों कोभी काम मिलेगा। इसप्रकार बेकारी की मात्रामें कमी होजायगी। इन कारणों के अतिरिक्त श्रमजीवियोंके हड़ताल करने और मित-मालिकोंके द्वारतालसे भी अल्पकालिक बेकारी उत्पन्न होजाती है।

पूर्वोक्त कारणोंसे जो बेकारी उत्पन्न होजाती है उसकी तुलनामें आर्थिक अपकर्ष और गरसे जनित बेकारी वही अधिक भीषण समझी जाती है इसका कारण यह है कि इसप्रकार की बेकारीका परिमाण बहुत अधिक रहता है। मधुकन राज्यमें १९२९-१९३३ के अपकर्ष कालमें लगभग २५ प्रतिशत श्रमजीवी बेकार होगये थे। यह बेकारी पूँजीवादसे मलग्न आर्थिक-चक्रका परिणामस्वरूप है। अतएव इसको दूर करनेकी समस्याभी बहुत कठिन है। जिन उपायोंसे आर्थिक अपकर्षकी गरिमा को घटाया जासकेगा और आर्थिक क्रियाओंके स्तरको सन्तुलित रूपसे उठाया जायगा उन्ही उपायोंसे इसप्रकार की बेकारी भी कमकी जासकेगी।

हमने बताया कि आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षके सम्बन्धमें उत्पत्ति, आय और नियोंके आकड़ोंका प्रयोग कियाजाता है। इन प्रधान आर्थिक अवयवोंके अतिरिक्त औरभी अवयव हैं जो उत्कर्ष और अपकर्षके साथ प्रभावित होते रहते हैं और इनके आकड़ेभी इस विषयपर प्रकाश डालते हैं। इनमें मुख्य द्रव्यका विशेषकर साख-द्रव्यका परिमाण, मूल्य-स्तर, व्याजकी दर और लाभकी दर हैं।

आर्थिक चक्र के सिद्धान्त

आर्थिक चक्र एक गहन और गूढ़ विषय है। इसके अन्तर्गत सभी आर्थिक प्रवृत्तियों के परिमाण और सम्बन्धों पर परिवर्तन होना रहता है। अतएव इसका कोई एक ही कारण नहीं होसकता है। जिन अर्थशास्त्रियों ने इस विषयकी व्यवस्था की है वह सभी इस विचारसे सहमत हैं कि आर्थिक उत्थान और अपकर्षको किसी एक वस्तु-स्वार्थ द्वारा समझाया नहीं जासकता है। इसका सूत्र अनेक कारणोंसे सम्बन्धित है जिनमेंसे कुछ आर्थिक हैं कुछ क्रियाशील हैं और कुछ भित्तिरूप, कुछ नियन्त्रण-साध्य हैं और कुछ नियन्त्रणमें नहीं लाये जासकते हैं। अतएव यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आर्थिक चक्रको समझनेके लिए अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। इन सिद्धान्तोंके अनुयायी अपने अपने दृष्टिकोणको अधिक महत्व देते हैं। अपने प्रतिपादित कारणोंको प्रधान और अन्य कारणोंको गौण समझते हैं। इस पुस्तकमें हम इन भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंकी विस्तृत विवेचना करनेमें असमर्थ हैं। केवल मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंकी मूल बातोंका पाठकाके सामने रखनेका प्रयत्न किया गया है।

कृषि-सिद्धान्त

आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षको समझनेके लिए एक पुराना मत खेतोंकी उत्पत्तिके परिमाणसे सम्बन्धित है। कहा जाता है कि जब उद्योग धन्धोंका आधार खेतोंसे उत्पन्न हुआ सत्य और कच्चा माल है। अतएव जब खेतोंसे होनेवाली उत्पत्तिमें वृद्धि होती है तो इससे आर्थिक उत्कर्ष होता है और जब खेतोंकी उत्पत्तिमें कमी आजाती है तो आर्थिक अपकर्ष प्रारम्भ होता है। खेतीकी उत्पत्तिके परिमाणमें परिवर्तन होनेका मुख्य कारण वृष्टिके परिमाणमें परिवर्तन होना है। इसलिये प्रोफेसर बेन्स का कहना है कि सूर्यके तापमें परिवर्तन होना है और यह चक्र १०-११ वर्षमें पूरा होता है अर्थात् १०-११ वर्षकी अवधिके अन्तर्गत सूर्यके तापकी तीव्रता और मन्दोके काल क्रमसे आते रहते हैं। आर्थिक-चक्रकी ओसत अवधिभी इसी परिमाणकी समझी जाती है। सूर्यके तापका प्रभाव वृष्टिके परिमाणपर पड़ता है।

जब सूर्यके तापमें प्रसरता रहनी है तो प्रचुर मात्रामें वृष्टि होती है और शस्योकी वृद्धि होती है। सूर्यके तापमें मन्दी आनेपर वृष्टि कम होती है और खेतोकी पैदावार भी घट जाती है। अमेरिकाके प्रोफेसर मूर ने भी मौसमके प्रभावसे खेती और खेतीके प्रभावसे आर्थिक चक्रको समझानेका प्रयत्न किया है।

खेतीका आर्थिक परिस्थितिमें विशिष्ट स्थान है, यह मानना पड़ता है। परन्तु जब हम आधुनिक आर्थिक विकासको ध्यानमें रखने हुए सयुक्त राज्य, इंग्लैंड इत्यादि औद्योगिक देशोंके उत्कर्ष और अपकर्षके कालकी आर्थिक परिस्थितिकी छानबीन करते हैं तो हमको खेतीकी उपजमें परिवर्तनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दिखायी देता है। एक बात तो यह है कि जिस प्रकारका स्पष्ट आर्थिक चक्र अन्य उद्योग धन्धोंमें पाया जाता है, उसप्रकार का खेतीकी उपजमें नहीं पाया जाता है। हमके अतिरिक्त औद्योगिक देशोंमें जहाँ आर्थिक चक्रमें अधिक तीव्रता देखीगयी है वहाँ कृषिका महत्त्व घटता जा रहा है। उदाहरणके लिए सयुक्त राज्यमें कृषिकी उपज कुल उपजका केवल दसवा भाग है। इसके साथ साथ सिंचाईके साधनोंकी वृद्धिके कारण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी वृद्धिके कारण और शस्योको सुरक्षित रखने के प्रबन्धमें उन्नतिके कारणभी आधुनिक कालमें कृषिकी उपजमें अधिक परिवर्तन नहीं होने पाता है।

वास्तवमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब अन्य उद्योग धन्धोंमें समृद्धि रहती है तो कृषिकी उपजकी मागकी वृद्धिसे इस व्यवसायमें भी समृद्धि आनेकी प्रवृत्ति होती है और जब अन्य उद्योग धन्धोंमें गिरावट आजाती है तो कृषिकी उपजकी मागके घट जानेसे इस व्यवसायमें भी मन्दी आनेकी आशंका रहती है। यदि कृषिकी उपज में वृद्धि ऐसे कालमें हुई हो जबकि अन्य उद्योग धन्धोंमें अवसाद छाया हुआ हो तो इस वृद्धिसे कृषिकी उपजका मूल्य-स्तर और भी नीचे गिरने लगता है। अतएव हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि कृषिकी उपजके परिमाणमें परिवर्तनका प्रभाव अन्य आर्थिक क्षेत्रोंकी परिस्थितिपर निर्भर करता है।

मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त

कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षके सम्बन्धमें मनोवैज्ञानिक कारणोंको

अग्निर मट्ट वदेते है। इनका अभिप्राय यह नहीं है कि मनोवैज्ञानिक कारण स्वतन्त्र कारण है परन्तु इनका कहना है कि इन कारणोंको ज्ञाना मट्ट व नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए।

आर्थिक क्षेत्रमें मनोवैज्ञानिक परिस्थितियोंका समावेश आशा, निराशा, आकांक्षा इत्यादि चिरम्बायी उपकरणोंमें लगाने और उनमें प्राप्त होनेवाली आयके धोखा समयका अधिक मात्रामें अनन्तर जाना है। इस कारण आर्थिक क्षेत्रोंमें अनिश्चितता और भयानकता समावेश होगया है। इनका परिणाम यह होता है कि इन कारणोंमें दृष्टिगोचर क्षमताकी क्रिया और प्रतिक्रियामें स्थिरता नहीं रहती है जितनी अन्य प्रकारके आर्थिक कारणों में। कभी कभी उत्पादकतामें आवश्यकताओंमें अधिक आकांक्षा होती है उठता है और नीचे गिर जाता है। उत्कर्षका सम्बन्ध आशा और अपकर्षका निराशा का निमित्त है। इस प्रकरणमें प्रोफेसर पीगू का कहना है कि उत्कर्ष का नाम है आकांक्षित करने और अपकर्ष का नाम है निराशा जितने भूलें हुआ करती है। इन मूलोंके कारण आर्थिक परिस्थितियाँ अधिक बदलने लगी हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ ही निराशा का नाम है। जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ ही निराशा का नाम है। जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ ही निराशा का नाम है।

इस निश्चित रूपमें मनोवैज्ञानिक विज्ञानोंका आर्थिक क्षेत्र में समझने और समझाने में हमका उपयोग करना पड़ता है और किसीभी अर्थशास्त्रीने इस विज्ञानका उपयोग नहीं समझा है। जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ ही निराशा का नाम है। जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ ही निराशा का नाम है। जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ ही निराशा का नाम है।

द्रव्य सम्बन्धी सिद्धान्त

कुछ ग्रंथशास्त्री जिनमें हीट्टे का नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है, द्रव्यके प्रसार और संकुचनसे आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षका सम्बन्ध स्थापित करते हैं। आधुनिक कालमें साख-द्रव्यकी प्रधानताके कारण और इसके परिमाणकी अस्थिरताके कारण आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होजाती है। साख-द्रव्यके प्रसारमें आर्थिक उत्कर्षका सूत्रपात होता है। यदि बैंक व्याजकी दर कम कर दें अथवा ऋण देनेकी शर्तोंमें अधिक उदारता दिखायें तो साख-द्रव्यकी माग बढ़जायेगी क्योंकि अपकर्षके गर्त की-प्रवृत्तिमें बैंक ऋण-देनेको उत्सुक रहते हैं। हीट्टेके मतमें व्यापारी वर्गको व्याजकी दरमें घुंझीभी नमी होनेसे वस्तुओंके सचयमें वृद्धि करनेकी प्रवृत्ति होती है। जब वह नये साख-द्रव्य द्वारा वस्तुओंको मोल लेता है तो यह द्रव्य उपभोक्ताओं की आयके रूपमें प्रकट होता है। उपभोक्ताओंको आयमें वृद्धि होनेके कारण उनके व्ययमें भी वृद्धि होने लगती है जिसके फलस्वरूप वस्तुओंकी मागमें वृद्धि होने लगती है और मूल्य-स्तरमें भी वृद्धि होनेकी प्रवृत्ति होती है। मूल्य-स्तरमें वृद्धि होनेसे उत्पादकोंको अधिक लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उत्पादन-व्ययमें धीरे धीरे वृद्धि होती है। इस लाभकी वृद्धिके कारण पूँजीके लगावमें भी वृद्धि होने लगती है और उत्पादक वस्तुओंकी मागमें भी वृद्धि होती है। उत्पादक वर्ग बैंकोंसे अधिक परिमाणमें ऋण लेते हैं जिससे पुनः उपभोक्ताओंके आय और व्ययमें वृद्धि होती है और पूँजीके लगावको नया प्रोत्साहन मिलता है। इसप्रकार आर्थिक उत्थानको अपनेही अन्तर्गत कारणोंमें प्रगति प्राप्त होने लगती है और उत्कर्षकी अवस्था प्राप्त होजाती है। जबतक बैंक द्रव्यकी बढ़ती हुई मागको पूरा करते रहते हैं तबतक उत्कर्षकी अवस्था बढी रहती है।

इस सिद्धान्तके अनुसार ज्योंही बैंक साख-द्रव्यके प्रसारमें नमी करने लगते हैं वैसेही अपकर्षका सूत्रपात होजाता है। अब प्रश्न यह है कि जैसे जैसे साख द्रव्यमें वृद्धि होती रहती है, बैंककी नकदी का अनुपात कम होता रहना है और यदि उनके नकदीके कोषमें पर्याप्त मात्रामें वृद्धि न होसके तो एक समय आजायेगा जबकि उनको अपना हाथ रोकना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त साख-द्रव्यकी वृद्धि और आर्थिक कार्य-स्तरकी प्रगतिके कारण समाजमें नकदीकी आवश्यकता भी बढ़ने लगती है।

साथही साथ केन्द्रीय बैंकभी द्रव्य स्फीतिकी आशकासे अपनी द्रव्य-नीति द्वारा साख-द्रव्यका नियन्त्रण करनेकी चेष्टा करते हैं। स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकको इस प्रकारकी नीतिको कार्य रूपमें लाना आवश्यक हुआ जाता था। साख-द्रव्यके प्रसारमें रोकथाम करनेके लिए बैंक व्याजकी दरमें वृद्धि कर देने हैं और पुराने ऋणोंके वापस होनेपर नया ऋण उससे कम परिमाणमें देते हैं। इस प्रकार साख द्रव्यका मकुचन प्रारम्भ हो जाता है।

इस सकुचनमें आर्थिक अपकष भी प्रारम्भ हो जाता है। व्यापारी बड़ीहुई व्याज की दरपर अपने वस्तुओंके सचयको कम करने लगते हैं और सचित वस्तुओंको शीघ्रता में बचनकी चेष्टा करते हैं। इससे उपभोक्ताओंकी आय और व्ययमें कमी आजाती है और विविध प्रकारकी वस्तुओंकी मागभी घटजाती है। मागके घटजाने पर मूल्य-स्तर गिरने लगता है और लाभकी मात्रामें कमी आजाती है और सीमान्त उत्पादकों को तो हानि उठानी पड़ती है। इसके फलस्वरूप पूजीके लगावमें कमी आजाती है और आर्थिक साधनोंमें बकासी भागसे उपभोक्ताओंके आय और व्ययमें पुन कमी होजाती है। इस प्रकार अपकष प्रारम्भ होनेपर स्वयमेव वह गतकी प्रार जाने लगता है। गतपर पहुचनपर धीरे धीरे बैंक प्रकृतिस्थ होने लगते हैं। पुराने ऋणोंके वापस होनेसे और नये ऋणोंकी माग न होनेके कारण बैंकोंमें नकदीका परिमाण बढन लगता है और वे ऋण देन को उत्सुक होने लगते हैं। अतएव वे व्याजकी दर कम करते हैं और ऋण देनमें अधिक उदारता दिखाने लगते हैं। जब व्यापारी इस परिस्थितिका लाभ उठान लगते हैं तो पुन आर्थिक क्रियाओंके स्तरमें पूर्ववत उत्थान और प्रगतिका संचार होने लगता है। हीट्रके मतानुसार यदि केन्द्रीय बैंक और अन्य व्यापारी बैंक अल्पाय द्रव्य-नीतिका प्रयोग करते रहें तो कोई कारण नहीं है कि उत्पादक वर्ग विजेषत व्यापारी वर्ग इसका लाभ न उठाए।

यह बात सभीको भान्य है कि वर्तमान आर्थिक प्रणालीमें द्रव्यको प्रमुख स्थान प्राप्त है और द्रव्यकी अस्थिरताके कारण आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। परन्तु आर्थिक-चक्रकी वास्तविकताका ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेसे पता चलता है कि सभी आर्थिक अस्थिरताएँ द्रव्यजनित नहीं होती। द्रव्यका सुप्रबन्ध होनेपर ही इन अस्थिरताओंका अन्त नहीं हो सकेगा। यह ठीक है कि आर्थिक उत्कर्षकी वृद्धिके लिए द्रव्यका प्रसार आवश्यक है। परन्तु यदि उत्पादक वर्गको अपनी पूजीके लगाव

से लाभकी आशा न होती वे केवल व्याजकी दरमें कमीके कारणसे ही बैंकोसे अधिक मात्रामें साख-द्रव्यकी माचना नहीं करेंगे। अनुभवसे ज्ञात होता है कि आर्थिक गत की अवस्थामें जबकि बैंक प्रयाप्त मात्रामें ऋण देनेके योग्य रहनेहैं और केन्द्रीय बैंकभी अपनी व्याजकी दर कम करके अथवा खुले हाटकी क्रियाओंसे आर्थिक क्षेत्र में द्रव्यके चलनमें वृद्धि करनेकी चेष्टा करता है उत्पादकवर्ग तबतक इस परिस्थितिमें लाभ उठानेकी चेष्टा नहीं करतेहैं, जबतक कि उनको पूँजीके लगावसे लाभ होनेकी आशा न हो। यह आशा केवल व्याजकी दरपर ही निर्भर नहीं रहती है। नये आविष्कार, नये बाजार, उत्पादन-व्ययमें कमी—इस प्रकारके वातावरणमें ही उत्पादकोंमें आशा और विश्वासका संचार होता है। यदि इस प्रकारका वातावरण न होता केवल साख-द्रव्यकी अधिक मात्रामें कम बाजारकी दरपर उपलब्ध करनेसे ही उत्थानका कार्य आरम्भ नहीं हागा। हौट्टेके मनमें अल्पकालीन व्याजकी दरमें परिवर्तन करना पर्याप्त होता है परन्तु अन्य अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार पूँजीके लगाव का सम्बन्ध विशेष रूपसे दीर्घकालीन व्याजकी दरसे होता है।

हायेक का सिद्धान्त

प्रोफेसर हायेकने द्रव्य सम्बन्धी परिस्थितियों द्वारा वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों का सम्बन्ध वर्णितहूए यह बतलानेकी चेष्टाकी है कि वर्तमान साख-द्रव्य-पद्धतिकी विकृतियोंके कारण पूँजीका लगाव उत्कर्षकालमें असन्तुलित रूपसे बढ़ताजाता है और एक ऐसी अवस्था आजाती है कि आर्थिक प्रगतिमें सकट आजाना अनिवार्य होजाता है। हायेकका कहनाहै कि साख-द्रव्यके प्रसारके आधारपर पूँजीके लगाव और उत्पादक वस्तुओंके उत्पत्तिके परिमाणमें जो वृद्धि होतीहै वह वृद्धि स्थायी नहीं रहसकती है। स्थायी रूपसे पूँजीके लगावकी वृद्धि स्वेच्छापूर्वक वचनके परिमाणपर निर्भर रहती है। यदि बैंकोकी व्याजकी दर सन्तुलन व्याजकी दर (अर्थात् वह दर जहापर ऋणकी माग वचनके परिमाणके बराबर रहतीहै) से कम रहतीहै तो इस प्रकारसे जो पूँजीके लगावके कार्यको कृत्रिम उत्साह मिलताहै उसके फल-स्वरूप आर्थिक साधनोंका प्रयोग उपभोगकी वस्तुओंके निर्माणसे हटकर उत्पादक वस्तुओंके निर्माणके कार्यमें होनेलगता है। इससे उपभोगकी वस्तुओंके मूल्य-स्तर

में वृद्धि होनाक कारण उपभोक्ताओंको विवश होकर अपने उपभोगक परिमाणमें कमी करके उत्पादक वस्तुओंके निर्माणके हेतु आर्थिक साधनाओंको उपलब्ध करनेके लिए बाध्य होनापड़ता है। इस वसात्कारसं जो पूँजी वस्तुओंके निर्माणमें लगायी जाती है उसके फलस्वरूप आर्थिक साधनाका भिन्न भिन्न अवयवोंमें वितरण विकृत होजाता है। इस प्रकारकी आर्थिक रचना स्थायी नहीं रहसकती है, उसपर सबट आना अनिवार्य होजाता है।

साख-द्रव्यके आधारपर पूँजीके लगाव और उत्पादक वस्तुओंके निर्माणके फल-स्वरूप जब उपभोक्ताओंके आय स्तरमें वृद्धि होनवाली है तो उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें वृद्धि होनलानी है क्योंकि उपभोक्ता लोग पुनः अपने उपभोगकी वस्तुओंके परिमाणको उसी स्तरपर लाना चाहते हैं जहाँसे विवश होकर उनका उनसे बचिन होनापड़ा था। यहाँपर एक विषय परिस्थिति उत्पन्न होजाती है। एक ओर तो उत्पादक वस्तुओंके निर्माणके लिए आर्थिक साधनाकी माग रहती है और दूसरी ओर उपभोक्ताओंकी आयमें वृद्धि होजानेके कारण उपभोगके पदार्थोंकी मागमें भी वृद्धि होजाती है और उनके निर्माणके लिए भी आर्थिक साधन चाहिए। अधिक सामान इतनी प्रगतिमानतामें नहीं प्राप्त होता कि दोनोंका माग पूरा रूपसे पूरी होसके। हायकने मतानुसार इस परिस्थितिमें उत्पादक वस्तुओंके निमाताओंका उपभोगके पदार्थोंका बचानाबाल उद्योग धनके पक्षमें आर्थिक साधनाको मुक्त करती पड़ता है। इसके दो प्रधान कारण हैं। एक तो यह कि उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें वृद्धि होनके कारण इनके उद्योग धनमें लाभकी वृद्धि होनसकती है जिसके कारण यह आर्थिक साधनाको अधिक मूल्य देनेमें समर्थ रहते हैं। अतएव उत्पादक वस्तुओंको बनाने वाले उद्योग धन्याक साथ प्रतिस्पर्धामें अपना हाथ ऊपर करसकते हैं। दूसरा कारण यह है कि इस अवसरपर वेकभी साख-द्रव्यको अधिक मात्रामें प्रसारित करनेमें असमर्थ होनेजाते हैं। अतएव वहभी व्याजकी दरमें वृद्धि करदते हैं। इस प्रकारकी परिस्थिति में उत्पादक वस्तुओंकी मागमें कमी आजाती है और उनपर पूँजीक लगावकी मात्राभी सकुचिन होन लगती है और आर्थिक अपनपका मूलपात हो जाता है।

हायकने अपकर्षोंकी दशाका पर्याप्त विवेचन नहीं किया है। उसका कहना है कि अपक उपभोगके उद्योग धन्यासे प्रारम्भ होकर सारी आर्थिक क्रियाओं

पर छाजाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि इन उद्योग धन्धोंमें सकट भ्रानके कारण पूँजीके लगावमें कमी आजाती है और द्रव्य बेकार संचित होने लगता है। द्रव्यके चलनके परिमाणमें सकुचन होने लगता है। मूल्य-स्तर गिरने लगता है और लाभकी दर व्याजकी दरसे कम होने लगती है। आय और मागमें इस प्रकार की कमी होनेके कारण उपभोगके पदार्थोंकी बनानेवाँ उद्योग धन्धोंमें भी मन्दी छाजाती है।

आर्थिक अपकर्षके कालमें आर्थिक क्षेत्रको इन नयी परिस्थितियोंके योग्य बनाने की चेष्टा की जाती है। साख द्रव्य जनित उत्पत्तिके उपकरणोंके विस्तारको कम किया जाता है। इसप्रकार कष्ट महनेट्टए आर्थिक परिस्थिति स्थिरताकी ओर (नीचे स्तर पर) अग्रसर होती है। मूल्य स्तरमें स्थिरता आजाती है और नैराश्याका अन्त हो कर आजाका संचार होन लगता है और चूँकि बेकारोंके पास बेकार संचित गन्दीका कोश पड़ा रहता है अतएव वेभी उद्योग धन्धोंको कम व्यय जकी दरपर उदारतापूर्वक नग्न देनको प्रस्तुत रहन हैं। इसप्रकार आर्थिक-चक्र पुन उत्थानके पथपर चडने लगता है।

हायेंकका यह सिद्धान्त वास्तविक परिस्थितिकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है और यह दिखानेकी चेष्टा करता है कि साख-द्रव्यके प्रसारसे किसप्रकार आर्थिक परिस्थिति विकृत होजाती है। परन्तु सभी परिस्थितियोंमें द्रव्यके प्रसार से आर्थिक विकृतियाँ उत्पन्न होना अवश्यम्भावी नहीं है। जब उत्पादनके साधना में बेकारी छापी हो तो ऐसी अवस्थामें द्रव्यके प्रसारसे यदि इनकी नियुक्ति होजाये तो कोई कारण नहीं है कि इस प्रकारका आर्थिक विस्तार अवाञ्छनीय सिद्ध होगा। इसके अनतिरिक्त बिना अन्य बाह्य प्रेरणाओंकी सहायताके केवल व्याजकी दरमें कमी होनेसे आर्थिक उत्थान प्रारम्भ होसकता है इस प्रकारका विश्वास अनुभवसे प्रमाणित नहीं होता है।

उपभोग-हानि सिद्धान्त

एक और सिद्धान्त जो विशेष रूपसे आर्थिक सकटके कारणोंपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा करता है, उपभोग-हानि सिद्धान्त है। इसको हमने उपभोग-

हानि सिद्धान्तका नाम दिया है। इस सिद्धान्तके मूलमें यह बात है कि पूजावादी आर्थिक पद्धतिमें सम्पत्ति और आयके वितरणमें बहुत असमानता है। आयका एक बड़ाभाग एक छोटे व्यक्तिवर्ग के पास पहुँचना है जिसमें अधिक परिमाणमें वचन करनेकी प्रवृत्ति होती है। उपभागके पदार्थोंकी अधिकतम भाग कम आयवाले व्यक्तिवर्गकी होती है। आयके वितरणकी अनुमानना के कारण कम आयवाले व्यक्तिवर्ग की भाग उस अनुपातमें नहीं बढ़ता है जिन अनुपातमें वस्तुधाराकी उत्पत्तिमें वृद्धि होती है। इसी कारण इन वस्तुधारा विनी कम हाजिरी है और उत्पादकाका मूल्य-स्तर घटानका चाप्य होता पड़ता है जिसमें उनका साम घट जाता है अथवा हानि होने लगती है। यहाँ आर्थिक मकड़का कारण हाजिरी है क्योंकि साममें कमी अथवा हानिके कारण उत्पत्तिक परिमाण और आर्थिक माचनक नियाममें कमी हानि लगती है। वितरणकी असमानतासे जा उपभागकी हानि होती है, उसका दूसरा रूप मापके प्रतिशतों पर भी कह सकते हैं अथवा इस प्रकारकी उत्पत्ति जिसकी द्रव्य-मयी भाग न होने पर उत्पादक-व्यय बराबर मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता है।

होमन जा इस सिद्धान्तका प्रमुख प्रतिपादक है, कहता है कि अधिक आय स्तर वाले लोग अपनी वचनको बराबर पूजाके कार्यमें लगात रहते हैं जिससे उत्पादक वस्तुओंके निर्माणमें वृद्धि होती रहती है। अब धूँकि उत्पादन क्रियाओंमें जा द्रव्य-मयी आय हाजिरी है, उसका एक बड़ा हिस्सा उन लोगोंके पास पहुँच जाता है जिनमें वचन करके उसका पूजाके रूपमें लगानेकी प्रवृत्ति होती है, अतएव इन उत्पादित वस्तुओं की भाग पूरी नहीं हो पाती है। होमन कहता है कि यदि पारिश्रमिककी वृद्धि करके कम आय-स्तरवाले लोगोंकी आयमें वृद्धि कर दी जाय जिनमें अपनी आयके एक बड़े भागकी उपभोगकी वस्तुओंमें व्यय करनेकी प्रवृत्ति होती है तो इससे भाग का परिमाण घटाने और आर्थिक क्रियाएँ भी ठीक ठीक चलती रहें क्योंकि उपभाग की वस्तुओंके निर्माणके लिए ही उत्पादक वस्तुधारा (यन्त्र मशीन इत्यादि उपकरण) का निर्माण किया जाना है। अतएव उत्पादक वस्तुधाराकी भाग घटती रहें। पूजावादी आर्थिक पद्धतिमें समय समय पर आयके वितरणकी असमानताके कारण उपभोगकी वस्तुओंकी भागमें हानि हो जाती है। अतएव पूजाके लगावमें भी कमी करनी पड़ती है जिसके फलस्वरूप आर्थिक मकड़का प्रादुर्भाव होता है।

यह बात सभीका मान्य है कि पूजावादी पद्धतिमें आयका वितरण बहुत असमान

हैं और यह भी सभी मानते हैं कि भ्रमजीवियों के आय-स्तर को ऊँचा करके उनके जीवन-स्तर को ऊँचा करना भौतिकही नहीं परन्तु आर्थिक दृष्टिसे भी अत्यन्त आवश्यक है। उपभोग-हानि सिद्धान्तका छिद्रान्वेषण इस दृष्टिकोणसे नहीं किया जाता है। हम तो यह जानना चाहते हैं कि क्या उपभोग के लिए वस्तुओं की मांग की हानि के कारणसे आर्थिक संकट का जन्म होता है। इस कसौटी पर यह सिद्धान्त ठीक नहीं उतरता है। पहिले तो हीट्सन की इस उक्ति में ही तथ्य नहीं है कि सारी की सारी वचत पूँजी के रूप में परिणत होकर आर्थिक क्रियाओं में लगा दी जाती है। जैसा कि हम वचत और पूँजी-लगाव के सिद्धान्त में देखेंगे, आर्थिक प्रस्थिरता और अपकर्ष का एक प्रधान कारण यह है कि वचत पूँजी के रूप में क्रियाशील न होकर बेकार संचित होने लगती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक उत्कर्ष के काल में जब भ्रमजीवियों का पूर्ण नियोग होने लगता है, उपभोग के परिमाण में वृद्धि होती है न कि हानि। हा यह बात अवश्य है कि जब आर्थिक अपकर्ष प्रारम्भ होता है तो उद्यम और आय में कमी आने के कारण उपभोग की वस्तुओं की माँग में भी कमी आ जाती है और इसके कारण अपकर्ष की गति से गत की ओर अग्रसर होने लगता है। उपभोग-हानि होती अवश्य है परन्तु यह अपकर्ष का कारण नहीं अपितु उसको उत्तेजित करती है। इस सम्बन्ध में एक बात और भी बही जा सकती है। अनुभव और आँकड़ों से पता चलता है कि अपकर्ष का प्रारम्भ उत्पादक वस्तुओं वाले उद्योग धन्धों में होता है और इन्हीं उद्योग धन्धों में आर्थिक-चक्र का बेग भी रहता है। हीट्सन के मतानुसार पहिले संकट उपभोग की वस्तुओं का बचाने वाले उद्योग धन्धों में होना चाहिए।

वचन और पूँजी-लगाव सिद्धान्त

आधुनिक चक्र के विवेचन और विश्लेषण में आधुनिक काल में एक नये और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का विकास हुआ है। यह दृष्टिकोण वचन की मात्रा और पूँजी के लगाव की मात्रा के सामंजस्य से सम्बन्धित है। इस दृष्टिकोण का आर्थिक-चक्र में समावेश करने का विशेष श्रेय इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स को दिया जाता है। केन्स का कोई निजी सिद्धान्त आर्थिक-चक्र को पूर्ण रूप से समझाने के लिए प्रतिपादित नहीं है। उसने वचन और पूँजी के लगाव की इस प्रकार की परिभाषाओं का प्रयोग

कियाहै कि इन दोनोंका परिमाण सदाही समान रहता है। इस प्रकारकी समानता प्रकट करनेमें कोई बंध दोष नहींहै परन्तु प्रगतिशील आर्थिक-चक्रको समझानेमें वचन और पूजोके लगावकी समानता मानकर चलनेमें हम अपनेको वास्तविकता से हटाहुआ पाते हैं। अतएव हम इस वचन और पूजोके लगावके सिद्धान्तकी विवेचना करनेमें वचन और पूजोके लगावके परिमाणमें सममानता होनेकी सम्भावना को माननेहुए आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षको समझानेमें इसका प्रयोग करेंगे।

हम विश्लेषणके कार्यको आर्थिक गणकी अवस्थासे प्रारम्भ करते हैं। कल्पना कीजिए किसी सयुक्तिक कारणसे पूजोके लगावमें वृद्धि होनेकी प्रवृत्ति होजाती है। होसकता है कि यह कारण नये आविष्कार, अल्पकला, विज्ञानमें उन्नति, युद्ध-सामग्रीके निर्माणकी वृद्धि अथवा व्याजकी दरमें कमी होनेमें सम्बन्धित हो। इस पूजोके लगावमें वृद्धिके लिए इष्ट या तो पूर्व सचयमें लियाजायेगा अथवा बैंक नये साख-द्रव्यकी सृष्टि करके उत्पादकोंको उपबन्ध करेंगे अथवा दोनों रीतिया साथ साथ प्रयोगमें आयेंगी। इसप्रकार पूजोके लगावकी मात्रा चालू वचनकी मात्रासे बढ़जायगी और यह वृद्धि पुरानी वचनको काममें लाकर अथवा नये साख-द्रव्य के प्रयोगसे पूरी कीजायगी। अनुभवसे ज्ञात होताहै कि पूजोके लगावके परिमाणमें वचनके परिमाणमें कही अधिक अस्थिरता रहतीहै क्योंकि पूजोका लगाव उसकी वर्तमान और भविष्यकी उत्पादकता और लाभकी आशापर निर्भर रहताहै। पूजोके लगावकी अस्थिरताही आर्थिक अस्थिरताका प्रधान कारण समझी जाती है।

गुणक सिद्धान्त

पूजोके लगावमें वृद्धि होनेसे आर्थिक साधनोंको अधिक काम मिलताहै और उनकी आयमें भी वृद्धि होती है। जब इस बढीहुई आयको उपभोगता लोग भिन्न भिन्न पदार्थोंपर व्यय करते हैं तो उन वस्तुओंके बनानेवालाकी आयमें वृद्धि होतीहै और जब ये लोग अपनी बढीहुई आय व्यय करतेहैं तो इसके फलस्वरूप नयी आय उत्पन्न होती है। इसप्रकार प्रारम्भमें पूजोके लगावकी मात्राको वचनकी मात्रासे बढ़ानेसे अन्ततोगत्वा कुल आयमें कईगुनी वृद्धि हो सकती है। उदाहरणके लिए यदि प्रारम्भ

में पूजाका लगाव बचतसे १००० रुपया अधिकहो तो उसके व्ययसे १००० रुपया प्रारम्भिक आय होगी। मानलीजिए इस प्रारम्भिक आयका कुछ हिस्सा बचा लियागया और शेष उपभोगकी वस्तुओंपर व्यय कियागया। इस व्ययसे जो आय होगी उसको द्वितीय आय कहसकते हैं। इस द्वितीय आयका परिमाण प्रारम्भिक आयसे कम होगा। इसीप्रकार द्वितीय आयका कुछ हिस्सा बचालिया जायगा और शेष उपभोगकी वस्तुओंपर व्यय किया जायगा। इससे तृतीय आयका सृजन होगा जिसका परिमाण प्रारम्भिक आयसे कम होगा। इसीप्रकार चतुर्थ, पंचम इत्यादि स्तरोंमें नयी आयका परिमाण कम होता जायगा। यदि हम इनसब स्तरोंकी आयों को जाँचें तो हमको ज्ञातहोगा कि यह कुल आय १००० रुपयेसे कईगुनी अधिक है। यदि यह कुल आय ३००० रुपयाहो तो हम कहसकते हैं कि पूजाके लगावकी मात्रामें बचतकी मात्रामें १००० रुपयेके आधिक्यसे ३००० रुपयेके बराबर कुल आय हुई। इन सम्बन्धको हम 'गुणक सिद्धान्त' कहेंगे। उपरोक्त उदाहरणमें गुणक ३ है। स्पष्टहै कि गुणकके परिमाणका बचतके परिमाणसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि प्रारम्भिक आय सबकी सब बचाली जाय तो इससे उत्तरगामी आय नहीं होगी और गुणक एक होगा। यदि आधी आय बचायी जाय तो गुणक दो और यदि चौथाई आय बचायी जाय तो गुणक चार होगा। जैसे बचतकी मात्रासे पूर्जा के लगावमें वृद्धि होनेसे कुल आयमें इस अन्तरमें अधिक मात्रामें वृद्धि होतीहै इसी प्रकार जब पूजाके लगावकी मात्रा चालू बचतसे कमहो जातीहै तो कुलआय इस अन्तरसे अधिक मात्रामें घटजाती है।

गति-वृद्धि सिद्धान्त

उपभोग्य वस्तुओंकी मागमें वृद्धि होनेसे पूजाके लगावको भी प्रोत्साहन मिलताहै और उत्पादक वस्तुओंकी मागमें वृद्धि हाती है। उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें जिस परिमाणमें वृद्धि होतीहै, उससे बड़े परिमाणमें उत्पादक वस्तुओंकी मागकी वृद्धि हाती है। उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें वृद्धिके फलस्वरूप पूजाके लगावमें जा वृद्धि हाता है उस सम्बन्धका 'गति-वृद्धि सिद्धान्त' द्वारा समझाया जाता है। इस पूजाके लगावमें वृद्धिके लिए द्रव्य बैंकोसे प्राप्त किया जाताहै और गुणक सम्बन्धी

वचतसे भी प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजोके लगावमें वृद्धि होनेसे पुनः आयमें वृद्धि होती है और पुनः गुणक सिद्धान्त सम्बन्धी आयका चक्र चलने लगता है। इसमें पुनः पूजोके लगावकी उत्तेजना मिलती है और इसप्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया चलने लगती है। यह गति-वृद्धि-सिद्धान्त अपकर्षके कालमें भी लागू होता है। जब उपभोग्य वस्तुओंकी माग कम होजाती है तो उत्पादक वस्तुओंकी मागमें इससे कहीं अधिक स्थितिलता आजाती है।

गुणक और गति-वृद्धिके सिद्धान्तके आधारपर हम अनुमान कर सकते हैं कि जब पूजोके लगावकी मात्रा चालू बचतकी मागसे बढ़ जाती है तो आर्थिक उत्कर्षमें तीव्रता क्यों आने लगती है। अब प्रश्न यह है कि इस प्रगतिमें बाधा क्यों पड़ जाती है और पूजोके लगावमें कमी क्यों होने लगती है। एक कारण तो यह है कि जैसे जैसे उत्पादक वस्तुओंके निर्माणमें वृद्धि होती रहती है कुछ समय बाद आर्थिक साधनोंका प्राप्त करनेके लिए उत्पादक-व्ययमें वृद्धि करना अनिवार्य होजाता है। इसके अनिश्चित यहि इस परिस्थितिमें बेकरी व्याजकी दरमें वृद्धि करने से नये उद्योग धन्ये जिस लाभकी आशासे चलाये गये, वह आशा क्षीण होने लगती है। टिकाऊ उत्पादक वस्तुओंकी मात्रामें वृद्धि होनेपर कुछ समयके बाद उनकी सीमान्त उत्पादकतामें ह्रास होने लगता है। इन सभी कारणोंके फलस्वरूप कुछ प्रचुर उद्योग धन्ये यहि ही धक्केको सन्तुलनमें अभिसर्य होते हैं और अपने व्यवसायका क्षेत्र कम करना आरम्भ कर देते हैं। अन्य उद्योग धन्ये भी घटित होने लगते हैं और शीघ्रतासे श्रम को उत्पन्न करनेका प्रयत्न करत हैं। वे पूजोके लगावसे हाथ धींचने लगते हैं। वे अपनेको कृण-शोधनशील बनाय रखनेके लिए पूजोको वचतके रूपमें रखने लगते हैं। जब चालू बचतकी मात्रा पूजोके लगावके रूपमें बाहर न निकलकर संचित रूपमें रखी जाने लगती है तो इससे भयानक आर्थिक विकृतिका सूत्रपात होजाता है। जो आय वचतके रूपमें रोक्ती गयी उसमें उत्पादक वर्गकी इसी परिमाणमें हानि होगी जिसमें पूजोके लगावको औरभी घटका पड़वेगा।

जैसे ही पूजोके लगावकी मात्रा चालू बचतकी मात्रासे कम होने लगती है, गुणक सिद्धान्त और गति-वृद्धि सिद्धान्त आर्थिक-चक्रों के गाय अपकर्षकी ओर ढकेल देते हैं। पूजोके लगावमें कमीके कारण आर्थिक साधनोंमें बेकारी आने लगती है और आय-स्तर गिरने लगता है। आरम्भिक आयमें कमीके कारण द्वितीय, तृतीय

तथा आगोंके स्तरोंकी आय भी घटती जाती है और आयमें कुल कमी पूँजीके लगाव में कमीसे कईगुना अधिक होजाती है। आयकी कमीके कारण उपभोग्य-वस्तुओं की मागमें भी कमी आजाती है जिससे पूँजीके लगावमें और भी अधिक ह्रास हो जाता है और इस कमीसे भी गुणक-रूपी आय वेगसे कम होने लगती है। इसप्रकार आर्थिक-चक्र गिरनेकी ओर अग्रसर होन लगता है।

आर्थिक-चक्र गिरताही क्या नहीं जाता है और कहापर जाकर सकता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपभोग्य वस्तुआकी मागमें उत्पादक वस्तुओंकी मागकी अपेक्षा अधिक स्थिरता होती है। अतएव आर्थिक अपकर्षकी प्रगतिमें एक रोक इस दिशासे आती है। जीवने-स्तरको अधिक मात्रामें गिरनेसे बचानेकी सभी चेष्टा करते हैं। जिसके निमित्त पुरानी वस्तुओंकी खरीद करने लगते हैं। इसप्रकार उपभोग्य वस्तुओंकी माग एक स्तरपर पहुँचकर स्थिर होजाती है। इसमें कुछ अंश में उत्पादक वस्तुओंकी मागभी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उत्पादक वस्तुओंकी मागके प्रभावसे और बराबर काममें लानेमें जीर्ण और अव्यवहार्य होजाती है। इन दोनों बदलने के लिए भी पूँजीका लगाव होता रहता है। इसप्रकार चिनगारी सुलगती रहती है और यदि इसमय पर पूँजी लगाने के नये अवसर प्राप्त हो और उत्पादक वर्गमें आशाका संचार होनेलगे तो शनैः शनैः उत्थानका क्रम आरम्भ होने लगेगा।

वचन और यज्ञोंके लगावका सिद्धान्तभी सम्पूर्ण आर्थिक-चक्रको नहीं समझाता है। परन्तु इस दृष्टिकोणसे विवेचना करनेमें एक विशेषता यह है कि हम इसमें अधिक उदाहरण पाते हैं। द्रव्यसम्बन्धी अनादिज्ञानिक तथा अन्य सिद्धान्तोंको इस के अन्तर्गत लिया जा सकता है। यही कारण है कि अर्थ-चक्रकी आधुनिक विवेचनामें इस सिद्धान्तकी एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है।

उत्कर्ष और अपकर्ष का प्रतिकार

पूँजीवादी पद्धतिके अन्तर्गत आर्थिक-चक्रका पूर्णरूपसे उन्मूलन करना असंभव प्रतीत होता है क्योंकि इसके संस्थान और सम्बन्ध इस प्रकारके होते हैं जिनसे अस्थिरता उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकती है। परन्तु आर्थिक योजना और नियन्त्रण द्वारा कुछ अंशतः इसका निराकरण किया जा सकता है। इसका भार विशेषरूपसे राज्य

वे ऊपर डाला जाता है कि वह अपनी राजस्व-नीति द्वारा और द्रव्य-नीति द्वारा आर्थिक अस्थिरता में कमी लाने का प्रयत्न करे। स्पष्ट है कि आर्थिक विषयों में राज्य का जितना अधिक हाथ होगा, उसी हिसाबसे वह इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेगा। पहिल महायुद्ध के बाद और विशेष रूपसे १९२६-१९३३ के विश्व-व्यापी आर्थिक संकट के बाद राज्य का हस्तक्षेप देशों के आर्थिक कार्यों में बहुत बढ़ गया है और यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। आधुनिक काल में राज्य द्वारा भी एक बड़ी मात्रा में पूँजी लगाने का कार्य होना है। हमें देना कि आर्थिक उत्कर्ष और प्रपक्ष का एक प्रधान कारण पूँजी के लगाव की मात्रा में अस्थिरता आना है। अन्य उत्पादक तो द्रव्यात्मक लाभ की आशासे पूँजी लगाते हैं और जब लाभ की आशा घटने लगती है तो वे भी पूँजी के लगाव में कमी करने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आर्थिक अपक्ष प्रारम्भ हो जाता है परन्तु राज्य के पूँजी-लगाव का उद्देश्य इस प्रकार का द्रव्यात्मक लाभ नहीं होता है। अतएव राज्य तो अपने पूँजी के लगाव के कार्यों में अस्थिरता आने को रोक सकता है। साथ ही साथ राज्य अपनी पूँजी के लगाव की नीति द्वारा कुछ अग्रगण्य क्षतिपूर्क का कार्य भी कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि आर्थिक परिस्थिति उन प्रकार की होगी हो कि पूँजीपति पूँजी के लगाव के परिमाण को घटाने लगेंगे तो और द्रव्य का संचय होना प्रारम्भ हो गया हो तो राज्य को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में वह अपनी पूँजी के लगाव में वृद्धि करके क्षतिपूर्क का काम करे। यह आवश्यक है कि योजनाएँ पहिल से ही तैयार रहें ताकि उचित समय पर तत्काल यह कार्य रूप में परिणत की जा सकें। नहीं तो आर्थिक साधनों के कुप्रयोग की आशंका होगी। राज्यावे पास इस प्रकार की योजनाओं की कमी नहीं हो सकती है। नहर सड़क रेल और अनुपयोगी भूमिको उपयोगी बनाना इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य सभी देशों में वांछनीय हैं। इन कार्यों के लिए राज्य को द्रव्य चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्य को या तो वह द्रव्य, जो कि बचकर मचित हो रहा हो, ऋण के रूप में लेकर पुनः चलन में लाना चाहिए अथवा नये साधन द्रव्य से अपने कार्यों का सम्पादन करना चाहिए। कर द्वारा द्रव्य प्राप्त करने की चेष्टा से पूँजी के लगाव में और भी कमी आने की आशंका रहती है।

राज्य के पूँजी के लगाव में वृद्धि होने से शणक-सिद्धान्त कार्यान्वित हो ने लगेगा और इससे उपभोक्ताओं की आय और मांग की मात्रा में भी वृद्धि होने की प्रवृत्ति होगी।

यह आवश्यक है कि राज्यका इस पूँजीके लगावका कार्य अपकर्ष आरम्भ होतेही चालू कर दिया जाय। देर होजानेसे जब आर्थिक परिस्थिति गर्तकी ओर बहुत दूर तक अग्रसर होगयी हो तो फिर राज्यको रोकथाम करना बहुत कठिन होजायगा। अपकर्षके कालमें बेकारोको द्रव्य-रूपमें सहायता देकरभी कुछ अशक्त उपभोगके पदार्थोंकी माग बनायी रखीजा सकती है। इसीप्रकार सर्वसाधारणके उपभोगकी वस्तुओपर कर-भार हलका करनेसे उनकी मांगमें वृद्धि होनेकी सम्भावना रहती है।

उत्कर्षके कालमें राज्यको यह देखना पडताहै कि पूँजीका लगाव असन्तुलित रूप में न बढ़ने पाये। इसकेलिए राज्यको पूँजीके लगावके नियन्त्रणकी आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त राज्यको अपनीपूँजीके लगावकी मात्राको भी इस आर्थिक परिस्थितिके अनुकूल बनाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितिमें राज्यको अपने व्ययमें कमी करनी पड़ेगी। अपने बजटमें वचतुत्तानेका प्रयत्न करना पड़ेगा। कर-नीति द्वाराभी इसप्रकार का प्रबन्ध करना पड़ेगा कि उत्कर्षमें उत्तेजना न घानेपाये।

जैसा ऊपर बतलाया जाचुका है कि आर्थिक क्रियाओको डुनाये रखनेके लिए यह आवश्यक है कि उपभोगकाओकी माग बनी रहे। क्योंकि कम आयवाले लोग अपनी आयका अधिकांश उपभोगके पदार्थोंमें व्यय करतेहैं और धनी वर्गमें वचत करनेकी प्रवृत्ति अधिक मात्रामें पायीजाती है। अतएव इसप्रकार की कर-नीति जिसके द्वारा धनका वितरण कम आयवालोके पक्षमें हो, उपभोगकी मात्राको प्रोत्साहित करनेमें सहायता देसकेगी।

द्रव्यनीति द्वाराभी आर्थिक-चक्रकी विपमताओको कम करनेमें सहायता प्राप्त होसकती है। केन्द्रीय बैंकका धर्महै कि वह निरन्तर आर्थिक परिस्थितियोंका अध्ययन करतारहे और सदैव सतर्क रहे। जैसेही विपमताओके लक्षण प्रकट होनेलगें वैसे ही अपने उपकरणोंका उनके प्रशमनके लिए काममें तानलगे और सरकारका ध्यान भी इसकी ओर आकर्षित करे। केन्द्रीय बैंकपर बहुत बडा उत्तरदायित्व है। उसको देशकी द्रव्य और बैंक प्रणालीपर पूरा अधिकार प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिए। व्याजकी दरका आर्थिक श्रवयबो और उसके सम्बन्धोपर बडा प्रभाव पडता है। केन्द्रीय बैंकको चाहिए कि वह समय समयपर आर्थिक परिस्थितिके अनुसार व्याजकी दरमें परिवर्तन लानकी चेष्टा करे।

वास्तवमें राजस्व नीति और द्रव्य नीतिका सामंजस्य करने ही उत्कर्ष और अपक्व सम्बन्धी व्याधियाँ को कम किया जा सकता है। अतएव सरकार और केन्द्रीय बैंक दोनोंकी नीतिमें विरोध नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय बैंकके राष्ट्रीयकरणसे यह आशा की जाती है कि ये दोनों नीतियाँ एक दूसरेका सहायता देती हुई आर्थिक-चक्रकी व्याधियोंके प्रसमनमें सफल हो सकेंगी।

राजस्व का स्वरूप और क्षेत्र

राज्य और शासन की आवश्यकता

मनुष्य समाजमें रहना पसन्द करता है। प्राचीन कालके इतिहासमें ज्ञात होता है कि वह किसी कुनबे, वबीले अथवा गिरोहका सदस्य रहा है। आधुनिक कालमें समाजका क्षेत्र बढकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। जब मनुष्य साथ साथ रहने लगनेहें तो अनेक इसप्रकारकी आवश्यकताएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनको सामूहिक आवश्यकताएँ कह सकते हैं। इसप्रकारकी आवश्यकताओंको पूरा करने का प्रबन्ध समाजको करना पड़ता है। उदाहरणके लिए बाहरी आक्रमणसे समाज की रक्षा कोई व्यक्ति-विशेष नहीं कर सकता है। यह सारे समाजका ही कर्तव्य हो जाता है कि वह मिलकर शत्रुको मार भगाय। इसी प्रकार मनुष्योंके साथ रहनेसे मारपीट, चोरी, डकैती होनेकी सम्भावना रहती है। इसमें मर्यादित पैदा हो जाती है। समाजका यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह इन व्याधियोंसे अपने सदस्योंकी रक्षाका प्रबन्ध कर और आततायीको दब दे। इसके अतिरिक्त सन्नामक रोगोंसे तथा अग्निकाण्डसे समाजके व्यक्तियोंको बचानेका प्रबन्ध भी करना पड़ता है। इसप्रकार के सामूहिक कर्तव्योंका पालन करनेके लिए तथा समाजके जीवनको व्यवस्थित करनेके लिए राज्य और शासनका सूत्रपात हुआ और शनैः शनैः उनका विकास हुआ। जिसप्रकार श्रम-विभाग और विनिष्ठीकरण से मनुष्य अपनी आवश्यकताओंकी अधिक मात्रामें और अधिक सुगमता और कुशलताके साथ तृप्ति कर सकता है, उसी सिद्धान्तके अनुसार सामूहिक आवश्यकताओंकी पूर्तिका प्रबन्ध एक विशेष सस्या द्वारा अधिक प्रवीणता और उत्प्रेरणाके साथ हो सकता है। एक प्रकारसे राज्य और शासनकी स्थापना और उनका विस्तार श्रम विभाग की विनिष्ठीकताका एक उदाहरण है।

प्रारम्भमें इस प्रकारकी आवश्यकताओंका क्षेत्र परिमित था। राज्यके तीन प्रधान कर्तव्य समझे जातेथे। पहिला—वाहरी आक्रमणसे रक्षाका प्रबन्ध, दूसरा—समाजके भीतर शांति रक्षाका प्रबन्ध और तीसरा—सरकारी इमारत, सड़क, पुल, और नहर इत्यादिके निर्माणका प्रबन्ध। सैन्य, सैन्यः अनुभवसे ज्ञातहुआ कि इन कार्यों के अतिरिक्त अनेक कार्य औरभी हैं जिनका सम्पादन राज्यद्वारा अधिक सुगमता और कम व्ययके साथ होसकता है। उदाहरणके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रबन्ध करना, डाक, तार, मुद्रा और बाटका प्रबन्ध करना इत्यादि। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ज्ञातहोगा कि आधुनिक कालमें हमारे आर्थिक कार्योंका शायद ही कोई एका क्षेत्र होगा जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमें राज्यका हस्तक्षेप न होता हो। दूर जानकी आवश्यकता नहीं, आजकल हमको अन्न और वस्त्र मनुष्य प्रारम्भिक वस्तुओंको प्राप्त करनेके लिए राज्यका मुह देखना पड़ता है क्योंकि इन वस्तुओंकी कमी है और जनताके हितके लिए यह आवश्यक है कि इनका वितरण इसप्रकार से हो कि धनी और निर्धनी सभी लोकोको उचित मूल्यपर ये वस्तुएं प्राप्त हो। यह कार्य राज्य द्वाराही किया जासकता है। इसप्रकार भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करनेके लिए राज्यके आर्थिक कार्योंका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और इसके आगेभी विस्तृत होनेकी सम्भावना है।

आर्थिक कार्यों में राज्यके हस्तक्षेप की आवश्यकता ३५३

कुछ काल पहिले ऐसी विचारधारा थी कि लोकोको अपने आर्थिक कार्य करनेकी स्वतन्त्रता होती चाहिए। ऐसा कहा जाताथा कि क्योकि मनुष्य समाजका ही अंग है इसलिए अपने हितके लिए जोकोई भी कार्य वह करेगा उससे समाजका हितही होगा। राज्यका कर्तव्य यही समझा जाताथा कि वह रक्षा, न्याय, सड़क इत्यादिका प्रबन्ध करदे। अन्य आर्थिक कार्योंमें राज्यका हस्तक्षेप अनावश्यक हीनही परन्तु अनुचित भी समझा जाता था। इसप्रकार की आर्थिक व्यवस्थाको पूजीवादका नाम दिया गया है।

पूजीवादके अन्तर्गत आर्थिक कार्यों और आर्थिक सम्बन्धोंको देखनेसे पता चलता है कि किसीभी व्यक्तिके स्वहितके कार्योंसे समाजका हित होना अवश्यम्भावी नहीं

हैं। उदाहरणके लिए यदि कोई पूजोपति मजदूरोसे १६ घंटे प्रतिदिन काम ले और उनको वेतन जीवन-निर्वाह योग्य वेतनदे तो उसका तो लाभही होगा परन्तु मजदूरों और उनके बच्चोंके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तरपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसप्रकार की परिस्थितिको पैदा होनेसे रोज़ानके लिए आजकल राज्यकी ओरसे न्यूनतम-वेतन और अधिकसे अधिक कामके घंटे निश्चिन करदिये जाते हैं। इसीप्रकार यदि जमीन्दार किसानोंसे भनमाना लगान वसूल करें और जब चाहें तब उनको निकालें तो इससे जमीन्दारोंका लाभ और किसानोंकी हानिही होगी। अब इन दोनों वर्गोंकी लाभ-हानिको दृष्टिमें रखतेहुए और यह देखतेहुए कि मजदूरों और किसानोंकी सरया मिल-मानिको और जमीन्दारोंकी मरदासे कईगुना अधिक है, यह निश्चय है कि इस प्रकारकी स्वेच्छाचारितामें समाजकी हानिही होगी। ऐसी अवस्थाधामें राज्यका हस्तक्षेप करना नितान्त आवश्यक होजाता है।

इतनाही नहीं आधुनिक कालमें राज्यसे यह आघाती जानीहै कि वह निपात्मक रूपसे समाजके आर्थिक कार्योंमें सहयोगदे और अपनी आर्थिक और राजस्व-नीतिको बदलतीहुई आर्थिक परिस्थितिके अनुकूल बनाये। वर्तमान आर्थिक व्यवस्थामें उत्पत्तिके साधन कभी कभी बेकार पड़ रहतेहैं और आर्थिक मन्दी—जोकि पूँजीवादमें समय समयपर उत्पन्न होजाती है, के अवसरपर तो यह बेकारी बहुत बड़ी मात्रामें होजाती है। इससे राष्ट्रीय आयमें कमी और रहन सहनमें क्षति हांजाती है। ऐसी अवस्थामें राज्यका कर्तव्य होजाता है कि वह अपनी राजस्व-नीति द्वारा बेकारी हटानेका नहीं तो कम करनेका प्रयत्न तो अवश्य करे और आर्थिक-पद्धतिको उत्कर्ष की स्थिरताकी ओर अग्रसर करे। कर, व्यय और ऋण सम्बन्धी अध्यायोंमें बताया जायेगा कि राज्य किन किन उपायोंसे इसप्रकार के कार्य करसक्ता है।

राजस्व के मुख्य विभाग

ऊपर दिखाने वृत्तान्तसे स्पष्ट होजाता है कि राज्यके आर्थिक कार्योंके क्षेत्रमें बहुत वृद्धि होगयी है। इन कार्योंके सम्पादनके लिए राज्यको साधनोंकी आवश्यकता होती है। ये साधन कहासे और किस प्रकारसे प्राप्त कियेजाय और इनका समाजके उत्पादन और वितरणके कार्योंमें किसप्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसप्रकारके विषयो

का विवेचन राजस्वका एक मुख्य अंग है। जिसप्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को द्रव्यरूपी आयमें पूरी करताहै इसीप्रकार सामूहिक आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए राज्यका भी द्रव्यके रूपमें आयकी आवश्यकता होती है। यह आय आधुनिक कालमें प्रधानतः राज्य अपनी पंजाम करके रूपमें लता है। राज्यका अपनी सम्पत्ति और अपने उद्योग धन्यता भी कुछ आय होती है। कुछ छोटी मानी मर्दाने आयकी औरभी है जिनका विवेचन राज्यकी आयके अध्यायमें किया जायगा।

राजस्वका दूसरा विभाग व्यय सम्बन्धी है। सामूहिक आवश्यकताओंकी पूर्ति का प्रबन्ध करनेके लिए राज्यका द्रव्यका व्यय करना पड़ता है। व्ययकी मात्रा मर्दाने है। कितना व्यय कितना मर्दाने कियाजाय और कि कालमें कियाजाय यह एक महत्वपूर्ण विषय है। राज्य जब बड़ी मात्रामें विविध कार्योंमें व्यय करताहै तो इसका प्रभाव नगर आर्थिक क्षणपर पड़ता है। अतएव राज्यको बहुत सावधानतासे अपनी व्यय नीति निर्धारित करनी पड़ती है।

अनक ऐसे अवसर आजाते हैं जबकि राज्यकी सामान्य आय व्ययके लिए पर्याप्त नहीं होती है। उदाहरणके लिए रत्न नहर युद्ध इत्यादि मर्दाने बहुत व्यय होता है और राज्य अपनी सामान्य आयमें इनकी पूर्ति करनेमें अपनेका असमर्थ पाता है। अतएव उमका ऋण लेना पड़ता है। कभी कभी द्रव्यके अत्यधिक प्रसारको कम करनेके लिएभी राज्य ऋण लेता है। आधुनिक कालमें प्रत्येक राज्यको ऋणकी मात्रामें बहुत वृद्धि होगीहै और इसमें अनक समस्यायेंभी उत्पन्न होगीहै। अतएव यहभी राजस्वका एक पृथक् विभाग बनगया है।

आय और व्ययका हिसाब रखना बजट बनाना बजटकी मर्दाने राज्य-परिषद द्वारा स्वीकृत करवाना और स्वीकृतिक अनुसार भित्त भित्त विभागों द्वारा निम्न भित्त मर्दाने व्ययका प्रबन्ध करना और उसकी जाच परताल करना—इसप्रकार के कार्यभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका विवेचन राजस्व प्रशासन विभागके अन्तर्गत कियाजाता है।

राजस्व-शास्त्रके यही चार मुख्य विभाग हैं। परन्तु यह नेही सम्पन्नता चाणिक कि राजस्वके ये चार विभाग एक दूसरेसे पृथक् हैं। विवेचनाकी सुगमताके लिए ही इनको अलग अलग कियागया है प्रत्येक एकका दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। उदाहरणके लिए राज्यका व्ययका समाजके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इसको पूरी तौर

पर जाननेके लिए यह आवश्यक है कि राज्यने यह धन किसप्रकार प्राप्त किया और उसका समाजपर क्या प्रभाव पड़ा।

राजस्व शास्त्रमें राज्यके आय व्यय और ऋण सम्बन्धी सिद्धान्तोंका विवेचन किया जाता है। यह अर्थशास्त्रका ही एक विभाग समझा जाता है क्योंकि जैसा आग चलकर जान होगा राज्यके आर्थिक कार्योंके अन्तर्गतभी अर्थशास्त्रके ही सिद्धान्त लागू होते हैं। मूलमें राज्यके सम्मुख भी वही परिस्थिति है जैसी कि किसी व्यक्ति-विशेष के अथवा आर्थिक समस्याके सम्मुख होती है अर्थात् राज्यके पास भी सामूहिक आर्थिक कार्योंको पूरा करने सम्पादन करनेके लिए पर्याप्त मात्रामें साधन नहीं हैं। अतएव उसकोभी उन साधनार्थ अधिकतम आर्थिक स्रोत उत्पन्न करनेके लिए उनका भिन्न भिन्न मसलमें नियमित रूपमें वितरण करना पड़ता है।

राजस्वसे सम्बन्धित राज्य शब्दका प्रयोग व्यापक रूपमें होता है। इसके अन्तर्गत केवल केन्द्रीय राज्यके आर्थिक कार्योंका ही नहीं बरन प्रांतीय राज्यके और स्थानीय निकायों जैसे जिलाबोर्ड म्यूनिसिपल बोर्ड आदि ग्रामपंचायतके भी आर्थिक कार्योंका समावेश होता है।

अधिकतम सामाजिक-लाभ सिद्धान्त

राज्यके आर्थिक कार्योंके मूलमें एक सिद्धान्त रहना है जिसका कि अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्तका तात्पर्य यह है कि राज्यको वहाँ आर्थिक कार्य करने चाहिए जिनके फलस्वरूप समाजका अधिकतम अधिक लाभ हो। ये कार्य कौनसे हैं? सबसे पहिले राज्यका सुरक्षा और शान्तिका ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभीभाग निश्चिन्त होकर अपने-अपने कार्य करें। इससे उपरान्त राज्यको अपनी प्रजाको सुखी और समृद्ध बनानेका प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए दो बातोंका विशेष आवश्यकता है। एक तो यह कि देशके उत्पादनपरिमाणमें वृद्धि की जाय और दूसरा यह कि उसके वितरणकी असमानताको कम किया जाय। उत्पादनकी मात्राको बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि समाजके उत्पन्न के साधनमें वृद्धि की जाय। उनकी निपुणता बढ़ायी जाय उनको बर्कार होनसे बचाया जाय और उनका प्रयोग ठीक अनुपातमें किया जाय। उपत्तिकी मात्राका बढाना

साथ साथ इस बातका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि भिन्न भिन्न प्रकारकी वस्तुओं का परिमाण समाजकी आवश्यकतानुसार हो।

पञ्चाङ्गम राष्ट्रीय आयका वितरण बहुत असमान हो जाता है। इससे आर्थिक क्षमकी कमी होती है। परन्तु आर्थिक पद्धतिक व्यवस्थित और अविराध रूपसे चलाने में भी रक्षाबद्ध पद्धत हो जानी है जिसके कारण आर्थिक सक्रिय और मन्दोका अवस्था उत्पन्न हो जानी है। अतएव केवल आयक दृष्टिकोणसे ही नहीं बरन आर्थिक व्यवस्थाम स्थिरता लानेके लिए और उपत्ति साधनाको पूर्ण रूपसे काममें लाया करनेके लिए यह आवश्यक है कि वितरणको असमानताको कम किया जाय।

राज्यका केवल वर्तमान पीढ़ीके आर्थिक क्षमको ही नहीं अपितु भविष्यमें आने वाली पीढ़ीके क्षमका भी ध्यानमें रखना पड़ता है। अतएव यदि किसी व्यक्तिसे वर्तमान पीढ़ीके अधिक हितके निमित्त आनेवाली पीढ़ीके आर्थिक क्षममें अधिक क्षति होनेकी सम्भावना हो तो राज्यों में कामका नियन्त्रण करना चाहिए। —हरणके लिए यदि वर्तमान पीढ़ी खानासे सभी कायला और लोहा निकाले तो —क्षम भविष्यकी जनताका वर्तमान क्षति होगी।

इसप्रकार हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि यदि राज्यके आर्थिक कार्यों द्वारा समाजका हित होना हो तो वे कार्य निम्न हैं। —पहला कठिनाई यह है कि समाजका काम होनेके नापनेके लिए हमारे पास कोई मापदण्ड नहीं है। इसलिए अनेक परिस्थिति निम्न यह कहना कठिन हो जाता है कि कौनसे कार्यों में समाजका हित अधिक होगा। —द्विहरणके लिए यदि राज्यके सामने प्रश्न है कि हमें कौनसे रूपसे शिक्षा अथवा चिकित्सा व्यय किया जाय तो यह निश्चय करना कठिन है कि समाजका अधिकतम क्षम शिक्षा प्रसारण होगा अथवा स्वास्थ्य रक्षा से। ऐसी अवस्थाम अनुमान और अनुभव आधार पर ही निणय करना पड़ता है।

व्यक्ति और राज्य के आय व्यय सम्बन्धी कार्यों में समानता और भेद

साधारण तौरपर यह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आयके अनुसार अपने व्ययका समीकरण करता है परन्तु राज्य अपने कर्तव्योंके अनुसार अपने व्ययका

अनुमान करता है और फिर उसके अनुसार अपनी आयका समीकरण करता है। इस भेदके कई अपवाद हैं। हम देखने हैं कि अनेक व्यक्ति व्ययके बढजाने से आय बढाने की चेष्टा करते हैं। उदाहरणार्थ महेगोके अवसरपर कम वेतन पानेवाले शिक्षक, क्लर्क लोग द्यूशन करके अथवा अन्य कोई सहायक कार्य करके अपनी आय बढाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि राज्य अपनी आयको व्ययके अनुसार अवश्यही बढा सके। यदि ऐसाही होता तो राज्यको ऋण न लेना पडता। अतएव राज्यको व्यय करनेके पूर्व अपनी आयपर दृष्टि रखनी पडती है। प्रधान भेद यह है कि राज्यके पास किमी भी व्यक्तिकी अपेक्षा आयके अधिक साधन हैं। उदाहरणके लिए कर लगाकर आय करनेका अधिकार राज्यको है व्यक्तिको नहीं। सभी सभी राज्य अतिनिम्न माध्यम शीर्षको ध्याकर और उनको राज-प्रामाणित द्रव्य घोषित करके अपनी आय बढाते हैं। यह अधिकारभी सामान्य व्यक्तिके पास नहीं है। ऋण लेकर तात्कालिक आय बढानकी क्षमताभी साधारण व्यक्तिकी अपेक्षा राज्यकी अधिक रहती है क्योंकि उसकी साधन अधिक होती हैं और वह देशके भीतर और दूसरे देशसे भी ऋण ले सकता है जहा साधारणतः प्रत्येक व्यक्तिकी पहुच नहीं होती है।

एक बड़ा भेद राज्यके और अन्य व्यक्तियोंके आर्थिक कार्योंमें यह है कि साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति अपने धनमें लाभकी आशा करता है और इसीप्रकार के उद्योग धन्धामें उसको लगाना है और ऐसे मूल्यपर अपनी वस्तुओं और सेवाओंको बेचन की चेष्टा करता है जिसमें उसका द्रव्य सम्बन्धी लाभ हो। परन्तु राज्यका यह दृष्टिकोण नहीं रहता है। यदि हम राज्यकी प्रमुख व्ययकी मदोंको देखें—जैसे रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा सड़क इत्यादि तो हमको ज्ञात होता है कि राज्यका उद्देश्य इनमें अपनी द्रव्य सम्बन्धी आयको बढाना नहीं होता है। कुछ वस्तुओं और सेवाओंको तो राज्य लागतसे कम मूल्यपर कभी कभी नि शुल्कभी बेचता है। उदाहरणके लिए नि शुल्क शिक्षा। यह अवश्य है कि राज्यको कुछ-वस्तुओंके विक्रयसे लाभभी होता है परन्तु इनकी भरपा कम है।

भविष्यके लिए उपयुक्त प्रवन्ध करनेके हेतु व्यक्तिकी अपेक्षा राज्यका दृष्टिकोण अधिक व्यापक होता है। किसीभी व्यक्तिको वर्तमानकी अपेक्षा निकट भविष्य की अधिक चिन्ता रहती है और जैसे जैसे भविष्यकी दूरी बढती जाती है वैसे वैसे उसकी दृष्टिमें मुद्दर भविष्यमें प्राप्त होनेवाली उपयोगिता बहुत कम मानूम पडनी

है। उदाहरणार्थ जंगल लगानेमें और उसके बढ़कर आय उत्पन्न करने योग्य होने में बरसों लगजाते हैं। शायदही किसी व्यक्तिको इतना धैर्यहो कि वह इस काममें अपनी पूजा लगाये। परन्तु राज्यको तो दीर्घकालिक दृष्टिकोणसे भविष्यकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर प्रवन्ध करना पड़ना है।

अपने द्रव्यको भिन्न भिन्न वस्तुओंमें व्यय करनेमें राजकीय व्यक्तीको अधिक कुशलता रहती है। कोईभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की उद्यत्ताक अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओंमें प्राप्त होनेवाली उपयोगिताओंकी अपने मनमें तुलना करके अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करसकता है। परन्तु राज्यको तो इसप्रकार की कोई सीधी अनुभूति होती नहीं जिसके आधारपर वह भिन्न भिन्न व्ययसे प्राप्त सीमान्त उपयोगिताओंके समीकरणका प्रयत्न करसके। अतएव बहुधा राज्य व्ययमें यह पायाजाता है कि क्षतिशाली सस्थाओं, व्यक्तियों अथवा सम्पादकीय टिप्पणियों का प्रभाव और दबावके कारण कम आवश्यकीय विभागोंको अधिक और अधिक प्रावश्यकीय विभागोंको कम अनुदान मिलता है।

राज्य का व्यय

राज्य के व्यय का महत्व

पहिले अध्यायमें हमने देखा कि आधुनिक युगमें राज्यके आर्थिक कार्योंका क्षेत्र बहुत बढ गया है और इसका समाजके आर्थिक क्षेत्र परभी यथेष्ट प्रभाव पडता है। इन कार्योंके सम्पादनके लिए राज्यके व्ययका परिमाणभी बहुत बढ गया है। इस कारण राजस्वके व्यय विभागका महत्वभी अधिक होता जा रहा है। प्राचीन कालमें जब राज्यके कर्तव्य थोडेसे ही थे और इनकी पूर्तिके लिए अधिक परिमाण में व्ययभी नहीं होता था तब इस विषयपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। राजस्व-शास्त्र की पुस्तकोंमें भी इस विषयपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। परन्तु अब यह बात नहीं है। समाजकी आयका एक बडा भाग अब राज्यके द्वारा व्यय किया जाता है। अतएव लोगोको इस बातकी जिज्ञासा होने लगी है कि यह द्रव्य किस प्रकार व्यय किया जाता है। इसका सदुपयोग होता है अथवा दुरुपयोग। इसका समाजपर क्या प्रभाव पडता है इत्यादि। इस प्रकारके प्रश्नोंके अन्तर्गत राज्यके व्ययका सिद्धान्त निहित है।

राज्य के व्यय का वर्गीकरण

राजस्व-शास्त्रके लेखकोंने अनेक प्रकारसे राज्यके व्ययका वर्गीकरण किया है। प्रत्येकने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणसे यह वर्गीकरण किया है। अतएव यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सा वर्गीकरण अधिक उपयुक्त है। भिन्न भिन्न वर्गोंसे इस विषयपर प्रकाश अवश्यही पडता है। अतएव हम कुछ प्रमुख वर्गोंकी विवेचना करेंगे।

एक. पुराना, वर्गीकरण, निम्नके आधारपर किया गया है। 'इस आधारपर राज्यके

व्ययके चार वर्ग किये गये हैं। पहिले वर्गमें वह व्यय है जिससे समाजके सभी लोगोंका हित होता है जैसे कि रक्षा, शिक्षा और सड़कोपर किया गया व्यय। राज्य का सबसे अधिक व्यय ऐसे ही कार्योंमें होता है जिससे सर्वसाधारण जनताका लाभ हो। दूसरा वर्ग वह है जो मार्बजनिक तो समझा जाता है किन्तु उसका लाभ समाज के कुछ ही लोगोंको प्राप्त होता है जैसे कि निर्धन और अपाहिजोंकी सहायतापर व्यय। इस प्रकारके व्ययमें इन लोगोंका हित तो होता ही है परन्तु समाजका भी हित होता है क्योंकि राज्यमें सहायता न प्राप्त होनेपर इनमेंसे कई चोरी, डकैती और लूटमार करने लगते हैं और समाजमें अशान्ति पैदा कर देते हैं। तीसरा वर्ग वह है जिसमें समाजके हितको दृष्टिमें रखने हुए व्यय किया जाता है परन्तु इससे विशेष लाभ उन्हीं लोगोंको होता है जो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ शुल्क देते हैं। उदाहरणार्थ न्यायालयोंकी स्थापना और न्यायाधीशोंकी नियुक्ति और उनपर व्यय सर्वसाधारण हितके लिए किया जाता है परन्तु व्यक्तिगत लाभ उन्हीं लोगोंको होता है जो न्यायालय को एक निरपेक्ष नार्डलीम बनाते। चौथे वर्गमें वे व्यय आते हैं जिनमें उन्हीं लोगोंको लाभ होता है जो राजस्व उन वस्तुओं या सेवाओंका पूरा मूल्य देते हैं। राज्यके डाक, तार, रेल इत्यादि विभागोंपर व्यय किये हुए द्रव्यसे उन्हीं लोगोंका हित होता है जो इन विभागों द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं और सेवाओंका पूरा मूल्य देते हैं। एक पोस्टकार्डका मूल्य तीनपैसे है। अतएव जो मनुष्य तीनपैसे व्यय करने को तत्पर है उसीको पोस्टकार्डमें लाभ भी हो सकता है।

राज्यके व्ययके एक दूसरे वर्गीकरण का आधार उस व्ययसे राज्यको प्राप्त होनेवाली आय है। इसमें भी चार वर्ग किये गये हैं। पहिले वर्गमें वह व्यय है जिनसे राज्यको कोई आय नहीं होती है जैसे निर्धन और अपाहिजोंपर किया गया व्यय। दूसरा वर्ग वह है जिसमें राज्यके व्ययसे प्रत्यक्ष रूपमें तो आय नहीं होती है परन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे आयकी वृद्धिमें सहायता मिलती है। उदाहरणके लिए शिक्षापर किया गया व्यय। ऐसा अनुमान किया जाता है कि शिक्षित लोगोंमें सुगमता और कम खर्चसे कर वसूल हो जाता है। तीसरे प्रकारके व्ययमें कुछ आय होती है। जैसे इस प्रकारकी शिक्षा का प्रबन्ध जिसमें कुछ व्ययकी पूर्ति विद्यार्थियोंसे ली गयी फीस से होती है अथवा इस प्रकारकी नहर जिनकी चालू लागतका कुछ भाग सिंचाईके शुल्कसे प्राप्त हो सके। चौथा वर्ग उस व्ययका है जिससे राज्यका इतनी आय होती

जाती है कि कुल व्यय बगूल होजाता है और कभी कभी लाभभी होता है। उदाहरणके लिए डाकखानों और रेलोंपर व्यय।

एक अन्य वर्गीकरण राज्यके कर्तव्योंके आधारपर किया गया है। पहिले वर्गमें वह व्यय है जो देशकी रक्षाके लिए किये जाते हैं। उदाहरणके लिए सेना, पुलिस, न्यायालय और बिबित्सापर व्यय। दूसरे वर्गमें राज्यके उद्योग धन्धों और व्यापार पर किये गये व्यय शामिल हैं—जैसे रेल, विजली इत्यादिपर व्यय। तीसरे वर्गमें देश के आर्थिक विकास सम्बन्धी व्यय हैं। उदाहरणके लिए शिक्षा, सड़क, नहर और वन्दरगाह इत्यादिपर व्यय।

राज्यके कर्तव्योंके आधारपर दूसरे प्रकारसे भी वर्गीकरण किया गया है। इसमें दो मुख्य वर्ग हैं। एक प्रथम श्रेणीका और दूसरा द्वितीय श्रेणीका। प्रथम श्रेणी के व्ययमें रक्षा, शान्ति-स्थापना, प्रशासन और ऋण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित हैं। द्वितीय श्रेणीमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक बीमा इस प्रकारके समाज-सुधार पर व्यय, राज्यके उद्योग धन्धों और निर्माण कार्योंपर व्यय सम्मिलित हैं। द्वितीय श्रेणीसे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके द्वारा सम्पादित कार्योंका महत्व कम है।

एक वर्गीकरणके अनुसार राज्यके व्ययको उत्पादक और अनुत्पादक वर्गोंमें विभक्त किया गया है। उत्पादक व्यय वह है जिनसे राज्यको इतनी आय होती है जिससे व्यय पूरा बनूँ होजाय अथवा जिनसे समाजके आर्थिक क्षेत्रकी वृद्धि हो—जैसे रेल सड़क, तथा शिक्षा इत्यादिपर व्यय। अनुत्पादक व्ययसे न तो द्रव्य सम्बन्धी आय होती है और न समाजके आर्थिक क्षेत्रमें ही वृद्धि। उदाहरणके लिए उम युद्ध से सम्बन्धित व्यय जिसका अन्त पराजयमें हुआ हो।

एक प्रकारका व्यय वह है जिसके बदलेमें राज्य वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करता है, अर्थात् व्ययको उन वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य समझ सकते हैं। उदाहरणके लिए पुलिसपर व्यय किये गये व्ययको पुलिसमैनाकी सेवाका मूल्य, अध्यापकोंपर व्यय किये गये व्ययको अध्यापकोंकी सेवाका मूल्य समझा जा सकता है। इसके प्रतिकूल दूसरे प्रकारका व्यय वह है जिसके बदले राज्यको प्रत्यक्ष रूपमें कोई वस्तु अथवा सेवा प्राप्त नहीं होती है। उदाहरणके लिए निर्वाण और अपाहिजोंपर किया गया व्यय।

एक और वर्गीकरण देकर हम इस प्रकारके समाप्त करेंगे। इस वर्गीकरण के अनुसार राज्यका एक व्यय इस प्रकारका होता है जिसमें राज्य व्ययको केवल

हस्तान्तरित करता है अर्थात् समाजमें द्रव्य लेकर समाजको द्रव्यही वापिस कर देता है। उदाहरणके लिए राज्यकर द्वारा समाजमें रुपया प्राप्त करता है और उस द्रव्य के एक भागको पेन्शनके रूपमें अथवा निबंनो और अपाहिजोंकी सहायतामें अथवा शाजने रूपमें समाजके व्यक्तियोंको देता है परन्तु दूसरे प्रकारका व्यय वह है जिसमें राज्य समाजके उत्पत्तिके साधनोंको काममें लाता है। उदाहरणार्थ सड़क, नहर, पुल और शिक्षालय इत्यादिके बनानेमें राज्य जो द्रव्य व्यय करता है उसमें वह उत्पत्ति के साधनोंका प्रयोग करता है। इस प्रकारके व्ययसे उत्पत्तिके साधनोंके वितरणमें प्रभाव पड़ता है। पहिले प्रकारके व्ययको हम 'हस्तान्तरित' व्यय और दूसरे प्रकार के व्ययको 'वाम्नाविक' व्यय कहेंगे।

राज्य के व्ययसम्बन्धी नियम

राज्यके व्ययके कार्योंमें चार नियमोंको ध्यानमें रखना आवश्यक कहा गया है। पहिला नियम यह है कि व्ययसे समाजका अधिकतम हित हो। इस नियमको कार्यान्वित करनेके लिए यह आवश्यक है कि व्यय करनेसे पूर्व इस बातकी अच्छीतरह ध्यानबीन कर ली जानी चाहिए कि किस मदमें व्यय करनेसे समाजको अधिकसे अधिक क्षेम प्राप्त होगा। दूसरा नियम मितव्ययिताका है। मितव्ययिताका अर्थ कृपणता नहीं है। इसका यह तात्पर्य है कि राज्यके द्रव्यको व्यय करनेमें उसी प्रकारकी सावधानीमें काम लेना चाहिए जिस प्रकारकी सावधानी कोई व्यक्ति अपने धनको व्यय करने में लेता है। अनिव्यय और बरबादी न होनेदेनी चाहिए। तीसरा नियम स्वीकृति का है। इसका यह तात्पर्य है कि बिना उचित अधिकारके राज्यके द्रव्यका व्यय नहीं होना चाहिए। पहिले अधिकारियोंमें स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए और तब व्यय करना चाहिए नया स्वीकृतिसे अति व्यय नहीं करना चाहिए और जिसकार्य के लिए स्वीकृति मिली हो उसी कार्यमें व्ययभी करना चाहिए। चौथा नियम आय-व्ययके सामंजस्यका है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक अवस्थामें आय से व्यय कम होना चाहिए क्योंकि ऐसेभी अवसर आ जाते हैं जबकि राज्यको ऋण भी लेना पड़ता है। परन्तु इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए कि प्रतिवर्ष राज्यका बजट घाटेका बजट न हो।

केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय व्यय

भारतवर्ष जैसे बड़े देशोंमें राज्यका कार्य केन्द्रीय स्तरपर ही नहीं पग्नू प्रान्तीय और स्थानीय स्तरपर भी होना अनिवार्य होजाता है। कौनसा कार्य किस स्तरपर होताहै यह प्रत्येक देशकी ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थितिसे प्रभावित होता है। उदाहरणके लिए ब्रिटिश कालमें भारतवर्षमें लगभग राज्यके सभी आर्थिक कार्यों का केन्द्रीयकरण था। अब धीरे धीरे प्रान्तीयकरण होने लगा है। इसके प्रतिकूल मयुक्त राज्यमें केन्द्र अपने कार्योंके क्षेत्रको बढा रहा है। केन्द्रीय, प्रान्तीय अथवा स्थानीय राज्योंका व्यय उन कार्यों और कर्तव्योंपर निर्भर होताहै जो उनके आधीन कियेगये हो और उनके आयके साधनों परभी निर्भर होता है।

कौनसे कार्य केन्द्रीय राज्य और कौनसे प्रान्तीय अथवा स्थानीय राज्योंको सौंपे जाने चाहिए और किसप्रकार उनमें आयके साधनोंका बढवारा होना चाहिए इसका कोई प्रामाणिक रूप नहीं है। प्रत्येक देशमें उसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियोंका उमकी सामनपद्धति पर प्रभाव पडता है। साधारणतः इस बातको ध्यानमें रखना पडताहै कि कौनसे कार्य किस स्तरपर अधिक निपुणता और मितव्ययिता के साथ सम्पादित होसकने है। उम स्तरके आयके साधनोंको भी ध्यानमें रखनापडता है। सामान्य तौरपर जिन कार्योंका सम्बन्ध सारे देशसे हो अथवा जहा एक व्यापक दृष्टिकोणकी आवश्यकता हो और देशभर में एकता और समानताको ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता हो ऐसे कार्य और उनका व्यय केन्द्रीय होताहै। जिन कार्योंका क्षेत्र मरुचित होनाहै अथवा जिनका सम्बन्ध किसी स्थान-विशेषसे होताहै अथवा जिनके सम्पादनके लिए स्थानीय विशेषताया का अध्ययन करना पडनाहै और विस्तृत रूपसे निरीक्षणकी आवश्यकता होती है ऐसे कार्य प्रान्तीय अथवा स्थानीय स्तरपर सम्पादित होने चाहिए। उदाहरण के लिए बाहरी आक्रमणसे रक्षा, डाक, तार, मुद्रा तथा विदेशोंसे सम्बन्ध इत्यादि कार्य केन्द्रीय स्तरपर, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रक्षा, सडक, नहर, उद्योग धन्धे और खेती सम्बन्धी कार्य प्रान्तीय स्तरपर और प्रारम्भिक शिक्षा, जल, नाली, ट्राम, बस, रोगनी इत्यादिका प्रबन्ध स्थानीय स्तरपर अधिक कुशलताके साथ होसकता है।

राज्य के व्यय का आर्थिक प्रभाव

राज्यके व्ययका देशके आर्थिक कार्योंपर बहुत प्रभाव पड़ता है और जितनी अधिक मात्रामें राज्यका व्यय होता है उतनाही वह अधिक प्रभावात्पादक भी होता है। राज्यकी आय समाजकी आयका ही भाग होता है। यदि यह आय राज्य द्वारा व्यय न होकर समाजके व्यक्तियों द्वाराही व्यय होती तो यह सम्भव है कि वह उन मर्दानों पर और उन परिणामोंमें व्यय न होती जैसीकि राज्य द्वारा हाती है। अतएव हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि राज्य अपनी व्यय-नीतिसे समाजकी आयका एकभाग इस प्रकारके कार्योंमें लगाता है जिनमें बिना उसके हस्तक्षेपके वह न लगाया जाता अथवा कमसे कम उतनी मात्रामें न लगता। इसके परिणाम स्वरूप देशकी उत्पत्तिके साधनाके आर्थिक कार्योंके वितरणमें भिन्नता हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि उत्पत्तिके साधनोंके प्रवाहकी दिशाको बदलनेमें समाजका हितहोगा अथवा ग्रहित यह बहुत गम्भीर विषय है। हमका दो प्रकारकी आर्थिक स्थितियोंकी तुलना करनी पड़ती है। एक स्थिति समाजमें उत्पत्तिकी मात्रा और उसके वितरणमें राज्यके हस्तक्षेप करनेके पूर्वकी है दूसरी स्थिति उत्पत्तिकी मात्रा और उसके वितरणपर राज्यके अपनी व्ययनीति द्वारा प्रभाव डालनेके बादकी है। इन दो प्रकारकी आर्थिक स्थितियोंकी तुलना करनेपर यदि हम इस परिणामपर पहुँचें कि राज्यके हस्तक्षेप करनेके बादकी आर्थिक स्थितिमें समाजका अधिक हित होता है तो हम कह सकते हैं कि राज्यके व्ययसे उत्पत्तिके साधनाको भिन्न भिन्न व्यवसायोंपर वितरण करनेमें जो परिवर्तन हुआ वह वांछित है। उदाहरणके लिए यदि समाजकी कुछ आय बेकार पड़ी है और उत्पत्तिके कुछ साधनभी बेकार पड़े हों तो ऐसी अवस्थामें यदि राज्य उस द्रव्यका कर के रूपमें लेकर उत्पत्तिके बेकार साधनोंकी काममें लगामके तो इससे निस्सन्देह उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होगी। इसीप्रकार यदि राज्य अपनी कर और व्यय-नीति द्वारा हानिकारक विलासिताकी वस्तुओंसे उत्पत्तिके साधनोंकी कम कर के उनको जीवन-निर्वाह अथवा निपुणतादायक वस्तुओंके उत्पादनमें लगाये तो इससे समाजका हितही होगा। इसके प्रतिकूल यदि राज्य अपनी आयका कुछ हिस्सा बरबाद करे जिसकी समाजके सोग उपयोगी कार्योंमें लगाने तो इसमें समाजकी हानि होगी।

मोटे तौरपर हम कह सकते हैं कि राज्यके व्ययके द्वारा समाजका अधिकतम हित करनेके लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि हो, उसकी भिन्न भिन्न मदों में सन्तुलन हो, वितरणकी असमानता कम हो और आर्थिक अस्थिरतामें भी कमी हो। अब हम यह बतानेकी चेष्टा करेंगे कि राज्यके व्ययसे किसप्रकार और किस अंशतः इनमें सफलता प्राप्त हो सकती है।

राज्य के व्यय पर उत्पादन का प्रभाव

राज्यके वह व्यय जिनसे रक्षा, शान्ति और न्यायका प्रबन्ध होता है, उत्पादन कार्यके लिए आवश्यक है। परन्तु यह देखा गया है कि इन मदोंपर विशेषकर बाहरी आक्रमण से रक्षार्थके लिए बहुत व्यय किया जाना है। यदि प्रत्येक देश इस मदमें बौस प्रतिशत वृद्धि कर दे तो रक्षाका स्तर तो पूर्ववत् ही रहेगा परन्तु इसी परिमाणमें उत्पादनके साधन अन्य मदोंसे निकालकर इन मदोंपर लगाये जायेंगे। इसके प्रतिकूल यदि प्रत्येक देश अपनी रक्षाके व्ययमें बौस प्रतिशत कमी कर दे तो उत्पत्तिके कई साधन अन्य आर्थिक प्रयोजनोंके लिए बच जायेंगे जिनसे समाजका अधिक धोम होगा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय-सुरक्षा समझौते द्वारा ससारभर में शान्तिका समुचित प्रबन्ध हो सके तो इसमें प्रत्येक देशमें रक्षापर व्यय कम होगा और उत्पादनके साधन जो युद्ध सामग्रियोंके बनानेमें लगे हुए हैं, अन्य लाभदायक पदार्थोंके लिए प्राप्त हो सकेंगे।

सामाजिक दृष्टिकोणसे इस प्रकारका राज्यका व्यय वाछनीय है जिससे उत्पादन शक्ति बढ़े। इस प्रकारके व्ययमें शिक्षा, चिकित्सा, अन्वेषण, यातायातके साधन, सिंचाई और सामाजिक सुरक्षापर व्यय सम्मिलित है। इसीप्रकार पूँजीकी वृद्धि भी उत्पादनको बढ़ानेके लिए आवश्यक है। यदि राज्यकी व्यय-नीति द्वारा नयी पूँजी बनानेमें सहायता मिले तो इनमें भी उत्पात्तिकी मात्रामें वृद्धि होगी। राज्यके व्यय से उत्पत्तिके परिमाणमें ही वृद्धि नहीं होती है अपितु उत्पत्तिके अन्तर्गत भिन्न भिन्न वस्तुओंकी मात्राओंमें भी सन्तुलन किया जा सकता है। यदि समाजके हितकी दृष्टि से कपास अधिक परिमाणमें उत्पन्न करना आवश्यक हो तो राज्य इस व्यवसाय को आर्थिक सहायतादेकर प्रोत्साहन दे सकता है। आवश्यकता होनेपर राज्य स्वयं ऐसे

उद्योग धंधाका राष्ट्रीयकरण करनेकी इच्छा है जिनकी उत्पत्ति और मूल्यका नियंत्रण समाजके हितके लिए हो।

उत्पत्तिका परिमाण लोगोंकी काम करनेकी इच्छापर भी निर्भर होता है। यदि राज्यके व्ययस लोगोंके काम करनेकी इच्छामें हल्ला हो तो इसमें उत्पत्तिकी हानि होता सम्भव है। यदि लोगोंका विना किसी बाधनक राज्यमें आर्थिक सहायता मिलनेकी आशाहो तो सम्भवहै कि कुछ लोगोंपर इसका प्रभाव काममें जाचुरान पर पड़। परन्तु यदि आर्थिक सहायता बीमार पन्नपर अथवा अनिच्छामयी बकाराक समय बाजाय तो इससे काम करनेकी इच्छाधामें कमी नही होगी।

आधुनिक कालमें राज्यके व्यय द्वारा आर्थिक व्यवस्थामें स्थिरता लानेकी तथा मंदी और बकारीको कम करनेकी बहुत महत्व दिया जा रहा है। अनुभवसे ज्ञान हुआहै कि पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्थामें स्थिरता नही रहती है। समय समयपर इसमें मंदी और बकारी उत्पन्न होजाती है। राज्यका यह कर्तव्य समझा जाताहै कि वह इन व्याधियोंमें समाजको रक्षा करे। अन्य उपायोंके साथ साथ राज्यकी व्यय नीति भी इस काममें सहायता करसकती है। यह आशा कीजाती है कि अपने सावजनिक निर्माणके कार्योंके द्वारा राज्य आर्थिक मंदीकी रोकथाम करसकता है। मंदीक प्रवृत्तिपर पूँजीपति उत्पत्तिकी भावनामें क्षिपकर उत्पादक वस्तुओंके उत्पादन में कमी करदेते हैं जिससे उत्पत्तिके माधनार्थ बकारी हानिलगती है। ऐसे अवसरपर यदि राज्य सावजनिक निर्माण कायमें वृद्धि कर तो बकाराको रोजगारमिलगा उनकी आयमें वृद्धि होगी और उपभोग्य वस्तुओंकी भागमें वृद्धि होनेके कारण अन्य व्यवसायोंका उत्थान होन लगेगा। एक वानम अवश्य सावधान रहना पड़गा कि राज्य के काय अन्य व्यवसायोंमें प्रतिस्पर्धा न करें नहानो जिस परिमाणमें राज्य द्वारा उत्पादनक माधनाका काय मिलेगा उसी परिमाणमें अन्य व्यवसायोंमें बकारी होगी। यहभी आवश्यकहै कि राज्य बकारीको कम करनेके लिए कोईभी काय बिना किसी याजनाके आरम्भ न करे। इसमें उत्पत्तिके माधनाकी बरबादी होनेकी सम्भावना रहती है। मंदी और बकारी आनेके बहुत पहिलसे ही राज्यको निर्माण-कायको योजनाएँ तैयार रखनी चाहिए। इस बातका भी ध्यान रखना पड़ताहै कि इन निर्माण कायोंमें लगानेके लिए द्रव्य अधिक मात्रामें कर द्वारा नही बरन गृहणकर प्राप्त करना चाहिए। मंदीके समय द्रव्यके चलनमें वेग लानेकी आवश्यकता है।

करके भारकी अधिकतासे सम्भवहै कि पूजीके लगावकी मात्रामें औरभी कमी आ जाय। इसलिए राज्यको उस द्रव्यको जो समाजमें बकार पड़ा हुआ हो, ऋणके रूपमें प्राप्तकर उसको निर्माणके कार्यमें लगाकर उसके चलनके वेगमें वृद्धिकी चेष्टा करनी चाहिए।

राज्य के व्यय का वितरण पर प्रभाव

पूजीवादी आर्थिक व्यवस्थामें धनके वितरणमें बहुत असमानता होजाती है। अतएव यदि राज्यके व्ययके द्वारा इस असमानतामें कमी होसके तो इससे समाजके आर्थिक क्षेममें वृद्धि होगी। अनेक प्रकारसे राज्य गरीब लोगोंकी आयमें वृद्धि करके असमानता कम करसकता है, बेकारा और अपाहिजोंको आर्थिक सहायता देकर गरीबों के लिए नि शुल्क शिक्षा और चिकित्साका प्रबन्ध करके इस वर्गकी आर्थिक स्थिति सुधारी जासकती है। इसीप्रकार से मजदूरोंके लिए सम्ते मकान बनवाकर और जिन जीवन निर्वाह और निपुणता दायक पदार्थोंका गरीब लोग अधिक मात्रामें सेवन करतेहैं, उन व्यवसायोंको आर्थिक सहायता देकर उनका मूल्य कम करवाके भी इनकी वास्तविक आयमें वृद्धिकी जासकती है। आधुनिक कालमें प्रत्येक देशमें राज्यकी आयके एक बड़े हिस्सेको सामाजिक-सुरक्षाकी मदोंमें व्यय करनेकी प्रवृत्ति होरही है। इसका अधिक लाभ गरीब लोगोंको मिलता है। क्योंकि इस व्ययका एक बड़ा भाग धनी लोगोंसे बर्द्धमान कर के रूपमें लियाजाता है। इसीलिए यह आशा कीजाती है कि इस प्रकारकी नीतिसे, धनके वितरणकी असमानतामें कमी होगी।

कभी कभी राज्यके व्ययसे असमानतामें वृद्धिभी होजाती है। यदि राज्यके ऊपर बहुत अधिक ऋणहो और राज्यके माहूकार धनी वर्गके लोग हों तो उनको एक बड़ी रकम व्याजके रूपमें मिलजाती है। यदि इस रकमका कुछ हिस्सा गरीब लोगोंसे करके रूपमें वसूल कियाजाय तो इससे असमानतामें वृद्धि होगी। जिस देशमें अप्रत्यक्ष करोंकी प्रधानता है, जिनका भार अधिक मात्रामें गरीबोंपर पड़ताहै और यदि इस देशमें सामाजिक-सुरक्षाकी मदोंमें राज्य बहुत कम द्रव्य व्ययकरे तो ऐसी अवस्था में वितरणकी असमानतामें वृद्धि होगी। कुछ काल पूर्व भारतवर्षमें यह अवरुपायी।

राज्य की आय

राज्य की आय की मदे .

हम देख चुके हैं कि आधुनिक कालमें राज्यके आर्थिक कार्यों और कर्तव्याती सरया बहुत बढ गयी है और बढती जा रही है। इन कार्योंके सम्पादनके लिए राज्यको माधन चाहिए। अन्तनोगत्वा ये माधन वस्तुओं और सेवाओंके रूपमें ही होते हैं परन्तु आदिमें ये साधन राज्यको द्रव्यके रूपमें इकट्ठा करने पडते हैं। आधुनिक कालमें राज्यकी आयका एक बडा भाग जनतामे कर के रूपमें वसूल किया जाता है। यह भाग कुल आयका दो तिहाईमें तीन चौथाई तक होता है। आचीन कालमें राजाओं और राज्यके पास अपनी निजकी सम्पत्ति अधिकतर भूमिके रूपमें होती थी जिसकी आयमे राज्यके सीमित कार्य अधिकतर सम्पादित होते थे। विंशष अवस्थामें जैसे युद्धकालमें राज्य अपनी प्रजासे दबाव डालकर आवश्यक सामग्रिया प्राप्त करलता था। परन्तु आजकल राज्यके पास अपनी सम्पत्ति बहुत थोड़ी रहती है किन्तु उस की आवश्यकताए बढ गयी है। दबाव डालकर सामग्रिया प्राप्त करनेकी प्रथाभी अब बहुतकम काममें लायी जाती है। इसलिये राज्यको अपनी आयको बढानेके लिए कर-प्रणाली की व्यवस्था करनी पडी है।

कर से राज्यको सबसे बडी आय होती है। कर वह रकम है जो प्रजाको राज्यको अवश्यमेव देनी पडती है। इसके मुगतानमें इस बातका विचार नहीं होता है कि कर देनेवालाको उम रकमके बराबर राज्यसे प्राप्ति हो। करका परिमाण किस सिद्धान्त के अनुसार निश्चित किया जाना है उमका विवेचन एक स्वतन्त्र अध्यायमें किया जायगा। परन्तु कर की अपेक्षा कुछ अन्य मदे भी हैं जिनसे राज्यको आय होती है। पहिले इन मदोपर प्रकाश डालकर हम इनका वर्गीकरण करेंगे।

सबसे पहिले हम राज्यकी सम्पत्तिमें प्राप्त होनेवाली आयकी विवेचना करेंगे।

प्राचीनकालमें राज्यकी प्रधान सम्पत्ति भूमि के रूपमें थी जिसमें खेती होती थी। इनसे राज्य को पर्याप्त माना में आयहो जाती थी, परन्तु आजकल इस रूपमें राज्य के पास भूमि बहुत कम है जिसमें राज्यकी ओरसे खेती होती हो और खेतीके कार्य में उसको आय हो। जगलोके रूपमें राज्यके पास विस्तृत भूमि अब भी रहती है। जंगलोंसे विविध रूपमें जैसे लकड़ी, घास, वनस्पति और जंगलोंमें उत्पन्न हुई वस्तुओंको बेचनेमें राज्यको कुछ आय तो अवश्य ही होती है, परन्तु जंगलों को राज्य के अधीन रखनेका मुख्य उद्देश्य आय नहीं है। जंगलोंके रक्षणका मुख्य उद्देश्य बाढ़ की रोकथाम और सतहकी उपजाऊ मिट्टीको बहनेसे रोकना है। इसी प्रकार राज्य खानोवाली भूमि का भी रक्षण करता है जिसमें वर्तमान पीढ़ी सभी खनिज पदार्थों का अपने काममें साँकुर भविष्यकी पीढ़ियों को बचि न करे। लाइमेंसदारोसे राज्यको अवश्य ही रॉयल्टी (मालिकाना) मिलती है।

राज्य के उद्योग-धन्धे

१-

राज्यको कुछ आय अपने उद्योग-धन्धोंमें भी होती है। उदाहरणके लिए भारतवर्ष में केन्द्रीय सरकारको रेलवे और स्थानीय सरकारोंको ट्राम और बसोंमें आय होती है। परन्तु राज्यके उद्योग-धन्धोंका ध्येय हमेशा आयही नहीं होता है। प्रायः राज्य उन उद्योग-धन्धोंको अपने हाथमें लेता है जिनका समाजके क्षेत्रसे घनिष्ठ सम्बन्ध हो। कुछ इस प्रकारके व्यवसाय होते हैं जो समाजके लिए हितकारी हैं, परन्तु उनपर पूँजीपति अपना लगानेको तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनपर प्रारम्भिक व्यय बहुत मात्रामें करना पड़ता है और लाभकी आशा बहुत कम अथवा दीर्घकालके बाद होती है जैसे जंगल लगाना और नहरें बनवाना आदि। कुछ उद्योग-धन्धोंका राष्ट्रीयकरण इस कारण होता है कि उनका सम्बन्ध युद्धसे रहता है जैसे मन्त्र शस्त्रोंके कारखाने। कुछ सार्वजनिक सेवाएँ जैसे पानी, बिजली इत्यादि इस प्रकारकी होती हैं जिनका यदि राज्य द्वारा प्रबन्ध न हो तो स्वतन्त्र एकाधिकारियों के हाथमें पड़नेमें उनके मनमाने मूल्य लिये जाने की सम्भावना रहती है। अतः हम देखते हैं कि इनका प्रबन्ध म्यूनिसिपैलिटियों द्वारा होता है। कभी कभी एकाधिकारी की शक्ति को कम करनेके लिए और प्रतियोगिताका समावेश करनेके लिए भी राज्य

को उस व्यवसायमें हिस्सा लेनेको प्रेरित किया जाता है। हानिकारक पदार्थोंके उत्पादन और व्यापारका नियन्त्रण करनेके लिएभी राज्य ऐसे धन्यको अपने अधीन रखना चाहता है। भारतवर्षमें अफीमका व्यापार इसका उदाहरण है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य केवल आयके निमित्त ही उद्योग-धन्धोंको अपने हाथमें नहीं लेता है। इस नीतिके अन्तर्गत राज्यके उद्योग-धन्धोंमें उत्पन्न हुई वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य निर्धारण करनाभी रहता है। यदि राज्यको अपनी आय अधिकतम करनेकी हो तो वह ऐसे मूल्य निर्धारित करेगा जिनमें उसको अधिकतम लाभ हो। परन्तु अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ यह मूल्य केवल लागतके बराबर होता है। कभी कभी बिना मूल्यके भी राज्यमें सेवाएँ और वस्तुएँ मिलती हैं। उनको सागन राज्यकी आयसे पूराकी जाती हैं। पोस्टकार्डों को केवल लागत पर बेचना, मजदूरों को लागतमें कम किराये पर भूतान देना, निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा इसके उदाहरण हैं। आरुढ़ासे पता चलता है कि राज्यके उद्योग-धन्धोंमें अधिक आय नहीं होती है। वर्तमान कालमें कुछ राज्य प्रधानतः आयके लिए कुछ उद्योग-धन्धाका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। यदि बड़ी मात्रा में इस प्रवृत्ति का विनाश हो तो सम्भव है कि भविष्यमें इन मदोंसे राज्यको पर्याप्त आय हो सके।

प्रणामनकारी आय

३८

सासन सम्बन्धी कार्योंमें भी राज्यको कुछ आय हो जाती है। राज्यके कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनका उपयोग करनेके लिए फीस देनी पड़ती है। उदाहरणके लिए न्यायालयका उपयोग करनेके लिए कोर्टफीस देनी पड़ती है। इसी प्रकार दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री करानेके लिए फीस देनी पड़ती है जिसमें उसपर राज्यकी मुहर लग जानमें दस्तावेज सम्बन्धी लगे-देने अथवा ग्रह-विशेष राज प्रमाणित हो जाता है। जनताको अनेक उद्योग-धन्धोंको चलानेके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस प्राप्त करनेसे विभी कामको करनेकी अनुमति मिल जाती है और लाइसेंस लेनेके लिएभी रुपया जमा करना पड़ता है जिससे राज्यको आय होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फीस और लाइसेंस से आयके साथ साथ नियन्त्रणका

कामभी लिया जाता है। यह नहीं समझना चाहिए कि फीससे विभागका पूरा व्यय निकल आता है। फीसकी दर निर्धारित करते समय इस बातको महत्व नहीं दिया जाता है।

घोड़ीसी आय राज्यको जुमाने और दंडसे भी होजाती है। राज्यके नियमोंका उल्लंघन करनेपर दंड दियाजाता है। कभी कभी यह दंड द्रव्यके रूपमें वसूल कियाजाता है, जिसको जुर्माना कहते हैं। कुछ आय भेंटके रूपमें भी होजाती है। कुछ लोग राज्यको पाठशाला, चिकित्सासय, पुस्तकालय खोलनेके लिए रुपया देतेहैं अथवा युद्धके समय रुपयो और अन्य वस्तुओंसे सहायता करते हैं। कभी कभी लावारिस माल भी सरकारके हाथ लगजाता है। परन्तु इनसब मदोंकी आय बहुतही कम होतीहै और इस पर अधिक भरोसा नहीं किया जासकता है।

एक विशेष प्रकारका देय होताहै जो कर से मिलता जुलता होताहै। राज्य इस देयको उन लोगोंसे वसूल करताहै जिनकी सम्पत्तिको उसके किमी कार्य विशेष से प्रत्यक्ष लाभ हुआहो और इस देयके अनुपातका आधार लाभकी मात्रा रहती है। उदाहरणके लिए यदि किसी स्थानमें पानीके बहावका उचित प्रबन्ध किया गयातो उससे उस स्थानके मकानों और दुकानोंका मूल्य बढ़ जायगा। नाली बनानेमें, मड़कको ठीक करने इत्यादिमें म्यूनिसिपैल्टीका जो व्यय हुआ उसको वह इस विशेष देयद्वारा उन लोगोंसे वसूल करलेतीहै जिनके मकानों अथवा भूमिके मूल्यमें वृद्धि हुई। यह देय अनिवार्य होताहै और इसीलिए यह कर से मिलता जुलताहै परन्तु यह एक विशेष लाभके बदलेमें लियाजाताहै इसकारण यह कर से भिन्न है।

प्राचीन कालमें विशेषकर युद्धकालीन सकटावस्थामें कई राज्योंने अविनिमय-साध्य नोटोंको छापकर उममें अपनी आय बढ़ाई और उससे सैनिकोंको वेतन देनेका और सामग्रियोंके मूल्यके भुगतान करनेका काम लिया। इससे द्रव्यके अत्यधिक प्रसार होनेके कारण तमाम्मन्वी आर्थिक व्याधियोंका मृजन होता है। अतएव आधुनिक कालमें यह उपाय बहुत निन्दात्मक समझा जाताहै और इसका प्रयोगभी इस रूपमें नहीं कियाजाता है। एक असाधारण प्रकारकी आय ऋण लेनेसेभी होती है। यह असाधारण इसलिए है कि भविष्यमें इसको लौटाना पड़ता है। इस विषय का आजकल बहुत महत्व होगया है। इसीलिए हम इसको एक स्वतन्त्र अध्याय देंगे।

राज्य की आय का वर्गीकरण

जिस सिद्धान्तपर राज्यके व्ययका वर्गीकरण किया गया था, उसी सिद्धान्तपर आय का वर्गीकरण भिन्न भिन्न लेखकोंने भिन्न भिन्न आधारपर किया है। इनमेंसे मुख्य मुख्य वर्गीकरणों को आगे दिया जाता है।

एक पुराने वर्गीकरणके अनुसार राज्यकी आयको दो हिस्सोंमें विभाजित किया गया है। एक हिस्सेमें राजा अथवा राज्यकी सम्पत्तिकी आय और दूसरे हिस्सेमें प्रजामें प्राप्त आय रखी जाती है। एक और वर्गीकरणसे आयके तीन भाग किये गये हैं। पहिले भागमें वह आय है जो राज्यको अपनी सम्पत्तिसे, अपने उद्योग-धन्धोंसे, दान और भेंटमें अथवा अपहरणसे प्राप्त होती है। दूसरे भागमें वह आय है, जो कर, फीस, विशेष-देय और जुमानिसे प्राप्त होती है। तीसरे भागमें वह आय शामिल है जो ऋणसे प्राप्त होती है। तीसरे वर्गीकरणके भी तीन भाग हैं। पहिले भागमें वह आय है जो स्वतन्त्र रूपसे होती है जैसे दान, भेंट। दूसरे भागकी आय नियन्त्रित होती है जैसे राज्यकी सम्पत्ति और उद्योग-धन्धोंसे आय। तीसरे भाग में अनिवार्य-देय आय शामिल है जैसे कर, फीस, जुमाना विशेष देय इत्यादि। एक और वर्गीकरणमें राज्यकी आय दो भागोंमें विभक्त है। पहिले भागको 'साधारण आय' कहते हैं जिसमें कर, फीस, राज्यकी सम्पत्ति और उसके उद्योग-धन्धोंकी आय शामिल है। दूसरे भागको 'असाधारण आय' कहते हैं। इसमें राज्यकी सम्पत्तिको बेचनसे अथवा ऋणसे प्राप्त होनेवाली आय शामिल है। आधुनिक कालमें जो वर्गीकरण प्रचलित है उसके अनुसार राज्यकी आयके दो बड़े भाग किये गये हैं। पहिले वर्गमें वह सब आय शामिल है जो करोंसे प्राप्त होती है और करोंके अतिरिक्त आय जैसे राज्यकी सम्पत्ति और व्यवसायोंमें प्राप्त, प्रशासन सम्बन्धी मदोंसे प्राप्त और ऋणसे प्राप्त दूसरे भागमें रखी गयी है।

राज्य की अच्छी आय-पद्धति की विशेषताएँ

राज्यकी आय-पद्धति को समाजके आर्थिक कार्योंमें एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतएव इसकी व्यवस्था और न्यायपर विशेष ध्यान देना पड़ता है। आधुनिक

कालमें सभी देशोंकी आय पद्धतिमें करोंको विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसी मद से अधिनगम आय होती है। इसीलिए अच्छी आय-पद्धतिकी विशेषताएं अच्छी कर-प्रणालीपर अधिग्रहण रूपसे लागू होती हैं।

एकजान ध्यानमें रखनीहै कि सारी आय-पद्धतिकी सम्पूर्ण रूपसे देवना चाहिए। उसके एक हिस्सेको लेकर किसी निर्णय पर पहुँचना उचित नहीं है। प्रायः ऐसा सम्भव है कि एक कर अलगसे इस प्रकारका है जिसका भार गरीब लोगपर अधिक हो परन्तु दूसरी ओर यह भी होसकता है कि सभी करोंका सामूहिक प्रभाव इस प्रकारका हो कि उनी लोगपर अधिक भार और गरीबोंपर कम भार पड़े। अच्छी आय-पद्धतिकी अवयव मनुष्यनिरूपमें एक दूसरेमें सम्बन्धित होने चाहिए। उनमें विरोधलता नहीं होनी चाहिए। यदि राज्यकी आयको बढ़ाना है तो यह नहीं होना चाहिए कि आयकी किसी मदको लेकर उसकी दर बढ़ा दी जाय। प्रत्येक मदको पूरे प्रकरणमें अध्ययन करके किसी निश्चय पर पहुँचना चाहिए।

अच्छी आय-पद्धतिवा मुख्य गुण यह है कि समाजके ऊपर उसका भार कमसे कम हो। यह सभी होसकता है जबकि भिन्न भिन्न श्रेणीके व्यक्तियोंपर उसका भार उचित रूपसे विभाजित हो। उदाहरणके लिए यह मानीहुई बात है कि अप्रत्यक्ष करोंका भार गरीबोंपर अधिक होता है और आयकरोंका धनीलोग पर। अतएव यदि किसी देशमें अप्रत्यक्ष करोंकी प्रधानता हो तो कर-प्रणाली व्यायानुकूल नहीं रही जगजगी है। इस विषयपर अधिक प्रचार आगे अध्यायमें डाला जायगा।

उत्पादक आय पद्धति एक विशेष गुण सम्भवा जाता है। यदि और सब बातें यथावत् हों तो वह आय-पद्धति अधिक उपयुक्त समझी जाती है जो अधिक उत्पादक हों। राज्यकी आयकी आवश्यकता है। यदि पद्धतिमें और सभी गुण विद्यमान हों, परन्तु आय बहुत अपर्याप्त हो तो ऐसी आय-पद्धति किस काम की। अतएव आय-पद्धतिकी और उसके अवयवोंकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे राज्यको पर्याप्त मात्रामें अनवरत आय होती रहे। इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आय अनवरत हो। यदि राज्य एकही वर्ष जगजगी सभी पेड़ काटकर लकड़ी बेच डाले तो इसमें उस वर्षमें तो बहुत आय होगी परन्तु अगले वर्षोंमें जगलोसे प्राप्त आय बन्दहा जायगी। इसीप्रकार यदि करोंकी दर इतनी बढ़ा दी जाय कि पूँजी-

पतियोका उत्साह भग होजाय और उत्पत्तिकी मात्रा और राष्ट्रीय आयका ह्राम होनेलगेतो इससेभी राज्यकी आय कम होने लगेगी। अन्ततोगत्वा राज्यकी आय समाजकी आयपर निर्भर है। यदि समाज सम्पन्न होगा तो राष्ट्रभी अपनी आय सुगमतासे बढ़ा सकेगा। इसलिए यह आवश्यकहै कि कर इस प्रकारके हो और ऐसे मादामें लगाये जायें कि उत्पत्तिके श्रोत मूलने न पायें। जहातक इसके राज्य को अपनी आय-पद्धतिको देशकी आर्थिक-पद्धतिके अनुकूल बनाकर उत्पादन कार्योंमें स्थिरता और वृद्धि लानेकी चेष्टा करनी चाहिए, उत्पादनके अन्तर्गत आय को एकत्र करनेमें मितव्ययिता भी शामिल है।

अच्छी आय-पद्धतिमें लोच हानाभी आवश्यकहै अर्थात् आय-पद्धति और उसके प्रवयव इस प्रकारके होने चाहिए कि आवश्यकतानुसार उनसे आय सुगमतासे घटायी और बढ़ायी जासके। कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होजाती है जंमे युद्धकाल में जबकि वीरतासे आयको बढ़ानेकी आवश्यकता पडजाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि आय-पद्धतिमें लोच न होतो उसको समायानुकूल नहीं बनाया जासकता। आयमें आवश्यकतानुसार घटबढ़ करनेके लिए दो बातोंको ध्यानमें रखना पडता है। एकतो यह कि पद्धतिकी मदें विस्तृतहो और दूसरी बात यहहै कि साधारण अवस्थामें इनमधी मदोमे अधिकतम प्राप्य आय वसूल न कीजाय अर्थात् सकटावस्था के लिए कुछ अवकाश रखना चाहिए।

आय-पद्धतिमें विशेषकर कर-प्रणालीमें एकबात ध्यानमें रखनी चाहिए कि कर देनेवालों की अकारण कष्ट और भय न हो। राज्यके प्रति उनका मद्भाव बनारहे इसकेलिए यह आवश्यकहै कि कर का परिमाण निश्चितहो और देनेकी विधि और काल सुविधाजनक हो। कर वसूल करनेवाले कर्मचारी स्वेच्छाचारिता न करने पावें। साथही आय पद्धति सुगम और सुबोध होनी चाहिए। इससे भी कर वसूल करनेमें सहायता मिलतीहै और करदेन वालाका विरोधभी कम होजाता है।

जंसा हम ऊपर सकेन करआयेहे, आय-पद्धति विस्तृत होनी चाहिए अर्थात् एक या दो मदो तरुही सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगले अध्यायमें हम एककर-प्रणाली और बहुकर-प्रणालीकी विवेचना करेंग। यहापर इतनाही बहकर हमें इसप्रकरणको समाप्त करतेहे कि भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न भिन्न प्रकारमे कर प्राप्त करनेमें सुविधा, सुगमता और मितव्ययिता होती है।

कर-प्रणाली

कर की उत्पत्ति और विकास

पिछले अध्यायमें बताया गया है कि आधुनिक कानून राज्यकी आयका एक बहुत बड़ा हिस्सा करोस प्राप्त होता है जो प्रजासे अनिवार्य रूपसे राज्यके कार्योंके लिए वसूल किये जाते हैं। आजकल करोकी अनिवार्यताका विरोध नहीं होता है, परन्तु प्रारम्भमें जब इस नीतिका प्रयोग किया गया तब इसका विरोध हुआ। लोगोंको इस बातका विश्वास धीरे धीरे हुआ कि करोसे राज्यको जो आय होनी है, उसको राज्य ऐसी मदामें व्यय करता है जिनमें समाजके व्यक्तियोंकी हम प्रकारकी आवश्यकताओंकी पूर्ति होती है जिनको वे व्यक्तिगत स्तरपर अच्छी तरह पूरी नहीं कर सकते हैं। यदि पूरी कर भी सकें तोभी उनको अपना व्यय करना ही पड़गा। उदाहरणके लिए राज्य द्वारा रक्षा शिक्षा और चिकित्सा इत्यादिका प्रबन्ध होता है। इनसे सभीको लाभ होता है और यदि राज्य इनका प्रबन्ध न करता तो व्यक्तिगत रूपसे इनका प्रबन्ध करना पड़ता। जब लोग कर देते हैं तो उनको यह समझकर सन्तोष करना चाहिए कि इन मदोंपर स्वयं व्यय न करके वह अपना राज्यको देते हैं जो इनका प्रबन्ध करता है। यहा तक बात समझमें आती है कि समाजके लोगों को अपने हितके लिए राज्यको साधन उपलब्ध करने चाहिए। अन्ततोगत्वा इन साधनोंकी आवश्यकता श्रम तथा वस्तुओंके रूपमें होती है। द्रव्यमयी आर्थिक पद्धतिमें यह साधन द्रव्यके रूपमें ही अधिक उपयुक्त होने है। परन्तु जब यह प्रश्न उठता है कि कौन व्यक्ति कितना दे तब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किस व्यक्तिसे कितना रकमा कर के रूपमें लिया जाय इसको अधिकारियोंकी स्वेच्छाचरितापर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसका निर्णय किसी सिद्धान्तके अनुसार होना चाहिए।

कर के सिद्धान्त

इस प्रकरणमें दो सिद्धान्त प्रतिपादित हुए हैं। इनमेंसे एकको 'लाभ-सिद्धान्त' और दूसरेको 'शक्ति अथवा क्षमता सिद्धान्त' कहते हैं। लाभ-सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको राज्य-कोषमें इतना द्रव्य कर के रूपमें देना चाहिए जिसके बराबर राज्य के कार्योंसे उसको लाभ हुआ हो। सरसरी तौरपर बातों की मालूम देती है कि यदि राज्यको कर इसलिए दियेजाने हैं कि उनसे समाजका लाभ होता है तो प्रत्येक व्यक्तिको लाभके अनुपातमें ही कर देना चाहिए, परन्तु जब इस सिद्धान्तको कार्य रूपमें परिणत करनेकी चेष्टा कीजानी है तो कई समस्याएँ सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि राज्यद्वारा अनेक प्रकारकी सेवाएँ उपलब्ध होती हैं जिनमें से कई ऐसी हैं जिनसे प्राप्त लाभको व्यक्तिगत स्तरपर मापना असम्भवमान ही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, उत्तर प्रदेशकी सरकार ६ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पुलिस पर व्यय करती है जिसमें प्रान्तमें शान्ति बनी रहे। इस सामाजिक सेवासे कितना लाभ श्री उमाकान्तको हुआ, इसकी रुपये-आने-पार्षमें प्रकट करना असम्भव माना पड़ता है। यही समस्या सेनापर, स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी कार्योंपर और एडवांस व्ययकी भी है। यदि किसी प्रकारसे इस बातका हिसाब लगाभी लिया जाय कि प्रत्येक व्यक्तिको राज्यके कार्योंसे कितना लाभ हुआ तो दूसरी समस्या यह उत्पन्न होती है कि क्या प्रत्येक व्यक्तिमें प्राप्त हुए लाभके अनुसार कर वसूल करना न्याय-संगत है। इस युगमें राज्य अपनी आयका एक बड़ा हिस्सा ऐसे कार्योंमें व्यय करता है जिससे निर्धना, अपाहिज, बेकार, विधवा, अनाथ और बूढ़ा इत्यादि प्रकार के वर्गोंको लाभ होगा है। क्या इन लोगोंसे यह कहना न्यायसंगत होगा कि जितना लाभ उनको राज्यद्वारा हुआ हो उसी अनुपातमें वे कर के रूपमें राज्य-कोषमें रूपया जमा कर दें? यह तो भूखताकी दान होगी। अतः इस लाभ-सिद्धान्तके बारेमें हम इतनाही कह सकते हैं कि सार समाजके दृष्टिकोणसे इस दानमें कुछ सार है कि सबको मिलकर राज्यको समाज-हित कार्यों के लिए पर्याप्त द्रव्य कर के रूपमें देना चाहिए। परन्तु प्रत्येक व्यक्तिके भागका निर्णय इस सिद्धान्तके आधारपर करना बहुत कठिन ही नहीं, प्रत्युत अनेक परिस्थितियोंमें अनुचित भी है।

लाभ-सिद्धान्तका ही प्रतिरूप एक सिद्धान्त और भी प्रतिपादित किया गया है

जिनको लागत-पूरक अथवा क्षति-पूरक सिद्धान्त भी कहते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार राज्यको लागतके अनुपातमें कर लेना चाहिए अर्थात् किसी व्यक्तिको कोई सेवा उपलब्ध करनेमें जितना राज्यका व्यय होता है उतनाही उस व्यक्तिमें कर लेना चाहिए। इस सिद्धान्तको कार्यरूपमें परिणत करनेमें भी बड़ी कठिनाइयां होती हैं जिनका लाभ-सिद्धान्तमें विवेचन किया जा चुका है। मार्वजनिन सेवाओंको उपलब्ध करनेसे राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्तिको जो लाभ हुआ हो उसमें राज्यकी जिनकी लागत लगी इसका हिसाब लगाना बहुत कठिन काम है और अनक व्यक्ति एमें है जो इस लागतको नुकता करनेमें प्रमथ्य हैं।

..

शक्ति अथवा क्षमता सिद्धान्त

दूसरा सिद्धान्त शक्ति अथवा क्षमता सिद्धान्त है। इस सिद्धान्तके अनुसार जनताको अपनी शक्ति और सामर्थ्यके अनुसार राज्यको कर देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि सभीको राज्यकी सेवाओं उसी अनुपातमें लाभ हा। देखनेमें यह सिद्धान्त अमर्षित मानूम होता है कि जो जितना देसकता है उतनादे और बाहरी तौरपर आधुनिक कर-प्रणालियां इसीके आधारपर बनी मालूम पड़ती हैं, परन्तु इस सिद्धान्त के अनुसार कर का परिमाण निर्धारित करनेमें भी अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। पहिली कठिनाई यह है कि कर देनेकी शक्ति अथवा सामर्थ्य किस वस्तुमें नापी जाय। व्यवहारमें तीन मापदंड काममें लाये गये हैं (१) सम्पत्तिका परिमाण (२) आय (द्रव्यके रूपमें) का परिमाण और (३) व्ययका रूप। इन तीनोंमें से अनुभवके आधारपर आयका परिमाण कर देनेकी क्षमताको नापनेके लिए अधिक सुगम और उपयुक्त समझा गया है अर्थात् लोग अपनी आयके अनुसार कर दें। तो क्या हम इससे यह परिणाम निवास सकते हैं कि बराबर आयवा नाके कर देनेकी क्षमता भी बराबर होती है। वास्तवमें यह बात नहीं है। दो व्यक्तियोंमें जिनकी आय बराबर हो वडे कुटुम्ब वालेकी क्षमता अविवाहित अथवा छोटे कुटुम्ब वालेसे कम होती है। इसीप्रकार अपने व्यक्तिगत परिश्रमसे उपार्जित आयमें श्रेयर बौद्ध, मकान मंदिर सम्पत्तिसे प्राप्त की हुई आयसे कम कर-क्षमता होती है, क्योंकि बीमारी, बेकारी और बुढ़ापेमें श्रमकी शक्ति क्षीण होनेसे आय कम या बन्द होजानी है, परन्तु सम्पत्ति

से आय मिलती रहती है। समान आय होनेपर स्थिर आयमें अस्थिर आयसे अधिक कर-क्षमता होती है। इसप्रकारके अपवादोंको ध्यानमें रखकरही आयके परिमाण को कर-क्षमताका माप-दंड समझा जाता है।

परन्तु इतनेही पर हमारी कठिनाइयोंका अन्त नहीं होजाता है। यह माना कि अन्य बाने समान होनेपर अधिक आय वालेकी कम आय वालेसे अधिक कर-क्षमता होती है, परन्तु कितनी अधिक? क्या कर-क्षमता उमी अनुपातमें बढ़ती है जिस अनुपात में आय बढ़ती है या उससे अधिक अनुपातमें? इस प्रश्नका उत्तर देनेसे पहिले हमको कुछ गहराईमें उतरना पड़ता है। जब मनुष्य कर देने है तो वास्तवमें वे उन वस्तुओं और सेवाओंकी तृप्ति (तुष्टि) का त्याग करने हैं जो उम द्रव्यसे प्राप्त होती है। उदाहरणके लिए जो व्यक्ति दस रुपया कर देता है वह दस रुपयेसे जिन वस्तुओं और सेवाओंको मौल्यलेता उनसे प्राप्त होनेवाली तुष्टिका त्याग करता है और जो व्यक्ति बीस रुपया कर देता है वह बीस रुपयेके व्ययसे प्राप्त तुष्टिका त्याग करता है। एक मत यह है कि भिन्न भिन्न आयके व्यक्तियोंको इतना कर देना चाहिए जिसमें उनकी तुष्टि-त्यागकी मात्रा बराबर हो। हमारे उदाहरणमें यदि दस रुपया कर देनेवाले की आय दोस्रो रुपया और बीस रुपया कर देनेवाले की आय चारसौ रुपया प्रतिमास होती क्या हम कहसकते हैं कि कर देने से उनका समान तुष्टि-त्याग हुआ? क्रमागत-उपयोगिता-ह्रास-नियमके अनुसार जैसे जैसे आयमें वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे आयकी सीमांत उपयोगिता कम होनी जाती है। यह सम्भव है कि दोस्रो रुपया आयवालेको दस रुपया कर देनेमें चारसौ रुपया आयवालेके बीस रुपया कर देनेकी अपेक्षा अधिक तुष्टि त्याग करना पड़नाहो। क्योंकि पहिले व्यक्तिको कुछ जीवन-रक्षक अथवा निपुणतादायक पदार्थोंसे अपनको वचित करना पड़ताहो और दूसरे व्यक्तिको सम्भव है कुछ बिलासिताकी वस्तुओंका उपभोग कम करना पड़े। अतएव समान तुष्टि-त्यागके सिद्धान्तके अनुसार अधिक आयवालोंको कम आय वालोंकी अपेक्षा अधिक अनुपातमें कर देना चाहिए अर्थात् समान तुष्टि-त्यागके लिए दोस्रो रुपये आयवाले व्यक्तिको दसमें कम कर देना चाहिए। एक सिद्धान्त यह भी है कि राज्यको इस परिमाणमें कर लेना चाहिए जिससे समाजका तुष्टि-त्याग न्यूनतम हो। इस सिद्धान्तके अनुसार कर-प्रणाली बनानेमें गरीब लोगोंसे एक निर्धारित सीमातक बिल्कुल कर नहीं लेना चाहिए। उसके ऊपरकी आयमें वर्धमान कर लगाना

चाहिए। इस प्रकरणमें हम यह बता देना चाहते हैं कि भिन्न भिन्न व्यक्तियोंके आयकी सीमान्त-उपयोगिताको नापनेका कोई साधन नहीं है। इसलिए उनकी तुलना करना कठिन है। यह तुलना एक विचारयुक्त अनुमानके आधारपर की जाती है।

वर्धमान और आनुपातिक कर

वर्धमान-कर उसको कहते हैं जिसकी दर आयकी वृद्धिके साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे दामो रुपया मासिक आयपर पांच प्रतिशत, चारसी की आयपर दस प्रतिशत, आठसी की आयपर बीम प्रतिशत इत्यादि। आनुपातिक कर में कर की दर समान रहती है चाहे आयका परिमाण कुछभी क्यों न हो। यदि पांच रुपया प्रतिशत आय-कर हो तो पूर्वोक्त उदाहरणमें दोसौकी आयपर दस रुपया, चारसी की आयपर बीम रुपया और आठवीं की आयपर चालीम रुपया कर देना पड़ता। स्पष्ट है कि दम रुपया, बीम रुपया और चालीम रुपया कर का परिमाण दोसौ रुपया, चारसी रुपया और आठवीं रुपया आयके परिमाणके अनुपातमें है। अब नीचे दी गयी तालिकापर ध्यान दीजिए:

आय	आनुपा- तिक कर की दर	कर का परिमाण	बची आय	वर्धमान कर की दर	कर का परिमाण	बची आय
२०० रु	५ %	१० रु	१९० रु	५ %	१० रु	१९० रु
४०० रु	५ %	२० रु	३८० रु	१० %	४० रु	३४० रु
८०० रु	५ %	४० रु	७६० रु	२० %	१६० रु	६०० रु

इस तालिकासे एक बात स्पष्ट है कि आनुपातिक दर लगानेसे कर का परिमाण आय के परिमाणके अनुपातमें ही है और कर देनेके बाद जो आय बच जाती है वह भी उसी अनुपातमें रहती है जिस अनुपातमें पहिले थी। इसके समर्थकोंके अनुसार यह आनुपातिक कर की विशेषता है कि कर देनेके बाद भी कर देने वालोंके पारस्परिक

आर्थिक स्तरमें कोई बदलाव नहीं होना है। इन लोगोंके अनुसार राज्यको अपनी कर-नीति द्वारा भिन्न भिन्न आर्थिक वर्गोंकी पारस्परिक आर्थिक स्थितिमें विषमता पैदा नहीं करनी चाहिए। जैसाकि हम नीचे समझाएंगे यह तर्क ठीक नहीं है। एक बात और इस बारे में पहले यह कही जाती है कि यह एक सुझाव सोचा कर है जो बहुत आसानीसे समझमें आ जाता है और इसकी गणितभी भुगमनामें आती है। परन्तु केवल सिधार्थही कर का गुण नहीं मना जा सकता है।

ऊपर दीगयी तालिकामें वर्धमान कर का भी विवरण दिया गया है। अधिक आय पर कर की दरभी अधिक है और कर का परिमाणभी आयके अनुपातकी अपेक्षा अधिक है। बची हुई आयका देखनेमें पता चलता है कि उमरा वितरण पहिलेमें कम विषम हो गया है। इस तरह के समर्थक अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिए समानतुष्टि-त्याग और न्यूनतम तुष्टि-त्यागके सिद्धान्तका सहारा लेते हैं। इनका कहना है कि क्यों-कि आयकी वृद्धिके साथ साथ उमकी सीमान्त-उपयोगिता घटती जाती है और बहुत अधिक आयके स्तरोंपर सीधतामें कम होती है, अतएव समान तुष्टि-त्याग और न्यूनतम तुष्टि-त्यागके दृष्टिकोणसे वर्धमान कर का प्रयोग होना चाहिए। एक विशेष बात वर्धमान कर के सम्बन्धमें यह है कि इसके द्वारा राज्यको पूँजीवादके अन्तर्गत सम्पत्ति और आयके वितरणकी विस्तृत विषमताको कम करनेमें सहायता मिलती है। समाजका क्षम अधिकस अधिक बनानेके लिए यह आवश्यक है कि वितरणकी विषमतामें कमी की जाय और इसके सम्पादनके लिए कर नीतिका प्रयोग एक वांछित उपकरण सिद्ध हुआ है। वर्धमान कर में एक बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए कि कर की दर इसप्रकार की न होना चाहे जिसमें पूँजी मजदूरोंके कार्यमें और उत्पादनके माधनोंको काममें लगानमें निश्चिन्ता आजायें।

वर्धमान कर के विपरीत ह्राम-मान कर होता है जिसकी दर आयकी वृद्धिके साथ साथ घटती जाती है। इसप्रकार के कर को किसी सिद्धान्तपर भी व्यासगत नहीं ठहराया जाता और प्रत्यक्ष रूपसे यह प्रयोगमें नहीं आता। परन्तु अप्रत्यक्ष रूपमें कभी कभी इसप्रकार का परिणाम देखनेमें आता है। उदाहरणके लिए अंग्रेजी राज्यमें भारतवर्षमें नमकके कर का भार धनी लोगोंपर कम और निम्नतर पर अधिक था।

कर-क्षमता-सिद्धान्तके पक्षमें अनेक बातें कही गयी हैं जिनके राज्यके अधिकारियों

को मान्यभी है। परन्तु जब हम कर-प्रणालियोंका अध्ययन करतेहैं तो हमको कही भी ऐसी प्रणाली नहीं मिलती जिसका आधार केवल यही सिद्धान्त हो। उदाहरण के लिए परोक्ष करो का भार विनोदकर उन वस्तुआपर लगनेवाले करोका जिनका उपयोग गरीब जनता करतीहै, धनी लोगोकी अपेक्षा गरीबोपर अधिक पड़ता है। परन्तु किसीभी राज्यमें अभीतक इनका प्रयोग छोड़ा नहीं गया है। परिस्थितिके अनुसार कर प्रणाली प्रभावित होतीरहती है।

प्रत्यक्ष और परोक्ष कर

हम प्रकरणमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का भेद स्पष्ट कर देना उचित होगा। प्रत्यक्ष करोस प्रायः ऐसे कर समझे जातेहैं जिनका भार वहीलोग वहन करतेहैं जिनपर कर लगाया जानाहै अर्थात् कर देनेवाले उसको दूसरे लोगोमें वमूल नहीं करसकते हैं। इसके विनिष्ट उदाहरण आय कर, सम्पत्ति-कर और उत्तराधिकारी-कर हैं। इसके प्रतिकूल परोक्ष कर उनको कहतेहैं जिनका भार प्रारम्भिक कर देनेवाला पूरे अथवा आंशिक रूपमें अपने कंधोंसे उतारकर दूसरोके कंधोंपर ढाल देताहै अर्थात् वहभी कर की रकमका पूरा अथवा उसका कुछ हिस्सा दूसरे लोगोमें अपनी आर्थिक गियाओके द्वारा वमूल करलेता है। अतः वास्तवमें राज्यको कर दूसरेही लोगोसे प्राप्त होता है। इसके उदाहरण आयात-निर्मान-कर, बिक्री-कर और उत्पत्ति-कर हैं। सशेषमें परोक्ष कर वहहै जो दूसरोपर ढाला जासकताहै और प्रत्यक्ष कर वहहै जो दूसरोपर ढाला नहीं जासकता है। एक और प्रकारसे भी यहभेद स्पष्ट समझाया गया है। प्रत्यक्ष कर मनुष्योंपर और परोक्ष कर वस्तुओंपर लगाये जाते हैं। अतः प्रत्यक्ष करोको वर्धमान किया जासकता है, परन्तु परोक्ष करोको वर्धमान करनेमें कठिनाई पड़ती है। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर का भेद वास्तविक नहीं है। उदाहरण के लिए किसी वस्तुपर आयात-कर लगाया गया, परन्तु किसी कारणसे उसपर का बोझ उस वस्तुके भेजनेवाले परही रहगया अर्थात् वह अपनी वस्तुके मूल्यको बढ़ा न पाया जिससे वह कर वमूल करपाता। चूंकि कर का भार दूसरोपर न ढाला जा सका इसलिए इसको प्रत्यक्ष कर समझना चाहिए, परन्तु साधारणतः वस्तुओंपर लगाया गया कर परोक्ष समझा जाता है।

एककर प्रणाली और बहुकर प्रणाली

आधुनिक कालमें राज्य अनक प्रकारके कर लगाताहै और उनकी मर्याद बढ़ती जा रही है। परन्तु समय समयपर कर-प्रणालीको मसिप्त बनानेके विचार प्रकट किये गये हैं। इस प्रकरणमें एककर-प्रणालीको विशेष रूपसे चर्चा हुई है। फ्रान्सको एक आधिक विचार-धाराके लोगो (जिनको सिजियोनेन्स कहते हैं) के कथनानुसार राज्यको केवल एकही कर लगाना चाहिए क्योंकि उनकी धारणा थी कि आधिक पद्धतिमें कर जाहे वहीपर लगाया जाय घूमफिरकर वह अन्तमें भूमि-कर परही बसेगा। जैसाकि हम अगले अध्यायमें बनायेंगे उनकी यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण थी। कुछ समय ठुमा अमेरिकामें हन्री जॉन् नेभी एककर प्रणालीके लिए बहुत प्रयत्न किया था। उनकाभी यही कहनाथा कि राज्यको केवल एक भूमि-करही लगाना चाहिए। उसका एक कारण यहहै कि भूमि-कर उद्योग-धन्वाके विकासमें बाधा नहीं पहुँचायगा, परन्तु प्रधान कारण यह बताया जाताहै कि भूमिकी एक विशेषता यहहै कि वह प्रकृतिकी देनहै और क्योंकि भूमिका क्षेत्र परिमितहै अतएव जनसंख्या की वृद्धिमें भूमिकी माग और उसका मूल्य बढ़ताजाता है। मूल्यमें यह वृद्धि जो किसी व्यक्ति विशेषके उद्योगमें नहीं हुईहै समाजको प्राप्त होनी चाहिए अतएव राज्यको इसे कर के रूपमें लाना चाहिए। इस तर्कमें एक कठिनाई यह मान्य पड़तीहै कि भूमिके किसी टुकड़की मूल्य-वृद्धिमें कितना हिस्सा जनसंख्या और माग की वृद्धिके कारणहै और कितना हिस्सा उसके स्वामीकी पूँजी और परिश्रमके कारण। बिना इस बातका विचारकिय जा भूमि कर हेनरी जॉन्की योजनाके अन्वय लगाया जायगा उसमें भूमिके सुधारमें पूँजी लगानेमें उत्साह कमहो जायगा। जबकि भूमि-कर लगानसे कर-क्षमता मिद्धान्तकी अवहेलना होतीहै, क्योंकि एक करोड़पतिको जिसके पास भूमि नहींहै कुछभी कर नहीं देना पडगा। इसके अतिरिक्त भूमि-कर आधुनिक राज्यके बढ़नेहुए व्ययका पूरा करनेमें अपर्याप्त होगा विशेषकर उन देशोंमें जहाँ कि जनसंख्याकी वृद्धि रुकगयीहै और घटनेभी लगी है।

एककर-प्रणालीमें केवल आय-कर लगानका भी सुझाव किया गयाहै क्योंकि अन्तर्गतत्वा सभी कर आय-कर से ही दिय जातेहैं अतएव यह सीधा मार्गहै कि कर आय परही लगाया जाय। भूमि-कर की तुलनामें यह कर अधिक उपयुक्त प्रतीत

होता है। यह प्रत्येक प्रकारकी आयपर लगाया जासकता है और वर्धमान कर-नीति का प्रयोग करके इसको क्षमता-सिद्धान्तके अनुकूल भी बनाया जासकता है। फिर भी केवल आय-कर लगानेमें कुछ असुविधाएँ हैं। अनुभवके आधारपर श्रात हुआ है कि कर लगाने और उसको इकट्ठा करनेमें बहुत परेशानी और व्यय भी होता है। पूजी-वादी देशोंमें कम आयवालेही अधिक सरायों पायेजाते हैं। यह भी देखा गया है कि और करोंकी अपेक्षा आय-कर से बचत करनेके उत्साहमें मन्दी आनेकी प्रवृत्ति रहती है। इसके अतिरिक्त यदि आयपर ही कर लगाया जाय तो जो बड़ी बड़ी सम्पत्तिमा उत्तराधिकारियोंका मिलती है और जिनमें पर्याप्त मात्रामें कर देनेकी क्षमता होती है वह कर से मुक्त रहेंगी। इन अन्तिम दो समस्याओंका कुछ अंशमें समाधान हो सकता है, यदि वचतके ऊपर आय-कर न लगाया जाय और उत्तराधिकारीकी सम्पत्ति को उत्तराधिकारके समय आय मान लिया जाय।

एक कर-प्रणाली का एक रूप यह बताया जाता है कि सम्पत्तिके मूल्यपर कर लगाया जाये। इस सम्पत्ति-कर का क्षेत्र आय-कर से सङ्कुचित होगा, क्योंकि इसमें परिश्रमसे जो आय होती है उसपर कर नहीं लिया जावेगा। अनेक व्यक्ति जैसे वकील, डाक्टर, इंजीनियर और लेखक अपने परिश्रमसे बहुत धन पैदा करते हैं और इनकी कर-क्षमता बहुत रहती है। इसके अतिरिक्त अनुभवसे और सिद्धान्तिक दृष्टि दोनोंसे भी यह सिद्ध होगया है कि सम्पत्तिकी अपेक्षा आय, कर का अधिक उपयुक्त आधार है। सम्पत्तिका मूल्य आकनेमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है।

एक कर-प्रणालीके इन उदाहरणोंमें जो अलग अलग असुविधायें और दोष बताये गये हैं इनके अतिरिक्त सभी प्रकारकी एक कर-प्रणालियोंमें कुछ समान असुविधायें और दोष होते हैं। इनको बहु-कर-प्रणालीके सांभोके प्रकरणमें समझा जासकता है। बहुकर-प्रणालीका मुख्य लाभ यह है कि यदि किसी कर से क्षमता-सिद्धान्तका उल्लंघन होगया होतो उसका प्रतिकार अन्य करोंसे किया जासकता है। इसके अतिरिक्त बहुकर-प्रणाली द्वारा भिन्न भिन्न आर्थिक वर्गोंकी और भिन्न भिन्न आर्थिक स्थितियोंके अनुसार भिन्न भिन्न करोंका प्रयोग किया जासकता है। जैसा कि राज्य की अर्थी आय-वृद्धतिकी विशेषताओंके विवेचनमें बताया आ चुका है। बहुकर-प्रणालीसे प्रायः सोचदार बनायी जासकती है। एक कर-प्रणालीकी अपेक्षा बहुकर-

प्रणालीमें कर स बचकर निकलनकी चष्टाकी पकड़की जासकतोहै क्याकि जय अन्तक करोके सम्बन्धमें आकड इकट्ठा कियेजायेंगे तो इनकी जाच पडनाम करनस वास्तविक स्थितिका बोध अधिक सुविधाके साथ होसक्या।

ऊपर दिग्गय विवेचनमे हम इसी परिणामपर पहुँचतेह कि किसीभी एककर-प्रणालीकी अपेक्षा बहुकर प्रणाली अधिक श्रेयस्करह। परन्तु इसस यह नहा समझना चाहिए कि जितन अधिक कर होंगे उतनीही अच्छी कर प्रणालीभी होगी। कराकी बहुतायतसे भी भ्रष्ट और समुविधाए उत्पन्न होनाता ह। पाठम सप्रभाव करा का प्रयोग हाना चाहिए। जहातक धनी लागाका सम्बन्धहै उनपर आय-कर, सम्पत्ति कर उत्तराधिकार-कर और विलासिताकी वस्तुमापर कर का प्रयोग होना चाहिए। यदि गरीब लागास कर लना आवश्यक होजाता ह ता उनस इस प्रकारकी वस्तुमापर कर बसूल करना चाहिए जा वस्तुए जीवन निवाहके लिए आवश्यक और निपुणता दायक न ह और जिनका प्रचुर मात्रामें सबन हाताहा जम नम्बाकू सराव इत्यादि।

कर सम्बन्धी नियम

कराने विषयमें अवतक ना कुछ कहागया ह उसक आधारपर कर सम्बन्धी नियम बनायगय ह। सबसे पुरान नियम अग्रजी श्रमामें स्मिथके प्रतिपादित नियम समझ जातह जा अवतरु आदरकी दृष्टिसे देखजाते ह। बादमें इनम कुछ और नियमभी जाड दियगय ह। स्मिथक प्रतिपादित चार नियम ह

(१) समानता अथवा क्षमता नियम—इस नियमका तात्पर्य यहहै कि प्रजाके लोगका अपना गति आर सामर्थ्य अनुपातमें राज्यका कर दना चाहिए। यह कर उस अनुपातमें हाना चाहिए कि अनुपातमें राज्यकी छत्र छायामें वे अपनी आयका उपभोग करत ह। स्मिथक मतव्यसे इस प्रकारसे कर दनवालाक तुष्टि-ल्योगमें समानता होगी और इसप्रकार की कर-प्रणालीमा न्यायसगत होगा। पाठवाके ध्यानमें आगया होगाकि इस नियमकी भूलक कर क क्षमता-सिद्धातमें भा पायी जाती है। लोगको बकाहै कि स्मिथ ग्रानुपातिक कर के पक्षमें था अथवा वधमान करक, क्याकि नियमनी व्याख्यामें जिस नापाका प्रयोग उसन कियाहै उससे स्पष्ट

बोच नहीं होता है कि उसका अभिप्राय क्या था?

(२) निश्चयताका नियम—प्रत्येक व्यक्तिके कर का परिमाण निश्चित होना चाहिए न कि मनमाना। देनेका समय और विधिभी स्पष्ट और सुगम होनी चाहिए। राज्यों भी निश्चयतासे बोध होजाता है कि उसको कर से कितनी आयकी आशा करनी चाहिए। इस नियमका पालन होवेमे कर देनेवालोंका राज्यके प्रति सद्भाव होता है।

(३) सुभीतेका नियम—प्रत्येक कर इस विधिसे और ऐसे समयपर लगाना चाहिए जिस प्रकार कर देनवालोंको सुभीता हो।

(४) मितव्ययिताका नियम—प्रत्येक करकी व्यवस्था इस प्रकारकी होनी चाहिए जिससे राज्यके कोषमें कर के परिमाणका अधिकसे अधिक भाग जमाहो अर्थात् कर उगाहने और प्रबन्ध करनेमें व्यय कमसे कम हो। इस नियमकी व्याख्या आजकल अधिक व्यापक रूपसे की जाती है। उगाहनेके दृष्टिकोणसे कोई कर मितव्ययी होसकता है, परन्तु यदि उसके कारण लोग उत्पत्तिकी मात्राको कम कर दें तो इससे राष्ट्रीय आय कम होजायेगी और राज्यको भविष्यमें कम कर मिल सकेगा।

एक नया नियम उत्पादकता का है। अधिकांश कर आयके लिए ही लगाये जाते हैं। यदि सब नियमोंका पालन होगया परन्तु आय पर्याप्त नहीं हुई तो राज्यके कार्योंमें रुकावट पड़ने लगेगी। यदि करोसे यथेष्ट आय हो तो छोटे मोटे दोषोंपर पर्दा पड़जाता है। परन्तु एक बातका ध्यान रखना पड़ता है कि उत्पादकता वर्तमान कालकी ही नहीं, परन्तु अनवरत होनी चाहिए।

एक और नियमके अनुसार कर में खोच होनी चाहिए अर्थात् आवश्यकतानुसार कर में कम अथवा अधिक आय प्राप्त करनेका गुण होना चाहिए।

इन सभी नियमोंका एकसाथ पालन करना सर्वदा सम्भव नहीं होता है। सधर्प हानपर अधिक महत्वपूर्ण नियमका अधिक ध्यान रखना पड़ता है।

कर-भार का हस्तान्तरण और आर्थिक प्रभाव

कर-भार

राज्य प्रारम्भमें जिस व्यक्ति अथवा संस्थानमें कर जाता है उस कर का भार यह धारक नहीं है कि उन्हींपर रहे। वे इस बातकी चेष्टा करते हैं कि किमी विधिसे वे उस भारको पूर्ण अथवा आंशिक रूपमें दूसरीपर डालकर स्वयं उस भारमें मुक्त हो जायें। कभी कभी वे ऐसा करनेमें समर्थ हो जाते हैं और कभी कभी नहीं भी होते। कर-भारको दूसरीपर डालनेकी क्रियाको हम कर का हस्तान्तरण कहेंगे। हस्तान्तरित करल करल एक एसी स्थिति आजाती है जहापर आगे हस्तान्तरित करने सम्भव नहीं होता। प्रिम स्थानपर यह क्रिया रुकजाती है उसको हम कर-भार का विराम कहेंगे। उदाहरणके लिए कल्पना कीजिए, राज्यने हरिसे १० रु० कर के रूप में निषा हरि मोहनसे वह क्षया वसूल किया और मोहनने रामसे वसूल किया। परन्तु राम उस भारको अन्य किमीपर न डाल सका। उसको स्वयं उठे वहन करना पडा। यहा हस्तान्तरण कार्यका अन्त होगया, अर्थात् कर-भार विराम अवस्थामें पहुचगया। इस प्रकरणमें जब हम कर-भार शब्दका प्रयोग करते हैं तो हमने द्रव्य की उस मात्राका समझना चाहिए जो राज्यका कर के रूपमें प्राप्त हुई हो।

प्रसरण-सिद्धान्त

कर-भारको हस्तान्तरित करनेके और उसके विराम-स्थानके विषयमें समय समय पर लोग भिन्न भिन्न परिणामापर पहुचे हैं। एक सिद्धान्तके अनुसार जिसको प्रसरण-सिद्धान्त कहते हैं, किमीभी कर को, कहींपर भी और किसी प्रकारसे भी क्यों न लगाया जाय, वह हस्तान्तरित होता जायेगा, यहानक कि अन्तमें उसका भार थोडा

थोड़ा सभी लोगोपर पड़ेगा। जिसप्रकार निमी तालाबमें क्वड डालनेसे पहिले एक छोटा वृत्त बनताहै, फिर उससे बड़ा और फिर उससे भी बड़ा, इसप्रकार अन्त में वह सारे तालाबकी सतहको घेर लेता है। इसीप्रकार इस कर-प्रसारण सिद्धान्तके अनुसार कर का भार फैलते फैलते सारे समाजपर पड़ताहै और उस भारको निश्चित करना असम्भव होजाता है। यह धारणा ठीक नहीं है। कुछक जिनमें प्रत्यक्ष-कर अधिक सरायमें है, ऐसेभी होनेहैं जिनका भार देनेवाले पगही पड़ताहै और जिनको वह हस्तान्तरित नहीं करसकता है। कुछ कर एमेभी है जो हस्तान्तरित हातहैं परन्तु उनके सम्बन्धमें यह ज्ञान किया जासकताहै कि अन्तमें किसपर कितना भार पड़ा। हा, कुछकर अनेकबार हस्तान्तरित होनेहैं और इनके बारेमें भारके वितरण को मानुस कग्ना अवश्यही कठिन कार्य होजाता है।

कर को हस्तान्तरित करने की क्रिया

करको प्रागे और पीछे दोनों ओर हस्तान्तरित किया जासकता है। कल्पना कीजिए, राज्यने सिगरेटपर कर लगा दिया। यदि सिगरेट बनानेवाला कर का सिगरेटके मूल्यमें जोड़कर उसको सिगरेट भोल लेनेवालोंमें वसूल करलेता है तो इस कर-भारको प्रागेकी ओर हस्तान्तरित करना कहते हैं। परन्तु यदि वह इस कमीको सिगरेट बनानेवाले मजदूरोंका बेतन घटाकर अथवा कच्चे मालको सस्ते दामोंमें खरीदकर पूरी करलें तां ऐसी दशामें कर-भारको पीछेकी ओर हस्तान्तरित कग्ना कहते हैं। कर देनेवाला दोनों प्रकारमें अपनेको कर-भारसे मुक्त करनेकी चेष्टा करताहै, परन्तु अधिकतर कर-भार प्रागेकी ओरही हस्तान्तरित होता है।

कर एक प्रकारकी लागतहै और जिनप्रकार लोग लागतको मूल्यमें शामिल कर लेतेहैं उमीप्रकार करको भी मूल्यमें शामिल करके वसूल करनेकी चेष्टा कीजाती है। मूल्यके हागही कर का भार हस्तान्तरित किया जासकता है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि कर को मूल्यमें सम्मिलित करनेका सुयोगहै तबतो उसको हस्तान्तरित किया जासकता है अन्यथा नहीं। अनेक कर ऐसेहैं जिनमें यह सुयोग प्राप्त नहीं। इस लिए कर देनेवालेही उसका भार वहन करतेहैं। आय कर के सम्बन्धमें ऐसीही परिस्थिति रहती है।

यदि वर का मूल्यमें समावेश करनेवा सुयाग हो, तबभी यह आवश्यक नहीं है कि वह अवश्यमव हस्तान्तरित हो जायेगा। मान लीजिए ए० टिन सिगरेटका मूल्य २५० है और उसपर राज्यन २ आना कर लगाया। अब यदि सिगरेट बेचने वाला सिगरेट का मूल्य २५० से बढ़ाकर २६० २ आ० वर दे और उसके ऐसा करनेसे उसकी आममें क्षति न हो, तो वह सफलतासे कर-भारका अपने ग्राहकों के ऊपर ढाल सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि विक्रेता कर को मात्राका मूल्यमें जोड़ देता है और अपने ग्राहकों के बमूल करना है। कुछ प्रत्यक्ष उदाहरणभी ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनमें कर लगाने के बादही वस्तुका मूल्यभी ठीक उतनाही बढ़ जाता है जितनी कि करकी मात्रा होती है। पर इससे यह परिणाम निकालना गलत होगा कि प्रत्यक्ष कर वस्तुका मूल्यमें जोड़कर दूसरों पर ढाल दिया जाता है। माना कि विक्रेताको अपनी वस्तुका मूल्य बढ़ानेकी स्वाधीनता है, परन्तु क्या इससे यह सिद्ध होजाता है कि वह जितना चाहे उतना मूल्य बढ़ा देगा? यदि यही बात होती तो वह सिगरेटका मूल्य कभीका बढ़ाचुका होता कर लगाने के समयकी प्रतीक्षा न करता। विक्रेताको इस बातका ध्यान रखना पड़ता है कि किस मूल्यपर उसको अधिकतम बिक्री होगी और अधिकतम लाभ होगा। अन्य परिस्थितियाँ ममान रहने पर मूल्यमें बदलाव होनेसे मागके परिमाणमें भी बदलाव हा जाता है जिसे विक्रेता को ध्यानमें रखना पड़ता है। यदि मूल्यमें वृद्धि करनेसे उमकी बिक्री घट गई तो यह सम्भव है कि वर वसूल हो जानेपर भी उसके लाभकी मात्रा में कमी होजाये। अतएव इसको मूल्य बढ़ानेसे पूर्व मागकी दशाका अध्ययन करना पड़ता है। किसी भी वस्तुकी मागके परिमाणमें मूल बात उपयोगिता रहती है। कर लगानेसे किसी वस्तुकी उपयोगिता बढ़ तो नहीं जाती जिसके कारण ग्राहक अधिक मूल्यपर भी उस वस्तुको उतनेही परिमाणमें मोलसे जितनी कि वे कर लगानेके पूर्व कम मूल्यपर लिया करते थे। मूल्यकी वृद्धि होनेसे कुछ लोग उस वस्तुको कम परिमाणमें लेंगे और कुछ लोग प्रतिनिधि वस्तुधोका प्रयोग करने लगेंगे। हा यदि वह वस्तु अत्यन्त आवश्यक प्रयोगकी है, उसकी प्रतिनिधि वस्तुभी कोई नहीं है और उसकी माग बढ़ोचढ़े तो ऐसी परिस्थितिमें ग्राहक मूल्य वृद्धि होजाने परभी अपनी मागके परिमाणको कम नहीं करेंगे और ऐसी दशा में विक्रेता सफलतापूर्वक कर को हस्तान्तरित कर सकेंगे।

भाग और पूर्ति का प्रभाव

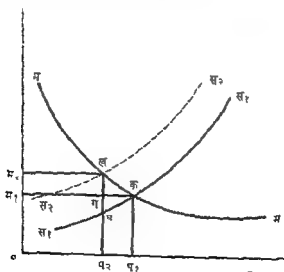
इस विवेचनसे पाठकोंकी समझमें आगया होगा कि कर के भारकी हस्तान्तरित करना केवल विक्रेताओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। कर को मूल्यमें समावेश करके दमूल किया जा सकता है अथवा नहीं, यदि हाँ तो किम अक्षतक? इन बातोंका विचार करनेके लिए हमको उन सभी बातोंको ध्यानमें रखना पड़ता है जिनसे मूल्य निर्धारित होता है। इसी लिए कहा जाता है कि कर-हस्तान्तरण का अध्ययन करने के लिए हमको मूल्य-निर्धारण क्रियाका अध्ययन करना पड़ता है। मूल्य निर्धारित करनेमें माग और पूर्ति और उनको प्रभावित करनेवाली बातोंका अध्ययन करना पड़ता है। जिन बातोंका माग और पूर्तिपर प्रभाव पड़ता है उन्हींसे मूल्य निर्धारित होता है और उनके विवेचनसे ही कर के हस्तान्तरित करनेकी समस्या परभी पकाश पड़ता है। अतएव हम इन्हीं विषयोंकी विवेचना करेंगे।

पहिले पूर्तिपर ध्यान दीजिए। किसी वस्तुका विक्रता यदि कर वसूल करनेके लिए उस वस्तुके मूल्यको बढ़ाना चाहता है तो उसको उस वस्तुके परिमाणको घटाना पड़ेगा। जैसे जैसे किसी वस्तुका परिमाण घटता जाता है वैसे वैसे, अन्य बातें यथावत् रहनेपर उस वस्तुके मूल्यमें वृद्धि होती है, क्योंकि वैसे वैसे उसकी सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है। विक्रेता उस वस्तुके परिमाणको घटायेगा अथवा घटा सकता है कि नहीं यह अनेक स्थितियोंपर निर्भर करता है। उत्पत्तिकी मात्राका घटाने के लिए उमरे उत्पादनके साधनोंकी उस धन्यमें निवालकर किसी दूसरे धन्यमें लगाया पड़ेगा। यदि वह धन्य इस प्रकारका हो जिसमें मशीन इत्यादि प्रचल पूँजीकी अधिकता हो जिसको मुगमतासे दूसरे धन्यमें न लगाया जा सकता है, तो उत्पत्तिक परिमाणको अधिक नहीं घटाया जा सकता। अनेक अवस्थाओंमें उत्पत्तिके साधनोंकी बेकार रखकर उनकी लागतको वहन करनेकी प्रपेक्षा यह लाभदायक होता है कि उनकी काममें लगे रहने दिया जाये। हाँ, यह अवश्य होगा कि दीर्घ-कालमें मशीन इत्यादिके घिस जानेके बाद नई पूँजी उस धन्यमें नहीं लगाई जायेगी जिसमें उत्पत्तिकी मात्रा कम हो जायेगी। परन्तु निकट भविष्यमें उत्पत्तिकी मात्रा में विषय कमी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी धन्यमें इस प्रकारके साधन लगे भी हों जिनको मुगमतासे एक धन्यसे दूसरे धन्यमें लगाया जा सकता है तो ऐसा

वरमके लिए भा दा वानाकी आवश्यकता है। पहिले ता यह कि पूजीपति को अथ धधका जान हा और वह नथ धधका जायिमाको सहन करनके त्रिए तत्पर हो। दूसरी बात यह कि अथ उद्याग धधमें पूजी लगानस पहिले ध धकी अप्रमथा अधिक नाभ होनकी सम्भावना हा। यदि सभी उद्योग धधपर कर नगा हुआ हा ता पूजी का एक धधस हटा कर दूसरम लगानस अधिक लाभकी आशा कमही ह गी। सधाप म कह सकत ह कि यदि बिना किसी प्रकारकी धनिके किसी वस्तुका उत्पादक उस धधम नग हुए माधनाको मर धध म नगाकर पहिली वस्तुक परिमाणमें बमी कर सके ता एसी स्थितिम वह कर न भारका मूल्यम गलतर ग्राहकाम वसूल कर सकेगा। अथान किमा वस्तुका पूरिम जितनी अधिक लाच होशी उननीहा अधिक मात्राम कर भार का हस्तांतरित करनम मजिदा हागी।

अथ मागध पक्षमा अध्ययन कर। जिसभा वस्तुक ग्राहक उस वस्तुके मूल्यका वास्तव एकादश प्रतिशतका चष्टा करम। इस कामध उनका तभी सफलता प्राप्त हो सकताह नर कि वह बड़ टण म दपर अपना मागका पर्याप्त मात्रा म कम कर सक। एसा करनस बिना का वस्तुए कम परिमाणम विक्री और उनका बचनके लिए उसे मूल्य कम करना पगा पगन ग्राहक लोगभी उस वस्तुकी माग पर्याप्त मात्रा म तभी कम कर सकन ह अतः कि वस्तु अधिक आवश्यक न हा अथवा उसकी प्रति निधि वस्तुए बतमान हा तिनका प्रयोग के कर वाली वस्तुक स्थानपर कर सके अथवा यदि उस वस्तुका माग वाचदार हो तो ग्राहक मागम बमी कर सकत ह और बिना का धध अगनके लिए बाध्य कर सकत ह। जितना अधिक मात्रामें मागम लोन हागा उननी अधिक इस कायम ग्राहका का सफलता मिलगी और कर का भार बिनामापर बना रहगा। पर तु यदि वह वस्तु आवश्यक ह और उसकी प्रतिनिधि वस्तुए नहीं ह अथवा प्रतिनिधि वस्तुआपर भी कर लगा हुआ हो तो ग्राहका को दाना पडगा और कर भार नी उ टापर अधिक हागा। सामूहिक उपभागकी अनक वस्तुए एसी हानी ह जसे नमक तम्बाक जिनकी मागम बहुतरुम लोच होती ह और थोडी मात्राम मायकी वटिम उनकी बिनीम कोइ अतर नही अता। एसी ही वस्तुआका मूल्य बिना नाग कर क पूर परिमाणक बराबर बढ़ाकर ग्राहकासे वसूल करत ह शर इसको आधारपर लागू मगझने ह कि सभी करा पर यही बात लागू होगी।

माग और पूर्तिके दोनों पक्षोंको साथ साथ रखकर हम कह सकते हैं कि उत्पादक लोग उत्पत्तिकी मात्रामें कमी करके कर के भारको ग्राहकोंपर डालनेकी चेष्टा करते हैं और ग्राहक भोग अपनी भागको कम करके उनकी इग चेष्टामें बाधा डालनेका प्रयत्न करते हैं। इस प्रतिद्वन्द्वितामें कौन अधिक सफल होगा यह माग और पूर्तिकी सापेक्ष लाचपर निर्भर करता है। यदि मागमें लोच नहीं है अथवा बहुत कम है तो बिना अधिक सफलतासे कर का मूल्यमें जोड़ सकेगा, क्योंकि उसकी उत्पत्तिकी मात्रामें कमी करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परन्तु यदि माग बहुत लाचदार है तो कर के भारको ग्राहकोंपर डालना दुष्पर होगा क्योंकि ऐसी अवस्थामें उत्पत्तिकी मात्रामें अधिक कमी करनेकी आवश्यकता पड़ेगी। अतएव कमसे कम वर्तमान और निश्च भविष्यकालमें कर का अधिकांश भाग उत्पादकोंपर ही रहगा। यदि माग और पूर्तिकी लोच समान है तो कर का भार दोनों पक्षोंपर बराबर होगा। इस स्थितिमें हम रेखा-चित्र द्वारा भी चित्रित कर सकते हैं।



इस रेखा-चित्र में 'म' माग रेखा है और 'स१ स२' कर लगनेके पूर्व पूर्तिकी रेखा है। 'ख' 'ग' 'घ' की मात्रा है जिसे लगनेपर पूर्तिकी रेखा उसी परिमाणमें ऊँची

होकर स२ स२ हाफ्ट है। कर लगानेसे पूर्व माग और पूर्तिवा सन्तुलन ०५१ परि-
माण और तदनुसार ०५१ मूल्यपर होता है और कर लगानेके पश्चात् ०५२ परि-
माण और ०५२ मूल्य पर होता है। स्पष्ट है कि जिस वस्तुकी माग और पूर्तिके-
दशा इस प्रकारकी होगी, उस पर लगाएगये 'स घ' वस्त्रे भार का 'द ग' माग उस
वस्तुके ग्राहको पर और 'स घ' उत्पादको पर पड़ेगा।

एकाधिकारी पर कर

एकाधिकारीपर कर लगानेमें यह किस प्रकार उसके भारको हस्तान्तरित करनेकी
चेष्टा करेगा, इसका विवेचन साधारण प्रतिस्पर्धाकी अवस्थासे कुछ भिन्न है, क्योंकि
एकाधिकारी का किसी वस्तुकी पूर्तिपर अधिकार रहता है। एकाधिकारीपर कर
प्रकारमें कर लगाया जा सकता है। यदि कर उत्पत्तिकी मायाके हिसाबमें लगाया
जाये और कर लगानेके पूर्व एकाधिकारी अपनी वस्तुके मूल्यका स्तर इस प्रकार
निर्धारित कर चुका हो, तो कर लगानेसे वह वस्तुके मूल्य का उचा करेगा अथवा नहीं
और यदि ऊचा करेगा तो किस स्तर तक इसका निर्णय माग और पूर्ति की विषयतामा
पर ही निर्भर करता है। यदि उस वस्तु की मागमें बहुत बरा मोच हो और उसकी
प्रतिनिधि वस्तुएं प्राप्त न हों तो एकाधिकारी कर के भार का अपने ग्राहकों पर
जालनमें समर्थ हो सकता है। परन्तु यदि उस वस्तुकी माग बहुत मोचदार हो और
एकाधिकारी उत्पत्ति व मायका को बहुत मुश्किलतासे उद्योग-धन्यामें लगाकर
उस वस्तुके परिमाणका पर्याप्त मात्रामें कम करनेमें असमर्थ हो तो कर का अधि-
कास एकाधिकारी पही रहगा। यदि कर वस्तुप्राप्ती की माया पर न लागकर एका-
धिकारीके लाभ पर लगाया गया हो तो एकाधिकारीको कर के बराबर मूल्य बरा
कर हस्तान्तरित करनेकी प्रवृत्ति नहीं होगी। लाभ पर कर दो प्रकारमें लगाया जा
सकता है। एक विधि यह है कि एकाधिकारीसे एक निर्धारित रकम कर के रूपमें ले
ली जाये और दूसरी विधि यह है कि लाभ पर एक निर्धारित दरके हिसाबसे कर
लिया जाये। कल्पना कीजिए कि राज्य ने एकाधिकारी पर १००० रु० वार्षिक
कर लगाया अथवा उसके लाभ पर १० प्रतिशत लगाया। कर लगानेसे पहिले
एकाधिकारी अपनी वस्तुका मूल्य इस प्रकार निर्धारित कर चुका होगा कि उस

मूल्य पर उसको अधिकसे अधिक लाभ हो और उससे कम या अधिक मूल्य पर लाभ की मात्रा कम होजाय। अब नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दीजिए :

१ मूल्य की दर	२ लाभ	३ कर की मात्रा	४ कर घटा- कर लाभ	५ कर की दर	६ कर की मात्रा	७ कर घटा- कर लाभ
६०	६०	६०	६०		६०	६०
१०	५०००	१०००	४०००	१०%	५००	४५००
६	६०००	१०००	५०००	१०%	६००	५४००
८	७०००	१०००	६०००	१०%	७००	६३००
७	६०००	१०००	५०००	१०%	६००	५४००
६	४०००	१०००	३०००	१०%	४००	३६००

(१) और (२) खानोंसे पता चलता है कि ८६० मूल्यकी दर रखनेसे एकाधिकारी को अधिकसे अधिक लाभ अर्थात् ७००० ६० प्रति वर्ष प्राप्त होता है। इससे कम या अधिक मूल्य पर द्रव्य गिरने लगता है। (३) और (४) खानोंसे पता चलता है कि १००० ६० एक निर्धारित रकम कर के रूपमें देनेके बादभी अधिकतम लाभ अर्थात् ६००० ६० ८६० मूल्यपर ही प्राप्त होता है। इसी प्रकारसे १० ६० प्रतिशत लाभ भन् कर लगाने पर भी (६) और (७) खानोंसे ८६० मूल्य पर ही ६३०० ६० लाभ बचता है जो इस अवस्थामें अधिकतम है।

आयात और निर्यात कर

११८

अब हम कुछ विशेष प्रकारके करोंके सम्बन्धमें कर-भार हस्तान्तरित करनेकी क्रियाओं का उल्लेख करेंगे। किसी देशमें जो वस्तुएं बाहर जाती हैं उन पर लगाये गये कर को निर्यात-कर कहते हैं और विदेशोंसे देशमें आनेवाली वस्तुओंपर लगाये गये वरोंको आयात-कर कहते हैं। उदाहरणके लिए मान लीजिए भारत चाय पर निर्यात-कर लगाता है। क्या इस दर का भार भारतवर्ष के चायके व्यापारिया

और उत्पादकों पर पड़ेगा अथवा उन देशवासियों पर पड़ेगा जो भारत की चायका उपयोग करने हैं। यदि भारत की चाय की उत्पादिका एकाधिकारी स्थान प्राप्त हो अथवा अधिकतर चाय भारत में ही पैदा होनी हो और चाय के बदले में उस चाय-उत्पन्नता को तृप्त करनेवाली अन्य वस्तु न हो और चाय की माग में विशेष लोचन हो तो निम्नोक्त कर का भार विदेशी उपभोक्तान्त्रों पर पड़ेगा। परन्तु यदि अन्य देशों में चाय उत्पन्न होनी हो (चाय चीन, जापान, बर्मा, लन्का आदि देशों में होती है) अथवा चाय के मूल्य में वृद्धि होने पर विदेशी उपभोक्ता चाय के बदले में कौकी, कोका आदि अन्य वस्तुओं का उपभोग करने लगे तो भारत के चाय के व्यापारियों की हस्तान्तरण शक्ति का हानि हो जायगा और इस अवस्थामें कर का अधिकांश भार उन्हीं पर रहेगा। हा, यदि चाय उत्पन्न करनेवाले देशों की सग्या थोड़ी हो और वे आपस में मिलकर एकाधिकार का पद प्राप्त कर लें तो अवश्य ही उनको कर के भार को अन्य देशवासियों पर डालने में अधिक सफलता मिल सकेगी। लेकिन वास्तव में इस प्रकार का एकाधिकार स्थायी नहीं रहता।

आयात-करा के सम्बन्ध में कुछ लोगों की धारणा है कि इनका भार विदेशी माल भेजनेवाले पर रहना है। परन्तु यह धारणा प्रत्येक अवस्थामें सही नहीं है। यह तभी ठीक होनी है जब कि आयातनाली वस्तु देशवासियों के लिए आवश्यक न हो और उसकी प्रतिनिधि वस्तु सुगमतासे प्राप्त हो सकती हो अर्थात् यदि उस वस्तु की माग विशेष रूपसे लोचदार हो और विदेशी व्यापारी की उम वस्तु की माग अन्य देशों में न हो अथवा बहुत कम हो। ऐसी अवस्थामें कर का अधिकांश भार विदेशी व्यापारी को सहन करना पड़ेगा। परन्तु इस प्रकार की अवस्था बहुत कम रहती है। यदि विदेशी वस्तु आयात करनेवाले देशवासियों के लिए आवश्यक हो और उसकी प्रतिनिधि करनेवाली अन्य वस्तु सुगमतासे न प्राप्त हो सकती हो और यदि उस वस्तु की माग अन्य देशों में भी हो तो निर्यात करनेवाले देश की शक्ति बढ़ जाती है। अतएव ऐसी अवस्थामें आयात-कर का अधिकांश भार आयात करनेवाले देशवासियों पर ही पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयात-कर को हस्तान्तरित करना उन्हीं परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिन परिस्थितियों पर देश के भीतर बचायी गयी वस्तुओं पर लगाये गये कर को हस्तान्तरित करना सम्भव हो सकेगा। दोनों परिस्थितियों में एक ही सिद्धान्त लागू होता है।

मकानों पर कर

यदि मकान पर कर लगाया जाये तो मालिक मकान किराया बढ़ा कर (यदि मकान किराये पर उठाया जाता हो तो) कर के भारको किरायेदारपर डालनेकी चेष्टा करेंगे। यदि कर किरायेदार से लिया जाये तो वह मालिक मकान को उतना कम किराया देकर कर के भारमें अपने को मुक्त करनेकी चेष्टा करेगा। कहा तक ये लोग अपनी चेष्टामें सफल होंगे, यह मकानोंकी भाग और पूर्तिकी दशा पर अवलम्बित है। अधिकतर यह देखा गयाहै कि भिन्न भिन्न आर्थिक स्थितिके लाग विशेष प्रकारके मकानों और मुहल्लामें रहना पसन्द करते हैं। इसके प्रतिरिक्त जहां लोग रहते आनेहैं वहांके लोगोंसे ज्ञान पहचान और अन्य व्यावहारिक सम्बन्ध हो जाते हैं। मकान बढ़ानेमें असुविधाएँ और व्यय भी होता है। अतएव मकानोंकी मागमें अधिक लोच न होनेके कारण कर का कुछ अंश अवश्यही किरायेदारों को वहन करना पड़ता है। यदि, जैसा आजकल बड़े शहरोंमें है, राज्य द्वारा किराया निश्चित कर दिया गया हो तो कर का भार मकान मालिकों पर ही रहेगा, यदि उनको कर के अनुसार किराया बढ़ाने की अनुमति न मिले।

यदि किराया मकान मालिकोंसे लिया गयाहै तो जिस अवधि तक मकान मालिक और किरायेदार के बीच किरायेके परिमाणकी लिखापढी हाँचुकी हो तब तक कर का भार मकान-मालिक पर ही रहेगा (किरायेदार से कर वसूल करनेपर इस अवधि तक कर का भार किरायेदार पर ही रहेगा। पट्टा पूरा हो जानेपर मालिक मकान किराया बढ़ानेकी चेष्टा करेगा)। मकानोंके सम्बन्धमें एक विशेष बात यह है कि मकान बहुत टिकाऊ होते हैं और निकट भविष्यमें इनकी संख्या कम करके इनका किराया सुगमतासे बढ़ाया नहीं जा सकता। अतएव यदि मकानोंकी मागमें शिथिलता हो और कुछ मकान खाली पड़े हो तो ऐसी अवस्थामें कर का भार अधिकांशमें मकान-मालिकों पर ही रहेगा। वस्तुतः माग और पूर्तिकी विशेषताओं को साथ साथ रखने पर ही कर-भार का वितरण निश्चित होगा। यदि कर देनवाला किसी प्रकार का व्यवसाय करता हो तो ऐसा भी हो सकता है कि वह कर के कुछ अंशका भार अपनी वस्तुके ग्राहकोंपर डाल दे। नये मकानों को बनवानेमें कर का कुछ भार मकान बनाने वालोंपर भी पड़ सकता है।

खेती की भूमि पर कर

यदि जमीन्दार अपने आनामियोंमें पूरा अधिक लगान वसूल कर रहा हो तो कर का भार जमीन्दार को ही वहन करना पड़ेगा, परन्तु यदि वास्तविक लगान अधिक लगानमें कम होना करवा कुछ अनामीयों पर डाला जा सकता है। भूमि का क्षेत्रफल घटाना नहीं कामना। अतएव ऐसे देशोंमें जहाँ आबादीके स्थिर रहने अथवा घटनेके कारण भूमिकी मागकी लोचमें बर्षा आगई हो वहाँ भूमि-कर का अधिकार भार जमीन्दार परही रहेगा। आबादीकी वृद्धिके कारण अनाजकी माग में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसी अवस्थामें कर का कुछ अनाजके मूल्यमें वृद्धि करके उनके ग्राहकोंपर भी डाला जा सकता है।

आय-कर

आय-कर के बारेमें साधारणतः यही धारणा है कि इसका भार कर देनेवाले परही रहता है। इस प्रकारमें बेतन, मजदूरी, पेंशन इन प्रकारके आय-कर की प्रीट् वाणिज्य-व्यापारके आय-कर की अलग अलग विवेचना करना ठीक जानपड़ता है। जहाजक बेतन और मजदूरीका प्रश्न है, कर देनेवाला कर का भार अपने नियोजता के ऊपर डालना चाहेगा। ऐसा करनेमें वह तभी सफल होयकेगा जब नियोजता उसके बेतन अथवा मजदूरीमें कर के बराबर वृद्धि करदे। परन्तु नियोजता इस प्रकारकी वृद्धि बर्दा करे। आय-कर देनेके बाद नियोजताके लिए श्रमजीवियोंका काम अधिक उपयोगी अथवा लाभप्रद तो हो नहीं जाता है। यदि वह उनका उच्चतर सीमान्तिक उत्पादकताके अनुसार पारिश्रमिक दे रहा हो तो फिर वह उनमें वृद्धि करनेवाला करेगा। ऐसी अवस्थामें कर का भार श्रमजीवीपर ही रहेगा। परन्तु यदि पारिश्रमिक सीमान्तिक उत्पादकतामें कम परिमाणमें दिया जा रहा हो तो बहुत सम्भव है कि कुछ अशक्त पारिश्रमिकमें वृद्धि कर नियोजता आय-कर के भारको अपने ऊपर लेले। अतएव श्रमजीवियोंकी सन्तुष्टि प्रश्न है, यदि वे अपने श्रमकी मात्रा कम करनेमें समर्थ हों तो अपनी आयको बढ़वा सकने हों। परन्तु इसमें कठिनाई है। पहिले तो यदि किसी एक प्रकारके व्यवसायके श्रमजीवी उस व्यवसायको छोड़कर

अन्य व्यवसायोंमें जानेकी चेष्टा करते और इसप्रकार उच्च व्यवसायमें धमकी मात्रा को कम करके अपने पारिश्रमिक को बढ़वानेमें अधिक समर्थ होते। परन्तु यदि सभी प्रकारके व्यवसायोंके श्रमजीविधोगे आय-कर लिया जाता हो तो एक व्यवसायसे दूसरे व्यवसायमें जानेसे कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि आय-कर के भारके फलस्वरूप धमकीवादी अपने काम करनेके घटे कम और अवकाश अधिक करना चाहता हो, तो पारिश्रमिक बढ़नेकी सम्भावना हासिल होती है। परन्तु यदि कर देनेके पश्चात् आय कम रह जानेके कारण कर देनेवाला अपना जीवनस्तर पूर्ववत् बनाये रखनेके लिए अधिक घटे काम करना चाहे तो इससे पारिश्रमिककी दृष्टि में वृद्धि नहीं होगी। बौन कर देनेवाला किस प्रकारका आचरण करेगा, यह साधारणतः उसके आय-स्तरपर निर्भर करता है। अधिक आय-स्तरवाने धमकीवादी आय-कर बढ़ जाने से काम कम और अवकाश अधिक और निम्न स्तरवाले धमकीवादी अधिक काम और अवकाश कम चाहेंगे। अतएव पहिली दशामें कर-भारको नियोक्तापर डालनेकी अधिक सम्भावना रहती है और दूसरी दशामें कर-भार श्रमजीवियोंपर ही रहेगा।

वाणिज्य और व्यवसाय द्वारा जो आय होती है उगपर लगाया कर साधारणतः हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। व्यापारी और व्यवसायी लोग तो कहते हैं कि यदि राज्यने आय-करमें वृद्धि की तो वे वस्तुका मूल्य बढ़ाकर बमूल कर लेंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि वे वस्तुओंको अधिक मूल्यपर बेच सकते थे, तो आय-कर की प्रतीक्षा क्यों करते रहे। पहिलेही से उन्होंने वस्तुका मूल्य आय-कर के परिमाणके भरावर बढ़ाकर लाभ क्यों नहीं उठाया। आय-कर के लगनेके कारण ही उनकी वस्तुकी चाह प्रेताग्रोंको अधिक नहीं होजायेगी। इसके अतिरिक्त व्यवसाय और व्यापारकी आयपर कर लाभपर लगता है और वस्तुके बेचनेसे जो प्राप्ति होती है उस परिमाणमें से लागतको निकालकर लाभका परिमाण जाना जा सकता है। अब वस्तु तो थिक चुकी है तो कैसे उसके मूल्यको बढ़ाकर कर के भारको नेताओपर डाला जा सकता है। एक वस्तुके उत्पादन कार्यको छोड़कर दूसरी वस्तुके उत्पादन कार्यमें लगनेसे भी कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि सभी व्यवसायोंसे प्राप्त लाभपर आय-कर लगता है। अतएव जो कार्य आय-कर देनेके पूर्व अधिक लाभदायक था, वही आय-कर देनेके पश्चात् भी तुलनात्मक दृष्टिसे अधिक लाभदायक रहेगा।

कर-भार को हस्तान्तरित करनेकी क्रियाको और तत्सम्बन्धी समस्याओंको करो

के कुछ उदाहरण द्वारा हमने समझानेकी चेष्टाकी है। यह विषय बहुत विवादका है। एक कठिनाई यह है कि करोंके कारण आर्थिक व्यवस्था कई प्रकारसे प्रभावित होती है। द्रव्यमय कर भारको हस्तान्तरित करनेकी चेष्टामें भी आर्थिक कार्यों और सम्बन्धोंमें परिवर्तन होता है। परन्तु इस परिवर्तनसे कर-भार हस्तान्तरित हो जायेगा, यह नहीं समझना चाहिए। उदाहरणके लिए यदि राज्यने किसी व्यक्तिपर १० रु० मासिक आय-कर लगाया और उसने १०,२० मासिक वाले नौकरको निकाल दिया, तो क्या हम कह सकतेहैं कि कर देनेवालेने अपने कर का भार अपने नौकर पर ढाल दिया? नहीं। यदि कर देनेवालेने नौकरको निकालकर १० रु० की क्षति पूरी कर ली, तो भी वह नौकरकी सेवाओंमें वंचित रहा।

करों का आर्थिक प्रभाव

कैसाकि पिछले अध्यायोंमें लिखा जा चुका है, आधुनिक राज्य समाजकी आयरा-बड़ा हिस्सा कर के रूपमें ले लेतेहैं और उसको अनेक प्रकारमें भिन्न भिन्न मदोंमें व्यय करत है। इसका समाजके आर्थिक कार्यों जैसे उत्पादन उपभोग, निर्माण, वितरण पूँजीके धनने तथा लगाने और आर्थिक प्रगतिपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रभावका आर्थिक विवेचन राज्यके व्ययके अध्यायमें किया जा चुका है। परन्तु व्यय करनेके लिए आयकी आवश्यकता होती है जोकि साधारणन कर के रूपमें होती है। विविध प्रकारके करोंका भिन्न भिन्न आयस्तरके व्यक्तिपर और सामान्यी आर्थिक नियमोंपर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। इस प्रकरणमें इसी विषयपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा की गई है। कभी कभी राज्य ऋण लेकर भी व्यय करता है। इसका प्रभाव राज्यके ऋणवाले प्रकरणमें दिया जायेगा।

करों का उत्पत्ति पर प्रभाव

कर उत्पत्तिके कुल परिमाण और उसके अन्तर्गत भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओं के परिमाणोंको, लोगोंकी कार्य करनेकी शक्ति, निपुणता और प्रवृत्ति, पूँजी संचय करनेकी और उसको आर्थिक कार्योंमें लगानेकी प्रवृत्ति और आर्थिक साधनोंको एक

व्यवसायसे दूसरे व्यवसायोंमें तगानेके द्वारा प्रभावित करता है। यदि करोंके लगाने के कारण कर देनेवालोंकी कार्य-क्षमता का ह्रास होता हो तो इससे उत्पत्तिके परिमाणमें भी कमी आजायगी। अतएव राज्यको चाहिए कि वह अपनी कर पद्धति इस प्रकारकी बनाये जिससे एक विनाश आय-स्तरसे निम्न आयवाले व्यक्तियोंपर कर का भार न पड़े। यह आयस्तर एक अपेक्षित जीवन-स्तर बनाय रखनेके आधारपर निर्धारित होना चाहिए। यदि इस स्तरसे निम्न आयस्तरोंके व्यक्तियोंपर कर-भार डाला जाये तो वे जीवन निर्वाह और कार्य-कुशलता वाली वस्तुओंका उचित मात्रामें उपभोग करनेसे वंचित रहेंगे। इससे न केवल उनकी कार्य-क्षमता और स्वास्थ्यका क्षति पहुँचेगी, बल्कि उनके बच्चोंको उपयुक्त भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि न मिल सकनेके कारण भविष्यकी उत्पत्तिकी मात्रामें भी क्षति हानकी भावका है।

यदि राज्य किसी मनुष्यकी आयका एक भाग कर के रूपमें ले तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका कार्य करनेकी प्रवृत्ति और पूँजी संचय करनेकी प्रवृत्तिमें निधिलता आजाये। यदि ऐसा हुआ तो उत्पत्तिकी मात्रामें क्षति होनेकी सम्भावना है। ऐसा होगा अथवा नहीं यह कर का स्वरूप उसकी मात्रा और कर देनेवालोंकी प्रतिश्रियाँपर अवलम्बित रहता है। जिन लोगपर एक बड़ा कुटुम्बका भार है, यदि उनकी आय कर देनेके कारण पर्याप्त नहीं होती, तो सम्भव है कि ऐसे लोग अपने जीवन-स्तरको बनाये रखनेके लिए अधिक कार्य करनेको बाध्य हों। इसी प्रकार जो लोग भविष्यमें एक निश्चित आय बनाये रखनेके लिए बचत करते हैं, कर-भार के कारण बचतकी मात्रा बनाये रखनेके लिए भी उनको अधिक उद्योग करना पड़ेगा। आर्थिक मन्दीके अवसरपर कर-भारसे उद्योग और उत्पत्तिकी मात्रामें अधिक क्षति होनेकी सम्भावना है। परन्तु आर्थिक उत्कर्षके कालमें उत्पादक लोग इन्हीं करोंसे कुछ भी नहीं घबराने और उत्पत्तिके कार्योंको आगे बढ़ाते रहते हैं।

जो कर अनपेक्षित आयपर लगाये जाते हैं उनका कार्य करनेकी अभिलाषा पर किसी प्रकारका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीप्रकार इस प्रकारके एकाधिकारी पर कर का जोकि उसमें एक निर्धारित परिमाणमें अथवा उसके लाभकी एक निर्धारित दरके हिस्सेसे लिया जाता है, एकाधिकारीको अपने व्यवसायकी मात्रा घटानेमें प्रेरित नहीं करता। यदि उत्तराधिकार-कर के कारण उत्तराधिकारीको कम प्राप्ति की सम्भावना हो तो ऐसी अवस्थामें सम्भवतः वह बेकार रहनेकी अपेक्षा कुछ उद्योग

में लगे रहनेको चेष्टा करेगा जिसमें उत्पत्तिकी भावनामें वृद्धि होगी।

घाय-वर साधारणतः वर्तमान होते हैं। अतएव बहुत सम्भव है कि ऊंचे घाय-स्तर पर जहापर कि दर बहुत बढ जाती है, इस प्रकारका कर उद्योग और पूँजीके मध्यमें कमी लानेकी प्रवृत्ति उत्पन्न करे। यह कहना कठिन है कि कितने घाय-स्तर पर कर की कौनसी दर इस प्रकारका प्रभाव उत्पन्न करगी। यदि घाय-वर इस प्रकार लगाया जाये जिसमें परिश्रमसे प्राप्त घायपर उसकी दर कम हो और सम्पत्ति में प्राप्त घायपर अधिक हो, तो बचत और पूँजीकी भावनामें कमी आनेकी सम्भावना रहेगी।

पूर्वकालमें एक ऐसी धारणा थी कि यदि आर्थिक साधनोंको भिन्न भिन्न व्यवसायोंमें प्रवेश करनेमें कोई व्याघात न हो तो स्वयमेव उनका वितरण इस प्रकारसे हो जायेगा जिससे बेहो वस्तुएं उनमेंही परिमाणमें उत्पादित की जायेंगी जो उद्योग-भोक्ताओंको अपेक्षित हो। यदि राज्य अपनी कर-नीति द्वारा इसमें व्यवधान उत्पन्न करे, तो इससे इस प्रवृत्तिमें रकावट होगी और साधनोंका भिन्न भिन्न व्यवसायोंमें उपयुक्त वितरण नहीं हो पायेगा, यह तर्क ठीक नहीं है। पूँजीवादमें इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है ब्रिमके कारण भिन्न भिन्न वस्तुओंका परिमाण समाजके हितके लिए नहीं, अपितु पूँजीपतियोंके लाभकी दृष्टिसे होता है। अतएव राज्यको हस्तक्षेप करना पड़ता है। करोड़ प्रयोगसे आर्थिक साधनोंके भिन्न भिन्न व्यवसायों में वितरणको बदला जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि राज्य भूलसे प्रयत्न परिस्थितिवश इस प्रकारके कर लगादे जिससे साधनोंका वितरण अनपेक्षित हो जाये। उदाहरणके लिए, यदि दूधपर कर लगानेके कारण उसका मूल्य बढ जाये, और दूध की भाग कम होनेके कारण मा-पालनके व्यवसायमें कमी आ जाये तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चा तथा रोगियोंके क्षमकी क्षति होनेकी सम्भावना है। परन्तु यदि शराब और अन्य नशीली वस्तुओंपर कर लगानेसे उनके उपभोग और उत्पादनमें कमी हो और उन व्यवसायोंसे निकालकर साधनोंको अधिक उपयोगी व्यवसायोंमें लगाया जाये, तो इससे समाजवांछित होगा। इसी प्रकार यदि विदेशी प्रतियोगिता के कारण ऐसे उद्योग धन्य जिनका स्वदेशमें होना आवश्यक है, न पनपने पायें-तो इस प्रकारकी विदेशीय आनेवाली वस्तुओंपर सरक्षण कर लगाकर देशमें उत्पत्तिके साधनोंको इन उद्योग-धन्यकी ओर आकृष्ट किया जा सकता है। परन्तु इस बात

का ध्यान रखना पड़ता है कि सरक्षण-कर बड़ी सावधानीसे देशके हिताको न कि किमी सस्या विषय के हितोंको दृष्टिमें रखकर लगाया जाये।

करों का वितरण और नियोग पर प्रभाव

पूजीवादी आर्थिक व्यवस्थामें समय समयपर उत्पत्तिके साधनोंमें बंकारी आजाती है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक उद्योगमें शिथिलता और राष्ट्रीय आयमें भी क्षति आजाती है। कुछ समय पहिले एक विचार-धारा प्रचलित थी कि स्वतन्त्र आर्थिक पद्धतिमें थोड़ीसी अनिवार्य बंकारीको छोड़कर प्रतिभागिताके कारण लागत मूल्य-स्तरोंमें इस प्रकारका बढेसाव होजाता है जिससे स्वयमेव सभी साधन किसी न किसी व्यवसायमें लग जाते हैं, परन्तु वास्तवमें यह स्थिति पाई नहीं जाती। प्राधुनिक पूंथशास्त्री इस विचारके हैं कि पूजीवादी व्यवस्थामें आर्थिक कार्या (उद्योगों) की प्रगतिशीलतामें रुकावट पैदा करनेवाले कुछ इस प्रकारके विकार उत्पन्न होजाते हैं जिनका निराकरण स्वयमेव नहीं होसकता। इनमें आयके वितरण और उपयोग, बचत और पूजीके लगावमें असम्बद्धता होजाना एक प्रधान विकार है। चूँकि पूजीवादमें उत्पत्ति मागपर निर्भर रहतीहै, अतएव उसको प्रगतिशील बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक है कि मागका परिमाण न केवल बनाही रहे, बल्कि उसमें वृद्धि हो। भूचा माल, मशीन, कल कारखाने इत्यादि वस्तुओंकी माग अस्तनोगत्वा उपभोग की वस्तुओंकी मागपर ही अवलम्बित रहनी है। अब यदि उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें अव्यवस्था उत्पन्न होजाये तो इससे सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमें अव्यवस्था उत्पन्न होजाती है। आर्थिक व्यवस्थाकी स्थितिके लिए यह आवश्यक है कि उपभोगकी वस्तुओंकी और उत्पादन वस्तुओंकी माग बनी रहे। समाजकी आयके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एकभाग तो उपभोगके पदार्थोंमें व्यय किया जाताहै और दूसरा भाग बचतके रूपमें, जो पूजी बनकर व्यवसायोंमें लगाया जाताहै, परन्तु बचत स्वयमेव पूजीके कार्यमें प्रवृत्त नहीं होजाती। पूजीपति अपनी बचतको उत्पादनके कार्यमें तभी लगातेहैं जबकि उनको लाभकी आशा हो। यदि लाभकी आशा गिरने लगे तो बचत द्रव्यके रूपमें बेकारही संचित रहेगी। पूजीवादकी विशेषता यहहै कि इसमें आयका वितरण बहुत असमान होता है। आयका एक बड़ा भाग कुछ धनी

योगके पाम पञ्चित्र होजाता है जिनमें वचन करनकी शक्ति एवं प्रवृत्ति अधिक होता है। एसी परिस्थितिमें उपभोगकी वस्तुगाकी मागमें चिबिखता आजाता है। नाभकी आगा कम हानलगती है और पूजीक लगावकी भागा भी घटन गगता है। फलस्वरूप उत्पत्तिवे सावनाम बकारी और राष्ट्रीय आयमें कमी आजाती है।

राज्य इस परिस्थितिवा सामना करनके लिए कुछ अस तक कर-नीतिका प्रयोग करसकता है। कर नीति द्वारा आयक वितरणमें असमानता कम की जासकती है। यदि कर का भाग निम्न आय-मनरा कर कम करदियाजाय तो इससे उपभोगके पदार्थोंकी मागको प्रोत्साहन मितगा क्याकि इस श्रेणीके लोग अपनी आयका बहुत बडा भाग उपभागवे पदार्थोंमें ही व्यय करते हैं। इसीप्रकार राज्य यदि एसी वस्तुआपर कर घटा या हटा दे जिनको साधारण आयके व्यक्ति अधिक माना में मान लते हैं तोभी मागका प्रोत्साहन मिनगा। इसप्रकार हम देखतेहै कि व्यवस्थित कर प्रणाली जिसके द्वारा वितरणकी असमानता कुछ अशतक कम का जासकती है वचननतिव दृष्टिकानम ही नहै। त्रिपितु आर्थिक प्रगतिका बनाव रखनके लिए भी चाहिए है। यदि राज्य ऐसे कर लगाए जिनसे यह वचन जा बकार मचिन द्रव्यके रूपमें पडाहु है उदाग घाघामें गगन गगता उससे भा आर्थिक स्थिति सुधर जायगी।

कराके आर्थिक प्रभावका जा चित्रण इस अध्यायमें किया गयाहै उसमें हमका आर्थिक व्यवस्थाम जो बदलाव होताहै उसका पूरा रूप सामन नही दियाहै दना। "साहरणक निग हमन एक स्वानपर कहाहै कि यदि करके कारण अल्प आयवाले व्यक्ति अपन जीवन-मरके घटानकी बबगहा ता उससे डलकी तथा उनकी म नानकी काम कृगलता एवं स्वास्थ्यको क्षति पहुचगी। यह चिय अपूण है। यदि राज्य इस प्रकारके करकी प्रायसे इस श्रणाके लोगाको कम मूल्यपर खान पीन की वस्तुओं और कम मितगपर रहन योग्य भवान मुलभ कराये और उनके वच्चा के लिए नि शुल्क शिक्षा दना इत्यादिका प्रबन्धो तो जो शक्ति उनको कर देनस हातीहै उनकी पूर्तिग भा अधिक क्षम उनको राज्यकी व्यय नीति द्वारा होसकता है। आलाचनाकी सुगमताक लिए हमन व्यय और कर नीतिके आर्थिक प्रभावको अलग अलग दिया है। वस्तुतः राज्यकी व्यय तथा कर नानि द्वारा उत्पन्न आर्थिक प्रभाव का पूण चित्र एकसाय दलना चाहिए।

राज्य-ऋण

राज्य-ऋण का प्रयोजन और महत्व

आधुनिक कालमें सभी देशोंमें राज्य-ऋणका परिमाण बहुत हागया है। कुछ समय पूर्व अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञोंकी यह धारणा थी कि राज्य-ऋण समाजके ऊपर भार-स्वरूप होता है। अतएव राज्यको सकटके समय ही ऋण लेना चाहिए और संघर्षोत्तर उद्घुण होनेकी चेष्टा करनी चाहिए। साधारण आर्थिक अवस्थामें राज्य-ऋणको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था, परन्तु आजकी विचार-धारा भिन्न है। 'राज्यके आर्थिक कार्य बहुत बढगये हैं और उनके द्वारा समाजके सम्पूर्ण आर्थिक अवयवोंको पुष्ट, उन्नतिशील और प्रगतिशील बनानेकी चेष्टा की जाती है। इस प्रकारके अनेक आर्थिक-कार्योंके लिए राज्यको ऋण लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि करते जो आय होती है वह पर्याप्त नहीं होती और अनेक अवस्थाओंमें जैसे आर्थिक मन्त्रीके अवसरपर कर-भार बढाना उपयुक्त नहीं समझा जाता। वर्तमान आर्थिक व्यवस्थामें राज्य-ऋणको भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हागया है जिसके द्वारा राज्य अपनी आर्थिक दृश्य-सम्बन्धी और राजस्व-सम्बन्धी नीतिके कार्यान्वित करनेकी चेष्टा करते हैं।

राज्य अनेक प्रयोजनोंके लिए ऋण लेते हैं। एक कारण यह है कि राज्यको करो ले जाँ आय होनेके वह उभी समय और उभी परिमाणमें नहीं होती जिस समय थोर निम्न परिमाणमें राज्यको व्ययकी आवश्यकता होती है। अतएव जिस समय तक पर्याप्त मात्रामें राज्यको अपने व्ययको पूरा करनेके लिए आय न मिलजाये तबतक के लिए उसको ऋणका ही सहारा लेना पडता है। यह ऋण कुछही महीनाके लिए या तो केन्द्रीय षेत्रमें लिया जाता है अथवा अल्पकालीन सरकारी-दुर्ग द्वारा अनन्त से प्राप्त विप्रेजाना है। आय होजानेपर इस ऋणका भुगदान करदिया जाता है।

राज्यको समाजके हितके लिए कुछ इसप्रकार के निर्माण कार्य करने पड़ते हैं जिनपर बहुत द्रव्य व्यय करना पड़ता है। इतना द्रव्य राज्यकी सामान्य आयसे प्राप्त नहीं होसकता है। उदाहरणके लिए बड़ी बड़ी नहरें खुदवाने, सड़कें और पुल बनवाने, बड़ी मात्रामें जंगल लगवाने, भूमिकी उन्नति करने तथा नदियोंकी घाटियोंके निर्माण-कार्योंके लिए राज्यको बहुत बड़ी मात्रामें व्यय करना पड़ता है। यदि इन निर्माण-कार्योंके सम्पादनके लिए राज्यकी सामान्य आयका ही भरोसा किया जायतो इसमें बहुत अधिक समय लगजायगा और कार्यभी रुक रुक कर होगा। आवश्यकता इसबाट कीहै कि इसप्रकार के आर्थिक निर्माणके कार्य यथाशीघ्र पूरे किये जायें। अतएव राज्यको ऋणका ही सहारा लेना पड़ता है। इसप्रकार का ऋण स्वभावतः दीर्घकालीन होताहै और राज्य बीड, मिक्चरिटी इत्यादि साख-पत्रोंके द्वारा इन प्रयोजनोंके लिए दीर्घकालीन पुजी ऋणके रूपमें प्राप्त करने है।

इस प्रकरणमें राज्यके निर्माण कार्योंको दो भागोंमें विभाजित किया जासकता है। एक प्रकारके कार्य वे हैं जिनके निर्माणके पश्चात् उनमेंही द्रव्यके रूपमें इतनी आय होजाती है कि उसमें ऋणपर व्याज और ऋणके कुछ भ्रशको चुकना करनेके लिए भी रकम बचजाती है। भारतमें ऐसी अनेक नहरें हैं और रेलें हैं जाकि ऋण लेकर धनायी गयी हैं और उनसे जो आय होतीहै उससे प्रतिवर्ष व्याज चुकाकर ऋण परिशोधन-कोषमें भी कुछ रकम डाल दीजाती है। इसप्रकार का ऋण उत्पादक ऋण कहलाता है। दूसरे प्रकारका ऋण वहहै जिसके निर्माण कार्यसे द्रव्य रूपमें इस प्रकारकी आय नहीं होतीहै जैसे सड़कें, पुल और अस्पताल एव पाठशालाकी इमारतें आदि। ये कार्यभी आर्थिक उन्नतिके लिए आवश्यकहै और इनसेभी उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि करनेमें सहायता मिलतीहै, परन्तु प्रत्यक्ष द्रव्यके रूपमें इतनी आय नहीं होती कि उस आयसे व्याज और ऋण चुकता किया जासके।

आर्थिक अपकर्षके अवसरपर भी राज्यको ऋण लेनेकी आवश्यकता पड़ जाती है। उद्योग-धन्वों और वाणिज्य व्यवसायके गतमें पड़ जानेके कारण उत्पादनके साधनों और प्रधानतः श्रमजीवियोंमें बहुत बेकारी आजाती है। राज्यका कर्तव्य होजाताहै कि बेकारोंको आर्थिक सहायतादे और आर्थिक व्यवस्थाको भी गतसे निकालकर समृद्धिकी ओर अग्रसर करे। इन कार्योंमें बहुत रुपया व्यय होताहै जो कि कर-द्वारा प्राप्त नहीं होसकता है। वैसेही राष्ट्रीय आयके गिरजानेसे आर्थिक

अपक्वके समय कर आय गिरजाती है। नये कर लगानमें अथवा पुराने कराकी दरमें वृद्धि करनेसे अपक्वके और भी गहन होनेकी आशका रहती है। ऐसा परिस्थिति में जो द्रव्य बकार संचित पड़ा है, उसको अथवा बेकासे नया साख द्रव्य ऋण लेकर आर्थिक महायताके और निर्माणके कार्योंमें राज्य व्यय करता है। अपक्वके समयके अतिरिक्त भी जब कभी आर्थिक स्वतन्त्रताके अतगत उत्पादनके साधना का कुल नियोग नहीं हो पाताहै ऐसे समयोपर भी राज्यका कर्तव्य समझा जाताहै कि वह अपनी साधारण कर की आयसे अधिक व्यय कर अर्थात् ऋण लेकर बकार साधनोंकी कार्यमें लगानकी चेष्टा कर।

युद्ध-कालीन ऋण

वर्तमान राज्याकी ऋण घमनाका सबसे बड़ा कारण युद्ध है। आधुनिक युद्धोंमें बहुत व्यय होताहै जिसकी पूर्ति कर की आयसे करना असम्भव होजाता है। अतएव राज्यको बड़ी मात्रामें ऋण लेना आवश्यक होजाता है। ऋण लेनेसे राज्यका एक सुभीता यह होताहै कि वह अयाजोद्य आवश्यक युद्ध-सामग्री प्राप्त करसकताहै और उत्पादनके साधनाको सुगमतासे युद्ध सामग्रिया बताने वाल उद्योग धन्धामें नियुक्त करसकता है। ऐसे कर जिनमे सीधतासे श्वर मात्रामें आय होसके अल्प कालमें नहीं सँजोष प्राप्तकरने है। इसके अतिरिक्त जनता भी कराका विरोध करता है। कुछ कालान्तरमें ही करा द्वारा आयकी वृद्धि होसकती है। परन्तु युद्धकी प्रतीक्षा करनी नहीं। अतएव राज्यको ऋण ही सहारा लेना पडता है। ऋणके पक्षमें एक बात यहभी कही जासकतीहै कि जो व्यक्ति अथवा मस्थाए राज्यको ऋण देती है वह सरकारकी बौद्ध और निवृत्तिकी सम्पत्ति का एक रूप मानतेहैं जिनपर उनको ब्याज मिलताहै और ऋणकी अवधि समाप्त होनेपर मूलधनभी वापस मिलजाता है। यह समझने हुएभी कि किसी न किसी दिन ब्याज और ऋणको चक्रान्तके लिए कर देना ही पडया मुद्दर भविष्यमें लियाजाय वाला कर इस समय भार स्वरूप नहीं जान पडता है।

कुछ लोगोका कहनाहै कि युद्ध कालमें जो ऋण लिया जाताहै उसका परिशासक भविष्यकी पीडी करगी। इसप्रकार युद्धक कुछ भार भविष्यकी जनतापर भी पडगा।

इस तकमें बाँट भाग रहा है। जहाँतक युद्धके भारका प्रश्न है वह युद्ध कालीन पीढ़ी पर ही पड़ता है क्योंकि इसी पीढ़ीको अनक प्रकारकी वस्तुआ और सहायसे वचित रहना पड़ता है। जहाँतक भविष्यका जनताका प्रश्न है व्याज गोर ऋण परिधाधक किए उसपर जो बर लगाया जाता है वह उसीका वापस मिल जाता है। हा ऐसा हासकता है कि राज्यका ऋण दनवान ऊँच माय स्तर बाँटता भार वह दनवाला न अधिकारी जिन आय स्तरके लागू है। ऐसा अवस्थाम प्रायः वितरणमें अधिक विषमता आजायगा और ऋणका भार निम्न आयवाला जनतापर अधिक पड़गा। यदि राज्य अन्य राष्ट्रात्म ऋण लेता अवश्यही इस ऋणका भार भविष्यकी जनता पर पड़गा क्योंकि इसका उन सामग्रियों अपनका वचित करना पड़गा जिनका द्वारा ऋणका परिधाध लिया जायगा।

कराक द्वारा युद्ध किए आय संचय करतन परामें रहा जाता है कि जिन ऋण स्तरपर भी युद्धका भार वतमान पीढ़ीपर है पड़ता है ता इसी भारको करके रूपमें हा क्या न यह पीढ़ी सहन करे। इसमें राज्यका भविष्यमें व्याज गोर ऋण परिधाधक किए चिन्ता न करनी पड़गी। यहभी कहा जाता है कि यदि युद्धके आरम्भमें ही पर्याप्त मानामें करों बढ़ि करदा जान ना जनता कम आयकर वस्तुआ और सवाओंके उपभोगकी मानामें उमा उरक उपत्तिक साधनाका युद्धकी सामग्रियोंके लिए मुक्त करदगी। वह पक्षवाताना यहभी कहना है कि यदि राज्य अधिक मात्रा में बकामें अवकाशका द्वारा उपलब्ध द्रव्यका अथ व्यक्तियों अथवा सन्धाओंसे ऋणके रूपमें तब व्यय करने इसमें द्रव्य स्फीतिकी आशका रहती है। इन तकों में कुछ सार अवश्य है परन्तु जमाकि हम ऊपर लिख आयह पर्याप्त मानामें कर लगानमें राज्यका अनक प्रकारकी समस्याओंका सामना करना पड़ता है। परन्तु शर्तें शर्तें राज्यकी अपनी कर प्रणालीका समयाचित बनाकर और जनतामें भी विश्वास पैदा करके अपना बर आय बढ़ानी चाहिए। अन्तर्गत युद्ध व्यय का एक बड़ा भाग करों आयसे ही चकाना चाहिए। जहाँतक द्रव्य-स्फीतिकी प्रश्न है यह वास्तवमें चिन्ताका विषय है। जबतक बकार आर्थिक साधनाका पूरा रूपसे नियोजित नहा किया जासकता है तब तब द्रव्य-स्फीति जनित कष्टों और दुरावस्थाओं का अधिक भय नहीं है। परन्तु लम्बा अधिक युद्धमें शीघ्रही ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँक काममें योग्य सभी मानव नियुक्त होजाते हैं। ऐसी अवस्थामें ऋण

व्ययमें द्रव्य स्फीति जनित मूल्य-वृद्धि होनेके कारण अव्यवस्था और निम्न-आय-स्तर वालाको परेशानी उठानी पड़ती है। इसका आधिक निगरान करनकेलिए ही मूल्य नियन्त्रण और आवश्यक वस्तुओं पर परिमित मात्रामें मभीको उपलब्ध कराने के लिए राज्यको प्रवच करना पड़ता है।

ऋण अथवा कर

उपयुक्त विवेचनमें ज्ञान होजाताहै कि हमी अवस्थाएँ और समस्याएँ उत्पन्न होती रहनीहैं जिनके सम्बन्धमें राज्य का आयपर ही निर्भर नहीं रहसकता है। यह ज्ञानतुहा भी कि यथामाम्भव राज्यको अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति का आय स ही करनी चाहिए यह बातभी निर्विवादहै कि प्राशुनिक आर्थिक व्यवस्थामें राज्य-ऋणना भी एक महत्व पूर्ण म्यान है। ऋण और करना एक दूसरेका प्रतिद्वन्द्वी नहीं परन्तु पूरक समझना चाहिए और युक्ति पूर्वक इनका मामजस्य करना चाहिए। किस अवस्थामें ऋण लियाजाना चाहिए और किस अवस्थामें करनागाना चाहिए तथा किस प्रकार इनका सम्मिश्रण करना चाहिए इसका निणय तत्कालीन आर्थिक स्थिति, कर भार कर दाताओंकी मनस्थिति और कनअ्यकी अपरिहायता और अविलम्बनापर निर्भर हागा। इस सम्बन्धमें हम आर्थिक अपकरण और युद्ध-व्ययक प्रकरणमें विवेचना करमाय है।

ऋण-परिशोधन

ऋणकी अवधिके समाप्त हानपर ऋण चुकाना पड़ता है। कभी कभी राज्य ऋणको अम्वीकार करदेतेहैं अर्थात् ऋण चुकानसे इनकार करदेते ह इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। एकता राज्यकी साथ गिर जातीहै और उसकी भविष्यमें ऋण प्राप्त करनेमें कठिनाई होमकतीहै अथवा अधिक व्याज देनपर ही ऋण मिल सकता है। दूसर यदि साधारण आयवाला भी बीड आर निव्यूरिटी खरीदी हो तो उन्हें आर्थिक सक्कका सामना करना पड़ेगा।

ऋणपरिशोधनके लिए अनन्य उपाय काममें लायजाने हैं। एक उपाय यहहै कि

राज्य वज्रकी वचनकी रकममें बाजारमें घोंड खरीद कर ऋणकी मोटा कम करे। इस उपायमें अधिक सफलता मिलनेकी आशा नहीं की जा सकती। पहिले तो आज-कालके वज्रमें वचन हानकी सम्भावना ही कम रहनी है अतः कि विशेष रूपसे उसका प्रबन्ध न किया जाय। इसके अनिश्चय बोझ यदि नामांकित मूल्यमें कम मूल्यपर बिके तभी लाभ प्राप्त होता है।

ऋण-परिशोधन-कोष

कभी कभी ऋण चुकानेके लिए परिशोधन-कोषकी स्थापना की जाती है। कुछ समय पूर्व एक प्रथा यह थी कि ऋण देनेके पश्चात् उसके परिशोधनके लिए एक कोषमें प्रतिवर्ष इतना द्रव्य जमा किया जाता था जाकि च न वृद्धि व्याज सहित ऋणकी अवधि पूरी हान हाने ऋणके परिमाणके बराबर होजाय। यह प्रथा पश्चिमी देशों में चली थी। आधुनिक कालमें इसमें कुछ परिवर्तन हो गया है। अब यह आवश्यक नहीं है कि कोषमें द्रव्य इस हिमायसे जमा किया जाय कि वह ऋण अवधि तक इसका परिमाणके बराबर होजाये। कौंटमी काय जो ऋण कम करनेके लिए बनाया जाता है उसका ऋण-परिशोधन कोष कहने से। यह आवश्यक नहीं कि इसमें द्रव्य जमा हाना रहा हो। यह कभीभी घोंड खरीदनेके काममें लिया जा सकता है। इसमें माल में जो कुछ रकम वज्रमें उच जाय वह जमा किया जा सकता है अथवा इसमें लिए वज्रमें विद्यमान रूपमें एक निर्धारित रकमका प्रबन्ध किया जाता है अथवा आयकी किसी विशेष मदमें जो प्राप्ति हो वह इस कोषमें डाल दी जाती है। इस प्रकारके कोषमें लनदारोंका आश्रयमान रहता है कि समयपर उनके ऋणका भुगतान होजायगा। परन्तु इस कोषके सुरक्षित रखना, इसका समुचित प्रबन्ध करना और अन्य मदोंपर व्यय न करना इत्यादि समस्याएँ इसके साथ लगी हुई हैं।

विशेष पूजा कर

प्रथम महायुद्ध के बाद राज्य ऋणकी जीघ्रतासे और बड़ी मात्रामें कम करनेके लिए एक मुभाके अंतर्गत यह स्थापना कि मगाजकी पूजापर एकहजार एक विशेष कर लगाया

आय और इससे जो आयही उससे इकट्ठाही राज्य-ऋणका परिशोध किया जाये। इसके पक्षमें यह कहागया कि युद्धकालमें अनेक व्यक्तियों और सस्थाओंकी पूजीमें युद्ध जनित कारणोंसे बड़ी मात्रामें वृद्धिहुई, अतएव इस पूजी-वर का भार इन्हीं लोगोंपर पड़ेगा, और चूकि इस प्रकारके योग अधिकतर सम्पन्न हानेहे और कर भी वर्धमान सिद्धान्तके अनुसार लगाया जायगा, अतएव इसका भार हेंसियमके अनुसार होगा जिससे धनके वितरणकी असमानतामें भी कमी होगी। इस पूजी-कर के प्रतिकूलभी अनन्य बातें बहीगयीं। कहागया कि युद्ध ऋण मार देशकी भलाईके लिए लियागया था तब उसका भार थोड़ेसे सम्पन्न लोगोंपर ही क्यों डाला जा रहा है? इसका परिणाम यह होगा कि जिन लोगोंने बचतकी है और पूजी बढ़ाई है उनको एक प्रकारका दंड मिला और जिन लोगोंने अपनी आय भाग-विलासमें लगा दी वह छूट जायेंगे। इससे बचत करनेकी प्रवृत्तिको घटका लगेगा। यदि इन करकी दर भारीहुई तो उद्योग बन्वोंमें पूजी लगानमें भी उत्साह मन्दा पडसकता है। इसके अतिरिक्त यदि इस प्रकारका वर राज्य बराबर लगाने लग तो कुछ समय बाद सारी सम्पत्ति राज्यवे पास चली जायगी।

राज्य-ऋण चुकानेका यह उपाय विशेष रूपसे काममें नहीं लाया गया। कुछ देशोंमें एक विशेष कर अवश्य काममें लायागया, जोकि आय कर के सदृश था। यह एक बड़ी मात्रामें और वर्धमान नियमानुसार निर्धारित कियागया जिसका भुगतान वार्षिक किस्तोंमें कई वर्षोंकी अवधिमें फैलाकर, कर दियागया था।

ऋण-परिवर्तन

जैसा नामसे बोध होता है ऋण-परिवर्तनसे ऋण-परिशोधन तो वास्तवमें नहीं होता है, परन्तु उसको भविष्यके लिए टाला जासकता है। जब किसी ऋणकी अवधि पूरी होजाती है और राज्यके पास परिचायनके लिए धन नहीं है और वह देनेसे इनकार भी नहीं करना चाहता है तो वह या तो ऋणकी अवधि बढ़ा देता है अथवा उसकालमें नया ऋण लेकर पुराने ऋणको चुकता करदेता है। एक प्रकारसे कहा जासकता है कि ऋणका परिशोधन होगया, यद्यपि वस्तुतः पुराने ऋणके बदले ननवाही नया ऋण होगया। बहुधा जिन व्यक्तियों और सस्थाओंके पास सरकारी बौड होनेहे वे उनको

नये बाँडोंसे वसूल लेते हैं। उस समय ऋण सम्बन्धी शर्तोंमें परिवर्तनभी करसकते हैं। उदाहरणके लिए व्याजकी दर घटासकते हैं अथवा यदि पुगने ऋण आय-कर से मुक्त होता उनपर आय-कर लगाया जासकता है। सक्तावस्थामें जब राज ऋण लेता है तो उसका बहुधा अनिक व्याजको दर देनीपड़ती है। यदि ऋण-परिवर्तनके समय व्याजकी दर गिरगई होना राज्य अधिक व्याजके ऋणको कम व्याजके ऋण में परिवर्तन कर व्याजके भारको कम करसकते हैं। आधुनिक कालमें सरकारी बाँड इस प्रकारसे निखलाने हैं कि कुछ अवधिके बाद राज्यको अधिकार रहना है कि वह चाहे तो ऋणका भुगतान करसकता है। एक १०/३० बाँडका यह तात्पर्य होता है कि ३० वर्षके बाद तो राज्य इस बाँडका अवश्यही भुगतान करेगा, परन्तु १० वर्ष के बाद राज्यको अधिकार हाजिरगा कि वह जब चाहे तब भुगतान करे। यदि वस्तु और तौल इसके बीच व्याजकी दर गिरगई होना राज्य पुराने ऋणको कम व्याज देने लगे ऋणमें परिवर्तित कर सकता है।

तटस्थ स्थिति ६८
 तुम्हो ११५, १२४
 तुलनात्मक द्रव्य १२०
 द्रव्य २२३, की आवश्यकता
 २२३, और वचन २२६, क
 प्रकार २२६, धातु—२३०,
 साख—२३६, साख—कासृजन
 २४०, पद्धतिया २४४, पद्धतियों
 के प्रकार ४४०, का विनिमय
 मूल्य २६२ के विनिमय मूल्य
 का पारिमाणिक मिद्धान्त २६६,
 का मचयन मिद्धान्त २७०, के
 विनिमय म धर्म परिवर्तन का
 प्रभाव २७० अन्तर्राष्ट्रीय—
 रूप ३०५ सम्बन्धी सिद्धान्त
 ३३७
 द्विधातु पद्धति २४५
 नाइट २२६
 निकोलस ११५
 नियति और आन्त्रि सहान्ता
 ३२७
 नोट २२८ विनिमयमाध्य—
 २३६ अविनिमयमाध्य—२३६
 प्रतिस्थापना ६८, का मह-व
 ६८, और तटस्थ स्थिति ६८,
 और उपभाग १०१, और उत्पा-
 दन १०१ और विवरण १०२,
 की विरागी शक्तिया १०३
 प्रतिस्पर्धा अपूर्ण—और एकावि-
 कारकी सीमा ७५, का अर्थ ६७,
 पूर्ण—के फल ६६, पूर्ण—और

एकाधिकार ७०, अल्पकाल, पूर्ण
 —और मूल्य ८३, अपूर्ण—और
 मूल्य ८८ धाणिककाल, पूर्ण—
 और मूल्य ८३
 परिवर्तनीय अनुपात का सिद्धान्त
 १२८
 पीयू १८१
 पूण उद्यम और गतिशीलता ७६
 पूर्ति मान—और मूल्य ८१
 पूजी की गतिशीलता ७८, की
 वैकल्पिक परिभाषा १४८,
 विभिन्न प्रकारकी—१४८, और
 वचन १५०, का मरक्षण १५०
 वचन और—लगाव मिद्धान्त
 ३४३, विशेष—कर ४०८
 पूजीवाद का अर्थ १७०, के लक्षण
 १७१, का विकास १७२
 पेनी ११५, १२३, १२५
 पेरटो ४६, १२१
 पिजियोस्टम् १३४, ३८२
 फिशर १८०-१८१, २१२ २६६
 २६६
 व्याज २०८, की दर २०६, और
 द्रव्य बरीयता २१४, और पूजी
 की उत्पादनशीलता २१५
 वचन और पूजी लगाव सिद्धान्त
 ३४३
 बाजार का विस्तार ६१ धर्म—
 ६३, शुद्ध—के लक्षण ६०
 बाजारों क प्रकार ५६, की
 व्यवस्था ६३

वामबावर्क ११६, १४५, २११-

२१२

वारवा ११५

बील ११५

बुरीदान् ११५

बकारी ३३२

बंक २७५, केन्द्रीय—२८२

बैंको का विकास और उनके कार्य
२७७, की लेनी-देनी २७६

भूमि १२५ की गतिशीलता ७७,

कर १८८ रिकार्डों का—कर

मिदाल १८८, कर का आधु-

निक मिदाल १६३, कृषि

सम्बन्धी समुत्पत्ति और—११

१६५, खती की—पर कर ३६६

मजुरी की परिभाषा १६६, का

लौह-मिदाल १६७, कोष

मिदाल १६८, जीवन मन्त्र और

—२०२, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और

—२०३ नय आविष्कार और—

२०६

मनोवैज्ञानिक आर्थिक उप-

अपकर्ष का—मिदाल ३३४

माकर्म ११६

माक्सवाद १०४ की शाखाएं
१७५

मापदंड मूल्य का—२०५, का

मापन—२२८

मार्शल ११८ १०८ ११०, १८०-

१८१ १८८, २०१, २१०, २१८,

२२०

माल्यम १०७, १३५, १३८

माग ३३, का तात्पर्य ३३, का

नियम ३५, में परिवर्तन ३७,

की लोच ३६, की लोच में भिन्नता

४२, की लोच का महत्व ८५,

पूर्ति और मूल्य ८१, गम्भिरता

—६६, की लोच और घन-

राष्ट्रीय व्यापार ३१८

मिज १०३-१०४ १५१, २१२

मुद्रा ७३१

मूर ३३५

मन्य भेद ७२ निर्धारण की विधि

८० के प्रकार ८०, का महत्व

८० माग पूर्ति और—८१,

काल भेद—८०, दार्शनिक काल,

पूर्ण प्रतिस्पर्धा और—८३,

अल्पकाल पूर्ण प्रतिस्पर्धा

और—८३, अल्पकाल अका-

धिकार और—८७, अपूर्ण प्रति-

स्पर्धा और—८८ बाजार

मूल्य और सामान्य—८२,

गम्भिरता उत्पत्ति और—८६,

एक वस्तु के भिन्न भिन्न—८७,

का मापदंड २२६, और उसके

मिदाल ११४, का अर्थ ११४,

का प्रथममिदाल ११५ और

विनिमय मूल्य २६१, द्रव्य का

विनिमय—७६१

मूल्या का पारम्परिक सम्बन्ध

१०८ का मनुदेन १०८

मेजर ७११

युद्धकालीन ऋण ४०५

राज्य और शासन की आवश्यकता
३५१, आर्थिक कार्या में—के
हस्तक्षेप करने की आवश्यकता
३५२, की आय २६८, की आय
की मदें ३६८, के उद्योग-धन्धों
३६९, की आय का वर्गीकरण
३६२, की अच्छी आय पद्धति
की विशेषताएँ ३७२, ऋण
४०३, ऋण का प्रयाजन और
महत्व ४०३

राजस्व के मुख्य विभाग ३५३,
का स्वरूप और क्षेत्र ३५१

राष्ट्रीय-आय १८०, का अर्थ
१८०, की माप-विधि १८१ की
वैकल्पिक माप-विधियाँ १८२,
और भौतिक कल्याण १८३,
राष्ट्रीय आय मापने के लाभ
१८५,

रिकाडों ११६, १०६ १८८-१८९,
१९१-१९३, २०१

रिकाडों का भूमि-कर सिद्धान्त
१८८, के सिद्धान्त की आलोचना
१९१

रोबिन्स १७०

लाभ २१७, शुद्ध और मिश्रित—
२१७, का भूमि-कर सिद्धान्त
२१७, जोखिम और—२२०,
का प्रगतिशील सिद्धान्त २२१,
अधिकतम सामाजिक—सिद्धान्त
३५५

सॉक ११५

व्यवस्था १५०, की आवश्यकता
१९२, के रूप १२८

वैज्ञानिक-प्रवन्ध का अर्थ तथा उद्देश्य
१६६, के दोष १६८

वाकर ११८, २१७

वानरेम १०५, ११९

व्यापार उन्मुक्त और मरक्षित—
३२०

व्यापारिक विषमता सिद्धान्त
२९४ समनुबन्ध ३२७

व्हाइट याजना ३०५

वावी १६५

विबस्टीड ११९, २१५

विक्रमेल १४७, १५२

विनिमय वस्तु—की प्रथा २२४,
का माध्यम २२५, —माध्य नोट

२३६, स्वर्ण—द्रव्य-पद्धति २४८,
द्रव्य का—मूल्य २६१, मूल्य और

—मूल्य, २६१ विदेशी—२९०,
विदेशी—की आवश्यकता २९०,

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति और विदेशी
—२९७, नियन्त्रित विदेशी

—२९७, अविनिमय साम्य
द्रव्य पद्धति और विदेशी—३००

विनियोग सर्वोत्तम—का सिद्धान्त
१३१

विश्वबैंक ३१०

वीजर ११९, १२४

वैकल्पिक व्यय १२०

श्रम की गणितीयता ७७, बाजार

६३ और उत्पादन व्यय सिद्धान्त
की दृष्टि ११८ की परिभाषा
१३४ कुलनता १६० विभाजन
के लाभ १४२
स्वानापन्नता की दर ५२ की लोच
१७ सीमान्त—१०० दो
प्रकार की स्वानापन्न बस्तुएँ ६६
स्वयं द्रव्य पद्धति २४६ अमुद्रित
—०४७ के गण और दोष
२४६ का अर्थ २४६
स्वयं मुद्रा पद्धति २४७
स्वयं विनिमय द्रव्य पद्धति २४८
मट्टा ६६
सन्तुलन आर्थिक १०४ मन्वा का
१०४ सम्वा का १०७ उद्योग
और उनका १११ उत्पादन और
उपका १११
समाजशास्त्र १०४
साख द्रव्य २३६ द्रव्य का सञ्चय

२४० और साख पत्र २७५
साखना की अविभाज्यता १३३
सापेक्ष मूल्य ८८
साम्यवाद १७६
सोमान्त उपयोगिता २५ सम—
उपयोगिता नियम २८ उरया
विनाया का अनुपात ५३ उपा
दन व्यय ८८-८९ आन ८६
६२ उपयोगिता सिद्धांत ११६
उत्पत्ति सिद्धांत १६८ तुष्टि
१०२
सूचकप्रक २६३
हासशील जन सरया १०६
हटिस्टन १४०
हायक ३३८-३४१
हायक का सिद्धांत ३३८
हनरा जान ३८०
हो ३३७-३३८
हीमन ३४२-३४३